



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13]  
No. 13]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 1992/चैत्र 8, 1914  
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 1992/CHAITRA 8, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II) PART II—Section 3—Sub-section (II)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government  
of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

यह विदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में  
प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुनित प्राप्त, बम्बई सम्मुख हाजिर हों।

[का.सं. 673/398/91-सी.सु.-8]

रूप चंद्र, अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

का.सं. 927.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी  
मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52)  
की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया  
है, उक्त अध्याय के अधीन आदेश का.सं. 673/308/91-सी.सु. 8  
तारीख 8-11-91 को यह विदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री रमेश  
शार. रामभिया, महेंद्रा विला, जे.वी. रोड, पहली मंजिल, घाटकोपर  
बम्बई-400086 जोखम पर लिया जाए और केन्द्रीय जेल बम्बई में  
अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे किसी भी ऐसे का से रोका जा  
सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि  
पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या घपने को छिपा रहा है जिससे  
उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-  
धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए

S.O. 927.—Whereas the Joint Secretary to the Govern-  
ment of India, specially empowered under sub-section (1) of  
section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and  
Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974)  
issued under No. 673/398/91-CUS. VIII dated 8-11-1991  
under the said sub-section directing that Shri Ramesh R.  
Ramibhia, Mahendra Villa, J. V. Road, 1st Floor, Ghatkopar,  
Bombay-400086 be detained and kept in custody in the  
Central Prison Bombay with a view to preventing him from  
acting in any manner prejudicial to the augmentation of  
foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/398/91-CUS.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.प्रा. 928.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/399/91-सी.पु.-8 तारीख 8-11-91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री सिद्दीकी मोह. सलीम, 23-ई, मूर्गमुला स्ट्रीट, डोंगरी, बम्बई 400009 महाराष्ट्र को कि निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के सात दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के सम्मुख हजरि हो।

[का.सं. 673/399/91-सी.पु.-8]

रूप चन्द्र, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 928.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/399/91-CUS. VIII dated 8-11-1991 under the said sub-section directing that Shri Siddique Mohd. Salim, 23-E, Murgimulla Street, Dongri, Bombay-400009, Maharashtra be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/399/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.प्रा. 929.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52)

की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/423/91-सी.पु.-8 तारीख 18-12-91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि जगदीश हस्तीमल छजेव, फ्लैट नं. टी-5, तीसरा तल, "बी" बिल्डिंग, गार्डन कॉलोनी एन.जे. क्रॉस रोड नं. 2, महिम (पं.) बम्बई-16 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त बम्बई के सम्मुख उपस्थित हो।

[का.सं. 673/423/91-सी.पु.-8]

रूप चन्द्र, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 929.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/423/91-CUS. VIII dated 18-12-1991 under the said sub-section directing that Shri Jagdish Hastimal Chhajed, Flat No. T-5, 3rd Floor, "B" Building, Garden Colony, L. J. Cross Road No. 2, Mahim (West) Bombay-16 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/423/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.प्रा. 930.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश का.सं. 673/424/91-सीमा शुल्क-8 तारीख 6-12-91 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री प्रभुल कयाम दामोदी उर्फ महबूब, कांभवाला भवन, प्रथम तल, निजाम स्ट्रीट, बम्बई-3 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, बम्बई के समक्ष उपस्थित हों।

[फा.सं. 673/424/91-सी.गु.-8]

रूप चन्द, प्रवर सचिव

### ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 930.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/424/91-CUS. VIII dated 6-12-1991 under the said sub-section directing that Shri Abdul Qayoom Damodi @ Mehboob, Kanchwala Building, 1st Floor, Nizam Street, Bombay-400003 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/424/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

फा.सं. 931.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/425/91-सी.गु.-8 तारीख 17-12-1991 यह निदेश देने हुए जारी किया गया था कि श्री विजेन्द्र कुमार पौन, सुपुत्र श्री राम बहादुर जैन, 2294, गली पहाड़वाली धरमपुरा, दिल्ली-6 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोक जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष उपस्थित हों।

[फा.सं. 673/425/91-सी.गु.-8]

रूप चन्द, प्रवर सचिव

### ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 931.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. N. 673/425/91-CUS. VIII dated 17-12-1991

under the said sub-section directing that Shri Vijender Kumar Jain, son of Shri Ram Bahadur Jain, 2294, Gali Paharwali Dharampura, Delhi-110006 be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[No. 673/425/91-CUS. VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

### आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

फा.सं. 932.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/430/91-सी.गु.-8 दिनांक 18-12-91 को यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री रविन्दर पाल सिंह सेठी, पुत्र फकीर सिंह, 20/8, ओल्ड राजिन्दर नगर, नई दिल्ली-110008 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोक जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष उपस्थित हों।

[फा.सं. 673/430/91-सी.गु.-8]

रूप चन्द, प्रवर सचिव

### ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 932.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/430/91-Cus. VIII dated 18-12-1991 under the said sub-section directing that Shri Ravinder Pal Singh Se hi @Bawa, son of Shri Faqir Singh, 20/8, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110008 be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/430/91-Cus.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.भा. 933.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/431/91-सी.गु.-8 तारीख 18-12-91 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री नरेन्द्र पाल सिंह, सुपुत्र श्री लखबीर सिंह, निवासी घर-54, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली को निष्कृत कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त दिल्ली के समक्ष हाजिर हों।

[फा.सं. 673/431/91 सी.गु.8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

O. 933.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/431/91-Cus. VIII dated 18-12-1991 under the said sub-section directing that Shri Narender Pal Singh, son of Shri Lakhbir Singh, Resident of R-54, Greater Kailash-I, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/431/91-Cus.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.भा. 934.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/438/91-सी.गु.-8 दिनांक 27-12-91 को निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री जे. सम्पाथ कुमार; पुत्र भार. जयराम रेड्डीयार, नं. बी-12, शास्त्री रोड, थिलाई नगर, तिरुची, तमिलनाडु को निष्कृत कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिरुची में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक तमिलनाडु, मद्रास के समक्ष हाजिर हों।

[फा. सं. 673/438/91-सी.गु.8]

रूप चन्द, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 934.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/438/91-Cus. VIII dated 27-12-1991 under the sub-section directing that Shri J. Sampath Kumar, son of R. Jayaraman Reddiar, No. B-12, Shastri Road, Thillainagar, Trichy, Tamilnadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Trichy with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Tamilnadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/438/91-Cus.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.भा. 935.—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/437/91-सी.गु. 8 तारीख 20-12-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री एम. मोहम्मद इकबाल, सुपुत्र वी. मोहम्मद, इक्यू-83, कोवार्ड-पुडूर, कोयम्बटूर, तमिलनाडु को निष्कृत कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, कोयम्बटूर में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अब अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, तमिलनाडु, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 673/437/91 सी.गु.8]

रूप चन्द, अवर सचिव



## ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 935.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/437/91-Cus. VIII dated 20-12-1991 under the said sub-section directing that Shri M. Mohd. Iqbal, son of B. Mohammed, W-83, Kovaipudur, Coimbatore, Tamilnadu be detained and kept in custody in the Central Prison, Coimbatore with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the D.G. of Police, Tamilnadu, Madras within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/437/91-Cus.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.प्र. 936 भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 673/400/91-सी.शु. 8 तारीख 8-11-1991 यह निदेश देते हुए जारी किया था कि श्री चन्द्रकान्त एच. शाह उर्फ चन्दुभाई, 58/60, मिंट रोड, कमरा नं. 6, तीसरी मंजिल, फोर्ट, बम्बई-400001, को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय जेल, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे ऐसे किसी भी कार्य से रोका जा सके जो विदेशी मुद्रा के संवर्धन के लिए हानिकारक हो।

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन के 7 दिन के भीतर पुलिस प्रायुक्त, बम्बई के सम्मुख हजरि हों।

[फा. सं. 673/400/91 सी.शु. 8]

रूप चन्द, अधीक्षक सचिव

## ORDER

New Delhi, the 18th March, 1992

S.O. 936.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued under F. No. 673/400/91-Cus. VIII dated 8-11-1991 under the said sub-section directing that Shri Chandrakant H. Shah @ Chandubhai, 58/60, Mint Road, Room No. 6, 3rd

Floor, Fort, Bombay-400001 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from acting in any manner prejudicial to the augmentation of foreign exchange;

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Bombay within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/400/91-Cus.VIII]

ROOP CHAND, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वैकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 25 मितम्बर, 1991

का.प्र. 937.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसरण में केन्द्रीय निदेशक ब्रोड ने भारत सरकार को 30 जून, 1991 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट भेजी है जो नीचे उद्धृत की जाती है:—

भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 1 जुलाई, 1990 से 30 जून, 1991 तक

भाग I—आर्थिक स्थिति

## 1. विहंगावलोकन

1.1 निरन्तर चले जा रहे राजकोषीय एवं विदेशी भुगतान असन्तुलनों के रहते हुए भी, वर्ष 1990-91 के दौरान अर्थ-व्यवस्था में संवर्धन की गति पर्याप्त सन्तोषजनक स्तर पर बनी रही, जिसका श्रेय लगातार तीसरी बार हुई अच्छी फसल को जाता है। अनुमान है कि वास्तविक सकल देशी उत्पाद में पिछले वर्ष के दौरान 5.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1990-91 में 5.0 प्रतिशत वृद्धि हुई। जहां कृषि एवं उत्पादन क्षेत्रों की स्थिति बेहतर रही, वहीं मूलभूत क्षेत्र की प्रगति धीमी रही और सेवाओं के क्षेत्र में भी वृद्धि की रफ्तार काफी कुछ धीमी रही।

1.2 ऐसा अनुमान है कि समग्र कृषि उत्पादन 1989-90 के 1.7 प्रतिशत और 1988-89 के 21.0 प्रतिशत की तुलना में 1990-91 में 4.0 प्रतिशत से थोड़ा अधिक हुआ। खाद्यान्न की पैदावार भी 1989-90 के 170.6 मिलियन के मुकाबले 1990-91 में 176 मिलियन टन आंकी गयी है। उद्योग के क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में गतिशील रूप से काम होने के कारण औद्योगिक उत्पादन का समग्र सूचकांक 1989-90 में हुई 8.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1990-91 में बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गया।

1.3 घरेलू बचत की दर में गिरावट दर्ज की गयी, हालांकि यह गिरावट आंशिक ही थी। इसके बावजूद 1990-91 में, सकल घरेलू निवेश दर 24 प्रतिशत से (अधिक रही क्योंकि विदेशी पूंजी प्रवाह अर्थात् चालू खाते घाटे का प्रतिरूप) में वृद्धि हो गई। वर्ष 1990-91 के दौरान पूंजी बाजार के प्राथमिक निर्गम खण्ड में समष्टि अर्थव्यवस्थाजन्य दबावों और अनिश्चितताओं के कारण पर्याप्त निष्क्रियता अनुभव की गयी। दूसरी ओर, गौण बाजार में विपरीत प्रवृत्तियों का अनुभव किया गया और शेयर मूल्यों में निरन्तर समग्रतः वृद्धि दर्ज की गयी। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे जुलाई 1990 में घोषित संरचनात्मक सुधार के उपायों की शृंखला के बाद उल्लेखनीय रूप से पुनः प्रवृत्त किया गया।

1.4 वर्ष 1990-91 के दौरान निर्यात क्षेत्र का काम सन्तोषजनक नहीं रहा। वाणिज्य व्यापार के आंकड़ों से विदित होता है कि वस्तुतः निर्यात वृद्धि जो पिछले चार वर्षों के दौरान लगभग 10 से 12 प्रतिशत वार्षिक रही, 1990-91 में भारी गिरावट की स्थिति बनती चली गयी। रुपये के रूप में, निर्यात में पिछले वर्ष के 36.8 प्रतिशत की तुलना में 1990-91 के दौरान 17.5 प्रतिशत वृद्धि हुई। अमरीकी डालर के रूप में वृद्धि की दर पिछले वर्ष के 18.7 प्रतिशत से गिरकर 9.0 प्रतिशत हो गयी। रुपयों में आयात में पिछले वर्ष की 25.4 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 21.9 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि डालर के रूप में उनमें वृद्धि की रफ्तार अधिक तेज, अर्थात् 11.2 प्रतिशत की तुलना में 13.1 प्रतिशत रही। वाणिज्य व्यापार में फलतः गिरावट लगभग पूरी तरह से पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयातों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि और इससे भी ज्यादा पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के मूल्यों में आये एक बड़े उछाल के कारण आयी। उच्चतर व्यापार घाटे के अतिरिक्त अदृश्य प्राप्तियों में भारी गिरावट आयी जिसके फलस्वरूप चालू खाता घाटे एवं सकल देशी उत्पाद का 1989-90 का 2.3 प्रतिशत का अनुपात 1990-91 में बढ़कर अनुमानतः 2.5 प्रतिशत हो गया।

1.5 केन्द्र सरकार का बजट घाटा, जिसका 1990-91 में 7,206 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया था, नवम्बर, 1990 के मध्य तक अति-अति 15,442 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था और जो अन्ततः 11,430 करोड़ रुपये रह गया अर्थात् बजट अनुमान से 60 प्रतिशत अधिक। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार का मुद्राकृत घाटा भी अनुमान से कहीं ज्यादा अधिक था।

1.6 मुद्राकृत घाटे में फैलाव के बावजूद, 1990-91 में व्यापक मुद्रा (एम<sup>3</sup>) के फैलाव की रफ्तार धीमी रही और इसकी वजह निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में भारी कमी का आ जाना था। विदेशी मुद्रा की प्राग्क्षिण निधि में कमी के अलावा, परिश्रम और अन्य वुनियादी संरचनात्मक रुकावटों के फलस्वरूप वास्तविक

अर्थव्यवस्था में आयी मुस्ती, रहन-सहन के खर्च में लगातार वृद्धि, जिसने घरेलू बचत की प्रवृत्ति को बुरी तरह प्रभावित किया तथा बचत की अन्य आकर्षक लिखतों, विशेषतः म्युचुअल फण्ड का उदय, इन कारणों से बैंक की जमा-राशियों में बढ़ोतरी की गति धीमी रही।

1.7 समष्टिगत आर्थिक असमानताओं की प्रवृत्ति स्फीतिकारी दबावों को बढ़ाने में लगी रही। थोक भाव सूचकांक में वृद्धि 1989-90 के 9.1 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 12.1 प्रतिशत हो गयी। सामान्यीकृत मुद्रास्फीति के अलावा, सामान्य उपभोग की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धियों की उच्च दरें औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1990-91 में हुई 13.6 प्रतिशत की वृद्धि से स्पष्ट है जबकि यही वृद्धि पिछले वर्ष 6.6 प्रतिशत थी।

1.8 विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों पर 1990-91 की दूसरी छमाही तथा वर्ष 1991-92 के प्रारम्भिक सप्ताहों में भारी दबाव पड़ा। अतः भुगतान सन्तुलन का अल्पकालिक प्रबन्ध आर्थिक नीति के लिए दबावयुक्त तात्कालिक चिन्ता का विषय बन गया। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में तेजी से आयी कमी के फलस्वरूप चालू घाटे का वित्तपोषण कठिन हो गया क्योंकि जो अल्पावधि और दीर्घावधि वित्त पहले उपलब्ध थे उनका मिलना काफी कठिन हो गया। यही कारण था कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय दोनों प्रकार की एजेंसियों से विशिष्ट वित्तपोषण की मांग की गयी और उसे प्राप्त किया गया। स्वर्ण के लेन-देन से भी पूरक वित्त जुटाया गया। आर्थिक मोर्चे पर दबाव और तनाव प्रारम्भ में केन्द्र सरकार का नियमित बचत में होने के कारण उजागर हुए। ऐसी दशा में, अल्पकालीन आर्थिक प्रबन्ध का लगभग समूचा बोझ काफी हद तक मौद्रिक और ऋण नीति पर आ पड़ा। इस प्रकार, गैर-परम्परागत मौद्रिक नीति लिखतों का खुलकर इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया।

1.9 तथापि, जुलाई, 1991 के महीने में समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व और संरचनात्मक सुधार लाने के लिए दूरगामी नीतियां शुरू हो गयीं। सर्वप्रथम, रिजर्व बैंक ने लगभग 18-19 प्रतिशत के द्विस्तरीय निम्नगामी समायोजन बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में किये ताकि हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी हो सके, अनिवार्य आयातों में कमी आ सके, पूंजी-पलायन के प्रत्याहनों को कम-से-कम किया जा सके, पूंजीगत खाते में स्थायित्व लाया जा सके तथा देश की भुगतान सन्तुलन की अर्थक्षमता को सामान्यतः बहाल किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विनिमय दर में समायोजनों के लाभ मुद्रास्फीति के रूप में मामने न आयें, मौद्रिक नीति का बैंक दर, जमा एवं उधार की ब्याज दरों और पुनर्वित्त की दरों में वृद्धि करके साथ-साथ नियंत्रित किया गया। दूसरे, भारत की व्यापार नीति में, विनिमय दर समायोजन के साथ-साथ, ऐसे महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार किये गये कि व्यवस्था को प्रशासनिक नियंत्रण और लाइसेंसों के दायरे में यथासम्भव परे रखा जा सके और इस प्रकार निर्यातों को बढ़ावा

दिया जा सके और अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता और उद्यम को सामान्यतः प्रोत्साहन दिया जा सके। उदासीकृत उपायों की एक और कड़ी अगस्त 1991 में शुरू की गयी जिनमें 20 आयात और 16 निर्यात मदों का मुक्त किया जाना तथा निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा खाला खोलने की सुविधा दिया जाना शामिल है। व्यापार-नीति सम्बन्धी सुधारों में एक महत्वपूर्ण तत्व है विशिष्ट अनिवार्य आयातों को छोड़ सभी आयातों को निर्यातों से जोड़ना। तीसरे, औद्योगिक लाइसेंसिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी प्रौद्योगिकी करारों से सम्बन्धित नीति ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। नये नीति पैकेज में यह व्यवस्था की गयी है : 18 विशिष्ट औद्योगिक श्रेणियों को छोड़कर, सभी उद्योगों के लिए तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए निरन्तर आरक्षण को छोड़कर, औद्योगिक लाइसेंसिकरण की अपेक्षा को समाप्त करना, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों और प्रभावशाली उपक्रमों के लिए आस्ति सीमा हटाना, ऐसे 10 क्षेत्रों में प्राइवेट निवेश की भी अनुमति देना जो अभी तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, 34 चयनित क्षेत्रों में 51 प्रतिशत तक विदेशी ईक्विटी भागीदारी के लिए अनुमोदन प्रदान करना और साथ ही, विदेशी प्रौद्योगिकी करारों के लिए स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था। लघु, अति लघु और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए उपायों की एक शृंखला पहले ही तैयार की जा चुकी है। चौथे, 1991-92 के केन्द्रीय बजट में लक्ष्य यह रखा गया है कि राजकोषीय समायोजनों की प्रक्रिया की शुरुआत करके 1991-92 के दौरान समष्टिगत आर्थिक स्थिरता के प्रति योगदान दिया जाए और उसके बाद लगभग तीन वर्ष के मध्यावधि परिप्रेक्ष्य के सन्दर्भ में अनवरत राजकोषीय सुदृढ़ता लाते हुए इसका अनुपरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बजट में इस आशय के ठोस उपाय किये गये हैं कि सकल राजकोषीय घाटे को 1990-91 के

लगभग 8.4 प्रतिशत के सकल देशी उत्पाद से घटाकर 1991-92 में 6.5 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक ले आया जाए और इसके साथ ही, राजस्व घाटे एवं सुद्रीकृत घाटे को भी एक उल्लेखनीय सीमा तक सीमित रखा जाए। बजट में ऐसे कई गैर-राजकोषीय उपाय भी तय किये गये हैं जो वित्तीय व्यवस्था को आगे ले जाने में सहायक हैं, जैसे लघु बचतों पर ब्याज की दरों में वृद्धि, मीयादी ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं को छूट देना ताकि वे अपने उधार-कर्तियों की साख के हिमाख में ब्याज में 15 प्रतिशत की निम्नतम सीमा पर परिवर्तन कर सकें, डिबेंचरों पर दिये जाने वाले ब्याज की दरों पर से सभी प्रतिबन्ध हटा लेना, पूंजी बाजार को मजबूत बनाने के उपाय करना, पूंजी निर्गम नियंत्रण को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एस०ई०बी०आई०) को अन्तर्गत करना तथा म्यूचुअल फण्ड के कार्यकलाप के निजी क्षेत्र में जाने की अनुमति देना। अन्त में, जहां तक वित्तीय क्षेत्र का स्वयं का सम्बन्ध है, सरकार ने इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सुधारों की शुरुआत के प्रति अपने इरादे के संकेत दिये हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र-विशेष की संस्थाओं की स्थिति सुधारने के साथ-साथ आर्थिक प्रगति और प्रतियोगितात्मक क्षमता के अनिवार्य सहयोगी के रूप में वृत्तियादी भूमिका को बनाये रखना होगा।

## 2. राष्ट्रीय आय, बचत और निवेश

### वृद्धि का परिदृश्य

2.1 वर्ष 1990-91 के दौरान वास्तविक सकल देशी उत्पाद (जी०डी०पी०) की वृद्धि का अन्तिम अनुमान 5 प्रतिशत है। 1989-90 में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो सातवीं योजना में हासिल की गयी 5.6 प्रतिशत और नौवें दशक के दौरान हासिल 5.3 प्रतिशत की प्रवृत्ति वृद्धि दर से अधिक है। कृषि की वृद्धि दर में थोड़ा-सा सुधार अनुमानित है जबकि आधारभूत संरचना क्षेत्र और सेवाओं की मन्द वृद्धि ने 1990-91 में सकल देशी उत्पाद में कुछ कम वृद्धि दर का योगदान किया है।

सारणी 2.1 : वास्तविक सकल देशी उत्पाद में वृद्धि दर

क्षेत्र	(वास्तविक स.दे.उ.)					वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	1970-71	1980-81	1989-90	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90*
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कृषि और सम्बन्ध कार्य	44.5	38.2	32.1	+0.3	-1.7	+0.4	15.4	2.5
(क) कृषि	39.7	34.7	29.7	+0.3	-1.7	+0.7	16.3	2.3
2 उद्योग	18.6	20.8	24.6	+4.5	+7.8	+7.0	+8.7	7.7
(क) विनिर्माण	16.1	17.6	20.5	+4.0	+7.0	+7.3	+8.4	+7.4
(ख) सेवाएं	38.9	41.0	43.3	+7.2	+6.4	+6.2	+7.8	+5.8
जोड़ (स.दे.उ.)	100.00	100.00	100.00	+4.1	+3.9	+4.5	+10.4	+5.2

\* निर्माण सहित

## बचत और निवेश की प्रवृत्तियाँ

2.2 वर्ष 1990-91 के अन्तिम अनुमान यह दर्शाते हैं कि वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद की तुलना में सकल देशी बचत के अनुपात में आंशिक गिरावट आयी है। यह अनुपात 1989-90 में 21.6 प्रतिशत था, जो घटकर 21.7 प्रतिशत हो गया (सारणी 2.2) ऐसा होने पर भी यह 1988-89 में प्राप्त 21.1 प्रतिशत की दर तथा सातवीं योजना के 20.2 प्रतिशत के औसत से अधिक है।

2.3 उक्त अनुमान यह भी संकेत देते हैं कि वर्ष 1990-91 में विदेशी संसाधनों के शुद्ध आगम में और बढ़ोतरी हुई और सकल देशी उत्पाद में उसका अनुपात 1989-90 के 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गया। सकल देशी बचतों की दर में कुछ गिरावट आने के बावजूद यह अनुमान है कि वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में कुल देशी निवेश के अनुपात में 1990-91 में मामूली वृद्धि हो जाएगी और वह 1989-90 के 24.2 प्रतिशत से बढ़कर 24.4 प्रतिशत हो जाएगा।

## सारणी 2.2 देशी बचत तथा निवेश अनुपात के अनुमान

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/राजकोषीय वर्ग	चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल बचत तथा निवेश			चालू बाजार मूल्यों पर शुद्ध देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में शुद्ध बचत तथा निवेश		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. घरेलू क्षेत्र की बचत जिसमें से :	17.1	17.8	17.6	14.6	15.5	15.5
वित्तीय आस्तियों *में बचत	7.3	8.9	8.6	8.0	9.9	9.7
3. सार्वजनिक क्षेत्र	2.0	1.7	1.6	—2.7	—3.3	—3.6
3. देशी निजी कंपनी क्षेत्र	2.0	2.1	2.4	0.5	0.5	0.5
4. कुल : देशी बचत (1+2+3)	21.1	21.7	21.6	12.4	12.7	12.4
5. कुल विदेशी स्रोतों का शुद्ध आगमन	2.8	2.5	2.8	3.1	2.7	3.2
6. कुल निवेश (4+5)	23.9	24.1	24.4	15.5	15.4	15.6
चालू बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद/शुद्ध देशी उत्पाद (करोड़ रुपये)	3,94,992	4,42,769	5,18,500	3,55,902	3,97,239	4,64,245

वित्तीय दायित्वों के लिए इनका समायोजना किया गया। चूंकि वित्तीय आस्तियों में बचत अथवा आस्तियों के लिए पूंजी के उपयोग में शामिल नहीं होते, अतः शुद्ध औसत, सकल औसतों से अधिक आते हैं, इसी प्रकार विदेशी स्रोतों के शुद्ध आगमन में होता है।

टिप्पणियाँ 1. नये आंकड़ों के प्राप्त होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय तथा बचत और निवेश के अनुमानों में संशोधन होने के कारण बैंक के पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दिए गये तथा 1989-90 के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने "एवरि अनुमानों" में प्रकाशित औसत, 1988-89 तथा 1989-90 के औसतों से भिन्न हैं। इन अनुमानों में आगे और संशोधन होगा जब केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन 1990-91 के लिए अपने "एवरि अनुमानों" को प्रकाशित करेगा।

2. अंतरों को पूर्णतः किये जाने के कारण आंकड़े कुल योग से भेद नहीं खा सकते।

2.4 सकल देशी बचत अनुपात में 1990-91 में आयी थोड़ी-सी गिरावट वित्तीय आस्तियों में घरेलू क्षेत्र की बचत दर तथा ऐसे ही सार्वजनिक क्षेत्र की बचत दर गिरावट की द्योतक है। तथापि, निजी कम्पनी क्षेत्र की बचत दर में कुछ और सुधार हुआ। शुद्ध देशी बचतों की क्षेत्रीय संरचना की पहली की तरह यह विशेषता बनी रही कि सार्वजनिक क्षेत्र ने बड़ी मात्रा में निर्वाचित किया और निजी कम्पनी क्षेत्र के बचत की मात्रा बहुत कम थी।

वित्तीय आस्तियों में बचत और उसकी संरचना

2.5 वर्ष 1989-90 में पायी गयी वित्तीय आस्तियों में (सकल) घरेलू क्षेत्र की बचतों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के

विपरीत, सकल देशी उत्पाद में ऐसी बचतों के अनुपात में गिरावट दिखाई दी और वह 1989-90 के 11.3 प्रतिशत से घटकर 1990-91 में 10.8 प्रतिशत हो गया। शुद्ध देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में वित्तीय आस्तियों (शुद्ध) में घरेलू क्षेत्र की बचत भी 1989-90 के 9.9 प्रतिशत से घटकर 1990-91 के दौरान 9.7 प्रतिशत हो जाने की प्रत्याशा की जाती है।

2.6 यह अनुमान है कि चल मुद्रा की वृद्धिशील अभि-धारिता, जो 1989-90 में सकल देशी उत्पाद का 1.7 प्रतिशत थी, वहां 1990-91 के दौरान उसमें गिरावट आने की आशा है। इसी प्रकार, बैंक जमा राशियों के रूप में

जो बचतें 1989-90 में सकल देशी उत्पाद 4.5 प्रतिशत के बराबर थी, उनके भी 1990-91 में कम हो जाने की सम्भावना है। अतः यह प्रत्याशा की जाती है कि चल मुद्रा और बैंक जमागणियों के रूप में धारित मुद्रागत आस्तियों के अंश में 1989-90 के मुकाबले 1990-91 के दौरान कमी आएगी। सकल देशी उत्पाद के अनुपात के रूप में संविदागत बचतें (जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य और पेंशन निधियां) 1989-90 के 3.1 प्रतिशत से घटकर 1990-91 में 2.9 प्रतिशत हो गयी। सरकार पर दावों के रूप में बचतें भी 1989-90 और 1990-91 इन दोनों वर्षों में सकल देशी उत्पाद के 1.4 प्रतिशत के आसपास वस्तुतः अपरिवर्तित रहीं। तथापि, शेयरों और डिबेंचरों में घरेलू क्षेत्र की बचतों का अंश जिसमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा अन्य म्यूचुअल निधियों की यूनिटें भी सम्मिलित हैं, 1989-90 में जहाँ सकल देशी उत्पाद में 0.7 प्रतिशत वृद्धि थी, वहीं 1990-91 में उसमें मामूली वृद्धि हो जाने की आशा की जाती है। सकल वित्तीय आस्तियों में ऐसी आस्तियों का अंश भी 1989-90 के 6.6 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 9.5 प्रतिशत हो जाने की आशा है।

2.7 वित्तीय आस्तियों में पारिवारिक बचत का (विभेदी) अभिलक्षण रहा है, ऐसी बचतों का बैंक जमा से शेयरों और ऋण पत्रों और यू टी आई की यूनिटों, म्यूचुअल फण्ड की ओर जाना, यह वित्तीय प्रणाली में बढ़ती हुई विविधता और लाभ के लिए, संबेदनशील अधिक परिष्कृत निवेशक वर्ग के प्रादुर्भाव को प्रकट करता है।

### 3. कृषि उत्पादन

3.1 वर्ष 1990-91 के दौरान, लगातार तीसरे वर्ष भी कृषि उत्पादन में सतत वृद्धि हुई जिसमें अर्थव्यवस्था में काफी सुदृढ़ता आयी। 1990 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून

के 'असाधारण रूप' से अच्छा होने के कारण पिछले दशक में हुई वर्षा में उसका स्थान तीसरा रहा। समय और स्थान की दृष्टि से वर्षा काफी अच्छी थी। उत्तर-पूर्वी मानसून भी अनुकूल था।

3.2 अनुमान है कि कृषि उत्पादन के समग्र सूचकांक में 4.0 प्रतिशत से थोड़ी अधिक वृद्धि हुई जबकि 1989-90 में उसमें 1.7 प्रतिशत तथा 1988-89 में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। खाद्यान्नों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के अलावा जूट और मेस्ता तथा गन्ने जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में भी भारी वृद्धि होने का अनुमान है।

### खाद्यान्न उत्पादन

3.3 वर्ष 1990-91 के दौरान खाद्यान्न के कुल 176.0 मिलियन टन का लगभग उत्पादन का अनुमान लगाया गया जो 1989-90 में हुए 170.6 मिलियन टन के सर्वाधिक उत्पादन से 3.3 प्रतिशत अधिक है तथा आलोच्य वर्ष के लिए निर्धारित 176.5 मिलियन टन के लक्ष्य के भी अनुरूप है। खरीफ के खाद्यान्नों का 100.4 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है जो 1989-90 में हुए 100.9 मिलियन टन उत्पादन से थोड़ा कम था। रबी का उत्पादन 75.9 मिलियन टन होने का अनुमान है जो 1989-90 में हुए 69.7 मिलियन टन के उक्त उत्पादन से काफी अधिक है। मिट्टी में अच्छी नमी और जलाशयों में पर्याप्त जल-स्तर के कारण उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा पिछले वर्ष रबी के उत्पादन में हुई कमी को पूरा किया जा सका। अलग-अलग फसल की दृष्टि से गेहूं की फसल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; इसके कारण है अधिक भूमि पर गेहूं की फसल उगाना तथा उत्पादकता में सुधार लाना (सारणी 3.1)।

सारणी 3.1 : खाद्यान्नों का उत्पादन

(मिलियन टन)														
	सर्वा खाद्यान्न	आवल	गेहूं	मोटे अनाज	दालें	जूट	खरीफ				रबी			
							चावल	मोटे अनाज	दालें	जूट	आवल	गेहूं	मोटे अनाज	दाल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1988-89	169.9	70.5	54.1	31.5	13.8	95.6	63.4	26.6	5.6	74.3	7.1	54.1	4.9	8.2
1989-90	170.6	74.0	49.7	34.3	12.6	100.9	66.3	29.2	5.4	69.7	7.7	49.7	5.1	7.2
1990-91 (संभावित उपलब्धि)	176.0	75.0	54.0	33.4	14.2	100.8	67.1	28.0	5.7	76.4	7.9	54.6	5.4	8.5

स्रोत : कृषि मंत्रालय।

3.4 खाद्यान्न सुरक्षा तथा पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की दृष्टि से 1990-91 के दौरान दालों के समग्र उत्पादन में हुई और अधिक वृद्धि उल्लेखनीय है तथापि, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अब भी काफी मात्रा में आयात की आवश्यकता है। राष्ट्रीय वलहन विकास कार्यक्रम तथा विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, जिनमें चना और अरहर जैसी दालों को शामिल किया गया था, के कार्यान्वयन से 1990-91 में इन दालों का उत्पादन काफी बढ़कर 14.0 मिलियन टन हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 12.6 मिलियन टन था, तथापि 1990-91 में उत्पादन का स्तर

इस वर्ष के लिए निर्धारित 15 मिलियन टन के लक्ष्य से कम रहा।

खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक

3.5 राजकोषीय वर्ष 1990-91 के दौरान बेहतर फसल होने तथा सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्यों में काफी वृद्धि के अनुरूप ही सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक अथवा 23.8 मिलियन टन खाद्यान्नों (चावल और गेहूं) की खरीद की गयी जबकि पिछले वर्ष 20.2 मिलियन टन खाद्यान्नों की खरीद की गयी थी (सारणी 3.2)।

सारणी 3.2 : पण्यों की सरकारी खरीद, निकासी और स्टॉक

(मिलियन टन)

राजकोषीय वर्ष अवधि	सरकारी खरीद			निकासी			स्टॉक*		
	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़	चावल	गेहूं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1988-89	7.6	6.5	14.1	9.1	8.7	18.0	4.7	2.7	7.4
1989-90	11.2	9.2	20.2	8.4	7.3	15.8	7.9	3.6	11.7
1990-91	12.7	11.1	23.8	8.3	8.3	16.7	11.2	5.8	17.3
पहली तिमाही (अप्रैल-जून)									
1990	1.4	10.9	12.3	2.0	1.4	3.4	6.9	13.2	20.3
1991	1.3	7.7	9.0	2.4	2.1	4.5	9.9	11.0	21.1

अनंतिम

\* ये स्टॉक राजकोषीय वर्ष की अवधि के लिए मार्च के अंत के हैं तथा प्रथम तिमाही की अवधि के लिए जून के अंत के हैं।

(@) मोटे अनाज शामिल हैं

3.6 यद्यपि 1990-91 में गेहूं की भरपूर फसल हुई है, तथापि 1981-82 के चालू विपणन मौसम (अप्रैल-मार्च) के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रही। जून 1991 के अन्त तक गेहूं की कुल खरीद 1990-91 की तदनुसूची अवधि के 10.9 मिलियन टन और पूरे रबी 1990-91 विपणन मौसम के कुल 11.1 मिलियन टन की तुलना में 7.7 मिलियन टन रही। मौसम के बीच में किसानों की खरीद-मूल्य में वृद्धि की आशा होना, परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां और प्रमुख वसूली क्षेत्रों में समग्र अनिश्चितता एवं व्यापारियों द्वारा स्पर्धात्मक खरीद, गेहूं की अपेक्षाकृत कम खरीद के कारण हैं।

3.7 खाद्यान्नों की निकासी 1989-90 के 15.8 मिलियन टन से बढ़कर 1990-91 में 16.7 मिलियन टन हुई जो कि अधिकतर भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुले बाजार में उच्चतर बिक्री के कारण थी। निकासी में अपेक्षाकृत अल्पतर वृद्धि के बावजूद अधिक वसूली होने

के परिणामस्वरूप मार्च 1991 की समाप्ति पर 17.3 मिलियन टन के उच्चतर स्तर पर खाद्यान्न स्टॉक रहा जो एक वर्ष पूर्व के 11.7 मिलियन टन के स्तर से उल्लेखनीय रूप में अधिक था।

3.8 वाणिज्य फसलों में गन्ना तथा पटसन और मेस्ता के उत्पादन में क्रमशः 1989-90 के 222.6 मिलियन टन से 1990-91 में 234.7 मिलियन टन तक एवं 82.9 लाख गांठों से 91.0 लाख गांठों तक की वृद्धि परिलक्षित हुई। परिणामस्वरूप, जून 1991 की समाप्ति पर चीनी का स्टॉक एक वर्ष पहले के 47.37 लाख टन की तुलना में 60.96 लाख टन पर काफी अधिक था। इन फसलों के निष्पादन में मौसम की सुधरी हुई स्थितियों का योगदान रहा। लम्बे समय तक और बेमौसम वर्षा एवं कीटों के हमलों से कारण भी कपास की फसल को क्षति पहुंची जिससे पिछले वर्ष की भरी-पूरी फसल की 114.1 लाख गांठों से 1990-91 में अनुमानित 100.0 लाख गांठों तक गिरावट आयी। 21 जून, 1991 को कपास परामर्शदाता

बोर्ड (सी ए बी) द्वारा किये गये अनुमान के अनुसार इसके परिणामस्वरूप 1990-91 कपास मौसम (सितम्बर-अगस्त) की समाप्ति पर कपास के स्टॉकों में पिछले कपास-मौसम (1989-90) की समाप्ति पर 30.79 लाख गांठों की स्थिति की तुलना में 17.29 लाख गांठों तक कमी रहेगी। तिलहनों में, मूंगफली का खरीफ 1990 का उत्पादन इस पैदावार के प्रमुख क्षेत्र गुजरात और तमिलनाडु में अपर्याप्त वर्षा के कारण कुछ कम हुआ। फिर भी, तोरिया/सरसों और सोयाबीन का प्रचुर रबी उत्पादन इसकी क्षतिपूर्ति से भी अधिक था। 1990-91 के दौरान तिलहनों का कुल उत्पादन 19.2 मिलियन टन की नई उंचाई पर रहा जो पिछले वर्ष में प्राप्त 16.8 मिलियन टन के उत्पादन से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

#### 4. औद्योगिक उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

4.1 वर्ष 1990-91 के दौरान समग्र औद्योगिक कार्य-शीलता काफी उत्पादजनक रही। इसका मुख्य कारण विनि-

र्माण क्षेत्र की बेहतर कार्यशीलता था। पिछले वर्ष यह क्षेत्र कुछ कम सक्रिय रहा। खनन और उत्खनन से अपेक्षाकृत कम वृद्धि परिलक्षित हुई। इसका कारण था। कोयले का कम उत्पादन और पेट्रोलियम कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट। बिजली के उत्पादन में 1989-90 के दौरान काफी तेजी से वृद्धि हुई थी, जबकि 1990-91 में इसमें कुछ गिरावट आयी, क्योंकि तापीय संपन्न में बिजली का उत्पादन कम हुआ। 1991 की राजकोपीय अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सामान्य सूचकांक (आधार : 1980-81-100) में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में 8.6 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी थी (सारणी 4.1) आलोच्य वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गयी, हालांकि यह कम थी। पिछले वर्ष के उत्तरार्ध में औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति जारी रहने के साथ-साथ औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में 1990-91 के उत्तरार्ध में गिरावट की प्रवृत्ति पायी गयी।

सारणी 4.1 : औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ  
(आधार: 1980-81-100)

वर्ष/भारत क्षेत्र	खनन और उत्खनन		विनिर्माण		बिजली		सामान्य सूचकांक	
	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सूचकांक	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1986-87	177.9	+6.2	149.7	+9.3	168.1	+10.3	155.1	+9.1
1987-88	184.6	+3.8	161.5	+7.9	181.0	+7.7	166.4	+7.3
1988-89	199.1	+7.9	175.6	+8.7	198.2	+9.5	180.9	+8.7
1989-90	211.6	+6.3	190.7	+8.6	219.7	+10.8	196.4	+8.6
1990-91	219.1	+3.5	208.2	+9.2	238.6	+8.6	212.9	+8.4

#### प्रमुख समूह

4.2 जहाँ विनिर्माण उत्पादन की वृद्धि दर में 1980 के 8.6 प्रतिशत से 1990-91 में 9.2 प्रतिशत की तीव्र बढ़ोतरी परिलक्षित हुई, वहीं खनन (3.5 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष में 6.3 प्रतिशत रही) तथा कुछ सीमा तक बिजली में भी (8.6 प्रतिशत की जबकि पिछले वर्ष में 10.8 प्रतिशत रही) वृद्धि की गति सुस्पष्ट रूप से धीमी रही।

#### विनिर्माण क्षेत्र

4.3 1990-91 में औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में तीव्र वृद्धि इस प्रकार पूर्णतः विनिर्माण क्षेत्र द्वारा हुई थी। औद्योगिक उत्पादन में योगदान सात उप-समूह अर्थात् बिजली की मशीनों का विनिर्माण, खाद्य-पदार्थ, सूती वस्त्र, लकड़ी के उत्पाद, कागज तथा कागज के बोर्ड, मशीनें तथा मशीनी औजार और मूल धातु तथा मिश्रधातु के उत्पादों का रहा। 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान उनकी वृद्धि दर का विस्तार 9.0 प्रतिशत से 22.7 प्रतिशत तक था जबकि

पिछले वर्ष में यह विस्तार (-) 0.8 प्रतिशत से 31.8 प्रतिशत तक रहा। इसके अतिरिक्त आंकड़ों से यह भी परिलक्षित होता है कि विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि प्रभावोत्पादक ही नहीं बल्कि उसका व्यापक आधार भी है। 17 प्रमुख समूहों में से कम से कम 14 समूहों का भार बिन्दु था अर्थात् इनमें 71.4 प्रतिशत सकारात्मक वृद्धि हुई, पिछले वर्ष में 15 समूहों में सकारात्मक वृद्धि हुई थी; किन्तु इनका 65.3 प्रतिशत बिन्दुओं तक ही था। 1990-91 के दौरान केवल 3 समूहों के उत्पादन में अर्थात् वस्त्र उत्पाद, रबर, प्लास्टिक, पेट्रोलियम तथा कोयला उत्पाद और 5.7 प्रतिशत बिन्दुओं की भारिता के साथ अन्य विनिर्माण उद्योगों में पूर्णतः गिरावट दर्ज की गयी।

#### उपयोग-आधारित वर्गीकरण

4.4 155 चुने हुए उद्योगों के सन्ध में 1990-91 के दौरान की अवधि के दौरान उपलब्ध आंकड़ों से, जिसका

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल भारांक 85.5 प्रतिशत है, यह परिलक्षित होता है कि 92 उद्योगों में 68.7 प्रतिशत भारांक के साथ सकारात्मक वृद्धि दरें प्राप्त हुईं, उक्त अवधि के दौरान इन उद्योगों में से 35 उद्योगों ने लगभग 15.9 प्रतिशत भारांक के साथ 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शायी। पिछले वर्ष 4.7 उद्योगों ने 21.4 प्रतिशत भारांक के साथ 10.0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्शायी थी।

4.5 उपर्युक्त 155 उद्योगों की रिपोर्ट में आंकड़ों के उपयोग आधार पर वर्गीकरण में पूंजीगत माल उद्योग और उपभोक्ता टिकाऊ माल उद्योग में 1990-91 के दौरान लगातार उन्नति होती रही (सारणी 4.2)। पूंजीगत माल क्षेत्र में ही अपने उपयोगकर्ता उद्योगों के कार्य निष्पादन में सुधार के आधार पर चीनी और कागज मिल मशीनरी में क्रमशः 32.7 प्रतिशत एवं 114.2 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इसी प्रकार, अन्य कारणों के अतिरिक्त, भवन निर्माण के कामकाज में तेजी के कारण लिफ्ट एवं फ्रेम में क्रमशः 60.5 प्रतिशत एवं 20.1 प्रतिशत की बहुत देखी गई। पिछले वर्ष की 14 प्रतिशत की वृद्धि के अतिरिक्त कृषि ट्रैक्टर में 14.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कृषि उत्पादन की उर्ध्वमुखी प्रगति का लगातार तीमरा वर्ष है। बिजली उद्योग में सामान्य विस्तार के साथ-साथ, बिजलीग कंप्लेक्सों और उत्पादन इकाइयों द्वारा कैप्टिव पावर जनरेटरों के लगाये जाने की प्रवृत्ति से, बिजली जनरेटर, बिजली की मोटरें और वाईडिंग तार और विद्युत

संधारित्र (केपेसीटर) आदि विभिन्न बिजली के उपकरणों में तेजी से वृद्धि हुई (वर्ष 1990-91 के दौरान यह वृद्धि दर 15 प्रतिशत से 34 प्रतिशत के बीच रही) इसी प्रकार में आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए कम्प्यूटरीकरण से पिछले दो वर्षों के दौरान कम्प्यूटर प्रणाली और उसके सहायक उपकरणों में 35 प्रतिशत की सतत उच्च वृद्धि हुई। दो वर्षों की मंदी के बाद सड़क यातायात गतिविधियों में सुधार के कारण व्यवसायिक वाहनों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। उपभोक्ता टिकाऊ, वस्तुओं में, बिजली के पंखे (12.4 प्रतिशत), और दो पहिया व त्रिपहिया वाहनों (6.4 प्रतिशत), कनाई घड़ी (19.4 प्रतिशत), टेलीफोन उपकरण (26.9 प्रतिशत) के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में वृद्धि में कमी (5.2 प्रतिशत) स्थिर रही। मध्यवर्ती वस्तु उद्योग में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि सामान्य रही, तथापि पिछले वर्ष (4.3 प्रतिशत) की तुलना में यह अधिक ही रही। इस श्रेणी में जिन उद्योगों ने उच्च वृद्धि का योगदान दिया वे हैं, सूती धागे, जूट के उत्पादन और मानव निर्मित रेशों की कुछ मर्दें। आधारभूत उद्योगों का कार्य निष्पादन पिछले वर्ष (5.2 प्रतिशत के मुकाबले 4.3 प्रतिशत) की तुलना में निराशाजनक रहा। यह कमी खनन और उत्खनन क्षेत्र में कम उत्पादन गतिविधियों, कोयला और पेट्रोलियम कच्चा तेल का निराशाजनक उत्पादन और बिजली बनाने में कमी आदि के कारण रही।

सारणी 4.2: औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर-उपयोग-आधारित वर्गीकरण

उद्योग समूह	भारांक	सभी उद्योगों			चुने हुए 155 उद्योग*		
		आर्थिक भोक्त प्रतशत वृद्धि					
		1981-82 से 1984-84	1985-86 से 1989-90	उद्योगों की संख्या	भारांक	निम्नलिखित के प्रतिशत परिवर्तन 1989-90	दौरान 1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8
1. मूल वस्तुएं	39.42	+ 8.8	+ 7.4	40	38.36	+ 5.2	+ 4.3
2. पूंजीगत वस्तुएं	16.42	+ 6.3	+ 14.8	32	11.32	+ 29.1	+ 21.9
3. मध्यवर्ती वस्तुएं	20.51	+ 6.1	+ 6.5	36	16.10	+ 4.3	+ 5.6
4. उपभोक्ता वस्तुएं	23.65	+ 5.3	+ 7.3	47	21.76	+ 5.2	+ 6.1
5. (क) टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	2.55	+ 14.4	+ 11.8	12	2.20	+ 2.0	+ 10.9
(ख) गैर-टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं	21.10	+ 4.0	+ 6.5	35	19.56	+ 5.8	+ 5.2
सामान्य सूचकांक	100.00	+ 7.0	+ 8.5	155	85.54	+ 9.2(%)	+ 8.5

\* उत्पादन के अंतिम आंकड़े जो 155 उद्योगों से संबंधित हैं तथा औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में जिनका भारांक 85.5 प्रतिशत है।

(%) पिछले वर्ष की तत्काल अवधि की तुलना में 155 उद्योगों के संबंध में सूचकांक परिवर्तन।

#### निविष्टि-आधारित वर्गीकरण

4.6 वर्ष 1990-91 के दौरान 155 चयनित उन्ही उद्योगों के निविष्टि-आधारित वर्गीकरण में कृषि आधारित उद्योगों में चीनी में तीव्र वृद्धि हुई (0.4 प्रतिशत ह्रास

के विरुद्ध 22.7 प्रतिशत)। यह वृद्धि गन्ने की प्रचुर मात्रा में उत्पादन के साथ-साथ गन्ने की विलम्बित और शीघ्र पेरई के लिए दिए गए प्रोत्साहन के कारण संभव हुई। सूती वस्त्रों के उत्पादन में 16.7 प्रतिशत की प्रभावी वृद्धि



हुई जबकि इसकी तुलना में 1989-90 में 4.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई थी। इस वृद्धि का कारण था लगातार दूसरे वर्ष भी कच्चा की बेहतर आपूर्ति। इस समूह के अंतर्गत विविध क्षेत्रों में उत्पादित वस्त्रों के उत्पादन में वर्ष 1990-91 में 33.5 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि मिल क्षेत्र के उत्पादन में 2.2 प्रतिशत की गिरावट आयी, यह गिरावट 1989-90 में आयी 5.7 प्रतिशत तथा 1988-89 के 7.2 प्रतिशत की गिरावट के अलावा है। पटसन की बेहतर उपलब्धता एवं अधिक निर्यात मांग के साथ पटसन के उत्पादन में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि वर्ष 1989-90 (अप्रैल-मार्च) में इसमें 6.5 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। वनस्पति उत्पादन में वर्ष 1989-90 में 5.7 प्रतिशत की गिरावट आयी तथा वर्ष 1990-91 में उसमें 12.2 प्रतिशत की और गिरावट आयी। चाय के उत्पादन में वर्ष 1990-91 में 1.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष की वृद्धि दर की तुलना में 3.5 प्रतिशत है, इसका कारण चाय के उत्पादक क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियाँ थी। रसायन आधारित उद्योगों में नाइट्रोजनी उर्वरक एवं फास्फेटिक उर्वरक दोनों में वृद्धि हुई; वर्ष 1990-91 में फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके ठीक विपरीत पिछले वर्ष इसमें 20.3 प्रतिशत की गिरावट आयी थी और इस वृद्धि का कारण आयातित फास्फेटिक अम्ल (एसिड) की अच्छी उपलब्धता है। अधिकतर कृत्रिम रेशे तथा धागे जैसे पी. वी.सी. रेजिम्स पोलिस्टीरीन, विस्कोस फिलामेंट धागे एवं नायलोन फिलामेंट धागे के उत्पादन में निरपेक्षतः गिरावट आयी जिसका कारण खाड़ी संकट था। इसने पेट्रो-रसायन के कच्चे माल की आपूर्ति तथा उनके मूल्यों के साथ-साथ निर्यात बाजार को भी प्रभावित किया। इस समूह में अपवाद है-नायलॉन टायर कोर्ड, पोलियेस्टर रेशे तथा पोलियेस्टर फिलामेंट धागे, जिनकी वृद्धि 3.7 प्रतिशत से 30.1 प्रतिशत के दरम्यान थी क्योंकि इन उद्योगों के लिए आधारभूत निवेश के प्रोजेक्ट्स देश में ही उपलब्ध हैं।

4.7 धातु आधारित उद्योगों के समूह में स्वचालित वाहन (ऑटोमोबाइल) के उत्पादन में भिन्न प्रवृत्तियाँ दिखायी दीं। वाणिज्यिक वाहनों, जिनके उत्पादन में 1990-91 के दौरान 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, के अलावा निम्न-लिखित में उल्लेखनीय वृद्धि पायी गयी: मोटर साइकिल (11.0 प्रतिशत), स्कूटर तथा मोपेड (4.9 प्रतिशत)।

और ऑटोमोबाइल (4.9 प्रतिशत) रेल के माल डिब्बों के उत्पादन में भी 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी तरफ वर्ष 1990-91 में यान्त्रीय कार एवं जीप के उत्पादन में गत वर्ष क्रमशः 12.8 प्रतिशत और 21.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1.1 प्रतिशत एवं 16.0 प्रतिशत की गिरावट आयी। इस गिरावट का कारण बिक्री मूल्यों में आवधिक वृद्धि और ईंधन के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण मांग में कमी थी।

#### आधारभूत उद्योग

4.8 जैसा कि ऊपर कहा गया आधारभूत उद्योगों का कार्य निष्पादन पिछले वर्ष जैसी ही उल्लेखनीय रूप से कम रहा। छह मूलभूत उद्योगों के औसत मसिख सूचकांक (औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचकांक में 28.77 प्रतिशत के वजन के लिए की गयी गणना सहित) में 1990-91 में 4.8 प्रतिशत की अल्प वृद्धि परिलक्षित हुई जबकि इसकी तुलना में यह 1989-90 में 6.2 प्रतिशत तथा 1988-89 में 8.2 प्रतिशत थी। जबकि छह मूलभूत उद्योगों में से चार अर्थात् बिजली, कोयला, बिक्रीयोग्य इस्पात तथा सीमेंट के वास्तविक उत्पादन में 1990-91 के दौरान सुधार हुआ, किन्तु सभी उद्योगों के उत्पादन में उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों में गिरावट आयी थी,। गुजरात, असम और दक्षिणी क्षेत्र में स्थित अनेक स्थानों पर विभिन्न समस्याओं के साथ-साथ विभिन्न निष्क्रिय कुओं, सम्पूर्ण या परीक्षण उपकरणों जैसी नाजुक निष्पिण्डियों नल-तल, दलाई की अनुपलब्धता के कारण कच्चे तेल का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में (34.1 मिलियन टन की तुलना में 33.1 मिलियन टन) 3.1 प्रतिशत कम था तथा पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद 0.3 प्रतिशत कम (48.3 मिलियन टन की तुलना में 48.2 मिलियन टन) था। बिजली उत्पादन में 1989-90 में 10.9 प्रतिशत की तुलना में 7.8 प्रतिशत की अल्प वृद्धि थर्मल यूनिटों में काफी कम कार्य होने के कारण थी जो कोयले की समुचित मात्रा में आपूर्ति न होने के कारण तथा साथ ही बढ़ी हुई हाइड्रो जनरेशन (15.3 प्रतिशत) के परिणामस्वरूप थर्मल स्टेशनों की कम क्षमता होने के कारण थी। बिक्री योग्य इस्पात तथा सीमेंट का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 1990-91 के दौरान अधिक था (सारणी 4.3)।

सारणी 4.3 : आधारभूत संरचना वाले उद्योगों के उत्पादन की प्रवृत्तियाँ

उद्योग	भारतक	इकाई	अप्रैल-मार्च			राज्यीय योजना	
			1988-89	1989-90	1990-91	योजना लक्ष्य*	सूचकांक (1980 S1 = 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
बिजली	11.43	बिलियन इकाई	221.14	245.14	264.15	280.00	251.0
			(+9.5)	(+10.9)	(+7.8)		

1	2	3	4	5	6	7	8
2. कोयला (लिंगाइट को छोड़कर)	6.61	मिलियन टन	194.71 (+ 8.3)	200.89 (+ 3.2)	211.73 (+ 5.4)	226.00	198.2
3. बिजली योग्य इस्पात	5.21	"	9.21 (+ 7.2)	9.03 (— 2.0)	9.31 (+ 3.1)	12.64	201.2
4. सीमेंट	1.60	"	44.28 (+ 12.0)	45.78 (+ 3.4)	48.70 (+ 6.4)	49.00	262.6
5. पेट्रोलियम अपरिष्कृत	2.41	"	32.04 (+ 5.5)	34.08 (+ 6.4)	33.03 (+ 3.1)	34.53	330.0
6. पेट्रोलियम रिफाइनरी के उत्पाद	1.52	"	45.38 (+ 2.2)	48.30 (+ 6.4)	48.15 (+ 0.3)	45.57	188.5
आधारभूत संरचना उत्पादन का संयुक्त सूचकांक (आधार: 1980-81 = 100)	28.77		193.2 (+ 8.2)	205.2 (+ 6.2)	215.0 (+ 4.8)		233.8

टिप्पणी. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना की तुलना में प्रतिशत में षट् बर्ष दर्शाते हैं।

(ii) ये सातवीं पञ्चवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में प्राप्त करने के लिए निर्धारित मूल लक्ष्य हैं।

\* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित सूचकांक।

### औद्योगिक नीति प्रयास

4.9 भारत सरकार की औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को संसद में की गई थी इस नीति में औद्योगिक लाइसेंसिकरण, सीधा विदेशी निवेश, विदेशों के साथ औद्योगिकी करार, सरकारी क्षेत्र नीति और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम (एम. आर. टी. पी.) के सम्बंध में औद्योगिक नीति संबंधी पहल की गयी है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। यह नीति व्यापार, विनियमन, दर, प्रबंधन, राजकोषीय नीति और अन्य स्थूल और क्षेत्रीय मुद्दों के क्षेत्र में पहले से किये गये संरचनात्मक मुद्दों की पूरक नीति है। इस नीति का उद्देश्य है उसीकरण, ताकि इसके माध्यम से उद्यमी अपनी ही वाणिज्यिक सूक्ष्मता के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय ले सकें। उद्योगों के निवेश के आकार पर विचार किये बिना सभी उद्योगों के संबंध में औद्योगिक लाइसेंसिकरण की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो उद्योग, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठान, सामाजिक प्रयोजनों, खतरनाक रसायन और पर्यावरण संबंधी मामलों से सम्बन्धित हैं, वे और जो मर्दों धनी वर्ग हस्तेमाल करता है उन मर्दों से सम्बन्धित 18 उद्योग इस उदारीकरण में शामिल नहीं हैं। जो उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित है वे उस क्षेत्र के लिए आरक्षित रहेंगे। कतिपय नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं से किये जाने वाले मीयादी ऋणों पर बाध्यकारी परिवर्तन खंड लागू नहीं होगा। दूसरा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को इस तरह संशोधित किया जायेगा कि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के लिए परिसम्पत्तियों की न्यूनतम सीमा हटाया जा सके और उन्हें नये उपक्रमों के लिए तथा

विस्तार समायोजन, विलयन और वर्तमान उपक्रमों के स्वामित्व अंतरण के लिए पूर्वानुमोदन की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके। यह नीति एकाधिकारी, प्रतिबंधात्मक और अवैध व्यापार सम्बन्धी व्यवहारों को नियंत्रित करने और उन्हें विनियमित करने पर अधिक बल देती है। तीसरा, जहां तक सरकारी क्षेत्र का प्रश्न है यह क्षेत्र भविष्य में अपना ध्यान सामरिक, उच्च औद्योगिक और आवश्यक आधारभूत संरचना उद्योगों पर केन्द्रित करेगा इससे अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए जो 10 उद्योग आरक्षित थे वे अब निजी निवेश के लिए खुले रहेंगे। सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम लम्बी खण्णता के शिकार हो जाते हैं उन्हें अर्थक्षम कार्यक्षम बनाने की योजनाओं को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को या इस प्रयोजन के लिए बनायी गयी ऐसी ही उच्च स्तरीय संस्थाओं को सौंपा जायेगा। खण्ण उद्योगों को कार्यक्षम बनाने की योजनाओं से प्रभावित होने वाले कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था बनायी जायेगी, चौथा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में उपयुक्त संशोधन किया जायेगा ताकि यदि विदेशी ईक्विटी आयातित पूंजीगत माल के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा के बराबर या इससे अधिक होती है तो 34 उच्च प्राथमिकता प्राप्त औद्योगिक श्रेणियों में सीधे विदेशी निवेश के लिए अपने आप अनुमोदन प्राप्त हो जायेगा यह जरूरी नहीं होगा कि विदेशी ईक्विटी प्रस्तावों के साथ विदेशी औद्योगिकी करार अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जायें। विशेष कार्यक्रम के माध्यम से अधिक संख्या में निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त बोर्ड का गठन किया जायेगा। इस बोर्ड का उद्देश्य बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बातचीत करना और चुने हुए क्षेत्रों में सीधे विदेशी निवेश का अनुमोदन करना है। ऐसे कार्यक्रम उच्च

प्रौद्योगिकी और विश्व बाजार में पहुंचने के लिए मार्ग तैयार करेंगे। अंत में, उपयुक्त 34 उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की श्रेणी के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी करार करने के लिए सीधे अनुमति दी जायेगी। ऐसे करारों की एकमुश्त अदायगी राशि एक करोड़ रुपये की होगी उसमें घरेलू विप्रेषण के लिए 5 प्रतिशत रायल्टी होगी और 8 प्रतिशत निर्यात के लिए होगी। यह 10 वर्ष की अवधि के दौरान हुई विप्रेषण के 8 प्रतिशत की कुल अदायगी के अधीन होगी।

4.10 6 अगस्त 1991 को जारी किए गए नये लघु उद्योग नीति विवरण में भारत सरकार ने इस क्षेत्र को और अधिक क्षमतावान और इसकी वृद्धि में तेजी प्रदान करने का विचार किया है। नई नीति में लघु उद्योग क्षेत्र के भीतर ही "अति लघु" उद्यमों के संवर्धन और पोषण करने पर अधिक ध्यान दिया गया है। उस नीति के प्रमुख तत्व हैं: "अति लघु" उद्यमों के लिए निवेश सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना, आसान संस्थागत ऋण सरकारी खरीद में प्राथमिकता और श्रम कानूनों के कुछ प्रावधानों में छूट जैसे विशेष लाभों को "अति लघु" उद्यमों तक ही सीमित करना, जबकि अन्य छोटी इकाईयों को भूमि आबंटन, विद्युत कनेक्शन और कार्य कुशलता/प्रौद्योगिकी कोटि उपभोग जैसे एक बार दिये जाने वाले कुछ लाभ मिलेंगे। वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से मिश्रित ऋण प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय ईक्विटी फंड और सिंगल विंडो ऋण स्कीम का दायरा व्यापक करना, आर्थिक सहायता प्राप्त/मस्ते ऋण की बजाए ऋण के पर्याप्त प्रवाह और इसके वितरण की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना जिसका सुनिश्चयन विशेष मानिटैरिंग एजेंसी करेगी, लघु प्रौद्योगिक इकाईयों में अन्य प्रौद्योगिक उपक्रमों द्वारा ईक्विटी में सहभागिता की अनुमति देना (24 प्रतिशत तक) ताकि सहायक उद्योग तथा उप संविदा को बढ़ावा मिल सके: लघु उद्योग क्षेत्र को जोखिम पूंजी की पूर्ति बढ़ाने के लिए सीमित साझेदारी अधिनियम लागू करना और कुछ उद्योगों के बिलों के शीघ्र भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून बनाना।

#### 5. मुद्रा नीति संबंधी गतिविधियां

व्यापक नीतिगत जोर

5.1 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में सूचित किया गया है, वर्ष 1990-91 के लिए मुद्रा और ऋण नीति बताते समय सर्वोपरि आवश्यकता इस बात की थी कि वर्ष 1989-90 में चलनिधि के काफी अधिक बढ़ जाने और मुद्रास्फीति के पुनः उभर जाने के परिप्रेक्ष्य में मुद्रास्फीति गत प्रत्याशाओं में तीव्र कमी लायी जाए। अन्य बातों के साथ-साथ, समय मुद्रा विस्तार की गति में तीव्र कमी लाने का प्रयास कर इस लक्ष्य की पूर्ति की जानी थी। मुद्रा प्रवन्ध के इस लक्ष्य का समग्र बजटीय घाटे में उल्लेखनीय कमी लाने के राजकोषीय उद्देश्य द्वारा भी समर्थन किया गया। परंतु देशी और विदेशी दोनों संदर्भों में, घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ के कारण

समष्टि आर्थिक असंतुलन की स्थिति और बिगड़ गयी। अन्धल क्षेत्रों, विशेष कर कृषि क्षेत्र के लगानार तीसरे वर्ष के लिए काफी संतोषजनक कार्य निष्पादन के बावजूद मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं में कोई कमी नहीं आई और 1990-91 के दौरान वे और भी खराब होती गई। बजट घाटे में तथा मुद्रीकृत घाटे में कटौती करने के स्वीकृत लक्ष्य की पूर्ति नहीं की जा सकी। विशेष कर, अगस्त 1990 में प्रारंभ हुए खाड़ी संकट के बाद नेजी में बिगड़ती विदेशी भुगतान की स्थिति के फलस्वरूप प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में भारी कमी आयी। वर्ष 1991-92 के लिए नियमित केन्द्रीय बजट के तथा पुनः समष्टि आर्थिक स्थापित करने के लिए मध्यवर्धि स्थिरीकरण कार्यक्रम के अभाव में, विशेषकर फरवरी, 1991 में अल्पावधि आर्थिक प्रवन्ध की लगभग पूरी जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की मुद्रा और ऋण नीति पर आ पड़ी।

5.2 हाल ही की अवधि में समय मांग के और खासकर आयातों के लिए मांग को रोकने के लक्ष्य के साथ किये गये उपाय मुद्रा और ऋण नीति के प्रमुख तत्व रहे हैं। तेजी से घटती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में ऋण और मुद्रा नीति के उपायों को प्रगामी रूप में कठोर बना दिया गया और अंततः उनकी परिणति के रूप में खुले मामान्य लाइसेंस के अंतर्गत किये जाने वाले वस्तुओं के आयातों पर काफी अधिक अर्थात् 200 प्रतिशत का तथा विशिष्ट लाइसेंस के अंतर्गत 150 प्रतिशत का नकदी मार्जिन लागू किया गया, (इन उपायों का क्रमबद्ध विवरण इस रिपोर्ट के भाग-11 में दिया गया है)। कुल मांग प्रवन्धन के अंश के रूप में जमा और उधार दरों में बढ़ोतरी की गयी। वृद्धिशील प्रारक्षित अनुपात को लागू किया गया, निर्यात वित्तपोषण पर व्याज दर अधिभार लगाया गया और बड़ी ऋण सीमाओं वाले ऋणकर्तव्यों द्वारा किये जाने वाले आह्वानों पर प्रतिबंध लगाया गया। इस प्रतिबंधात्मक नीति की पद्धति में निर्यात ऋण को वित्तियमों की मज्दती से छूट देने के प्रावधान किये गये थे। कतिपय परिपक्वता अवधि के बाद के निर्यात ऋणों में बढ़ोतरी की गयी ताकि निर्यात आगमों की शीघ्र वसूली की जा सके। निर्यात को प्रदान किये जाने वाले बैंक वित्त को दी गयी प्राथमिकता के कारण रिजर्व बैंक की निर्यात पुनर्वित्त सुविधा में छूट दी गयी तथा वर्ष में निर्यात पुनर्वित्त सुविधा में छूट दी गयी तथा वर्ष 1991-92 में बनाये रखे जाने वाले वृद्धिशील खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात में संबंधित शर्त निर्यात ऋणों पर लागू नहीं की गयी। इसके अलावा तीव्र विदेशी भुगतान असंतुलन में तेजी से सुधार लाने के उद्देश्य से रुपये के विनिमय दर में किये गये ममायोजन तथा व्यापार नीति में किये गये महत्वपूर्ण संशोधन के अनुरूप, 4 जुलाई 1991 को मुद्रागत उपायों को पुनः लागू किया गया और 10 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद बैंक दर को संशोधित कर बढ़ाया गया, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमा दरों में सभी स्तरों पर वृद्धि की गयी, 2 लाख रुपये में अधिक की ऋण सीमाओं के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की न्यूनतम व्याज दर में तीव्र वृद्धि की गयी और रिजर्व बैंक से उपलब्ध विभिन्न पुनर्वित्त सुविधाओं में संबंधित व्याज दरों में बढ़ोतरी की गयी। सरकार के इस निर्णय के

साथ कि सपूण की वित्तमय दर में समायोजन किए जाने के परिणामस्वरूप निर्यात के लिए आर्थिक सहायता समाप्त की जाए, निर्यात ऋण की ब्याज दरें 6 अगस्त 1991 से बढ़ाई गई।

5.3 अल्पावधि ऋण प्रबंधन जहाँ अनिवार्यता: एक प्रमुख पूर्व निर्धारित कार्य रहा है, वहाँ ऋण वितरण प्रणाली में सुधार लाने, ऋण निर्वहन उपायों को लागू करने में लीचलापन लाने तथा मुद्रा बाजार में विन्यासात्मक परिवर्तन लाने के अपेक्षाकृत लंबे अवधि के लक्ष्यों पर भी यथोचित ध्यान दिया गया।

5.4 आलोच्य अवधि के दौरान किये गये ऋण नीति संबंधी महत्वपूर्ण उपायों के ब्यौरे निधि क्रमानुसार नीचे दिये गये हैं:

#### ब्याज दरों के विन्यास का युक्तिकरण

5.5 22 मिनस्वर 1990 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ब्याज दर विन्यास में मुख्य सुधार लाया गया। बैंकों के लिए निर्धारित किया गया ब्याज दर विन्यास एक लंबे अंतराल के बाद सम्मिश्र स्वरूप का बन गया था। इस विन्यास की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—ब्याज दरों में रियायत के साथ इन दरों की विविधता बहुविध मानदण्डों पर आधारित थी जैसे कि ऋण का आकार, क्षेत्र की प्राथमिकता का स्वरूप, कार्यकलाप का स्थान, विशिष्ट कार्यक्रम से संबंधित ऋण, ऋणकर्ताओं के आय के माधन आदि। इस प्रकार के दर विन्यास का संचालन करना कठिन बन गया था और उसको तर्कसंगत बनाना अत्यावश्यक हो गया था। तथापि, दर विन्यास के भीतर प्रति सहायता का तत्व लाना आवश्यक था क्योंकि सामाजिक हितों के लिए छोटे ऋणकर्ताओं तथा समाज के कमजोर वर्गों के संदर्भ में रियायत का तत्व जारी रखना आवश्यक है। इस पृष्ठभूमि में बैंकों के लिए पुनर्निर्धारित ब्याज दर संबंधी अपेक्षाओं को लागू किया गया। संशोधित दर विन्यास में, समस्त क्षेत्र के लिए लागू तथा विशिष्ट कार्यक्रम के लिए लागू, ब्याज दर संबंधी शर्तों को समाप्त कर दिया गया है, तथापि विभेदक ब्याज दर योजना और निर्यात ऋण इसके लिए अपवाद है। इस नये विन्यास में ब्याज दरों में रियायत के तत्व को ऋण के आकार के साथ सम्बद्ध करने में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि मूलभूत सामाजिक हितों का ध्यान रखा गया है और साथ ही दर विन्यास की बहुविधता और समिश्रता में उल्लेखनीय रूप से कमी लायी गयी है। इस संशोधित विन्यास में कार्यशील पूँजी और मीयादी ऋणों के बीच विद्यमान अंतर को भी समाप्त कर दिया गया है, तथापि कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों तक के स्वामी रहने वाले सड़क परिवहन चालकों को प्रदत्त 25,000/- रुपये से अधिक राशि के मीयादी ऋणों पर यह बात लागू नहीं होती। 2 लाख रुपये से अधिक राशि के ऋणों के लिए ब्याज दर निर्धारित करने का विवेकाधिकार जहाँ बैंकों को दिया गया, वहाँ उन्हें यह भी सूचित किया गया कि वे इस विवेकाधिकार का उपयोग तर्कसंगत ढंग से करें। सार्वजनिक

क्षेत्र की वसूली/वितरण एजेंसियों के मामले में नये ब्याज दर विन्यास में वर्तमान दरों की तुलना में वृद्धि अभिप्रेत थी। परंतु बैंकों को यह सूचित किया गया कि ऐसी एजेंसियों द्वारा (उधारों पर) वार्षिक 16.0 प्रतिशत की दर पर ब्याज लिया जाना तर्कसंगत रहेगा।

5.6 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए 22 मिनस्वर 1990 से लागू संशोधित ब्याज दर विन्यास (विभेदक ब्याज दर ऋणों तथा निर्यात ऋण के लिए लागू दरों को छोड़कर) को नीचे दर्शाया गया है:

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋणों के लिये 22 मिनस्वर 1990 से लागू ब्याज दर विन्यास

(विभेदक ब्याज दर ऋणों तथा निर्यात ऋण को छोड़कर)

ऋण-सीमा का आकार	ब्याज दर (वार्षिक प्रतिशत)
(क) 7,000 रुपये तक और उससे अधिक	10.0
(ख) 7,500/- रुपये से अधिक और 15,000/- रुपये तक	11.5
(ग) 15,000/- रुपये से अधिक और 25,000/- रुपये तक	12.0
(घ) 25,000 रुपये से अधिक और 50,000/- रुपये तक	14.0
(ङ) 50,000/- रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक	15.0
(च) 2 लाख रुपये से अधिक	16.0 (न्यूनतम)

5.7 ब्याज दरों के उपर्युक्त विन्यास को कार्यशील पूँजी और मीयादी ऋण दोनों के लिये लागू किया गया। कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों तक के स्वामी रहने वाले चालकों के मामलों में निम्नलिखित दरें निर्धारित की गयी।

ऋण सीमा का आकार	ब्याज दर (प्रतिशत)
(1) 25,000 रुपये से अधिक और 50,000/- रुपये तक	13.0
(2) 50,000/- रुपये से अधिक	14.00

5.8 22 मिनस्वर 1990 में 16.0 प्रतिशत (न्यूनतम) के वर्ग में आने वाले ऋणकर्ताओं के लिये बिलों की भुनाई से संबंधित प्रभावी ब्याज दर को इस वर्ग के ऋणकर्ताओं से ली जाने वाली उधार दर से 1 प्रतिशत अंक कम पर निर्धारित किया गया।

5.9 इस नये ब्याज दर विन्यास के प्रभाव का जहाँ तक संबंध है, 25,000 रुपये तक के अल्पावधि कृषि ऋणों के मामले में पुरानी रियायती दरों की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि 25,000- रुपये से अधिक

और 2 लाख रुपये तक के ऋणों के लिये ऋण की राशि के आधार पर ब्याज में कुछ कटौती की गयी है। लघु उद्योगों को प्रदत्त अल्पावधि ऋणों के मामले में, हालांकि दरें केवल ऋण के प्रकार से संबंधित रही हैं तथापि वे अधिकांश ऋणकर्ता के लिये पहले की दरों के मुकाबले वस्तुतः भिन्न नहीं रही हैं। जहां तक मीयादी ऋणों का संबंध है, नया ब्याज दर वित्याम, पिछले वित्याम के विपरीत मात्र ऋण प्रकार के साथ जोड़ दिया है, तथापि कृषि, लघु उद्योग और दो वाहनों तक के परिवहन वाहनों के लिये कतिपय प्रकार के मीयादी ऋणों के मामले में इस उद्देश्य के साथ 1 से 2 प्रतिशत तक के अंक से न्यूनतर दरें निर्धारित की गयी कि नयी दरों को उस समय प्रचलित दरों के यथासंभव निकट रखा जाए।

5.10 चूंकि उधार दर वित्याम को तर्कसंगत बनाये जाने का उद्देश्य अपेक्षाकृत कम ब्याज दरें दिये जाने के कारण कतिपय ऋणों के लिये मांग को प्रोत्साहन देना नहीं था, 10 अक्तूबर 1990 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे ऋणों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू ब्याज दरों का निर्बाध रूप से निर्धारित करें : (i) रिकार्ड उपभोक्ता वस्तुओं के ऋण के लिये ऋण; (ii) शेयरों और डिबेंचरों/बाण्डों पर अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण; और (iii) प्राथमिक क्षेत्रों के अन्य व्यक्तिगत ऋण।

बितीय वर्ष 1990-91 के उत्तरार्ध के लिये नीतिगत उपाय

5.11 वर्ष 1990-91 की दूसरी छमाही के लिये ऋण नीति 9 अक्तूबर 1990 को घोषित की गयी। यह ऋण नीति खाड़ी संकट, भुगतान संतुलन पर आप्र दबाव तथा तेजी में बढ़ते मुद्रास्फीतिकारी दबावों के परिप्रेक्ष्य में बनायी गयी थी। तीन क्रमिक वर्षों के लिये अच्छी कृषि पैदावार होने के बावजूद मूल्यों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी रही थी। यह महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय पैट्रोलियम मूल्यों में तीव्र वृद्धि होने के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबाव और भी बढ़ जायेगा। वर्ष 1990-91 के वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में धीमी गति मुद्रा विस्तार होने पर भी यह अनुभव किया गया कि प्रारंभित मुद्रा में तीव्र वृद्धि होने के फलस्वरूप वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रा विस्तार में तेजी आ सकती है। खाड़ी की स्थिति तथा भुगतान संतुलन पर आये परिणामी दबाव के संदर्भ में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे निर्यात क्षेत्र की ऋण संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिये हर संभव प्रयास करें। मीयादी ऋणदात्री संस्थाओं के पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिये उपलब्ध विदेशी मद्रागत ऋण सुविधाओं का उपयोग करने के महत्व पर बल दिया गया और बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे ऋण संबंधी ऐसी मांग को इन ऋण सुविधाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित किये जाने के लिये उक्त वित्तीय संस्थाओं को अंतरित

कर दें। (विस्तृत ब्यौरे के लिये इस रिपोर्ट का भाग II देखें)।

5.12 आलोच्य अवधि के दौरान किये गये मुख्य नीतिगत परिवर्तन निम्नलिखित हैं :—

(क) जमा दरें

5.13 10 अक्तूबर, 1990 से, तीन वर्ष और उभय अधिक की अवधियों की जमाराशियों की एक नयी श्रेणी आरंभ की गयी जिसके संदर्भ में वार्षिक 11.0 प्रतिशत की ब्याज दर लागू थी, इससे मीयादी जमाराशियों पर देय अधिकतम दर में एक प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हो गयी। इस उपाय का निश्चय ही यह अभिप्राय था कि अधिक नवी अवधि की मीयादी बैंक जमाराशियों के रूप में की जाने वाली बचतों पर बेहतर ब्याज दरें दी जा सकें तथा बैंकों के जमा संचयन के प्रयामों में सहायता की जा सके।

(ख) विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के लिये कामबंदी अवधि :

5.14 पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों और खाद्येतर ऋणों में मार्च 1990 के अंतिम आठ दिनों में भारी वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप कुल मुद्रा और बैंकिंग राशि की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सरकार की प्राप्तियां और सवितरण जैसे बैंकों के नियंत्रण से पूरे तत्व इसके लिये जहां अंशतः जिम्मेदार थे, यह स्पष्ट था कि एस तत्व वर्ष के अंत में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के लिये पूर्णतः उत्तरदायी नहीं थे। एक निवारक उपाय के रूप में, यह निश्चय किया गया कि रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के बिना 9 मार्च 1991 से 19 अप्रैल 1991 तक की तीन पखवाड़ों की अवधि के दौरान बैंकों को विवेकाधीन पुनर्वित्त का आहरण करने की अनुमति न दी जाये।

(ग) मांग मुद्रा बाजार में प्रवेश :

5.15 मुद्रा बाजार को और व्यापक बनाने तथा उसके विभिन्न क्षेत्रों में अधिक समन्वय लाने के उद्देश्य से बिल पुनर्भर्नाई बाजार के उन समस्त महभागियों को, जो मांग/सूचना मुद्रा बाजार में कार्यशील नहीं थे, 20 अक्तूबर, 1990 में श्रृणकर्ताओं के रूप में मांग/सूचना मुद्रा बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। तथापि मांग मुद्रा बाजार के संस्थागत महभागियों को मांग/सूचना मुद्रा बाजार में तब उधार देने की अनुमति नहीं दी गई जब उन्होंने रिजर्व बैंक से अल्पावधि ऋण लिये हों।

(घ) ऋण सीमाओं के अप्रयुक्त अंश पर वायदा प्रभार

5.16 ऋण सीमाओं के एक बड़े अप्रयुक्त अंश के कारण बैंकों द्वारा अनुभव की गई समस्याओं तथा स्थूल ऋण नीति के कार्यान्वयन में इस वजह से उत्पन्न होने वाले अनेकों प्रतिबंधों के परिप्रेक्ष्य में यह निश्चय किया गया कि कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के अप्रयुक्त अंश पर वायदा शुल्क लगाया

आए। तदनुसार, 1 जनवरी, 1991 से 1 करोड़ रुपये और उसमें अधिक राशि की कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं में वृद्ध गमन ऋणकर्ताओं के मामले में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गई कि वे निमाही कार्यशील सीमाओं के अप्रयुक्त अंश पर वार्षिक 1 प्रतिशत का न्यूनतम ब्याज प्रभार लागू करें तथापि वे उस संबंध में 1.5 प्रतिशत कर छूट स्तर रखें। यह आशय की गई कि यह उपाय ऋणकर्ताओं द्वारा लिये जाने वाले बैंक वित्त में अनुशासन लायेगा और बैंकों द्वारा निधियों का बेहतर द्य से प्रविवंध किया जा सकेगा।

(इ) देशी उधार बित्री का वित्तपोषण :

5.17 वित्त संस्कृति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य मार्च 1987 में यह संकेत दिया गया था कि 1 अप्रैल 1988 से किसी बैंक द्वारा उस समय के ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत आने वाले उधारकर्ताओं को बही ऋण पर मंजूर की जाने वाली ऋण सीमाएं ऐसे ऋणकर्ताओं को देशी उधार बित्री के लिए स्वीकृत कुल सीमाओं के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि इस शर्त को निर्धारित किये जाने के बावजूद काफी समय बीत चुका था यह निश्चय किया गया कि 5 करोड़ रुपये और उसमें अधिक की निधि आधारित कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के मामले में 1 जनवरी 1991 से बही ऋण वित्त के उस अंश पर संबंधित तकदी ऋण लागू दर से 2 प्रतिशत अंक अधिक का ब्याज लिया जाना चाहिए, जो देशी उधार बित्री के वित्तपोषण के लिए ऋणकर्ताओं को स्वीकृत सीमाओं के 75 प्रतिशत के निर्धारित मानदण्ड से अधिक हो।

(च) रिजर्व बैंक के पास बनाये रखे गये तकदी शेप पर प्रगामी ब्याज दर की संशोधित योजना :

5.18 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास बनाये रखे गये तकदी शेप के संबंध में, बैंकों के संतोषजनक अनुपालन को देखते हुए प्रगामी ब्याज दर की योजना को 29 दिसम्बर, 1990 से संशोधित किया गया। वर्तमान योजना के अंतर्गत जहां प्रारक्षित तकदी निधि अनुपात में आने वाली कमी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे 'पात्र' तकदी शेप पर क्रमशः न्यूनतर ब्याज दरें निर्धारित की गई थीं; इसके विपरीत संशोधित योजना के अंतर्गत बैंक नियमित ब्याज दर पर (अर्थात् 23 मार्च 1990 को विद्यमान शुद्ध मांग और सियादी देयताओं पर बनाये रखे 'पात्र' तकदी शेप पर वार्षिक 10.5 प्रतिशत और उसके बाद वृद्धिशील शुद्ध मांग और सीयादी देयताओं पर बनाये रखे गये 'पात्र' तकदी शेप पर वार्षिक 800 प्रतिशत) ब्याज अर्जित करते हैं, तथापि इस प्रकार निकाली गई ब्याज की राशि में से उक्त कमी की राशि पर वार्षिक 25 प्रतिशत की दर पर आकलित राशि बटा दी जायेगी। इस आधार पर पात्र तकदी शेपों पर प्रभावी ब्याज दर में स्वाभाविक रूप से कमी आयेगी और तकदी प्रारक्षित निधि में आने वाली कमी की लागत में पहले की तरह घट बढ़ नहीं होगी जब कमी की विभिन्न

सीमाओं की लागत भिन्न भिन्न हुआ करती थी। (तीन ही गई मार्गियां 5.1 और 5.2 देखें)।

मार्गणी 5.1 : तकदी शेप पर प्रगामी ब्याज दर की अनुसूची

विद्युती

(21 अप्रैल 1990 से प्रभावी)

बनाये रखे जाने के लिए अपेक्षित 23 जून 1990 के विद्यमान शुद्ध प्रारक्षित तकदी निधि की समग्र राशि मांग और सीयादी देयताओं पर भरसुत: बनाये रखी गयी 3 प्रतिशत की न्यूनतम मासिक राशि से अधिक की राशि पर देय ब्याज दर

1	2
0.0	10.50
2.0	10.00
4.0	9.25
6.0	8.50
8.0	7.00
10.0	6.00
10.0 से अधिक	00.0

संशोधित

(29 दिसम्बर 1990 से प्रभावी)

मद	ब्याज की दर (वार्षिक प्रतिशत)
I. निम्नलिखित से संबंधित पात्र तकदी शेप पर देय ब्याज :	
(क) 23 मार्च 1990 को विद्यमान शुद्ध मांग और सीयादी देयता	10.5
(ख) तदनंतर वृद्धिशील शुद्ध मांग और सीयादी देयता	8.0
II. प्रारक्षित तकदी निधि अनुपात में आने वाली कमी की राशि पर ब्याज की कटौती	25.0
III. देय शुद्ध ब्याज (I—II)	

मार्गणी 5.2 : 'पात्र' जमा रकम पर प्रभावी ब्याज दर और प्रारक्षित तकदी निधि अनुपात में आने वाली कमी की संबंधित लागत संबंधी स्पष्टीकरण

विद्युती योजना ( 7 अप्रैल 1990 से प्रभावी )			संशोधित योजना ( 29 दिसम्बर 1990 से प्रभावी )	
कमी बनाये रखे जाने के लिए अपेक्षित प्रारक्षित तकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में	पात्र जमा रकम पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	कम की लागत (प्रतिशत)	पात्र जमा रकम पर प्रभावी ब्याज दर (प्रतिशत)	कमी की लागत (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
0.0	10.17	0.0	10.17	0.0
0.5	9.74	69.1	10.01	25.0

1	2	3	4	5
1.0	9.74	34.3	9.85	25.0
1.5	9.73	22.7	9.69	25.0
2.0	9.73	16.9	9.52	25.0
2.5	9.08	33.5	9.36	25.0
3.0	9.08	27.7	9.19	25.0
3.5	9.08	23.6	9.02	25.0
4.0	9.08	20.95	8.84	25.0
4.5	8.43	28.9	8.66	25.0
5.0	8.43	25.8	8.49	25.0
5.5	8.43	23.3	8.30	25.0
6.0	8.43	21.2	8.12	25.0
7.0	7.14	31.3	7.75	25.0
8.0	7.14	26.9	7.36	25.0
9.0	6.29	30.3	6.96	25.0
10.0	6.30	26.8	6.56	25.0
10.5	0.00	80.0	6.35	25.0
11.0	0.00	76.5	6.14	25.0
11.5	0.00	73.3	5.92	25.0
12.0	0.00	70.3	5.70	25.0
15.0	0.00	56.8	4.33	25.0
20.0	0.00	43.2	1.73	25.0
22.9	0.00	38.0	0.00	25.0
23.0	0.00	37.9	0.00	37.9

## टिप्पणियाँ :

- उपरोक्त दरों और प्रभावी लागतों को 23 मार्च, 1990 को शुद्ध भाग और मीयाबी देयताओं के मुकाबले विद्यमान बकाया राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाने हुए निकाला गया है।
- वस्तुतः बनाये रखी गयी पात्र जमा रकम पर व्याज में हानि और 22.9 प्रतिशत से अधिक की कमी के मामले में लागू वण्ट स्वरूप दर कमी की लागत होती है।

## (छ) जमा प्रमाणपत्र :

5.19 जमा प्रमाणपत्र में प्राथमिक बाजार के आधार को व्यापक बनाने तथा उसके गौण बाजार की गतिविधियों को सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से, बैंकवार सीमाओं को वर्ष 1989-90 की औसत सकल जमा राशियों के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। इसके फलस्वरूप, जमा प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में बैंकिंग प्रणाली के लिए सकल सीमाओं की राशि 3,018 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,522 करोड़ रुपये हो गयी। जमा प्रमाणपत्र की न्यूनतम भूतल वर्ग को 10 लाख रुपये से कम कर 5 लाख रुपये कर दिया गया और निर्गम के न्यूनतम आकार को भी 50 लाख रुपये से कम कर 25 लाख रुपये कर दिया गया।

## (ज) निर्यात ऋण पुनर्वित्त :

5.20 निर्यात ऋण की वृद्धि दर शुद्ध बैंक ऋण की समग्र वृद्धि दर के अनुरूप नहीं रही थी और खाद्य क्षेत्र की

गतिविधियों को देखते हुए तथा भुगतान संतुलन पर भारी दबाव का कारण बैंकों को यह सूचित किया गया कि निर्यातों को समर्थन देने के लिए काफी प्रयास करें। निर्यातों का संवर्धन करने तथा निर्यातों का वित्तपोषण करने के लिए बैंकों को अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता को देखते हुए बैंकों की उपलब्ध निर्यात ऋण पुनर्वित्त की मात्रा में बढ़ोतरी की गई और 1 जनवरी, 1991 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की वित्तीय वर्ष 1988-89 के निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर की तुलना में निर्यात ऋण में हुई वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर का निर्यात ऋण पुनर्वित्त वार्षिक 9 प्रतिशत की दर पर प्रदान किया गया। इस उपाय के कारण 1990-91 के वित्तीय वर्ष में बैंकों को उपलब्ध निर्यात पुनर्वित्त में लगभग 1,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

## (झ) वयनात्मक ऋण नियंत्रण :

5.21 1990-91 के मौसम के लिये अच्छी खरीफ खाद्यान्न की पैदावार की तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संतोषजनक भंडार को देखते हुए धान/चावल तथा अन्य खाद्यान्न पर दिये जाने वाले बैंक ऋणों पर न्यूनतम मार्जिन में सभी स्तरों पर 10 अक्तूबर, 1990 से 15 प्रतिशत अंकों की कमी लायी गई। तथापि, धान/चावल और अन्य खाद्यान्न से संबंधित तदनुसूची कीमत-उत्पादन गतिविधियों की समीक्षा करने के बाद 8 जनवरी, 1991 से न्यूनतम मार्जिनों को सभी स्तरों पर 15 प्रतिशत अंक बढ़ा दिया गया है।

1991-92 के वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए नीतिगत उपाय :

5.22 वर्ष 1991-92 के लिए ऋण नीति बनाने समय, वर्ष के लिए 4 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक सकल देशी उत्पादन की वृद्धि के आधार पर योजना बनाने की बात को व्यावहारिक समझा गया। प्राथमिक चलेनिधि में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा मांग में वृद्धि को नियंत्रित करने के आवश्यकता को महसूस करते हुए मुद्रा और ऋण विस्तार की गति में कमी लाने की अनिवार्य समझा गया। केन्द्रीय सरकार के अंतरिम बजट में यह संकेत दिया था कि वित्तीय वर्ष 1991-92 में सकल राजकोषीय घाटे को सकल देशी उत्पाद के 0.5 प्रतिशत तक सीमित करने का सरकार का अभिप्राय है। इस राजकोषीय लक्ष्य के समर्थन में और सकल देशी उत्पाद में 4 प्रतिशत की पुर्वानुमानित वास्तविक वृद्धि एवं 7 प्रतिशत में घनत्विक की मुद्रास्फीति के अनुरूप मुद्रा नीति का लक्ष्य यह निर्धारित किया गया कि वर्ष 1991-92 (अप्रैल-मार्च) में मुद्रा विस्तार (एम3) को 14 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए।

5.23 बैंकों को यह सूचित किया था कि वे 1991-92 (अप्रैल-मार्च) में 20,500 करोड़ रुपये (15.4 प्रतिशत) की जमा वृद्धि के कार्यक्रमित अनुमान के आधार पर धान ऋण बजट को योजना करें। यह अनुमान था कि मार्च-जून 1990 के दौरान खाद्य ऋणों में 1,000 करोड़

रुपए की बढ़ोतरी होगी और अगली तिमाही में 800 करोड़ रुपए की कमी आएगी। वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में घाबतर ऋणों में लगभग 3,500 रुपए की बढ़ोतरी होने का अनुमान था। चूंकि कठिन विदेशी मुद्रागत स्थिति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1991-92 के लिए ऋण नीति बनायी गयी थी, बैंकों को यह स्पष्ट किया गया कि आयातों पर अतिरिक्त नकदी माजिन लगा देने से (इसे इस अध्याय के अंत में स्पष्ट किया गया है) हालांकि उनके घटकों के लिए कुछ समस्या पैदा हो सकती है इस उपाय को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए कि विदेशी मुद्रागत स्थिति में सुधार लाने के सर्वापरि लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके। इस बात पर भी बल दिया गया कि निर्यातों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए हालांकि, इस नीति की पूर्वव्यवस्था मुख्यतः अल्पकालित प्रबंधन से संबंधित थी, मुद्रा बाजार के संरचनात्मक विकास के संबंधित कतिपय उपाय भी लागू किए गए। ऋण नीतिगत उपायों में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

क. वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर) जमा अनुपात

5.24 वर्ष 1990-91 में मुद्रास्फीति का दर में तीव्र वृद्धि होने तथा विदेशी भुगतान की स्थिति खराब हो जाने के कारण बैंक ऋण में विस्तार के संघर्ष में अत्यंत सावधान दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी कि 1991-92 (अप्रैल-मार्च) के लिए उनका वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण (निर्यात ऋण को छोड़कर)—जमा अनुपात 45 प्रतिशत से अधिक नहीं था। निर्यात-प्रयासों के लिए प्रोत्साहन ऋण जमा अनुपात के विन्यास से बाहर रखा गया। इस अनुपात के लिए 22 मार्च, 1991 को आधार तारीख के रूप में निर्धारित किया गया और इस अनुपात पर पाक्षिक आधार पर संचयी रूप से निगरानी रखी जाएगी। जिन बैंकों का अनुपात निर्धारित स्तर से अधिक हो गया था, उनसे 20 अप्रैल, 1991 से प्रारंभ होने वाले पखवाड़े से उस दर पर अतिरिक्त ब्याज दर लिया जाता है, जो रिजर्व बैंक से समस्त सुविधाओं (निर्यात, आयात, विवेकाधीन और 182 दिवसीय से खजाना बिल) के अंतर्गत निर्धारित स्तर से अधिक की ऋण राशि के संबंध में आह्वित किया गया पुनर्वित्त या लिया गया पुनर्वित्त, इनमें से जो भी कम हो, 3 प्रतिशत अंक अधिक होगा। जिन बैंकों का अनुपात निर्धारित स्तर से निरंतर रूप से अधिक रहता है उनसे समस्त पुनर्वित्त सुविधाएँ पूर्णतः आपस ली जा सकती हैं।

ख. निर्यात ऋण पुनर्वित्त

5.25 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अब तक वर्ष 1988-89 के निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर के मुकाबले निर्यात ऋण में हुई वृद्धि 100 प्रतिशत के बराबर का निर्यात ऋण पुनर्वित्त प्रदान किया जाता था। इन पुनर्वित्त सीमाओं की राशि 22 मार्च, 1991 की

4,129 करोड़ रुपए, जो बकाया निर्यात ऋण के 46.6 प्रतिशत के बराबर थी। निर्यात पुनर्वित्त को निर्धारित करने के लिए आधार में प्रति वर्ष वृद्धि करने की सामान्य पद्धति रहीं हैं। यह पद्धति उस तंत्र में अपरिहार्य थी, जहां बैंकों को वृद्धिशील निर्यात ऋण के लिए 100 प्रतिशत का निर्यात पुनर्वित्त प्रदान किया जाता था। निर्यात क्षेत्र को सतत सहायता प्रदान करने की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए तथा साथ ही निमित्त धन में अनुचित रूप से भारी वृद्धि होने से बचते हुए, आधार में परिवर्तन के कारण होने वाले प्रभाव को द्विस्तरीय निर्यात पुनर्वित्त सूत्र लागू करते हुए कम किया गया। तदनुसार, 27 जुलाई, 1991 से बैंकों को 1988-89 के मासिक औसत स्तर की तुलना में निर्यात ऋण में होने वाली वृद्धि के 50 प्रतिशत की सीमा तक 1989-90 के मासिक औसत स्तर तक का और 1989-90 में निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर के मुकाबले हुई वृद्धि के 100 प्रतिशत के बराबर का निर्यात पुनर्वित्त प्रदान किया जाएगा। इस नए सूत्र के कारण बैंक संसाधन संबंधी प्रतिबंध के बिना निर्यात क्षेत्र की वृद्धिशील ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। यद्यपि, बैंकों के पुनर्वित्त स्तर में प्रारंभ से कमी लायी जाएगी, अधिक कामकाज का समय शुरू होने से काफी पहले उनमें सुधार लाया जाएगा।

ग. उधार दरें

5.26 वर्तमान उच्च मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए और मुद्रा विस्तार को रोकने की अत्यधिक आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में यह निश्चय किया गया कि 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं के ब्याज दरों में 13 अप्रैल, 1991 से एक प्रतिशत अंक की वृद्धि की जाए। इस प्रकार उक्त ब्याज दर को 16.0 प्रतिशत (न्यूनतम) से बढ़ाकर 17.0 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दिया गया। बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में प्रचलित दर के मुकाबले कम-से-कम 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि करें। इस वर्ग के उधारकर्ताओं के लिए विनियम बिलों की भुनाई पर प्रभावी ब्याज दर को वर्तमान 15.0 प्रतिशत (न्यूनतम) के ब्याज 16.0 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दिया गया और ली जाने वाली वास्तविक दर इस वर्ग के ऋणकर्ताओं से ली जाने वाली तदनुसृत ब्याज दर में 1 प्रतिशत अंक कम होगी। कृषि, लघु उद्योग और दो बाहनों तक के परिवहन वाहनों को प्रदत्त मीयार्थ ऋणों के मामले में 22 सितम्बर, 1990 को निर्धारित की गयी वास्तविक ब्याज दर अपरिवर्तित रही।

5.27 अर्थव्यवस्था के कुल भोग को कम करने की आवश्यकता के संदर्भ में तथा जमा दरों (नॉवे उलेखनीय) में वृद्धि की ध्यान में रखते हुए 4 जुलाई, 1991 से 2 लाख से अधिक ऋण सीमाओं पर उधार दर 1.5 प्रतिशत बढ़ाई गयी। अर्थात् उसे 17.0 प्रतिशत वार्षिक (न्यूनतम) से बढ़ाकर 18.5 प्रतिशत (न्यूनतम) कर दिया गया। उधारकर्ताओं का इस श्रेणी के लिए विनियम बिल की भुनाई पर प्रभावी ब्याज दरें इसी श्रेणी के उधारकर्ताओं पर प्रभावित



तदनुरूप उधार दरों से एक प्रतिशत कम होंगी। कृषि, लघु उद्योग और दो पहिए वाले वाहनो के परिवहन परिचालकों को दिए जाने वाले मीमादी ऋणों के मामलों में इस प्रकार के ऋणों पर 32 सितंबर 1990 को निर्धारित ब्याज दरें लागू रहेंगी।

#### (ध) जमा दरें

5.28 अधिकतम जमा दर और वैकल्पिक बचत लिखतों पर होने वाली आय के बीच बेहतर सिधार्ड लाने की आवश्यकता को देखते हुए तथा वर्तमान मुद्रास्फीति की दर को कम करने के उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि की मीमादी जमा दर में 13 अप्रैल 1991 में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गयी और इसे 11.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.0 प्रतिशत कर दिया गया। शेष सभी जमा दरें अपरिवर्तित रही। जमाराशियों पर लागू की गयी इस उच्चतर ब्याज दर के कारण बैंकों को होने वाला लागत, उपर्युक्त उच्चतर उधार के परिणामस्वरूप उनकी बड़ी हुई ब्याज आय के लगभग बराबर होंगी।

5.29 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक अपने ही संसाधनों में से अपने ऋण प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम चलाना है और बैंकों को वैकल्पिक बचत लिखतों में प्रतिस्पर्धा के फाविल बनाने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीमादी जमा दरों में सभी स्तरों पर 4 जुलाई 1991 से एक प्रतिशत बढ़ा दी गयी है। संशोधित ब्याज दरें—केवल नई जमाराशिया और अवधि समाप्त जमाराशियों के नवीकरण पर लागू होंगी। वर्तमान और संशोधित जमा दरों का छांचा (विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों/अनिवासी विदेशी खातों को छोड़कर) नीचे दर्शाया गया है :

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों पर ब्याज दरें  
(विदेशी मुद्रा निवासी खाता/अनिवासी विदेशी खातों को छोड़कर)

खाते का प्रकार	(प्रतिशत वार्षिक)		
	10 अक्टूबर 1990 से प्रभावी दरें	13 अप्रैल 1991 से प्रभावी दरें	4 जुलाई 1991 से प्रभावी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)
घातू	शून्य	शून्य	शून्य
बचत	5.0	5.0	5.0
मीमादी जमाराशियां			
(क) 46 दिनों से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम अवधि तक	8.0	8.0	9.0
(ख) एक वर्ष से अधिक परन्तु 2 वर्ष से कम अवधि तक	9.0	9.0	10.0
(ग) दो वर्ष से अधिक परन्तु 3 वर्ष से कम अवधि तक	10.0	10.0	11.0
(घ) तीन वर्ष और इससे अधिक	11.0	12.0	13.0

टिप्पणी :—जमा दरों में यह परिवर्तन केवल नई जमाराशियों और अवधि समाप्त जमाराशियों के नवीकरण पर लागू है।

(इ) अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों के अंतर्गत जमा राशियों पर ब्याज दरें

5.30 13 अप्रैल 1991 से 3 वर्ष और उससे अधिक की परन्तु 5 वर्ष से कम अवधि की तथा 5 वर्ष और उससे अधिक अवधि की अनिवासी (विदेशी) रुपया जमा राशियों पर देय ब्याज दरों में 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि की गयी। तदनुरूप, अनिवासी (विदेशी) रुपया जमाराशियों पर अधिकतम ब्याज दर को अब तक के 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।

#### (च) चयनात्मक ऋण नियंत्रण

5.31 चयनात्मक ऋण नियंत्रण के क्षेत्र में निम्न-लिखित दो उपायों को लागू किया गया।

##### (i) ऋण की उच्चतम सीमाओं के लिए संदर्भ अवधि

13 अप्रैल 1991 से प्रभावी उच्चतम ऋण सीमाओं के लिए संदर्भ अवधि जिन पण्यों के मामले में, 1986-87 से 1988-89 (नवम्बर-अक्तूबर) तक की 3 वार्षिक अवधि के आधार पर उच्चतम ऋण सीमा का स्तर निर्धारित किया गया था, उन मामलों में आधार अवधि को 13 अप्रैल 1991 से 1989-90 को समाप्त होने वाली 3 वार्षिक अवधि तक आगे ले जाया गया।

##### (ii) उच्चतम ऋण सीमाओं का स्तर

उसी तारीख से निम्नहूनों/वनस्पति तेल पर लागू उच्चतम ऋण सीमा के स्तर की प्रत्येक पार्टी द्वारा 1989-90 (अक्तूबर-नवम्बर) को समाप्त होने वाली 3 वार्षिक अवधि के लिए बनाए रखे गए शिखर ऋण स्तर के 100 प्रतिशत से घटाकर 13 अप्रैल, 1991 से 85 प्रतिशत कर दिया गया।

##### (iii) चीनी

5.32 गन्ने के मूल्य में वृद्धि को देखा हुआ गया उत्पादकों को देय बकाया राशि और उन्हें राशन प्रदान करने की आवश्यकताओं को देखते हुए 9 मई 1991 से चीनी के भोजन स्टॉकों की जमानत पर दिए गए बैंक ऋणों पर लागू न्यूनतम मार्जिन को अभिसंस्कार यूनिटी/मिलों के लिए 20 प्रतिशत को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 17.5 प्रतिशत कर दिया गया। यह रियायत केवल तीन महीने की अवधि के लिए पर्याप्त 8 अगस्त 1991 तक उपलब्ध थी। इस तारीख के बाद न्यूनतम मार्जिन पूर्ववत् 20 प्रतिशत हो जाएगी। चयनात्मक ऋण नियंत्रण में शामिल पण्यों की जमानत पर दी जाने वाली ऋणों के संबंध में ऋण की उच्चतम दरों का न्यूनतम मार्जिन/स्तरों को मारपी 5.3 में दर्शाया गया है।

भारतीय 5 3: न्यूनतम माजिन और उच्चतम ऋण सीमा का स्तर

(9 मई, 1991 से)

(प्रतिशत)

पक्ष	न्यूनतम घण्टा	माजिन गोदाम रसीमें सीमा का स्तर (माध्यम वर्ष)	उच्चतम ऋण को समाप्त तीन वर्ष (नवम्बर-मार्च)
1. बाल/बाबल	45	80	45 85
2. बाले	45	60	45 85
3. बाल बाबल	45	60	45 85
4. तिलहन (जैसे मूंगफली/ तोरिया/ सरसों, बिभीला, धलसी, एरण्ड और सभी प्राया- नित तेल)	60	75	60 85
5. वनस्पति (जैसे मूंगफली, तोरिया/ सरसों, धलसी एरण्ड, वनस्पति और सभी प्रायासित तेल)	60	75	60 85
6. बीनी :			
(क) आपासी स्टॉक शुभ	..	..	..
(ख) अतिरिक्त स्टॉक 17.5%	..	..	..
(ग) निर्यात स्टॉक	75	75	60 ..
7. गुरु और बंडसोरी	45	75	60 ..

(@) पेशीकृत तेल मिलों और वनस्पति निर्माताओं के संबंध में लागू।

.. लागू नहीं।

† 8 मगस्त, 1991 तक, इसके बाद न्यूनतम माजिन फिर से 20 प्रतिशत कर दिया गया।

### (छ) जमा प्रमाणपत्र

5.33 46 प्रमुख अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 22 फरवरी 1991 तक जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों की कुल बकाया राशि 3,035 करोड़ रुपए थी जो इन बैंकों की जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निर्धारित 4,383 करोड़ रुपए की संशोधित सीमा का 69.2 प्रतिशत थी। बड़ी मात्रा में निधियों के लिए अन्य लिखतों के साथ बैंक कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें तथा जब ऐसी निधियां आवश्यक हों, तब बैंकों को बाजार से निधियां जुटाने में सुविधा हो—इस उद्देश्य से यह आवश्यक समझा गया कि जमा प्रमाणपत्रों के लिए काफी बड़ी सीमाएं प्रदान की जाए ताकि अपेक्षाकृत छोटे बैंकों के पास भारी निधियां जुटाने के लिए पर्याप्त सीमाएं हों। तदनुसार, 20 अप्रैल 1990 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) /

द्वारा जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी सीमाओं को 1989-90 बकाया कुल जमा राशियों के पाक्षिक औसत के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। इससे फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली के जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी कुल सीमाओं 4,522 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7,537 करोड़ रुपए कर दिया गया।

### (ज) वाणिज्यिक पत्र

5.34 वाणिज्यिक पत्र के लिखत को प्रयोग में लाने के संबंध में पर्याप्त अनुभव अर्जित कर लिया गया था और यह अनुभव किया गया कि व्यापक सहभागिता को सुलभ बनाने तथा उसके परिचालन में अधिक मात्रा में लचीलापन को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में छूट दी जा सकती है। तदनुसार, 30 मई 1991 में उससे संबंधित योजना में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए :

(i) जारी करने वाली कंपनी की कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमा तो अब तक के 15 करोड़ रुपए के बजाय 10 करोड़ रुपए से धन्यून बना दिया गया।

(ii) वाणिज्यिक पत्र के निर्गम द्वारा किसी कंपनी द्वारा जुटाई जाने वाली कुल राशि संबंधी उच्चतम सीमा को उसकी कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमा के 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया।

(iii) वाणिज्यिक पत्र का मूल्य-वर्ग 5 लाख रुपए (अब तक 10 लाख रुपए) के गुणजों में हो सकता है; परन्तु इस संबंध में यह धर्ते है कि किसी एक ही निवेशक के लिए निर्गम का न्यूनतम आकार अब तक के 50 लाख रुपए (अंकित मूल्य) के बखले 25 लाख रुपए (अंकित मूल्य) होगा।

(iv) बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करने की पहल की शर्त को समाप्त कर दिया गया। तथापि पार्टियों के लिए अपने बैंकों के जरिए त्रिधाविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति करनी होगी और बैंकों को मंजूरी पश्चात आधार पर पाक्षिक विवरणियां रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

(झ) मांग/सूचना मुद्रा और बिल पुनर्मुद्राई बाजारों में सहभागिता को व्यापक बनाना

5.35 मांग/सूचना मुद्रा और बिल पुनर्मुद्राई बाजारों को व्यापक बनाने के बारे में अनुभव की गयी आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में उन ऋणकर्ताओं को इन बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जो उधार देने योग्य अपनी भारी संसाधनों के बारे में रिजर्व बैंक को प्रमाण देने में सक्षम होंगे ऐसी संस्थाओं का प्रति लेनदेन 20 करोड़ रुपए का न्यूनतम आकार रखा होगा और ये लेनदेन केवल भारतीय मिलीकाटा और वित्त गृह के जरिए करने की

अनुमति दी जाएगी। इन उद्योगिकी संस्थाओं से यह बचन देने की अपेक्षा की जाएगी कि बैंकिंग प्रणाली से उनका कोई प्रभावी उधार नहीं है। मांग/मुचन मूला और विल पुर्न-भुनाई बाजारों में सहयोगी होने की दृष्टिको संस्थाओं का चाहिए कि वे इन बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करें।

#### (का) मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड

5.36 निवेशकों को अनिश्चित अवधि निवेश की सुविधा देने और व्यक्तियों तथा छोटे निकायों के पहुंच के भीतर मुद्रा बाजार लिखतों को लाने के उद्देश्य से यह बांछनीय समझा गया कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा उनकी सहयोगी संस्थाओं को मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड की एक ऐसी विशेष श्रेणी है जो अवधि स्वल्पा की उच्च गुणवत्ता से युक्त मुद्रा बाजार लिखत में निवेश के लिए है। हाल ही में अनेक मुद्रा बाजार लिखत खलाए गए हैं, जैसे जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्य पत्र और 182 दिवसीय खजाना बिल। ये प्रत्येक विशेष रूप से बड़े पैमाने पर निधियों जुटाने के लिए थे और इसलिए इन में न्यूनतम कारोबार की अपेक्षाकृत परिकल्पित था। अतः निवेशकों को अनेक संख्या में अवधि मुद्रा बाजार लिखत उपलब्ध कराए गए ताकि मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड बड़े आकार की मध्य-वर्ती संस्था बन सकें। इसी संदर्भ में इस फंड ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड से संबंधित योजना की रूप रेखा इस प्रकार है:—

- (i) मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड को स्थापित करने की अनुमति केवल बैंकों और उनकी सहयोगी संस्थाओं को दी जाएगी।
- (ii) व्यक्तियों और अन्य निकायों को पराक्राम्य/अंतरणीय लिखतों और इस फंड के जमाबानों में अपने समाधनों के निवेश की अनुमति दी जाएगी। बैंकों और उनकी संस्थाओं द्वारा इस प्रकार की निधियां जुटाने दर उपयुक्त अधिकतम सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। (प्रारंभ में यह सीमा कुल जमागणियों का एक प्रतिशत हो सकती है)।
- (iii) निवेश की न्यूनतम राशि एक लाख होगी और पुनः खरीद 3 महीने की न्यूनतम अवधि के अधीन होगी।
- (iv) मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड के अंतर्गत केवल निर्दिष्ट अवधि मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा—(जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, 182 दिवसीय खजाना बिल, वाणिज्यिक बिलों की पुर्नभुनाई तथा मांग और अन्य मुचन धन) यह फंड उधारधना के रूप में निवेश करेगा। उक्त निधियों में निवेशित राशि का कम-से-कम 20 प्रतिशत 182 दिवसीय खजाना

बिलों में और अधिकतम 20 प्रतिशत मांग प्रत्येक मुचन धन में प्रतिधारित किया जा सकता है।

- (v) मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड द्वारा जुटाई गई निधियों पर प्रारंभित अपेक्षाएं लागू नहीं होगी क्योंकि ये निधियां मुद्रा बाजार लिखतों में निवेशित की जाएगी।

- (vi) स्टाम्प शुल्क के प्रश्न का अध्ययन करने की आवश्यकता है।

5.37 इस विस्तृत ढांचे का पूरी तरह विकास करने तथा इस प्रकार की योजना में निहित पहलुओं पर विचार करने के लिए रिजर्व बैंक एक कृतिक बन गठित करेगा जिसमें बैंकों और रिजर्व बैंक प्रतिनिधि होंगे। यह उल विस्तृत परिचालनात्मक मार्गदर्शी लिखत और मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड के प्रलेखन निर्धारित करेगा।

#### (ट) निर्यात ऋण व्याज दरें

5.38 जो निर्यातक निर्यात मूल्य शीघ्र प्रत्यावर्तित करने हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए तथा जो निर्यातक निर्यात मूल्य प्रत्यावर्तित करने में विलंब करते हैं उ के लिए ऋण महंगा करने के उद्देश्य से मौन-नदार्तों पर ऋण पर की जाने वाली व्याज दरें संशोधित की गयी है। संशोधित व्याज दरें पहली अप्रैल, 23 अप्रैल और 6 अगस्त 1991 से तीन स्तरों में लागू होंगी। निर्यात मूल्यों के प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में 45 दिन की अवधि के लिए 7.0 प्रतिशत की विशेष रियायती व्याज दर निर्धारित की गयी है, जबकि 45 दिन की इस अवधि से अधिक तथा 90 दिन तक व्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यदि निर्यात मूल्य पोतलदान के 90 दिन के बाद किंतु 6 महीने के भीतर प्रत्यावर्तित किया जाता है तो अग्रिम लेने की तारीख से संपूर्ण अवधि के लिए 18 प्रतिशत की व्याज दर लागू होगी। यदि निर्यात मूल्य 180 दिनों के बाद प्रत्यावर्तित किया जाता है तो अग्रिम लेने की तारीख से संपूर्ण अवधि के लिए 25 प्रतिशत की व्याज दर लागू होगी (सारणी 5.4)।

#### (ड) अग्रिमों पर व्याज दरें निर्यात ऋण

5.39 रूप की विविध दर में समायोजन के करने माध सरकार ने निर्यात पर दी जाने वाली प्राधिकृत सहायता समाप्त करने का निर्णय लिया है। तदनुसार 6 अगस्त 1991 से निर्यात ऋण के व्याज दर ढांचे में संशोधन किया गया। 180 दिनों तक पोतलदान पूर्व ऋण पर लगाई जाने वाली व्याज दर बढ़ाकर 12.50 प्रतिशत वापिक कर दिया गया, जबकि 180 दिनों से अधिक 270 दिनों तक (ऐसे मामले में रिजर्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है) के पोतलदान पूर्व ऋणों के लिए व्याज दर 14.50 प्रतिशत वापिक निर्धारित की गयी।

## (ड) वृद्धिशील प्रारक्षित नकदी अनुपात

5.40 विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति और उसके परिणामस्वरूप मुद्रामत विस्तार को संयत बनाकर समय समग्र मांग को नियंत्रित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर 15 प्रतिशत के नकदी प्रारक्षित अनुपात के अलावा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से यह अपेक्षा की गयी कि वे 4 मई, 1991

से 3 मई, 1991 को जो स्तर या उसमें अधिक निवृत्त मांग और मीयादी देयताओं में होने वाली वृद्धि का 10 प्रतिशत वृद्धिशील प्रारक्षित अनुपात बनाये रखें। इस प्रावधान का परिणाम प्रत्येक बैंक पर अलग-अलग होगा जो उनके निवृत्त मांग और मीयादी देयताओं की वृद्धि पर निर्भर होगा।

सारणी 5.4 : अनुसूचित वाणिज्य बैंक : निर्यात ऋण पर व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

निर्यात ऋण	31 मार्च 1991 तक दरें	1 अप्रैल 1991 से प्रभावी दरें	23 अप्रैल 1991 से प्रभावी दरें	6 अगस्त 1991 से प्रभावी दरें
1 पोतलदान से पूर्व ऋण				
(क) (i) 180 दिनों तक	7.50	7.50	7.50	12.5
(ii) 180 दिन से अधिक और 270 दिन तक (भारिब के पूर्वानुमोदन सहित)	9.50	9.50	9.50	14.50
(ख) नकद प्रोत्साहन, इत्यादि के लिए ई सी जी सी द्वारा शामिल, 90 दिन की गारंटी	7.50	7.50	7.50	12.50
2 पोतलदान के पश्चात ऋण				
(i) मार्गस्थ अवधि के लिए मांग बिल (फैडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट)	8.65	8.65	7.00	12.50
(ii) मियादी बिल (निर्यात बिलों, फैडाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मार्गस्थ अवधि की मियादी अवधि को शामिल करते हुए कुल अवधि के लिए, जहां भी लागू हों अतिरिक्त अवधि भी) शामिल है				
(क) 45 दिन तक			7.00	
(ख) 45 दिन से अधिक 90 दिन तक	8.65 (180 दिन तक)	8.65 (90 दिन तक)	8.65	12.50
(ग) 90 दिन से अधिक और पोतलदान से छः माह तक		16.00 (अग्रिम की तारीख से)	18.00 (अग्रिम की तारीख से)	18.00 (अग्रिम की तारीख से)
(घ) पोतलदान की तारीख से छह माह से अधिक		16.00 अग्रिम की तारीख से 2.00 का अग्रिभार जोड़े	25.00 (अग्रिम की तारीख से)	25.00 (अग्रिम की तारीख से)
(iii) ई सी जी सी गारंटी में शामिल सरकार से प्राप्त नकद प्रोत्साहन, ड्यूटी बैंक (90 (90 दिन तक)	8.65	8.65	8.65	12.50
(iv) अनाहरित शेष राशि (90 दिन तक)	8.65	8.65	8.65	12.50
(v) अग्रिधारण क्षमता के लिए (केवल आपूर्ति भाग के लिए) पोतलदान की तारीख (90 दिन तक) से एक वर्ष से ही देय	8.65	8.65	8.65	2.50
3 आस्थगित ऋण 180 दिन से अधिक की अवधि के लिए आस्थगित ऋण	8.65	8.65	8.65	12.50
4 ड्यूटी ड्रा बैंक डिट क्रेडिट स्कीम, 1976 सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अस्थायी रूप से प्रमाणित ड्यूटी ड्रा बैंक के लिए (90 दिन तक)	(व्याज मुक्त)	(व्याज मुक्त)	(व्याज मुक्त)	(व्याज मुक्त)
5 निर्यात ऋण, अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट नहीं	14.00 से 15.00	18.50 (न्यूनतम)	18.00 (न्यूनतम)	18.50 (न्यूनतम)

## (ड) आयात वित्त पर ब्याज दर अधिभार

5.41 आयात वित्त पोषण के लिए बैंक ऋण के अपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आयात बिल पर ब्याज दर अधिभार लगाया गया। तदनुसार बैंकों को यह सूचित किया गया था कि आयात वित्त पोषण के लिए बैंक ऋण को नकद ऋण सीमा की पृथक ऋण उप-सीमा के अंतर्गत निर्धारित किया जाना चाहिए और जिन पार्टियों के लिए आयात ऋण उप-सीमा के अंतर्गत दर्शायी राशि पर 9 मई 1991 से 2 लाख रुपये और उससे अधिक हो उन पर 25 प्रतिशत ब्याज दर अधिभार लगाया गया। इस अधिभार के प्रयोजन के लिए आयातों पर नकदी मार्जिन प्रदान करने के लिए बैंक वित्त के आहरणों को आयात वित्त माना जायेगा और आयातों का भुगतान करने के लिए नामे राशियां मानी जायेंगी। आयात उप-सीमा के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियां उस समय कम होंगी जब आयातों पर नकदी मार्जिन मुक्त की जायेगी जबकि आयात उप-सीमा की चुकौतियों के लिए उसी आगम से इस शर्त के साथ अनुमति दी जायेगी कि एक महीने की अवधि के दौरान बिक्री से प्राप्त राशि के द्वारा आयात उप-सीमा में से आयातों का भुगतान नही किया जा सकता। आयातों पर अधिभार लगाया जायेगा और यह अधिभार आयातों पर नकदी मार्जिन "शून्य" के अधीन होगा साथ ही, निर्धारित नकदी मार्जिन पर किये जाने वाले आयात के अधीन होगा। पूंजीगत माल के आयातों पर भी अधिभार लागू होगा। निर्यात पैकिंग ऋण के अंतर्गत आनेवाली आयातित निविष्टियों के खर्च को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया वित्त अधिभार से मुक्त रखा गया है।

## (ण) बड़ी नकदी ऋण-सीमा के अंतर्गत आहरणों पर रोक

5.42 वर्तमान नकदी ऋण प्रणाली के अंतर्गत ऋण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने में बैंकों द्वारा महसूस की गयी कठिनाइयों के कारण स्वीकृत सीमा और उनके वास्तविक उपयोग के बीच काफी अंतर आ गया है। अगले कुछ-महीनों में ऋण विस्तार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप में विदेशी मुद्रा निधि के संरक्षण के संदर्भ में बैंकों को यह सलाह दी गयी थी। जिन उधारकर्ताओं के खातों को 1 लाख रुपये या उससे अधिक की सीमाएं प्राप्त हैं उन सब के मामले में, नकदी सीमा और 9 मई 1991 से 30 सितंबर 1991 की अवधि के अंतर्देशीय बिलों के लिए सीमाओं के अंतर्गत प्रभावी आहरण अधिकार पिछले तीन वर्षों में 9 मई-30 सितंबर की तदनुसूची अवधि के दौरान वास्तविक उपयोग के उच्चतर स्तर के 100 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। बैंकों से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित था कि प्रभावी आहरण सीमा तय करने की यह पद्धति किसी भी हालत में नकदी सीमा उस स्तर से अधिक नहीं बढ़ाती जो 8 मई 1991 को था। रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत सीमाएं और निर्यात ऋण (पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर प्रयाजनों के लिए स्वीकृत निर्यात बिल की सीमाएं) सीमाएं तथा रुग्ण कमजोर यूनिटों की सीमाएं, जिनके लिए कार्यक्रम बनाने

के कार्यक्रम स्वीकृति किये गये हैं इस शर्त के दायरे में नहीं आयेंगी। जिन नवस्थापित यूनिटों में उत्पादन प्रा म्भ होने ही वाली है और जिन वर्तमान यूनिटों का विस्तार, विविध-करण या आधुनिकीकरण हो रहा है उनके मामले में उच्चतम उपयोग संबंधी मानदंड लागू करने में कुछ ढील दी गयी है। चीनी उद्योग के लिए बैंक आवश्यकता-आधारित ऋण सीमाएं मंजूर करेंगी जो वास्तविक उपयोग के उच्चतर स्तर के 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

5.43 बैंकों को यह सूचित किया गया था कि 9 मई से 30 सितंबर 1991 की अवधि के लिए सामान्य मार्जिन और अन्य शर्तों के अधीन उन मिलों को अतिरिक्त साख सीमाएं मंजूर किये जायें जिनके पास 1989-90 के गन्ना पेरार्ड मौसम की तुलना में 1990-91 के मौसम के दौरान चीनी स्टॉक का स्तर उच्चतर है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि चीनी मिलों को इस प्रकार स्वीकृत और संवितरित अतिरिक्त साख सीमा की राशि का उपयोग केवल गन्ना उत्पादकों को देय राशियां अदा करने के लिए ही किया जायेगा।

## (त) बैंक दर में वृद्धि

5.44 विदेशी भुगतान के असंतुलन को संशोधित करने के लिए जो अन्य उपाय किये गये हैं उनके अनुरूप मौद्रिक उपायों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता के संदर्भ में किए गए अनेक मौद्रिक उपायों में से एक उपाय था-बैंक दर को एक प्रतिशत अंक बढ़ाना, अर्थात् 3 जुलाई 1991 को कारोबार की समाप्ति के समय से उसे 10.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.0 प्रतिशत करना। रिजर्व बैंक से अग्रिमों पर ब्याज की सभी दरें विशिष्ट रूप से बैंक दर से मिलते हुए जब तक अन्य प्रकार से विनिर्दिष्ट न किया गया हो तदनुसूची ही एक प्रतिशत बढ़ा दी गई।

## (थ) रिजर्व बैंक से ऋण सहायता पर ब्याज दरें

5.45 बैंक दर में हुई वृद्धि के अनुरूप और अनुसूचित बैंकों की उधार दरों में हुई वृद्धि के अनुरूप पुनर्वित्त की दरों में तारतम्य स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए निम्नलिखित पुनर्वित्त सुविधाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरें 3 जुलाई 1994 से बढ़ाई गयीं।

भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त पर ब्याज दरें

पुनर्वित्त सुविधा	3 जुलाई 90 तक प्रभावी	4 जुलाई 91 से प्रभावी
निर्यात पुनर्वित्त	9.0	9.5
आयाती पुनर्वित्त	12.5	13.5
विवेकाधीन पुनर्वित्त	14.0	17.0
	(न्यूनतम)	(न्यूनतम)
खाद्य पुनर्वित्त	11.5	14.00

## 6. मुद्रा और ऋण की प्रवृत्तियाँ

6.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुल मुद्रा राशि में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि कम हुई। राजकोषीय वर्ष 1990-91 के दौरान व्यापक और संकीर्ण दोनों ही मुद्राओं की विस्तार दर गत वर्ष की तुलना में अत्यंत कम रही। उसमें गिरावट की यह प्रवृत्ति वर्ष 1991-92 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान भी बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक से सरकार को निवल ऋण में हुआ विस्तार 1990-91 में और 1991-92 की पहली तिमाही के दौरान उच्च स्तर पर बना रहा। राजकोषीय वर्ष 1990-91 के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र की बैंक ऋण की संवृद्धि में कुछ कमी आई और यह प्रवृत्ति 1991-92 की पहली तिमाही के दौरान भी जारी रही। पिछले वर्ष के दौरान या इसके आसपास सुस्पष्ट रूप से धीमे मुद्रा विस्तार में योगदान देने वाला प्रमुख घटक यह रहा है कि भुगतान संतुलनों में हुए चालू खाते के काफी घाटे के परिणाम स्वरूप बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में व्यापक हानि हुई। वर्ष 1990-91 के दौरान बैंकों की जमा राशियों में अपेक्षाकृत धीमी गति संवृद्धि हुई, खाद्येतर ऋण विस्तार में कई घटकों की वजह से कमी आयी वृद्धिशील खाद्येतर ऋण जमा अनुपात से संबंधित 60 प्रतिशत का निर्धारण का जारी रहना, निजी कंपनी क्षेत्र की सुधरी हुई नकदी प्रवाह स्थिति, कंपनी निकायों द्वारा पूंजी बाजार के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से पूंजी का जुटाया जाना ऋण राहत योजना के प्रचालन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की न्यूनतर मांग होना और कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत बैंकों द्वारा कृषि और अन्य ऋणों की वास्तव में बढ़ते खाते डाला जाना।

## मुद्रा आपूर्ति

6.2 वर्ष 1990-91 के दौरान स्थूल मुद्रा के रूप में हुआ 35,904 करोड़ रुपये (15.5 प्रतिशत) का मुद्रा विस्तार, 1989-90 के दौरान हुई 37,866 करोड़ रुपये (19.6 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में काफी कम था (सारणी 6.1)। वर्ष 1990-91 के दौरान हुआ मुद्रा विस्तार अप्रैल 1990 में की गई ऋण नीति घोषणा में निर्धारित संवृद्धि की दर में पिछले वर्ष के विस्तार से 4 प्रतिशतता अंक की कमी लाने के लक्ष्य के लगभग अनुरूप था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण की राशि 7,206 करोड़ रुपये रहेगी, इस स्वीकृत तथ्य पर लक्ष्य का अनुमान लगाया गया था, जबकि वास्तविक ऋण की राशि 31 मार्च, 1991 के आंकड़ों के अनुसार (14,746 करोड़ रुपये) या पूर्व-कल्पित आंकड़ों से दुगुनी रही, मौद्रिक लक्ष्य की प्राप्ति आकस्मिक ही है क्योंकि इसका व्यापक रूप से यह प्रभाव पड़ा कि निवल विदेशी मुद्रागत आस्तियों में आहरण के कारण सभी आयी शुक्रवारों को प्राप्त सूचना के औसत के आधार पर वर्ष 1990-91 के दौरान एम 3 की संवृद्धि की दर 16.6 प्रतिशत थी, इसकी तुलना में पिछले वर्ष वह 18.8 प्रतिशत थी।

6.3 सार्वजनिक क्षेत्र की मुद्रा आपूर्ति (एम 1) में 1990-91 के दौरान 13,160 करोड़ रुपये (16.2 प्रतिशत) की न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई इसकी तुलना में 1989-90 के दौरान उसमें 14,814 करोड़ रुपये (22.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। शुक्रवारों को प्राप्त सूचना के औसत के रूप में भी देखा जाए तो एम 1 की 17.6 प्रतिशत विस्तार दर पिछले वर्ष की 20.1 प्रतिशत की तुलना में कम ही थी।

सारणी 6.1 : मुद्रा स्टॉक (एम. 3) में घट बढ़

(करोड़ रुपये)

मदें	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़**							
	1989-90		1990-91*		1990-91 (अप्रैल-जून)		1991-92*	
	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. एम 3 (क+ख+ग)	37,866	19.6	35,904	15.5	10,162	4.4	10,166	3.8
क) जमा के पास चल मुद्रा	8,231	21.4	6,727	14.4	2,494	5.3	3,482	6.5
ख) बैंकों के पास कुल जमा राशि (i+ii)	29,269	18.9	27,823	15.1	7,681	4.2	7,506	3.5
i) मांग जमा राशियाँ	6,217	22.4	5,079	15.0	1,772	5.2	1,793	4.6
ii) मौदादी जमा राशियाँ	23,052	18.2	22,744	15.2	5,909	3.9	5,713	3.3
ग) भारतीय रिजर्व बैंक के पास "अन्य जमा राशियाँ"	366	79.2	1,354	163.5	-13	-1.6	-822	-37.7
II. एम 1 [क+ख (i)+ग]	14,814	22.2	13,160	16.2	4,253	3.2	4,453	4.7
III. मुद्रा स्टॉक के स्त्रोत (एम 3) (1+2+3+4+5)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सरकार को निवल बैंक ऋण (अ+ब)	19,630	20.3	21.483	18.4	9,737	8.4	12,677	9.2
अ. सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण (i+ii)	13,031	21.7	13,594	18.6	6,661	9.1	9,286	10.7
	(ए)		(बी)		(सी)			
i) केन्द्रीय सरकार पर निवल दावे (क+ख)	12,672	21.2	13,955	19.2	7,172	9.9	9,429	10.9
क) केन्द्रीय सरकार पर दावे	12,626	21.1	13,997	19.3	7,259	10.0	9,438	10.9
ख) केन्द्रीय सरकार की जमा राशियाँ	-46	-46.0	42	77.8	87	16.11	9	9.4
ii) राज्य सरकारों पर निवल दावे (क-ख)	359	245.9	-361	-71.5	-511	-101.2	-143	-99.3
क) राज्य सरकारों पर दावे	362	232.1	-359	-69.3	-507	-97.9	-142	-89.3
ख) राज्य सरकारों की जमा-राशियाँ	3	30.0	2	15.4	4	30.8	1	6.7
आ. सरकार को अन्य बैंकों के ऋण	6,599	17.9	7,889	18.2	3,076	7.1	3,391	6.6
2. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	23,183	18.2	21,912	14.6	2,974	2.0	1,667	1.0
क. वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण @	257	5.2	305	5.9	-246	-4.7	-20	-0.4
ख. वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों का ऋण	22,926	18.8	21,607	14.9	3,220	2.2	1,687	1.0
3. बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ (क+ख)	69	1.1	1,429	\$21.7	-352	-5.4	-660\$	-8.2
			(-4,944)\$	(-75.0)\$			(-1,417)\$	(-17.7)\$
क) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ	85	1.4	1,429	23.9	-352	-5.9	-660	-8.9
ख) अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ	-16	-2.7	--	--	--	--	--	--
4. जनता के प्रति सरकार की ऋण-मुद्रा देयताएं	80	5.4	52	3.3	22	1.4	--	--
5. भौयार्दी जमा-राशियों के अलावा बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुदेतर देयताएं (क+ख)	5,096	13.2	8,972	20.5	2,219	5.1	3,518	6.7
क) भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,930	11.8	7,988	\$43.8	203	1.1	1,115	\$4.3
ख) अन्य बैंकों की निवल मुदेतर देयताएं (प्रवर्गित)	3,166	14.2	934	3.9	2,016	7.9	2,403	9.1

\*\*मार्च के अन्तिम शुक्रवार की सूचना पर आधारित।

@ ताबाई की स्थापना से बैंकों को उसका पुनर्वित्त शामिल नहीं।

\*अनंतिम

‡ 722 करोड़ रुपये (क)/325 करोड़ रुपये (ख)/240 करोड़ रुपये (ग) की धनराशि शामिल है जो भंडार को जारी किए गए अपरकाम्य ध्याज रहित प्रतिभूतियों को केन्द्रीय सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के दावों द्वारा प्रतिस्थापन को दर्शाता है ताकि कोष में से पुनःश्रय किया जा सके।

\$ 17 अक्टूबर 1990 में प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लगभग घासपास पुनर्मूल्यन के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल है। ऐसे अधि-मूल्यन का रिजर्व बैंक की निवल मुदेतर निवल देयताओं पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है।

@@ स्वर्ण का पुनर्मूल्यन शामिल नहीं है।

6.4 एम 3 के सभी घटकों अर्थात् चल मुद्रा और मांग तथा मियादी जमा राशियों में 1990-91 के दौरान विस्तार की गति धीमी रही।

6.5 सरकार को निवल बैंक ऋण में यद्यपि सापेक्षिक रूप से न्यूनतम वृद्धि (1989-90 की 20.3 प्रतिशत की तुलना में 18.4 प्रतिशत) हुई लेकिन समग्र रूप में यह वृद्धि पिछले वर्ष के 19,630 करोड़ रुपये के मुकाबले काफी अधिक अर्थात् 21,483 करोड़ रुपये थी। इसमें मुख्य योगदान केन्द्र सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण का रहा जिसमें पिछले वर्ष के 12,672 करोड़ रुपये (21.2 प्रतिशत की तुलना में 13,955 करोड़ रुपये (19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में वित्तीय वर्ष की घट-बढ़ के पाक्षिक आंकड़ों का औसत (मार्च 31 को छोड़कर) 10,167 करोड़ रुपये था जो वर्ष 1989-90 के दौरान के 10,513 करोड़ रुपये के आसपास ही है। वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण में 1990-91 के दौरान 21,912 करोड़ रुपये (14.6 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष हुई 23,183 करोड़ रुपये (18.2 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में कम है। बैंकिंग क्षेत्र को निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1,429 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई जिसका मुख्य कारण स्वर्ण का 17 अक्टूबर, 1990 को प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आसपास पुनः मूल्यांकन करना था। चूंकि ऐसे पुनर्मूल्यांकन का रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताओं (मुद्रा आपूर्ति के लिए एक अवरोधी घटक) पर तदनुरूप प्रभाव पड़ता है, कुल मुद्रा राशि

पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि स्वर्ण के मूल्य में वृद्धि को शामिल नहीं किया गया होता तो 1990-91 में निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में 4,944 करोड़ रुपये की कमी आ गई होती।

6.6 वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 की प्रथम तिमाही (अर्थात् 28 जून, 1991 तक) दौरान एम 3 और एम 1 दोनों के विस्तार की गति 1990-91 की तदनुरूप अवधि की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी रही। हालांकि, सरकार को प्रदत्त निवल बैंक ऋण की राशि उच्चतर थी, वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण की राशि 1990-91 की तदनुरूप अवधि की तुलना में कम थी। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में उल्लेखनीय कमी सतत रूप से बनी रही।

6.7 प्रारक्षित मुद्रा में 1990-91 के दौरान 9,020 करोड़ रुपये (12.2 प्रतिशत) की वृद्धि ही हुई थी। जबकि पिछले वर्ष उसमें 10,830 करोड़ रुपये (17.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। पाक्षिक औसत के आधार पर, प्रारक्षित मुद्रा में हुआ 16.0 प्रतिशत का विस्तार 1989-90 के दौरान हुए 18.2 प्रतिशत के विस्तार की तुलना में कम ही था। यदि घटक बार देखा जाए, तो जनता के पास चल मुद्रा और रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियों में भी कमी आयी जबकि रिजर्व बैंक के पास रहने वाली जमा राशियां और बैंकों के पास नकदी में हुआ विस्तार 1990-91 के दौरान अधिक था (सारणी 6.2)।

सारणी 6.2 : प्रारक्षित मुद्रा में घट-बढ़ घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

सर्वे	निम्नलिखित के दौरान घट-बढ़ ₹			
	1989-90	1990-91*	1990-91 (अप्रैल-जून)	1991-92* (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5
प्रारक्षित मुद्रा (1 + 2 + 3 + 4)	10,830 (17.4)	9,020 (12.3)	5,993 (8.2)	10,193 (12.4)
1. जनता के पास चल मुद्रा	8,231 (21.4)	6,727 (14.4)	2,494 (5.3)	3,482 (6.5)
2. भारतीय रिजर्व बैंक के पास "अस्थ" जमा राशियां	366 (79.2)	1354 (163.5)	- 13 (- 1.6)	- 822 (- 37.7)
3. बैंकों के पास नकदी	167 (9.3)	257 (13.1)	565 (28.9)	398 (18.0)
4. भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशियां	2,066 (9.5)	682 (2.9)	2947 (12.4)	7,135 (29.2)



1	2	3	4	5
प्रारक्षित मुद्रा के स्त्रोत (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 6)				
1. सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण†	13,031(क) (21.7)	13,594(ख) (18.6)	6,661(ग) (9.1)	9286 (10.7)
2. वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के ढावे @	- 693 (- 11.0)	1,627 (28.9)	110 (2.0)	2,703 (37.2)
3. वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक का ऋण	257 (5.2)	305 (5.9)	- 246 (- 4.7)	- 20 (- 0.4)
4. भारतीय रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ	85 (1.4)	1,429** (- 4,944) @ (23.9) (- 75.0) @	- 352 (- 5.9)	- 660** (- 1,417) @ (- 8.9) (- 17.7) @
5. सरकार की षल मुद्रा देयताएं	80 (5.4)	52 (3.3)	22 (1.4)	-- (- )
6. भारतीय रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताएं	1,930 (11.8)	7,987** (43.8)	202 (1.1)	1,116** (4.3)

\* अंतिम

\$ मार्च के अंतिम शुक्रवार की सूचना पर प्राधारित

@ नाबाई सहित

† इसमें (क) 722 रुपये (ख) 325 करोड़ रुपये (ग) 240 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जो आमुको को जारी किय गये अपरक्राम्य ब्याज रहित प्रतिभूतियों को केन्द्रीय सरकार पर भारतीय रिजर्व बैंक के ढावों द्वारा प्रतिस्थापन को दर्शाता है, ताकि कोष से पुनः क्रय किये जा सकें।

\*\* 17 अक्टूबर 1990 से प्रभावी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के लगभग आसपास पुनर्मूल्यान के बाद स्वर्ण के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल है। ऐसे अधि मूल्यान का रिजर्व बैंक की निवल मुद्रा देयताओं पर तबनु रूप प्रभाव पड़ता है।

@ @ स्वर्ण का पुनर्मूल्यान शामिल नहीं है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत घट-बढ़ को दर्शाते हैं।

6.8 प्रारक्षित मुद्रा में संवृद्धि के स्त्रोतों में सरकार को रिजर्व बैंक के निवल ऋण में हुई वृद्धि की राशि 1989-90 के 13,031 करोड़ रुपए (21.7 प्रतिशत) की तुलना में 13,594 करोड़ रुपये (18.6 प्रतिशत) थी। वाणिज्य और सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक के ढावों में पिछले वर्ष आयी कमी के विपरीत इस वर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई।

6.9 अब तक के वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान (अर्थात् 28 जून, 1991 तक) प्रारक्षित मुद्रा में विस्तार की गति 12.4 प्रतिशत रही जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलनीय अवधि के दौरान की गति (8.2 प्रतिशत) से अधिक है। इसके अतिरिक्त, सरकार को प्रदत्त निवल रिजर्व बैंक

ऋण में हुई तीव्र वृद्धि प्रारक्षित मुद्रा में बढ़ोतरी के लिए प्रमुख उत्तरदायी रही है।

6.10 वर्ष 1990-91 के दौरान वाणिज्य और सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सहायता में अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि हुई जिसका कारण यह था कि मांग मुद्रा बाजार धर को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा का अधिक उपयोग किया गया और आस्थिरता में कमी लाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत उन्हें अधिक सहायता उपलब्ध करायी गयी। साथ ही, वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से सीधे ही प्रदान की गई रिजर्व बैंक की सहायता में वृद्धि परिलक्षित होती रही (सारणी 6.3)।

सारणी : 6.3 : बैंकों और वाणिज्यिक क्षेत्र पर रिजर्व बैंक का ढावा

(करोड़ रुपए)

निम्नलिखित के अंत में बकाया	निम्नलिखित पर रिजर्व बैंक के ढावे			
	वाणिज्य और सहकारी बैंक	नाबाई	वित्तगृह	वाणिज्य क्षेत्र (वित्तीय संस्थाएं)
1984-85	1,584	1,219	--	2,765
1988-89	3,937	2,387	51	4,899
1989-90	2,810	2,821	77	5,130
1990-91	3,999	3,259	77	5,435
29 जून, 1990	2,882	2,858	77	4,884
28 जून, 1991	6,63	3,322	77	5,415

## मुद्रा का आय-वेग

6.11 मुद्रा का आय-संचलन वेग, अर्थात् वर्तमान बाजार कीमतों पर सकल देशी उत्पाद का स्थूल मुद्रा (एम 3) के औसत में अनुपात, जिसमें 1970 के दशक के प्रारंभिक काल से ही लगभग लगातार ही दीर्घावधिक गिरावट की

प्रवृत्ति दिखाई दे रही थी, 1989-90 के 2.08 से मामूली सा बढ़कर 1990-91 में 2.09 हो गयी (तालिका 6.4)। भारत में मुद्रा के आय-संचलन वेग में आई निरंतर कमी इस अनुभवसिद्ध स्थापित तथ्य को प्रकट करता है कि इस अवधि के दौरान एम 3 के लिए मांग की वास्तविक आय लोच समरूपता से बहुत अधिक रही है।

सारणी-64 : चलमुद्रा के आय-वेग की प्रवृत्तियाँ, कुल जमा राशियाँ एम 1 और एम 3

वर्ष	औसत* (करोड़ रुपये)					आय संचलन वेग अनुपात		
	मुद्रा	कुल जमा- राशियाँ	एम 1	एम 3	चलमुद्रा	सकल देशी उत्पाद		
						कुल जमा- राशियाँ	एम 1	एम 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1985-86	24058	86714	40824	110016	10.911	3.027	6.430	2.386
1986-87	27011	103261	46835	130527	10.863	2.841	6.265	2.248
1987-88	31410	121451	53866	153133	10.587	2.739	6.174	2.172
1988-89	35842	143136	61688	179361	11.020	2.760	6.403	2.202
1989-90	42539	170035	74113	213148	10.409	2.604	5.974	2.077
1990-91*	49926	197336	87149	248446	10.385	2.627	5.950	2.087

\*वर्ष में शुक्रवारों को प्राप्त सूचना का औसत

अ. प्रवृत्ति

## कुछ मौद्रिक सम्बन्ध

6.12 कुल जमाराशियों में चल मुद्रा की और एम 3 में चल मुद्रा से सम्बंधित प्रमुख मौद्रिक अनुपातों में औसत आधार पर 1990-91 के दौरान उर्ध्वगामी गति थी जो मुख्यतः समूचे वर्ष के दौरान उच्चतर मुद्राकृत समूचे वर्ष के दौरान उच्चतर मुद्राकृत घाटे को प्रदर्शित करता है। मौद्रिक क्षेत्रों में अधोगामी समायोजन को दर्शाने वाले आरक्षित अपेक्षाओं में परिवर्तन के लिए असमायोजित वृद्धिशील मुद्रा गुणक ( $\Delta$ एम 3/ $\Delta$ आर.एम) में अंक दर अंक आधार पर में वृद्धि हुई। किन्तु, औसत आधार पर, इस अनुपात में मामूली सी कमी दिखाई देती है (सारणी 6.5)।

## बैंकिंग चल राशियों में घट-बढ़

6.13 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनों ने समस्त वित्तीय वर्ष 1990-91 (23 मार्च 1990 से 22 मार्च 1991) के दौरान सभी महत्वपूर्ण आयामों में न्यूनतर

संवृद्धि के चिह्न को दर्शाया। कुल जमाराशियों में संवृद्धि भी समग्र तथा प्रतिशतता दोनों ही रूपों में गिरावट आई और उनकी राशि पिछले वर्ष 26,809 करोड़ रुपये (19.1 प्रतिशत) की वृद्धि के मुकाबले इस वर्ष 25,583 करोड़ रुपये (15.34 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। कुल जमा राशियों में हुई वृद्धि अप्रैल 1990 में की गयी ऋणनीति की घोषणा में वर्ष के लिए संसूचित 27,500 करोड़ रुपये के कार्यकारी आकलन से कम थी। यह न्यूनतम वृद्धि मांग और मीयादी दोनों ही जमाराशियों में सुस्पष्ट है।

6.14 वर्ष 1990-91 में बैंक ऋण में विस्तार की गति उल्लेखनीय रूप से घटती रही। खाद्य ऋणों में जहाँ तीव्र वृद्धि हुई वहाँ खाद्येतर ऋणों में समग्र और प्रतिशतता दोनों ही रूपों में काफी कम विस्तार हुआ, और उसकी मांग 1989-90 में 15,497 करोड़ रुपये (18.5 प्रतिशत) के मुकाबले में, 1990-91 में 12,348 करोड़ रुपये (12.4 प्रतिशत) थी, जबकि एक सीमा तक इसका 1990-91 के दौरान कृषि

सारणी 6.5 : मौद्रिक अनुपात - वृद्धिशील

मध्य	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
<b>अंक दर अंक आधार पर</b>						
<b>(वृद्धिशील अनुपात)</b>						
क) चल मुद्रा/कुल जमा राशियाँ	0.174	0.180	0.293	0.193	0.281	0.242
ख) चल मुद्रा/एम 3	0.152	0.152	0.227	0.161	0.217	0.187
ग) कुल जमा राशियाँ/एम 3	0.870	0.844	0.775	0.834	0.773	0.773
घ) स्थूल मुद्रा गुणक (एम 3/वृद्धिशील अनुपात)	2.588	3.233	2.625	3.268	3.496	3.980
ङ) संकीर्ण मुद्रा गुणक (एम 1/वृद्धिशील अनुपात)	0.619	1.090	0.781	0.970	1.368	1.459
च) बैंक की प्रारक्षित मुद्रा/कुल जमा राशियाँ	0.294	0.181	0.201	0.168	0.076	0.034
<b>असत आधार</b>						
<b>वृद्धिशील अनुपात</b>						
क) चल मुद्रा/कुल जमा राशियाँ (चल मुद्रा/असत जमा राशियाँ)	0.181	0.178	0.242	0.204	0.249	0.271
ख) चल मुद्रा/एम 3 (चल मुद्रा/एम 3)	0.154	0.151	0.195	0.169	0.198	0.209
ग) कुल जमा राशियाँ/एम 3 (कुल जमा राशियाँ/एम 3)	0.852	0.848	0.803	0.828	0.796	0.773
घ) स्थूल मुद्रा गुणक (एम 3/वृद्धिशील अनुपात)	3.952	3.156	2.477	3.128	3.191	3.180
ङ) संकीर्ण मुद्रा गुणक (एम 1/वृद्धिशील अनुपात)	1.206	0.972	0.771	0.933	1.173	1.174
च) बैंक की प्रारक्षित मुद्रा/कुल जमा राशियाँ (अनुपात/कुल जमा राशियाँ)	0.123	0.194	0.257	0.178	0.135	0.117

टिप्पणी : अंक दर अंक आधार पर निकाले गए अनुपात मार्च के अंतिम शुक्रवार की रिपोर्ट पर आधारित हैं जबकि असत आधार के अनुपात वर्ष में रिपोर्ट किए गए शुक्रवारों की सूचना के असत के आधार पर निकाले गए हैं। इस सारणी के सभी अनुपात वृद्धिशील अनुपात हैं।

और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाले गए 3,770 करोड़ रुपये की राशि के साथ संयुक्त रूप से मूल्यांकन किया जाना है। एक हृष तक, इसे सामान्यतः अर्थव्यवस्था की निम्नतर क्रम की संवृद्धि की पृष्ठ भूमि के साथ-साथ कंपनी क्षेत्र के बेहतर कार्यनिष्पादन की तुलना में भी देखा जाना है जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष संसाधनों का अधिक मात्रा में आंतरिक सृजन हुआ था।

6.15 सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेशों में 1990-91 में हुई 10,696 करोड़ रुपये की वृद्धि 1989-90 की 9,707 करोड़ रुपये की वृद्धि से अधिक थी। रिजर्व बैंक में रहने वाली बैंकों की जमाशेष में पिछले वर्ष हुई, 2,087 करोड़ रुपये की भारी वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 398 करोड़ रुपये की न्यूनतर वृद्धि हुई (बड़ी मात्रा के ये अन्तर एक पखवाड़े से दूसरे पखवाड़े के बीच रिपोर्ट किए जाने वाले शुक्रवार के आंकड़ों में घट-बढ़ को प्रदर्शित करते हैं और प्रारक्षित नकदी निधि संबंधी अपेक्षाओं से सम्बन्धित नीति की स्थिति को प्रकट नहीं करते। बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए गए उधारों में 1,069 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज हुई जब कि इसके विपरीत, पिछले वर्ष उनमें 1,128 करोड़ रुपये की गिरावट आई थी (सारणी-6.6)।

मौद्रिक चल राशियों में वर्ष के अंत में वृद्धि

6.16 अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ताह में कुल जमा राशियों और ऋणों में असामान्य

रूप से काफी वृद्धि की सूचना देते आ रहे हैं, वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान, यह प्रवृत्ति बढ़ी। इस प्रकार, 22 मार्च 1991 से 31 मार्च 1991 तक की नौ दिनों की अवधि में ही कुल जमा राशियों में 12,232 करोड़ रुपये (6.4 प्रतिशत) की और बैंक ऋण में 7,134 करोड़ रुपये (6.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 1989-90 की इसी अवधि के दौरान कुल जमा राशियों में 8,434 करोड़ रुपये (5.1 प्रतिशत) की और बैंक ऋणों में 5,182 करोड़ रुपये (5.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। मार्च 1991 के अंतिम सप्ताह में, मांग जमा राशियों के संदर्भ में हुई, 7,329 करोड़ रुपये (22.1 प्रतिशत) की वृद्धि अधिक ही रही, जो कि 1989-90 में इसी अवधि के दौरान हुई 5,538 करोड़ रुपये (19.2 प्रतिशत) तुलना में विशेष रूप से अधिक है। कुल जमा राशियों में हुई उक्त वृद्धि 1990-91 के समस्त वर्ष के दौरान शुक्रवार को दी गई सूचनाओं के आधार पर जमा राशियों में हुई वृद्धि के 47.8 प्रतिशत की छोटकरी है, और इस अवधि के दौरान मांग जमा राशियों में हुई वृद्धि काफी अधिक अर्थात् 169 प्रतिशत तक थी (सारणी 6.7)। 30 मार्च 1991 और 31 मार्च 1991 को दो दिन की अवधि के दौरान जमा वृद्धि में आयी सर्वाधिक तेजी चौकाने वाली बात थी। कुल जमा राशियों में इन दो ही दिनों में 3,575 करोड़ रुपये (1.8 प्रतिशत) और बैंक ऋण के सम्बन्ध में 1,570 करोड़ रुपये (1.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि एक ही दिन में अर्थात् 30 मार्च, 1990, 31 मार्च 1990 के बीच, कुल जमा राशियों में हुई।

## सारणी 6.6 : महत्वपूर्ण बैंकिंग संसूचक - अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ रुपये)

मर्दाने	निम्नलिखित तारीखों को बकाया						घट-बढ़		
	34 मार्च	23 मार्च	22 मार्च	29 जून	28 जून	वित्तीय वर्ष के दौरान घट-बढ़	1990-91 अप्रैल से जून	1991-92 अप्रैल से जून	
	1989	1990	1991	1990	1991*	1989-90 1990-91			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. कुल मांग और मीयादी देयताएं (भारिबै/भाभी-विबै/ताबाई से किए गये उधार को छोड़कर)	156,637	185,845	212,086	192,349	218,446	29,208	26,241	6,504	6,360
2. कुल जमा राशियां (क+ख)	140,150	166,959	192,542	173,088	198,753	26,809 (19.1)	25,583 (15.3)	6,129 (3.7)	6,211 (3.2)
(क) मांग जमा राशियां	23,342	28,856	33,193	29,946	34,354	5,514 (23.6)	4,337 (15.0)	1,090 (3.8)	1,161 (3.5)
(ख) मावधि जमा राशियां	116,808	138,103	159,349	143,142	164,399	21,295 (18.2)	21,246 (15.4)	5,039 (3.6)	5,050 (3.2)
3. भारिबै से उधार	3,527	2,399	3,468	2,458	6,104	-1128 (-32.0)	1069 (44.6)	59 (2.5)	2,636 (76.0)
4. बैंक ऋण (क+ख)	84,719	101,453	116,301	104,011	117,552	16,734 (19.8)	14,848 (14.6)	2,558 (2.5)	1,251 (1.1)
(क) खाद्य ऋण	769	2,006	4,506	3,917	5,317	1237	2,500	1911	811
(ख) खाद्येतर ऋण	83,950	99,447	111,795	100,094	112,235	15,497 (18.5)	12,348 (12.4)	647 (0.7)	440 (0.4)
5. निवेश (क+ख)	54,662	64,369	75,065	67,568	78,248	9,707 (17.8)	10,696 (16.6)	3,199 (5.0)	3,183 (4.2)
(क) सरकारी प्रतिभूतियां	35,815	42,292	49,998	45,321	53,401	6,477 (18.1)	7,706 (18.2)	3,029 (7.2)	3,403 (6.8)
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	18,847	22,077	25,067	22,247	24,847	3,230 (17.1)	2,990 (13.5)	170 (0.8)	-220 (-0.9)
6. हाथ में नकदी	1,444	1,648	1,804	2,100	2,069	204	156	452	265
7. भारिबै के पास जमाशेष	21,376	23,463	23,861	26,026	30,790	2,087 (9.8)	308 (1.7)	2,563 (10.9)	6,929 (29.0)
8. ऋण जमा अनुपात (प्रतिशत)	60.4	60.8	60.4	60.1	59.1				
9. खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	59.9	59.6	58.1	57.8	56.5				

\* अनंतिम

टिप्पणी :

- कोष्ठकों में दिए आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ को दर्शाते हैं।
- आंकड़ों को पूर्णकृत किए जाने की वजह से घटक मदों के योग कुल जोड़ के साथ मेल नहीं खाएंगे।
- सकारात्मक घट-बढ़ के लिए कोई चिह्न नहीं दिया गया है।

संख्या 6.7. प्रयुक्त वाणिज्य बैंकों की वृद्धि मंदी में घट-बढ़ : मार्च 1991 के अंतिम माताह के आंकड़े

(करोड़ रुपये)

मंदी	निम्नलिखित तिथियों की वृद्धि						घट-बढ़					
	23 मार्च	22 मार्च	29 मार्च	21 मार्च	5 अप्रैल	19 अप्रैल	23 मार्च	22 मार्च	29 मार्च	22 मार्च	31 मार्च	5 अप्रैल
	1990	1991	1991	1991	1991	1991	1990 की तुलना में 23 मार्च 1991	1991 की तुलना में 29 मार्च 1991	1991 की तुलना में 31 मार्च 1991	1991 की तुलना में 31 मार्च 1991	1991 की तुलना में 5 अप्रैल 1991	1991 की तुलना में 19 अप्रैल 1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. कुल जमा राजियाँ (क + ख)	166959	192342	201199	204774	198069	195979	25583 (-15.3) [33.8]	8657 (4.5) [33.8]	3575 (1.8) [14.0]	12232 (6.4) [47.8]	-6705 (-3.3)	-2090 (-1.1)
(क) सांग जमा	28556	33193	38300	40522	35254	33845	4337 (15.0) [4117.8]	5107 (15.4) [4117.8]	2222 (5.8) [51.2]	7329 (22.1) [169.0]	-5268 (-13.0)	-1409 (-4.0)
(ख) भौयादी जमा	138103	159349	162899	164252	162815	162134	21246 (15.4) [16.7]	3550 (2.2) [16.7]	1353 (0.8) [6.4]	4903 (3.1) [23.1]	-1437 (-0.9)	-681 (-0.4)
2. बैंक ऋण (क + ख)	101453	166301	121865	123435	118376	118395	14848 (14.6) [37.5]	5564 (4.8) [37.5]	1570 (1.3) [10.6]	7134 (6.1) [48.0]	-5059 (-4.1)	19 (0.0)
(क) खाद्य ऋण	2006	4506	4569	4569	4141	4391	2500 (124.6) [2.5]	63 (1.4) [2.5]	0 (0.0) [0.0]	63 (1.4) [2.5]	-128 (-2.8)	-50 (-1.1)
(ख) खाद्येतर ऋण	99447	111795	117296	118866	113935	114004	12348 (12.4) [44.5]	5501 (4.9) [44.5]	1570 (1.3) [12.7]	7071 (6.3) [57.3]	-4931 (-4.1)	69 (0.1)

\* अन्तिम

टिप्पणी :

1. कोष्टको में दिए गये आंकड़े प्रतिवर्त घट-बढ़ को दर्शाते हैं।
2. चौकोर कोष्टको में दिये गये आंकड़े परिशुद्ध घट-बढ़ को वित्तीय वर्ष की घट-बढ़ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाते हैं।
3. सकारात्मक घट-बढ़ के लिये कोई चिन्ह नहीं दिया गया है।

1,185 करोड़ रुपए (1.1 प्रतिशत) की वृद्धि से तुलनीय है। जैसा कि पिछले दो वर्षों में हुआ है, इस वर्ष भी मार्च के अंतिम सप्ताह में जमा राशियों में आई असामान्य वृद्धि को बनाए नहीं रखा जा सका, जो कि 5 अप्रैल, 1991 को समाप्त होने वाले तुरंत बाद के सप्ताह में तथा 19 अप्रैल 1991 को समाप्त पंद्रहवाड़े में जमा राशियों में तेजी से आई कमी से स्पष्ट है, जब कुल जमा राशियों क्रमशः 6,705 करोड़ रुपए और 2,090 करोड़ रुपए की कमी आई और इस प्रकार मार्च 1991 के अंतिम सप्ताह के दौरान जमा राशियों में हुई वृद्धि के 72 प्रतिशत से निष्प्रभावी हो गयी। मार्च के अंत में बैंक की कुल जमा राशियों में इन वृद्धियों का एक आंशिक कारण सार्वजनिक क्षेत्र के गैंगठनों और सरकारी विभागों द्वारा वर्ष के अंत में खातों का समायोजन, धाज का लागू होना तथा जमा राशियों की वृद्धि के आधार पर प्रत्येक बैंक की शाखा के कार्य को प्रस्तुत करने की बैंक प्रबंधकों की चिंता थी। जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भी बताया गया था, 1990-91 में बैंकिंग एकल जमा राशियों में वर्ष के अंत में भारी वृद्धि इस बात पर पुनः बल देती है कि 31 मार्च के आंकड़े मूलभूत अतर्निहित बैंकिंग की गतिविधियों के आकलन के प्रयोजनों के लिए अर्थवान नहीं हैं और इसीलिए इस रिपोर्ट में बैंकिंग विश्लेषण अंतिम एकवार को प्राप्त सूचना के आंकड़ों पर आधारित है, न कि 31 मार्च को प्राप्त आंकड़ों पर।

#### 1991-92 की पहली तिमाही में प्रवृत्तियाँ

6.17 वर्ष 1991-92 की पहली तिमाही के दौरान, जमा राशियों में 6,211 करोड़ रुपए (3.2 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो 1990-91 में इसी अवधि के दौरान हुई 6,129 करोड़ रुपए (3.7 प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में थी। बैंक ऋण में 1,251 करोड़ रुपए (1.1 प्रतिशत) का हुआ विस्तार पिछले वर्ष में हुए 2,558 करोड़ रुपए (2.5 प्रतिशत) के विस्तार से काफी कम है।

#### ऋण का क्षेत्रवार वितरण

6.18 राजकोषीय वर्ष 1990-91 के दौरान, वृद्धिशील सकल बैंक ऋण की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन पाया गया। खाद्यान्न वस्ती एजेंसियों को दिए जा रहे ऋणों में तेजी से वृद्धि आई। खाद्येतर ऋण के विस्तार में आई गिरावट का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदत्त अग्रियों के मामले में ऐसी गिरावट अधिक सुस्पष्ट थी किन्तु आमतौर पर कुछ उसका स्वरूप तकनीकी था तथा ग्रामीण ऋणों को बड़े खाते डाला गया। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बैंक ऋण में हुई वृद्धि की राशि 2,497 करोड़ रुपए वृद्धिशील सकल बैंक ऋण का (19.9 प्रतिशत) थी, जो पिछले वर्ष 6,164 करोड़ रुपए (39.2 प्रतिशत) आंकड़ों से बहुत ही कम है। मार्च 1991 के अंत में निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र को प्रदत्त बकाया ऋण का अंश 39.2 प्रतिशत रहा, जो कि लक्ष्य के करीब ही है, तथापि, यह पिछले वर्ष के 42.4 प्रतिशत

के स्तर से कम है। ग्रामीण ऋणों को बड़े खाते डालने के कारण इस क्षेत्र का बकाया ऋण स्तर कम हो गया और इस प्रकार आंकड़ों के अनुसार कृषि क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में मात्र 230 करोड़ रुपए की वृद्धि (1.8 प्रतिशत) हुई जबकि 1989-90 के दौरान उसमें 2,576 करोड़ रुपए (16.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। मझौले और बड़े उद्योगों को सकल बैंक ऋण में पिछले वर्ष हुई 0.077 करोड़ रुपए की वृद्धि की तुलना में इस वर्ष 6,163 करोड़ रुपए का विस्तार हुआ। तथापि, वृद्धिशील खाद्येतर ऋणों में इसका काफी अधिक प्रतिशत हिस्सा था जो 1989-90 के केवल 38.7 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 49.1 प्रतिशत था। “अन्य क्षेत्रों” (जो कि शेष वर्ग है और जिसमें वित्तीय संस्थाओं, किराया खरीद एजेंसियों, पट्टे पर देने वाली कम्पनियों, आवास वित्त इत्यादि शामिल है) ने पिछले वर्ष के 2,760 करोड़ रुपए (17.6 प्रतिशत) की तुलना में 3,480 करोड़ रुपए (27.7 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी है (सारणी 6.8)।

6.19 बैंक ऋण का उद्योगवार (लघु, मझौले और बड़े) विप्लेषण यह तथ्य प्रकट करता है कि इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात तथा अन्य वस्त्र उद्योगों, कागज और कागज के उत्पादों, रबड़ और रबड़ के उत्पादों, सीमेंट, निर्माण कार्य और रत्न तथा आभूषणों को प्रदत्त बैंक अग्रियों में 1990-91 के (अप्रैल-मार्च) दौरान काफी गिरावट पायी गयी जबकि रासायनिक वस्तुओं, रंजकों तथा पेंटों आदि कोयला, अन्य धातुओं और धातु उत्पादों तथा वनस्पति तेलों (वनस्पति सहित) को प्रदत्त ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज हुई। बिजली (100 करोड़ रुपए) तथा नयी योजना के अंतर्गत विदेशों से प्राप्त जहाज (62 करोड़ रुपए) के मामले में ऋणों में भारी गिरावट आई। 1990-91 के (अप्रैल-मार्च) दौरान जिन उद्योगों को ऋण विस्तार का बड़ा भाग मिला वे थे—सभी इंजीनियरिंग उद्योग (1,430 करोड़ रुपए), रासायनिक, रंजक और पेंट इत्यादि (931 करोड़ रुपए), अन्य वस्त्र उद्योग (459 करोड़ रुपए); लोहा और इस्पात (442 करोड़ रुपए), सूती वस्त्र उद्योग (404 करोड़ रुपए), अन्य धातुएं और धातु उत्पाद (378 करोड़ रुपए) और निर्माण कार्य (223 करोड़ रुपए) (सारणी-6.9)।

#### भारतीय रिजर्व बैंक पुनर्वित्त

##### (i) निर्यात ऋण पुनर्वित्त

6.2029 जून 1990 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त संभाएँ 4,118.2 करोड़ रुपए की राशि की रहीं (बकाया निर्यात ऋण का 46.3 प्रतिशत) जब निर्यात ऋण पुनर्वित्त संभाओं को निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए अपनाए गए आधार को 25 अगस्त 1990 से कैलेंडर वर्ष 1987 के बजाए वित्तीय वर्ष 1988-89 के बकाया निर्यात ऋण का मासिक औसत स्तर बनाया गया, तो बकाया निर्यात ऋणों में निर्यात पुनर्वित्त संभाओं का अनुपात 24 अगस्त, 1990 के 44.1 प्रतिशत से घटकर 7 सितम्बर

1990 को 32.6 प्रतिशत रह गया। 1 जनवरी 1991 से प्रभावी, निर्यात ऋण पुनर्वित्त अनुपात को 1988-89 के लिए बकाया निर्यात ऋण के मासिक औसत स्तर की

तुलना में उनमें हुई वृद्धि के 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप, बैंकों की निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाएं 28 दिसम्बर 1990

सारणी 6, 8 : प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर कम बैंक ऋण का क्षेत्रीय विस्तार\*

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	निम्नलिखित को बकाया			निम्नलिखित के दौरान	
	24 मार्च	23 मार्च	22 मार्च	(वित्तीय वर्ष)	
	1989	1990	1991	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
(I) सकल बैंक ऋण (1 + 2)	85,728	102,671	1,17,723	+16,943	+15,052
1. सार्वजनिक खाद्य वस्तुओं का ऋण	769	2,006	4,506	+1,237	+2,500
2. खाद्योत्तर सकल बैंक ऋण	84,959	1,00,665	1,13,217	+15,706	+12,352
				(+100.0)	(+100.0)
(अ) प्राथमिक क्षेत्र	34,219	40,383	42,880	+6,164	+2,497
	[43.2]	[42.4]	[39.2]	(+39.2)	(+19.9)
(i) कृषि	13,950	16,526	16,756	+2,576	+230
	[17.6]	[17.4]	[15.3]	(-16.5)	(+1.8)
(ii) मधु उद्योग	13,135	15,543	17,151	+2,408	+1,608
				(+15.3)	(+12.8)
(ii) अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	7,134	8,314	8,973	+1,180	+659
				(+7.5)	(+9.3)
(आ) उद्योग (महाशिला और बड़े)	32,185	38,262	44,425	+6,077	+6,164
				(+38.7)	(+49.1)
(इ) बाक व्यापार (खाद्यान्न वस्तुओं के अतिरिक्त)	4,767	5,472	5,884	+705	+412
				(+4.5)	(+3.3)
(i) भारतीय रई निगम	37	140	91	+103	-49
				(+0.7)	(-0.3)
(ii) भारतीय खाद्य निगम—उर्ध्वक वितरण के लिए	202	230	212	+28	-18
				(+0.2)	(-0.1)
(iii) भारतीय जूट कारपोरेशन	98	54	62	-44	+8
				(-0.3)	(-)
(iv) अन्य व्यापार	4,430	5,048	5,519	+618	+471
				(+3.9)	(+3.7)
(ई) अन्य क्षेत्र	13,788	16,548	20,028	+2,760	+3,480
				(+17.6)	(+27.7)
(II) निर्मित ऋण (मद-2 के अन्तर्गत शामिल)	6,141	8,245	9,153	+2,104	+908
(III) निवल बैंक ऋण—	79,234	95,132	1,09,283	+15,898	+14,151
(ग्रन्थ: बैंकीय सहभागिता सहित)					

\*समंतिम

टिप्पणी :

- ये आंकड़े 50 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (विलय के कारण मार्च 1990 से 49 और अगस्त 1990 से 48) सम्बन्धित हैं, जो कि सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए लगभग 95 प्रतिशत बैंक ऋण को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त इन सकल बैंक ऋण में भारतीय, अष्टौबीबीआई, निर्यात-आयात बैंक, अन्य अनुमोदित विदेशी संस्थाओं और अंतः बैंक सहभागिता के साथ पुनः मुद्राएँ गण किये की भी शामिल किया गया है।
- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वृद्धिशील खाद्योत्तर सकल बैंक ऋण को समानुपाती हैं।
- बोकोर कोष्ठकों में दिए गये आंकड़े मद III में दिए निवल बैंक ऋण (अंतः बैंकीय सहभागिता सहित) के समानुपाती हैं।

सारणी 6.9 : सकल बैंक ऋण का उद्योगवार विवरण\*

(करोड़ रुपये)

उद्योग	निम्नलिखित की वकाया			निम्नलिखित के	
				बौरान घट-बढ़	
	24 मार्च 1989	23 मार्च 1990	22 मार्च 1991	(वित्तीय वर्ष) 1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
<b>उद्योग</b>	<b>45,320</b>	<b>53,805</b>	<b>61,576</b>	<b>+ 8,485</b>	<b>+ 7,711</b>
(सबू, मशीने और बड़े उद्योगों का जोड़)					
1. कोयला	210	178	241	-32	+ 63
2. लोहा	2,245	2,835	3,277	+ 590	+ 442
3. अन्य धातुएं तथा धातु उत्पाद	1624	1,838	2,216	+ 214	+ 378
4. सभी इंजीनियरी उनमें से : इलेक्ट्रॉनिक्स	10623 ( 677)	12,509 ( 1,290)	13,939 ( 1,852)	+ 1,886 ( + 613)	+ 1,430 ( + 562)
5. बिजली	1,042	1,258	1,158	+ 216	-100
6. सूती वस्त्र	3,216	3,659	4,063	+ 443	+ 404
7. जूट वस्त्र	276	340	348	+ 64	+ 8
8. अन्य वस्त्र	2,742	3,297	3,756	+ 555	+ 459
चीनी	669	647	624	-22	-23
10. चाय	524	571	575	+ 47	+ 4
11. खाद्यान्न संसाधन	469	1,056	1,214	+ 587	+ 158
12. वनस्पति तेल (वनस्पति सहित)	599	700	864	+ 101	+ 164
13. तम्बाकू और तम्बाकू के उत्पाद	297	379	392	+ 82	+ 13
14. कागज और कागज के उत्पाद	1,142	1,346	1,478	+ 204	+ 132
15. रबर और रबर के उत्पाद	750	912	982	+ 162	+ 70
16. रसायन रंजक, पेंट आदि उनमें से :	5,922	6,785	7,716	+ 863	+ 931
(i) उर्वरक	( 1,019)	( 1,075)	( 1,298)	( + 56)	( + 223)
(ii) पेट्रो रसायन	( 339)	( 681)	( 681)	( + 342)	( -)
(iii) तवाइयाँ और औषधियाँ	( 452)	( 1,013)	( 989)	( + 561)	( -24)
17. सीमेंट	689	843	899	+ 154	+ 56
18. लकड़ा और लकड़े के उत्पाद	691	931	996	+ 240	+ 65
19. हीरे और प्राकृषण	483	1,214	1,242	+ 731	+ 28
20. विनिर्माण	759	1,091	1,314	+ 332	+ 223
21. पेट्रोलियम	30	137	54	+ 107	-53
22. नयी योजना के अन्तर्गत विदेशों से लिये गये जहाज	191	149	87	- 42	-62
23. अन्य उद्योग	10,127	11,130	14,141	+ 1,003	+ 3,011

\*अंशतः



बढ़कर 11 जनवरी, 1991 को 3,977 करोड़ रुपए हो गई। तदनुसार, निर्यात—ऋण निर्यात पुनर्वित्त सीमाओं का अनुपात भी 28 दिसम्बर 1990 के 32.6 प्रतिशत से बढ़कर 11 जनवरी 1991 को 43.4 प्रतिशत हो गया। बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमाओं की राशि 28 जून 1991 को 5,222 करोड़ रुपए (बकाया निर्यात ऋण का 52.6 प्रतिशत)। 29 जून 1990 से 28 जून 1991 तक की अवधि के दौरान, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत किये गये अधिकतम पाक्षिक औसत उपयोग की राशि 14 जून 1991 को समाप्त पखवाड़े के दौरान जहाँ 5,168 करोड़ रुपए थी, वहाँ उपयोग का दैनिक शिखर स्तर 5,203 करोड़ रुपए, कुल सीमा का 98.2 प्रतिशत था जो कि इसी पखवाड़े में पाया गया।

### (ii) आपाती पुनर्वित्त

6.21 29 जून 1990 से 28 जून 1991 तक की अवधि के दौरान, 3 बैंकों को 2 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए के बीच की आपाती पुनर्वित्त सीमाएं प्रदान की गयीं।

### (iii) विवेकाधीन पुनर्वित्त

6.22 मांग मुद्रा दर की अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने अधिक मात्रा में अपनी विवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करायी। बैंकों को मंजूर की गयी विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं की राशि 30 नवम्बर 1990 के 1,631 करोड़ रुपए से घटकर दिसम्बर 1990 के अंत में 898 करोड़ रुपए हो गयी। महंगी चलमुद्रा का प्रभाव उच्च दरों में परिलक्षित हुआ और इन दरों को कम करने के लिए स्वीकृत सीमाओं को बढ़ाकर 8 मार्च 1991 को 2,181

करोड़ रुपए तथा 19 अप्रैल 1991 को 4,987 करोड़ रुपए कर दिया गया। उसके पश्चात् मांग मुद्रा दरों में गिरावट आने के साथ-साथ इन सीमाओं में उल्लेखनीय कमी आयी और वह 28 जून 1991 को 2,432 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गयी (सारणी 6.10)। इस सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि 18 अप्रैल 1991 को 4,677 करोड़ रुपए के शिखर स्तर पर पहुंच गयी। (यह राशि स्वीकृत सीमाओं का 93.8 प्रतिशत थी) (सारणी 6.11)। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह सूचित किया गया कि केवल अल्प अवधि के लिए ही विवेकाधीन पुनर्वित्त को यह मात्रा प्रदान की जाए, अन्यथा मुद्रा नीति के स्थूल उद्देश्यों में कमी आ जाएगी और इसलिए इन अपेक्षाकृत बड़ी विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं को क्रमिक रूप से कम करना होगा तदनुसार, विवेकाधीन पुनर्वित्त सीमाओं की राशि को 28 जून, 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए क्रमशः कम करते हुए 2,432.02 करोड़ रुपए कर दिया गया।

### पुनर्वित्त की समग्र स्थिति

6.23 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत प्रदत्त कुल सीमाओं (नौवहन ऋणों, शुल्क वापसी, आदि पर दिए गए विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर) की कुल राशि 29 जून 1990 को 4,992 करोड़ रुपए थी।

इन बैंकों को मंजूर की गयी कुल सीमाओं की राशि 19 अप्रैल 1991 तक तेजी से बढ़कर 9,911 करोड़ रुपए हो गयी, जो 1 जुलाई, 1990 से 28 जून 1991 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत सीमाओं का शिखर स्तर थी। उक्त तारीख तक प्रयुक्त कुल राशि 9,113 करोड़ रुपए (92.0 प्रतिशत) थी। कुल पुनर्वित्त सीमाओं में निर्यात

सारणी 6.10 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की भारतीय रिजर्व बैंक की वित्तीय सहायता (नौवहन ऋणों, शुल्क वापसी, आदि पर प्रदत्त विशेष पुनर्वित्त को छोड़कर)

(करोड़ रुपये)

मिम्नलिखित के सूचना देने के लिए अंतिम शुक्रवार की	निर्यात ऋण पुनर्वित्त		आपाती पुनर्वित्त		विवेकाधीन पुनर्वित्त		182 टिक्कीय खजाना विम पुनर्वित्त		कुल पुनर्वित्त	
	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया	सीमा	बकाया
1990										
मार्च	3,564.00	2133.41	..	..	476.17	85.16	209.73	2.50	4,249.90	2,221.07
अप्रैल	3,782.58	2,652.58	5.00	..	508.75	89.68	223.26	..	4,519.59	2,742.26
मई	4,057.73	3,716.41	22.00	20.00	510.94	186.73	268.01	2.50	4,858.68	3,925.63
जून	4,118.15	2,338.45	11.00	9.00	433.13	..	429.75	..	4,992.03	2,347.45
सितम्बर	2,697.71	1,211.67	11.00	9.00	479.54	..	668.14	22.50	3,856.39	1,243.17
दिसम्बर	2,717.52	1,641.77	18.00	..	898.26	29.74	560.49	3.50	4,194.27	1,674.01
1991										
मार्च	4129.08	2812.25	..	..	3225.97	533.97	210.93	..	7565.98	3346.22
अप्रैल	4575.76	4448.34	..	..	4987.00	4655.00	348.03	10.00	9910.79	9113.34
मई	5111.06	3167.57	..	..	3065.76	120.00	291.38	37.50	8498.20	3383.07
जून	5222.10	4467.98	..	..	2432.02	1546.33	555.10	..	8209.22	6014.31

## सारणी 6.11 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की प्रदत्त मरकेड विवेकाधीन पुनर्वित्त

( करोड़ रुपये )

निम्नलिखित तारीख को समाप्त होने वाले अंतिम शुक्रवार को		सीमाएं	पञ्चवारों के दौरान बकाया शिफ्टिंग राशि
अक्तूबर	5, 1990	609.23	330.02
	19, 1990	1,599.73	1,410.98
नवंबर	2, 1990	1,587.80	1,331.81
	16, 1990	1,561.73	1,282.62
	30, 1990	1,630.76	1,330.46
दिसम्बर	14, 1990	946.65	94.82
	28, 1990	898.26	415.34
जनवरी	11, 1991	1,824.32	1,352.82
	23, 1991	2,402.99	1,961.60
फरवरी	6, 1991	2,349.07	1,469.85
	22, 1991	2,164.03	1,908.51
मार्च	8, 1991	2,180.56	1,882.25
	22, 1991	3,175.97	3,106.97
अप्रैल	5, 1991	4,747.00	4,325.00
	19, 1991	4,987.00	4,677.00
मई	3, 1991	3,917.20	3,841.38
	17, 1991	3,368.75	3,299.58
	31, 1991	3,085.76	2,956.11
जून	14, 1991	2,759.45	2,620.51
	28, 1991	2,432.02	2,312.03
जुलाई	12, 1991	2,338.99	2,109.03
	26, 1991	2,128.37	1,839.07
अगस्त	9, 1991	2,095.60	1,530.89

ऋण पुनर्वित्त सीमाओं का अनुपात काफी अधिक (63.6 प्रतिशत) था। (सारणी 6.10)।

## ऋण वजट

6.24 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 56 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वर्ष 1990-91 ऋण-वजटों की जांच की गयी। 21 सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 3 विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ जून-अगस्त 1990 के दौरान विचार-विमर्श किए गए। इन विचार-विमर्शों के दौरान बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे वर्ष 1990-91 के लिए बैंकिंग प्रणाली को कुल जमा राशियों में परियोजित वृद्धि में अपने बाजार घंण के आधार पर अपने ऋण संबंधी गति-विधियों की योजना करें। दूसरे बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे वृद्धिशील मुख्य खाद्योत्पाद ऋण-जमा अनुपात को 23 माघे 1990 को आधार मानते हुए 1990-91 के पूरे वर्ष के दौरान 60 प्रतिशत के भीतर सामित करने संबंधी लक्ष्य का कड़ाई से पालन करें। तीसरे, उन्हें यह सुनिश्चित

करने के लिए सूचित किया गया कि उनके ऋण संबंधी कार्यक्रमों उनके स्वयं के स्थायी संसाधनों के अनुरूप थे और वे अधिक मात्रा में ऋण प्रदान करने तथा अस्थिर मुद्रा बाजार की निधियों पर अधिक मात्रा में निर्भर रहने से बचें। चौथे बैंकों को यह संकेत दिया कि जिस सीमा तक उनकी देयताएं अस्थिर या अस्थायी स्वरूप की थीं, यदि 182 विवसीय खजाना बिलों जैसे अल्प परिपक्वता अवधि वाली और लगभग चल आस्तियों के समतुल्य संविभाग होने से उनके काम में बाधा नहीं आयी। पांचवें, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि जमा प्रमाणपत्र जारी करते समय दी जाने वाली ब्याज दर जारी किए जाने वाले लिखत की परिपक्वता अवधि के अनुरूप है। अंत में, बैंकों से इस बात से बाज आने के लिए आग्रह किया गया कि मार्च के अंत के समय अपनी जमा राशियों खाद्योत्पाद ऋणों में ऊपरी विखावट दिखाने के लिए वृद्धि न की जाए क्योंकि जमा राशियों और खाद्योत्पाद ऋणों में की जाने वाली ऐसी वृद्धियां बैंकिंग तंत्र की वास्तविक गति-विधियों की योजना नहीं होतीं।

वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण जमा अनुपात की प्रवृत्तियाँ

6.25 राजकीयीय वर्ष 1989-90 के लिए मूलतः नवम्बर 1989 में लागू किया गया 60 प्रतिशत का वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात का उपाय राजकीयीय वर्ष 1990-91 के लिए भी जारी रखा गया, तथापि, ऐसे अनुपात के संगणन के लिए आधार को 23 मार्च 1990 तक आगे ले जाया गया। वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च) में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 48.3 प्रतिशत निकलता है। तथापि, यदि कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के अंतर्गत/कृषि/अन्य ऋणों को बढ़े खाता डालने के संदर्भ में खाद्येतर ऋण के आंकड़ों में समायोजन किया जाता है, तो वर्ष 1990-91 में वृद्धिशील शुद्ध खाद्येतर ऋण-जमा अनुपात 58.4 प्रतिशत होगा, जबकि वर्ष 1989-90 में वह 57.8 प्रतिशत था। 23 मार्च

1990 से 22 मार्च 1991 तक के पूरे वर्ष के लिए संचयन बने वाले 74 अनुसूचित वाणिज्य बैंक में से 13 बैंकों का अनुपात निर्धारित 60 प्रतिशत में अधिक था और उनका अतिरिक्त ऋणों की कुल राशि 732 करोड़ रुपए थी।

अल्पावधि मुद्रा बाजार प्रवृत्तियाँ

6.26 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुद्रा बाजार की प्रवृत्तियों को नीचे वर्णित किया है :

भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लि. (वित्त. गृह)

6.27 मांग मुद्रा बाजार और अन्य अल्पावधि मुद्रा बाजार की लिखतों में भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह (वित्त गृह) का वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान कुल संचयी आवर्त पिछले वर्ष के मुकाबले उल्लेखनीय रूप से अधिक था, जैसा कि सारणी 6.12 में दर्शाया गया है।

सारणी-6.12 : राजकीयीय वर्ष की अवधि के दौरान मुद्रा बाजार लिखतों में भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह का संचयी आवर्त

लिखित (1)	(करोड़ रुपये)	
	1989-90 (2)	1990-91 (3)
1. मांग और नोटिस निधियाँ	88,577	2,02,792
2. 182 दिवसीय खजाना बिल	21,953	32,329
3. वाणिज्यिक बिल	10,682	12,675
4. जमा प्रमाणपत्र	3	8
5. वाणिज्यिक पत्र	26	107
6. मीमांसा जमा राशियाँ	244	3,532

6.28 भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह की औसत दैनिक मांग मुद्रा उधार राशि में 1990-91 में 546 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जबकि 1989-90 में उसमें 240 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। वर्ष 1990-91 के दौरान वित्त गृह अपनी मियादी ऋणों के संवितरणों में भी पर्याप्त वृद्धि कर पाया था। वित्त गृह ने 182 दिवसीय खजाना बिलों और वाणिज्यिक बिलों के संचयी आवर्त में भी काफी वृद्धि की थी, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली को चल निधि उपलब्ध हुई। आलोच्य वर्ष के दौरान वित्त गृह ने नयी दिल्ली कलकत्ता, मद्रास, ग्रहमदाबाद और बंगलूर में अपनी शाखाएं खोलीं। अपने कार्यकलापों में विशाखन लाने और देश के बड़े केन्द्रों में मुद्रा बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह आशा की जाती है कि इसमें मुद्रा बाजार समेकन में सुविधा होगी।

भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह को रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त

6.29 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ने वित्त गृह को 182 दिवसीय खजाना बिलों की जमानत पर 1,000 करोड़ रुपए और वाणिज्यिक बिलों की जमानत पर 700 करोड़ रुपए की सर्वाधिक पुनर्वित्त सीमा मंजूर की (सारणी 6.13)। 182 दिवसीय खजाना बिलों पर प्रदत्त पुनर्वित्त

के लिए ब्याज की दर 1990-91 के दौरान (26 जून 1991 तक) वार्षिक 10.0 प्रतिशत और 14.5 प्रतिशत के बीच थी तथा वाणिज्यिक बिलों पर 13.0 प्रतिशत और के बीच थी। वित्त गृह को उपलब्ध कराए गए पुनर्वित्त पर दी जाने वाली रिजर्व बैंक की ब्याज दरें मुद्रा बाजार में विद्यमान स्थितियों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समायोजित की जाती हैं। तदनुसार, पुनर्वित्त पर रिजर्व बैंक की ब्याज दरों को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 182 दिवसीय खजाना बिल के संदर्भ में 33 अवसरों पर और वाणिज्यिक बिलों के संदर्भ में 30 अवसरों पर परिवर्तित किया गया (सारणी 6.14)।

बिल पुनर्भुनाई बाजार

6.30 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुनाए गए वाणिज्यिक बिलों की भकाया राशि नवंबर 1990 के अंत के 5,230 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 1991 के अंत में 3,479 करोड़ रुपए रह गयी जबकि मार्च 1990 के अंत में उक्त राशि 3,934 करोड़ रुपए थी। बिल पुनर्भुनाई बाजार में निधियों के प्रवाहों में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बिलों

संजी 8-13 भारतीय-मिलोकाटा और वित्त गृह को रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त

(करोड़ रुपये)

महीने के अंतिम शुक्रवार को		1982 दिवसीय खजाना बिलों की जमानत पर पुनर्वित्त			अल्पवधि धाणिष्यिक बिलों पर पुनर्वित्त			
सीमा	बकाया राशि	महीने के दौरान प्रयुक्त अधिकतम राशि	स्तंभ 4 में दर्शायी गयी अधिकतम प्रयुक्त राशि के अनुरूप सीमा	सीमा	बकाया राशि	महीने के दौरान प्रयुक्त गयी अधिकतम राशि	स्तंभ 8 में दर्शायी गयी अधिकतम प्रयुक्त के अनुरूप सीमा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1990								
मार्च	500.00	460.35	506.70	600	500.00	492.64	492.64	500
	100.00		(29.3.90)				(31.3.90)	
जून			140.58	200	100.00			
			(18.6.90)					
सितंबर	700.00	684.55	700.00	700	100.00	100.00	100.00	100
			(17.9.90)				(229.90)	
दिसंबर	500.00	437.35	500.00	500	100.00	85.89	89.08	190
			(3.12.90)				(20.12.90)	
1991								
मार्च	200.00	126.81	230.26	300	700.00	700.00	700.00	700
			(19.3.91)				(23.3.91)	
जून	100.00		212.17	300	700.00		700.00	700
			(20.6.91)				(1.6.91)	

90 दिन से अनधिक की असम्पत्त अवधिवली व्युत्पन्न सीमादी वचन पत्रों की जमानत पर वित्त गृह को बढ़ी हुई पुनर्वित्त सीमाएं प्रदान की और उक्त सुविधा के अंतर्गत अधिकतम सीमा की राशि 1990-91 के दौरान 700 करोड़ रुपए थी।

सारणी 6.14. भारतीय मिलोकाटा और वित्त गृह को प्रदत्त रिजर्व बैंक के पुनर्वित्त का ब्याज दरें

182 दिवसीय बिलों के धारकों पर पुनर्वित्त

(क) 182 दिवसीय खजाना बिल

6.31 नवम्बर 1986 में नीलामी के आधार पर प्रारंभ किए गए 182 दिवसीय खजाना बिल अब मुद्रा-लिखत के रूप में काफी अच्छी तरह से स्थापित हो गए हैं। 182 दिवसीय खजाना बिलों की बकाया राशि मार्च 1990 के 774.30 करोड़ रुपए से बढ़कर 22 मार्च 1991 को 1077.59 करोड़ रुपए तथा 28 जून 1991 को और बढ़कर 2,146.77 करोड़ रुपए हो गयी। 182 दिवसीय खजाना बिलों की बकाया राशि का शिखर स्तर 3 अक्टूबर 1990 को 2,363 करोड़ रुपए था। इन बिलों पर अधिकतम आय जुलाई 1990 के 9.97 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी-1991 में वार्षिक 10.08 प्रतिशत हो गयी और अगस्त 1991 के प्रारंभ में काफी अधिक घटकर 10.00 प्रतिशत रह गयी (सारणी 6.15)।

प्रभावी तारीख

ब्याज की दर  
(वार्षिक प्रतिशत)

जुलाई	2,	90	10.50
	9,	90	10.00
	16,	90,	10.50
	21,	90	10.00
अगस्त	25,	90	10.50
	30,	90	11.00
सितंबर	12,	90	11.50
	14,	90	12.00
	15,	90	13.00
	18,	90	12.50
	20,	90	13.00

1	2	4	वाणिज्यिक दिनों पर कुलविवेक		
मकरावर	6, 90	13.50	प्रभावी. गारीख	व्याज की दर (दैनिक प्रतिशत)	
	10, 90	14.00			
	13, 90	14.50			
	20, 90	14.00			
	22, 90	13.50			
	26, 90	14.00			
जनवरी	3, 90	13.00	मकरावर	1, 90	15.00
	5, 90	12.50		11, 90	16.00
	8, 90	13.00		13, 90	17.00
	9, 90	12.50		15, 90	17.50
	14, 90	13.00		16, 90	18.00
	17, 90	14.00		23, 90	17.50
	19, 90	14.50		25, 90	17.00
	23, 90	12.50		27, 90	17.50
दिसंबर	1, 90	11.00		30, 90	17.00
	8, 90	10.50		31, 90	13.00
	29, 90	11.00	जनवरी	5, 90	15.00
जनवरी	12, 91	10.50		10, 90	14.00
फरवरी	15, 91	10.00		13, 90	15.00
मार्च	5, 91	10.25		15, 90	16.00
	16, 91	10.50		20, 90	14.00
	23, 91	10.00			
	28, 91	10.25	दिसंबर	8, 90	13.00
अप्रैल	6, 91	10.00	फरवरी	15, 91	13.50
	15, 91	10.25		26, 91	14.00
	16, 91	10.50		28, 91	14.50
	18, 91	11.00	मार्च	4, 91	15.00
	19, 91	10.75		6, 91	15.50
	20, 91	10.00		11, 91	15.75
मई	6, 91	10.25		23, 91	16.75
	8, 91	10.50	अप्रैल	3, 91	15.75
	13, 91	10.75		6, 91	14.00
	20, 91	11.00		9, 91	14.50
	21, 91	11.50		10, 91	15.00
	25, 91	11.00		11, 91	15.50
जून	1, 91	10.25		13, 91	16.50
	6, 91	10.00		16, 91	16.50
	13, 91	10.25	जुलाई	17, 91	16.25
	14, 91	10.00		18, 91	16.00
	18, 91	10.25		29, 91	15.75
	19, 91	10.50	अगस्त	5, 91	15.00
	22, 91	10.00		7, 91	14.00
जुलाई	8, 91	10.25			
	9, 91	10.00			
	13, 91	10.50			
	15, 91	10.75			
	17, 91	10.50			
	18, 91	10.25			
	22, 91	10.00			

## घासी १, १३, भास्वत काका के १३१ विपरीत लुकाता थिल

वीरगोपी की तारीख	प्रस्तुत बोधिया		प्रयुक्त बोधिया		१०० रुपये के धनिका	अधिकतम प्राय (राशिका प्रतिमन)	मकाना घासा थिली का (करोड़ रुपये)
	वस्था	कुल प्राधिकृत राशि (करोड़ रुपये)	संख्या	कुल प्राधिकृत राशि (करोड़ रुपये)	मूल्य के लिए अधिकतम प्राय		
1	2	3	4	5	6	7	8
1990							
मार्च 11	21	149.00	10	90.50	95.25	9.97	1489.94
23	20	194.00	11	101.00	95.25	9.97	1475.44
अप्रैल 8	27	536.00	19	416.00	95.25	9.97	1811.34
21	18	117.50	9	111.50	95.25	9.97	1856.89
मई 5	22	216.00	12	167.00	95.25	9.97	1994.84
19	19	450.50	12	416.50	95.25	9.97	2347.84
जून 1	13	72.00	8	53.00	95.25	9.97	2363.34
15	13	73.50	6	49.50	95.25	9.97	2329.94
30	12	41.49	6	26.49	96.25	9.97	2295.59
जुलै 14	8	127.25	4	113.75	95.25	9.97	2204.24
27	7	135.00	4	126.50	25.95	9.97	2030.24
अगस्त 12	8	52.10	5	41.60	95.25	9.97	1909.34
26	11	80.45	10	75.45	95.24	10.00	1788.79
1991							
जनवरी 9	9	57.00	9	57.00	95.22	10.04	1755.29
23	11	62.70	11	62.70	95.20	10.08	1716.99
फरवरी 6	16	290.05	12	273.05	95.20	10.08	1576.04
20	13	108.00	10	98.00	95.20	10.08	1552.54
मार्च 6	6	38.30	6	38.30	95.20	10.08	1423.84
20	13	79.75	9	70.25	95.20	10.08	1077.59
अप्रैल 3	19	243.00	15	197.00	95.20	10.08	1221.59
16	25	596.00	21	579.00	95.20	10.08	1751.09
30	6	100.40	5	97.90	95.20	10.08	1822.50
मई 14	13	244.27	10	139.27	95.20	10.08	1938.02
30	8	167.30	5	156.80	95.20	10.08	1968.32
जून 12	6	98.00	7	87.50	95.20	10.08	2014.22
26	24	715.00	4	208.00	95.22	10.04	2146.77
जुलाई 10	23	326.00	9	198.00	95.23	10.02	2287.77
24	22	144.80	14	275.50	95.23	10.02	2500.57
अगस्त 7	25	1001.25	10	576.25	95.24	10.00	2801.77

## (ख) जमा प्रमाण पत्र

6.32 50 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों के संबंध में बकाया राशि 14 जून, 1991 को 4,506 करोड़ रुपए थी, जो उन बैंकों की सीमाओं का 61.5 प्रतिशत बनता है (सारणी 6.16) बैंक 3 महीने से लेकर 1 वर्ष की अवधि के बीच की परिपक्वता वाले जमा प्रमाणपत्र जारी करने आ रहे

सारणी 6.16—अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना

निम्नलिखित को समाप्त पञ्चमासा	जिन बैंकों ने जमा प्रमाण- पत्र जारी किये उनकी संख्या (पञ्चमासे के अन्त में)	कुल बकाया राशि (करोड़ रुपए)	पञ्चमासे के दौरान सभी परिपक्वता प्रबंधियों के लिए जारी किए गए जमा प्रमाणपत्रों की प्रभावी व्याज दर (सीमा) (वार्षिक प्रतिशत)
1	2	3	4
1990			
जुलाई	13	2,000	10.00 — 16.33
	27	2,162	9.00 — 13.50
अगस्त	10	2,341	10.00 — 15.00
	24	2,377	10.50 — 13.00
सितम्बर	7	2,406	10.00 — 13.00
	21	2,480	10.50 — 14.00
अक्तूबर	5	2,476	10.50 — 13.50
	19	2,489	11.50 — 13.01
नवम्बर	2	2,494	10.00 — 14.00
	16	2,529	11.00 — 16.33
	30	2,535	9.00 — 13.70
दिसम्बर	14	2,439	10.00 — 15.32
	28	2,462	10.00 — 13.10
1991			
जनवरी	11	2,690	11.00 — 14.00
	25	2,703	10.00 — 14.50
फरवरी	8	2,932	11.00 — 14.00
	22	3,035	10.50 — 14.02
मार्च	8	3,181	9.02 — 14.20
	22	3,203	10.00 — 14.87
अप्रैल	5	3,551	10.30 — 14.94
	19	3,674	10.00 — 14.69
मई	3	3,979	10.50 — 13.00
	17	4,398	9.00 — 16.30
	31	4,695	10.00 — 16.75
जून	14	4,506	10.00 — 16.80
	28	4,556	12.00 — 16.80

## (ग) वाणिज्यिक पत्र

6.33 जनवरी 1990 में योजना का प्रारंभ किये जाने के बाद, 23 कंपनियों ने 30 जून 1991 तक 419.4 करोड़ रुपए के मूल्य के जमा प्रमाणपत्र (50 निर्गम) जारी किये हैं। 9 कंपनियों द्वारा जारी किये गए जमा प्रमाणपत्रों (30 जून 1991 तक) की बकाया राशि 64.70 करोड़ रुपए थी। हालांकि कंपनियों द्वारा जारी किये गए जमा प्रमाणपत्रों की परिपक्वता अवधि 3 महीने और 6 महीने के बीच अनियमित थी, अधिकांश जमा प्रमाणपत्र 6 महीने की परिपक्वता के साथ जारी किये गये। प्रभावी व्याज दरें वार्षिक

हैं। यद्यपि 3 महीने की परिपक्वता वाले जमा प्रमाणपत्र 9.00 प्रतिशत से 16.6 प्रतिशत तक के बीच की व्याज दर पर जारी किये गये थे, इस परिपक्वता अवधि के लिए विशिष्ट व्याज दर सीमा वार्षिक 11.0 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत के बीच थी। एक वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए व्याज दर सीमा जहां 10.75 प्रतिशत और 16.6 प्रतिशत के बीच थी, वहां विशिष्ट दरें 12.0 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत के बीच थी।

11.7 प्रतिशत और 18.50 प्रतिशत की सीमा के बीच थी।

मांग मुद्रा बाजार

6.34 मांग मुद्रा दरें अक्तूबर 1990 के मध्य तक स्थिर रहीं परन्तु तत्पश्चात वे भीधता से बढ़कर उच्च स्तर पर पहुंच गयी और भारतीय सिटीकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा दर काफी अधिक बढ़कर 19 अक्तूबर 1990 को 61 प्रतिशत हो गयी थी। मांग मुद्रा दरों की अस्थिरता ने कमो जाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने कतिपय उपाय किए जिसमें निम्न-लिखित शामिल है—निवेकाधीन पुनर्वित्त सुविधा अधिक

मोती में उपलब्ध कराना, प्रारंभित नकदी निधि अनुपात के मामलों में ब्याज में हानि को कम करना और बैंकों द्वारा जमा प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी सीमाओं में वृद्धि करना। 2 नवम्बर 1990 को समाप्त हुए पखवाड़े में मांग मुद्रा दरों में कमी आयी और उनमें अधिकतम गिरावट 28 दिसम्बर 1990 को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान आयी जब वह 16.25 प्रतिशत रह गयी। मांग मुद्रा दरें 22 फरवरी 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े तक 15.6 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही। 22 मार्च 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान वित्तगृह की अधिकतम मांग दर फिर से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गयी। 19 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान मांग दर में तेजी आयी और वित्तगृह की मांग दर 19 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े में बढ़ कर 46 प्रतिशत के शिखर स्तर पर पहुंच गयी। हाल ही की अवधि में मांग मुद्रा दरों में हुयी इस तीव्र वृद्धि का कारण यह है कि मार्च 1991 के अन्तिम पखवाड़े में बैंकों की जमा-गणियों में भारी वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 5 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े को बैंकों की शुद्ध मांग और मीमादी देयताओं में तीव्र बढ़ोतरी हुई जिसके फलस्वरूप 19 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े में नकदी प्रारंभित निधि अनुपात के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए 3 मई 1991 को समाप्त हुई पखवाड़े के लिए सांविधिक चननिधि अनुपात के लिए बैंकों की निधि संबंधी आवश्यकताओं में वृद्धि हुई। 5 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े में कतिपय वित्तीय संस्थाओं में मांग मुद्रा बाजार में उधार देना या तो कम कर दिया या बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले कुल औसत दैनिक उधारों की राशि 22 मार्च 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े के 5,024 करोड़ रुपये से घटकर 5 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े में 4.14 करोड़ रुपये हो गयी।

6.35 सहभागियों की संख्या में वृद्धि कर मांग और नोटिस मुद्रा बाजार को व्यापक बनाने के लिए किये गये उपायों के कारण मांग और अल्प नोटिस मुद्रा बाजार में निधियों के प्रवाह में वृद्धि हुई। वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रवृत्त कुल औसत दैनिक उधारों की राशि 13 जुलाई 1990 को समाप्त हुए पखवाड़े के 3,296 करोड़ रुपये से काफी अधिक बढ़कर 12 जुलाई को समाप्त हुए पखवाड़े में 5,568 करोड़ रुपये हो गयी; उनमें भारतीय यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक और ग्रामीण विकास बैंक का अंश कुल तीन-चौथाई था। वित्तगृह की उधार दरों के संबंध में न्यूनतम, अधिकतम और मध्य दरों के औसत के संबंध आंकड़े सारणी 6.17 में दिये गये हैं।

#### मुद्रा बाजार की भूमिका

6.36 निर्बाध रूप से कार्य करने वाला मुद्रा बाजार वित्तीय बाजारों की वर्तमान स्थितियों का एक संवेदनशील बैरो-मीटर है और इस बाजार को आदर्श रूप में श्रद्धावधिक अधिगेषों और घाटों का बाजार से निपटान करने की व्यवस्था करनी चाहिए। पिछले चार वर्षों के दौरान भारतीय मुद्रा

बाजार में कई उल्लेखनीय गतिविधियां देखने में आयी हैं। 1987 तक मुद्रा बाजार में निखतों का अभाव था तथा ब्याज दरों और सहभागियों, दोनों को ही कड़ाई से विनियमित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप बाजार वस्तुतः मृतप्राय हो गया। हाल ही के वर्षों में लागू किये गये विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बाद मुद्रा बाजार में उल्लेखनीय रूप से गतिशीलता आयी है। कई नये लिखतों को परिचालन में लाया गया, मुद्रा बाजार को ब्याज दरों को पूर्णतः मुक्त किया गया, सहभागिता को व्यापक आधार प्रदान किया गया और भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह लिमिटेड (वित्त गृह) में स्थापना कर गौण बाजार को विकसित किया गया। वित्तीय बाजार के एक हिस्से को मुक्त करते हुए दूसरे हिस्सों को कड़े नियंत्रण के अन्तर्गत रखने में स्थिति में असंतुलन का तत्त्व इस प्रकार

सारणी 6.17 : भारतीय मित्रीकाटा और वित्त गृह की मांग मुद्रा उधार दरें

1989-90

निम्नलिखित को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए		उधार दर (वार्षिक प्रतिशत)		
		न्यूनतम	अधिकतम	मध्य दर का औसत*
1989				
जुलाई	14	5.50	11.00	9.85
	28	6.50	10.50	8.85
अगस्त	11	8.25	12.00	9.85
	25	7.25	10.75	9.30
सितंबर	8	7.25	10.50	9.15
	22	8.75	10.75	9.60
अक्तूबर	6	6.50	13.50	11.30
	20	10.50	20.00	14.80
नवंबर	3	8.75	21.00	15.15
	17	14.50	27.00	18.70
दिसम्बर	1	7.00	25.00	13.20
	15	7.50	13.50	10.45
	29	9.25	15.50	12.35
1990				
जनवरी	12	10.50	15.00	12.35
	26	8.75	14.00	10.85
फरवरी	9	6.50	12.75	11.10
	23	10.25	25.00	15.80
मार्च	9	7.00	28.00	16.65
	23	10.00	34.00	21.50
अप्रैल	6	10.00	58.25	40.05
	20	13.00	22.00	15.90
मई	4	8.75	23.75	17.50
	18	13.00	36.00	23.00
जून	1	9.50	38.00	21.65
	15	13.00	14.00	13.50
	29	11.00	11.50	11.50
जुलाई	13	8.50	13.75	11.45
	27	7.50	12.25	10.10
अगस्त	10	8.00	11.00	9.50

\* यह दैनिक मध्य दर का साधारण औसत है।



संख्या: 6.17-जारी

1990-91

निम्नलिखित को समाप्त हुए पखवाड़े के लिए		उधार दर (वार्षिक प्रतिशत)		
		न्यूनतम	अधिकतम	मध्य दर का औसत?
1990				
जुलाई	13	8.50	13.75	11.45
	27	7.50	12.25	10.10
अगस्त	10	8.00	11.00	9.50
	24	6.00	11.00	9.10
सितम्बर	7	6.50	15.75	12.25
	21	10.00	26.00	16.50
अक्तूबर	5	10.00	34.00	22.60
	19	16.00	60.50	37.20
नवम्बर	2	9.00	31.00	21.00
	16	8.00	28.00	19.35
	30	7.50	28.00	16.60
दिसम्बर	14	4.00	14.00	10.50
	28	7.50	15.00	13.20
1991				
जनवरी	11	7.00	15.25	13.40
	25	5.00	15.00	11.80
फरवरी	8	6.00	14.25	12.65
	22	8.75	15.75	12.80
मार्च	8	13.75	17.75	16.10
	22	7.00	27.75	21.30
अप्रैल	5	5.00	25.00	16.05
	19	14.25	46.00	23.75
मई	3	24.25	45.00	32.25
	17	20.00	60.50	42.90
	31	4.50	45.00	29.10
जून	14	13.50	28.00	23.40
	28	6.00	38.00	25.13
जुलाई	12	10.25	38.50	23.40
	26	5.00	27.00	14.05
अगस्त	9	5.00	17.50	12.60

\*यह दैनिक मध्य दर का साधारण औसत है।

में आ जाता है कि प्रणाली को संतुलित करने का पूरा भार विनियमन से मुक्त किये गये क्षेत्र पर आ पड़ता है।

6.37 कभी-कभी यह अमूर्ण तर्क दिया जाता है कि मुद्रा बाजार को विनियम मुक्त कर देने से उन बैंकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, जो ऋणकर्ता रहे हैं क्योंकि इससे उनकी निधियों की लागत बढ़ जाती है। जब मुद्रा बाजार दरों पर उच्चतम सीमा की शर्त लागू थी, तब भी मुद्रा के मंहगी हो जाने की अवधियों के दौरान वास्तविक दरों में चढ़ाव आया था और उनकी उच्चतम दरों में कमी लाने के लिए विभिन्न उपाय किये गये थे। अतः यह दलील देना नास्तबसी होगी कि विनियममुक्त प्रणाली में मुद्रा बाजार की ब्याज दरें विनियमन मुक्त प्रणाली की दरों की अपेक्षा उच्चतर होती हैं।

6.38 एक अन्य जिम मामले पर चर्चा करना जरूरी है वह दीर्घकालिक ऋणकर्ताओं को दीर्घकालिक ऋणदाताओं के प्रश्न से संबंधित है। बाजार में संरचनात्मक असंतुलन विद्यमान है और मुद्रा बाजार में ऋणकर्ताओं और ऋणदाताओं

दोनों द्वारा सहभागियों की ऐसी एक तरफा स्थितियां होना इष्टतम निधि प्रबंधन में कमी का संकेत देती है। कोई भी बैंक यह प्रतिपादित कर ही नहीं सकता कि उसकी मुद्रा बाजार में बड़ी मात्रा में और बिन्यासात्मक निर्भरता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये जाने चाहिए कि उसे न्यून ब्याज दर पर निधियां उपलब्ध कराया जाती हैं। विनियम मुक्त मुद्रा बाजार की यह नीति रही है कि मुद्रा बाजार बैंकों द्वारा निधियों वाले बैंक को अपने असंतुलन को ठीक करने के लिए बाध्य किया जाए। इस प्रकार विनियमन मुक्त मुद्रा बाजार बैंकों द्वारा निधियों का विवेकमुक्त ढंग से प्रबंधन किये जाने को सुनिश्चित करता है।

6.39 इस संदर्भ में जो एक और प्रश्न उभरता है वह है मुद्रा बाजार की ब्याज दरों की गतिविधियों के मुकाबले रिजर्व बैंक की भूमिका। रिजर्व बैंक जहां या तो प्रत्यक्षतः या वित्त गृह के माध्यम से अपने पुनर्वित्त में वृद्धि कर दुर्लभ मुद्रा बाजार में निश्चय ही राहत पहुंचा सकता है, इस बात को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि रिजर्व बैंक का पुनर्वित्त भी मुद्रागत नीति का एक उपकरण है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऐसा पुनर्वित्त इतना अधिक नहीं हो जाता कि वह मुद्रा नीति के मूल सिद्धांतों के विपरीत हो। हाल ही की अवधि में रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1991 के प्रारम्भ में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का विवेकाधीन पुनर्वित्त प्रदान किया है और वित्त गृह की औसत मांग दर 5 अप्रैल 1991 को समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान 16 प्रतिशत के आसपास थी जबकि वह पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में 40 प्रतिशत थी। तथापि, विवेकाधीन पुनर्वित्त का उतना उच्च स्तर लम्बी अवधियों के लिए बनाए रखना तर्क संगत नहीं होगा क्योंकि उससे मुद्रा नीति के लक्ष्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

6.40 अप्रैल और मई 1991 के महीनों में मांग मुद्रा दरों में अत्यधिक उच्च स्तरों पर चढ़ाव आया और 17 मई 1991 समाप्त हुए पखवाड़े के लिए, उनका औसत काफी अधिक अर्थात् 43 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के लिए वह 23 प्रतिशत था। ऐसी ऊंची मांग दरें ऋणकर्ताओं की वृद्धि से निश्चय ही लाभप्रद नहीं है और अतः निधियों के लिए उनकी मांग में कमी आनी है। इस प्रकार, हाल ही की अवधि में, मांग मुद्रा दरों में गिरावट आने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। 31 मई 1991 को समाप्त हुए सप्ताह के लिए औसत मांग दर 23 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में वह 22 प्रतिशत थी। जून और जुलाई 1991 के महीनों में मांग मुद्रा बाजार में और भी गिरावट आयी और 12 जुलाई 1991 के समाप्त हुए पखवाड़े के दौरान औसत मांग दर 23 प्रतिशत थी जबकि 26 जुलाई 1991 को समाप्त हुए अगले पखवाड़े के दौरान वह गिरकर 14 प्रतिशत हो गयी। उच्च मांग दरें निवेश के स्वरूप को आवश्यक क्षति पहुंचानी है, जिनके कारण, उत्पादक प्रयोजनों के

लिए निवेश करने की प्रपेक्षा अल्पावधि आधार लिये जाते हैं। यदि उचित दरों को प्रचलित रखना है, तो बेकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस आशा में भ्रम प्रदान करने के संदर्भ में अपनी सीमा को नहीं लांघें कि गांग बाजार अंतर की पूर्ति करेगा।

#### 7. मूल्य स्थिति की समीक्षा

7.1 वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान सामान्य मूल्य स्तर पर तीव्र वृद्धि रहा। 1989-90 में निमित्त मूल्यों में वृद्धि की गति विशेष रूप से खाड़ी संकट के उपरान्त क्रमिक रूप से तीव्र हुई तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक 12.1 प्रतिशत तक पहुँचकर इसने दहाई अंक पार कर लिया है। घाटे वाली मूल्य वृद्धि का यह क्रम, जैसेकि 1989-90 में 9.1 प्रतिशत वृद्धि के परिणामस्वरूप और लगातार तीन वर्षों के लिए संतोषजनक कृषि उत्पादन के बावजूद हुआ था, गंभीर चिन्ता का कारण बना। सामान्यतः अत्यंत भारी वृद्धियाँ आवश्यक पण्यों के मूल्यों में हुई थीं।

7.2 1990-91 के दौरान अधिक वार्षिक मूल्य वृद्धि की विशेषता भारी बिपरीत—सोसमी मूल्य वृद्धि से हुई। यद्यपि मूल्य स्तर पर दबाव अधिकांश 'प्राथमिक वस्तुओं' ने किया, खाद्य तथा गैर-खाद्य, ईंधन, शक्ति, विद्युत और स्नेहक समूह ने भी सामान्य मूल्य स्तर पर काफी अधिक दबाव किया। इसके प्रतिरिक्त खाद्य वस्तुओं तथा कृषि-आधारित औद्योगिक कच्चे माल में अधिक मूल्य वृद्धियों के क्रमशः निमित्तित उत्पादों में और अधिक मूल्य वृद्धियाँ हुईं। यह सामान्यीकृत स्कीतिकारक स्थिति विभिन्न चटकों देशों और विदेशी, वोलों के परिचालन से, अत्यंत प्रमुख रूप से, गत कुछ वर्षों में लगातार राजकोषीय घाटे से हुए नकदी बचावों से उत्पन्न हुई थी। वित्तीय

वर्ष के द्वितीयाध के दौरान देश में प्रचलित अस्थिर स्थिति स्कीतिकारक दबावों से जुड़ गई। इसके प्रमुख चटक थे—वायो, तिलहन और खाद्य तेलों जैसे आवश्यक पण्यों में आपूर्ति-मांग के असंतुलन, भारी विदेशी मुद्रा की कमी के कारण आयातों के माध्यम से कम आपूर्ति की जाने वाला पण्यों की आपूर्ति को बढ़ाने में प्रतिबंध, अतिश तेज, विशाल जैसे औद्योगिक उत्पादों के सरकारी मूल्यों तथा साथ ही गेहूँ, बाजरा, जौ,चना आदि जैसी प्रमुख फसलों की सरकारी/समर्थन मूल्यों में अधिक वृद्धियाँ रेल भाड़ा, उत्पाद शुल्क और अन्य लेवियों में वृद्धियाँ, खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप ईंधन मूल्यों वृद्धि तथा कुछ क्षेत्रों की ऊर्जा के कांटे की कटौती के निमित्त आपूर्ति में अड़चने होती हैं परिवर्तनशील प्रभाव, बढ़ती हुई आयात लागत, बाजार में कमी जैसे कि सीमेंट के मामले में हैं।

चोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वार्षिक प्रवृत्तियाँ

7.3 चोक मूल्य सूचकांक (आधार: 1981-82=100) में वृद्धि की दर में जो कि बिन्दुवार आधार पर, 1988-89 में 5.7 प्रतिशत तथा 1989-90 में 9.1 प्रतिशत रही थी, उसने और अधिक बढ़कर 12.1 प्रतिशत हो गई। औसत आधार पर भी चोक मूल्य सूचकांक में 10.3 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई थी जबकि पिछले दो वर्षों में यह प्रत्येक में 7.5 प्रतिशत रही।

7.4 1990-91 के दौरान औद्योगिक कामगारों, शहरी शारौरिक श्रम करने वाले इतर शहरी कर्मचारियों तथा कृषि श्रमिकों से संबंधित सभी तीनों उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों ने उत्प्रेक्षनीय वृद्धि की दरें दर्शाईं। इस प्रकार औद्योगिक कामगारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1982=100 में 13.6 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष यह 6.8 प्रति-

सारणी 7.1: चोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वषा परिवर्तित मूल्य वृद्धियों की वार्षिक दरें (प्रतिशत वृद्धि)

1	चोक मूल्य सूचकांक		उपभोक्ता मूल्य सूचकांक					
	(आधार : 1981=82-100)		औद्योगिक कामगार*		इतर शहरी कर्मचारी@		कृषि मजदूरी\$	
	बिन्दुवार- आधार	औसत आधार	बिन्दुवार- आधार	औसत आधार	बिन्दुवार- आधार	औसत आधार	बिन्दुवार- आधार	औसत आधार
2	3	4	5	6	7	8	9	
1985-86	4.8	4.5	8.9	6.4	8.1	6.7	7.5	4.8
1986-87	5.1	5.7	7.5	8.8	7.0	7.9	3.1	4.8
1987-88	10.7	8.2	9.8	9.1	10.3	8.9	14.8	10.00
1988-89	5.7	7.5	8.6	9.1	7.0	8.2	10.8	12.7
1989-90	9.1	7.5	6.6	6.6	8.0	6.9	1.0	5.4
1990-91	12.1	10.3	13.6	11.2	13.4	11.0	16.6	7.6

\* प्रमुख: 1988 से आधार है 1982=100

उस से पूर्व है 1960=100

@आधार: 1984, 85=100

\$ आधार: 1960-61=100

एक रही, आर्थिक अर्थ करने वाले दूसरे श्रेणी कर्षणियों के संबंध में आधार (आधार 1984-85=100) 13.4 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि गत वर्ष यह 8.0 प्रतिशत थी तथा कृषि अर्थियों के संबंध में (आधार 1960-61=100) काफ़ी अधिक 16.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज अधिक मात्रा में 10 प्रतिशत थी। औसत आधार पर सूचकांक में ऐसी भारी वृद्धि की दंगे का भी पता चलता है। 1990-91 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में नौ अधिक वृद्धियाँ 1989-90 में उनकी वृद्धियों तथा 1990-91 में थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की तुलना में, मुख्यतः खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के कारण हुई थी जिसे थोक मूल्य सूचकांक की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिक महत्व मिलता है (प्राप्त अ)

#### समूहवार प्रवृत्तियाँ

7.5 समूह-वार, विन्तुवार आधार पर 1990-91 में प्राथमिक वस्तुओं (1990-91 में 17.1 प्रतिशत थी जबकि 1989-90 में 6.4 प्रतिशत रही) तथा ईंधन, शक्ति, विद्युत और स्नेहकों (14.4 प्रतिशत थी जबकि 1989-90 में 6.3 प्रतिशत रही) के थोक मूल्यों सूचकांकों में वृद्धियाँ विनिर्मित उत्पादों में हुई कम वृद्धि (8.9 प्रतिशत की जबकि 11.1 प्रतिशत रही) के विपरीत हुई औसत आधार पर मूल्य वृद्धियों ने भी सभी समूहों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति का पता चलता है।

#### मौसमी प्रवृत्ति

7.6 विन्तुवार आधार पर थोक मूल्यों की मौसमी प्रवृत्ति के मूल्यांकन में पता चलता है कि मार्च के अंत से अगस्त 1990 के अंत के बीच की अवधि वाले प्रथम चरण के दौरान मूल्य वृद्धि अधिक थी किन्तु गत वर्ष के तदनुवर्ती चरण की तुलना में थोड़ी सी कम रही। अगस्त के अंत से दिसंबर के अंत तक की अवधि के द्वितीय चरण में जिसकी सामान्य विशेषता

पता, थोक मूल्यों के सूचकांक में मौसमी गिरावट होती है, 1989 की तदनुवर्ती अवधि में हुई 0.4 प्रतिशत की गिरावट के विपरीत 3.9 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई। अंतिम चरण के दौरान, जिसमें दिसंबर अंत से मार्च अंत तक की अवधि आती है, वर्ष 1989-90 के अंतिम चरण में हुई वृद्धि की तुलना में थोड़ा सा घटी हुई। प्राथमिक वस्तुओं के समूह में प्रथम चरण में दर्शाई मूल्य वृद्धि (10.1 प्रतिशत, दूसरे चरण में 3.3 प्रतिशत की विपरीत मौसमी वृद्धि तथा अंतिम चरण में 3.1 प्रतिशत की वृद्धि और स्नेहक "तथा" विनिर्मित उत्पादों में दूसरे चरण में प्रमाद्वारण वृद्धियों हुई।

#### पथ-वार घट-वृद्धि

7.7 सारणी 7.2 में मूल्य प्रवृत्तियों के पथ-वार आधार पर प्रस्तुत किये गये हैं। विन्तुवार आधार पर बावल के मूल्य सूचकांक में वृद्धि में 1989-90 के केवल 1.6 प्रतिशत की तुलना में 13.4 प्रतिशत हुई, जबकि गेहूँ के मूल्यों में गत वर्ष में हुई 16.6 प्रतिशत गिरावट के विपरीत 48.9 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई इसका प्रमुख कारण था सरकार की खरीद के मूल्यों में काफी अधिक वृद्धियाँ और निर्गम मूल्यों में परिणामी वृद्धि जिसने खुले बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति निर्धारित की है। दालों में मूल्यों में उत्पादन ज्यों का त्यों रहने तथा मार्ग में दीर्घकालीन वृद्धि के कारण, 1989-90 में हुई 11.2 प्रतिशत वृद्धि के अनिश्चित 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई फल सब्जियाँ अब मछली और मांस तथा मिर्च मसाले व जटनी में अंशतः परिवर्तन लागत वृद्धियों के कारण 10.5 प्रतिशत में 32.3 प्रतिशत तक की सीमा में मूल्य वृद्धियों का पता चलता है। अन्य खाद्य वस्तुओं में काफी के मूल्यों में 61.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि अन्य रेशे में कपास के मूल्यों में 44.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिकूल मौसमी स्थितियों के कारण प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में खराब मृदाकली फसल की कमी से तिलहन के मूल्यों में 1989-90 में हुई 27.4 प्रतिशत वृद्धि से भी सर्वाधिक 26.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। उत्पादन में गिरावट ने आयातों को

सारणी 7.2 : थोक मूल्यों के सूचकांक में घट-वृद्धि

(आधार : 1981-82=100)

#### प्रतिशत वृद्धि

प्रमुख समूह, समूह उप-समूह/पथ	विवरण	वित्तीय वर्ष के दौरान				प्रथम तिमाही के दौरान	
		विन्तुवार आधार		औसत आधार		विन्तुवार आधार	
		1939-90	1990-91	1989-90	1990-91	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी पथ	100.000	9.1	12.1	7.5	10.3	4.1	2.4
I. प्राथमिक वस्तुएं	32.295	6.4	17.1	2.1	13.1	8.7	4.6
1. खाद्य वस्तुएं	17.386	2.1	18.9	1.2	12.0	11.5	6.2
क अनाज	6.824	-6.2	25.3	2.2	7.9	7.8	-2.2
(i) चावल	3.685	1.6	13.4	4.7	5.7	5.6	4.7
(ii) गेहूँ	2.248	-16.6	48.9	-3.7	16.2	14.0	-15.4
ख. दालें	1.093	11.2	10.8	2.9	10.7	6.7	4.1
ग. फल व सब्जियाँ	4.089	3.6	22.7	-8.1	19.8	23.8	18.2
घ. ईंधन	.961	4.5	8.9	8.9	4.2	3.6	6.0
ङ. अंडे, मछली और मांस	1.783	6.3	10.5	4.5	9.1	1.5	11.0
च. मिर्च-मसाले, जटनी आदि	0.947	5.4	32.3	-13.8	25.9	16.6	13.2
छ. अन्य खाद्य वस्तुएं	0.689	26.1	-2.0	46.2	13.3	13.0	-6.5
i) चाय	0.564	29.7	-12.6	55.4	6.1	11.8	-2.3
ii) काफी	0.125	7.9	61.3	5.3	60.6	20.3	-19.9

	2	3	4	5	6	7	8
2. गैर-खाद्य असेसुएं	10.031	13.4	19.3	3.4	17.2	6.5	2.6
क. वेजें	1.791	-4.0	24.5	11.1	5.2	5.9	15.2
i) कपास	1.335	-17.6	44.3	4.3	-0.7	9.9	21.1
ख. तिलहन	3.861	27.4	26.6	-0.3	28.9	10.5	2.4
3. खनिज	4.828	10.8	-0.5	3.7	6.7	-0.5	1.0
i) पेट्रोलियम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	4.274	12.5	-0.4	2.9	8.5	-0.4	--
II. ईंधन, शक्ति, विद्युत और स्नेहक	10.663	6.3	14.4	3.7	12.3	0.7	0.5
क. कच्चा कोयला	0.353	-	-	9.9	-	-	-
ख. खनिज तेल	6.666	9.1	20.6	0.5	19.3	0.4	-
ग. बिजली	2.741	4.7	11.4	6.3	7.1	1.8	1.5
III. विनिर्मित उत्पाद	57.042	11.1	8.9	11.3	8.4	2.3	1.5
क. चीनी, खाण्डसारी और गुड़	4.059	13.1	0.1	19.7	0.3	6.3	10.7
i) चीनी	2.013	10.5	0.4	11.6	-	-0.9	4.0
ii) खाण्डसारी	0.300	36.4	-2.8	32.2	-1.9	-2.8	16.0
iii) गुड़	1.746	12.7	0.1	27.0	0.8	15.5	16.9
ख. खाद्य तेल	2.445	17.2	32.7	4.0	26.0	9.4	1.8
ग. सूती वस्त्र	6.093	16.6	6.5	13.9	8.0	-0.5	2.2
घ. रसायन और रसायन उत्पाद	7.355	4.8	7.3	3.1	5.6	0.8	1.2
ङ. सीमेंट	0.860	14.9	14.1	10.9	17.2	-0.7	7.5
च. लोहा और इस्पात	2.441	11.8	6.0	15.5	6.7	0.8	-

से जुड़कर खाद्य तेलों के मूल्यों में 1989-90 में हुई 17.2 प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त कुछ 32.7 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि की खनिज तेलों के मूल्यों में, अक्टूबर 1990 में उनके मूल्यों में हुई 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के उपरान्त 1989-90 के 9.1 प्रतिशत की तुलना में 20.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। 1990-91 में सीमेंट के मूल्यों में 1989-90 में हुई 14.9 प्रतिशत वृद्धि से भी सर्वाधिक 14.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसत आधार पर थोक मूल्यों के आंकड़ों से भी लगभग सभी सपण्यों के लिए इसी प्रकार की स्थिति का पता चलता है।

#### भारतांक योगदान

7.8 थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि हेतु विभिन्न सपण्यों/पण्यों के भारांक योगदान के मूल्यांकन से पता चलता है कि बिन्दुवार आधार पर 32.3 प्रतिशत भारांक वाली प्राथमिकता वस्तुओं ने सामान्य सूचकांक में 1990-91 की कुल मूल्य वृद्धि में 44.6 प्रतिशत का अत्यधिक योगदान किया जबकि 1989-90 में यह योगदान लगभग आधा 23.0 प्रतिशत था। 10.7 प्रतिशत भारांक वाले ईंधन समूह ने सामान्य सूचकांक में गत वर्ष के 7.3 प्रतिशत की तुलना में 12.2 प्रतिशत का योगदान किया जबकि थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में विनिर्मित उत्पादों का योगदान 1989-90 के 70.3 प्रतिशत की तुलना में 43.0 प्रतिशत रहा। तीन मदों अर्थात् तिलहन, खाद्य तेल और खनिज तेल के लगभग 25 प्रतिशत का भारांकित योगदान आका गया तथा केवल अनाज से और 12.7 प्रतिशत आया। सामान्यतः इसी प्रकार की प्रवृत्ति औसत आधार पर देखी गई।

#### सरकारी मूल्य

7.9 औद्योगिक उत्पादों अर्थात् कोयला, लोहा और इस्पात, अलौह धातुएं (अल्युमिनियम को छोड़कर) पेट्रोलियम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, खनिज तेल बिजली तथा उर्वरक से सरकारी मूल्यों के संश्लिष्ट सूचकांक में जिनका थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में 19.7 का भारांकित योगदान रहा, 1990-91 में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो गत वर्ष की 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में अधिक थी। बिन्दुवार आधार पर थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में सरकारी विनिर्मित उत्पादों का भारांकित योगदान 1989-90 के 14.7 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा सा कम 1990-91 में 14.3 प्रतिशत था। प्रमुख मदों के सूचकांक में सरकारी मूल्यों में हुई वृद्धि के उपरान्त जिन मदों में परिवर्तन हुआ वे इस प्रकार थे : पेट्रोलियम उत्पाद (20.6 प्रतिशत), बिजली (11.4 प्रतिशत), लोहा और इस्पात (6.0 प्रतिशत) और अलौह धातुएं (9.4 प्रतिशत)।

#### प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 1991-92) प्रवृत्तियाँ

7.10 चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान सामान्य मूल्य स्तरों पर दबाव कुछ सीमा तक कम हुआ और थोक मूल्यों के सामान्य सूचकांक में 1990-91 की तुलना में 4.1 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में बहुत कम 2.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मूल्य वृद्धि के घातपान मुख्यतः प्राथमिक वस्तुओं के सूचकांक में हुई कम वृद्धि के कारण था जिसमें 1990-91 की तुलना में अवधि में दर्ज की गई 8.7 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि की तुलना में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। चावल और गेहूँ की संतोषजनक स्टाक स्थिति आपूर्ति की अड़चने न होना कुछ घटक थे उन्होंने प्राथमिक वस्तुओं

के मूल्यों में कम वृद्धि के लिए योगदान किया। ईंधन नफ़ि, विद्युत, स्नेहक सूचकांक में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गत तदनुकूपी अवधि में यह वृद्धि 0.7 प्रतिशत थी। विनिर्मित उत्पादों के समूह में अप्रैल-जून 1992 के दौरान 1.5 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की गई जबकि 1990-91 की प्रथम तिमाही में यह वृद्धि 2.3 प्रतिशत थी।

7.11 1991-92 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में विन्दुवार आधार पर 4.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जोकि 1990-91 की तदनुकूपी अवधि में दर्ज की गई 4.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में कम थी। दूसरी ओर, औसत आधार पर 12.4 प्रतिशत की वृद्धि गत वर्ष की तदनुकूपी अवधि में हुई 7.7 प्रतिशत से उल्लेखनीय रूप से अधिक थी।

#### कृषि मूल्य नीति

7.12 1990-91 में सभी प्रमुख फसलों के लिए सरकारी खरीद समर्थन मूल्य, गत वर्ष में उनके मूल्यों में की गई व्यापक वृद्धियों के बावजूद बढ़ाये गये गेहूं में 17.5 प्रतिशत और धान/बाजरा (औसत कोरम) में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि रही। 1990-91 के विपणन मौसम में गेहूं, जौ, चन्ना तथा सरसों के मूल्यों में प्रतिशत वृद्धियां गत वर्ष की वृद्धियों से अधिक थीं। धान, दालों, तिलहन (सरसों की छोड़कर) के लिए वृद्धियां यद्यपि 1989-90 की वृद्धियों से यथानुपात कम थीं, तथापि व्यापक द रहीं। 1991-92 के विपणन मौसम के लिए गेहूं, जौ, चन्ना, कुसुम तोरिया, सरसों, गन्ना और पटसन के सरकारी खरीद मूल्यों की घोषणा कर दी गई। इसमें पटसन के मूल्य में यथानुपात वृद्धि 17 प्रतिशत अधिक थी जबकि गेहूं के लिए यह 4.7 प्रतिशत रही। 1991-92 का नियमित वार्षिक बजट कृषकों को, कम विखेपण उर्ध्वकों को मूल्य तथा उधार चढ़ाव नियंत्रण से मुक्त करने तथा सभी अन्य उर्ध्वकों के मूल्य में औसत पर 40\* प्रतिशत की वृद्धि और एक ही स्तर फायदे पर प्रति टन को आर्थिक सहायता के संबंध में अधिकतम मात्रा के फलस्वरूप कृषि उत्पादन की लागत में होने वाली

परिणामी वृद्धि की सरकारी खरीद मूल्यों में उच्च वृद्धि करके लक्ष्यपूर्ति करना चाहता है।

#### औद्योगिक मूल्य नीति

7.13 बाड़ी संकट के उपरान्त आयातित कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में हुई तीव्र वृद्धियों को प्रभावहीन करने के लिए खनिज तेलों के मूल्यों में 25 प्रतिशत की वृद्धि करना पड़ा; वर्ष में इन वृद्धियों से पूर्व पहले की मूल्य वृद्धियां हुई थीं। पुनः 1991-92 के केन्द्रीय बजट ने जुलाई 1991 में पेट्रोल, मोटर स्प्रिट तथा विमानन टरबाइन ईंधन के मूल्यों में 20 प्रतिशत वृद्धि प्रस्तावित की है। डीजल को वृद्धि से छूट दी गई तथा केरोसिन के मूल्यों को 10 प्रतिशत कम किया गया। निवेश मूल्यों तथा अन्य लेखियों में वृद्धि को पूरा करने के लिए लोहा और इस्पात के मूल्यों को संशोधित किया गया। अलौह धातुओं (अल्यूमिनियम को छोड़कर) अर्थात् तांबा, जस्ता, सोना तथा क्लर्क के मूल्य, जिनको अधिकांशतः आयात किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यों और विनियम वरों में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किए गए। बिजली के मूल्यों में भी वृद्धि की गई। 1991-92 के केन्द्रीय बजट ने मार्गजिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत चानी के मूल्यों में बढ़ोतरी तथा बिजली की चीनी पर उत्पाद शुल्क वृद्धि प्रस्तावित की है। 1991-92 के रेलवे बजट ने रेल भाड़ा प्रसारों में 10 प्रतिशत की सामान्य वृद्धि प्रस्तावित की है, तथापि खाद्य तेल, खाद्यान्न चानी, गुड़, फल व सब्जियों जैसे कुछ आवश्यक पदार्थों को वृद्धि से छूट दी गई।

#### सोने और चांदी के मूल्य

7.14 सारणी 7.3 में दशमि अनुसार 1990-91 के दौरान बम्बई सराफा बाजार में सोने के मूल्य में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 1989-90 में हुई 1.9 प्रतिशत वृद्धि से काफी अधिक थी। सोने के मूल्य में वृद्धि चांदी के मूल्य में हुई वृद्धि से भी अधिक थी। तथापि, चांदी

सारणी 7.3 बम्बई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण तथा चांदी की कीमतें

वर्ष	सोना		चांदी		बम्बई और लंदन के मूल्यों में अंतर	
	बम्बई बाजार (स्टैंडर्ड बम्बई बाजार रुपये सोना प्रति 10 ग्राम)	औसत	बम्बई बाजार (0.999 तक परिष्कृत प्रति कि.ग्रा.)	औसत	सोना*	चांदी की कीमतें* **
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,700 (27.8)	1,522 (31.3)	2,720 (2.4)	2,617 (13.9)	+ 2.5	-34.9
1981-82	1,645 (-3.2)	1,719 (12.9)	2,680 (-1.5)	2,636 (0.7)	+ 2.41	+ 0.3
1982-83	1,800 (9.4)	1,723 (0.2)	3,105 (15.9)	2,798 (6.2)	+ 37.8	- 1.1
1983-84	1,975 (9.7)	1,859 (7.8)	3,570 (15.0)	3,506 (25.3)	+ 38.5	- 0.3
1984-85	2,130 (7.8)	1,984 (6.8)	3,955 (10.8)	3,594 (2.5)	+ 53.3	+ 27.9
1985-86	2,140 (0.5)	2,126 (7.1)	4,015 (1.5)	3,918 (9.0)	+ 64.8	+ 63.5

1	2	3	4	5	6	7
1986-87	2,570 (20.1)	2,324 (9.3)	4,794 (19.4)	4,247 (8.4)	+ 47.3	+ 91.1
1987-88	3,130 (21.8)	3,082 (32.7)	6,066 (26.5)	5,539 (30.4)	+ 61.2	+ 83.6
1988-89	3,140 (0.3)	3,175 (3.0)	6,755 (11.4)	6,367 (14.9)	+ 62.0	+ 114.3
1989-90	3,200 (1.9)	3,229 (1.7)	6,463 (-4.3)	6,482 (7.5)	+ 56.5	140.4
1990-91	3,466 (8.3)	3,452 (6.9)	6,646 (2.8)	6,761 (-1.2)	+ 59.5	+ 162.1

\*दरों का अंतर लंदन बाजार में डालर प्रति शुद्ध ऑंस को रुपये प्रति 10 ग्राम में—लंदन में अमरीकी डालरों की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के दैनिक औसत एवं रिजर्व बैंक के स्टिलिंग की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के औसत की प्रति दरों के आधार पर बदलने के बाद निकाले गए हैं।

\*\*दरों का अंतर न्यूयार्क बाजार में सेक्टर प्रति शुद्ध ऑंस को रुपये प्रति किलोग्राम में अमरीकी डालरों की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के दैनिक औसत एवं रिजर्व बैंक के स्टिलिंग की हाजिर खरीद और बिक्री दरों के औसत की प्रति दरों के आधार पर बदलने के बाद निकाला गया है।

टिप्पणी : कोटो में दिखे गये आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत के रूप में बट-बट हैं।

की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में इसकी देशी कीमत पर प्रचलित प्रीमियम न केवल उल्लेखनीय रूप से अधिक था (1990-91 में 162 प्रतिशत या जबकि सोने में 59.5 प्रतिशत रहा। बल्कि सोने की देशी कीमत में उल्लेखनीय प्रीमियम की प्रवृत्ति की तुलना में हाल के वर्षों में, उसमें काफी अधिक तीव्र वृद्धि हुई।

7.15 सोने और चांदी के संबंधित मूल्यों के उतार चढ़ाव सारणी 7.4 और ग्राफ आ में दर्शाये गये हैं। जैसा कि उसमें देखा जा

सकता है, 1990 के दशक के दौरान देशी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच हमकी संबंधित कीमतों में स्पष्ट रूप से प्रतिशत प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, एक ग्राम सोना, औसत आधार पर, 1980-81 में 37 ग्राम चांदी खरीद सकता था किन्तु 1990-91 में वह 83 ग्राम तक चांदी प्राप्त कर सका जिससे सोने के अनुकूल तीव्र मूल्य वृद्धि परिलक्षित होती है। इसके विपरीत, देशी बाजार में, एक ग्राम सोने का बिनियम 1980-81 में 59 ग्राम चांदी के लिए अथवा 1981-82

सारणी 7.4 : ग्रामों के अनुसार सोना और चांदी का अनुपात

वर्ष प्रति 1 ग्राम स्टैण्डर्ड सोने के लिए उपलब्ध ग्राम चांदी (0.999 तक परिष्कृत) —

वर्ष	बम्बई बाजार में*		अंतर्राष्ट्रीय बाजार में \$	
	औसत मूल्य आधार पर (ग्राम)	वर्ष के अंत में मूल्य आधार पर (ग्राम)	औसत मूल्य आधार पर (ग्राम)	वर्ष के अंत में मूल्य आधार पर (ग्राम)
3	2	3	4	5
1980-91	59	63	37	43
1981-82	66	61	46	45
1982-83	62	58	44	39
1983-84	53	55	38	40
1984-85	55	53	46	49
1985-86	55	54	54	65
1986-87	55	54	71	67
1987-88	56	51	64	64
1988-89	50	46	66	66
1989-90	47	49	72	75
1990-91	51	53	83	92

\*बम्बई मुलियन संघ के भावों पर आधारित

लंदन और न्यूयार्क बाजार के लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से प्राप्त भावों पर आधारित।

में 66 ग्राम बांधी के लिए किया जा सकता था किन्तु 1990-91 में केवल 31 ग्राम के लिए किया जा सका जिससे बांधी के अनुकूल हुई संबंधित मूल्य वृद्धि का पता चलता है। देशी बाजार में बांधी की कीमती पर तीव्र दबाव संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में कम हुई विपत्तिकालीन विक्रियां तथा इस धातु के औद्योगिक उपयोगों में काफी तीव्र वृद्धि से माना जा सकता है।

7.16 रुपये की विनियम दर में दो चरणों में समायोजन से जुलाई 1991 के दौरान बंबई सराफा बाजार में सोने और चांदी के मूल्य कुछ मुख्य रूप से स्थिर रहे।

#### सरकारी बिल

##### केन्द्रीय सरकार का बजट घाटा

8.1 वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार के बिल पर बहुत दबाव रहे। समष्टिगत आर्थिक कठिनाइयां जाड़ी संकट आ जाने से और भी बढ़ गयीं तथा पहले से ही दबावग्रस्त राजकोषीय स्थिति पर और अधिक दबाव पड़ा। राजस्व प्राप्ति में अनुमानित से कम रही तथा कुल बितरण मूल अनुमानों से बढ़ गया। मध्य वर्ष में किये गये अतिरिक्त कर उपायों तथा व्यय में सीधी कटौती एवं किराये के अन्य उपायों के बावजूद यह स्थिति उत्पन्न हुई। संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार का परंपरागत बजट घाटा 1990-91 के दौरान, 10,772 करोड़ रुपये था जो बजट में अनुमानित 7,206 करोड़ रुपये की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। रिजर्व बैंक के अभिलेख के अनुसार 1990-91 का वास्तविक घाटा लेखे बंद होने के बाद 11,430 करोड़ रुपये (अथवा सकल देशी उत्पाद का 2.2 प्रतिशत) अनुमानित था जबकि 1989-90 में यह 10,624 करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद का 2.4 प्रतिशत) था। 1990-91 के संशोधित अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की राशि जिस पर केन्द्र के बजट संबंधी कार्यकलापों का मुद्रागत प्रभाव पड़ता है, अनुमानित: 13,000 करोड़ रुपये थी जो 1989-90 के उपर्युक्त वास्तविक निवल ऋण की 13,813 करोड़ रुपये की राशि से थोड़ी सी कम है।

अंततोगत्वा, 31 मार्च 1991 को सरकारी लेखा बंद होने पर इसकी 14,746 करोड़ रुपये की राशि अपेक्षाकृत बहुत अधिक थी।

8.2 1990-91 में बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण में मौसमी घट-बढ़ के अध्ययन से पता चलता है कि घाटे के इन मामलों में वर्ष में अधिकांश समय अनुमानित स्तर से काफी अधिक होने एवं वर्ष के अंतिम सप्ताह में सरकारी लेखा बंद होने के समय काफी गिर जाने की प्रवृत्ति बनी रही। 1990-91 के दौरान बजट घाटा और केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण मई 1990-91 में ही अपने अनुमानित स्तर से अधिक हो गया था। 1991-92 के अंतिम बजट में अनुमानित बजट घाट की 9,977 करोड़ रुपये की राशि का भी जून 1991 के प्रथम सप्ताह में ही अतिक्रमण हो गया। अनुमानित घाटे के राजकोषीय वर्ष के प्रारंभिक महीनों में अनुमानित स्तर से बढ़ जाने की प्रवृत्ति अब कुछ वर्षों से नियमित प्रवृत्ति बन गयी है (सारणी 8.1)।

8.3 24 जुलाई 1991 को संसद में प्रस्तुत 1991-92 के नियमित बजट के अनुसार अतिरिक्त संसाधन जुटाय जाने को हिसाब में लेने पर परंपरागत घाटा अनुमानित: 7,719 करोड़ रुपये है जो 1990-91 में 10,772 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 28.3 प्रतिशत कम है। इससे यह पता चलता है कि 1991-92 में बजट संबंधी कुल परिचय का लगभग 6.6 प्रतिशत अंश अपूरित रहेगा जबकि 1990-91 में अपूरित अंश 9.8 प्रतिशत था।

#### राजकोषीय घाटा

8.4 पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में केन्द्रीय सरकार के बजट संबंधी कार्यकलापों के पूर्ण प्रभाव को समाहित करने हेतु घाटे के विभिन्न मामलों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया था। परंपरागत घाटा और केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण सरकार के राजकोषीय कार्यकलापों में संरचनात्मक असंतुलनों का एक अंश ही दर्शाते हैं जबकि घाटे की व्यापक संकल्पना अर्थात् सकल राज-

सारणी 8.1: केन्द्र के बजट घाटे तथा केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण के पाक्षिक स्तर--

(करोड़ रुपये)

केन्द्र का बजट घाटा					केन्द्र को भारतीय रिजर्व बैंक का निवल ऋण				
अवधि		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
1		2	3	4	5	6	7	8	9
बजट अनुमान		7,484	7,337	7,206	7,719	7,484	7,337	7,206	7,719
वास्तविक पाक्षिक प्रांकड़े)	तारीख								
1	6-4-90	2,401	1,170	2,679	2,271	2,036	2,011	2,712	2,427
2	20-4-90	3,782	3,497	3,204	3,716	3,508	3,722	4,050	3,269
3	4-5-90	4,976	6,043	5,754	5,508	4,378	5,461	4,994	3,962
4	38-5-90	5,639	5,176	6,638	8,409	5,001	6,392	7,058	6,764
5	1-6-90	6,134	8,865	8,228	8,925	4,180	7,675	6,907	7,534
6	15-6-90	7,525	9,508	7,698	11,029	6,976	7,784	7,463	9,607
7	29-6-90	8,667	9,824	9,107	11,503	8,582	7,858	7,703	9,168
8	13-7-90	9,468	11,378	9,996		9,035	9,500	9,883	
9	27-7-90	8,515	11,382	10,128		7,344	9,140	8,185	
10	10-8-90	9,300	13,416	10,976		8,331	10,277	9,018	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	24-8-90	8,332	12,596	8,729		7,029	9,938	6,543	
12	7-9-90	9,897	13,265	10,290		7,355	20,664	8,209	
13	21-9-90	8,831	11,535	10,289		6,723	9,111	7,269	
14	5-10-90	9,438	12,953	11,971		7,253	11,186	9,245	
15	19-10-90	9,249	10,375	10,755		7,474	9,869	10,241	
16	2-11-90	9,079	10,934	11,830		6,424	8,901	10,438	
17	16-11-90	9,422	13,044	13,636		8,081	12,403	12,476	
18	30-11-90	10,308	13,789	13,001		7,875	12,748	12,978	
19	14-12-90	10,154	13,317	15,330		9,065	13,634	15,159	
20	28-12-90	8,546	11,789	14,097		8,060	12,611	13,029	
21	11-1-91	9,172	14,206	15,093		9,679	15,277	15,055	
22	25-1-91	9,134	14,158	15,123		9,334	10,255	14,621	
23	8-2-91	10,187	13,675	15,442		9,965	15,395	15,447	
24	22-2-91	9,437	13,790	14,627		9,742	15,804	15,107	
25	8-3-91	8,597	14,266	15,072		9,228	16,383	16,064	
26	22-3-91	7,184	10,290	11,969		8,175	14,344	14,486	
31 मार्च		5,810	10,624	11,430		6,503	13,813	14,746	
तिमाही औसत									
पहली तिमाही		5,060	6,398	6,187		4,347	5,843	5,841	
दूसरी तिमाही		9,001	12,262	10,068		7,771	9,772	8,185	
तीसरी तिमाही		9,457	12,314	12,803		7,747	11,622	11,936	
चौथी तिमाही		8,503	13,001	14,108		8,947	15,182	15,075	
वित्तीय वर्ष औसत		8,114	10,947	10,818		7,309	10,635	10,337	

② भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों पर आधारित

§ वर्ष 1990-91 के संघर्ष में पखवाड़ों की संवर्धित तारीखें दी गयी हैं, अन्य वर्षों के मंदर्भ में आंकड़े तदनु रूप पखवाड़ों से संबंधित हैं।

टिप्पणी : 1. वर्ष 1989-90 के लिए 23 अगस्त 1989 से सम्मिलित केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निवल ऋण की राशि 78 करोड़ से 721.43 करोड़ रुपये तक है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पुनः ऋण की सुविधा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जारी की गयी अपरकाम्य व्याज रहित प्रतिभूतियों के प्रतिस्थापन की द्योतक है जिनके दावे केन्द्रीय सरकार पर हैं।

2. बजट संबंधी आंकड़ों के अनुसार केन्द्र का बाटा 1988-89 में 5,642 करोड़ रुपये था तथा 1989-90 में 10,592 करोड़ रुपये।

कोषीय घाट, अनुदानों सहित राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक कुल संवितरणों की दृष्टि से संसाधनों में समग्र कमी दृश्यता है जिससे राज कोषीय कार्यक्रमों के केन्द्रीय सरकार की ऋणग्रस्तता पर प्रभाव का पूरा-पूरा चलता है। केन्द्रीय सरकार के घाट के बैकल्पिक मानों की वर्ष 1989-81 से प्रचलित तथा वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में उनके अनुपात सारणी 8.2 में दिये गये हैं।

8.5 परंपरागत घाट तथा मुद्राकृत घाटे के बढ़ते हुए आकार के अलावा सकल राजकोषीय घाट में पिछले दशक के दौरान काफी अधिक वृद्धि हुई। यह 1980-81 के 8,299 करोड़ रुपये से बढ़कर 1985-86 में 21,857 करोड़ रुपये हो गया तथा 1990-91 में 43,331 करोड़ रुपये। सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 1980-81 के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर 1985-86 में 8.3 प्रतिशत हो गया तथा 1990-91 में उसके 8.4 प्रतिशत होने का अनुमान है। 1990-91 में सकल राजकोषीय घाट द्वारा निरूपित संसाधनों की समग्र कमी का केवल एक चौथाई भाग ही परंपरागत घाटे में समाहित हुआ (घाफ "ह" और "ई" भी देखें)।

8.6 पिछले दशक के दौरान सकल राजकोषीय घाटे की वित्त व्यवस्था के स्वरूप (जैसा कि सारणी 8.3 में दिया गया है) से पता चलता है कि विदेशी वित्त पर निर्भरता 1980-81 के 15.4 प्रतिशत से कम होकर 1990-91 में 9.2 प्रतिशत रह गयी तथा संसाधनों में कमी के अधिकाधिक अंश के लिए वित्त व्यवस्था देशी उधार से की गयी

है उपर्युक्त अवधि के दौरान इसका अंश 84.6 प्रतिशत से बढ़कर 90.8 प्रतिशत हो गया। देशी स्रोतों के अंतर्गत बाजार ऋण तथा परंपरागत घाटे का अंश 1980-81 के क्रमशः 32.3 प्रतिशत तथा 29.9 प्रतिशत से कम होकर 1990-91 में क्रमशः 18.5 प्रतिशत और 24.8 प्रतिशत रह गया जबकि अन्य देयताओं (जिनमें अल्प बचत, भविष्य निधियां, विशेष जमा राशियां तथा लोक लेखा से निवल वृद्धि आदि शामिल हैं) से संसाधनों में बढ़ती हुई कमी की मुख्यतः वित्त व्यवस्था की गयी। इन स्रोतों से, 1990-91 में संसाधनों में कमी के 47.5 प्रतिशत अंश की वित्त व्यवस्था की गयी जो 1980-81 के दौरान वित्त व्यवस्था में उनके 22.5 प्रतिशत के अंश के तुल्य से भी अधिक है।

8.7 संसाधनों में समग्र कमी के बढ़ते हुए स्तर के परिणामस्वरूप नवें दशक के दौरान केन्द्रीय सरकार की देशी ऋणग्रस्तता तेजी से बढ़ने लगी। केन्द्रीय सरकार की बकाया देशी देयताओं की कुल राशि बढ़कर मार्च 1991 के अंत में 2,79,528 करोड़ रुपये हो गयी जो सकल देशी उत्पाद का 53.9 प्रतिशत अंश है, जबकि मार्च 1981 के अंत में यह राशि 48,451 करोड़ रुपये या सकल देशी उत्पाद का 35.6 प्रतिशत थी (सारणी 8.4)।

8.8 हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ती हुई लागत पर राशित बढ़ती हुई देयताओं से भारतीय अर्थव्यवस्था को राजकोषीय अस्तव्यस्तता स्पष्ट होती है। जो राजस्व लेखों के बढ़ते हुए घाटे तथा गैर योजना व्यय में संसाधनों के अधिक उपयोग से संश्लेष है।



## सारणी 8.2 : मुद्रिकृत, बजट सकल और निवल राजकोषीय घाटा

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा@	निवल राजकोषीय घाटा@	मुद्रिकृत घाटा	परम्परागत घाटा	राजस्व घाटा	बाजार मूल्यों पर सकल उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	8,299	5,110	3,551	2,477	2,037	1,26,013
1981-82	8,666	4,593	3,207	1,400	392	1,59,760
1982-83	10,627*	5973*	3,368	1,656	1,308	1,78,132
1983-84	13,030*	8,171*	3,949	1,417*	2,540	2,07,589
1984-85	17,416	10,972	6,055	3,745	4,225	2,31,387
1985-86	21,857*	13,543*	6,190	5,315*	5,889	2,61,920
1986-87	26,342	17,036	7,091	8,251	7,777	2,91,974
1987-88	27,044	18,431	6,559	5,816	9,137	3,22,616
1988-89	30,923	20,770	6,503	5,653	10,515	3,94,992
1989-90	35,630	23,720	13,813	10,593	11,912	4,42,769
1990-91 (क)	43,331	30,207	14,746†	10,772	17,585	5,18,500‡
1991-92 (अंतरिम बजट अनुमान)	38,475	27,791	9,971	9,977	17,766	
1991-92 (नियमित बजट अनुमान)	38,727	24,191	7,719	7,719	13,854	5,80,403£

## बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा@	निवल राजकोषीय घाटा@	मुद्रिकृत घाटा	परम्परागत घाटा	राजस्व घाटा	बाजार मूल्यों पर सकल उत्पाद
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	6.10	3.78	2.61	1.81	1.50	
1981-82	5.42	2.87	2.01	0.88	0.55	
1982-83	5.97	3.35	1.89	0.93	0.93	
1983-84	6.28	3.94	1.90	0.68	1.22	
1984-85	7.53	4.74	2.62	1.62	1.63	
1985-86	8.34	5.17	2.36	2.03	3.25	
1986-87	9.02	5.83	2.43	2.43	2.66	
1987-88	8.13	5.54	1.97	1.95	2.75	
1988-89	7.83	5.26	1.65	1.43	2.66	
1989-90	8.05	5.36	3.12	2.39	2.69	
1990-91	8.36	5.83	2.84	2.08	3.39	
1991-92 (नियमित बजट अनुमान)	6.50	4.17	1.33	1.33	2.39	

@ गत लेख में कतिपय प्रति प्रविष्टियों के समायोजन के कारण ये आंकड़े प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हैं।

\* भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राप्त बोधरूपाट का भुगतान करने के लिए राज्यों को दिये गये 1982-83 का 1743 करोड़ रुपये, 1983-84 के 400 करोड़ रुपये और 1985-86 के 1628 करोड़ रुपये के मध्यवर्गीय ऋण इसमें शामिल नहीं किए गए हैं।

† भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार वास्तविक आंकड़े।

‡ अनुमानित रिपोर्टों का अध्याय 2 देखें।

£ (क) आंकड़े संशोधित अनुमानों से संवर्धित हैं।

टिप्पणी 1 (1) आंकड़े अद्यतन बजट प्रस्तावों पर आधारित हैं तथा पहले प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

2 पाठ्य संबंधी संकल्पनाओं की परिभाषा के लिए वार्षिक रिपोर्ट 1989-90 का पृष्ठ 84-85 देखें।

स्त्रोत : केन्द्रीय सरकार के बजट प्रलेख तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेख एवं राष्ट्रीय लेखा साक्ष्यिका 1991।

सारणी 8.3 : सकल राजकोषीय बाटे हेतु वित्त व्यवस्था

(करोड़ रुपए)

वर्ष	विदेशी वित्त	देशी वित्त				कुल वित्त सकल राजकोषीय धाटा
		बाजार ऋण +	अन्य देयताएँ	परंपरागत षाटा	जोड़ (3+4+5)	
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1281 (15.4)	2679 (32.3)	1862 (22.4)	2477 (29.9)	7018 (84.6)	8299 (100.0)
1981-82	984 (11.1)	2913 (33.6)	3389 (39.1)	1400 (16.2)	7792 (88.9)	8666 (100.0)
1982-83	1258 (11.8)	3771 (38.5)	3942 (37.1)	1656* (15.6)	9369 (88.2)	10627 (100.0)
1983-84	1338 (10.3)	4038 (31.0)	6237 (47.8)	1417* (10.9)	11692 (89.7)	13030 (100.0)
1984-85	1452 (8.3)	4095 (23.5)	8124 (46.7)	3745 (21.5)	15964 (91.7)	174146 (100.0)
1985-86	1449 (6.6)	4884 (22.4)	10209 (46.7)	5315* (24.3)	20408 (93.4)	21857 (100.0)
1986-87	3024 (7.7)	5532 (21.0)	10525 (39.9)	8261 (31.4)	24318 (92.3)	26342 (100.0)
1987-88	2893 (10.7)	5862 (21.7)	12473 (46.1)	5816 (21.5)	24151 (89.3)	27044 (100.0)
1988-89	2460 (8.0)	8418 (27.2)	14403 (46.6)	5642 (18.2)	28463 (92.0)	30923 (100.0)
1989-90	2595 (7.3)	7404 (20.8)	15039 (42.2)	10592 (29.7)	33035 (92.7)	35630 (100.0)
1990-91 (सं.घ.)	3984 (9.2)	8000 (18.8)	20575 (47.5)	10772 (24.8)	39347 (90.8)	43331 (100.0)
1991-92 (अंतरिम बजट अनुमान)	4000 (10.4)	7500 (19.5)	18998 (44.2)	9977 (25.9)	34475 (89.6)	38475 (100.0)
1991-92 (अंतिम बजट अनुमान)	3510 (9.3)	7500 (19.9)	18998 (50.3)	7719 (20.5)	34217 (90.7)	37727 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल वित्त/सकल राजकोषीय बाटे में प्रतिशत भाँस दर्शाते हैं।

+ कुछ वर्षों के संदर्भ में ये आंकड़े लेखा सम्बन्धी अप्रति और पश्चात के कारण सारणी 8.11 में दिये गए आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं जो भारतीय बैंक के रिजर्व रिकार्ड पर आधारित हैं।

\* भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त धोवर-ड्राफ्ट का भुगतान करने के लिये राज्यों को दिये गए 1982-83 के 1,743 करोड़ रुपए, 1983-84 के 400 करोड़ रुपए और 1985-86 के 1,628 करोड़ रुपए सम्भाव्य ऋण इसमें शामिल नहीं किए गए हैं।

† अन्य देयताओं में माल्य बजट, धनिय्य निधियाँ, विशेष जमा राशियाँ, प्रारंभित निधियाँ आदि शामिल हैं।

\$ भारतीय रिजर्व बैंक के पास लकड़ी शोध राशियों में परिवर्तनों के घटाने के बाद जारी किए गए 91 विवसीय खजाना बिलों के बट-बट के रूप में परिभाषित।

स्रोत: भारत सरकार के बजट प्रलेख

सारणी 8.4 : भारत सरकार की कुल बकाया देयताएँ

(करोड़ रुपये)

वर्ष	आंतरिक ऋण	अल्प बचत	अविष्य निधि और अन्य लेखे	प्रारक्षित निधि और जमा राशियाँ	कुल आंतरिक देयताएँ	विदेशी देयताएँ	कुल देयताएँ
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30864 (22.7)	7976 (5.9)	5977 (4.4)	3634 (2.6)	48451 (35.6)	11298 (8.3)	59749 (43.9)
1981-82	35653 (22.3)	9375 (5.9)	7203 (4.5)	3627 (2.3)	55858 (35.0)	12328 (7.7)	68186 (42.7)
1982-83	46939 (26.4)	11098 (6.2)	8789 (4.9)	4364 (2.5)	71190 (40.0)	13682 (7.7)	84872 (47.7)
1983-84	50263 (24.2)	13506 (6.0)	10368 (5.5)	6004 (2.9)	80141 (38.6)	15120 (7.3)	95261 (45.9)
1984-85	58537 (25.3)	17157 (7.4)	12547 (5.4)	8563 (3.7)	96804 (41.8)	16637 (7.2)	113441 (49.0)
1985-86	71039 (27.1)	21449 (8.2)	15410 (5.9)	11433 (4.4)	119331 (45.6)	18153 (6.9)	137484 (52.5)
1986-87	86312 (29.6)	24725 (8.5)	20204 (6.9)	15006 (5.1)	146247 (50.1)	20209 (6.9)	166546 (57.0)
1987-88	98646 (29.6)	28358 (8.5)	26170 (7.9)	19164 (5.8)	172338 (51.8)	23223 (7.0)	195561 (58.8)
1988-89	114498 (29.0)	33833 (8.6)	34702 (8.8)	20992 (5.3)	204025 (51.7)	25746 (6.5)	229771 (58.2)
1989-90	133193 (30.1)	41791 (9.4)	45273 (10.2)	19592 (4.4)	239849 (54.2)	28343 (6.4)	268192 (60.6)
1990-91 (सं.प्र.)	151352 (29.2)	49071 (9.3)	57208 (11.0)	21897 (4.2)	279528 (53.9)	31831 (6.1)	311359 (60.0)
1991-92 (ब.प्र.)	171589 (29.5)	56281 (9.7)	68046 (11.7)	24162 (4.2)	320078 (55.1)	35123 (6.1)	355201 (61.2)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद में प्रतिशत प्रशं वसति हैं।

स्रोत : भारत सरकार के बजट प्रलेख।

8.9 संशोधित अनुमानों के अनुसार 1990-91 के दौरान कुल व्यय की राशि 1,09,385 करोड़ रुपये की जिससे बजट में अनुमानित स्तर से 7,251 करोड़ रुपये की काफी अधिक वृद्धि परिलक्षित होती है। उपादानों व्याज सुगमताओं, ग्रामीण ऋण राहत तकनीकी ऋणों राज्यों तथा संशोधित क्षेत्रों को अधिक गैर-योजना सहायता के कारण व्यय में काफी अधिक वृद्धि के अलावा 300 करोड़ रुपये का वह अप्रत्याशित व्यय था जो कुवैत से भारतीय नागरिक के प्रत्यावर्तन पर किया गया। सकल कर राजस्व के बजट अनुमान से 862 करोड़ रुपये कम होने की आशा थी और यह कमी अति-काष्ठित सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में थी। राजकोषीय वर्ष 1990-91 के मध्य में सरकार ने अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक समाधानों के लिए एकमुष्ट उपाय किये जिसका प्रयोजन अतिरिक्त संसाधन

जुटाना और साथ ही साथ व्यय पर कड़ा नियंत्रण रखना था। दिसम्बर और दिसम्बर 1990 के दौरान कुछ अतिरिक्त कर लगाये जिससे अतिरिक्त कर राजस्व के रूप में 1,600 करोड़ रुपये जुटाये जाने का अनुमान था। व्यय के संघर्ष में वर्ष में दो बार, 2 जुलाई और 30 नवंबर 1990 को व्यय में सीधी कटौती की गई। अतिरिक्त कर के बावजूद आर्थिक वर्ष के संशोधित अनुमानों से सकल कर राजस्व, विशेषकर से सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क की उगाही में भारी गिरावट परिलक्षित हुई। इसी प्रकार, व्यय में कटौती के बावजूद संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल व्यय बजट अनुमानों से 7.1 प्रतिशत अधिक था दिसम्बर 1990 में संसद में प्रस्तुत तत्कालीन वित्त मंत्री के वक्तव्य में सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह राजकोषीय स्थिति के सुधार तथा नयेकन की प्रक्रिया राजकोषीय वर्ष

1991-92 में भी जारी रखेगी। यह आशा की गयी थी कि 1991-92 में केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा काफी घटाकर सकल देशी उत्पाद का लगभग 6.5 प्रतिशत कर दिया जाएगा। उस वक़्त-वक़्त में कहा गया था 'ऐसी कटौती तीन वर्ष की अवधि में हमारे प्रोत्साहनयोग्य राजकोषीय वास्तव-पद्धति में संक्रमण का प्रारंभ होगी जिसमें राजकोषीय घाटा कम होकर सकल देशी उत्पाद के 3 से 4 प्रतिशत तक रह जाएगा जैसा कि आठवीं दशक के मध्य में था।'

राजकोषीय समायोजन और संरचनात्मक सुधार

8.10 नवें दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में विस्तारजनक सम-ष्टिगत आर्थिक प्रसंगजनक परिलक्षित हुए जिनसे 1990-91 में अदृष्ट पूर्व राजकोषीय और भुगतान संकुल संकट उत्पन्न हो गया। इस पण्ड भूमि में केन्द्रीय सरकार ने राजकोषीय समायोजन और समष्टिगत आर्थिक विपरीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया है तथा उनके बाद वर्तमान राजकोषीय वर्ष 1991-92 में प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की मध्यम अवधि में निरंतर राजकोषीय समकेंद्रित किया जाएगा। समायोजन का ऐसा कार्यक्रम अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया पर दृढ़भाव डाले बिना तथा निर्धनों पर समायोजन का काम से कम भार डालने के प्रयास सहित चराने का प्रस्ताव है।

अंतरिम बजट

8.11 राजकोषीय प्रसंगजनक कटौती करने की प्रक्रिया अंतरिम बजट में सकल राजकोषीय घाटे की राशि को पिछले वर्ष की तुलना में स्थूल स्तर पर रख कर शुरू की गयी। 1991-92 के अंतरिम बजट में 38,475 करोड़ रुपये के सकल राजकोषीय घाटे की परि-कल्पना की गयी जबकि 1990-91 में यह राशि 43,331 करोड़ रुपये थी। अंतरिम बजट में परिकल्पित सकल राजकोषीय घाटे में की गयी ऐसी कटौती राजस्व और गैर-योजना व्यय के क्षेत्र में मुक्ति-करण के कतिपय चुनिंदा उपायों द्वारा की जाएगी: (i) प्रमुख उपदानों पर व्यय में 934 करोड़ रुपये की कटौती (ii) राष्ट्रीय बजट योजना का प्रस्तावित भारत बजट बैंक में अंतरित करने के परिणामस्वरूप राज्यों और संघ शोषित क्षेत्रों को अल्पवक़्त में उनके हिस्से के कारण दिये जाने वाले ऋणों में कमी (iii) सरकारी क्षेत्र के चुनिंदा उप-क्रमों में केन्द्रीय सरकार की ईश्वरीय धारिताओं के 20 प्रतिशत का म्यूचुअल फंड और अन्य वित्तीय या निवेश संस्थाओं के पक्ष में वित्ति-वेश करने का प्रस्ताव एक प्रमुख कार्य है जिससे 1991-92 में 2,500 करोड़ रुपये के संसाधन प्राप्त होंगे। वर्ष के दौरान व्यय के गर्म प्राव-धानों के पुनरीक्षण तथा उपयुक्त उपायों की निगरानी सकल-राज-कोषीय घाटा 1990-91 के 8.4 प्रतिशत की तुलना में 1991-92 में सकल देशी उत्पाद का 6.5 प्रतिशत रह जाने की आशा की।

8.12 चालू वर्ष के पहले चार महीने की अवधि के दौरान व्यय में अपेक्षित कटौती हेतु उपयुक्त नीतिगत उपायों के समाव में राजकोषीय स्थिति और विशुद्ध होगी।

1991-92 का नियमित बजट

8.13 24 जुलाई 1991 को संसद में प्रस्तुत किये गये केन्द्रीय सरकार के नियमित बजट में बार-बार व्यय के स्वरूप को मुक्तिमुक्त बनाकर राजकोषीय समायोजन का एक बड़ा कोणिका की गयी। राज-कोषीय क्षेत्र में बजट में सकल राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे तथा परंपरागत घाटे के स्तरों में काफी कमी की परिकल्पना की गयी है। कर और शुल्क की संशोधित शर्तों पर 1991-92 में सकल राज-कोषीय घाटा 37,727 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है जो 1990-91 के 43,331 करोड़ रुपये के स्तर से 5,604 करोड़ रुपये कम है। इस स्तर पर सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 1990-91 के 8.4 प्रतिशत से कम होकर 1991-92 में 6.5 प्रतिशत रह जाएगा।

8.14 परंपरागत घाटा 3,724 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है, इसमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों को हिमाव में नहीं लिया गया है। अतिरिक्त संसाधन जुटाने के प्रस्तावों में बैंड की प्राप्त होने वाली 2,005 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का को हिमाव में लेने पर 1991-2 में 7,719 करोड़ रुपये घाटा होने का अनुमान है जबकि 1990-91 में यह राशि 10,772 करोड़ रुपये थी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्व घाटे का स्तर जिसमें पिछले दशक में निरंतर वृद्धि परिलक्षित हुई है 1991-92 में 13,854 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो 1990-91 के 17,585 करोड़ रुपये की तुलना में 3,731 करोड़ रुपये कम है (सारणी 8.5)।

8.15 सकल राजकोषीय घाटे तथा राजस्व घाटे में परिकल्पित कमी के लिए गैर-योजना व्यय मुक्तिमुक्त बनाया गया है तथा अति-रिक्त कराधान किया गया है। यद्यपि, प्रमुख उपदानों के लिए किये गये प्रावधान में चालू वर्ष के दौरान 1,726 करोड़ रुपये की कटौती की गयी है तथापि महंगाई भत्ते की अतिरिक्त वित्त जो चालू वर्ष में देय हो सकती है, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा अतिरिक्त व्यय के मंचालयों के योजना आवंटनों पर प्रभाव डाले बिना उनके अनुमोदित बजट अनुमानों में ही समाहित हो जाने की आशा है। परिणामतः व्याज भुगतान को छोड़कर 1991-92 के संशो-धित अनुमानों की तुलना में 4.6 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। अंतरिम बजट में उल्लेखनीय, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में 2,500 करोड़ रुपये तक के विनिवेश के प्रस्ताव को बजट में भी शामिल किया गया है परंतु ईश्वरीय न केवल संस्थाओं और कर्मचारियों को वित्त निवेशकर्ता जनता को भी जारी की जाएगी (जैसा कि नयी औद्योगिक नीति संबंधी दस्तावेज में उल्लेख किया गया है) इसके अतिरिक्त बजट में 1990-91 के दौरान 2,617 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए संसाधन जुटाने के उपाय भी दिये गये हैं।

8.16 विदेशी मुद्रा के आगम और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में दो महत्वपूर्ण उपायों का उल्लेख किया गया है। पहले उपाय के अंतर्गत भारत में किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा के प्रेषण किये जा सकते हैं और उन पर उपहार कर से छूट दी गयी है। ऐसे प्रेषणों पर कर संबंधी कानून लागू नहीं होंगे तथा ऐसी निधि-यों के स्वतंत्रों के संबंध में जांच भी नहीं की जाएगी। दूसरे उपाय के अंतर्गत विनिवेशी भारतीयों और विदेश स्थित उनके कंपनी निकायों को बचने के लिए भारतीय स्टैंड बैंक द्वारा "भारत विकास बॉन्ड" जारी करने का प्रस्ताव है। एक तो ये बॉन्ड संपदा कर से छूट प्राप्त है, दूसरे इन बॉन्डों में विनिवेश दर संबंधी सुरक्षा मिलेगी तथा इनके अंकित मूल्य और व्याज का निर्धारण प्रत्यावर्तन किया जा सकेगा।

इनके अलावा, अब विनिवेशी भारतीयों को आवाग, मूलभूत सुविधा तथा स्थावर संपदा जैसे क्षेत्रों में गैर-प्रत्यावर्तन के आधार पर निवेश करने की अनुमति दी गयी है और साथ ही, उन्हें आवासीय संपत्ति प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुमति से सी सामान्य छूट दी गयी है।

8.17 एक अन्य उपाय के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 30 नवंबर 1991 को या उससे पहले राष्ट्रीय आवास बैंक में जमा राशि रख सकेगा तथा निधियों के स्वतंत्र के बारे में बिस्कुल कोई पुष्टवाच और जांच नहीं की जाएगी; ऐसे जमा राशियों का 20 प्रतिशत विशेष लेवो के रूप में काटा जाएगा तथा उसे राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा क्षोभ-पट्टी हटाने एवं निर्धनों के लिए कम लागत के मकान बना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

8.18 देश में व्याज दर के स्वरूप में बहुत से सुधार करने के लिए भी बजट में प्रस्ताव है। पूँजी बाजार पर लागू व्याज दरों के परभाव, घन्य वचन योजनाओं के संबंध में देय व्याज दर की भी बैंक जमागणियों संबंधी व्याज दरों में हाल ही में की गयी वृद्धि के अनुरूप के प्रतिशत अंक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

8.19 बजट में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया है। इन क्षेत्रों का अण योजना सभाधनों का 50 प्रतिशत हो रहेगा। विकास संबंधी कार्यनीति का पुनर्निर्धारण करके

मानवीय संसाधनों एवं समाज के कमजोर वर्गों के विकास के लिए अभिप्रेरक रोजगार कार्यक्रम तथा समाज-कल्याण कार्यक्रम घनाये जाएंगे। बजट में पांच नये कार्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है जैसे पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु एक निगम की स्थापना करना, तकनीकी परिवर्तनों और आधुनिकीकरण के क्षमकों पर भार को कम करने के लिए राष्ट्रीय मशीकरण कोष स्थापित करना, सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित परिवारों के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, युवाओं की सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का संवर्द्धन करना तथा दक्षिण-वर्षिण सहयोग को बढ़ावा देना।

सारणी 8.5 बजट घाटा, बाजार ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्रीय सरकार को सहायता (1989-90 से 1991-92 तक के राजकोषीय वर्ष)

संके	(करोड़ रुपये)			
	1989-90 (लेखा)	1990-91 (बजट अनुमान)	1990-91 (संशोधित अनुमान)	1991-92 (बजट अनुमान)
1	2	3	4	5
1. राजस्व लेखा	54614	60763	60049	70870
(i) प्राप्तियां (क)				
(ii) व्यय (क)	66526	73795	77634	84724
(iii) अधिशेष (+)/घाटा (-)	11912	—13032	17585	—13854
2. पूँजीगत लेखा				
(i) प्राप्तियां	30018	34165	38564	38174
(ii) वितरण	28698	28339	31751	32039
(iii) अधिशेष (+)/घाटा (-)	+1320	+5826	+6813	+6135
3. कुल प्राप्तियां [1 (i) + 2(i)]	84632	94928	98613	109044
4. कुल व्यय [1 (ii) + 2(ii)]	95224	102134	109385	116783
5. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	—10592	—7206	—10772	—7719
6. (4) के प्रतिशत के रूप में (5)	11.1	7.1	9.8	6.6
7. निवल बाजार ऋण*	7404 (8044)	8000 (8988)	8000 (8988)	7500 (8918)
8. (3) के प्रतिशत के रूप में (7)	8.7	8.4	8.1	6.9
9. भारतीय रिजर्व बैंक की खजाना बिंदो से भिन्न सरकारी रुपया प्रतिभूति संबंधी धारिताएं (ख)	+3000		+33481	
10. केंद्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में वृद्धि (+)/गिरावट (-) (ग)	+13813	+7206	+13000	+7719

\*सकल बाजार ऋण कोष्ठकों में दिये गये हैं।

(क) इसमें वाणिज्यिक विभाग शामिल है। राजस्व प्रक्रिया में प्रस्तावों के प्रभाव को शामिल किया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के अभिलेखों के अनुसार बड़ी मूल्य के आधार पर।

(ग) केंद्रीय सरकार के बजट में उल्लेखनीय मेमोरेंडम मद के अनुसार।

(घ) बड़ी मूल्य के अनुसार

#### केंद्र का योजना परिव्यय

8.20 1991-92 में केंद्रीय योजना परिव्यय की कुल 42,960 करोड़ रुपये की राशि से 1990-91 के संशोधित परिव्यय की तुलना में 12.9 प्रतिशत और उमी वर्ष के लिए बजट में अनुमानित परिव्यय से 9.3 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है। योजना परिव्यय के लिए बजट सहायता की राशि 1989-90 के 18,159 करोड़ रुपये कर दी जाएगी यद्यपि कुल वित्तपोषण में इसका अंश 1990-91 के 46.24

प्रतिशत से गिरकर 44.3 प्रतिशत रह जाएगा। राज्य और संघशासित क्षेत्रों की योजनाओं के लिए बजट सहायता में हाल के वर्षों में उच्च दर पर वृद्धि हो रही थी, जब उसके 19.0 प्रतिशत बढ़कर 1991-92 में 14.710 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है, वह वृद्धि 1990-91 में की गयी 20.7 प्रतिशत वृद्धि के प्रतिरिक्त होगी।

योजना और गैर-योजना व्यय\*

8.21 1991-92 के लिए अनुमानित 33,725 करोड़ रुपये का कुल योजना व्यय, 1990-91 में 29,956 करोड़ रुपये के तदनुरूप स्तर

\*इसका जड़ पूर्वकित कुल व्यय को धराबर् नहीं होता जिसमें वाणिज्यिक व्यवसायों तथा डाक सेवाओं के लेनदेन समग्र आधार पर दर्शाये गये हैं।

से 12.6 प्रतिशत अधिक होगा। इसमें से राजस्व योजना व्यय कुल व्यय का 50.6 प्रतिशत होगा अर्थात् योजना व्यय का एक बड़ा भाग उपयोग व्यय, आस्तियों के रखरखाव जैसे चालू शीर्षों के अंतर्गत किया जाएगा न कि नयी आस्तियों के निर्माण पर। व्यय में कटौती करने के एक महत्वपूर्ण प्रयास के अंतर्गत बजट में कुल नैर-योजना व्यय को 1990-91 के 76,761 करोड़ रुपये से 3.8 प्रतिशत बढ़ाकर 1991-92 में 79,697 करोड़ रुपये कर देने का प्रावधान किया गया है, वास्तविक अर्थों में यह पिछले वर्ष की तुलना में भारी कटौती का द्योतक है। नैर-योजना व्यय के अंतर्गत व्याज भुगतान, व्यय की सबसे बड़ी मद बने रहेंगे तथा 1991-92 में उनके 25.6 प्रतिशत बढ़कर 27,450 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। 1991-92 में 16,441 करोड़ रुपये की व्याज प्राप्ति के लिए समायोजित निवल व्याज-भार 1990-91 के 27.7 प्रतिशत की तुलना में केन्द्र की शुद्ध कर प्राप्ति के 31.3 प्रतिशत को आत्मसात् करना। 1991-92 में प्रस्तावित 16,350 करोड़ रुपये का कुल रक्षा व्यय केवल 3.8 प्रतिशत अथवा पिछले वर्ष के रक्षा व्यय से 600 करोड़ रुपये अधिक होगा। उपदानों के लिए कुल प्रावधान में 1990-91 के 12,121 करोड़ रुपये से 1991-92 में 10,395 करोड़ रुपये तक कमी की गई है तथा इन राशियों में दोनों में से प्रत्येक वर्ष में किसानों को ऋण राहत के लिए 1,500 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। प्रमुख उपदानों पर व्यय, जिसे 1990-91 के 9,550 करोड़ रुपये से 1991-92 में 8,616 करोड़ रुपये कर अंतरिम बजट में नीचे लाया गया था, को अनुमानित 7,824 करोड़ रुपये तक और कम कर दिया गया है। अंतरिम बजट में किश गन्ने प्रावधान से अधिक 792 करोड़ रुपये की वचत इसमें अंतर्निहित है, परंतु यह 1990-91 के स्तर से अधिक 1,726 करोड़ रुपये की व्यापक कटौती का द्योतक है। विनिमय दरों में समायोजनों और पुनः लाइसेंस प्रणाली के विस्तार के परिणामस्वरूप निर्मात उपदान 1990-91 के 2,700 करोड़ रुपये से 1991-92 में 1,224 करोड़ रुपये तक कम कर दिया गया है जोकि चालू वर्ष में 1,476 करोड़ रुपये की कटौती का द्योतक है। उर्वरकों के विषय में निम्न विशेषण वाले उर्वरकों, जिन्हें मूल्य और आवाजही के नियंत्रणों से मुक्त किया गया है, को छोड़कर अन्य सभी उर्वरकों के मूल्य में औसतन 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बाद में संसद में यह घोषणा की गई थी कि उर्वरकों के मूल्यों में बढ़ि को 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक कम किया जाएगा। जिसके परिणामस्वरूप बजट में व्यवस्थित वचत में 18,00 करोड़ रुपये से 1,350 करोड़ रुपये तक कमी आएगी। इसके अलावा लघु और सीमांत कृषकों को इस मूल्य-वृद्धि से छूट दी जाएगी जिससे 1991-92 के दौरान 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुमानित भार अधिरोपित किया जाएगा। जब कि सरकार ने चीनी के लिए उपदान (जो कि 350 करोड़ रुपये है) समाप्त करने का प्रस्ताव किया है, उसने खाद्यान्न उपदान हेतु प्रावधान अंतरिम बजट में व्यवस्थित 1,800 करोड़ रुपये और 1990-91 के लिए निर्धारित 2,450 करोड़ रुपये की तुलना में चालू वर्ष के लिए 2,600 करोड़ रुपये तक बढ़ाया है। बजट में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों तथा विदेशी सरकारों को योजनेतर अनुदानों, सरकारी उद्यमों को योजनेतर ऋणों एवं अन्य योजनेतर पूंजी परिव्यय पूंजी जैसी अन्य अनिवार्यतर मदों पर योजनेतर व्यय में कटौती का भी प्रस्ताव किया गया है। परिणामतः व्याज अदायगियों, रक्षा और प्रमुख उपदानों के लिए प्रावधान को हिसाब में लिये बिना कुल योजनेतर व्यय 1990-91 के 29,611 करोड़ रुपये से 1,538 करोड़ रुपये की कमी दर्शाते हुए 1991-92 में 28,073 करोड़ रुपये तक नीचे आएगी। इसके अलावा चालू वर्ष के दौरान देय होने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते की अदायगी के लिए बजट में कोई अलग व्यवस्था नहीं की गयी है, अतः अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किसी भी अदायगी के लिए वर्तमान बजट के प्रावधानों के अंतर्गत ही व्यवस्था करनी होगी। व्यय के क्षेत्र में इन समायोजन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप व्याज अदायगियों को छोड़कर कुल योजनेतर व्यय पिछले वर्ष के तुलना में 4.9 प्रतिशत की कमी दर्शाते हुए 54,911 करोड़ रुपये से 1991-92 में 52,247 करोड़ रुपये तक

नीचे आयेगा। तथापि, व्याज अदायगियों, रक्षा और उपदानों को एक साथ लेने पर भी उनका योग 1990-91 के 64.8 प्रतिशत की तुलना में 1991-92 में कुल योजनेतर व्यय का 68.0 प्रतिशत होगा।

#### बजट प्रस्ताव

8.22 राजकीय समायोजन द्वारा प्रधानतः 1991-92 में 2,617 करोड़ रुपये की सीमा तक अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर बल दिया गया है। इस प्रकार संसाधन जुटाने का प्रयास कुल कर-राजस्व में प्रत्यक्ष करों के अंशदान में निरावट की प्रवृत्ति को उलटने, विशिष्ट उपयोग को नियंत्रित करने, समाज के समृद्ध वर्गों को बढ़ते हुए कर-भार के अधीन करने एवं अनिवार्य उपयोग के पण्यों को उदार कर-व्यवहार प्रदान करने के द्वारा करना उद्दिष्ट है। प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में बजट प्रस्तावों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं : कंपनी कर दर में 5 प्रतिशत अंशों की वृद्धि, संबंध और मशीनों के मूल्यवृद्धि का सामान्य दर 33.3 प्रतिशत से 25 प्रतिशत कर घटाना 3 प्रतिशत पर निर्धारित दर के साथ बैंकों और विबीवी संस्थाओं की कुल व्याज आय पर व्याज कर का पुनः प्रवर्तन तथा व्यय-कर के आधार का विस्तार। परीक्ष कर संरचना में प्रस्तावित परिवर्तनों में सम्मिलित है : विशेष उत्पादन शुल्क की दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि, कुछ विलास-वस्तुओं के लिए शुल्क की दरों में उच्चमूर्खी संशोधन, अधिकतम 150 प्रतिशत तक मूल और सहायक सीमा शुल्क की मूलानुसार दर में कटौती आदि। राजस्व पर अतिरिक्त संसाधन जुटाने संबंधी (ए आर एम) उपायों के प्रभाव के बारे में नीचे की सारणी में दिये गये हैं :

कर शीर्ष	(करोड़ रुपये)		
	बजट प्रस्ताव	राज्यों का अंश	केन्द्र का निवल अंश
1. कंपनी कर	1,304	..	1,304
2. आयकर	125	97	28
3. व्याज कर	535	..	535
4. व्यय कर	150	..	150
5. सहपदा कर	25	..	25
6. सीमा शुल्क	510	..	510
7. संच के उत्पादन शुल्क	988	515	473
कुल	2.616	612	2.005

8.23 इसके अलावा, प्रवर्तित मूल्यों के क्षेत्र में कुल पेट्रोलियम उत्पादों के साथ मोटर स्पिरिट, घरेलू एलपी गैस और विमानन टरबाइन ईंधन के मूल्यों को बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि उद्योगोत्प्रेरण उपयोग के लिए मिट्टी के तेल की कीमतों में अक्टूबर 1990 से प्रचलित मूल्यों से कमी होगी।

#### राज्य बजट 1991-92

8.24 25 राज्यों, जिनमें से 10 राज्यों ने फरवरी/मार्च 1991 में लेख अनुदान (वोट ऑन अकाउंट) बजट प्रस्तुत किये हैं, कि संयुक्त बजट स्थिति से यह संकेत मिलता है कि कराधान की 1990-91 दर से समेकित राज्य बजटों के परिणामस्वरूप 1990-91 के 578 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) और 1989-90 के 127 करोड़ रुपये की तुलना में 1991-92 में 2,164 करोड़ रुपये का समग्र (पारंपरिक) घाटा होने का अनुमान है। 7 राज्यों द्वारा परिकल्पित अतिरिक्त संसाधन जुटाने (एआर एम) के उपायों से 17 राज्यों द्वारा 1990-91 में जुटाये गये 722 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन की तुलना में 93 करोड़ रुपये की शुद्ध राशि प्राप्त की जाएगी। 1991-92 के लिए नियमित संघीय बजट के अनुसार केन्द्र के नये कर प्रस्तावों में राज्यों का अंश 612 करोड़ रुपये रखा गया

अतिरिक्त संग्रहित जुटाने (एआरएम) और केन्द्र के अतिरिक्त कर प्रस्तावों से राज्यों के अंश के साथ समायोजित कुल घाटा 1,459 करोड़ रुपये हुआ। वित्तिय राज्य अपने नियमित बजटों के समय अतिरिक्त संसाधन जुटाने (एआरएम) के उपाय करने हेतु बचतबद्ध है, जबकि अन्य राज्य योजनाएं, विकासोन्मुख व्यय पर अधिकतर नियंत्रण जैसे-सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता प्रवर्द्ध करने, अन्य बचत का अतिरिक्त संसाधन करने, कर-दण्ड को रोकने, वर्तमान कर-संरचना के पुनर्विचार और कुशल प्रबंधन तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के द्वारा घाटा पूरा करने के लिए आशान्वित है।

बजट घाटे की अपेक्षाकृत संकल्पना और राज्य

8.25 पिछले दशक के दौरान केन्द्रीय सरकार की तरह राज्यों के बजट कार्यों में संसाधनों के समग्र अंतर में बहुविध वृद्धि हुई थी। जबकि राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे के संपूर्ण स्तरों में 1980 के बाद के दशक के पूर्वार्ध में 1980-81 के 3,712 करोड़ रुपये से 1985-86 में 7,250 करोड़ रुपये तक दुगुनी वृद्धि हुई, उक्त दशक के उत्तरार्ध में उसकी वृद्धि 158 प्रतिशत पर अधिक तेज थी और वह 1990-91 में 19,404 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष से 1991-92 में 20,567 करोड़ रुपये तक अथवा 6.0 प्रतिशत की वृद्धि करने हेतु बजट में व्यवस्था की गई है (सारणी 8.6 करोड़ रुपये और ग्राफ 8) तदनुसार, सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे में 1980-81 के 2.7 प्रतिशत से 1985-86 में 2.9 प्रतिशत तक और आगे 1990-91 में 3.7 प्रतिशत तक वृद्धि हुई।

8.26 राज्यों के समग्र संसाधन अंतर के आकार में वृद्धि और उनके वित्त पर उसके प्रतिकूल परिणामों को प्रमुख राजस्व खाने में राज्य सरकारों के परिवर्तनों के साथ ध्यान में रखा जाता बाह्य जिनमें 1980 के बाद के दशक के उत्तरार्ध में स्पष्ट हुआ था। राज्यों का संयुक्त समग्र राजस्व खाना जो 1986-87 तक कुल निराकर आधिक्य दिखा रहा था, बाह्य के वर्ष में घाटे के रूप में परिवर्तित हुआ और तब से राजस्व घाटे का परिमाण गीघ्र गति से बढ़ता रहा है जिसे पूंजीगत संसाधनों से

वित्तपोषित करने की आवश्यकता है। 1991-92 में बजट में व्यवस्थित 4,573 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा उस वर्ष में राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का 22.2 प्रतिशत है।

8.27 राज्यों के संसाधन अंतर की वित्त व्यवस्था के स्वरूप से यह स्पष्ट हुआ कि औसतन उक्त अंतर के आधे भाग को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋणों के माध्यम से वित्तपोषित किया गया जबकि शेष आधे भाग को बाजार में उधार, राज्य भविष्य निधियों और अन्य स्रोतों के माध्यम से पूरा किया गया (सारणी 8.7)।

संकेतित बजट स्थिति :

केन्द्र और राज्य

8.28 अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपायों से प्राप्त राशि को हिसाब में लेने के बाद 1990-91 के संशोधित अनुमानों (सारणी 8.8) में 11,350 करोड़ रुपये के घाटे में 19.1 प्रतिशत की कमी दर्शाते हुए, 1991-92 में संयुक्त समग्र घाटा 9,178 करोड़ रुपये रखा गया है। तथापि, 10 राज्यों द्वारा उनके नियमित बजट प्रस्तुत करने के बाद इस घाटे में कुछ संशोधन होने की संभावना है।

8.29 करो और श्रुतों की संशोधित दरों पर केन्द्र और राज्यों की कुल प्राप्ति जो 1991-92 में 1,77,094 करोड़ रुपये पर अनुमानित है, पिछले वर्ष में दर्ज की गई 15.8 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 11.9 प्रतिशत उच्चतर होगी। राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति दोनों के विषय में 1990-91 में उनके संबंधित स्तरों से वृद्धि होने की प्रत्याशा है। केन्द्र की निवल पूंजीगत प्राप्ति से प्रत्याशित एक प्रतिशत अंक की गिरावट के कारण समग्र पूंजीगत प्राप्ति में 1990-91 में हुई 23.5 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि की तुलना में 2.6 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। केन्द्र की निवल पूंजीगत प्राप्ति में समग्र कमी 1991-92 के बजट में प्रस्तावित कुल संरचनात्मक गमावों में से शुद्ध बाजार उधारों और बाहरी सहायता के निम्नतर प्रावधान एवं अन्य पूंजीगत प्राप्ति की कमी के कारण है।

सारणी 8.6 राज्यों का मुद्रांकन, बजट, राजस्व और निवल राजकोषीय घाटा

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	सकल राजकोषीय	निवल राजकोषीय	मुद्रांकन घाटा	पारंपरिक घाटा	राजस्व घाटा	चालू बाजार मूल्य पर सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	3712	1714	487	807	+1486	2.7
1981-82	4062	2209	789	1020	+1379	2.5
1982-83	4986	2830	+860	820	+888	2.8
1983-84	6359	4067	38	561	+211	3.1
1984-85	8199	5834	1486	1438	924	3.5
1985-86	7520	4799	+1862	+1688	+654	2.9
1986-87	9269	6107	516	667	+169	3.2
1987-88	11219	7742	+157	66	1088	3.4
1988-89	11672	8884	425	+380	1807	3.0
1989-90	15359	11547	255	127	3580	3.5
1990-91 (सं.अ.)	19404	14661	419	578	5308	3.7
1991-92 (अ.अ.)	20567	15093	उपलब्ध नहीं	1159	4573	—

+ आधिक्य दिखाता है।

\*आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के पास खाते रखने वाले 23 राज्यों से संबंधित हैं।

## सारणी-8.7 : राज्यों के सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय सरकार से ऋण (निवल)	बाजार से उधार (निवल)	अन्य	सकल राजकोषीय घाटा (2 + 3 + 4)	कुल	राज्यों का देकाया देयमाण (वर्ष की समाप्ति पर)	
						जितमें से	
						ग्रामिण केन्द्रीय सरकार से ऋण और	बाजार से ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1564 42.1	184 5.0	1964 52.9	3712 100.0	23977	17071	2973
1981-82	2000 49.2	339 8.4	1723 42.4	4062 100.0	27729	19080	3328
1982-83	2735 54.9	393 7.9	1858 37.2	4986 100.0	29457	20425(ले)	3735
1983-84	3031 47.7	563 8.8	2765 43.5	6359 100.0	38493	27539(ले)	4408
1984-85	3580 43.7	693 8.4	3926 47.9	8199 100.0	44394	31226	5100
1985-86	5757 76.6	1010 13.4	753 10.0	7520 100.0	51113	36984(ले)	6110
1986-87	4786 51.6	1147 12.4	3336 36.0	9269 100.0	57912	41770	7257
1987-88	5832 52.0	1523 13.6	3864 34.4	11219 100.0	67162	47602	8779
1988-89	6688 57.3	1973 16.9	3011 25.8	11672 100.0	78184	54292	10712
1989-90	7917 51.5	1869 12.2	5573 36.3	15359 100.0	91597*	62557*	12902*
1990-91*	10318 53.2	2341 12.1	6745 34.7	19404 100.0	106481‡	72091‡	15830‡
1991-92‡	11297 54.9	2205 10.7	7065 34.4	20567 100.0	उ.न.	उ.न.	उ.न.

§ इनमें प्रांतरिक ऋण, केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण और ग्रामिण एवं भविष्य निर्धियां आदि शामिल हैं।

\* संशोधित अनुमान । बजट अनुमान उ.न. = उपलब्ध नहीं।

(ले) केन्द्र द्वारा राज्यों को उनके ओवरड्राफ्ट चुकाने के लिए 1982-83 में दिये गये रुपये 1,743 करोड़ रुपये, 1983-84 में दिये गये 400 करोड़ रुपये और 1985-86 में दिये गये 1,628 करोड़ रुपये को मध्यावधि ऋण शामिल है।

टिप्पणी : 1. बराबर में दिये गये आंकड़ों कुल का प्रतिशत है।



सारणी 8.8 : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और वितरण राजकोषीय वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक

(करोड़ रुपये)

मदें	1989-90 (लेखा)	1990-91 (बजट अनुमान)	1990-91 (संशोधित अनुमान)	1991-92* (बजट अनुमान)	निम्नलिखित में प्रतिशत घट-बढ़	
					स्तंभ 2 की तुलना में स्तंभ 4	स्तंभ 4 की तुलना में स्तंभ 5
1	2	3	4	5	6	7
I कुल प्राप्तियाँ	136714	154571	158309	177094	15.8	11.9
अ. राजस्व प्राप्तियाँ	97950	109111	109260	126781	11.5	16.0
उनमें से :						
कर प्राप्तियाँ (क+ख)	77441	89285	89107	103323	15.1	16.0
(क) प्रत्यक्ष कर	13025	14793	15507	17829	19.1	15.0
(ख) परोक्ष कर	64416	74492	73600	85494	14.3	16.2
आ. पूँजीगत प्राप्तियाँ	38764	45460	49049	50313	26.5	2.6
II. कुल वितरण (अ+आ+ई)	147433	163514	169659	186272	15.1	9.8
अ. विकास संबंधी व्यय						
(क+ख+ग)	88418	96153	100713	104960	13.9	4.2
(क) राजस्व	63155	69947	72536	75976	14.9	4.7
(ख) पूँजीगत परिव्यय	15127	16585	16712	17608	10.5	5.4
(ग) ऋण और धनग्रहण	10136	9621	11465	11376	13.1	-0.8
आ. विकासेतर व्यय						
(क+ख+ग)	55089	62889	64455	74435	17.0	15.5
(क) राजस्व	49735	57218	58815	68304	18.3	16.1
(ख) पूँजीगत	4648	5349	5263	5750	13.2	9.3
(ग) ऋण और धनग्रहण	706	322	377	381	-46.6	11
इ. अन्य	3926	4472	4491	6877	14.4	53.1
III. समग्र अधिशेष (+)/घाटा (-)	-10719	-8943	-11350	-9178		

\*इसमें बजट प्रस्तावों के प्रभाव को हिसाब में लिया गया है।

टिप्पणी : 1. आकड़ों 25 राज्यों से संबंधित हैं, इनमें से 10 लेखा अनुदान बजट पर आधारित हैं और शेष 15 अंतिम बजट से लिये गये हैं। इसके अलावा नागालैंड, बिहार तथा जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में वर्ष 1989-90 के आकड़ों संशोधित अनुमान हैं।

2. अन्य वितरणों में आंतरिक और विदेशी ऋण की चुकोती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को मुद्रावजा और सभनूदेणन, आकस्मिक निधियों में वित्तियोजन एवं निवल प्रेषण शामिल है तथा इन्हे, राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने बजट में उल्लेखित राज्यों द्वारा केन्द्रीय सरकार को ऋणों के चुकोती संबंधी आकड़ों में भिन्नता के लिए समायोजित किया गया है।

वितरण : विकास संबंधी और विकासेतर

8.30 1991-92 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के समग्र वितरण 1,86,272 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जिससे 9.8 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है जबकि 1990-91 में 15.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। 1991-92 के दौरान विकासेतर व्यय में 15.5 प्रतिशत वृद्धि का बजट में अनुमान लगाया गया है जो 1990-91 में हुई 17.0 प्रतिशत वृद्धि के अतिरिक्त होगी, तथा विकास संबंधी व्यय की वृद्धि दर 13.9 प्रतिशत से काफी कम होकर 4.2 प्रतिशत रह जायेगी। परिणामतः केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कुल वितरणों में विकासेतर व्यय का अंश 1990-91 के 38.0 प्रतिशत से बढ़कर 1991-92 में 40.0 प्रतिशत हो जाएगा तथा तदनुसार अवधि में विकास संबंधी व्यय का अंश 59.4 प्रतिशत से कम होकर 56.3 प्रतिशत रह जायेगा। 1980-81 के दौरान विकास संबंधी और विकासेतर व्यय का अंश क्रमशः 66 प्रतिशत और 30.6 प्रतिशत था जिससे पिछले दशक के दौरान सरकार के व्यय के स्वरूप में तेज गिरावट परिलक्षित होती है (सारणी 8.9)। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में वृद्धि सारणी 8.10 में दर्शायी गयी है।

बाजार उधार

8.31 सारणी 8.11 में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा प्रायोजित प्राधिकरणों एवं संस्थाओं के बाजार उधार की प्रगति दर्शायी गयी है। केन्द्रीय सरकार के 8,989 करोड़ रुपये के सकल बाजार उधार में से नकदी अभिदान की राशि 8,531 करोड़ रुपये थी तथा

परिपक्व होने वाले ऋणों के परिवर्तन की राशि 458 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकारों के मामले में 1990-91 के दौरान परिपक्व होने वाले कोई ऋण नहीं थे।

8.32 1991-92 के अपने बजट में केन्द्र ने 8,918 करोड़ रुपये सकल बाजार उधार का अनुमान लगाया ज जिसमें से परिपक्व होने वाले ऋणों की चुकोती के लिए 1,418 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान करने के बाद निवल प्राप्ति की राशि 7,500 करोड़ रुपये होगी जो 1990-91 की कुल राशि की तुलना में 501 करोड़ रुपये (6.3 प्रतिशत) कम है।

केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर व्याज दरें

8.33 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋणों पर व्याज दरों के स्वरूप में परिवर्तन किया गया था तथा उन्हें 11.50 प्रतिशत की अधिकतम व्याज दर के अंतर रखा गया। संशोधित दरें निम्नानुसार हैं:

परिपक्वता (वर्ष)	1989-90 (प्रतिशत)	1990-91 (प्रतिशत)
5	10.00	10.50
10	10.50	10.75
15	11.00	11.25
20	11.50	11.50

\* 5 वर्ष की परिपक्वता वाले ऋण 1989-90 में जारी नहीं किये गये।

सारणी 8.9: केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विकास संबंधी तथा विकासेतर व्यय

(करोड़ रुपये)

वर्ष	केन्द्रीय सरकार			राज्य सरकारों			केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की संयुक्त स्थिति				
	विकास संबंधी व्यय	विकासे-तर व्यय	जोड़	विकास संबंधी व्यय	विकासे-तर व्यय	अन्य*	जोड़	विकास संबंधी व्यय	विकासे-तर व्यय	अन्य**	जोड़
1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-	11-	12-
1980-81	13932 (57.6)	10245 (42.4)	24177 (100.0)	15961 (70.1)	4289 (18.8)	2520 (11.1)	22770 (100.0)	25845 (66.0)	11977 (30.6)	1338 (3.4)	39160 (100.0)
1981-82	16084 (60.9)	10331 (39.1)	26415 (100.0)	17960 (70.2)	4996 (19.6)	2615 (10.2)	25571 (100.0)	28798 (64.7)	13609 (30.6)	2074 (4.7)	44479 (100.0)
1982-83	19557 (60.7)	12673 (39.3)	32230 (100.0)	20649 (71.0)	5883 (20.2)	2665 (8.8)	29097 (100.0)	33643 (64.6)	16473 (31.7)	1941 (3.7)	52057 (100.0)
1983-84	22207 (58.8)	15564 (41.2)	37771 (100.0)	23972 (71.2)	6882 (20.4)	2814 (8.4)	33668 (100.0)	38352 (63.9)	19936 (33.3)	1701 (2.8)	59989 (100.0)
1984-85	27375 (59.6)	18525 (40.4)	45900 (100.0)	27958 (70.3)	8340 (21.0)	3448 (8.7)	39746 (100.0)	46265 (64.6)	23390 (32.6)	1999 (2.8)	71654 (100.0)
1985-86	29979 (58.9)	20927 (41.1)	50906 (100.0)	31733 (70.7)	9617 (21.4)	3519 (7.9)	44869 (100.0)	55032 (65.1)	27332 (32.4)	2106 (2.5)	84470 (100.0)
1986-87	35498 (57.7)	26060 (42.3)	61558 (100.0)	36827 (70.6)	11220 (21.5)	4149 (7.9)	52196 (100.0)	64441 (63.4)	33682 (33.2)	3479 (3.4)	101602 (100.0)
1987-88	36573 (54.7)	30261 (45.3)	66834 (100.0)	42141 (70.2)	13754 (22.9)	4104 (6.9)	59999 (100.0)	69087 (62.2)	39460 (35.5)	2614 (2.3)	111161 (100.0)
1988-89	41536 (53.9)	35579 (46.1)	77055 (100.0)	47064 (69.8)	15803 (23.4)	4599 (6.8)	67466 (100.0)	78983 (61.6)	45940 (35.8)	3322 (2.6)	128245 (100.0)
1989-90†	53639 (56.3)	41585 (43.7)	95224 (100.0)	52555 (58.5)	19761 (25.8)	4393 (5.7)	76709 (100.0)	88418 (60.0)	55089 (37.4)	3926 (2.6)	147433 (100.0)
1990-91 (स.घ.)\$	60257 (55.1)	49128 (44.9)	109385 (100.0)	64487 (69.5)	23336 (25.1)	5042 (5.4)	92865 (100.0)	100713 (59.4)	64455 (38.0)	4491 (2.6)	169659 (100.0)
1991-92 (न.घ.)\$	62015 (53.1)	54748 (46.9)	116763 (100.0)	69896 (67.4)	28616 (27.6)	5197 (5.0)	103709 (100.0)	104980 (56.3)	74435 (40.0)	6877 (3.7)	186272 (100.0)

(a) आंतरिक और विदेशों की चुकौती शामिल नहीं है।

\$ आंकड़े 25 राज्यों से संबंधित हैं इनमें से 10 लेखा अनुदान पर आधारित हैं और शेष 15 अन्तिम बजट से लिये गये हैं। इसके अलावा, नागालैंड, विहार तथा जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में वर्ष 1989-90 के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

\* इसमें आंतरिक ऋण की चुकौती, केन्द्रीय सरकार को ऋणों की चुकौती, आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन तथा प्रेषण (निवल) स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज्य मन्त्रालयों को मुद्रावत्ता और समनुदेनन शामिल हैं।

SS इसमें आंतरिक और विदेशी ऋण की चुकौती, स्थानीय निकायों और पंचायती राज्य संस्थाओं को मुद्रावत्ता और समनुदेनन, आकस्मिक निधि के लिए विनियोजन, राज्य सरकारों के निवल प्रेषण शामिल हैं।

नया इन्हें राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में उल्लेखित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को ऋणों की चुकौती संबंधी आंकड़ों में मिश्रता के लिए समायोजित किया गया है।

टिप्पणी: 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित कुल व्यय में प्रतिशत अंश दर्शाते हैं।

2. अंतर सरकारों समायोजनों के कारण केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के आंकड़ों का जोड़ संयुक्त स्थिति से मेल नहीं खाता।

3. 1989-90 से पूर्व केन्द्रीय सरकार के व्यय संबंधी आंकड़ों में रेलवे पर किये गये पूंजीगत व्यय तथा आल्प व्यय जमाराशियों पर राज्यों के दिये गये ऋणों को हिमाय में नहीं लिया गया है।

आन्धीय ऋणों में रिजर्व बैंक की सहायता

8.34 वर्ष 1990-91 के दौरान केन्द्रीय सरकार के ऋणों में रिजर्व बैंक के प्रारंभिक अभिदान की राशि 4,432 करोड़ रुपये या जारी किये कुल ऋणों का 49.3 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष इसके प्रारंभिक अभिदान की 4,861 करोड़ रुपये (कुल राशि का 60.4 प्रतिशत) की राशि से काफी कम थी। 1990-91 के दौरान रिजर्व बैंक ने प्रारंभ में अभिवृद्धि अपनी प्रतिभृतियों का कुल अंश अपने खुले बाजार के कार्यक्रमों के माध्यम से देखा। केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभृतियों की रिजर्व बैंक की धारिताओं में 3,261 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जबकि

1989-90 में उनमें 3,106 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। रिजर्व बैंक ने पुनः कम आवश्यकता के अंतर्गत सम्भाव्य की केन्द्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभृतियों की धारिताओं में 1990-91 के दौरान 406 करोड़ रुपये की गिरावट आयी जबकि 1989-90 में उनमें 197 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। धारणाव्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने रिजर्व बैंक को 30,220 करोड़ रुपये मूल्य की विविध प्रतिभृतियों जारी की जिनमें से 30,000 करोड़ रुपये तदर्थ खजाना बिलों के निधीकरण हेतु थे। इससे पहले 1987-88 में 17,500 करोड़ रुपये के तदर्थ खजाना बिलों का निधीकरण किया गया था।

सारणी 8.10: केन्द्र और राज्यों के प्रत्यक्ष और परोक्ष कर राजस्व

(करोड़ रुपये)

केन्द्र (सकल)				राज्य +			संयुक्त		
वर्ष	प्रत्यक्ष	परोक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	परोक्ष	जोड़	प्रत्यक्ष	परोक्ष	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1980-81	2907	10242	13149	686	5929	6615	3593	16171	19764
क	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
ख	2.1	7.5	9.6	0.5	4.4	4.9	2.6	11.9	14.5
1984-85	4626	18802	23428	1230	11108	12338	5856	29910	35766
क	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.0	16.4	83.6	100.0
ख	2.0	8.1	10.1	0.5	4.8	5.3	2.5	12.9	15.4
1985-86	5563	23109	28672	1401	12919	14320	6964	36028	42992
क	19.5	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.0
ख	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6234	26559	32793	1585	14934	16619	7919	41493	49412
क	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
ख	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.2	16.9
1987-88	6751	30861	37612	1960	17438	19398	8711	48299	57010
क	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
ख	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.6	17.1
1988-89	8324	35596	44420	2413	19988	22401	11237	55584	66821
क	19.9	80.1	100.0	10.8	89.2	100.0	16.3	83.2	100.0
ख	2.2	9.0	11.2	0.6	5.1	5.7	2.8	14.1	16.9
1989-90 <sup>1</sup>	10003	41578	51581	3022	22838	25860	13025	64416	77441
क	19.4	80.6	100.0	11.7	39.3	100.0	16.8	83.2	100.0
ख	2.2	9.4	11.6	0.7	5.2	5.8	2.9	14.6	17.5
1990-91 (अंश)*	12180	46673	58853	3327	26927	30254	15507	73600	8910
क	20.7	79.3	100.0	11.0	89.0	100.0	17.4	82.6	100.0
ख	2.3	9.0	11.3	0.6	5.2	5.8	3.0	14.2	17.2
1991-92 (अंश)*	13892	51363	68755	3937	30631	34568	17829	85494	103323
क	20.2	79.8	100.0	11.4	83.6	100.0	17.3	82.7	100.0
ख	2.4	9.4	11.8	0.7	5.3	6.0	3.1	14.7	17.8

1. इसमें, केन्द्रीय बजट प्रलेखों में सूचित केन्द्रीय करों में राज्यों का अंश शामिल नहीं किया गया है।

\* अनुमानित

(क) कुल कर राजस्व में प्रतिगत अंश दर्शाता है, और

(ख) सकल देशी उत्पाद के अनुपात की तुलना में प्रतिशत दर्शाता है।



9.1) मार्च 1990 के अंत की स्थिति यह है कि जहाँ बैंकों की वित्तीय प्राप्तियाँ 2,05,515 करोड़ रुपये थीं, वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय प्राप्तियाँ 1,02,184 करोड़ रुपये थीं (सारणी 9.1) एवं (9.2)। ठीक इसी समय वित्तीय संस्थाओं के बकाया ऋण व प्रथम बाणिज्य बैंकों के बकाया ऋण के लगभग 47 प्रतिशत के बराबर थे। सरकारी प्रतिष्ठितियों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बांडों और डिबेंचरों में तथा निजी कंपनी। शेयर की इक्विटियों और डिबेंचरों में वित्तीय संस्थाओं का निवेश, बाणिज्य बैंकों के इसी प्रकार के निवेशों के लगभग 49 प्रतिशत के बराबर था।

जहाँ सभी वित्तीय संस्थाओं (नाबांडें सहित) के बकाया ऋणों और प्रथमों में 1989-90 के दौरान 6,175 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, वहीं बाणिज्य बैंकों के मामले में यह वृद्धि 16,737 करोड़ रुपये हुई। जैसा कि हमारी पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था, जहाँ वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बीच कुछ वित्तीय घातन-प्रयाण के कारण इस घाकड़ों की बारीकी से तुलना नहीं हो सकती, इससे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यकलापों के बायरे को एक प्रत्यक्ष अन्तर मिलती है।

#### सारणी-9.1: वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की वित्तीय प्राप्तियाँ

मार्च के अंत/अंतिम शुक्रवार की स्थिति

		(करोड़ रुपये)					
संस्था संवर्ग		1981	1986	1987	1988	1989	1990
1		2	3	4	5	6	7
I	बैंक (1 + 2 + 3)*	46987	108372	127876	147186	176461	205515
1.	सभी अनुसूचित बाणिज्य बैंक**	44622	103627	122513	140747	168480	196377
2	गैर अनुसूचित बाणिज्य बैंक***	9	23	30	36	53	62
	कुल बाणिज्य बैंक (1 + 2)	44631	103650	122543	140783	168533	196439
3.	राज्य सहकारी बैंक**	2356	4722	5333	6403	7928	9076
II	वित्तीय संस्थाएं	16650	45907	54470	66828	83651	102184
4	सीमादी ऋण देने वाली संस्थाएं (अखिल भारतीय)	6143	21555	25674	31239	37874	44941
5.	राज्य स्तरीय संस्थाएं	1733	4341	5290	6241	7204	7899
6.	निवेश संस्थाएं†	8534	19143	22475	28037	36980	47694
7.	अन्य संस्थाएं(‡)	240	868	1031	1311	1593	1650
III	जोड़ (I + II)	63637	154279	182346	214014	260112	307699
IV	प्रतिशत अंश						
(क)	III में I का	73.8	70.2	70.1	68.8	67.8	66.8
(ख)	III में II का	26.2	29.8	29.9	31.2	32.2	33.2

\* य मदें शामिल करें: (i) रोकड़ गेय एवं रिक्त बैंक के पास गेय (ii) बैंकिंग व्यवस्था की प्राप्तियाँ (iii) निवेश (iv) बैंक ऋण (कुल ऋण, तकदी ऋण तथा ओवरड्राफ्ट और खरीदे व भुनाये गये बिल) और बैंकों पर बकाया।

\*\* भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अन्तर्गत विवरणियों के अनुसार।

\*\*\* बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अन्तर्गत विवरणियों के अनुसार।

† सीमादी ऋणदात्री संस्थाओं में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा निर्यात-आयात बैंक शामिल हैं।

‡ निवेश संस्थाओं में भारतीय यूनित ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा इनकी सहायक संस्थाएं शामिल हैं।

§ राष्ट्रीय आवास बैंक शामिल है।

(@) अन्य संस्थाओं में निवेश बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम तथा भारतीय निर्यात गारंटी निगम शामिल हैं।

## सारणी-9.2: वित्तीय संस्थाएँ: कुल बकाया वित्तीय प्राप्तियाँ

(करोड़ रुपये)

संस्था	1980-81	1986-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
<b>घ. ग्रामीण भारतीय मीडाटी बिजनेस बाली संस्थाएँ</b>						
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3098.6	9633.9	11529.6	13922.3	17053.9	20317.9
2. नावाडे*	1635.1	6568.6	7445.4	8776.4	10363.8	11771.7
2. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	727.9	2210.6	2799.4	3652.8	4500.1	5603.9
4. भारतीय औद्योगिक बिजनेस निगम	589.1	1998.3	2426.7	2105.7	3707.3	4477.6
5. निर्यात-आयात बैंक	--	811.1	1042.2	1276.0	1478.4	1715.9
6. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	92.4	342.3	430.2	503.6	589.8	694.0
7. राष्ट्रीय आवास बैंक	--	--	--	--	181.1	360.3
'घ' का जोड़ (1 से 7 तक)	6143.1	21354.8	25673.5	31238.8	37874.4	44941.3
<b>घा. राज्य स्तरीय संस्थाएँ</b>						
8. राज्य वित्तीय निगम	1073.6	2696.7	3264.9	3910.9	4657.0	5994.2
9. राज्य औद्योगिक विकास निगम	659.5	1643.9	2024.6	2329.6	2347.2	2404.9
'घा' का जोड़ (8 से 9 तक)	1733.1	4340.6	5289.5	6240.5	7204.2	7899.1
<b>द. विशेष संस्थाएँ</b>						
10. जीवन बीमा निगम	6814.9	12935.9	14225.2	17086.9	20118.0	23988.4
11. साधारण बीमा निगम और सहायकी संस्थाएँ	1198.9	2806.7	3323.0	3735.5	4418.8	5284.6
12. भारतीय युनिट ट्रस्ट	520.6	3346.3	4927.3	7214.6	12443.1	18421.2
'द' का जोड़ (10 से 12 तक)	8534.4	19142.9	22475.5	28037.0	36979.9	47694.2
<b>इ. अन्य संस्थाएँ</b>						
13. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम	200.3	781.6	919.1	1163.9	1372.5	1423.1
14. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	39.5	86.9	112.0	142.3	215.3	226.9
'ई' का जोड़ (13 से 14 तक)	239.8	868.5	1031.1	1311.2	1592.8	1650.0
कुल जोड़ (घ+घा+द+ई)	16850.4	45906.8	54489.6	66827.6	83631.3	102184.6

\* 1980-81 के आंकड़े कृषि पुनर्विलस और विकास निगम से संबंधित हैं क्योंकि नावाडे की स्थापना 1982 में हुई थी।

9.4 यहाँ यह जान लेना असंभव नहीं होगा कि स्वयं देश का वित्तीय बाजार फीलाव और बहुप्राथम्य होने का एक और प्रक्रिया में होकर गुजर रहा है। हाल के वर्षों में कई ऐसी वित्तीय संस्थाएँ स्थापित की गयी हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों, जैसे रेलवे, बिजली, परिवहन, आवास आदि की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इनमें से कुछ थोड़े दिवसों में जारी कर संसाधन जुटाती आ रही हैं। इसके प्रतिरिक्त, कई नए बैंक वित्तीय कर्मियों एवं घरेलू क्षेत्र की बचतों का एक हिस्सा उगाह कर किस्म-किस्म की वित्तीय सेवाएँ दे रही हैं। बैंकों द्वारा स्थापित उपायी कारोबार में म्युचुअल फंड, लीजिंग, पूंजी उधम, आवास विल तथा ग्राहक जैसे कार्य-कलाओं की प्रपना लिया गया है। पाप बैंक की उपायी इकायों के म्युचुअल फंड, विभिन्न योजनाओं, खिन्में पर्यटन कर राहत मुक्त इक्विटी लिक्विड बचत योजनाएँ भी शामिल हैं, के माध्यम से जनता से 1990-91 के दौरान उल्लेखनीय धन राशियाँ अटाने में सफल रहे हैं।

9.3 वित्तीय संस्थाओं के लिए सहायकों का एक बड़ा स्रोत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी दीर्घकालीन प्रवर्तन निधियाँ तथा साथ ही अल्प-कालिक ऋण सोमाओं के माध्यम से ली जाने वाली वित्तीय सहायता है (सारणी 9.3)। सभी दीर्घकालीन प्रवर्तन निधियों के अंतर्गत जून 1991 के अंत तक कुल बकाया राशि 9,465 करोड़ रुपये थी। इसके प्रतिरिक्त निष्पक्ष बैंकों और सरकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक के दायों का राजि मान

1990 के अंत तक के 2,910 करोड़ रुपये में बढ़कर कर मार्च 1991 के अंत में 3,999 करोड़ रुपये हो गयी है। आवधिक रूप में ऋण देने वाली अन्य प्रमुख भारतीय संस्थाओं की तरह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भी अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 व 46 के अंतर्गत अल्पकालिक/दीर्घकालिक निधियाँ कर्ज देने का पात्र है और इस प्रयोजन के लिए अधिनियम की उक्त धाराओं में शोधित संशोधन किया गया है ताकि यह बैंक ऐसी सहायता प्रदान करने में समर्थ हो सके। वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को इस वर्ष के दौरान उपयोग के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से 400 करोड़ रुपये का दीर्घकालीन ऋण संचर किया गया था जिसकी चुकोती 6 प्रतिशत वार्षिक की शियायती दर पर 15 वर्ष के बाद की जा सकेगी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने इस ऋण सोमा का पूरा-पूरा उपयोग किया और इस बैंक द्वारा राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि से लिये गये ऋण का बाग्या राजि धाज की तारीख में 400 करोड़ रुपये है। इसके प्रतिरिक्त, वर्ष के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 300 करोड़ रुपये प्रत्येक की ती धन-अल्प धर्मात् कुल 600 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सोमाएँ संचर की गयीं। तथापि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 300 करोड़ रुपये की पहली ऋण सोमा में से मई 1991 के अंत तक केवल 74 करोड़ रुपये का ही उपयोग किया।

सारणी-9, 3 वित्तिय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता दीर्घकालीन प्रवर्तन निधिवा, लाभ का आवंटन और मध्यावधि/ अल्पवधि ऋण

(करोड़ रुपये)

	1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91	
	वर्ष के लिए मंजूर	जून के अंत में बकाया संचयी	वर्ष के लिए मंजूर	जून के अंत में बकाया संचयी	वर्ष के लिए मंजूर	जून के अंत में बकाया संचयी	वर्ष के लिए मंजूर	जून के अंत में बकाया संचयी	वर्ष के लिए मंजूर	जून के अंत में बकाया संचयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क. निम्नलिखित से दीर्घवधि सहायता:										
I राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घवधि प्रवर्तन) निधि										
1 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	330.0	2,875.3	360.0	3,198.6	375.0	3,528.0	375.0	3,822.0	--	3,703.2
2 निर्यात-आयात बैंक	85.0	345.0	90.0	433.0	95.0	530.0	95.0	625.0	120.0	745.0
3 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	15.0	25.0	20.0	45.0	25.0	70.0	25.0	95.0	35.0	130.0
4 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	--	--	--	--	--	--	--	--	400.0	400.0
II. राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि राष्ट्रीय आवास बैंक	--	--	--	--	50.0	50.0	25.0	75.0	50.0	5,125.0
ख. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए आवास भारतीय रिजर्व बैंक के लाभ का आवंटन										
I. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि/नाबाड़े	350.0	2,355.0	300.0	2,855.0	330.0	2,985.0	330.0	3,315.0	375.0	3,690.0
II. राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्वरोत्थन) निधि/नाबाड़े जोड़ (अ + आ)	10.0	630.0	10.0	640.0	10.0	650.0	10.0	660.0	10.0	670.0
		6,230.3		6,973.6		7,813.3		8,592.0		9,465.2
ग. रिजर्व बैंक द्वारा माध्यमिक मध्यावधि ऋण सहायता										
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	300.0 }		300.0 }		300.0 }		400.0 }		400.0 }	--
2. भारतीय औद्योगिक वित्त नियम	15.0 }		15.0 }		30.0 }		40.0 }		50.0* }	41.0
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश नियम	10.0 }	82.5	25.0 }	24.5	25.4 }	42.4	30.6 }	67.6	33.0 }	-
4. राज्य वित्तीय नियम	55.2 }		65.4 }		82.9 }		83.0 }		98.2 }	10.6@@
5. भारतीय लघु-उद्योग-विकास बैंक	-- }	--	-- }		-- }		-- }		300.0 }	--
									300.0 }	
ह. सामान्य ऋण सुविधा- नाबाड़े जोड़ (इ + ई)	1400.0	949.7	1,950.9	1,416.8	2,700.0	2,277.7	3,35.0	2,858.4	3,350.0	3,322.4
बकाया संचयी सहायता का कुल जोड़ (अ + आ + इ + ई)		1,032.2		1,441.3		2,320.1		2,926.0		3,374.0
		7,262.5		8,414.9		10,133.4		11,518.0		12,839.2

@नवंबर वर्ष 1991 के लिए मंजूर (बाद में सीमा को बढ़ा कर 60 करोड़ रुपये किया गया)

\*वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च के लिए) मंजूर

ईसी सीमाओं में से केवल पहली सीमा से 75 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया

@@ अल्पवधि

[भाग II-खण्ड 3(ii)]

सारणी का संशोधन: मार्च 25, 1992/भाग 9, 1994

वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान सहायता

9.6 वर्ष 1990-91 के दौरान सभी वित्तीय संस्थाओं (संवि०स\*) द्वारा कुल 19,917.1 करोड़ रुपये की धननिष्ठ सहायता मंजूर की गई। सहायता की यह राशि पिछले वर्ष की राशि (15,647.3 करोड़ रुपये) से 4,269.8 करोड़ रुपये अर्थात् 27.3 प्रतिशत अधिक थी। इन संस्थाओं द्वारा वर्ष 1990-91 के दौरान कुल मिलाकर 12,369.1 करोड़ रुपये वितरित किए गये जो पिछले वर्ष के 10,031.9 करोड़ रुपये के वितरणों से 2,335.2 करोड़ रुपये अर्थात् 23.3 प्रतिशत अधिक थे (सारणी 9.4)।

9.7 अधिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान मंजूर की गई धननिष्ठ सहायता की कुल राशि अनुमानतः 19,414.5 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष में मंजूर की गई 15,197.7 करोड़ रुपये की तुलना में 27.9 प्रतिशत अधिक थी। इसी प्रकार इन संस्थाओं द्वारा इसी अवधि के दौरान किया गया 11,863.6 करोड़ रुपये का वितरण भी वर्ष 1989-90 में वितरित 9,274.8 करोड़ रुपये की तुलना में 27.9 प्रतिशत अधिक रहा।

कमसी निवेश

9.8 'निजी कंपनी करोड़ार क्षेत्र' के निवेश के वार्षिक पूर्वानुमान के सन्दर्भ में रिज़र्व बैंक के तीसरे अध्ययन, जो सन सभी परियोजना पर होने वाले पूंजीगत व्यय की संभावित चरणबद्धता पर आधारित है, जिनके लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने सहायता मंजूर की हुई हो, के अंतर्गत अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1990 के दौरान कुल मिलाकर 15,813 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय किये जा सकते थे

जो 1989 के दौरान के अनुमानित पूंजीगत व्यय से 44.0 प्रतिशत अधिक होते। उन राशियों को मिलाकर, जिनका वितरण संस्थाओं की वित्त पुनर्गठन योजना और तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत किये जाने की योजना थी, वर्ष 1990 के दौरान कुल अनुमानित पूंजीगत व्यय 16,372 करोड़ रुपये बैठता था जो 1989 में हुई इसी प्रकार के व्यय से 16.9 प्रतिशत अधिक था। यदि किसी उपयुक्त अपस्फावक द्वारा अपस्फीत किया जाए तो 1980-81 के मूल्यों पर कुल निवेश (वास्तविक वर्ष में) 1989 में 34.9 प्रतिशत और 1990 में 33.4 प्रतिशत उच्चतर उछाल दर्शाता है। जहां तक उद्योग का संबंध है, धातु और धातु के उत्पाद 1989 के दौरान के अपने 26.9 प्रतिशत शेयर (109 प्रोजेक्ट) के मुकाबले 28.2 प्रतिशत के उच्चतम शेयर (107 प्रोजेक्ट) रहे। रसायन और पेट्रोसायन 1989 के अपने 18.7 प्रतिशत शेयर (115 प्रोजेक्ट) की तुलना में 1990 में 22.1 प्रतिशत (170 प्रोजेक्ट) शेयर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इसके बाद कपड़ा उद्योग (पटसन को छोड़कर) का स्थान रहा जिसका शेयर 1989 के 15.0 प्रतिशत की तुलना में 1990 में 8.0 प्रतिशत रहा।

\* सभी वित्तीय संस्थाओं (स. वि. सं.) में शामिल हैं: अधिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय पर्यटन वित्त निगम, भारतीय मोबहून ऋण एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम एवं संबद्ध संस्थाएं) और 18 राज्य वित्त निगम व 26 राज्य औद्योगिक विकास निगम।

सारणी - 9.4 : सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता (घरेलू - मात्र)

(करोड़ रुपये)

संस्थाएं	1989-90 मंजूरियां	वितरण	1990-91* मंजूरियां	वितरण
1	3	3	4	5
अ. अधिल भारतीय विकास बैंक (1 से 6)	@ 12,936.5 @@ (11,170.2)	7,418.3 (6,437.7)	16,101.6 (14,035.3)	9,603.2 (8,329.8)
1. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	@ 5,330.9 @@ (4,664.2)	3,130.0 (2,823.8)	6,450 (5,569.9)	4,016.0 (3,483.8)
2. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	2,294.9	1,121.8	2,965.1	1,574.9
3. भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	2,850.6	1,357.1	3,861.1	1,967.6
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	2,086.1 @@ (986.5)	1,570.9 (896.5)	2,408.8 (1,222.6)	1,838.5 (1,097.3)
5. भारतीय पर्यटन वित्त निगम	52.8	12.8	85.0	39.2
6. भारतीय मोबहून ऋण और निवेश निगम	321.2	225.7	331.6	167.0
आ. निवेश संस्थाएं (7 + 8 + 9)	2,096.6	1,715.4	3,078.2	2,106.5
7. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	1,307.2	1,080.6	2,077.2	1,532.7
8. जीवन बीमा निगम	578.2	455.2	688.1	427.4
9. साधारण बीमा निगम	211.2	179.6	312.9	146.4
इ. अन्य संस्थाएं	146.6	141.1	234.8	153.9
10. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	146.6	141.1	234.7	153.9



1	2	3	4	5
ई. ग्रामिण भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता	@ 15,179.7	9,274.8	19,414.5	11,863.6
उ. राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं (11+12)	2,333.9	1,739.7	2,568.9	1,778.9
11. राज्य वित्तीय निगम	1,543.6	1,190.2	1,870.1	1,260.1
12. राज्य औद्योगिक विकास निगम	690.3	549.5	698.8	518.8
ऊ. सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल सहायता (अ+आ+इ+उ) (@@)	15,647.3	10,033.9	19,917.1	12,369.1

## \* अग्रान्तिम

(@) प्रांकड़े भन्त - संस्थागत (ग्रामिण भारतीय) धन प्रवाह का निबल है।

(@@) प्रांकड़े भन्त - संस्थागत (ग्रामिण भारतीय एवं राज्य स्तरीय) धन प्रवाह का निबल है।

टिप्पणी :—

1. प्रांकड़े का भन्त: संस्थागत उपलब्धता के लिए समायोजन किया गया है। इसमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों को किये गये पुंजितपोषणों, मूल पूंजी सहायता और भारतीय औद्योगिक विकास निगम एवं जीवन बीमा निगम द्वारा अन्य वित्तीय संस्थाओं को दी गई संसाधन सहायता से संबंधित समायोजन शामिल हैं। राज्य वित्त निगमों तथा राज्य औद्योगिक विकास निगमों के 1990-91 के प्रांकड़े अनुमानित हैं।
2. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने अप्रैल 2, 1990 से काम करना प्रारम्भ किया तथा इस बैंक के 1989-90 के प्रांकड़े लघु उद्योग विकास निधि और राष्ट्रीय इन्विस्टी निधि योजना, जिन्हें इस बैंक ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से अपने हाथ में लिया था, से संबंधित हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 1990-91 की सज़ूरियों और संवितरणों में 415 करोड़ रुपये के अल्पकालीन जिन शामिल नहीं हैं।
3. भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने फरवरी, 1 1989 से काम करना प्रारम्भ किया।

स्रोत : संबंधित वित्तीय संस्थाएं उपलब्धता का निबल जोड़ हैं।

### भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ("सिडबी")

9.9 पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व में उसकी सहायता संस्था भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ("सिडबी") की स्थापना की गई है जिसने अपना कार्य अप्रैल 2 1990 से करना शुरू कर दिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उद्योग क्षेत्र को वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके, "सिडबी" ने तात्कालिक जोर इन मुद्दों पर दिया। (i) मौजूदा इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए प्रारम्भिक कबज उठाना, (ii) लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों के देश-विदेश के बाजारों में विपणन के लिए अधिक रास्ते तैयार करना, और (iii) रोजगार उन्मुखी उद्योगों का फैलाव, विशेषतः शहरी क्षेत्रों में ताकि रोजगार के और अधिक अवसर तैयार हो सकें तथा आबादी को शहरी और महानगरीय क्षेत्रों की तरफ आने से रोका जा सके। वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान, "सिडबी" द्वारा संजूर एवं वितरित की गयी राशि का क्रमशः 2,823.8 करोड़ रुपये एवं 2,253.5 करोड़ रुपये थी। "सिडबी" द्वारा प्रदत्त सहायता का बड़ा हिस्सा पुनर्वित्त के रूप में था जो वर्ष के दौरान कुल संजूरियों का 72.7 प्रतिशत और कुल वितरणों का 69.3 प्रतिशत था।

9.10 लघु उद्योग इकाइयों द्वारा वित्तस्थित भुगतानों के कारण अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से "सिडबी" ने अलग से प्राप्त कम्पनियों के प्रवर्तन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयनित प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर चलने का निर्णय लिया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा स्थापित "एक्सप्रेस आई फंडर्स" एवं कनमिशन संविसेस प्राइवेट लिमिटेड में "सिडबी" की ईक्यूटी आगोदारी है। हाल ही में जो "सिडबी"

ने इसी प्रकार की ईक्यूटी आगोदारी केन्द्र बैंक द्वारा स्थापित केन बैंक फंडर्स में ली है। इसके अतिरिक्त, "सिडबी" ने लघु उद्योगों के उत्पादों की बिक्री के लिए विपणन के रास्ते तैयार करने के लिए वित्तपोषण की योजना भी प्रारम्भ की है ताकि उनके उत्पादों की कुल बिक्री राशि की बमूही में विलम्ब को कम से कम किया जा सके।

### पूँजी बाजार

9.11 छाड़ी संकट से उभरी समष्टिगत आर्थिक असमानताओं की श्रृंखला तथा विदेशी मुद्रा के संचित रिजर्व बैंक को खाली होते रहने और नाभ अर्थव्यवस्था में आर्थी अनिश्चितता की तात्कालिक प्रक्रिया यह हुई कि पूँजी बाजार के प्रमुख हिस्से की 1990-91 के दौरान एक भारी मंदी का मुंह देखना पड़ा, विशेषतः परिवर्तनीय डिबेंचर निगमों में विच्छेद वर्ष की तुलना में एक बहुत बड़ी मात्रा में आयी गिरावट के कारण तथापि, नये निर्गमों के प्रति जनता का सतत कुन मिलाकर उल्हासजनक रहा।

9.12 सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार की कंपनियों को वर्ष 1990-91 के दौरान प्रांमियम शेयरों के लिए प्रदत्त (किन्तु बोनस शेयरों के लिए नहीं) अनुमोदनों/प्रतिस्वीकृतियों ने 12,191 करोड़ रुपये के चरम स्तर की छू लिया था जो पिछले वर्ष के 11,191 करोड़ रुपये के अनुमोदनों से 4.2 प्रतिशत अधिक थे (सारणी 9.5)। जहाँ गैर सरकारी कंपनियों को वर्ष 1990-91 के दौरान दिये गये 6,124 करोड़ रुपये के अनुमोदन पिछले वर्ष के (7,567 करोड़ रुपये) की तुलना में 19.1 प्रतिशत कम थे, वहीं सरकारी कंपनियों को वर्ष 1990-91 के दौरान दिये गये 6,067 करोड़ रुपये के अनुमोदन 1989-90 के (4,133 करोड़ रुपये) के मुकाबले 46.7 प्रतिशत अधिक थे।

सारणी 9.5 : सरकारी और गैर सरकारी कम्पनियों को पूंजी जुटाने के लिए नियंत्रक, पूंजी निर्गम द्वारा पदम सहस्र राशियाँ/अभिस्वीकृत राशियाँ

				(करोड़ रुपये)	
		1989-90		1990-91	
		(अप्रैल - मार्च)		(अप्रैल - मार्च)	
क्रम	निर्गम का प्रकार	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	शेयर (i + ii)	437	1,749	503	2,613
		(4)	(61)	(4)	(60)
	(i) प्रारंभिक निर्गम	189	906	233	1,282
		(-)	(-)	(2)	(30)
	(ii) बाव के निर्गम*	248	843	270	1,331
		(4)	(61)	(2)	(30)
2.	डिबेंचर और बाव (i + ii)	205	9,953	250	9,578
		(16)	(4,074)	(17)	(6,007)
	(i) परिवर्तनीय	80	2,798	137	2,588
		(-)	(-)	(-)	(-)
	(ii) अपरिवर्तनीय	125	7,154	113	6,990
		(16)	(4,074)	(17)	(6,007)
3.	उप जोड़ (1 + 2)	642	11,702	753	12,191
		(20)	(4,135)	(21)	(6,067)
4.	बोनस शेयर	319	374	352	441
		(1)	(22)	(10)	(140)
5.	कुल जोड़ (3 + 4)	961	12,076	1,105	12,632
		(21)	(4,157)	(31)	(6,207)

\* इसमें 1989-90 में 77 निर्गमों के प्रीमियम को 213 करोड़ रुपये की राशि और 62 निर्गमों की 274 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े सरकारी कम्पनियों को प्रवृत्त अनुमोदनों से संबंधित हैं, जो कि संबंधित जोड़ में शामिल हैं।

स्त्रोत : नियंत्रक, पूंजी निर्गम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

#### नये निर्गमों का बाजार

9.13 जैसा कि पहले ही इशारा किया जा चुका है, नये निर्गमों के बाजार को वर्ष 1990-91 के दौरान भारी मंदी में दो-बार होता पड़ा। गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के वर्ष 1990-91 के दौरान के (365 निर्गमों के माध्यम से जारी) 4,20.18 करोड़ रुपये के पूंजी निर्गमों (जिनमें प्रीमियम निर्गम शामिल हैं किन्तु बोनस निर्गम नहीं) में 1989-90 में 408 निर्गमों के माध्यम से जारी 6,473.1 करोड़ रुपये के पूंजी निर्गमों से 35.1 प्रतिशत की गिरावट आयी, (सारणी 9.6)। जहाँ तक प्रतिभूति का संबंध है, डिबेंचर निर्गम 2,94.10 करोड़ रुपये की पर्याप्त नीची ताबाद में जारी हुए जिनमें 1989-90 की तुलना में भी 2305.4 करोड़ रुपये अर्थात् 43.9 प्रतिशत की कमी आयी। यह कमी परिवर्तनीय डिबेंचरों के कारण आयी जिनमें 51.9 प्रतिशत की गिरावट आयी, गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमों में 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1,247.5 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर 1989-90 की तुलना में 2.4 प्रतिशत की सीमांत वृद्धि लिए हुए थे।

#### सार्वजनिक क्षेत्र के बांड

9.14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 1990-91 के दौरान जारी 5,463 करोड़ रुपये के बांड (अनन्तिम आंकड़ों) के अनुसार पिछले वर्ष के दौरान जारी बाण्डों की राशि (3,729 करोड़ रुपये) से 46.5 प्रतिशत अधिक रहे। इनमें से, दोनों वर्षों के दौरान जनता को प्रत्येक वर्ष में केवल 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये तथा शेष राशि प्रॉवेट प्रायोजनों के लिए रख ली गयी।

#### नये निर्गमों का कारोबार विश्लेषण

9.15 बंबई स्टॉक एक्सचेंज से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1990-91 के दौरान नये निर्गमों (सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों सहित) के प्रति जन माधारण का रख कूल मिलाकर पर्याप्त रूप से उत्साहजनक रहा। निर्गमों की संख्या जिनका अंश 10 गुणा से अधिक था, वर्तमान निर्गम के 15.1 प्रतिशत के बराबर थी, हालांकि यह 1989-90 के 30 प्रतिशत की तुलना में कम थी। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों इंगित है कि जनसाधारण के अंशदान

के लिए प्रस्तावित कुल राशि 1989-90 के 26 प्रतिशत की तुलना में वर्तमान निर्गम का 45 प्रतिशत थी।

#### 1990-91 के दौरान नीति निर्धारण

9.16 सुस्पष्टता और खूपापन लाने की दृष्टि से भारत सरकार ने जुलाई, 1990 में शेयरों के मूल्यांकन और लाभांश तथा किये जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये। निवेश करने वाली जनता के लाभ के साथ-साथ ऐसा उन कंपनियों को सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है जो पूंजी निर्गम नियंत्रक से सहमतियाँ प्राप्त कर रहे हैं।

मार्ग 9.6. गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पूंजी निर्गम (करोड़ रुपये)

क्रम. सं.	निर्गम का प्रकार	1989-90(a)		1990-91(b)	
		(अप्रैल-मार्च)		(अप्रैल-मार्च)	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6
1	डिविडेंड शेयर* (क + ख)	268	1,218.8	248	1,247.5
		(57)	(272.0)	(41)	(126.4)
	(क) विवरण-पत्र	143	734.1	105	963.5
		(17)	(30.0)	(15)	(73.3)
	(ख) अधिकार-पत्र	125	484.7	143	284.0
		(40)	(242.0)	(26)	(53.1)
2	अधिमानी शेयर (क + ख)	4	7.9	4	13.3
	(क) विवरण-पत्र	3	5.4	2	13.0
	(ख) अधिकार-पत्र	1	2.5	2	0.3
3	डिविडेंड (क + ख)	136	5,246.4	113	2,941.0
	(क) विवरण-पत्र	44	2,400.7	44	997.8
	(ख) अधिकार-पत्र	92	2,845.7	69	1,943.2
	इनमें से				
1	परिवर्तनीय (क + ख)	109	4,762.2	92	2,288.7
	(क) विवरण-पत्र	37	2,240.4	36	831.6
	(ख) अधिकार-पत्र	72	2,521.8	56	1,457.1
2	अपरिवर्तनीय क + ख	27	484.2	21	652.3
	(क) विवरण-पत्र	7	160.3	8	166.2
	(ख) अधिकार-पत्र	20	323.9	13	486.1
4	जोड़ (1 + 2 + 3)	408	6,473.1	365	4,201.8
	(क) विवरण-पत्र	190	3,140.2	151	1,974.3
	(ख) अधिकार-पत्र	218	3,332.9	214	1,227.5

(a) अनंतिम

बोनस निर्गम शामिल नहीं

विषयवस्तु -

- (1) कोटको में किये गये आकड़े पूंजी निर्गमों पर लाभांश संबंधी आकड़े हैं, जो कि संबंधित जोड़ में शामिल हैं।
- (2) इन आकड़ों में वित्तीय संस्थाओं आदि के पास निजी तौर पर वित्तियोजित निर्गम शामिल नहीं हैं।
- (3) आकड़ों में अंशदान में अधिक राशि उन मामलों में दी गयी है जिनमें विशिष्ट सूचना उपलब्ध थी। तथापि, जहां राशि अंशदान से कम रही है, उसे वित्तीय में नहीं लिया गया है क्योंकि सूचना उपलब्ध नहीं थी।

क्षेत्र: कंपनियों द्वारा जारी विवरण पत्र परिपक्व/विज्ञान/प्रस्ताव-पत्र कंपनियों द्वारा रिजर्व बैंक की प्रस्तावियों के प्राप्त किये गये उत्तर/वित्त मंत्रालय के स्टॉक एक्सचेंज प्रभाव से प्राप्त एकत्र की गयी जानकारी, विशिष्ट स्टॉक एक्सचेंज प्रेम रिपोर्ट क्षेत्र घाउट आदि।

9.17 बैंककारा विनियमन अधिनियम, 1949 का धारा 6(i)(ख) के अंतर्गत भारत सरकार ने 2 जुलाई, 1990 को "आहुत" को एक ठोस पाठ्य कार्यकलाप के रूप में अधिसूचित किया जिसे बैंक अपने कारोबार में शामिल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने ऐसे मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किये हैं जो भारत में आहुत के कारोबार के व्यवहार को निर्वाचित करेंगे। आहुत में सम्बद्ध इकाइयों के कार्यकलाप, बैंककारा विनियम अधिनियम 1949 का धारा 19(2) द्वारा नियंत्रित होंगे। इसके अनुसरण में, भारतीय स्टेट बैंक और केंद्र बैंक ने आहुत इकाईयें, खोल दी हैं और इसके लिए "सिडको" के साथ ऊपर दिये अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ इक्विटी हिस्सेदारी रखी है।

9.18 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा अन्य मीयादी ऋण वित्तीय संस्थाओं ने 1 अगस्त, 1990 से बड़े, मध्यम और लघु स्तर के क्षेत्र को औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ऋणों हेतु एक द्विस्तरीय व्याज दर प्रणाली आरंभ की है। पहला स्तर शुद्ध के दो वर्षों अथवा औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण का अवधि से संबंधित है तथा दूसरा स्तर उसके बाद की उस अवधि से संबंधित है जब औद्योगिक परियोजनाओं से उत्पादन शुरू होने की आशा होती है। पहले स्तर के लिए 14 प्रतिशत वार्षिक का सामान्य व्याज दर पर लिया जाने वाला अग्रशिवित रहेगा जबकि दूसरे स्तर के लिए व्याज की सामान्य दर 15 प्रतिशत वार्षिक होगी। और अधिक लचीलापन लाने का दृष्टि से जुलाई 1991 में यह निर्णय लिया गया कि मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं को 15 प्रतिशत की न्यूनतम दर से अधिक व्याज दरें वसूल करने की छूट दी जाए।

9.19 पूंजी बाजार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि परिवर्तनीय और गैर-परिवर्तनीय डिविडेंडों पर व्याज दरों को स्वतंत्र कर दिया जाए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (एस. ई. बी. आई.) को प्रतिभूति संविदा एवं विनियमन अधिनियम, 1957 और कंपनी अधिनियम के संबंधित उपबन्धों के निष्पादन के लिए सांविधिक अधिकार दिये जाने हैं और इसके लिए पूंजी निर्गम नियंत्रक से अधिकार अंतरित किये जाएंगे। इसके फलस्वरूप भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड को देश में स्थित स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज के प्रभावी ढंग से विनियमन संवर्धन और नियंत्रण के लिए आवश्यक प्राधिकार प्राप्त हो जाएगा। म्युचुअल फंडों की प्रगति को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए इन्हें निजी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के 1990-91 के दौरान कार्यकलापों से संबंधित प्रगति

9.20 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने 1990-91 के दौरान व्यापारी बैंकिंग, म्युचुअल फंड और निवेशकर्ता की सुरक्षा से संबंधित कई उपाय शुरू किये हैं। ये निम्नलिखित हैं:—

## व्यापारी बैंकिंग

9.21 व्यापारी बैंकिंग के पर्यवेक्षण को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने नवम्बर, 1990 में व्यापारी बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किये थे जिनमें कई क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया था जैसे व्यापारी बैंकों द्वारा परिचालन किये जाने हेतु प्राधिकृत शब्द मूल्यावत्ता एवं वास्तविक कार्यकलाप, उनकी आचार संहिता तथा शीर्ष प्रबंधकों के लिए उत्तरदायित्वों का निर्धारण भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने फरवरी 1991 में एक निर्गम से संबंधित शीर्ष प्रबंधकों, सलाहकारों और परामर्शदाताओं की संख्या से संबंधित मानदंडों में संशोधन किया। तदनुसार कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये से कम के प्रत्येक निगम की कुल राशि के लिए शीर्ष प्रबंधक दो से अधिक नहीं होंगे; कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपये तथा अधिक किन्तु 100 करोड़ रुपये से कम के प्रत्येक निगम की कुल राशि के लिए यह संख्या तीन तक जा सकती है, कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये तथा अधिक के प्रत्येक निगम की कुल राशि के लिए यह संख्या अधिकतम चार हो सकती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने जन सामान्य के लिए प्रचारित सूचना पर आधारित विवरण पत्रों को प्रमोद करना प्रारंभ कर दिया है। मई 1, 1991 में उक्त बोर्ड ने ऐसे व्यापारी बैंकों के लिए दंड व्यवस्था प्रारंभ कर दी है जो उनके लिए निर्धारित आचार संहिता के प्रति चूक करते हैं तथा जो निर्गम प्रबंध, हाथीदारी, संविभाग प्रबंध सेवाओं और परामर्शी सेवाओं जैसे कार्यकलापों के बारे में उनको जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन में चूक करते हैं।

## म्यूचुअल फंड

9.22 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने म्यूचुअल फंड के लिए विज्ञापनों तथा प्रकटीकरण एवं सूचना प्रकाशन संबंधी अपेक्षाओं के बारे में जनवरी, 1991 में दिशा-निर्देश जारी किये थे। लाभों का वादा करने वाले तथा पिछले कारोबार का खाका दर्शाने वाले विवरणों के साथ-साथ सम्भाव्य निवेशकर्ताओं को म्यूचुअल फंड में निवेश करने से जुड़े वास्तविक जोखिम के बारे में भी जानकारी दी जानी होगी। इसके अतिरिक्त उक्त बोर्ड ने सभी म्यूचुअल फंड इकाईयों से कहा है कि वे प्रकटीकरण के मापदंड निर्धारित करें तथा निवेशकर्ताओं को इक्विटी, डिबेंचर और सरकारी प्रतिभूतियों आदि में उनके द्वारा निवेश किये जाने से अन्य उनकी हैसियत के बारे में अवगत कराएं। साथ ही म्यूचुअल फंड इकाईयों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे शेयरधारकों को निजी विनियोग से संबंधित व्यौरा प्रस्तुत करें। म्यूचुअल फंड इकाईयों से यह भी अपेक्षित है कि वे जनसाधारण को उक्त बोर्ड द्वारा निर्धारण फॉर्मेट में लेखा परीक्षा रहित छमाही परिणाम तथा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा से अवगत करावें।

## निवेशकर्ताओं का संरक्षण

9.23 भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण की एक प्रणाली विकसित की है और कंपनियों, दलालों तथा अन्य बिचौलियों के विरुद्ध निवेशकर्ताओं को बराबर उठाता रहा है। अगस्त, 1990 से लेकर उक्त बोर्ड शिकायतों के स्वरूप और प्रकारों के बारे में पाक्षिक रूप से प्रेस में ब्यान देता रहा है तथा बड़ी चूककर्ता कंपनियों की सूची भी प्रकाशित करता रहा है।

## भारत स्थित ऋण निर्धारण एजेंसियां

9.24 वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड ने 46 कंपनियों के संबंध में 1,689.9 करोड़ रुपये के ऋण कवर करते हुए 77 ऋण लिखतों (जैसे डिबेंचर, सावधि जमा एवं कमशियल पेपर प्रोग्राम आदि) का निर्धारण किया जबकि पिछले वर्ष इसकी तुलना में 49 कंपनियों के संबंध में 2,098.4 करोड़ रुपये के ऋण कवर करते हुए 73 ऋण लिखतों का निर्धारण किया गया था। भारतीय ऋण निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड की जनवरी 1988 में हुई स्थापना से लेकर मार्च 1991 के अंत तक इसके द्वारा 124 कंपनियों द्वारा जारी 176 ऋण लिखतों पर 4,357 करोड़ रुपये के ऋण कवर किये गये जिनमें से 423 करोड़ रुपये की कुल राशि की 44 ऋण लिखतें कमशियल पेपर से संबंधित थीं।

9.25 भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 16 जनवरी, 1991 को एक ऋण निर्धारण एजेंसी, इन्वेस्टमेंट इन्फार्मेशन एण्ड क्रेडिट मेट्रि-एजेंसी ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित का है जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और जिसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है। प्रारंभिक वत्त शेयर पूंजी 3.50 करोड़ रुपये होगी जिसका अंशदान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय मुनिट्र ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक और 17 अन्य बैंकों द्वारा किया जाएगा। आइआईसीआईएन ने मार्च 15, 1991 से गैर-काज प्रारंभ कर दिया है।

## इक्विटी मूल्य

9.26 वर्ष 1989-90 के दौरान शेयर-मूल्यों में जो वर्षोत्पादन देखने में आया था, वह 1990-91 में भी लगभग घटतूबर, 1990 के मध्य तक बरकरार रहा। इस उछाल की प्रतिक्रियास्वरूप, साधारण शेयर मूल्यों के भारतीय रिजर्व बैंक (माप्ताहिक) सूचकांक (आधार: 1980-81-100) अक्टूबर 13, 1990 को समाप्त में अग्रतपूर्व रूप से 654.2 की उंचाई पर पहुंच गया। हालांकि इसके बाद इसमें काफी गिरावट आ गयी थी। 1990-91 का 500.3 का औसत सूचकांक पिछले वर्ष की तुलना में 39.2 प्रतिशत की बढ़ि लिये हुए था (सारणी 9.7)।

9.27 विन्डुवार आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का सूचकांक मार्च 1990 के अंत के 400 से बढ़कर अक्टूबर 13, 1990 को समाप्त मप्ताह में 654.2 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और इस प्रकार इसमें 63.6 प्रतिशत की निचल बढ़ि हुई। इसके बाद सूचकांक मार्च 1991 के अंत तक 527.9 तक गिर गया और इस तरह इसमें 19.3 प्रतिशत की कमी आयी तथा वर्ष में 32 प्रतिशत की निचल बढ़ि हुई।

9.28 उद्योग-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि सभी उद्योग समूहों ने निचल बढ़ियां मार्च 1990 के अंत और अगस्त 1990 की उच्च-निम स्थिति के मध्य में प्राप्त की; केवल नीचतम को छोड़कर जिसमें 17.8 प्रतिशत की निचल गिरावट आयी। जिन उद्योग समूहों में

अप्रैल-अक्तूबर के दौरान 1990 प्रतिशत की निवल वृद्धि दर्ज की गयी, वे थे: विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति (256.6 प्रतिशत) सीमेंट (239.3 प्रतिशत) एवं सूती कपड़ा (185 प्रतिशत)। इसके बाद, केवल सीमेंट उद्योग को छोड़कर (जिसने 4.3 प्रतिशत की निवल वृद्धि दर्ज की),

अन्य सभी उद्योग समूहों के शेयर मूल्यों में गिरावट आयी। जिन उद्योग-समूहों ने भारी गिरावट दर्ज की, वे थे: मानव-निर्मित फाबर (41.9 प्रतिशत), सूती कपड़ा (35.0 प्रतिशत), विद्युत उत्पादन और आपूर्ति (34.9 प्रतिशत) तथा अस्पुमिनियम (30.0 प्रतिशत)।

सांख्यी 97 : भारतीय रिज़र्व बैंक साधारण शेयर मुख्य सूचकांक (साप्ताहिक)

(आधार 1980-81 = 100)

वर्ष/माह	असत	उच्च	निम्न	माह/वर्ष के अंतिम सप्ताह के अंत में		
1	2	3	4	5		
1989-90	359.4	411.4	317.7	400.0		
(अप्रैल-मार्च)	(45.2)@					
1990-91	500.3	654.2	395.6	527.9		
(अप्रैल-मार्च)	(39.2)@					
अप्रैल 90	399.9	405.7	395.6	401.6		
मई	409.4	413.5	402.7	413.5		
जून	414.9	420.0	408.9	419.3		
जुलाई	450.9	481.4	430.4	481.4		
अगस्त	506.4	527.5	488.6	527.5		
सितम्बर	599.1	643.0	555.9	643.0		
अक्तूबर	617.2	654.2	587.4	587.4		
नवंबर	588.1	608.7	567.3	567.3		
दिसंबर	518.3	522.1	490.7	490.7		
जनवरी	468.6	471.5	463.6	463.6		
फरवरी	483.3	510.8	462.7	510.8		
मार्च	531.3	536.2	527.9	527.9		
1991-92						
अप्रैल	554.9	568.0	536.9	568.0		
मई	563.8	570.2	558.9	570.2		
जून*	563.4	573.5	554.7	565.5		
जुलाई*	602.2	634.1	565.1	634.1		
स्थापन मंडे	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	पाँच वर्षों का औसत
अंतर						(1986-87 से 1990-91 तक)
(घ) अंतरका गुणांक (प्रतिशत में)**	3.65	4.82	16.36	6.10	14.80	9.15
(घा) विद्योक्त	3.83**	40.0	121.1	93.7	258.6	110.3
सीमा *						

@ पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर दर्शाया गया है।

\*अन्तिम सप्ताहिक सूचकांकों पर आधारित

9.29 संपूर्ण जिलेय वर्ष भर, सीमेंट उद्योग की वृद्धि अधिकतम (254.0 प्रतिशत) रही जिसके बाव विद्युत उत्पादन और आपूर्ति (132.1 प्रतिशत) और सूती कपड़ा (85.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। तथापि, नौवहन और मानवनिर्मित फाइबर ने क्रमशः 23.1 प्रतिशत और 20.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की।

9.30 वर्ष 1990-91 के दौरान इस्विटी मूल्यों में उतार-चढ़ाव पिछले वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक रहा। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्ष 1989-90 के 6.1 प्रतिशत की तुलना में समीक्षा वर्ष का परिवर्तनशीलता का अनुपात 14.8 प्रतिशत की ऊंचाई लिए हुए था। साधारण गेयर-मूल्यों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव (अथवा उच्च एवं निम्न के बीच घटा-बढ़ी की सीमा) भी 1939-90 के 93.7 प्वाइंट की तुलना में 1990-91 के दौरान 258.6 प्वाइंट की उच्च-तर सीमा पर था (सारणी 9.7)।

9.31 अक्तूबर 1990 के बाद के चरण में गेयर मूल्यों में प्रायः ठहराव के बाव 1991-92 (अर्थात् अप्रैल, जून) की पहली तिमाही के दौरान इसके मूल्यों के पूर्ववस्था में लौटने के कुछ साफ-साफ आसार अल्पनिहित आशा के साथ उस स्थिति में नजर आये थे जब इस्विटी मूल्यों के सूचकांक में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देखी गयी आशावा-विता जुलाई, 1991 के महीने के दौरान उभर कर आयी और समीक्षा-धीम अवधि के दौरान किये गये संरचनात्मक समायोजनों के फलस्वरूप जून 1991 की तुलना में सूचकांक में 12.1 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी।

#### 10. बाह्य क्षेत्र की गतिविधियाँ

##### भुगतान संतुलन

10.1 राजकोपीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की पहली तिमाही के दौरान विदेशी क्षेत्र पर संकट जैसा दबाव रहा और विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों के अत्यधिक ह्रास तथा भुगतान संतुलन की अत्यधिक शोचनीय स्थिति के रूप में यह परिलक्षित हुआ। यद्यपि बाह्य संकट के लक्षण सातवीं योजना अवधि में ही स्पष्ट हो गये थे तथापि उसके बाव 1990-91 से विश्वव्यापी गतिविधियों के कारण समस्या और बढ़ गयी। पूँजी की पर्याप्तता संबंधी मानदंडों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक भी कम जोखिम उठाने के प्रयास करने लगे। अल्पावधि ऋण, विशेषरूप से बैंकों की स्वीकृति सुविधा तक पहुँच, प्रतिबंधित होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमता निधिरण एजेंसियों ने भारत/भारतीय संस्थानों की ऋण श्रमता कम कर दी जिससे वाणिज्यिक बाजारों में से निधियाँ जुटाना कठिन हो गया। इन परिस्थितियों में, देश को भुगतान संतुलन में सहायता हेतु बहुपक्षीय एजेंसियों तथा ऋण-दाता देशों को निवेदन करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की प्रारक्षित निधि संबंधी अंश में से 487 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के आहरण के अलावा देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वित्तपोषण संबंधी सुविधाओं के अंतर्गत 1.27 मिलियन विशेष आहरण अधिकार भी खरीदे। आयातों को नियंत्रित करने तथा निर्यात से प्राप्त राशि के प्रत्यावर्तन में तेजी लाने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से उपाय किये।

10.2 अंतर्राष्ट्रीय देयताओं को सुनिश्चित करने तथा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों का उचित स्तर सुरक्षित रखने की दृष्टि से हाल ही में कुछ प्रसाधारण उपाय किये गये जिनमें सोने से सम्बद्ध लेन-देन शामिल हैं। बाव के पैराग्राफों में इनका व्योरा दिया गया है।

10.3 विदेशी मुद्रा विनिमय दर में समायोजनों के साथ भारत की व्यापार नीति के संबंध में किया गया संरचनात्मक सुधार एक महत्व-

पूर्ण घटना है। 1 जुलाई और 3 जुलाई 1991 को के बाह्य मूल्य में दो बार तीव्र निम्नगामी समायोजन किया गया ताकि हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बनाये रखने की आवश्यकता के अनुरूप मूल्य को उचित स्तर पर कर दिया जाए। दूसरे, प्रशासनिक नियंत्रणों और लाइसेंसों से प्रणाली को उबार बनाने के लिए, निर्यातों को बढ़ावा देने तथा सामान्यतः अर्थव्यवस्था के प्रतिस्पर्धी एवं उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने 4 जुलाई 1991 को व्यापार नीति में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थ, उर्वरक तथा खाद्य तेल जैसे अनिवार्य आयातों के संरक्षण के सा-साथ नयी व्यापार नीति के अंतर्गत अन्य आयातों को निर्यातों के साथ संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, पुनः पूर्ति लाइसेंस प्रणाली को व्यापक एवं उदार बनाया गया है जिसके अंतर्गत निर्यातकों की अथ विद्यमान विभिन्न वर्गों के स्थान पर जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत की एकसमान पुनः पूर्ति दर का लाभ प्राप्त होगा। पुनः पूर्ति लाइसेंस का नाम एक्विम स्क्रिप्ट होगा तथा उसका निर्बाध लेनदेन किया जा सकेगा। व्यापार नीति को काफी उदार बनाये जाने तथा विनिमय दर को समायोजित करके घटाने की वजह से 3 जुलाई 1991 के नकदी क्षतिपूर्क योजना स्थगित कर दी गयी है। इस नई व्यापार नीति को 13 अगस्त 1991 को और सुवृद्ध बनाया गया। इसके साथ ही आयात-निर्यात बैंक की गेयर वरें बढ़ा दी गयी और आयात-निर्यात की कतिपय सदों को मारणी से हटा दिया गया।

10.4 वर्ष 1991 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं जिनके परिणामस्वरूप देश को भुगतान करना अनिवार्य हो गया। सर्वप्रथम, उद्योग प्रधान देशों में मंदी की स्थिति तथा सोवियत रूस सहित पूर्वी यूरोप में आर्थिक विघटन के कारण विश्व व्यापार में आयी विश्वव्यापी संकीर्णता से 1990-91 के प्रारंभिक महीनों से ही भारत के निर्यातों पर दुष्प्रभाव पड़ने लगा था तथा बढ़ते हुए आयातों की वजह से वाणिज्य व्यापार घाटा और बढ़ गया। दूसरी ओर, इससे भी अधिक, अगस्त 1990 में शुरू हुए खाड़ी संकट से विदेशी भुगतान स्थिति में काफी अधिक विघटन हो गया : मूल्य में तीव्र वृद्धि तथा देश में कच्चे तेल के उत्पादन में अपेक्षा-कृत कमी आ जाने के कारण पेट्रोलियम आयात की मात्रा में वृद्धि से पेट्रोलियम तथा चिकनाई के पदार्थों के आयात बिल में काफी वृद्धि हुई, पश्चिम एशिया को किया जाने वाला निर्यात भी अंशतः बंद हो गया तथा मध्य-पूर्व के प्रभावित देशों से भारतीयों के प्रत्यावर्तन पर भी विदेशी मुद्रा व्यय हुआ। तीसरे, आलोच्य अवधि के दौरान देश के कतिपय भागों में कतिपय सामाजिक और राजनैतिक अस्थिरता के कारण निजी प्रेषणों, यात्रा और पर्यटन की प्रायः आदि के रूप में अद्रव्य प्राप्तियों में भी तेज गिरावट आयी। चौथे, उपर्युक्त तथ्यों के कारण अस्थायी तौर पर उत्पन्न अविश्वास की भावना से अतिवासी जमागराशियों, जिनसे हाल के वर्षों में लगभग एक चौथाई चालू लेखा घाटे का वित्तपोषण किया जाता था, के अंतर्गत श्रद्धा प्रोद्भूत राशि में 1990-91 के दौरान काफी अधिक गिरावट आयी जो 1991-92 की पहली तिमाही में और भी ज्यादा थी। पांचवें देश की ऋण-श्रमता के निर्धारण में ह्रास एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में ऋणनिधि की ग्राम कमी की वजह से दीर्घावधि और अल्पावधि वित्त के स्रोत के रूप में वाणिज्यिक उधार बंद हो गये। 1990-91 के दौरान महायुद्ध के अधिक उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार के बावजूद महावर्धन स्थिरीकरण कार्यक्रम के अभाव में आलोच्य वर्ष के अंत तक विदेशी भुगतान की स्थिति पर दबाव बहुत बढ़ गया।

10.5 उपर्युक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप, 1990-91 के दौरान अनुमानित चालू लेखा घाटा 1989-90 की तुलना में काफी अधिक होगा। 1989-90 में 10,391 करोड़ रुपये (6,241 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 4,863 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) का उक्त घाटा अनुमानित है। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों का आयात 1989-90 के 6,273 करोड़ रुपये (3,768 मिलियन अमरीकी डॉलर) के स्तर से बढ़कर 1990-91 में 10,706 करोड़ रुपये (5,948 मिलियन अमरीकी डॉलर)

हो गया जिसमें अधिक मूल्य तथा मात्रा में भी वृद्धि परिलक्षित होती है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों के आयात की राशि क्रमशः 20.8 मिलियन टन और 8.2 मिलियन टन थी जबकि 1989-90 में यह क्रमशः 19.6 मिलियन टन और 7.1 मिलियन टन थी। कच्चे तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों का औसत मूल्य 1990-91 में क्रमशः 21.13 डॉलर प्रति बैरल तथा 279.2 डॉलर प्रति मेट्रिक टन था जबकि 1989-90 में यह क्रमशः 17.37 डॉलर प्रति बैरल और 176.8 डॉलर प्रति मेट्रिक टन था। इस प्रकार 1990-91 में चालू लेखा घाटा लगभग 13,100 करोड़ रुपये (7,301 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 5,271 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) होने का अनुमान है। सकल देशी उत्पाद (वर्तमान बाजार मूल्यों पर) के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा घाटा 1989-90 के 2.3 प्रतिशत से बढ़कर 1990-91 में 2.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

10.6 सातवी योजना की संपूर्ण अवधि के भुगतान संतुलन की स्थिति बकाययुक्त रही, इसका मुख्य कारण भारी व्यापार घाटा तथा अदृश्य,

लेनदेनों के अधिशेष में गिरावट। साथ ही, विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष काफ़ी अधिक पुनःक्रय जिनकी राशि सातवीं योजना अवधि के 2,752 मिलियन विशेष आहरण अधिकार थी, के कारण भी भुगतान संतुलन पर बकाय रहा। 1990-91 के दौरान विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत ऐसे पुनःक्रय की राशि 469 मिलियन विशेष आहरण अधिकार थी। इस अवधि के दौरान चालू लेखा घाटा औसतन 7,771 करोड़ रुपये (4,461 मिलियन विशेष आहरण अधिकार और 5,538 मिलियन अमरीकी डॉलर) प्रति वर्ष था जबकि छठी योजना अवधि के दौरान वार्षिक औसत 2,277 करोड़ रुपये (2,100 मिलियन विशेष आहरण अधिकार और 2,328 मिलियन अमरीकी डॉलर) थी। सातवी योजना अवधि के दौरान सकल देशी उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू लेखा घाटा औसतन 2.2 प्रतिशत होगा जबकि इस योजना अवधि के लिए योजना आयोग का लक्ष्य 1.6 प्रतिशत था तथा छठी योजना अवधि के दौरान यह घाटा औसतन 1.3 प्रतिशत था (सारणी 10.1 और 10.2)। सारणी 10.2 में 1986-87 से 1989-90 तक की अवधि के दौरान भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति का सारांश दिया गया है।

सारणी 10.1 : वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पादन के अनुदान के रूप में चालू लेखा लेन देन (प्रतिशत में)

संदे	1980-85 की अवधि में वार्षिक औसत	1985-86	1987-87	1987-88	1988-89	1989-90	1985-90 अवधि (अंतिम प्रनुमान)	अवधि वार्षिक औसत)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. निर्यात	5.0	4.4	4.5	4.9	5.2	6.4	5.1	
2. आयात	8.4	8.1	7.7	7.7	8.7	9.3	8.3	
3. व्यापार घाटा	3.4	3.7	3.2	2.8	3.4	2.9	3.2	
4. अदृश्य लेनदेनों से प्राप्तियां (आधिकारिक अनुदान सहायता सहित)	3.6	3.0	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	
5. अदृश्य भुगतान	1.5	1.6	1.6	1.9	2.0	2.3	1.9	
6. अदृश्य लेनदेनों (शुद्ध) 4-5)	2.1	1.4	1.2	0.9	0.8	0.6	1.0	
7. चालू लेखा घाटा * (3-6)	1.3	2.3	2.0	1.9	2.6	2.3	2.2	

\* यहाँ पर अधि-आधिक अनुदानों को चालू लेखा प्राप्तियों के अंतर्गत दिया गया है; उन्हें सारणी 2.2 में दिये गये बिंदुओं समाप्तों से निबल प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

सारणी 10.2 : भारत का समग्र भुगतान संतुलन

संदे	1989-90 अनुमान	1988-89	1987-88	1986-87 (अं. सं.)
1	2	3	4	5
अ. चालू लेखा				
1. निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	28,234.7	20,646.7	16,396.4	13,315.0
2. आयात (लागत, बीमा व भाड़ा सहित)	41,173.6	34,202.3	25,692.5	22,668.9
3. व्यापार संतुलन	-12,938.9	-13,555.6	-9,296.1	-9,353.9
4. मुद्रांतर स्वर्ण संबंधी घट-बढ़	6.4	—	—	—
5. आधिकारिक अंतरण (शुद्ध)	841.9	724.2	532.4	528.8
6. अदृश्य लेनदेन (शुद्ध)	1,699.5	2,421.4	2,471.1	2,998.6
7. चालू लेखा घाटा	-10,391.1	-10,410.0	-6,292.6	-5,830.0

1	2	3	4	5
भा. पूंजीगत लेखा				
1. विदेशी सहायता (शुद्ध)	3,054.2	3,209.7	2,928.2	1,807.8
संवितरण	4,970.0	4,859.6	4,453.9	3,056.2
ऋण परिशोधन	--1,915.8	--1,649.9	--1,525.7*	--1,248.4
2. वाणिज्यिक उधार (शुद्ध)*	2,866.0	2,742.9	1,282.6	2,513.2
संवितरण	4,237.9	4,265.0	1,945.7	3,115.6
ऋण परिशोधन	--1,371.9	--1,522.1	--663.1	--602.4
3. अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां (शुद्ध)	2,174.7	2,465.4	1,840.1	1,650.0
4. अन्य पूंजी (शुद्ध)	2,246.5	1,886.6	1,442.2	--71.6
5. कुल पूंजीगत लेखा	10,341.4	10,304.6	7,493.1	5,899.4
६. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (शुद्ध)	--1,459.6	--1,547.3	--1,209.0	--672.3
६. विशेष आहरण अधिकार आबंधन	--	--	--	--
ज. कुल पूंजीगत लेखा, पूंजीगत लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष आहरण अधिकार आबंधन	8,881.8	8,757.3	6,284.1	5,227.1
क. कुल ऋण लेखा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष पूंजीगत लेखा, आहरण अधिकार आबंधन	--1,509.3	--1,652.7	--8.5	--602.9
घ. मूल-चक्र	277.8	203.4	--947.7	--129.3
ऐ. प्रारक्षित निधियां और मुद्रागत स्वर्ण (वृद्धि—/गिरावट +) शोपन मद	1,231.5	1,449.3	956.2	732.2
चालू लेखा घाटा				
(i) विशेष अधिकार मिलियन में	4,863	5,404	3,675	3,774
(ii) मिलियन अमरीकी डालर में	6,241	7,188	4,854	4,562

घा. सं. —आंशिक रूप से संशोधित

\*इसमें पुनर्वित्त ऋण और पूर्व चुकौती राशियां शामिल नहीं हैं।

10.7 वर्ष 1988-90 और 1990-91 के लिए भुगतान संतुलन के अंतिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, प्रमुख लेखा शीर्षों के संदर्भ में कुछ प्राथमिक संकेतक प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक 1988-89 से ही अंतिम आंकड़ों को प्रकाशित कर रहा है, ताकि महत्वपूर्ण बातों की व्यापक रूप से देखा जा सके। 1988-90 के लिए इस प्रकार के अंतिम आंकड़ों का सारणी 10.2 में प्रस्तुत किये गए हैं। रिजर्व बैंक और सूचना के अन्य स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1990-91 के लिए भुगतान संतुलन के आंकड़ों के लिए तैयार आंकड़ों तैयार किये गये हैं। तैयार आंकड़ों के परिणाम सारणी 10.3 में दिये गये हैं। ये बताते हैं कि 1990-91 के दौरान व्यापार घाटा 15,142 करोड़ रुपये (8,439 मिलियन डॉलर) रहा जो पिछले वर्ष से 2,203 करोड़ रुपये (674 मिलियन डॉलर) अधिक था। 1990-91 के दौरान अन्य निवल वस्तु प्राप्तियों के आंकड़ों पिछले वर्ष के 1,700 करोड़ रुपये (1,021 मिलियन डॉलर) से घटकर 1,200 करोड़ रुपये (669 मिलियन डॉलर) पर आ गए। परिणामस्वरूप चालू लेखा घाटे में 2,697 करोड़ रुपये (1,056 मिलियन डॉलर) की भारी वृद्धि हुई। वर्ष में पूंजी लेख में विदेशी सहायता के अंतर्गत भारी निवल आहरण और अन्य पूंजी के अंतर्गत प्राप्तियां, निवल वाणिज्यिक उधारों और अनिवासी जमा राशियों के अंतर्गत तीव्र गिरावट से समायोजित हो गई। किंतु अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1988-90 के दौरान 1,460 करोड़ रुपये (877 मिलियन डॉलर) की निवल चुकौती की तुलना में 2,178 करोड़ रुपये (1,214 मिलियन डॉलर) का निवल आहरण किया गया। प्रारक्षित निधियों से किया गया आहरण पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दुगुना था।

#### विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

10.8 राजकोषीय वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान देश की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों में तेज गिरावट आयी जिसका कारण बहुत से अल्पकालिक प्रतिकूल तथ्य थे जैसे पेट्रोलियम, तेल और विक्रान्त के पदार्थों के आयात बिल में बढ़ोतरी अथवा लेनदेन से प्राप्त शुद्ध आय में निरंतर कमी होना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से निधियों की प्राप्ति में कमी तथा अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्राप्तियों में कमी। अप्रैल 1990 के शुरू में भारत की विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां 6,251 करोड़ रुपये (3,045 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) जो दो महीने के आयातों के मूल्य से थोड़ा-सा कम थी इनमें राजकोषीय वर्ष 1989-90 के दौरान 789 करोड़ रुपये (670 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) की गिरावट परिलक्षित होती है। आलोच्य वर्ष के दौरान कुछ विशेष लेनदेन किये गये। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रारक्षित अंश के अंतर्गत रखी 487 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (1,170 करोड़ रुपये के समकक्ष) की राशि का 20 जुलाई, 14 अगस्त और 4 सितम्बर 1990 को क्रिस्तों में आहरण किया गया। सितम्बर 1990 के अंत तक प्रारक्षित निधियां गिर कर 5,656 करोड़ रुपये (2,523 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) रह गयीं। 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण धारिताओं का लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है जबकि पहले मूल्यांकन 84.39 प्रति 10 शुद्ध ग्राम के सांख्यिक मूल्य पर किया जाता था। अक्टूबर-दिसम्बर 1990 की तिमाही के दौरान प्रारक्षित निधियों में 2,658 करोड़ रुपये, (1,080



मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार) की तेज गिरावट आयी, इसमें स्वर्ण का पुनः मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। निधियों की राशि विमर्श 1990 के अंत तक घट कर तीन मप्ताह के आयात बिल के बराबर रह गयी। बलनिधि प्रबंध हेतु किये जाने वाले प्रयासों के अंतर्गत भारत ने अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अतिपूरक और आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अंतर्गत 716.90 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार तथा कोष की आपाती व्यवस्था के पहले ऋण अंश के अंतर्गत 551.93 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार के आह्वरणों के लिए बातचीत की। ये आह्वरण 23 जनवरी 1991 को किये गये। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रारंभित निधियों में 1,871 करोड़ रुपये (668 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार) की वृद्धि हुई और मार्च 1991 के अंत में उनकी राशि 4,869 करोड़ रुपये (2,111 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार) हो गयी जिससे आन्वय वर्ष के दौरान प्रारंभित निधियों में 1,382 करोड़ रुपये (934 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार) की गिरावट परिलक्षित होती है। इसमें स्वर्ण का पुनः मूल्यांकन शामिल नहीं किया है। पूर्वोक्त स्वर्ण के पुनः मूल्यांकन को मिलाकर, मार्च 1991 के अंत में विदेशी मुद्रा प्रारंभित निधियों की राशि 11,416 करोड़ थी तथा जून 1991 के अंत में 9,926 करोड़ रुपये हो गई (सारणी 10.3), विशेष आह्वरण अधिकार के संदर्भ में प्रारंभित निधियां क्रमशः 4,329 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार तथा 3,564 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार थीं। अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण एवं प्रारंभित अंश के आह्वरण के शुद्ध उपयोग को छोड़कर तथा स्वर्ण पुनःमूल्यांकन संबंधी समायोजन करने के बाद 1990-91 में प्रारंभित निधियों में वास्तविक ह्रास की राशि 2,221 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार थी जबकि 1989-90 के दौरान प्रारंभित निधियों में 11 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की वृद्धि हुई, वृद्धि की राशि मामूली हो रहा (सारणी 10.4)। इसके अलावा, मार्च 1991 के अंत तथा जून 1991 के अंत तक की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा प्रारंभित निधियों में 2,073 करोड़ (833 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार) का स्वर्ण पुनःमूल्यांकन के कारण, और आर्थिक ह्रास हुआ, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष से किये गये लेन-देन को छोड़कर, तिमाही के दौरान प्रारंभित निधियों में 1,857 करोड़ अथवा 754 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार का ह्रास हुआ। जुलाई 1991 में अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अतिपूरक और आकस्मिक सुविधा के अंतर्गत 166.18 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार (570.41 करोड़) का दूसरा आह्वरण किया गया।

सारणी 10.3: भारत का समग्र भुगतान संतुलन — 1990-91  
(स्वरित अनुमान के आंकड़े)

मद	(करोड़ रुपये)
1	2
अ. बालू लेखा	
1. निर्यात (जहाज तक निःशुल्क)	33,178
2. आयात (सागत बीमा व भाड़ा सहित)	48,320
3. व्यापार संतुलन	-15,142
4. मुद्रांतर स्वर्ण संबंधी घट-बढ़	854
5. आधिकारिक अंतरण (शुद्ध)	1,200
6. अन्य अवश्य लेन-देन (शुद्ध)	-13,088

1	2
अ. पूंजीगत लेखा	
1. विदेशी सहायता (शुद्ध)	3,241
संवितरण	5,528
ऋण परिणोदन]]	2,287
2. वाणिज्यिक उधार (शुद्ध)*]]	1,244
संवितरण	3,507
ऋण परिणोदन]]	2,263
3. अनिवासी भारतीयों की जमा राशियां (शुद्ध)	209
4. अन्य पूंजी (शुद्ध)	3,923
5. कुल पूंजीगत लेखा	8,617
इ. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (शुद्ध)	2,178
ई. विशेष आह्वरण अधिकार आबंटन	
उ. कुल पूंजीगत लेखा, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष आह्वरण अधिकार आबंटन	10,795
ऊ. कुल बालू लेखा, पूंजीगत लेखा, अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विशेष आह्वरण अधिकार आबंटन	-2,293
ए. भू-पूक	-
ए. प्रारंभित निधियां और मुद्रागत स्वर्ण (वृद्धि-/ गिरावट-)	2,293

10.9 1990-91 के दौरान अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 525 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार (1,291 करोड़) की चुकोतियां की गयीं जिसमें से 469 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार की चुकोतियां विस्तारित निधि सुविधा से अंतर्गत थीं तथा 56 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार (135 करोड़) की व्यास निधि ऋण के अंतर्गत/विस्तारित निधि सुविधा के अंतर्गत चुकोतियों की सबसे अधिक राशि 1988-89 में तथा मार्च 1991 के अंत में थी तथा इन चुकोतियों की वजह से उपर्युक्त सुविधा के अंतर्गत खरीदे गये 3,900 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार के संदर्भ में बकाया देयता 679 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार (1,789 करोड़ रुपये) रह गयी। वर्ष 1990-91 के दौरान 56 मिलियन विशेष आह्वरण अधिकार (148 करोड़ रुपये की चुकोती से व्यास निधि ऋण की पूरी चुकोती हो गयी। विदेशी मुद्रा आस्तियां

10.10 विदेशी मुद्रा प्रारंभित निधियों के तीन घटकों में से भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा आस्तियों में 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान 1,399 करोड़ रुपये की गिरावट आयी जबकि 1989-90 में इसमें 818 करोड़ रुपये की गिरावट आयी थी, मार्च 1991 के अंत से लेकर जून 1991 के अंत तक की अवधि के दौरान इसमें 2,006 करोड़ रुपये की और गिरावट आयी।

सारणी 10.4 : भारत की आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां

निम्नलिखित माह के अंत में	आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां (करोड़ रुपये में)				कुल आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियां (मिलियन विशेष आहरण अधिकार में)	आरक्षित विदेशी मुद्रा निधियों में घट-बढ़ (मिलियन विशेष आहरण अधिकार में)	कोष में आरक्षित निधि की स्थिति मिलियन विशेष आहरण अधिकार में	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ : लेनदेन मिलियन विशेष आहरण				विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां में घट-बढ़ (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कृण घटाकर) (मिलियन विशेष आहरण अधिकार में)
	विशेष * आहरण अधिकार	स्वर्ण <sup>(६)</sup>	विदेशी मुद्रा आस्तियां	कुल (2+3+4)				सकल आहरण राशियां	पुनः कय राशियां	बकाया बिल आहरण (9-10)	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निवल आहरण (+) चुकोटी राशियां (-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मार्च 1939	161	274	6,605	7,040	3,715	- 771	487	3,900	2,071	1,829	- 804	33
जून 1989	213	274	6,075	6,562	3,408	- 307	487	3,900	2,219	1,681	- 148	- 159
मार्च, 1990	183	281	5,787	6,251	3,045	- 670	487	3,900	2,752	1,148	- 681	11
जून 1990	206	281	5,356	5,843	2,784	- 261	487	3,900	2,863	1,037	- 111	- 150
सितम्बर 1990	863	281	4,512	5,656	2,523	- 522	--	3,900	3,008	892	- 256	- 753
दिसम्बर 1990	565	6,585	2,152	9,302	3,659	614	--	3,900	3,100	800	- 348	- 475
				(2,998)	(1,443)	(- 1602)						(- 1741)
मार्च 1991	200	6,828	4,388	11,416	4,329	1,284	--	5,169	3,221	1,948	800	- 3
				(4,869)	(2,111)	(- 934)						(- 2,221)
जून 1991	133	7,411	2,382	9,926	3,564	- 765	-	5,169	3,300	1,869	- 79	- 686
				(2,796)	(1,278)	- 833)						(- 754)

\* संबंधित महीनों के अंत में रुपया-विशेष आहरण अधिकार की विनिमय दर पर।

(६) 3 में, 16 अक्टूबर, 1990 तक स्वर्ण का मूल्य प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपये पर किया गया और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य पर बन्द हो गया। स्तम्भ 6 में, 16 अक्टूबर, 1990 तक स्वर्ण का मूल्य प्रति शुद्ध औंस विशेष आहरण अधिकार 35 पर रखा गया और इसके बाद स्तंभ 3 में दिया गया रुपये का मूल्य महीने के अंत के रुपया-विशेष आहरण अधिकार की विनिमय दर पर परिवर्तित किया गया।

टिप्पणी : (1) सकल आहरण, पुनः कय, अंतर्राष्ट्रीय, मुद्रा कोष के बकाया निवल आहरण विस्तारित निधि सुविधा के संबंध में हैं अर्थात् इसमें न्याय निधि कृण शामिल नहीं है।

(2) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े स्वर्ण के पुनर्मूल्यांकन के लिए समायोजित आरक्षित निधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(3) आंकड़ों में सभी प्रकार के घट-बढ़ पहले मार्च के हैं।

## विशेष आहरण अधिकार

10.11 वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान विशेष आहरण अधिकार धारिताओं में 6.0 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की गिरावट आयी जबकि 1989-90 में इनमें 2.4 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की वृद्धि हुई थी। 1990-91 के दौरान यह गिरावट निम्नलिखित का संयुक्त परिणाम थी : 94.3 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के समकक्ष विशेष आहरण अधिकारों का शुद्ध अभिग्रहण, पारिश्रमिक हेतु 10.1 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की प्राप्ति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 557.4 मिलियन विशेष आहरण अधिकार के समकक्ष आहरण, 524.9 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों का पुनः क्रय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रभारों/व्याज हेतु 142.9 मिलियन विशेष आहरण अधिकार (व्याज सहायता को घटाकर) का भुगतान किया गया। अग्रे अप्रैल-जून 1991 के दौरान मुख्य के रूप में पुनः खरीदे के कारण (79 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (51 मिलियन विशेष आहरण अधिकार) को प्रभार के भुगतान के कारण 28.2 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की गिरावट आई।

## स्वर्ण

10.12 मार्च 1991 के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक की स्वर्ण धारिताएं 6,828 करोड़ रुपये की थी तथा जून 1991 के अंत में 7,411 करोड़ रुपये, जबकि 16 अक्टूबर 1990 तक ये 281 करोड़ रुपये की थी इसमें यह परिलक्षित होता है कि 17 अक्टूबर 1990 से किया

गया स्वर्ण का पुनःमूल्यांकन लगभग अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के मरकत ही था।

## वाणिज्य व्यापार

10.13 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान वष व्यापार संबंधी शेष राशि में गिरावट परिलक्षित हुई इसकी वजह यह थी कि निर्यातों की वृद्धि दर में तेज गिरावट आयी जबकि पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण आयात बिल काफी बड़ गया। राजकोपीय वर्ष 1990-91 के लिए वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय द्वारा विदेश व्यापार के संबंध में जारी किये गये अंतिम आंकड़ों के अनुसार व्यापार घाटा पिछले वर्ष 7,731 करोड़ रुपये था जिसमें 2,913 करोड़ रुपये (37.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह 10,644 करोड़ रुपये हो गया (सारणी 10.5); किन्तु भुगतान के आधार पर (पहले दर्शाये गये भुगतान संतुलन के आंकड़े-स्वरित आकलन) 1990-91 के दौरान व्यापार घाटा 1,514 करोड़ रुपये पहुंच गया। तेल तथा तेल से इतर घटकों के कुल घाटे के अलग-अलग विवरण से पता चलता है कि 1990-91 के दौरान तेल संबंधी घाटा 1989-90 के 5,496 करोड़ रुपये से 77.7 प्रतिशत बढ़कर 9,768 करोड़ रुपये हो गया जबकि इसी अवधि के दौरान तेल से इतर घाटा 2,235 करोड़ रुपये से घटकर 876 करोड़ रुपये रह गया अर्थात् उसमें 60.8 प्रतिशत की गिरावट आई। 1990-91 के दौरान कुल व्यापार घाटे में तेल संबंधी घाटे का अनुपात 91.8 प्रतिशत था जबकि 1989-90 में यह अनुपात 71.7 प्रतिशत और 1988-89 में 49.6 प्रतिशत था।

सारणी 10.5 : भारत का विदेश व्यापार

(अप्रैल-मार्च)	(करोड़ रुपये)			मिलियन अमरीकी डालर			(मिलियन विशेष आहरण अधिकार)		
	1990-91	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I निर्यात	32,527	27,681	20,281	18,128	16,626	14,005	13,090	12,954	10,529
	(17.5)	(36.5)	(29.0)	(9.0)	(18.7)	(15.5)	(1.0)	(23.0)	(14.7)
अपरिष्कृत तेल	--	--	--	--	--	--	--	--	--
पेट्रोलियम, तेल और	938	696	505	523	418	349	377	326	262
चिकनाई के पदार्थ	(34.8)	(37.8)	(-20.2)	(25.1)	(19.8)	(-28.6)	(15.6)	(24.4)	(-29.1)
तेल से इतर	31,589	26,985	19,776	17,605	16,208	13,656	12,713	12,628	10,267
	(17.1)	(36.5)	(31.1)	(8.6)	(18.7)	(17.4)	(0.7)	(23.0)	(16.5)
II आयात	43,171	35,412	27,693	24,060	21,269	19,123	17,373	16,572	14,377
	(21.9)	(27.9)	(23.9)	(13.1)	(11.2)	(11.9)	(4.8)	(15.3)	(10.2)
तेल पेट्रोलियम, तेल तथा	9,706	6,192	4,178	5,967	3,719	2,885	4,308	2,898	2,169
चिकनाई के पदार्थ	(72.9)	(48.2)	(3.5)	(60.4)	(28.9)	(-7.3)	(48.7)	(33.6)	(-8.0)
तेल से इतर	32,465	29,220	23,515	18,093	17,550	16,239	13,065	13,674	12,208
	(11.1)	(24.3)	(28.5)	(3.1)	(8.1)	(15.0)	(-4.5)	(12.0)	(14.2)
III. व्यापार संतुलन	-10,644	-7,731	-7,412	-5,932	-4,643	-5,118	-4,283	-3,618	-3,848
तेल संबंधी शेष	-9,768	-5,496	-3,673	-5,444	-3,301	-2,536	-3,931	-2,572	-1,907
तेल से इतर शेष	-876	-2,235	-3,739	-488	-1,342	-2,582	-352	-1,046	-1,941

टिप्पणी:— (1) दशमलव के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत बढ़-बढ़ दर्शाते हैं।

(2) स्तंभ 1, 2 और 3 क्रमशः मार्च 1991, 1990 और 1989 के प्रेस नोटों पर आधारित हैं।

स्त्रोत : वाणिज्य आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

10.14 1986-87 से लेकर चार वर्ष तक निर्यात संबंधी कार्य-निष्पादन में परिलक्षित उल्लेखनीय वृद्धि को 1990-91 में बनाये न रखा जा सका। वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार 1990-91 के दौरान निर्यातों में 17.5 प्रतिशत वृद्धि हुई और उनकी राशि 32,527 करोड़ रुपये हो गयी जबकि पिछले वर्ष के दौरान उनमें 36.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, अमरीकी डॉलर की दृष्टि से निर्यात की वृद्धि दर 18.7 प्रतिशत से गिरकर 9.0 प्रतिशत रह गयी तथा विशेष आह्वरण अधिकार की दृष्टि से यह 23.0 प्रतिशत से गिरकर 1.0 प्रतिशत रह गयी। सानवी योजना अवधि के अंतिम दो वर्षों में परिलक्षित आयात की उच्च वृद्धि दरें 1990-91 में भी बनी रहीं। आयात की 43,171 करोड़ रुपये की राशि से 1990-91 के दौरान 21.9 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है, हालांकि यह वृद्धि दर पिछले वर्ष की 25.9 प्रतिशत वृद्धि दर से कम है। अमरीकी डॉलर के रूप में, 13.1 प्रतिशत की वृद्धि दर पिछले वर्ष में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से अधिक थी। किन्तु, विशेष आह्वरण अधिकार के रूप में आयात की गति में 4.8 प्रतिशत की काफी कम दर पर पिछले वर्ष की 15.3 प्रतिशत की तुलना में काफी कम है।

10.15 जैसाकि पहले जोर दिया गया पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयात से ही आयात में वृद्धि हुई। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयात के मूल्य की वृद्धि के संदर्भ में 1989-90 में 48.2 प्रतिशत और 1990-91 में 72.9 प्रतिशत थी। इसका कारण पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के डॉलर मूल्य में हुई काफी वृद्धि थी। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों से इतर आयातों की वृद्धि 1989-90 के 24.3 प्रतिशत से घटकर 1990-91 में 11.1

प्रतिशत हो गयी या अमरीकी डॉलर के रूप में यह 8.1 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत तथा विशेष आह्वरण अधिकारों के रूप में 12.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इसमें 4.5 प्रतिशत की गिरावट आई। तेल से इतर आयातों की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक उपाय किये ताकि निर्यात जरूरी विदेशी मुद्रा का भंडार बनाये रखा जाये।

10.16 उपलब्ध संकेतकों से पता चलता है कि 1986-87 से 1989-90 तक के लगभग चार वर्षों में देखी गयी 10 से 12 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष रूप से हुई निर्यातों की वृद्धि 1990-91 में बनाये नहीं रखा गया और वस्तुतः अगर कोई वृद्धि हुई तो भी बहुत कम।

#### निर्यात

10.17 मूल्य की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 1990-91 की अवधि के लिए उपलब्ध पण्य-वार आंकड़ों से पता चलता है कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात से वृद्धि पिछले वर्ष के 30.5 प्रतिशत की वृद्धि से जहाँ 29.5 प्रतिशत पर स्थिर रही, वहीं विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि पिछले वर्ष के 34.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 15.2 प्रतिशत (सारणी 10.6) रह गयी। इसके परिणामस्वरूप, प्राथमिक उत्पाद के निर्यातों ने कुल निर्यात में अपने अंश को 1989-90 के 21.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 23.7 प्रतिशत कर दिया जबकि विनिर्मित वस्तुओं का अंश 73.4 प्रतिशत से गिरकर 71.9 प्रतिशत रह गया। विनिर्मित वस्तुओं की श्रेणी के अन्तर्गत सूती धागा, वस्त्र एवं तैयार वस्त्र (39.5 प्रतिशत) सिले-सिलाये वस्त्र (25.4 प्रतिशत) एवं इंजीनियरी वस्तुओं (20.4 प्रतिशत) के निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तथापि, हीरे और आभूषणों के निर्यात

सारणी 10.6 : भारत के मुख्य पण्यों का निर्यात

पण्य समूह	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90		1990-91	
					(प्र)	(प्र)	(प्र)	(प्र)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
प्राथमिक उत्पाद	3,803	4,145	4,086	4,560	5,951	7,708		
उनमें से	(34.9)	(33.3)	(26.1)	(22.5)	(21.5)	(23.7)		
1. कृषि और उससे संबद्ध उत्पाद	3,018	3,422	3,312	3,544	4,571	6,013		
	(27.7)	(27.5)	(21.1)	(17.5)	(16.5)	(18.5)		
2. अयस्क और खनिज	785	723	774	1,016	1,380	1,695		
	(7.2)	(5.8)	(4.9)	(5.0)	(5.0)	(5.2)		
विनिर्मित वस्तुएं	6,447	7,808	10,900	15,128	20,310	23,387		
	(59.2)	(62.7)	(69.5)	(74.8)	(73.4)	71.9		
1. वस्त्र विनिर्मित वस्तुएं	1,795	2,179	3,212	3,618	5,246	6,755		
उनमें से								
सूती धागा, कपड़े, तैयार वस्त्र,	574	637	1,131	1,134	1,480	2,065		
सिले-सिलाये वस्त्र	1,067	1,331	1,823	2,118	3,224	4,042		
2. चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं	770	922	1,252	1,522	1,951	2,554		
3. दस्तकारी की वस्तुएं	1,881	2,548	3,245	5,188	6,285	6,247		
उनमें से								
रत्न और आभूषण	1,503	2,074	2,612	4,391	5,296	5,210		
4. रसायन और उससे संबद्ध उत्पाद	498	583	839	1,259	1,997	2,330		
5. इंजीनियरी वस्तुएं	954	1,148	1,492	2,321	3,321	3,997		
खनिज और चिकनाई की वस्तुएं*	645	411	649	505	697	938		
	(5.9)	(3.3)	(4.1)	(2.5)	(2.5)	(2.9)		
जोड़ (अन्य सहित)	10,895	12,452	15,674	20,232	27,681	32,527		

प्र.—घनत्व

\*—केवल पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित हैं।

व्यामलष में दिए गए आंकड़े कुल निर्यात का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्त्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय।

में पिछले चार वर्षों में औसत रूप से प्रतिवर्ष 38.0 प्रतिशत की नियमित वृद्धि हुई और सामान्यतया कुल विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में लगभग इसका हिस्सा एक-सीधा है, मुख्य रूप से औद्योगिक देशों में आर्थिक मंदी की प्रवृत्ति के कारण 1990-91 में इसके निर्यात में 2.4 प्रतिशत की संपूर्ण गिरावट आयी। प्राथमिक उत्पादों के अंतर्गत, कृषि एवं उससे संबद्ध उत्पादों का कार्य निष्पादन 1990-91 में 31.5 प्रतिशत बढ़ गया।

10.18 गंतव्य-वार देखा जाए तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल देशों के समूह का भारत के निर्यातों में 50 प्रतिशत से अधिक अंश रहा और यूरोपीय आर्थिक समुदाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार रहा। एक ओर पूर्वी यूरोपीय देशों तथा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के अंश में गिरावट आयी, वहीं विकासशील देशों के अंश में 1990-91 में थोड़ी सी वृद्धि हुई, हालांकि यह वृद्धि अत्यंत कम थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में शामिल देशों के अंश में जो गिरावट आयी उसका मुख्य कारण था ईंगक तथा क्यूबैत के साथ इन देशों का व्यापार बंद होना।

#### आयात

10.19 आठवीं योजना अवधि के अंतिम दो वर्ष के दौरान देखी गयी आयातों की तीव्र गति, तीसरा परवर्ती वर्ष 1990-91 में भी जारी रही, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयातों में हुई पर्याप्त वृद्धि है। पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के आयातों की मात्रा में हुई लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा बाड़ी संकट के कारण इन आयातों के वाहन में लगभग 40 प्रतिशत की अनुमानित औसत वृद्धि से आयात बिल में वृद्धि हुई।

10.20 1990-91 की अवधि के लिए पण्य-वार आंकड़े यह बताते हैं कि कुल आयातों में हुई 7,755 करोड़ रुपये की वृद्धि में से, थोक आयात जिनमें पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों का आयात अन्य थोक खपत की वस्तुएं और अन्य थोक मर्च (जो उद्योग के लिए मूल निविष्टियों के रूप में है) आदि सम्मिलित हैं, में 4,904 करोड़ की वृद्धि (34.4 प्रतिशत) हुई और कुल वृद्धि में यह 63.2 प्रतिशत है। गैर-थोक आयातों में 2,855 करोड़ रुपये या 13.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें प्रमुख मद पूंजीगत वस्तुएं हैं और इनमें 1,585 करोड़ रुपये या 17.9 प्रतिशत (सारणी 10.7) की वृद्धि हुई। निर्यात से संबद्ध मदों के आयात में \* 18 करोड़ (या 0.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, इसका कारण है मोतियों, बहुमूल्य तथा कम मूल्य के रत्नों के आयात में 1989-90 के 4,242 करोड़ से 1990-91 में 3,732 करोड़ की गिरावट आना।

10.21 आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन भारत के आयातों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तौत रहा, परंतु कुल आयातों में इसका अंश अप्रैल-फरवरी 1989-90 के 60.0 प्रतिशत से गिरकर अप्रैल-फरवरी 1990-91 के दौरान 57.2 प्रतिशत रह गया। लगभग 20 प्रतिशत आयात अमरीका तथा जापान से होता है। जहाँ आपूर्तिकर्ताओं के रूप में पूर्वी यूरोपीय देशों के अंश में गिरावट आयी, वहीं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और विकासशील देशों के अंश में वृद्धि हुई।

\*निर्यात से संबद्ध आयातों में मोती, बहुमूल्य तथा कम मूल्यवान रत्न, काजू, सूखी घागा और रासायनिक पदार्थ हैं, जिनमें कार्बनिक एवं आकारांतिक दोनों शामिल हैं।

सारणी 10.7 भारत के मुख्य पण्यों का आयात

पण्य समूह	1985-86					
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (अ)	1990-91 (घ)
1. थोक आयात	10763	8024	9084	11316	14239	19143
	54.8	39.9	40.8	40.1	40.2	44.3
उत्तम से						
(क) पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के उत्पाद तथा संबंधित सामग्री	4989	2811	4043	4358	6274	10820
	25.4	14.0	18.2	15.4	17.7	25.1
(ख) थोक उपयोगिता वस्तुएं	1466	1179	1503	1889	911	955
	7.5	5.9	6.7	6.7	2.6	2.2
(i) अनाज और अनाज में बनी चीजें	110	87	66	774	378	151
(ii) खाद्य तेल	749	634	969	730	211	322
(iii) बाले	189	234	275	385	228	473
(iv) चीनी	418	224	193	न	97	9
(ग) अन्य थोक मर्च	4308	4034	3533	5069	7051	7368
	21.9	20.0	15.9	18.0	19.9	17.1
(i) उर्वरक	1436	921	508	934	1776	1697
कच्चा	163	145	139	190	253	339
संघक और बिना तपाए लोहे के पाइराइट विनिर्मित	220	200	181	251	295	267
	1053	576	188	493	1228	1091
(ii) शतौत धातुएं	542	517	639	776	1253	1109
(iii) कागज, रत्ता और उनसे बनी वस्तुएं (अखबारों कागज सहित)	226	217	270	303	358	463
(iv) कपड़ा रखे	101	107	120	173	172	226

वस्तु समूह	195-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90(अ)	1990-91(अ)
(v) लुग्दी और रूई कागज	245	244	239	260	304	451
(vi) धातुमय ग्रयस्क और धातु की छीसन	363	472	442	690	883	1209
(vii) लोहा और इस्पात	1395	1556	1320	1933	2305	2210
2. फुटकर आयात	8895	12072	13160	16919	21173	24028
उनमें से	45.2	60.1	59.2	59.9	59.8	53.7
(क) पूर्णजीवन वस्तुएं	4286	6488	6566	6956	8831	10416
	21.8	32.3	29.5	24.6	24.9	24.1
(ख) मुख्यतः निर्यात से संबद्ध मर्चे	2366	2856	3351	5400	6803	6785
	12.0	14.2	15.1	19.1	19.2	15.7
(i) मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर	1100	1489	2018	3176	4242	3732
	5.6	7.4	9.1	11.2	12.0	8.6
(ii) रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक	1089	1145	1082	1894	2135	2472
	5.5	5.7	4.9	6.7	6.0	5.7
(iii) वस्त्रोपयोगी धागा, वस्त्र आदि	153	151	187	269	349	449
(vi) काजू की गिरी कच्ची	24	71	64	61	77	132
(ग) अन्य	2243	2728	3243	4563	5539	6827
जिनमें से	11.4	13.6	14.6	16.2	15.7	15.8
(i) कृत्रिम रेजिन तथा प्लास्टिक के सामान	322	434	567	809	996	1096
(ii) व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा नैज संबंधी सामान आदि	379	512	500	679	886	1082
(iii) कोयला, कोक, और ब्रिकेट्स, आदि	224	203	227	431	562	780
(iv) औषधीय और भेषजीय उत्पाद	177	214	168	236	272	325
(v) कपास, ऊन, सिल्क और वस्त्र उद्योग से सम्बंधी अन्य मर्चे	200	164	232	379	259	280
(vi) रसायन सामग्री और उसके उत्पाद	114	152	191	187	222	279
(vii) अधात्वक खनिज विनिर्मित वस्तुएं	102	129	105	164	168	211
जोड़ (1+2)	19658	20096	22244	28235	35416*	43171

अ-अंतर्गत

\* 1989-90 का जोड़ आंशिक रूप से संशोधित किया गया है।

न-नगण्य

टिप्पणी: दशमलव में दिए गए आंकड़े कुल आयात का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय

रूपों में भुगतान करने वाले देशों के साथ भारत का व्यापार

10.22 रुपया भुगतान करार के अधीन आने वाले देशों के साथ व्यापार, व्यापार करार के अनुरूप किया जाता है जो प्रत्येक देश की कुल बिक्री के आकार और व्यापार की वस्तु के संघटन के लिए रख-रेखा प्रस्तुत करता है। फिलहाल, केवल तीन देश अर्थात् सोवियत संघ, चेकोस्लोवाकिया तथा रूमानिया रुपया-भुगतान करार के अधीन अपने भुगतान का निपटान करते हैं। तथापि, भारत तथा रुपया भुगतान करार के अधीन आने वाले तीन देशों के बीच के व्यापार की कुल बिक्री का 95 प्रतिशत सोवियत संघ द्वारा किया जाता है।

10.23 1990-91 के दौरान में भुगतान करने वाले देशों के साथ किये जाने वाले निर्यातों तथा आयातों दोनों की विकास दरों में अधिक मंदी हुई। इस अवधि के दौरान निर्यातों में 5,506 करोड़ रुपये पर 13.9 प्रतिशत और आयातों में 2,870 करोड़ रुपये पर 22.7 प्रतिशत की बढ़ि हुई जबकि 1989-90 की इसी अवधि के दौरान विकास दर

लगभग 70.8 प्रतिशत और 60.6 प्रतिशत बढ़ी की गई थी। आयातों में कम विकास दर के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ व्यापार अधिशेष की राशि 143 करोड़ रुपये बढ़ गयी, 1980-91 के दौरान यह 2,636 करोड़ रुपये रही जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 2,493 करोड़ रुपये थी। नौवें दशक के दौरान में भुगतान करने वाले देशों के साथ भारत की स्थिति बेहतर थी। उसका अधिशेष 1980-81 में 218 करोड़ रुपये से बढ़कर 1989-90 में 2,493 करोड़ रुपये हो गया।

10.24 इस समय सोवियत संघ के साथ भारत का व्यापार वर्ष 1991 के लिए व्यापार योजना के अधीन किया जाता है। करार में शामिल वस्तुओं से पता चलता है कि सोवियत संघ द्वारा भारत को आयात की जाने वाली चीजों में मुख्यतया कच्चा तेल तथा इसके उत्पाद, उर्वरक, औद्योगिक कच्चा माल, मशीनरी एवं परिवहन उपकरण शामिल हैं। दूसरी ओर भारत के निर्यातों में कृषि में संबंधित वस्तुएं, कच्ची धातु एवं खनिज, सिलेसिलायें वस्त्र तथा कपड़े, मध्यवर्गी रसायन, औषधीय तथा भेषजीय उत्पादन और हल्की इंजीनियरी वस्तुएं होंगी। पूरे नौवें

दशक में भारत का मोबियल संघ के साथ व्यापार अधिशेष में था। 1980-81 में भारत का व्यापार अधिशेष 212 करोड़ रुपये से बढ़कर 1989-90 में 2,425 करोड़ रुपये हो गया जबकि 1990-91 के म्यारह महीनों की अवधि के दौरान बढ़कर यह 2,714 करोड़ रुपये तक पहुँच गया।

नीति संबंधी गतिविधियाँ

10.25 विदेशी मुद्रा भंडार की कठिन स्थिति को ध्यान में रखकर दुर्लभ विदेशी मुद्रा विनिमय को बनाये रखने के लिए सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनेक उपाय किये गये थे। भारत सरकार ने कुछ श्रेणियों के पूंजीगत वस्तुओं को खुला सामान्य लाइसेंस श्रेणी से लाइसेंसिंग श्रेणी में बदलाव कर दिया ताकि उनके आयातों पर अधिक नियंत्रण हो सके। औद्योगिक यूनिटों को सूचित किया गया कि पुनः प्रति लाइसेंस/प्रतिरिक्त लाइसेंस पर वे कच्चे माल तथा कल-गुर्जों का आयात कर सकते हैं। मोटर, इलेक्ट्रॉनिक तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के विनिमय में व्यस्त वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत कच्चे माल, कल-गुर्जों एवं उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान वास्तविक खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत आने वाले निर्यातों के मूल्य के 15 प्रतिशत कटौती के अधीन हुए। यह एक ऐसा उपाय है, जिसके द्वारा सभी वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को अपने अनुपूरक लाइसेंसों पर उक्त वस्तुओं के निर्यात के लिए बाद में अनुमति दी गयी थी। एजेंसी के माध्यम से किये जाने वाले आयातों पर भी प्रत्येक मामले के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा मंजूरी की आवश्यकता सहित प्रतिबंध लगाये गये थे। आयात-प्राप्तियों के शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए सरकार ने उनकी बसूली के बाद ही आयात पुनः प्रति लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया।

10.26 रिजर्व बैंक द्वारा किये गये उपायों में से एक उपाय था नकद माजिन की उगाही जो आयातों के स्तर को सामान्य करने के लिए अविवेकपूर्ण रीति से मौद्रिक लिखत के प्रयोग का अनिवार्य रूप से संकेत करती है। इसके पहले विस्तृत रूप से बताया गया था कि निर्यातकों तथा अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा सामना की गयी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उपायों में संशोधन किये गये। निर्यातोनमुख यूनिटों, मुक्त व्यापार क्षेत्रों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्रों में स्थिति यूनिटों द्वारा किये जाने वाले 100 प्रतिशत आयात माजिन से मुक्त हैं, वरन् निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए हो और निर्यात करने की तिथि से छह महीने की अवधि के बाद कोई भी निर्यात बिल बकाया न हो। जिन मामलों में निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र तथा रुपया भुगतान क्षेत्र दोनों के लिए किये गये हैं उन मामलों में ऐसे आयातों को पिछले वर्ष के दौरान किये गये कुल निर्यातों में सामान्य मुद्रा क्षेत्र के लिए किये गये निर्यातों के अनुपात के आधार पर निश्चय किया जायेगा, जिन पर माजिन आवश्यकता की छूट दी जायेगी। कतिपय पूर्व-शर्तों के अधीन जिनमें से एक है, निर्धारित अवधि के निर्यात प्राप्तियों की बसूली, विभिन्न प्रकार के अधिमों तथा खुद के खपत के लिए पेशगी लाइसेंसों पर किया जाने वाले आयातों के लिए भी माजिन आवश्यकता से छूट दी गयी। परन्तु संबंधित निर्यातकों को (i) यदि लेन-देन का मूल्य क्रमशः 25 लाख/50 लाख से अधिक हो तो बैंक के मुख्यालय/भारतीय रिजर्व बैंक तथा (ii) यदि संवर्धी मूल्य 2 करोड़ रुपये से अधिक हो तो भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेनी होगी। निर्यातों के लिए रिजर्व बैंक के पूर्ण अनुमोदन की परवर्ती शर्त के 2 करोड़ रुपये के संवर्धी निर्यात को संशोधित कर 2 करोड़ रुपये तथा 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन पिछले वर्ष की निर्यात प्राप्तियों के 20 प्रतिशत कर दिया गया। साथ ही, अनुरक्षण आयातों जिनमें कच्चे माल शामिल हैं, को पिछले लेखा वर्ष के दौरान के सामान्य मुद्रा क्षेत्र से प्राप्त उनकी वास्तविक निर्यात वस्तुओं के 10 प्रतिशत की राशि तक बिना नकद माजिन के निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी। एक ओर जहाँ रिजर्व बैंक निर्यात से संबद्ध आयात बिलों की मंजूरी को वरीयता देगा वहीं दूसरी ओर ये

रियायतें उन्हीं निर्यातकों के लिए उपलब्ध हों, जिनके पास निर्यात की तिथि से छह महीने के बाद कोई भी निर्यात बिल बकाया न हो।

10.27 अल्पकालिक आर्थिक व्यवस्था के एक अंश के रूप में विदेशी मुद्रा के भंडार में तीव्र गिरावट के जवाब में सरकार ने अनेक उपाय किए। जन्म किये गये सोने में से सरकार ने 20 मेट्रिक टन सोना भारतीय स्टेट बैंक को पट्टे पर दिया और भारतीय स्टेट बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पुनःक्रय के विकल्प के साथ इसकी बिक्री की। इस लेन-देन के परिणामस्वरूप निम्न विदेशी मुद्रा विनिमय में 200 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई, जो लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि के समान है। सोने को पट्टे पर देने से देण में आने वाला सोना या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय की प्राप्तियों के रूप में रखे गये सोने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय स्टेट बैंक को केवल पट्टे पर छह महीने की अवधि के लिए सोना दिया गया है। पट्टा-करार के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संविदात्मक दायित्व के अंतर्गत पट्टे की अवधि की समाप्ति पर सरकार को सोना वापस किया जाना है। दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी रिजर्व प्रबंधनीय नीति तथा तात्कालिक रूप से संसाधनों को जुटाने के एक उपाय दोनों के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम द्वारा अनुमत 15 प्रतिशत की सीमा तक के सोने को विदेशों में रखने का निर्णय लिया था। अतः भारतीय रिजर्व बैंक ने 46.9 टन की कुल सोना की सीमा तक सोना जो अनुमत सीमा के गजदीक है, को चार किस्तों में बैंक ऑफ इंग्लैंड के वाल्ट में भेजा है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम बैंक की स्वर्णधारिता का 15 प्रतिशत सोना भारत के बाहर रखने के लिए बैंक को अधिकृत करता है। अधिनियम यह भी प्राधिकृत करता है कि बैंक एक महीने की अवधि के लिए किसी भी मौद्रिक प्राधिकरण से उधार ले सकता है और उसके लिए आवश्यक प्रतिभूति की व्यवस्था कर सकता है जुलाई 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड तथा बैंक ऑफ जापान से 1,037.73 करोड़ रुपये की कुल राशि (405.0 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर है) जुटायी गयी जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जमा किये गये सोने पर लिया गया था।

नयी व्यापार नीति की प्रणाली

10.28 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 को/के बाह्य मूल्य में दो बार तीव्र निम्नगामी समायोजन किये जाने से सरकार ने व्यापार नीति में मुख्य संशोधनों की घोषणा की। नयी नीति के अनुसार एक ओर जहाँ पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों, उर्वरक एवं खाद्य तेल जैसे आवश्यक आयातों में कटौती नहीं की जायेगी वहीं दूसरी ओर अन्य सभी आयातों को निर्यातों से संबद्ध किया जाएगा। 3 जुलाई 1991 को घोषित नीति की एक मुख्य बात यह है कि इन समय लागू जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत के बीच की विभिन्न दरों के स्थान पर जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 30 प्रतिशत की एक समान पुनः प्रति लाइसेंस वर वाली एक विस्तृत एवं उदारीकृत लाइसेंस प्रणाली को शुरूआत की गई। अब पुनः प्रति लाइसेंस को एक्जिम स्किप कहा जायेगा और उसमें मुक्त व्यापार किया जायेगा। व्यापार प्रणाली के काफी उदारीकरण तथा/की विनिमय दर में तीव्र समायोजनों को ध्यान में रखकर नकदी प्रतिभूति योजना को 3 जुलाई 1991 में निर्यात कर दिया गया।

10.29 व्यापार नीति की घोषणा का उद्देश्य यह है कि सरकार तीन वर्ष की अवधि में कुछ महत्वहीन सूची को छोड़कर पूंजीगत वस्तुओं तथा कच्चे माल के लिए सभी आयात लाइसेंस को हटा देगी और आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी चीजों/मदों का सरणीकरण बंद कर देगी, यह भी असा की जाती है कि तीन से पांच वर्षों में रुपया व्यापार खातों में पूरी तरह विनिमय होगा।

10.30 13 अगस्त, 1991 को सरकार ने व्यापार नीति में आरंभ सुधारों की घोषणा की। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, 100 प्रतिशत निर्यातोनमुख उकाइयो तथा निर्यात-संसाधन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन का

एक नया पैकेज, मूल्य योजित मर्चों के लिए निर्यात-आयात शेरों की वरों में वृद्धि, कतिपय आयात तथा निर्यात मर्चों को सरणी से हटाना और अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है। सभी प्रकार की निर्यात-आयात इकाइयों/निर्यात-संसाधन क्षेत्रों की इकाइयों निम्न विदेशी मुद्रा की भाव के 30 प्रतिशत तक निर्यात-आयात शेरों के लिए पात्र हैं, जबकि उच्च मूल्य-योजित कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा अर्थों को निर्यात-आयात शेरों में 40 प्रतिशत की छूट है। निर्यात की 16 वस्तुओं को सरणी से तत्काल हटा दिया गया है। निर्यात के मामले में, जहाँ 6 मर्चों को सरणी से हटाकर खुला सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया है, वहीं 14 मर्चों को सरणी से हटा दिया गया है। सरकार में निर्यात संवर्धन के एक हथियार के रूप में अग्रिम लाइसेंस प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये। अग्रिम लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया गया ताकि उसे शीघ्र जारी करना सुनिश्चित किया जा सके।

**व्यापार तथा भुगतान-संतुलन के आंकड़ों के बीच अंतर**

10.31 वर्ष 1991-92 के लिए त्रि-बैंक के भुगतान संतुलन के आंकड़ों (त्वरित आकलन) तथा वाणिज्यिक व्यापार से संबंधित (सारणी 10.2 तथा 10.4) वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महाविभाग के आंकड़ों के आयात आंकड़ों में 5,149 करोड़ रुपये (2,870 मिलियन डॉलर) का अंतर होया जबकि वर्ष 1989-90 में यह अंतर 5,762 करोड़ रुपये (3,461 मिलियन डॉलर) (अंतिम अनुमान) का था। इसका मुख्य कारण शामिल किये गये क्षेत्र, अवधि तथा मूल्यांकन में अंतर था। 1988-89 में, भुगतान संतुलन के आंकड़ों के अनुसार आयात के आंकड़े इसी प्रकार 6,509 करोड़ रुपये (4,495 मिलियन डॉलर) अधिक थे। इनके अंतर का मुख्य कारण था शामिल किए गए क्षेत्र, समय और मूल्यांकन में अंतर का होना। इन कारणों के बारे में वर्ष 1988-89 और 1989-90 की वार्षिक रिपोर्टों में विस्तृत रूप में बताया गया था। निर्यात आंकड़ों के संबंध में कुछ मामूली अंतर हैं।

**अदृश्य वस्तुएं**

10.32 उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि 1990-91 के दौरान अदृश्य लेन-देनों की प्राप्ति में, पिछले वर्ष की प्राप्ति की तुलना में रुपये तथा डॉलर दोनों में भारी गिरावट आयी होगी, उनमें निरक्षेप गिरावट आई होगी। 1990-91 के दौरान निम्न अदृश्य लेन-देनों की प्राप्ति में गिरावट में सहयोग का मुख्य कारण था 'खाड़ी क्षेत्र' से प्राप्ति में गिरावट के आंशिक कारण से निजी अंतरणों के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति का कम हो जाना। इसके अलावा यात्रा और पर्यटन से अर्जित राशि में डॉलर के संबंध में भारी गिरावट रिकार्ड करने की संभावना व्यक्त की गयी। 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान देश में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 8.8 प्रतिशत घट गयी थी जबकि पिछले वर्ष उनमें 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। भागे बाहरी सहायता तथा वाणिज्यिक शर्तों दोनों पर व्याज भुगतान एवं सेवा प्रभार बढ़ते जाने के कारण पहले जैसे ही निवेश भाव के अंतर्गत भुगतानों की वृद्धि जारी रही। तथापि अदृश्य लेन-देनों के अन्य घटकों को मिलाकर यह संभावना नहीं है कि पिछले वर्षों की तुलना में कोई महत्वपूर्ण अंतर दिखाई पड़े।

**बाहरी सहायता**

10.33 वर्ष 1990-91 के दौरान सकल बाहरी सहायता की प्राप्ति में वृद्धि हुई। ऋणों एवं अनुदानों का सकल उपयोग 6,660 करोड़

रुपये था जो 1989-90 के दौरान 5,803 करोड़ रुपये की तुलना में 857 करोड़ रुपये अधिक था, ऋण सहायता का अधिक उपयोग ही जिसका मुख्य कारण था। परिशोधन भुगतानों में वृद्धिशील प्रवृत्ति जारी रही और वर्ष 1990-91 के दौरान ये 2,395 करोड़ रुपये हो गया जबकि पिछले वर्ष यह 1,987 करोड़ रुपये था। 1990-91 के दौरान बाहरी सहायता की निम्न राशि 449 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,265 करोड़ रुपये हो गयी (सारणी 10.8)। तथापि, अमरीकी डॉलर के रूप में सहायता की निम्न राशियां पिछले वर्ष की तुलना में 2,373 मिलियन डॉलर की ओर अपेक्षाकृत अधिक है।

10.34 अन्य बातों के साथ-साथ, गंभीर भुगतान संकट का सामना करने के लिए किये जाने वाले प्रयासों में शीघ्र संवितरण के रूप में भुगतान-संतुलन के सहयोग के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा अनेक वाता देशों से प्रस्ताव आदि सम्मिलित हैं। अप्रैल 1991 के आरंभ में, एशियाई विकास बैंक ने भारतीय तेल निगम को 150 मिलियन अमरीकी डॉलर ऋण की मंजूरी दी ताकि ऊर्जा क्षेत्र खाड़ी संकट के प्रतिकूल प्रभाव से उबर सके। 29 मई 1991 को जापान ने एशियाई विकास बैंक द्वारा दी गई राशि से समान राशि को सह-वितीय सहायता के रूप में 150 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण उपलब्ध कराया। जापान ने, छोटे उद्योगों के विकास के लिए उप-उधार-कर्ताओं को पुनर्भित देने हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 150 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रतिरिक्त ऋण प्रदान किया। जून 1991 में 140 करोड़ रुपये (100 मिलियन स्विस फ्रैंक) की एक मिश्रित ऋण व्यवस्था के लिए हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें 40 प्रतिशत स्विस सरकारों के अनुदान के रूप में है और 60 प्रतिशत निर्यात ऋण के रूप में है।

**योजना अवधि के दौरान चाबू खाता घाटे के वित्त-पोषण की पद्धति**

10.35 सातवीं योजना अवधि के दौरान वित्त-पोषण की पद्धति से पता चलता है कि वित्त पोषण आवश्यकता का 29 प्रतिशत बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वाता देशों से, बाहरी सहायता के रूप में प्राप्त ऋणों से 24 प्रतिशत वाणिज्यिक उधारों से 23 प्रतिशत विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना तथा अनिवासी विदेशी रुपया खाता योजना के अंतर्गत अनिवासी जमा-राशियों से, लगभग 13 प्रतिशत अन्य पूंजीगत लेन-देनों से और शेष की पूर्ति आरक्षित निधियों के आहरणों से हुई है (सारणी 10.9)। ऊपर उल्लिखित अन्य पूंजीगत लेन-देन में मुख्य रूप से बैंकों की स्वीकृति सुविधा, अनिवासी भारतीय बांड, आफशोर म्यूचुअल निधि, बैंकों तथा अर्थों की विदेशी मुद्रा जमा राशियां तथा अंश 0.00 कोष से आरक्षित अंश आहरण (अंतिम दो मर्चे) 1990-91 में शामिल हैं।

**अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत वृद्धि**

10.36 वर्ष 1990-91 के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत 146 करोड़ रुपये के आहरण किये गये (अनुमानित व्याज घटक को छोड़कर) जबकि पिछले वर्ष यह 4 करोड़ रुपये का था। विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत 1990-91 के दौरान 255 करोड़ रुपये की निम्न प्राप्ति हुई जबकि 1989-90 में यह राशि 2,179 करोड़ रुपये थी (सारणी 10.10)।



## सारणी 10.8 : बाहरी सहायता

(करोड़ रुपये)

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. ऋण	2,493	3,176	4,574	4,739	5,138	6,089
2. अनुदान	443	429	478	566	665	571
3. सकल उपयोग	2,936	3,605	5,052	5,305	5,803	6,660
4. चुकोती राशियाँ	776	1,176	1,581	1,646	1,987	2,395
5. ग्रा. (3-4)	2,160	2,429	3,471	3,659	3,816	4,265
जापत मद						
निदल राशि						
मिलियन अमरीकी डॉलर में	1,766	1,901	2,628	2,527	2,292	2,377

टिप्पणी : 1. ऋणों में गैर सरकारी ऋण शामिल है, परन्तु आपूर्तिकर्ता ऋण तथा वाणिज्यिक उधार शामिल नहीं हैं और इसीलिए ये आंकड़े सारणी 10.2 के आंकड़ों से भेद नहीं करा सकते।

2. अनुदानों में पी. एल. 480-II अनुदान शामिल नहीं है।

(स) अन्तिम

## सारणी 10.9 : वित्तपोषण की आवश्यकता और वित्तपोषण के स्रोत

	करोड़ रुपये					मिलियन अमरीकी डॉलर	मिलियन विशेष आहरण अधिकार
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90अ		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. भूल-भूक सहित खाल खाता बाटा	5,347	5,959	7,240	10,207	10,113	38,866	22,255.7
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चुकोती राशियाँ	253	672	1,209	1,547	1,460	5,141	2,823.4
3. वित्तपोषण की आवश्यकता (1+2) निम्नलिखित से वित्तपोषित	5,600	6,631	8,449	11,754	11,573	44,007	25,079.1
4. बाहरी सहायता	1,676 (29.9)	1,808 (27.3)	2,928 (34.7)	3,210 (27.3)	3,054 (26.4)	12,676 (28.8)	9,093.9 (29.0)
5. वाणिज्यिक उधार	1,166 (20.8)	2,513 (37.9)	1,283 (15.2)	2,743 (23.3)	2,866 (24.8)	10,571 (24.0)	7,524.7 (24.0)
6. अनिवासी अमारणियाँ	1,767 (31.6)	1,650 (24.9)	1,840 (21.8)	2,465 (21.0)	2,175 (18.8)	9,897 (22.5)	7,163.1 (22.8)
7. अन्य पूर्ण	285 (5.1)	-71 (-1.10)	1,442 (17.1)	1,887 (16.1)	2,247 (19.4)	5,790 (13.2)	3,942.2 (12.6)
8. आरक्षित निधियों का प्रयोग	706 (12.6)	732 (11.0)	956 (11.3)	1,449 (12.3)	1,231 (10.6)	5,074 (11.5)	3,627.2 (11.6)

टिप्पणी : वित्तपोषण की आवश्यकता के अनुपात में प्रतिशत दर्शाते हैं (मद 3)। अमरीकी डॉलर तथा विशेष आहरण अधिकार में रूपांतरण 1985-90 के लिए तत्संबंधी वार्षिक औसत दरों पर किये गये हैं।

अ- अन्तिम

सारणी 10.10 : अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अन्तर्गत प्राप्तियां

(करोड़ रुपये)

राजकोषीय वर्ष	अनिवासी विदेशी रुपया खाता	विदेशी मुद्रा (अनिवासी खाता)	जोड़
1	2	3	4
1985-86	616	1,151	1,767
1986-87	477	1,173	1,650
1987-88	477	1,363	1,840
1988-89	335	2,230	2,465
1989-90	*4	2,179	2,175
1990-91	*146	255	109

@ इसमें अनुमानित प्रोद्भूत व्याज सम्मिलित नहीं है।

\*अनंतिम

सारणी 10.11 : अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना और विदेशी मुद्रा अनिवासी रुपया खाता योजना के अन्तर्गत जमादारियों की देयताएं

(करोड़ रुपये)

विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता

निम्नलिखित के मार्ग के अन्त में अनिवासी विदेशी रुपया खाता*	धनरीकी डॉलर	पॉड स्टैमिंग	ड्यूस मार्क	येन	जोड़@ (3 से 6)	कुल जोड़ (2+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1986	3,461	1,759 (1,419)	430 (236)	-	-	2,189	5,650
1987	4,336	3,047 (2,360)	464 (224)	-	-	3,511	7,847
1988	5,107	4,406 (3,410)	541 (222)	-	-	4,947	10,054
1989	5,899	6,648 (4,245)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	14,154
1990	6,507	9,304 (5,409)	337 (119)	1,028 (1,013)	655 (60,327)	11,324	17,831
1991	7,041अ	11,270 (5,754)	305 (89)	1,005 (874)	825 (59,403)	13,405	20,446

\* प्रोद्भूत व्याज सहित

@ प्रोद्भूत व्याज शामिल नहीं है।

अ. अनंतिम

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित मुद्राओं में बकाया जमादारियों में मिलियन में हैं।

सारणी 10.12: विदेशी मुद्रा अनिवार्य खाते की जमा राशियों पर व्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

प्रभावी तारीख	अमेरिकी डालर				पौंड-स्टेरलिंग				ड्यूज मार्क				येन			
	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	2 वर्ष से 3 वर्ष तक	केवल 3 वर्ष
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30 मई 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
19 जुलाई 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.25	8.25	8.25	8.25
13 अगस्त 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.50	8.50	8.50	8.50
3 सितम्बर 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	9.00	9.25	9.25	9.25
25 सितम्बर 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	9.25	9.50	9.75	9.75
4 दिसम्बर 1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.50	9.75	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00
14 जनवरी 1991	8.25	8.50	9.00	9.25	11.50	11.75	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50
8 फरवरी 1991	7.50	8.00	8.50	9.00	13.25	13.25	13.25	13.25	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50

10.37 सारणी 10.11 से यह पता चलता है कि मार्च, 1990 के अंत में अनिवासी जमाराशियां 20,446 करोड़ रुपये थीं (अनिवासी (विदेशी) रुपया खाता योजना के अंतर्गत 7,041 करोड़ रुपये तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत 13,405 करोड़ रुपये)।

अनिवासी जमाराशियों पर व्याज दरें

10.38 अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में व्याज दर में घट-बढ़ की प्रवृत्तियों को देखते हुए विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना के अंतर्गत जमाराशियों पर व्याज दरें, वर्ष 1989-90 के मुकाबले विचाराधीन अवधि के दौरान तुलनात्मक रूप से कम स्तर पर निर्धारित की गयी थीं। सारणी 10.12 में विचाराधीन अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता योजना की जमाराशियों पर विभिन्न मुद्राओं के संदर्भ में व्याज दरें दी गयी हैं।

विदेशी ऋण

10.39 पिछले कुछ वर्षों में देखे गये आवृत्तियों तथा बढ़ते हुए बाह्य खाता घाटों के साथ भारत की बाहरी देयताएं, जिनमें बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहायता, वाणिज्यिक उधार तथा अनिवासी जमाराशियां सम्मिलित हैं, क्रमिक रूप से इस अवधि में बढ़ गयी हैं। भारत के मध्यावधि तथा दीर्घावधि ऋणों (अनिवासी जमाराशियों से अन्य), अर्थात् मूल रूप से या बढ़ायी गयी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है, को राशि मार्च 1990 के अंत में 81,168 करोड़ रुपये (लगभग 47 मिलियन अमरीकी डालर) थी और यह अनुमान किया गया है कि मार्च 1991 के अंत में यह 1,00,197 करोड़ रुपये (51 मिलियन अमरीकी डालर) तक बढ़ेगी

(सारणी 10.13)। अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों सहित भारत की विदेशी देयताएं (अल्पावधि ऋण से अन्य) मार्च 1991 के अंत में 1,20,643 करोड़ रुपये (61.42 मिलियन अमरीकी डालर) परिलक्षित होंगी। दीर्घावधि तथा मध्यावधि ऋणों के अभाव में आयातों के साथ जहाँ अल्पावधि ऋण भी है। यह अल्पकालिक ऋण आपूर्तिकर्ताओं के उधार (एक वर्ष से कम परिपक्वता अवधि के साथ) बैंकों की स्वीकृत सुविधा के अंतर्गत व्यापार ऋणों की प्रकृति का है।

10.40 वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के संबंध में बाहरी ऋण (दीर्घावधि तथा मध्यावधि) मार्च 1991 के अंत में 19.3 प्रतिशत बढ़ते का अनुमान है जबकि ये मार्च 1990 के अंत में 18.4 प्रतिशत थे। ऋण (दीर्घावधि तथा मध्यावधि) निर्यात का अनुपात मार्च 1990 के अंत में लगभग 20.2 प्रतिशत था जबकि मार्च 1989 में यह 22.6 प्रतिशत था। यह नोट करने योग्य विषय है कि ऋण प्रदायगी अनुपात अर्थात् ऋण प्रदायगी भुगतान का अनुपात, जिसमें अनिवासी जमाराशियों पर व्याज सम्मिलित नहीं है, वस्तुओं तथा अदृश्य वस्तुओं के निर्यात जिसमें सरकारी अंतरण प्राप्ति सम्मिलित नहीं हैं वर्ष 1989-90 में 21.0 प्रतिशत तक घट जाने का अनुमान है जबकि वर्ष 1988-89 में यह 23.0 प्रतिशत था। साप्ताहिक योजना अवधि के दौरान वार्षिक औसत ऋण प्रदायगी अनुपात लगभग 21.0 प्रतिशत था, जो योजना दस्तावेजों में परिलक्षित 17.6 प्रतिशत औसत से काफी अधिक था। वर्ष 1990-91 के दौरान ऋण प्रदायगी अनुपात लगभग 21.3 प्रतिशत होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

सारणी 10.13: भारत के विदेशी ऋण

(करोड़ रुपये)

निम्नलिखित वर्षों के मार्च के अंत में

	1980**	1985	1986	1987	1988	1989	1990(अ)	1991(अ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. विदेशी सहायता	12,178	24,004	26,638	32,312	36,578	46,838	64,095	65,694
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष		4,888	5,271	5,548	4,732	3,696	2,573	3,133
3. बाहरी वाणिज्यिक उधार**	1,252	6,908	8,075	11,243	13,543	19,147	24,500	29,370
4.1 जोड़ (1+2+3)	13,430	35,800	39,984	49,103	54,853	69,681	81,168	1,00,197
4.2 जोड़	16,392	28,801	32,391	37,699	42,993	44,485	47,109	51,009
मिलियन अमरीकी डालरों में								
ज्ञापन मदें								
1. ऋण स्टॉक (दीर्घावधि तथा मध्यावधि) निर्यात अनुपात (a) (प्रतिशत में)		181	209	233	218	226	202	216
2. ऋण - भुगतान अनुपात (संबंध राजकोषीय वर्षों के लिए) (प्रतिशत में)		12.0	16.1	19.3	21.3	23.6	21.0	21.3

\*\* भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति के सर्वेक्षण पर आधारित भारतीय रिजर्व बैंक क्वार्टर, अप्रैल 1985 में प्रकाशित।

\* इसमें बाहरी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-सरकारी ऋण और पूर्वी यूरोपीय देशों से रुपये में प्रविष्टि आपूर्तिकर्ता के ऋण शामिल हैं।

(a) निर्यात में व्यापारिक वस्तुओं और सरकारी अंतरण को छोड़कर अदृश्य प्राप्ति के निर्यात शामिल हैं।

अ. अर्थात्

प्रमुख मुद्राओं की विविधता वर्षों में उतार-चढ़ाव

10.41 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, विदेशी मुद्रा विविधता बाजार कुछ प्रभावों के अधीन थे, अर्थात् प्रमुख औद्योगिक देशों में समष्टिगत आर्थिक गतिविधियों और उनके समर्थन में नीतिगत प्रतिक्रियाएं, खाड़ी संकट तथा पूर्वी यूरोप एवं सोवियत संघ में राजनीतिक गतिविधियां। आर्थिक विकास की मंटी के साथ-साथ बढ़ते हुए स्वीकार्य वस्तुओं का सामना करने वाले प्रमुख औद्योगिक देशों ने आर्थिक क्षमता के विकास के लिए अपने संरचनागत मुद्दों में आवश्यक समायोजन उपाय करने

की सहमति दी। फिर भी, विविधता बाजारों में पूर्णतः स्थिरता थी। आर्थिक तथा राजनीतिक बदलावों के अभाव में, व्याज दर घटने का विविधता दर उतार-चढ़ाव को प्रभावित किया। मध्य-पूर्वी संकट के दौरान, अमरीकी डालर पर दबल पड़ा जिससे उच्चरी मुद्रा ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर घा गई, विशेषकर दृश्य मार्ग के मुकाबले में। इस अवधि में आर्थिक कार्य-निष्पादन में गिरावट आयी थी और अनिवासी, कमांड तथा क्रेडिट की राष्ट्रीय धर्म-व्यवस्था आर्थिक-मंदी की ओर चल गयी। मिनम्बर 1990 तक पीड स्टॉकिंग में अनियमित उतार-चढ़ाव में उम्र समाय

बदलाव आया जब ब्रिटिश मुद्रा ने अक्टूबर, 1990 में यूरोपीय विनिमय दर प्रणाली अपना ली। अनुकूल विभेदक व्याज दरों के कारण जापानी येन विनिमय बाजार में संभल गया। ड्यूश मार्क के संबंध में, प्रारंभिक मुद्रादीकरण के बावजूद यह मुद्रा जर्मनी के पुनः एकीकरण से उत्पन्न दबाव के अधीन आ गई। खाड़ी युद्ध के बाद अमरीकी डालर तेजी से संभल गया और ड्यूश मार्क की तुलना में इसके मूल्य में वृद्धि हुई। विनिमय बाजारों में व्यापक अस्थिरता के बावजूद, विशेषकर खाड़ी संकट के बाद, समूह-7 के देशों ने विश्व-प्राथमिक कार्यानिष्पादन में अपने भरोसे की अभिव्यक्ति की और उनके मंत्रियों और केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों ने मुख्यवस्थित विनिमय बाजारों के लिए नजदीकी सहयोग देने की वचन-बद्धता पर पुनः जोर दिया।

10.42 1990-91 के दौरान (जुलाई-जून) मासिक औसत के संबंध में, अमरीकी डालर ने पिछले वर्ष की तरह ही एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाया जारी रखा। जुलाई-नवंबर 1990 के दौरान वह कमजोर हो गया। इसके पश्चात खाड़ी संकट की सफलतापूर्वक समाप्ति तक वह विशाहीन रहा, परन्तु बाद में जून 1991 तक प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले वह मजबूत हो गया। येन को छोड़कर अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में अमरीकी-डालर में थोड़ी वृद्धि दिखायी दी। जून 1990 के अंत से जून 1991 के अंत के बीच में पौड-स्टैलिग की औसत रूप से ड्यूश मार्क

की तुलना में उपलब्धि रही परन्तु विशेष आह्वरण अधिकार, अमरीकी डालर तथा येन के मुकाबले इसकी हानि हुई। इस अवधि के दौरान ड्यूश मार्क की सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले हानि हुई। पिछले वर्ष की प्रवृत्ति के विलकुल विपरीत, येन सभी प्रमुख मुद्राओं तथा विशेष आह्वरण अधिकारों की तुलना में सुदृढ़ बन गया (सारणी 10.14)

रुपये की विनिमय दर

10.43 रुपये का मूल्य, व्यापार में भारत के मुख्य सहभागिता के भारत मुद्रा समूह के संबंध में निर्धारित किया जाना और पौड स्टैलिग इसकी मध्यवर्ती मुद्रा होना जारी रहेगा। अव्यवस्था में अन्य मूल्यों की तरह विनिमय दर भी एक मूल्य है और इसका प्रयोग कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। विनिमय दर समायोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व बाजार में हमारे निर्यातों की प्रतिस्पर्धा को विकसित करना रहा है। इस संबंध में, यहाँ और विदेशों में पण्यों के मूल्यों की प्रवृत्तियों की समीक्षा करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हमारे निर्यातों के मुख्य अंतराष्ट्रीय बाजार के निर्यातों मूल्यों की तरह ही हैं। यह देखा गया था कि मूल्यह्रास की मदद के कारण नाममात्र की विनिमय दर और अक्टूबर 1990 से हमारे प्रभावी यथार्थ विनिमय दर में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फरवरी 1991 तथा जून 1991 के बीच के पांच महीने की अवधि में रुपये की नाममात्र की प्रभावी

सारणी 10.14 : रुपये की विनिमय दरें

(विशेष आह्वरण अधिकार/विदेशी मुद्रा की प्रति यूनिट के बराबर रुपये)

अवधि	विशेष आह्वरण अधिकार	अमरीकी डालर	पौड स्टैलिग	ड्यूश मार्क	जापानी येन
1	2	3	4	5	6
अ. वार्षिक औसत दरें					
(अप्रैल मार्च)					
1986-87	15.4472	12.7782	19.0722	6.2970	0.0802
1987-88	17.1208	12.9658	22.0872	7.4004	0.0941
	(-9.8)	(-1.4)	(-13.7)	(-14.9)	(-14.8)
1988-89	19.2619	14.4819	25.5959	8.0494	0.1130
	(-11.1)	(-10.5)	(-13.7)	(-8.1)	(-16.7)
1989-90	21.3684	16.6492	26.9179	9.0922	0.1166
	(-9.9)	(-13.0)	(-4.9)	(-11.5)	(-3.1)
1990-91	24.8491	17.9428	33.1930	11.4351	0.1279
	(-14.0)	(-7.2)	(-18.9)	(-20.5)	(-8.8)
आ. मासिक औसत दरें					
मार्च 1989	20.1989	15.5137	26.5858	8.3083	0.1190
मार्च 1990	22.2961	17.1274	27.8218	10.0454	0.1118
मार्च 1991	26.6358	19.2009	35.0742	11.9658	0.140
%मूल्यवृद्धि (+)					
मूल्यह्रास (-)					
मार्च 1990 की तुलना में					
मार्च 1991	(-16.29)	(-10.80)	(-20.68)	(-16.05)	(-20.14)
जून 1990	22.9224	17.4206	29.7858	10.3484	0.1133
जून 1991	27.7722	21.0053	34.6572	11.7874	0.1504
%जून 1990 की तुलना में					
जून 1991 में प्रतिशत					
मूल्यवृद्धि (+)					
मूल्यह्रास (-)					
	(-17.46)	(-17.07)	(-14.06)	(-12.21)	(-24.67)

1	2	3	4	5	6
१. निम्नलिखित को विनिमय दरें					
31 मार्च, 1989	20.2082	15.6630	26.40	8.2764	0.1180
30 मार्च, 1990	22.4090	17.3248	28.30	10.2118	0.1104
29 मार्च, 1991	26.3457@	19.6429	34.10	11.4784	0.1391
29 जून, 1990	23.1820	17.5439	30.50	10.5180	0.1145
28 जून, 1991	27.8550	21.0410	34.36	11.7390	0.1523
1 जुलाई, 1991	30.3402	23.1215	37.48	12.7613	0.1678
3 जुलाई, 1991	33.8930	25.9532	41.59	14.1569	0.1871

@दिनांक 28-3-91 को

विषयी-कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े रुपये की प्रतिशत मूल्यवृद्धि (+) मूल्यह्रास/(-) दर्शाते हैं।

विनिमय दर में केवल 2.5 प्रतिशत की गिरावट आई। हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमी होने के कारण विनिमय दर में समायोजन करने की आवश्यकता थी। इस संदर्भ में प्रत्येक को चाहिए कि वह विश्व बाजार में भारत के प्रतिस्पर्धी देशों की विनिमय दरों के व्यवहार को नोट करें।

तक भलावा, सभासनाओं तथा इस प्रकार की संभावनाओं से उत्पन्न आगामी बाजार व्यवहार को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में 1 जुलाई तथा 3 जुलाई 1991 की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य को निम्नगामी स्तर पर समायोजित किया गया, उपरिष्ठ रूप से, मध्यवर्ती मुद्रा अर्थात् पौंड-स्टर्लिंग के मुकाबले 17.38 प्रतिशत के समायोजन का अनुमान लगाया गया था। इस समायोजन से, हमारे निर्यातों के प्रतिस्पर्धी को बनाये रखने की आवश्यकता के अनुरूप रुपये को उचित स्तर पर रखा गया।

10.44 1990-91 के दौरान (अप्रैल-मार्च) रुपया-स्टर्लिंग दरों में 282 बार समायोजन किये गये जबकि 1989-90 की तदनुकूली अवधि के दौरान 252 बार समायोजन किये गये थे। अप्रैल-जून 1991 के दौरान ये समायोजन 91 प्रतिशत थे जबकि पिछले वर्ष की तदनुकूली अवधि में ये 55 प्रतिशत थे।

10.45 मार्च 1990 के अंत में तथा मार्च 1991 के अंत के बीच में सभी प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपये का मूल्यह्रास हुआ। जापानी येन की तुलना में यह मूल्यह्रास अत्यधिक (20.6 प्रतिशत) था, इसके पश्चात् पौंड स्टर्लिंग (17.0 प्रतिशत) अमरीकी डालर (11.8 प्रतिशत) और श्वैज़ मार्क (11.0 प्रतिशत) आदि आते हैं।

10.46 अप्रैल-जून 1991 के दौरान रुपये का मूल्यह्रास अमरीकी डालर के मुकाबले 6.6 प्रतिशत, जापानी येन के मुकाबले 8.7 प्रतिशत, श्वैज़ मार्क के मुकाबले 2.2 प्रतिशत तथा पौंड-स्टर्लिंग के मुकाबले 0.8 प्रतिशत हुआ। विशेष आह्वान अधिकारों के संदर्भ में रुपये का मूल्यह्रास मार्च 1990 के अंत में तथा मार्च 1991 के अंत के बीच बिन्दु बार 14.9 प्रतिशत और वर्ष 1990-91 के दौरान मासिक औसत आधार पर 16.3 प्रतिशत हुआ था (सारणी 10.13)। अप्रैल-जून 1991 के दौरान बिन्दु बार रुपये का मूल्यह्रास और बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया।

रुपया-रुबल विनिमय दर

10.47 ऋण और वाणिज्यिक बैंक-देशों के निपटान पर लागू रुपया रुबल विनिमय दर में वर्ष 1990-91 (अप्रैल-मार्च) के दौरान सात बार परिवर्तन किये गये अर्थात् 5 मई, 3 अगस्त, 3 तथा 24 मितम्बर 1990, 25 जनवरी, 11 फरवरी एवं 22 मार्च 1991 को। इसके परिणामस्वरूप रुपये का मूल्यह्रास 14.9 प्रतिशत पर मार्च 1990 के अंत के 19.92 रुपये प्रति रुबल से मार्च 1991 के अंत में 23.40

रुपये प्रति रुबल हो गया। 20 अप्रैल 1991 तथा 1 अप्रैल 1991 को दर में और आगे संशोधन के कारण रुपये का मूल्यह्रास प्रत्येक बार 3.0 प्रतिशत पर मार्च 1991 के अंत के 23.40 रुपये प्रति रुबल से 20 अप्रैल 1991 को 24.13 रुपये तथा 1 जून 1991 को 24.87 प्रति रुबल हो गया। बाद में, जुलाई 1991 में प्रमुख मुद्राओं के संदर्भ में रुपये की विनिमय दर में तीव्र समायोजन से रुपया-रुबल दर को भी 4 जुलाई 1991 को 26.73 रुपये प्रति रुबल करना पड़ा और 6 जुलाई 1991 को इसे 29.94 रुपये प्रति रुबल पर समायोजित किया गया। यह दर 17 अगस्त 1991 से और संशोधित करके 30.839 रुपये प्रति रुबल कर दी गई जिससे मार्च 1991 के अंत से रुबल की तुलना में भारतीय मुद्रा के मूल्यह्रास में 24.1 प्रतिशत की गिरावट आई।

अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक गतिविधियां

10.48 भारत के बाह्य भुगतान संकट, कुछ सीमा तक कठिन अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक परिदृश्य को प्रतिबिम्बित करता है। खाड़ी संकट से उत्पन्न तीसरी बार तेल के मूल्य में वृद्धि ने उसकी कीमत को काफी बढ़ा दिया और वर्ष 1990-91 में अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक आतावरण को प्रभावित करने वाली यह अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि थी। यह औद्योगिक और विकासशील देशों दोनों में वार्षिक विकास में मंदी की पहली से ही कठिन स्थिति पर और भार डालना था। इसके पहले तेल की कीमतों में दो बार वृद्धि की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित देशों द्वारा पहले ही ऊर्जा संबंधित समायोजनों ने विकासशील देशों की तुलना में अधिक आसानी से इस संकट को पार कर लिया और विकासशील देशों ने तेल से संबंधित अधिक आयात जिलों, निर्यातों तथा प्रेषणों के विघटन एवं खाड़ी क्षेत्र से वापस आ रहे श्रमिकों के पुनर्वास की मानवीय समस्याओं का सामना किया। विश्व वार्षिक व्यवस्था के विकास में 1989 के 3.3 प्रतिशत से 1990 में 2.1 प्रतिशत गिरावट आयी। औद्योगिक देशों की वृद्धि 1989 के 3.3 प्रतिशत से 1990 में 2.6 प्रतिशत घट गयी और विकासशील देशों की वृद्धि 3.1 प्रतिशत से घटकर 0.8 प्रतिशत रह गई।

10.49 अनुमान है कि विश्व व्यापार की मात्रा वर्ष 1990 में 4.6 प्रतिशत बढ़ी होगी जबकि 1989 में यह वृद्धि 7.2 प्रतिशत की थी इसका मुख्य कारण था उत्पादन वृद्धि में गिरावट तथा विशेषकर मीयादी निवेश की कमजोर वृद्धि। यह मांग का एक घटक है जो अमेका कृत व्यापार प्रधान है। औद्योगिक देशों की निर्यात मात्रा की वृद्धि 1989 के 6.8 प्रतिशत से 1990 में 5.9 प्रतिशत गिरावट आयी और आयात की मात्रा में 7.6 प्रतिशत से 6.0 प्रतिशत की विकासशील देशों के निर्यातों तथा आयातों दोनों में विकास की मात्रा में तीव्र गिरावट आयी, निर्यातों के संबंध में 1989 के 7.1 प्रतिशत से 1990 में 3.9 प्रतिशत और आयातों के संबंध में 8.3 प्रतिशत से 2.9 प्रतिशत की गिरावट आयी।

10.50 पूर्वी यूरोप तथा सोवियत संघ के आस्तिक सकल देशी उत्पाद में 1990 में लगभग 4 प्रतिशत की तीव्र गिरावट आयी और फिर 1991 में उसी सीमा तक गिरावट का अनुमान है। यह गिरावट देशी और बाह्य कारणों से आयी जिनमें वर्तमान आर्थिक प्रणाली के विघटन के परिणामस्वरूप हुए अव्यवस्था, मध्य पूर्वी की घटनाओं का प्रभाव, उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सख्त वित्तीय नीतियों के अन्वेषिक प्रभाव, पारस्परिक आर्थिक सहायता, परिषद के सदस्यों को भेजे जाने वाले निर्यातों में गिरावट और सोवियत संघ से और उसके भीतर तेल आपूर्तियों का विघटन आदि सम्मिलित हैं। प्रतिकूल वातावरण तथा समायोजन एवं संशोधन की लागतों में कमी पड़ जाने के बावजूद भी सभी पूर्वी यूरोपीय देशों ने मध्य उद्यारीकरण के उपायों की शुरुआत और मुद्रा परिवर्तनीयता तथा व्यापारिक सुधारों के संबंध में भी महत्वपूर्ण कदम उठाये। कुछ अभी भी नीतियां बनायी जा रही हैं, इसलिए इन सुधारों के प्रभाव, भारत जैसे अन्य देशों पर जिन्हें इनमें से कुछ देशों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार संबंध हैं, अभी भी सुस्पष्ट नहीं हैं।

10.51 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, जिनमें विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सम्मिलित हैं, ने पूर्वी यूरोपीय देशों को बाजार प्रधान सुधारों में सहयोग देने में अपनी तीव्र दिलचस्पी जाहिर की। यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसका उद्घाटन 15 अप्रैल 1991 को संदेन में किया गया था, ने अपने 30 प्रतिशत पूंजी को पूर्वी तथा मध्य यूरोप में द्विपक्षीय निवेश के लिए उद्घोषित किया है। यह आशा है कि बहुपक्षीय संस्थाएं पूर्वी यूरोप को प्रतिस्पर्धी सहायता उपलब्ध कराने के कार्य को सुनिश्चित करेंगी ताकि अन्य विकासशील देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति निधियों के अन्वेष निवेश के बिना हो जाए।

10.52 कोटे की नौवीं सामान्य समीक्षा के अंतर्गत 28 जून 1990 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल द्वारा सदस्यों के कोटे में वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। कुल निधि कोटा 50 प्रतिशत पर 90.1 बिलियन विशेष आहरण अधिकारों से 135.2 बिलियन विशेष आहरण अधिकार तक बढ़ेगा। यह वृद्धि करार नियमावली में तीसरे संशोधन पर सहमति प्राप्त करने के बाद लागू होगा। तीसरे संशोधन में उन सदस्यों के मतदान तथा संबद्ध अधिकारों को निर्लंबित करने की व्यवस्था है जो विनियमावली के अंतर्गत अपने बायिल्सों को पूरा नहीं करते।

10.53 भारत के कोटे में 2,207.7 मिलियन विशेष आहरण अधिकारों से 3,055.5 मिलियन विशेष आहरण अधिकार की वृद्धि होगी अर्थात् 38.4 प्रतिशत की वृद्धि जो आठवीं कोटा समीक्षा (28.5 प्रतिशत) की वृद्धि के कुछ अधिक है। फिर भी, कुल कोटा में भारत का अंश नौवीं समीक्षा के अंतर्गत 2.45 प्रतिशत से 2.26 प्रतिशत घट जायेगा। मतदान अधिकार के रूप में यह गिरावट 2.38 प्रतिशत से 2.22 प्रतिशत है।

10.54 मूलभूत मुद्दों पर सहमति के बिना ही दिसम्बर 1990 में बहुपक्षीय व्यापार वार्ता का उद्घाटन कर दिया गया। इस स्थगन का मुख्य कारण एक तरफ अमरीका के नेतृत्व के अधीन का चल और दूसरी तरफ यूरोपीय समुदाय के बीच कृषि में व्यापार के उद्यारीकरण पर परस्पर विरोधी विचार थे। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि देशी कृषि से संबंधित नीतियों के संबंध में विकासशील देशों पर किसी भी प्रकार के बंधन न लगाये जाएं। सेवाओं में व्यापार पर विकासशील देशों के लिए विशेष प्रबंध की व्यवस्था की आवश्यकता के संबंध में सभी विकासशील देश एकमत हैं। वार्ता में भारत के हित का एक पहलू है—जनशक्ति के निर्यात की संभावना। विकसित देश यह निर्णय ले रहे हैं कि केवल प्रबंधकीय कर्मचारीयों को हममें सम्मिलित किया जाए न कि कारीगर तथा अनियुक्त व्यक्तियों को। अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण को बनाने के लिए उद्घाटन की सफलता-पूर्वक समाप्ति की आवश्यकता है। इसकी विफलता से न केवल उद्यारी-

करण से प्राप्त भारी लाभों की उपलब्धि पर रोक लग जायेगी बल्कि संरक्षणवादी दबावों में और तेजी आयेगी। व्यापारिक साझेदारी के बीच भोजदा विवाद और बढ़ेंगे तथा व्यापार समस्याओं के द्विपक्षीय समाधान या क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों के माध्यम से समाधान को प्रोत्साहन मिलेगा इससे टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुशासन एवं अनुपक्षीयता से अत्यंत दूर जाना होगा।

#### 11 मूल्यांकन और संभावनाएं

11.1 बैंक की पिछले कई वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में उन असहनीय समष्टिगत आर्थिक असंतुलनों के पैदा होने की चेतावनी बनाया गया है जो बड़े बजट घाटों और भुगतान संतुलनों में आये बड़े चालू खाता घाटों में विस्फाड़ देते हैं। पहले ही कठिनाइयों से गुजर रही समष्टिगत आर्थिक स्थिति में खाड़ी संकट सबसे ऊपर रहा। अपरिहार्य रूप से इसका परिणाम हुआ विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि में भारी कमी, जिसकी वजह से 1990-91 के बाद के हिस्से में तथा 1991-92 के आरंभिक महीनों में अल्पकालिक आर्थिक संकट प्रबन्धन का सहारा लेना पड़ा ताकि सभी अंतर्राष्ट्रीय ऋण व भुगतान संबंधी दायित्वों के पूरा करने के मामले में भारत की जो बेबाग छवि है, वह सुनिश्चित तौर पर बनी रहे। इस अभूतपूर्व आर्थिक संकट के प्रति किये गये विशिष्ट नीतियुक्त उपायों का ब्योरा इस रिपोर्ट के शुरुआती हिस्सों में दिया गया है। अभी कुछ ही समय पूर्व, समष्टिगत आर्थिक स्थायीकरण और संरचनात्मक सुधारों की दिशा में किये गये विशिष्ट उपायों की श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में सरकार ने विनियम दर, विदेश व्यापार, राजकीय नीति, औद्योगिक नीति सार्वजनिक उद्यमों की भूमिका तथा बाह्य निवेश नीति से संबंधित आर्थिक नीति तंत्र की समुचित कार्यालय के लिए आरंभिक कदम उठाये जूलाई और अगस्त 1991 के दौरान पहले ही शुरू किये जा चुके सुधारात्मक उपायों का विस्तृत खाका भी इस रिपोर्ट के संबंधित परिच्छेदों में दिया गया है। इस परिच्छेद में उन उपायों के सवर्णों का मूल्यांकन प्रस्तुत है। इसमें ऐसे कुछ अनुवर्ती उपायों और साधनानियों की रूपरेखा भी दी गई है जिनकी यह सुनिश्चित किये जाने के लिए आवश्यकता है कि भारत का स्थायीकरण कार्यक्रम और इसके संरचनात्मक सुधार के उपाय, जिन्हें पूर्ण वेग और दायरे के साथ शुरू किया जा चुका है, वास्तव में अभीष्ट परिणाम प्राप्त करेंगे।

#### बाह्य क्षेत्र के निर्गम

11.2 भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू, जो पिछले कुछ समय से एक बड़ी चिन्ता का कारण रहा है, भुगतान संतुलन की स्थिति से संबंधित है। इसने राष्ट्र के आर्थिक कार्यक्रम के निर्धारण को प्रभावित किया है। सातवीं योजना का दौर भारत के चालू खाता घाटे के बढ़ते अन्तर का साक्षी है। चालू खाता घाटे और सकल देशी उत्पाद का 1985-90 की अवधि के दौरान अनुपात औसतन 2.2 प्रतिशत रहा जो सातवीं योजना प्रलेख में इस अवधि के लिए आंकड़े 1.6 प्रतिशत के आंकड़े से कहीं अधिक था। निर्यातों में हुई एक तगड़ी बढ़ोतरी की बावजूद चालू खाता घाटे में वृद्धि इसलिए हुई कि आयातों में वृद्धि के साथ साथ नियत अदृश्य प्राप्ति में निरन्तर गिरावट आती चली गयी। चालू खाता घाटे के वित्तपोषण का कुंघ भी समय के साथ-साथ बदलता गया क्योंकि भारत को मिलने वाली रियायती सहायता में कमी आ गयी और कुल विदेशी सहायता में रियायती सहायता का अनुपात कम से कमतर होता चला गया। रिजर्व बैंक की पिछली वार्षिक रिपोर्टों में हमारे भुगतान संतुलनों की स्थिति के संबंध में अनुभव की गई कठिनाइयों के विभिन्न कारणों पर विस्तार से चर्चा की जाती रही है। भुगतान संतुलन की पहले से कठिन चली आ रही स्थिति 1990-91 में तेल के मूल्य में तीव्र तेजी तथा खाड़ीयुद्ध के अन्य प्रभावों के कारण और गड़बड़ गयी। वर्ष 1990-91 के दौरान पेट्रोलियम, तेल और चिकनाई के पदार्थों के उत्पादों की लागत 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गयी। 1990-91 में 5.9 बिलियन अमरीकी डॉलर के व्यापारिक घाटे में से 5.4 बिलियन अमरीकी डॉलर (अथवा 90 प्रतिशत से भी अधिक) का घाटा तेल और पेट्रोलियम के उत्पादों के कारण था। निर्यातों की जो परिमाणिक वृद्धि

1986-87 से 1989-90 के दौरान औसतन 10 प्रतिशत वार्षिक के लगभग थी, वह भी संशतः पूर्वी यूरोप की लक्ष्यकारी आर्थिक परिस्थितियों और मध्य पूर्व की समस्याओं के कारण बहुत नीचे आ गयी। वाणिज्यिक ऋण की उपलब्धता भी कठिन हो गयी क्योंकि विदेशी ऋणदाताओं का भारतीय शासनप्रणाली और अर्थव्यवस्था के प्रति कुछ ऐसा-वैसा ही नजरिया और सबसे ऊपर यह कि बृहत्तर अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सामान्य आर्थिक तंगी के बारे में गुजर रहे थे। इस सबके परिणामस्वरूप 1990-91 के दौरान, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का स्तर, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 2.4 बिलियन अमरीकी डालर से गिर कर मार्च 1991 के अंत तक 2.2 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। प्रारंभित निधियों में गिरावट के पीछे कारण और परिणाम दोनों एक ही थे और यह था वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अतिवासी खाते में आभ्रम में कमी हो जाना और साथ ही, विदेश स्थित भारतीय बैंकों को अल्पकालीन ऋण का नवीकरण करने में सामान्य बैंकिंग चैनलों की अक्षमता। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं में पुनः तेजी से एक और गिरावट आयी और ये आवश्यकता अप्रैल 1991 के अंत तक आते-आते 1.2 बिलियन अमरीकी डालर के तात्कालिक स्तर पर रह गयीं तथा प्रारंभित निधियों में और कमी को तत्काल रोकना आवश्यक हो गया। जहाँ हमें अज्ञात है कि 1991-92 में चालू खाता घाटे में परिणत कमी 1989-90 या 1988-89 के स्तरों तक की हो रहेगी, वहाँ चिन्ता का विषय यह है कि वित्तपोषण की आवश्यकता इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद, संसाधनों की व्यवस्था सामान्य आगमनों से करना कठिन है। वित्तपोषण के कुछ साधनों, अधिक विशेषतः अल्पावधि और मध्यावधि दोनों ही प्रकार के वाणिज्यिक ऋणों की उपलब्धता के न रहने से, आयातों में भारी कटौती सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करना आवश्यक हो गया था ताकि विदेशों के प्रति भारत के सभी वित्तीय दायित्वों की अचनकता की बिना किसी चूक के पूरा किया जा सके। साथ ही, द्विपक्षीय खाताद्वय के ऋणदाताओं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से विशिष्ट वित्तपोषण का माग भी करना पड़ी। स्वयं के लेन-देन से भी पूरक वित्त जुटाया गया।

11.3 आयात वृद्धि पर नियंत्रण रखने के इस प्रयास में, मौद्रिक एवं ऋण नीति को अपनी सामान्य से अधिक जिम्मेदारी निभाना पड़ा। यद्यपि, मेट्रिक ताल ग्राम तौर पर मुद्रा आपूर्ति की, हालांकि प्रवृत्तियों, मूल्यों और उत्पादन की पृष्ठभूमि में तैयार की जाती है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में मौद्रिक नीति निर्देश पूर्णतः एक संकटमय भुगतान संतुलन की स्थिति की पृष्ठभूमि में तैयार किये गये हैं। वर्ष 1990-91 में मुद्रा विस्तार में कुछ कमी आयी, किन्तु निश्चित रूप से यह वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा की प्रारंभित निधियों में अद्वितीय द्वारा लायी गयी कमी का परिणाम था। तथापि, मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई जिसका प्राथमिक रूप से कारण तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी था। जैसा कि बैंक की पिछली रिपोर्टों में कहा गया है, किमी वर्ष-विशेष में, मूल्यों में हुई वृद्धि को केवल उस वर्ष में हुई मुद्रा आपूर्ति में परिवर्तन से सम्बद्ध करना ठीक न होगा। प्रणाली में आने वाले विभिन्न अवरोधों के कारण ये कुछ ऐसे संबंध हैं जो कुछ ही समय तक टिके रहते हैं। वर्ष 1991-92 में सकल वैश्व उत्पाद की वृद्धि की रफ्तार में संभावित कमी तथा मुद्रा स्थिति की वर को संयत रखे जाने की आवश्यकता के अनुरूप, मुद्रा नीति का रुख, हर हाल में, प्रतिबन्धनात्मक होगा, और भुगतान संतुलनों की स्थिति के कारण तो यह और भी बाध्यकर हो जाता है। अप्रैल 12, 1991 को वर्ष की पहली छमाही के लिए घोषित ऋण नीति में तीन वर्ष अथवा अधिक समय के बाद अर्ध-पूर्ण होने वाली बैंक जमाओं पर व्याज की दर एक प्रतिशत अंक से बढ़ाकर ऐतिहासिक रूप से 12 प्रतिशत के ऊंचे स्तर तक कर दी गई थी और साथ-ही-साथ बड़े उद्यार्कताओं के लिए न्यूनतम उधार दर भी एक प्रतिशत अंक बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दी गयी थी। वृद्धिशील खाद्योत्पन्न ऋण-जमा अनुपात निर्यातों को छोड़कर, 45 प्रतिशत पर सुनिश्चित कर दिया गया था। बाद में, 15 प्रतिशत के

औसत अनुपात के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का वृद्धिशील नकदी रिजर्व अनुपात भी लागू कर दिया गया। बड़े उद्यार्कताओं द्वारा वर्ष की पहली छमाही के दौरान निकाली जा सकने वाली राशि की भी एक सीमा तय कर दी गई। इन उपायों के साथ-साथ कुछ ऐसे अन्य कदम भी उठाए गये जिनका सीधा लक्ष्य आयात पर नियंत्रण और निर्यात का संवर्धन था। कुछ श्रेणियों के आयातों में संबंध में नकदी माजिन किये गये। ये माजिन अब 50 से 200 प्रतिशत के बीच हैं, तथापि, निर्यात से सम्बद्ध आयातों के प्रति रियायत बरती गयी है तथा ऐसे आयातों पर सामान्यतः नकदी माजिनों से छूट दी गई है। आयात वित्त की लागत में 25 प्रतिशत व्याज दर अभिभार लगाकर वृद्धि की गई जबकि पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण का 90 दिन से अधिक के व्याज की दरों में भी पर्याप्त वृद्धि कर दी गई ताकि निर्यात धूमनों में तेजी आ सके। यहाँ तक कि सशत मुद्रा नियंत्रण लगाते हुए इस बात के प्रति सावधानी बरती गई है कि निर्यात संबंधी प्रयासों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यही दजह है कि नकदी माजिन लगाये जाने के मामले में निर्यातों से सम्बद्ध आयातों पर से सामान्यतः प्रतिबंध हटा लिया गया है। यहाँ तक कि समग्र ऋण उपायों के संबंध में निर्यातों के मामले में छूट की व्यवस्था की गई है। वृद्धिशील खाद्योत्पन्न ऋण जमा अनुपात पर प्रतिबंध की गणना भी अब निर्यात ऋण घटा कर की जाती है।

11.4 कुल मिलाकर इन उपायों को मोटेतौर पर दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। उपायों का एक कड़ी का भीधा लक्ष्य है आयात पर नियंत्रण। एक ऐसे समय जबकि भुगतान संतुलनों की स्थिति कठिन बनी हुई है, ऐसे उपायों की आवश्यकता संभवतः सर्वमान्य ही कही जायेगी जहाँ निर्यातों के लिए आयातों को एक विनिष्ट वर्जा प्राप्त है इन उपायों का बिल्कुल स्पष्ट हरादा है आयातों को निरस्त/सहित करना। नकदी माजिन और आयात वित्त पर ऊँची व्याज दरें जैसे उपायों के लागू किये जाने को आयात नियंत्रण का भेदभाव रहित रास्ता माना जाता है। उपायों की दूसरी कड़ी प्रतिबंधक मुद्रा नीति से जुड़ी है जिसका लक्ष्य भुगतान संतुलनों में चालू खाता घाटे को नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता को पूरा करना है। शायद, कभी-कभी ऐसी किसी नीति की जरूरत को पूरी तरह समझा ही नहीं जाता है। चालू खाता घाटे का अभिप्राय है वस्तुओं और सेवाओं के आयात की मात्रा की तुलना में वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का अधिक होना, और इस चालू खाता घाटे का अर्थ है कि अमूक देश उत्पादन की तुलना में खर्च अधिक कर रहा है। अतः आद के एक निश्चित स्तर पर यदि अस्तित्व को कम नहीं किया जाता है, अर्थात् खर्चों को नीचे नहीं लाया जाता है तो भुगतान संतुलन के घाटों को भी कम किया जाना संभव नहीं है। अस्तित्व को कम करने का अर्थ अतिवर्धित व्यवस्था में समग्र मौद्रिक मांग को कम करना है। तथापि, समग्र मौद्रिक मांग को कम किये जाने का आशय जलदबाजी में यह नहीं निकालना चाहिए कि भुगतान संतुलनों की स्थिति में सुधार आ गया। इसे व्यवस्था की बहुत सी कड़ियों से जोड़कर चलना होगा तथा साथ में से सीमांत निर्यात प्रवृत्ति जैसे परिणामों पर निर्भर करेगा। कुछ हद तक कुल व्यय का नियंत्रित करने के लक्ष्य वाले उपायों का प्रभाव उत्पादन पर पड़ सकता है। जहाँ प्रभाव यही करने चाहिए कि ऐसे प्रतिकूल प्रभाव कम-से-कम हों, कुल मिलाकर खर्चों पर नियंत्रण का बाध्यता से तब तक नहीं बचा जा सकता जब तक भुगतान संतुलनों की स्थिति और सुदृढ़ स्तर पर नहीं आ जाता।

11.5 रिपोर्ट के पिछले परिच्छेदों में चर्चित कारणी के फलस्वरूप, 1991 में निर्यातों में वृद्धि की दर में तेजी से कमी आयी जबकि आयातों पर दबावों में बढ़ोतरी हुई। आने वाले दो वर्षों में आशा का जा सकता है कि निर्यात वृद्धि की दर एक बार फिर पिछले 3-4 वर्षों के दौरान प्राप्त स्तरों तक पहुँच जाए, जबकि आयातों में वृद्धि को पर्याप्त करना ही होगा। विनियम दर समायोजनों, व्यापार नाति एवं औद्योगिक नीति में सुधार तथा राजकीय घाटे का भुगतान संतुलनों पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा। उस हद तक, जहाँ तक ये उपाय अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ेंगे,



मध्यवर्धि सक्षय यह है हो सकता है कि चालू खाता घाटे में सकल देशी उत्पाद के एक समनुपात के रूप में 1990-91 के अनुमानित 2.5 प्रतिशत से 1992-93 में 1.8 प्रतिशत और उसके बाद 1994-95 में 1.5 प्रतिशत की कमी लायी जाए। इस मध्यवर्धि समायोजन के फलस्वरूप, चालू खाता घाटा सुदृढ़ अवस्था में आ जाएगा क्योंकि तब इसका वित्तपोषण सामान्य पूंजीगत आगमनों से होगा, जिनमें बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता, एक उचित स्तर तक बाह्य आणव्ययिक उधार तथा ईकविटी जैसे ऋण-अनुत्पादक साधन शामिल हैं। जाहिर है, एक लम्बे अन्तराल के बाद, आयातों की तुलना में निर्यात वृद्धि की दर जब इतनी तेज हो कि आय अधिक हो जाए, केवल तब ही इन ऋणों का चुका पाना संभव हो सकेगा और अर्थ व्यवस्था में वृद्धि की दर उच्चतर हो सकेगी।

#### स्थिरीकरण के उपाय

11.6 जुलाई 1991 के आरम्भ में प्राधिकारियों ने स्थिरीकरण के उपायों के एक संश्लिष्ट पैकेज की शुरुआत की। नीति का एक अंग यह था कि बाह्य भुगतान असंतुलनों को दूर करने के लिए रुपये का विनिमय दर जुलाई 1 और जुलाई 3 को दो बार कमी कर समायोजन किया गया। अमरीकी डालर के रूप में संचयी निम्नोन्मुखी समायोजन 18 प्रतिशत से कुछ ही कम था। चालू खाता घाटे का उन स्तरों तक सही किया जाना अपेक्षाकृत हो गया है जो सामान्य पूंजी आगमनों से ठीक किये जा सकते हैं। रुपये की विनिमय दर में निम्नोन्मुखी समायोजन ऐसे अन्य उपकरणों के साथ-साथ एक ऐसा उपकरण है जो इस कमी को दूर करने के लिए आवश्यक है। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि का निरन्तर क्षय एक ऐसी स्थिति है जो बाजार अपेक्षाओं के उखड़ने की प्रक्रिया को जन्म देती है। तात्कालिक कुछ समय के दौरान विनिमय दर के समायोजन से बाजार अपेक्षाओं को उलटने में मदद मिल सकती है और इस प्रकार पहले चरण में पूंजी के निर्गम में गतिरोध पैदा होगा, किन्तु बाह्य में आगम को बढ़ावा मिलेगा। अल्पकालिक और मध्यकालिक रूप में निम्नोन्मुखी समायोजन के फलस्वरूप देश की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में भी सुधार होगा और इस प्रकार व्यापार और चालू खाता घाटे में असंतुलन को सही करने में मदद मिलेगी। रुपये के विनिमय मूल्य में समायोजन से विक्रय वस्तुओं और अविशेष्य (अथवा स्वदेशी) वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य बढ़ जाते हैं (विदेशी मुद्रा का देशी मूल्य बढ़ाकर) और इस प्रकार व्यापार योग्य वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है जबकि उनके उपभोग के प्रति निरुत्साह पैदा होता है।

11.7 किसी भी मुद्रा की वास्तविक विनिमय दर अमुक देश में मूल्यों में हुए सापेक्ष परिवर्तन की सांकेतिक विनिमय दर होती है, यह दर विश्व बाजारों में उस देश की प्रतियोगितात्मकता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा अग्र्यत्र कहा जा चुका है, अभी हाल ही कुछ अवधि में रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि होने लगी थी। वस्तुतः जहाँ हमारे 20 कारोबारी प्रतियोगियों का सम्बन्ध है, रुपये की प्रभावी विनिमय दर एक लम्बे समय तक बढ़ती रही। 1979-1986 के बीच तो 20 प्रतिशत तक। वर्ष 1987 से इन देशों की मुद्रा की तुलना में वास्तविक दृष्टि से रुपये का अवमूल्यन हुआ है और वर्ष 1989 तक भारत 1989 की वास्तविक विनिमय दर के बराबर हो गया। इसकी तुलना में, भारत के कई कारोबारी प्रतियोगियों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान विनिमय दरों में बड़े समायोजन किये। उदाहरण के लिए, चीन और होंगकॉन्ग ने भारत की तुलना में 1980 के दिसम्बर-अन्त से लेकर 1989 के दिसम्बर-अन्त की अवधि के दौरान, निम्नस्तरीय मुद्रा-स्कीति के बावजूद, अमरीकी डालर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। जहाँ अमरीकी डालर के मुकाबले चीन ने 68 प्रतिशत और होंगकॉन्ग ने 65 प्रतिशत अवमूल्यन किया, वहीं भारत ने केवल 53 प्रतिशत अवमूल्यन ही किया जबकि चीन और होंगकॉन्ग में उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि निम्नस्तर पर थी क्रमशः 100 प्रतिशत एवं 111 प्रतिशत और उसी अवधि के दौरान भारत में उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि 114

प्रतिशत थी। हमारे निर्यातों में प्रतियोगितात्मकता को बहाल करने और सामान्यतः व्यापार और चालू खाता घाटों में कमी लाने के लिए रुपये का निम्नोन्मुखी समायोजन अनिवार्य हो गया था। समायोजन की सीमा निश्चित किये जाने के लिए, चार सम्बन्ध बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है:

- (1) भारत और बड़े औद्योगिक देशों के बीच मूल्य-स्तरों की विभेदकता,
- (2) भारत से प्रतियोगिता रखने वाले देशों की मुद्राओं के वास्तविक मूल्यहास की सीमा,
- (3) हमारे भुगतान संतुलनों में अपेक्षित सुधारों की मात्रा, और
- (4) बाजार अपेक्षाएं।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, रुपये के मूल्य में 18-19 प्रतिशत का मूल्यहास उपयुक्त प्रतीत होता है।

11.8 आने वाले कुछ समय के दौरान, विनिमय दर में समायोजन से बकाया निर्यात प्राप्ति की वधूली में सुविधा होगी और अस्थिर होती बाजार अपेक्षाओं को दबाते हुए मुद्रा-प्रेषण के आगमनों में सामान्यतः वृद्धि होगी। समय बीतने के साथ-साथ, निर्यात में वृद्धि लाकर और आयात में वृद्धि को दबाकर व्यापार-संतुलन की स्थिति सुधरेगी। विनिमय दर के समायोजन के साथ-साथ कुछ पूरक नीतियाँ भी तैयार किया जाना आवश्यक है जिससे उत्पादन में विस्तार होगा, विमोचन: निर्यातों के लिए और वास्तव में किया भी यही गया है।

11.9 सही अर्थों में कारगर होने के लिए, मुद्रा के मूल्यहास हेतु यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि घरेलू कीमतें मूल्यहास द्वारा प्रदान किए गए मूल्य लाभ को समाप्त कर बढ़ न जाएं। विनिमय दर समायोजन के कारण, मुद्रा नीति संबंधी उपाय और कड़े कर दिए गए, अर्थात् इसके साथ-साथ बैंक दर, सीमादी जमा दरों और बड़े ऋणकर्ताओं की उधार दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई और रिजर्व बैंक पुनर्वित्त दरों में उचित वृद्धि की गयी। हाल ही में उठाये गये प्रतिबन्धात्मक मुद्रा संबंधी नीतिगत उपायों से मुद्रा-स्कीति को नियंत्रित करने के लिए पहले के मुद्रा संबंधी नीतिगत उपायों को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी और इससे बैंक और संसाधन जुटा सकेंगे, ऋण की मांग के दबाव को कम कर सकेंगे तथा बाजार में निर्मित मुद्रा पर निर्भरता कम कर सकेंगे। इन उपायों से और अधिक वित्तीय अनुशासन, उत्पादन में सुधार तथा स्टाक जमा करने को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी। इस प्रकार, विदेशी भुगतानों के असंतुलन को शीघ्र ठीक करने के लिए उठाये गये विनियमों दर संबंधी नीतिगत उपायों को इन उपायों से सहायता मिलेगी। एक ओर जहाँ स्थिरीकरण उपायों के पैकेज का प्रभाव विदेशी मुद्रा भण्डार पर कुछ समय बाद पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर वर्तमान चल-निधि जरूरतों को ठीक करने की आवश्यकता होगी और विदेशी मुद्रा भण्डार में और वृद्धि करनी पड़ेगी तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 बिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी सहायता आवश्यक होगी। यही कारण है कि अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के साथ एक कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है ताकि निकट भविष्य में अनुसूचित ऋणवत्ता के बिना ही सुधार लाने में अर्थव्यवस्था सक्षम हो सके।

11.10 व्यापार नीति—फलक पर एक बड़ी युक्तिसंगत व्यवस्था शुरू की गयी है जिसके अन्तर्गत निर्यात संबंधी उपदान समाप्त कर दिय गये हैं और इसके स्थान पर आयात पुनःपूर्ति और पात्रता संबंधी एक विस्तृत योजना शुरू की है जिसमें निर्यात की आय के आधार पर 30 प्रतिशत की एकसमान दर लागू होगी। उच्चतर योजित मूल्य और अन्य उत्पादों के लिए 40 प्रतिशत निर्यात-आयात स्क्रिप पात्रताओं एवं निर्यात-आयात की मदों के विकेंद्रीकरण से उक्त व्यापार व्यवस्था को और अधिक उदारीकृत बनाया गया। ये विशिष्ट कदम हैं जिनसे मात्रा संबंधी प्रतिबन्धों से दूर रहा जा सकेगा। नयी औद्योगिक नीति में, औद्योगिक

लाइसेंसकरण बाह्य प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रौद्योगिकी करार, सार्वजनिक क्षेत्र की नीति और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की एक शृंखला है। इस नीति में बुनियादी तौर पर उद्योगों को उन नियन्त्रणों से मुक्त कराने पर बल दिया गया है जो व्यापारिक सिद्धान्तों पर नियंत्रण लिये जाने में बाधा डालते हैं तथा इस पर बल दिया गया है कि उद्यमियों को उनके अपने वाणिज्यिक फैसलों के आधार पर निवेश संबंधी निर्णय लेने दिया जाए।

11.11 सातवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के साथ ही नवें दशक के मध्य से शुरू किये गये प्रक्रिया संबंधी और नीति संबंधी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, व्यापार और उद्योग नीति-बोनों क्षेत्रों में नये उपायों में भारी अंतर आया है। इसमें विनियमों और नियंत्रणों में प्रणाली को मुक्त कर दिया गया है और उद्यमियों को उनके उत्पादन प्रयत्नों में हस्तानुसार कार्य करने की छूट दी गई है। इस प्रकार, बिपय वस्तु और महत्व दोनों ही दृष्टियों से नये प्रोत्साहन मही भायने में बहुत दूरगामी उपाय है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का उद्देश्य यह है कि तकनीकी प्रंतरण, विपणन विशेषज्ञता, अद्यतन प्रबंधकीय तकनीकी तथा गृहह निर्मित संभावनाओं का विद्यमान लाभ देश को मिल सके। विदेशी निवेश के संबंध में किये गये संशोधनों को पूंजी के एक स्थान से दूसरे स्थान में निवेश के कारण हुए उल्लेखनीय विश्वव्यापी परिवर्तनों के संबंध में देखना होगा। चूंकि विस्तार से संबंधित अड़चनें दूर की जा रही हैं, इसलिए संक्रमण की समस्या निश्चित रूप से खड़ी होगी। किन्तु, भारतीय उद्योग को देश और विदेश दोनों में ही प्रतिस्पर्धी वातावरण में रहने की आदत डालनी चाहिए।

#### राजकोषीय शोधन और मौद्रिक नीति

11.12 राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में भारतीय परिस्थिति में बहुत निकटता है। प्रारंभिक निधि में विस्तार और परिणामतः मुद्रा आपूर्ति में विस्तार के पीछे एक बड़ा कारण है सरकार को रिजर्व बैंक द्वारा दिया निवल ऋण। जब तक बजट घाटा बढ़ा बना रहेगा, मुद्रा प्रसार पर नियन्त्रण के प्रति रिजर्व बैंक की मायम सीमित बनी रहेगी। अधिक से अधिक रिजर्व बैंक इतना कर सकता है कि वह नकदी रिजर्व बैंक की अपेक्षा में परिवर्तनों जैसे माध्यम के सहारे गौण विस्तार को हथबंदी कर दे। यही वजह है कि मुद्रा प्रणाली के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित समिति ने मुद्रा-निश्चयधन की एक ऐसी प्रणाली की सिफारिश की है जो सरकार और रिजर्व बैंक दोनों को मौद्रिक विस्तार के ऐसे वांछित लक्ष्यों से जोड़ सकती है जो वास्तविक उत्पादन में वृद्धि और मूल्यों में वृद्धि के स्वीकार्य क्रम के अनुरूप हों।

11.13 भारत की राजकोषीय प्रणाली में बड़े बजट घाटे और अधिक विशेषतः बड़े राजस्व घाटे यहाँ की अपनी खासियत बन चुके हैं। कर्ज पर निर्भरता के कारण ऋण का बोझ तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसके साथ-साथ बढ़ते ब्याज का बोझ भी है। जैसे-जैसे राजस्व प्राप्तियों में से निवल ब्याज अवधायी का अनुपात बढ़ता चला जाता है, उतना ही चालू राजस्व में से पूंजीगत व्यय सहित अन्य खर्चों के लिए कम पड़ता है। भुगतान संतुलनों की बिगड़ती स्थिति के संबंध में राजकोषीय घाटे को कम किया जाना आवश्यक हो गया है। जुलाई 24, 1991 को प्रस्तुत केन्द्र सरकार के 1991-92 के बजट में राजकोषीय समायोजन और समष्टिगत आर्थिक स्थायीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत के गंभीर प्रयास किये गये हैं। समष्टिगत आर्थिक असंतुलन के शोधन की विधा में 1990-91 के 43,331 करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद का 8.5 प्रतिशत) के सकल राजकोषीय घाटे को कम करके 1991-92 में 37,727 करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद का 6.5 प्रतिशत) पर ले आना एक बड़ा योगदान होगा। इसी के समान और वस्तुतः और महत्वपूर्ण बात यह है कि 1990-91 के 10,772 करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद का 2.1 प्रतिशत) के परम्परागत घाटे को कम करके 7,719 करोड़ रुपये (सकल देशी उत्पाद का 1.3 प्रतिशत) पर ले आने से मुद्रा

आपूर्ति की वृद्धि को हल्का करने में मदद मिलेगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि राजस्व और व्यय पर उचित नियंत्रण के माध्यम से घाटा बजट स्तरों के बीच ही रहे। हाल ही के वर्षों में एक बार-बार देखने में आयी है कि वास्तविक घाटे के बजट अनुमानित घाटों से कहीं अधिक थे। राजस्व में किसी भी सीमा तक होनेवाली कमी को व्यय में कमियाँ करके तथा संसाधन जुटाकर दोनों में उचित तालमेल करते हुए पूरा किया जाएगा।

#### वित्तीय क्षेत्र के निर्गम

11.14 हाल के वर्षों में, भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक बड़ा विकास और परिवर्तन देखने में आया है। वित्तीय बाजार का नीचे से ऊपर की ओर जाने का एक अटूट मिलसिला कायम है, बैंकिंग उद्योग में क्रमिक उदारीकरण की एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है ताकि इस उद्योग के कार्य-कलापों में और सजीलापन आ सके। ऋण दिये जाने की प्रणाली में ब्याज दर के विनियमों में ढील दी गयी है और कार्यप्रणाली के अवरोधों को सुगम बनाया गया है। तथापि, बैंकिंग प्रणाली की वेयताओं और आस्तियों के संबंध में कई बाधाओं से होकर गुजरना है, क्षेत्र-विशेष को रियायती ब्याज-दरों पर उधार देना और प्रारंभिक निधि की अपेक्षाओं के अन्तर्गत बड़े पूर्वाधिकारों ने बैंकिंग प्रणाली की लाभकारिता पर भारी दबाव डाला है। बैंक लाभकारिता की राह में आयी कुछ नीतिगत बाधाओं को कुछ हद तक उधार की ब्याज दरों को पर्याप्त मुक्तिसंगत बनाकर तथा सेवा प्रभारों में संशोधन द्वारा दूर कर दिया गया है।

11.15 हालांकि, दृष्टि औद्योगिक इकाइयों की बड़ी और बढ़ती हुई संख्या के कारण बैंकिंग प्रणाली की लाभप्रवता वक्राव में बनी रही। वसूली की समयबद्धता महत्वपूर्ण है। बैंक के ढावों को लागू करने के लिए अदालती मुकदमों को निपटाने में कई वर्ष लग जाते हैं। बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बड़े-बड़े ढावों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना इस समस्या को व्यापक रूप से कम कर देगी। इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। प्राथमिकता क्षेत्र को दी गई निधियों को पुनः प्रयुक्त करने की भी गम्भीर समस्या है। अभी हाल ही की अवधि में यह समस्या कृषि और ग्रामीण ऋण राहत स्कीम द्वारा और बढ़ गई है, जिसमें विशिष्ट मापदण्डों के अनुसार उत्पादन और निवेश ऋण दोनों ही के अन्तर्गत बकाया राशियों में छूट दी जाती है, इससे बकाया राशि को वसूलने की सामान्य परिस्थितियों पर गम्भीर आघात पहुँचा है। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए जाँची-परखी क्रियाविधियाँ हैं, सभी स्तर पर ऋण और/या ब्याज में छूट से ऋण-अनुशासन गम्भीर रूप से क्षीण हो गया है। हाल ही में यह अनुभव वसूली के सम्भाव्य ठहराव और इसी के परिणामस्वरूप उधार देने में ठहराव की प्रवृत्ति का रहा है। ऐसी स्थिति और कुछ नहीं करेगी बल्कि वित्तीय प्रणाली को असाध्य नुकसान पहुँचाएगी, विशेषकर कृषि और ग्रामीण ऋण की आवश्यकताओं को यथासंभव पूरा करने के सम्बन्ध में। इसलिए, यह आवश्यक है कि ग्रामीण ऋण प्रणाली में साप्ताह्यता लाने के लिए कदम उठा जाएँ।

11.16 बैंकिंग परिचालनों को नमस्त दबता में सुधार लाने के उद्देश्य से बहु-आयामी कार्रवाई कार्यक्रम विकसित किए गए हैं और व्यवहार में लाए जा रहे हैं। प्रथम, देश के विभिन्न भागों में बैंक शाखाओं का बहुत कुछ व्यापक और पर्याप्त नेटवर्क तैयार कर लेने के पश्चात् बैंकिंग उद्योग समेकन की अवधि में प्रवेश कर चुका है और भावी शाखा प्रसार की अनुमति वहीं दी जाएगी जहाँ आवश्यकता और व्यापार श्रमता और प्रस्तावित कार्यालयों की वित्तीय सक्षमता सुस्पष्ट रूप से स्थापित हो जाएगी। दूसरे, बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है। तीसरे, खातों और परिचालनों में अधिकाधिक सुस्पष्टता के लिए बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची में संशोधन किया जा रहा है। यद्यपि, बैंकों के तुल्य पत्र और लाभ-हानि खाते के परिणामित प्राकृतिकों को जमा लागू किया जाना है। बैंकों को सूचित किया गया है कि ये 31 मार्च 1991 को समाप्त लेखा वर्ष और इसके पश्चात् अपने वित्तीय विवरणों

में परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बन्धित लेखा नीतियों को स्पष्ट करें। चौथे, बैंकों को सूचित किया गया है कि ऐसा व्याज, जिसके बसूले जाने की सम्भावना नहीं है, को शामिल करके धाय को बढ़ाना छोड़कर विवेकी लेखा विधियाँ अपनाएँ। अंतः, जोखिम प्रबंधन के लिए विवेक-सम्पन्न मापदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने भ्रम-भ्रम व्यापार संस्थान को सम्बन्ध में बैंक की पूँजी निधि के 25 प्रतिशत और किसी समूह के व्यापार संस्थान को सम्बन्ध में 50 प्रतिशत की शून्य सीमा निर्धारित की है। इसमें वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित सीमाएँ शामिल हैं, यद्यपि, इनसे जुड़े भार भ्रम-भ्रम हैं। बैंकों की ईक्विटी जब उनके ग्राहकों के उधार के लिए अनुरोधों के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से न्यून होती है तो इन अनुपातों को लागू किये जाने से उठे मुद्दों पर बैंक को पूँजी में वृद्धि के व्यापक प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में ध्यान दिया जाता है।

11.17 एकमुश्त वित्त व्यवस्था स्कीमों वाले म्युचुअल फंडों जैसी नई संस्थाओं के प्रादुर्भाव और प्रलाभकारी स्टाफ की कृपा से बैंकों के लिए गम्भीर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। यद्यपि, वित्तीय संरचना की प्रगति की विधा परिवर्तन और कुछ मध्यस्थीकरण समाप्त करने की आवश्यकता अपरिहार्य होगी। अनिवार्य प्रश्न यह है कि क्या बैंकिंग परिवर्तनों को विषय कार्य क्षेत्र की स्थिति का सामना करते रहना पड़ेगा या एक समान कार्य क्षेत्र की स्थितियाँ मूल्य की जाएंगी। वित्तीय प्रणाली में बैंकिंग प्रणाली अभी भी प्रमुख घटक है और वित्तीय बचतों का सब प्रमुख भाग यथासंभव बैंकिंग उद्योग द्वारा ही एकत्र किया जाता है और वास्तव में कोई भी संस्थागत प्रणाली भारत में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के बड़े नेटवर्क और सेवाओं के व्यापक क्षेत्र के साथ टक्कर नहीं ले सकती। मुद्दा यह नहीं है कि अन्य नवीनतर संस्थाओं को अनुमति दी नहीं दी जानी चाहिए बल्कि यह है कि बैंकिंग प्रणाली की दक्षता और मक्षमता को उन्नत करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता होगी। बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों की तुलनात्मक स्थिति की समीक्षा और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों को औचित्यपूर्ण बनाने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य से विभिन्न नियमक प्राधिकरणों की भूमिका को सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाता है। यद्यपि, पटुच में रहने वाले परिवर्तन श्रेयस्कर सिद्धांत हैं, तो भी व्यवहार में बैंकों और उनकी सहायक संस्थाओं के परिवर्तन आपस में गुंथे हुए हैं और इसलिए समूचे विषय में स्मैकिंग पर्यवेक्षण की आवश्यकता को अती-धार्ति मान्यता-प्राप्त है। इसी प्रकार, तेजी से बढ़ रही वित्तीय कंपनियों (पट्टाकारी और किराया खरीद कंपनियों) ऋण और निवेश कंपनियों, इत्यादि) का पर्यवेक्षण भी सुदृढ़ किया जाना है, विशेषरूप से जमाकर्ता के संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचे की सुदृढ़ करना आवश्यक है। पर्यावशी प्राधिकारी को यह शक्ति दी जाए कि वे इन वित्तीय कंपनियों द्वारा अपनी अमाराशि वेयताओं में चूक करने से काफी पहले ही सुधारात्मक उपाय कर सके। इस परिप्रेक्ष्य में वित्तीय कंपनियों की पूँजी और प्रारक्षित निधि के सुदृढ़ीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक शक्तियाँ प्रदान करना आवश्यक है।

11.18 इस समय बलाएँ जा रहे राजकोषीय समायोजन की पुष्ट-भूमि को देखते हुए बैंकों के सांविधिक परिसमापन अनुपात के परिवर्तन की समालोचनात्मक समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। जने-जैसे राज-कोषीय घाटा कम होगा, तो पूर्वक्रमाधिकारों के वर्तमान स्तर का नई दृष्टि से अवलोकन संभव हो जाएगा।

11.19 प्राथमिकता क्षेत्र के उधार को अब मोटेतौर पर ठीक किया जा चुका है, जिसे प्राप्त करने की कल्पना क्षेत्र के उत्पादन और क्षेत्र की ऋण उपलब्धता के बीच असंतुलन में की गई थी। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ-साथ यह जचने की आवश्यकता है कि समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए सामाजिक संस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से प्राथमिकता क्षेत्रों के उधार को अधिक प्रभावी तथा अधिक तीव्रतापूर्वक ध्यान दिया जा सकता है।

11.20 दूसरा प्रमुख मुद्दा है व्याज दर की नीति जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हाल की अवधि में व्याज दरों का, कुल मांग प्रबन्ध के एक लिखत के रूप में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। हाल की अवधि में बैंकों का उधार व्याज दरें तथा मुद्रा बाजार को दरें निश्चित रूप से अधिक रहा है किंतु ऐसे उच्च व्याज की दरें इसलिए आवश्यक हुई हैं, क्योंकि शीघ्र मौद्रिक सुधार लाने का प्रयास रहा है। चकि मुद्रा विस्तार और मुद्रा स्फीति काफी सामान्य स्तरों तक कम हो गए हैं। अतः व्याज की दरों में कमी होने के बारे में आशा करना उचित और विशेषकर उन दरों के बारे में जिनमें हाथ ही में तेजी से वृद्धि हुई थी।

11.21 जहाँ अधिकतर उधारकर्ताओं को बैंकों तथा संस्थाओं की उधार व्याज दरों, मुद्रा बाजार की दरों तथा डिबैंकरो दरों को मुक्त करके विनियमन हटाने का जो उल्लेखनीय कार्य किया गया है वहीं काफी अधिक संख्या में कई अन्य क्षेत्र हैं जहाँ व्याज की दरें विनियमित की जाती हैं जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, बैंक जमागणियाँ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार तथा कंपनी जमागणियाँ व्याज दरों की परस्पर विभिन्न लिखतों की परिपक्वता जोखिम और नकदी तथा व्याज दरों का स्तर, पूँजी की कमी को वणति है। लचीली व्याज दर नीति से जो कि समग्र नकदी स्थिति के अनुकूल होंगी, अतः जैसे ही मुद्रा स्फीति दरें कम होंगी व्याज की दरें कम होती जाएंगी। अतः यह अधिक उपयोगी होगा कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों को अधिक वक्षता के साथ उपयोग करने के लिए व्याज दर के ढाँचे की समग्र समीक्षा की जाए। ये तथा अन्य मुद्दे जैसे वित्तीय प्रणाली के संगठन और विन्यास से संबंधित, भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी ताकि वित्तीय प्रणाली की समीक्षा की जा सके। समिति के निष्कर्षों से वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों में सुविधा होगी।

वृद्धि की संभावना और मौद्रिक नीति की स्थिति

11.22 सुधारात्मक उपाय जो कि पहले ही किये जा चुके हैं, और जो किये जा रहे हैं उनसे वृद्धि की प्रक्रिया और विकास में दूरगामी परिणाम होंगे। अल्पावधि में पुनः समायोजन की प्रक्रिया समग्र वृद्धि में और विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में जो कि काफी अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के अनुदानों पर निर्भर हैं और जो अधिक सार्वजनिक क्षेत्र की मांग पर आधारित हैं, आवश्यक रूप से धीमापन लायेगा। सभी संकेत 1991-92 में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि की दर में कमी को सूचित करते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और सौराष्ट्र के अन्तर्गत आने वाले मौसमी प्रभावों को छोड़कर 1991 वित्तीय-वर्ष में मानसून की प्रगति अब तक संतोषजनक रही। समग्र रूप से 1991-92 में कृषि उत्पादन में लगभग एक प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है जो कि अपेक्षाकृत संतोषजनक निष्पादन माना जा सकेगा, यह इसलिए कि यह वृद्धि तीन वर्षों की लगातार कृषि वृद्धि से सर्वाधिक होगी। जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्र का संबंध है, 1991-92 के दौरान वृद्धि दर में आवश्यक रूप से कुछ धीमापन होगा। लागत में वृद्धि तथा कम उपलब्धता और सार्वजनिक व्यय में कटौती, एवं निवेश कार्यक्रम के साथ-साथ सामान्य आयात दबाव ऋण प्रतिबंध दोनों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक वृद्धि में धीमापन होगा। जहाँ खाद्य संसाधन जैसे उद्योग तथा कृषि पर आधारित अन्य ऐसे उप उद्योग जिनको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है, आयात कम होने के कारण प्रभावित न होने की संभावना है, वहाँ दूसरी ओर उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं तथा कम्प्यूटर, मिनी इत्याद संयंत्र और प्लास्टिक की वस्तुओं, जिनका अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आयात किया जाता है, में वर्ष 1991-92 के दौरान धीमी वृद्धि होगी। साथ ही उद्योगों की एक बहुत बड़ी संख्या में जो मांग की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर हैं, में भी कुछ गिरावट आयेगी। समग्र रूप से यह आशा की गयी है कि औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1990-91 के दौरान 8.4 प्रतिशत की प्राप्त वृद्धि दर की तुलना में 1991-92 में सम्पूर्ण वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत होगी। अर्थव्यवस्था में अनुभव की गई

कठिनाइयों की पुष्टि में, 1991-92 में सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर (1990-91 के 50 प्रतिशत की तुलना में) यदि 3 प्रतिशत प्राप्त की गई तो उसे काफी संतोषजनक निष्पादन मानना चाहिए।

11. 23 वृद्धि दर में आयी कमी और भुगतान संतुलन की स्थिति से उत्पन्न कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में मौद्रिक नीति की स्थिति ओ कि इस समय चल रही है उसके कम होने की बजाए बने रहने और शायद इस पर दबाव बढ़ाने की संभावना है। यदि हाल की अवधि में घपनाए गए, नीतिगत उपाय सफल होते हैं तो मूल्य वृद्धियों में कमी हो सकती है। जब कि रुपये का अवमूल्यन अपने में आयातित निवेशों की लागत में वृद्धि होने से मूल्यों में कुछ बढ़ोतरी कर सकता है, फिर भी, किए गए अन्य उपाय, जैसा कि बजट घाटे में लायो गई कमी और मुद्रा पूर्ति की वृद्धि दर में कुल मौद्रिक मांग को नियंत्रित करने में मदद पहुंचाएगी। 1991-92 में मौद्रिक नीति का कार्य स्पष्ट रूप से मुद्रा स्फीति को रोकना है। जब कि उपलब्ध ऋण में ही कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए जैसे कि निर्यात को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, कड़ी मौद्रिक नीति को केवल तभी बखला जा सकता है जब भुगतान संतुलन में उल्लेखनीय सुधार हो जाए और भारी मुद्रा स्फीति दबाव में कमी होना शुरू हो जाए।

## 12. मुख्य-मुख्य बातें

12.1 इस रिपोर्ट के भाग II में बैंकिंग विकास के परिचालनात्मक पहलुओं और संगठनात्मक मामलों तथा लेखा सहित रिजर्व बैंक के अपने परिचालनों का उल्लेख किया गया है।

12.1 इन गतिविधियों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(i) वाणिज्यिक बैंकों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकषित किया गया है कि वे अपनी लाभप्रदता में वृद्धि करें और अपने वित्तीय आधार को सुदृढ़ बनाएं। इस दिशा में, उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ यह मलाह दी गई है कि वे विवेक सम्मत लेखा मानकों और उचित स्थिति कूटों के अन्तर्गत अधिमों के वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पालन करें।

(ii) वित्तीय विवरणियों को अधिक सुस्पष्ट बनाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है और इस बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) को सूचित किया गया है कि वे 31 मार्च, 1991 को समाप्त वर्ष के लिए और इस अवधि के बाद अपनी वित्तीय विवरणियों में लेखों से संबंधित टिप्पणियों सहित एक स्थान पर परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में लेखा नीतियों को प्रकट करें।

(iii) बैंकों ने जुलाई 1990 से मार्च 1991 की अवधि के दौरान 275 शाखाएं खोली हैं।

(iv) केवल फैंडरिंग कामकाज हाथ में लेने के लिए अलग-अलग सहायक बैंक स्थापित करने के लिए दो बैंकों को अंतिम अनुमोदन दिया है।

(v) बैंकों में ग्राहक सेवा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए एम.एन. गोहोपाय्या, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

(vi) लघु उद्योग क्षेत्र (एस एस आई) में सम्भाव्य रूप से सक्षम नृण इकाइयों की पुनर्स्थापना के लिए निर्धारित मानदंडों से अधिक राहत/रियायत देने के लिए रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति की प्रणाली समाप्त कर दी गयी है।

(vii) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने 7,917 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण राहत प्रदान किया।

(viii) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने जुलाई 1991 में अपने बजट भाषण में रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर, श्री एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की घोषणा की है जो वित्तीय प्रणाली की संरचना, संगठन, कार्य और क्रियाविधियों के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

(ix) बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के एक सदस्य, एम.एस. मराठे की अध्यक्षता में रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है जो नये प्राथमिक सहकारी बैंकों को स्थापित करने की मौजूदा नीति और समितियों को प्राथमिक सहकारी बैंकों में परिवर्तित करने से संबंधित मामलों की समीक्षा करेगी।

(x) वित्तीय प्रणाली के अन्दर बेहतर समन्वय लाने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने "वित्तीय संस्था कक्ष" नामक एक नोडल यूनिट स्थापित की है।

(xi) आलोच्य अवधि के दौरान जमाराशियों, इकिया फंड और अनिवार्य भारतीय बांडों से संबंधित नई योजनाओं के लिए अनुमति दी गई है ताकि विदेशों से निधियों को जुटाया जा सके और अनिवार्य भारतीयों के लिए प्रतिरिक्त प्रोत्साहन और अपेक्षाकृत अधिक विकल्पों की व्यवस्था की जा सके।

(xii) सिद्धान्त रूप से यह निर्णय लिया गया है कि 1995 तक विभिन्न वर्णों में रु. 1/-, रु. 2/- और रु. 5/- का पूरी तरह सिककाकरण किये जाने के कार्यक्रम के बाद सिककों, तथा नोटों का एक नया सेट जारी किया जाएगा।

(xiii) भारतीय रिजर्व बैंक की आय विभिन्न प्रावधानों में समायोजन किये जाने के बाद 1990-91 के दौरान 4.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 4,625 करोड़ रुपये हो गयी है और निवल व्ययन आय 1989-90 में 1,107 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,345 करोड़ रुपये हो गई। सांख्यिक निधियों में उच्चतर अंशदान करने के बाद संघ सरकार को प्रतिरिक्त की गई प्रतिरिक्त राशि 1989-90 में 210 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1990-91 में 350 करोड़ रुपये कर दी गई थी।

## 13. वाणिज्य बैंकों से संबंधित गतिविधियाँ

बैंकों के लिए कार्य योजनाएँ : 1990-91

13.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा अप्रैल 1990 से मार्च 1992 तक की अवधि के लिए तैयार की गयी कार्य योजनाएं अब उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने तथा उनके वित्तीय आधार को सुदृढ़ बनाने की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए उन्हें यह सूचित किया गया है कि वे विवेकापूर्ण लेखा मानकों तथा निर्धारित स्वास्थ्य कूट के अंतर्गत अधिमों के वर्गीकरण के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करें। तथा स्वास्थ्य कूट सं. 6 से 8@ के साथ साथ स्वास्थ्य कूट सं. 5 के अधीन वर्गीकृत अधिमों पर भी ब्याज लगाना बंद कर दें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे परिमाण की दृष्टि से अपना कारोबार बढ़ाने अपनी प्राप्य राशियों को शीघ्र वसूली करने के लिए पूरा प्रयास करें। आय के नवीन साधनों का पता लगाकर व्यय को कारगर ढंग से नियंत्रित करके निधियों के सक्षम प्रबंध को सुनिश्चित करें तथा आशोध्य ऋणों को घटनाओं से कभी लायें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अधिक लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपनी लाभप्रदता में सुधार करने के लिए विस्तृत कार्य नीतियां बनायें ताकि अनुमानित ऋण हानि तथा अन्य आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए विद्यमान संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की जा सके। इस प्रयोजन हेतु बैंकों से कहा गया कि वे अप्राप्य अधिमों और अनप्रयोज्य अधिमों की मात्रा क्रमिक रूप में घटाये तथा अप्राप्त अधिमों के संबंध में ऋण की राशि काफी न्यून स्तर पर रोक वेमा सुनिश्चित करने के लिए कारगर कार्रवाई करें। छोटे बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वर्तमान 4 स्तरीय संगठनात्मक ढांचे को बदलकर 3 स्तरीय कर देने पर विचार करें। ताकि लागत को कम किया जा

सके तथा निर्णय संबंधी प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके और उसे अधिक कारगर बनाया जा सके। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को शाखा स्तर पर कार्य निष्पादन में सुधार लाने, असंतोषजनक शाखाओं को सुधारने तथा आदर्श शाखाएं विकसित करने पर निरन्तर ध्यान देने के लिए भी कहा गया है।

#### शाखा विस्तार

13.2 1985-90 की शाखा लाईसेंसिकरण नीति 31 मार्च 1990 को समाप्त हो जाने के कारण भविष्य में शाखा विस्तार के बारे में नीतिगत मार्गदर्शी निष्ठास्त तैयार किये गये हैं। 1985-90 की नीति के अंतर्गत ग्रामीण ग्रहणक्षेत्रों में जारी किये गये उन लाईसेंसों की वैधता अवधि एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 1991 कर दी गयी तथा बाद में 10 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 1992 कर दी गयी जिनका उपयोग 31 मार्च 1990 तक नहीं किया जा सकता था, ताकि बैंक अपने पहले के लाईसेंसों का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकें:

(a) ये कूट विनिर्देश इस प्रकार हैं:

कूट 5: संचित गये अधिम

कूट 6: खाते, जिनके संबंध में मुकदमा दायर किया गया है

कूट 7: डिग्रि प्राप्त ऋण

कूट 8: अगोच्य और संदिग्ध ऋण

13.3 शाखा विस्तार संबंधी नये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, (क) ग्रामीण क्षेत्रों में नयी शाखाएं खोलने के बारे में उन्हीं मामलों में विचार किया जाएगा जहां किसी एक शाखा को आबंटित सेवा क्षेत्र प्रबंधनीय नहीं है। तथा जहां दो स्थानों के बीच बहुत अधिक दूरी है अथवा किसी ग्रामीण शाखा का कारोबार इतना बड़ गया है कि वहां एक और शाखा खोलने की जरूरत है (ख) अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में शाखा विस्तार पर विचार करने समय यह देखा जाएगा कि व्यापार और उद्योग में वृद्धि अन्य आर्थिक कार्यक्षमताओं में वृद्धि को देखते हुए, शाखा विस्तार की बहुत आवश्यकता है एवं प्रस्तावित शाखा कार्यक्षम है; (ग) औद्योगिक परियोजना क्षेत्रों के संघर्ष में मानदंड बिल्कुल स्पष्ट किये गये हैं। जहां बैंकों की शाखाएं खोलने पर विचार करने समय तत्काल आवश्यकता और परियोजना संबंधी परिस्थित आदि को ध्यान में रखा जाएगा और (घ) शहरी और महानगरीय पतन क्षेत्रों के मामले में बैंक सुविधा रहित/अल्प बैंक सुविधायुक्त स्थानों का पता लगाने का कार्य लघु कार्यकारी दलों को सौंपा गया है जिनमें अन्यो के साथ-साथ बड़े वाणिज्य बैंकों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं तथा इनका संयोजक भारतीय रिजर्व बैंक का संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय होता है। अब रिजर्व बैंक, इन क्षेत्रों में पता लगाये गये स्थान कतिपय मानदंडों के आधार पर विभिन्न बैंकों को आबंटित करने का कार्य कर रहा है।

13.4 नयी नीति के अंतर्गत विस्तार काउंटरों की अनुमति की बियाबिधि को आसान बना दिया गया है। तदनुसार रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा के स्थान पर प्रत्येक बैंक को किसी एक विनिर्दिष्ट वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान अपनी शहरी और महानगरीय शाखाओं की पिछले वर्ष के अंत में कुल संख्या के 2 प्रतिशत तक विस्तार काउंटर खोलने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते कि वह विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति करता हो। आवास के विकास को दी गयी प्राथमिकता को देखते हुए तथा अधिक व्यावसायिकता प्राप्त करने के लिए, यह स्वीकार किया गया कि ऐसी विशेषज्ञतायुक्त शाखाएं स्थापित करने की आवश्यकता है जो केवल आवास वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्रारंभ में ऐसी विशेषज्ञतायुक्त शाखाएं केवल शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में खोली जाएं तथा बाद में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाए। सामाजिक सदस्यों की प्राप्त हेतु खोली गयी बैंकों की अलाभकर शाखाओं के कार्य-क्षमता में सुधार करने की दृष्टि से बैंकों को ऐसी शाखाएं, अन्य बैंकों के साथ सदस्यों की स्वतंत्रता दी गयी है।

13.5 जुलाई 1990 से मार्च 1991 तक की अवधि के दौरान 275 बैंक शाखाएं खोली गयीं। 31 मार्च 1991 को परिवर्धित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) की 60,101 शाखाओं में से 35,113 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में थीं। ये शाखाएं कुल शाखाओं का 58.4 प्रतिशत अंश है। 1990-91 के दौरान प्रति शाखा कार्यालय औसत जनसंख्या में और सुधार हुआ इसका अनुपात मार्च 1990 के अंत के 11,600 से गिरकर मार्च 1991 के अंत में 11,000 रह गया।

#### विदेशों में भारतीय बैंक

13.6 विदेशों में कार्यरत नौ भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं की संख्या 115 थी और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 11 थी। इसके अलावा, विदेशों में भारतीय बैंकों के संपूर्ण स्वामित्व वाली छः सहायोगी संस्थाएं थीं। (इनमें अमरावतियां स्वीकार करने वाली तीन कंपनियां भी शामिल हैं) तथा सात संयुक्त उद्यम बैंक थे।

#### भारत में विदेशी बैंक

13.7 चार विदेशी बैंकों को भारत में शाखाएं खोलने के लिए लाईसेंस जारी किये गये। सान्वा बैंक लि., तथा बार्कलेज, बैंक पी. एल. सी. बैंकों ने अपने प्रतिनिधि कार्यालयों का उद्घाटन करने क्रमशः मई दिल्ली और बंबई में अपनी पहली शाखाएं खोली हैं। इन दो शाखाओं के खुलने में उन विदेशी बैंकों की संख्या बढ़कर 24 हो गयी जिनकी भारत में शाखाएं हैं, तथा मार्च 1991 के अंत में उनकी कुल शाखाओं की संख्या 140 हो गयी। वर्ष 1990-91 (मार्च 1991 तक) के दौरान तीन विदेशी बैंकों अर्थात् एनएमबी पोस्ट बैंक ग्रुप, फ्यूजी बैंक लि., और इन्स्टीट्यूट बैंकर्स ऑफ पाओलो आईटोरियंट ने भारत में एक-एक प्रतिनिधि कार्यालय खोला। इससे तथा दो प्रतिनिधि कार्यालयों के शाखाओं में परिवर्धित हो जाने के कारण ये कार्यालय बंद हो जाने से देश में विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 23 हो गयी।

#### क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

13.8 आलोच्य वर्ष के दौरान 369 जिलों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या अपरिवर्धित रही उनके कार्यालयों की कुल संख्या 14,497 थी। दिगंबर 1990 के अंत में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल अतिरिक्त अमरावतिया तथा अग्रियों की राशि क्रमशः 4,419.35 करोड़ रुपये और और 3,501.81 करोड़ रुपये थी। परन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यालयाल संतोषजनक नहीं था तथा मार्च 1990 के अंत में 162 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की हानि की सम्मिलित राशि 282 करोड़ रुपये थी।

#### सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण

13.9 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण 1 अप्रैल 1989 से लागू है। ऋण धायाजनाओं में सेवा दृष्टिकोण के अंतर्गत निर्धारित परिस्थित को 1989-90 के 15,590 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1990-91 में 17,190 करोड़ रुपये कर दिया गया, इसे तीनों क्षेत्रों कृषि, उद्योग और सेवाएं के संदर्भ में बटाया गया है। अधिल भारतीय क्षेत्र-वार ऋण वितरण के लक्ष्य तथा वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1989-90		1990-91
	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य
कृषि	10,371	9,270	11,615
उद्योग	2,643	2,392	2,805
सेवा	2,576	2,441	2,770
जोड़	15,590	14,103	17,190

13.10 सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के राष्ट्रीय गठित खंड स्तरीय बैंकर समितियों के कार्यक्रमों के पुनरीक्षण से कतिपय कमियों का पता चलता है। इस प्रकार ऋणों की वसूली, मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था तथा ऋण को अधिक उत्पादक बनाने के लिए उत्पादन तथा विपणन संबंधी व्यवस्थाओं जैसे विषयों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है। रिजर्व बैंक ने सुधार संबंधी आवश्यक कार्यवाई शुरू कर दी है।

13.11 रिजर्व बैंक ने सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण आयोजना और जांच के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं जो 1 अप्रैल, 1991 से शुरू होने वाली ऋण आयोजना अवधि से लागू हो गये हैं। कुछ प्रमुख वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि जिला स्तर पर प्रांकडों की प्राप्ति का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को बैंकों की सहायता

13.12 सरकारी क्षेत्रों के बैंकों ने कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत अपने ऋणों की राशि मार्च 1990 के अंत के 39,418 करोड़ रुपये से बढ़ाकर मार्च 1991 के अंत में 42,276 करोड़ रुपये कर दी परन्तु कुल बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों का अंश यद्यपि विनिर्दिष्ट लक्ष्य को पूरा करता था, तथापि वह मार्च 1990 के अंत के 43.2 प्रतिशत से गिर कर मार्च 1991 के अंत में 40.0 प्रतिशत रह गया। यह गिरावट सभी संवर्गों में परिलक्षित हुई परन्तु यह ऋण के संबंध में अपेक्षाकृत अधिक थी। यह ग्रामीण ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन का परिणाम है।

13.13 निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों, जिनसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणों के अंतर्गत विभिन्न लक्ष्य और उप लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है, ने सितम्बर 1990 के अंत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 1,504 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जो उनके नियत बैंक ऋण का 34.9 प्रतिशत अंश है। निवल बैंक ऋण में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों का प्रतिशत अंश भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के मामले में मार्च 1989 के अंत के 8.4 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 1990 के अंत में 9.8 प्रतिशत हो गया तथा सितम्बर 1990 के अंतिम शुक्रवार को 9.7 प्रतिशत विदेशी बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे मार्च 1990 के अंत तक 12 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें और मार्च 1992 के अंत तक 15 प्रतिशत का लक्ष्य\*।

ऋण और ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990

13.14 ऋण और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 का कार्यान्वयन 15 मई 1990 से शुरू किया गया इसमें सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पात्र ऋणकर्ताओं को 10,000 रुपये तक ऋण राहत की परिकल्पना की गयी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं पिछले वर्ष की रिपोर्ट में दी गयी थीं। भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बैंकों से यह कहा गया है कि वे 31 मार्च 1991 तक योजना का कार्यान्वयन पूरा कर लें। किन्तु असम तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में यह अवधि जून 1991 के अंत तक है। राज्य सरकारों ने भी सहकारी क्षेत्र में कार्यान्वित करने के लिए ऐसी ही एक योजना बनायी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा नाबाई द्वारा सूचित अन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों ने लगभग 7,917 करोड़ रुपये तक की ऋण राहत प्रदान की है जिसमें से सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों ने 2,962 करोड़ रुपये, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 808 करोड़ रुपये तथा सहकारी बैंकों ने 4,147 करोड़ रुपये की ऋण राहत उपलब्ध करायी।

\*रोजगार पैदा करने तथा आसिन् निर्माण के लिए बैंक सहायता की अलग-अलग योजनाओं को परिष्कारित संबंधी व्योरे बैंक की भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, 1990-91 में दिए गये हैं।

वाध्य राशियों की वसूली

13.15 सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष ऋण ऋणियों की वसूली में 1988-89 तक सुधार हो रहा था, परन्तु 1989-90 (जुलाई-जून) में वह पिछले वर्ष के 57.3 प्रतिशत से काफी गिरकर मांग का 46.8 प्रतिशत रह गई। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में भी गिरावट आयी। वसूली, मार्च 1990 में समाप्त छमाही में मांग के 55.1 प्रतिशत से गिरकर सितम्बर 1990 में समाप्त छमाही में 45.8 प्रतिशत रह गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में वसूली का प्रतिशत 1988-89 में मांग के 48.6 प्रतिशत से गिरकर 1988-89 में 33.9 प्रतिशत रह गया।

लेखा नीतियां—बैंकों की वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता

13.16 समिति (अध्यक्ष श्री ए. घोष) द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार बैंकों के प्रकाशित लेखाओं में संपूर्ण प्रकटीकरण किये जाने की बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के द्वारा उन्हें प्रस्तुत अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचना जारी की, जिसमें उन्होंने उक्त अधिनियम की तीसरी अनुसूची में संशोधन करने, बैंकों के तुलन पत्र और लाभ हानि लेखों के फॉर्मेट में परिवर्तन/संशोधन करने के अपने अभिप्राय का उल्लेख किया है। जबकि परिशोधित फॉर्मेट, तीसरी अनुसूची के संशोधन को लागू किये जाने की पश्चात ही काम में लाये जायेंगे अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) को सूचित किया गया है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के पश्चात् धारण वाले वर्षों के लिए अपने वित्तीय विवरणों के खातों पर लिखी गयी टिप्पणियों के साथ एक ही स्थान के परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में लेखा नीतियों को नियमित रूप से प्रकट करें।

बैंकों का पूर्ण आधार

13.17 राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूर्ण आधार को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1990-91 के दौरान 700 करोड़ रुपये का अंशदान किया। इस प्रकार 1985 से कुल अंशदान 2,600 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,000 करोड़ रुपये हुई तथा इसकी प्रदत्त पूंजी भी 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 200 करोड़ रुपये हो गयी।

बैंकों का निरीक्षण

13.18 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक के 13 स्थानीय प्रधान कार्यालयों के संबंध में वार्षिक वित्तीय समीक्षा प्रारम्भ की। आलोच्य अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के तीन बैंकों, निजी क्षेत्र के 11 बैंकों और 12 विदेशी बैंकों तथा स्टेट बैंक ग्रुप सिविकम का वित्तीय निरीक्षण किया गया।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में ऋण-दुष्ट

13.19 पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर के राज्यों में बैंक के ऋणकर्ताओं को कतिपय रियायतें देने के बारे में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। इन रियायतों की अवधि और एक वर्ष पर्याप्त 31 मार्च, 1991 तक बढ़ा दी गयी है।

बैंकों द्वारा वित्तीय विविधीकरण

13.20 वाणिज्य बैंकों ने अपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से व्यापारी बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, आवास वित्त, किराया खरीद, उपस्कर पट्टे पर देना, फेक्टरिंग सेवाएँ प्रादि जैसे नये क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों के विविधीकरण में उल्लेखनीय प्रगति की। मार्च 1991 के अन्त में, सरकारी क्षेत्र के 8 बैंकों और निजी क्षेत्र के एक बैंक की उपस्कर पट्टे पर देने एवं व्यापारी बैंकिंग की सहायक कंपनियों की स्थापना की अनुमति दी गयी। उक्त अवधि के अन्त में बैंकों के म्यूचुअल फंड की संख्या पाँच

पर स्थिर रही। आवास वित्त पर अधिक जोर देने की दृष्टि से नौ बैंकों ने आवास वित्त कम्पनियाँ/सहायक कम्पनियाँ स्थापित की अथवा संस्थाओं द्वारा स्थापित आवास वित्त कंपनियों की इतिषदी में सहभागी बने।

13.21 आलोच्य अवधि के दौरान, पांच बैंकों को उनकी संबंधित व्यापारी बैंकिंग सहायक कंपनियों के माध्यम से किराया खरीद कारोबार करने की अनुमति दी गयी। दो बैंकों को फेडरिंग कारोबार करने के लिए पृथक सहायक कम्पनियाँ स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया।

#### ऋण स्थगन और समामेलन

13.22 सभीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्वांचल बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी जिसे कुछ समय के लिए ऋण स्थगन के अस्तंगत रखा गया था, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये गये अनुसार सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के साथ समामेलित किया गया। दि हाईलैंड बैंक लिमिटेड, ज़िपुरा स्टेट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड और शिमला बैंकिंग इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव लिमिटेड को पहली जुलाई, 1990 से 30 जून, 1991 की अवधि के दौरान विधटित किया गया; उसके साथ ही परिसमापन के अधीन बैंकों की संख्या अब 121 है।

#### ग्राहक सेवा

13.23 गत वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के चारों राज्यों में कार्यरत बैंकों में ग्राहक सेवा के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी चार प्रतिष्ठित व्यावसायिक एजेंसियों को सौंपी थी। उत्तर प्रदेश के एक राज्य को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों के संबंध में रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं और उनके निष्कर्षों का विश्लेषण किया जा रहा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री के मार्च 1990 में दिये गये बजट अभिभाषण के परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक ने सी. एम. एन. गोइपोरिया, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में 14 सदस्यों की समिति का गठन किया जिसका प्रतिनिधित्व रिजर्व बैंक, बैंकों, जमाकर्ताओं, कर्मचारियों, वित्तिमत्ता उद्योगों तथा निर्यात क्षेत्र ने किया। इस समिति के गठन का उद्देश्य बैंकों में ग्राहक सेवा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा इस क्षेत्र में बैंकों के कार्य निष्पन्न करने में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना था।

#### बैंक धा. म. श. नीति/कम्प्यूटरीकरण

13.24 बैंक के 20 कार्यालयों तथा भारत सरकार के तीन विभागों को संचयन और भ्रष्ट प्रेषण (स्टोअर एंड फारवर्ड ट्रान्समिशन) (एसएफटी) नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसी प्रकार, 19 कार्यालयों को जोड़ने वाले विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रायोजित ध्वनि (टेलेकेटेड स्वीच) नेटवर्क विकसित किया गया और अब तक 17 कार्यालयों को जोड़ा गया है तथा शेष दो कार्यालयों अर्थात् जम्मू तथा भोपाल को भी जोड़ा जाएगा। बैंकिंग प्रभाग (भारत सरकार) को भी रिजर्व बैंक की ध्वनि नेटवर्क से जोड़ा गया है।

13.25 रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंकनेट, विशिष्ट धाकड़ा संचार नेटवर्क की स्थापना करने के लिए रिजर्व बैंक सहयोग तथा प्रयास कर रहा है। बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बंगलूर हैदराबाद तथा नागपुर इन सात केन्द्रों में स्थित रिजर्व बैंक तथा अन्य बैंकों के लगभग 200 कार्यालयों को बैंकनेट से परस्पर संबद्ध किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, सभी शहरों के भीतर लाइनों को बिछाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। बैंक ने कुछ केन्द्रों में बैंकनेट के माध्यम से निज स्वस्थानीय समाशोधन स्थिति की सूचना भेजनी शुरू कर दी है। बैंकनेट का उपयोग निधियों का अंतरण बड़ी राशियों के लिए त्रुपट सूचनाएं जारी करने, विदेशी मुद्रा आदि के वर्गों की सूचना भेजने आदि के लिए भी किया जाएगा।

13.26 रिजर्व बैंक भारत में स्विफ्ट नेटवर्क (विश्वव्यापी अंतर-बैंक वित्तीय तुरसंचार समिति) के समन्वय के लिए भी कार्य कर रहा

है। भारत में रिजर्व बैंक सहित 42 बैंक स्विफ्ट के सदस्य-उप सदस्य बन गये हैं। हाईवेयर, साफ्टवेयर लगाने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने डेटा सफ्ट उपलब्ध करने तथा पीएसटीएन लोक चालित दूरसंचार नेटवर्क लाइनों का कार्य चल रहा है तथा आशा है कि 2 दिसम्बर, 1991 को बैंक स्विफ्ट से जुड़ जाएंगे।

13.27 जून 1991 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 1,700 शाखाओं में 5,190 एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाई, जिनमें से 4,977 एडवांस लेजर पोस्टिंग मशीनें परिचालित की गयी और 4,413 मशीनों पर कार्य किया जा रहा है। बैंकों ने केन्द्रीय/आंचलिक कार्यालयों में 282 मिनी कम्प्यूटर लगाये हैं। छः बैंकों ने अपने अपने प्रधान कार्यालयों में केन्द्रीय (मेनफ्रेम) कम्प्यूटर लगा लिया है तथा उसे परिचालित भी कर दिया है तथा बहुत से अन्य बैंकों ने केन्द्रीय कम्प्यूटर के लिए आदेश दे दिये थे और वे लगाये जा रहे हैं। अब तक बैंकों के लगभग 45,000 कर्मचारियों को कम्प्यूटर के बारे में एवं मशीन चलाने के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।

13.28 प्रत्येक बैंक की एक-एक शाखा में कार्यकलाप के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण का कार्य कार्यान्वयन के अधीन है और कुछ बैंकों में यह कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है।

#### बैंक समाशोधन का कम्प्यूटरीकरण

13.29 नागपुर में बैंक द्वारा परिचालित समाशोधन गृह में मशीनीकृत बैंक प्रोसेसिंग प्रणाली का प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है।

13.30 बैंकों की अंतर-शहर समाशोधन एक तरफा सुविधा अन्य चार छोटे केन्द्रों, अर्थात् अहमदाबाद, बंगलूर, हैदराबाद और नागपुर को प्रदान की गयी। कुछ अन्य केन्द्रों को दी जाने वाली बाहरी केन्द्रों में साइबर बैंकों के समाशोधन भी सुविधा खरण बड़ रूप से प्रदान की जाणगी। कोयम्बतूर को मद्रास के साथ जोड़कर अन्तर शहर समाशोधन में क्षेत्रीय संकुल (ग्रिड) की संकल्पना की शुरुआत की गई है।

13.31 एक लाख रुपये और उससे अधिक राशि के बैंकों को उसी दिन ग्राहक के खाते में जमा करने का विशेष समाशोधन का जो कार्य चार महानगरों में आरम्भ किया गया था, वह संतोषजनक रूप से चल रहा है। रिजर्व बैंक के बैंकों के माध्यम से अंतर-बैंक लेन-देन के निपटान के स्थान पर शुद्ध राशि के लिए अंतरबैंक समाशोधन भुगतान प्रणाली छः केन्द्रों अर्थात् बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद तथा हैदराबाद में प्रारंभ की गयी है।

13.32 समाशोधन गृह के वर्तमान एकममान विनियमों और नियमों का पुनरीक्षण करने के लिए बनाये गये विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट के ताद्विधिक आधार प्रदान करने की दृष्टि से भी इस ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

13.33 वर्ष के दौरान, पांच नये समाशोधन गृह खोले गये हैं। अब इसकी संख्या 848 हो गयी है।

#### ऋण निगरानी व्यवस्था

13.34 ऋण प्राधिकरण योजना के स्थान पर 10 अक्टूबर, 1988 से ऋण निगरानी व्यवस्था शुरू की गयी है, जिसमें बैंकों को बड़ ऋणकर्ताओं के ऋण प्रस्ताव संजूर करने का प्राधिकार दिया गया है बशर्ते वे संजुरी के बाद प्रस्ताव जांच के लिए रिजर्व बैंक को भेजें। इन प्रस्तावों की संख्या जून 1990 के अन्त में स्थित 18,825 से बढ़कर दिसम्बर, 1990 के अन्त में 2,135 हो गयी। दिसम्बर 1990 के अन्त में प्रचलित कुल कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं 33,608 करोड़ रुपये थी, उनमें से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अंश 16,366 करोड़ रुपये या 48.6 प्रतिशत था। दिसम्बर 1990 के अन्त में कुल ऋण सीमाओं का सुविधाकार स्वरूप

निम्नानुसार था : कार्यकारी पूंजीगत प्रयोजन (बैंकिंग ऋण, वेशी और विदेशी बिलों सहित) 90.4 प्रतिशत, मीमादी वित्त 9.0 प्रतिशत और आस्थायित प्रदायगी के आधार पर मशीनों की बिजली 0.6 प्रतिशत।

13.35 अब तक ऋण निगरानी व्यवस्था के अधीन 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक निधि-आधारित कार्यकारी पूंजी सीमाओं का लाभ उठाने वाले ऋणकर्ताओं को दी गयी ऋण सीमाओं की सभी मंजूरीय और/या नवीकरण और/या 2 करोड़ से अधिक मीमादी ऋण की रिपोर्ट बैंक द्वारा (एकमात्र बैंक या सहायता संघ के आग्रणी बैंक) रिजर्व बैंक को भेजा जाना अपेक्षित था। इसकी समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया था कि पहले की 100 प्रतिशत समीक्षा की बजाए ऐसे प्रस्तावों के लिए प्रतिशत समीक्षा प्रणाली जनवरी, 1991 से प्रारंभ की जाए ताकि टंडन/चोरे समिति की रिपोर्ट में लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति को ध्यान में रखते हुए बैंक ऋण का लाभ उठाने में वित्तीय अनुशासन लाया जाए। जबकि बैंकों को सूचित किया गया है कि ऋण सीमाओं की 100 प्रतिशत मंजूरी और/या नवीकरण के बारे में रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भेजने की प्रथा को बनाये रखें, ताकि बैंक द्वारा की जाने वाली मंजूरी पश्चात समीक्षा के स्तर में कमी करने की दृष्टि से जब कभी आवश्यकता हो, वे बैंक ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा निगरानी की अपनी वर्तमान प्रणाली की समीक्षा कर सकें, उसमें सुधार ला सकें।

बड़े कंपनी समूहों की लेखासंबंधी निगरानी

13.36 कुछ बड़े औद्योगिक समूहों के प्रवर्तकों द्वारा अपनी कुछ विद्यमान यूनिटों के खातों में चूक और/या गंभीर अनियमितताएँ होने के बावजूब नये यूनिट खोलने और/या विद्यमान यूनिटों में विस्तार करने के मामले रिजर्व बैंक के सामने आये हैं। परिणामस्वरूप, जहाँ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की काफी निधियाँ अनप्रयोज्य आस्तियों में अक्ल हो गयीं वहाँ किन्हीं अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की नये उद्यमों/विस्तार के लिए अतिरिक्त निधियाँ मंजूर करनी पड़ीं। अतः बड़े ऋणकर्ताओं समूहों के खातों की निरन्तर जांच करते रहने का निर्णय किया गया।

स्टॉक/प्राप्य राशि संबंधी मानदंडों का संशोधन तथा अन्य संबंधित मामले

13.37 देश की कठिन भुगतान संतुलन की स्थिति को देखते हुए अक्टूबर 1990 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे आयातित कच्चा माल निर्धारित स्तरों पर या 3 महीने की अवधि तक, इनमें से जो भी कम हो, ही रखने की अनुमति दें। ये मानदंड स्टॉक रखने की अधिकतम सीमा के ही धोतक हैं और अगर किसी ऋणकर्ता का काम पहले, स्टॉक के न्यून स्तर से चलता रहा है तो उसे स्टॉक के उच्च स्तर का अधिकारी नहीं मान लिया जाना चाहिए।

13.38 बड़ी ऋण सीमाओं के अंतर्गत आहरणों को प्रतिबंधित करने संबंधी नीतिगत उपाय इस खंड के अगले पैराग्राफों में दिये गये हैं। कतिपय उद्योगों की विशिष्ट समस्याओं को देखते हुए कतिपय रियायते दी गयीं। इस प्रकार, यद्यपि रिजर्व बैंक उपदान संबंधी प्राप्य राशियों के बैंकों द्वारा वित्तपोषण के पक्ष में नहीं हैं तथापि उर्वरक उद्योग के सामने आने वाली विशेष समस्याओं को देखते हुए बैंकों को सामान्य प्रतिधारण मूल्य योजना के अधीन 60 दिन तक की अवधि के लिए ऐसी प्राप्य राशियों का वित्तपोषण करने की अनुमति दी गयी है।

13.39 पॉलिएस्टर स्टेपल रेयो की विनिर्माता यूनिटों की न्यून मांग तथा क्षमता को कम उपयोग की समस्या के कारण पॉलिएस्टर स्टेपल रेयो के विनिर्माता यूनिटों के पास तैयार माल जमा हो गया तथा प्राप्य राशि बढ़ गयी, इसे देखते हुए, इन यूनिटों को 31 दिसंबर 1990 तक की अवधि के दौरान वचनात्मक आधार पर हर मामले के गुण-दोष देखते हुए तीन महीने तक की अवधि के लिए तैयार माल और बिल रखने की अनुमति दी गयी जबकि नियमित मानदंड के अनुसार उक्त अवधि 2

महीने की है। ऋण देने की पहली पद्धति के अंतर्गत कार्यकारी पूंजीगत अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने की सुविधा उन सभी कपड़ा मिलों के मामले में फरवरी 1991 के अंत तक बढ़ा दी गयी जिनका प्रबंध राष्ट्रीय वस्त्र निगम और राज्य वस्त्र निगमों द्वारा किया जाता है तथा उन्होंने आधुनिकीकरण आदि के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त की है; इससे इन यूनिटों का पूंजीगत आधार भावि को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी निधियों पर निर्भरता कम हो जाएगी। उन समिष्ट कपड़ा मिलों जिनके तैयार माल जमा हो जाने तथा बढ़ी हुई प्राप्य राशियों की समस्या बनी हुई है, के मामले में बैंकों को सूचित किया गया कि ये 30 सितंबर 1991 तक की अवधि में वचनात्मक आधार पर प्रत्येक मामले में गुण दोष को देखते हुए तैयार माल और प्राप्य राशियों के संबंध में 3.5 महीने तक का स्टॉक रखने की अनुमति दे सकते हैं जबकि नियमित संयुक्त मानदंड के अंतर्गत यह अवधि 3 महीने है। 1990 के अंत तक तीन वर्ष के लिए सभी हीरे के सभी नियतकों की (ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन (ऋण देने की पहली पद्धति के अंतर्गत करने की अनुमति थी, अब जनवरी 1991 से यह मूल्यांकन ऋण देने की दूसरी पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। जून 1991 में हीरा उद्योग से संबंधित मानदंडों के पुनरीक्षण करने पर यह निर्णय लिया गया कि धारिताओं के स्तर को घटाकर निम्नानुसार कर दिया जाए : कच्चे माल (अभिसंस्करण के अधीन स्टॉक सहित) के मामले में 2.5 महीने, तैयार माल के मामले में 1.0 महीना और प्राप्य राशियों के मामले में 3.0 महीने, जबकि पहले ये स्तर क्रमशः 3.5 महीने, 1.5 महीने और 3.0 महीने थे। कच्चे माल और तैयार माल के लिए 3.5 महीने के उपर्युक्त मानदंड में डी टी सी दर्शनी हुंडी के धारकों के मामले में अपरिष्कृत हीरे प्राप्त करने की 15 दिन की पार-वहन अवधि भी शामिल है। जो दर्शनी हुंडी के धारक नहीं हैं उनके मामले में अधिकतम 3 महीने का मानदंड ही लागू होगा।

लीजिंग और किराया खरीद प्रतिष्ठाओं को ऋण

13.40 लीजिंग और किराया-खरीद कंपनियों को बैंकों के ऋण उनके कुल बाहरी उधार के मामले में उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के बस गुना की निर्धारित समग्र उच्चतम सीमा के भीतर उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों के तीन गुना से अधिक नहीं होने चाहिए। भाव में, जुलाई 1990 में बैंकों को यह स्पष्ट किया गया था कि वित्तीय/निवेश संस्थाओं से जुटायी गयी निधियों को निवल स्वाधिकृत निधियों के तीन गुना की उच्चतम सीमा में सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं है, यह सीमा केवल बैंकों के ऋण पर ही लागू होती है। किन्तु, अधिकतम अनुमत बैंक वित्त की गणना करते समय निर्मित आस्तियों में वित्तीय/निवेश संस्थाओं से प्राप्त वित्त से निर्मित किराया-खरीद/लीजिंग आस्तियों को शामिल न किया जाये ताकि ऐसी आस्तियों के वित्तपोषण हेतु बैंक वित्त उपलब्ध न कराया जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि लीजिंग/किराया खरीद कंपनियों की ओर से बैंकों द्वारा दी जानेवाली आस्थायित प्रदायगी संबंधी गारंटियों को बैंकों के ऋण के बारे में निर्धारित उच्चतम सीमा में शामिल न किया जाए। इसी प्रकार, अधिकतम अनुमत बैंक वित्त की गणना करते समय भी ऐसी गारंटियों पर निर्मित आस्तियों को हिसाब में न लिया जाए।

आयातों का वित्तपोषण : विशेष विनियम

13.41 जैसा कि रिपोर्ट के भाग 1 में कहा गया है देश की विदेशी भुगतान सम्बन्धी तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति के कारण उन मामलों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक हो गया है जो विदेशी मुद्रा की अन्तर्वाध व्यवस्था से सम्बन्धित हैं और जिन्हें खुली विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि को सुरक्षित रखने के प्रथम प्रयोजन के साथ सुलझाना आवश्यक था। इसी विधा में, लगातार वनेत्र उपाय लागू किये गये जो आयात के लिए बैंक द्वारा वित्तीय सहायता देने से संबंधित हैं। इन उपायों से आयातों को केवल अत्यावश्यक स्तर तक ही सीमित कर दिया



गया और पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए खुली विदेशी मुद्रा पर आपातकाल की निर्धारणा को कम किया गया। तेजी से बढ़ती हुई परिस्थिति के मुकाबले, बैंक ने सितम्बर 1990 से निम्नलिखित उपाय लागू किये। इन उपायों की धारदार व्यापक स्वरूप देना, उनका क्षेत्र मजबूत करना, जो मंथीयत करना आवश्यक हो गया था। इन उपायों का मार्गदर्श दिया गया है।

#### पूँजीगत वस्तुओं का आयात

13.42 दिनांक 11 सितम्बर, 1990 को बैंकों को सूचित किया गया कि खुले सामान्य लाइसेंस या विशिष्ट आयात लाइसेंस के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं के आयातकों से कहा जाता चाहिए कि वे अपनी विदेशी मुद्रा के अणु सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए मीयादी ऋण देने वाली संस्थाओं से सम्पर्क करें। बैंक किन्हीं उपरिहाय्य कारणों से ऐसे प्रयोजनों के लिए ऋण प्रदान करते हैं तो विनिमय जोड़िम प्रवर्धन योजना, के अंतर्गत आने वाले विदेशी मुद्रा के ऋण पर जो करें लागू हैं उनसे 0.5 प्रतिशत अधिक ध्याज उनसे देना चाहिए। इस सम्बन्ध में, बैंकों द्वारा मीयादी ऋणकारी संस्थाओं को उनके द्वारा दिये गये ऋण के लिए गारंटी जारी करने पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटा दिया गया।

13.43 बैंकों से कहा गया कि वे दिनांक पहला नवम्बर, 1990 से पूँजीगत माल के सभी आयातकों की वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क करने के लिए निर्देश दें। बैंकों को उपरा मीयादी ऋण प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गयी जब वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध ऋण प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार के आयात न होते हैं।

13.44 24 दिसम्बर, 1990 को, बैंकों को वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में छुट्टी ऋणकर्तारों का और से साथ ही अन्यो की ओर से जो ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ वित्तीय संस्थाओं के कार्यालय नहीं हैं, वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटी जारी करने की अनुमति दी गयी है। यह गारंटी प्रस्ताव की वाणिज्यिक अर्थक्षमता और कतिपय अन्य शर्तों के अर्थन जारी की जावेगी।

13.45 बैंकों को 24 दिसम्बर, 1990 को यह सूचित किया गया कि युक्ति द्विपक्षीय समूह के व्यापार करने वाले देशों से पूँजीगत माल का आयात विदेशी ऋण प्रणाली से शामिल नहीं है अतः ऐसे आयातों को बैंक वित्तीय महायता देना जारी रखें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि जहाँ आयातक यह दावा करते हैं कि वे आयात की लागत अपने ही संसाधनों से पूरा करेंगे और बैंकों से अथवा वित्तीय संस्थाओं से किसी प्रकार का मीयादी ऋण प्राप्त नहीं करेंगे वहाँ बैंक इस बात से संतुष्ट होते के बाद कि इस प्रयोजन के लिए किसी निधि-आधारित सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जावेगा, वे आवश्यक साख-पत्र सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

13.46 संपीक्षा करने के बाद बैंकों को 6 फरवरी, 1991 को यह सूचित किया गया कि वे निम्नलिखित मामलों में पूँजीगत माल के आयात के लिए स्वयं मीयादी ऋण प्रदान कर सकते हैं: (क) भारत सरकार की ओर से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अलाय: गयी तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत किये जाने वाले आयात; और (ख) आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वर्तमान प्लानों द्वारा तकनीकी जानकारी के आयात, माय है: ऐसे मामले में जहाँ यह प्रस्तावित है कि इस प्रयोजन के लिए वित्तीय संस्थाओं से सम्पर्क नहीं किया जावेगा।

13.47 पूँजीगत माल के आयात के सम्बन्ध में जारी किये गये पहले के अनुदेशों के अधिग्रहण में, 19 मार्च, 1991 को यह सूचित किया गया कि अगले आठवण तक किन्हीं भी परिस्थितियों में पूँजीगत आयात के लिए खुली विदेशी मुद्रा की किसी भी अनुमति नहीं दी जावेगी। यह भी सूचित किया गया कि इस प्रकार के माल के आयात के लिए वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा ऋण प्रणाली में से वित्तीय महायता

दी जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, ऐसे ऋण मंजूर करना वित्तीय संस्थाओं के लिए सुविधाजनक हो इसलिए वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में 31 मार्च, 1991 के बाद भी गारंटियां जारी करने की अनुमति बैंकों को दी गयी।

13.48 खुली विदेशी मुद्रा में से पूँजीगत माल के आयात के लिए साख-पत्र खोलना कुछ विनिश्चित मामलों में 19 मार्च, 1991 के बाद भी अनुमय था। 25 फ़रवरी, 1991 को रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंकों के लिए यह ठोक होगा कि वे 19 मार्च, 1991 को या इससे पहले खोले गये साख-पत्रों को ऐसे आयातों के मामले में स्वीकार करें। परंतु ऐसी स्वीकार करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि ऐसे साख-पत्र वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप खोले गये हैं।

13.49 पूँजीगत माल के जो आयात साख-पत्रों के अंतर्गत नहीं आते तथा जहाँ पोतलदान 19 मार्च, 1991 को या इससे पहले पूरा हो गया हो, उनके मामले में बैंकों को सूचित किया गया था कि ऐसे आयातों को वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा की ऋण प्रणाली के अंतर्गत लाया जावे। यदि ऐसे आयात विदेशी मुद्रा ऋण प्रणाली के अंतर्गत नहीं लाये जा सकते तो किसी खुली विदेशी मुद्रा में की जा सकती है। परंतु ऐसी किसी इस बात से संतुष्ट होने पर ही की जावेगी कि आयातक स्वयं अपने संसाधनों से आयात की रकबा लागत पूरी करेगा।

13.50 31 मई, 1991 को बैंकों को सूचित किया गया कि पूँजीगत माल के जो आयात विदेशी ऋण सुविधा के अंतर्गत नहीं आते किन्तु एक वर्ष के लिए पूर्णतः ऋण के अंतर्गत आते हैं, उन आयातों का परीक्षण रिजर्व बैंक द्वारा तब किया जाएगा, जब उस परियोजना जिसके लिए यह आयात किया जाता है, उस परियोजना के वित्तपोषण के श्रोत, कार्यान्वयन के चरण पूर्णतः ऋण की शर्तों, कंपनी के निर्धारों का निष्पादन, तथा नयी परियोजना के मामलों में, विदेशी मुद्रा का अपेक्षित अर्जन/बचन के बारे में कतिपय ध्योरे रिजर्व बैंक को प्राप्त होंगे।

13.51 रूस, चेकोस्लोवाकिया और रूमानिया से पूँजीगत माल का आयात करने के लिए (परस्पर किये गये करार की वैध अवधि के दौरान) 13 जून, 1991 से साख-पत्र खोलने की अनुमति दी गयी।

13.52 जहाँ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विमास बैंक (आइ.बी.आर.डी.), अंतर्राष्ट्रीय विकास मंडल और एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) जसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं आयातों के लागत की, प्रतिपूर्ति करेंगी वहाँ ऐसी परियोजनाओं के लिए पूँजीगत माल के आयात करने हेतु बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 24 जुलाई, 1991 को साख-पत्र खोलने की अनुमति दी गयी।

#### पूँजीगत माल से इतर माल का आयात

13.53 बैंकों को 25 फ़रवरी, 1991 को सूचित किया गया कि वे कतिपय नियत-कार्यकलापों और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित आयातों को छोड़कर सभी कच्ची-सामग्री, पुर्जों इत्यादि के आयातों पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम नकदी मार्जिन बनाये रखें। आयातित माल के संवय का स्तर भी तीन महीने के उपयोग तक या निर्धारित स्तर तक, इसमें से जो भी कम हो, सीमित कर दिया।

13.54 25 नवंबर, 1991 को बैंक को जीवन रक्षक वसाइयों और उपकरणों को न्यूनतम नकदी मार्जिन की अपेक्षा से मुक्त रखा गया।

13.55 निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, बैंकों को 24 दिसंबर, 1991 को सूचित किया गया कि वे उन मुद्रियों को साख-पत्रों से संबंधित नकदी मार्जिन की अपेक्षा से छूट दें जिनका निर्यात पिछले लेखा वर्ष के दौरान उनकी कुल थिरी का कम से कम 25 प्रतिशत या 10 करोड़ रुपये प्रति-वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, रहा है। द्विपक्षीय व्यापार देशों

ने किये गये आयातों को भी नकदी मार्जिन की अपेक्षा से मुक्त रखा गया।

13.56 बैंकों को 24 जनवरी, 1991 को सूचित किया गया कि वे अधिम लाइसेंसों और अधिम मध्यवर्ती लाइसेंसों पर आयातों को 30 प्रतिशत की नकदी मार्जिन की अपेक्षा से छूट दें, बशर्तें इस प्रकार के आयात केवल स्वयं के उपयोग के लिए हों।

13.57 6 फरवरी, 1991 को बड़ी मात्रा में वबाइयां, मिश्रण और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयातों, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 से अंतर्गत प्रदत्त इन्फेण्ट प्राइवेट लिमिटेड बैररहाउस लाइसेंसधारी कंपनियों द्वारा किये जाने वाले आयातों तकनीकी जानकारी संबंधी आयातों और आपूर्तिकर्ता के न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के ऋण के अंतर्गत किये जाने वाले आयातों के संबंध में न्यूनतम नकदी मार्जिन से छूट दी गयी।

13.58 विनांक 19 मार्च, 1991 से प्रभावी, न्यूनतम नकदी मार्जिन का निर्धारण 50 प्रतिशत और 133.33 प्रतिशत पर किया गया, जो लाइसेंस के स्वरूप पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत पूंजीगत माल से इतर आयात किया जाना था और इस प्रकार की न्यूनतम नकदी मार्जिन उन आयातों पर भी लागू की गयी जो साख-पत्र के अंतर्गत नहीं किये गये। इसी के साथ-साथ निर्धारित न्यूनतम नकदी मार्जिन को केवल निम्न-लिखित आयातों के संबंध में दी गयी छूट को कम किया गया। सरकारी विभागों द्वारा किया गया आयात, पेट्रोलियम का आयात, तेल और चिकनाई के पदार्थ, उर्वरक खाद्यान्न और खाद्य तेल, प्रचुरकारी कागज और जीवन रक्षक दवाइयां। बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि उनके ग्राहकों को नकदी मार्जिन संबंधी अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिरिक्त सीमा/आवरण अधिकार नहीं दिये जाते।

13.59 100 प्रतिशत निर्यात-उत्पन्न पूंजीकृत यूनिटों, निर्यात अभि-संस्करण अंचलों में स्थित यूनिटों और मुक्त व्यापार क्षेत्रों द्वारा अपने उपयोग के लिये किये जाने वाले आयात पर 50 प्रतिशत नकदी मार्जिन की अपेक्षा से 1 अप्रैल, 1991 से छूट दे दी गयी। लेकिन यह छूट इस शर्त के अधीन थी कि वे अपने निर्यात सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों की करें और निर्यात मूल्य निर्यात की तारीख से छः महीने के भीतर वसूल करें।

13.60 अधिम और इम्प्रेस्ट लाइसेंसों पर स्वयं के उपयोग के लिए किये जाने वाले आयातों को निर्धारित न्यूनतम नकदी मार्जिन की अपेक्षा से छूट दी गयी, बशर्तें निर्यात के पास निर्यात की तारीख से छः महीने के अवधि से अधिक कोई भी निर्यात बिल बकाया न हो। आर.ई.पी. और प्रतिरिक्त लाइसेंसों के अंतर्गत किये जाने वाले आयातों पर 50 प्रतिशत की नकदी मार्जिन लगाई गयी, बशर्तें जिस निर्यात मूल्य पर इस प्रकार के लाइसेंस जारी किये गये थे, उनकी पूरी वसूली हो जाती हो।

13.61 सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत किये जाने वाले आयातों पर न्यूनतम नकदी मार्जिन और अधिक बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गयी और विशिष्ट लाइसेंस के अंतर्गत किये जाने वाले आयातों के लिए वह मार्जिन बढ़ाकर 150 प्रतिशत कर दी गयी। यह मार्जिन 22 अप्रैल, 1991 से लागू की गयी तथा 2 लाख रुपये तक का मूल्य होनेवाले जीवन-रक्षक उपकरणों के आयात की न्यूनतम नकदी मार्जिन से छूट दी गयी। इम्प्रेस्ट लाइसेंस के अंतर्गत, मूल्ययोजित पुनरिर्थात के लिए रतन और आभूषणों के आयातों को निर्धारित न्यूनतम नकदी मार्जिन से छूट दी गयी है, बशर्तें निर्यात निर्यात की तारीख से 90 दिनों से अधिक कोई निर्यात बिल बकाया नहीं रखता और वह बचन देता है कि वह भविष्य में किये जाने वाले निर्यात का मूल्य 90 दिनों के भीतर वसूल करेगा। आर.ई.पी. लाइसेंस पर दिये जाने वाले रतन और आभूषणों के आयातों को नकदी मार्जिन से छूट देने के लिए उनके संबंध में हम आशय का बचन आवश्यक किया गया कि भावी निर्यातों का मूल्य 90 दिनों के भीतर वसूल किया जाएगा और आपूर्तिकर्ता के ऋण की 90 दिन की अवधि उपलब्ध है।

13.62 जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, जो निर्यातक निर्यात मूल्य का प्रत्यावर्तन शीघ्र करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए तथा जो निर्यातक निर्यात मूल्य के प्रत्यावर्तन में देरी करते हैं उनके लिए ऋण महंगा करने के उद्देश्य से पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण से संबंधित उधार दरों में और भी संशोधन किया गया।

13.63 विनांक 23 अप्रैल, 1991 को भारत सरकार ने यह निष्पत्ति किया कि सभी आयात पुनर्भरण लाइसेंस जारी किये जाने चाहिए जब निर्यात मूल्य वसूल कर लिया जाये। इस परिवर्तनों को देखते हुए बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे इस प्रकार के भुगतानों पर पुनर्भरण लाइसेंसों पर किये जाने वाले आयातों के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम नकदी मार्जिन सम्बन्धी अपेक्षा को हटा कर दिया जाये।

13.64 एक वर्ष तथा इससे अधिक अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता के ऋण के अंतर्गत गैर-पूँजीगत माल के आयात के लिए 50 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम नकदी मार्जिन की अपेक्षा से 31 मई, 1991 से छूट प्रदान की गयी। (यह मार्जिन 19 मार्च, 1991 को लागू की गयी थी)।

13.65 विनांक 6 जून, 1991 से निर्यात संवर्धन के लिए परिष्कृत चमड़ा/चमड़े की वस्तुओं, रसायन और फार्मास्युटिकल्स, इंजीनियरी वस्तुओं, कस और सागरी उत्पादों के विनिर्माता-निर्यातकों को अनुमति दी गयी कि वे गैर-पूँजीगत माल बिना किसी नकदी मार्जिन के सामान्य मुद्रा क्षेत्र से आयात कर सकते हैं। वे इस प्रकार की छूट उनके वास्तविक निर्यात मूल्य के 10 प्रतिशत तक ले सकते हैं। इस आयात की अधिकतम सीमा 2.5 करोड़ रुपये वार्षिक होगी। विनिर्माता-निर्यातकों द्वारा रूस से चमड़ा और बाल के आयातों को निर्धारित नकदी मार्जिन की अपेक्षा से मुक्त रखा गया है। तथापि, उक्त छूट तभी उपलब्ध होगी जब कोई भी निर्यात बिल छह महीने से अधिक तक बकाया नहीं रहेगा।

13.66 समीक्षा दर की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने निर्धारित नकदी मार्जिन से सम्बन्धित वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों में 1 अगस्त, 1991 से निम्नानुसार संशोधन किया :

(क) निश्चित बड़ी मात्रा की वबाइयां और मिश्रण के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात को नकदी मार्जिन की अपेक्षा से मुक्त रखा गया है। इसके प्रतिरिक्त, जीवन रक्षक उपकरणों के आयात के लिए निर्धारित नकदी मार्जिन से छूट प्राप्त करने की वर्तमान 2 लाख रुपये की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी।

(ख) साख-पत्रों के अंतर्गत किये जाने वाले आयातों के मामलों में बैंकों को यह अनुमति दी गयी कि वे नकदी मार्जिन की राशि तभी प्रवस करें जब सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा माल क्लियर हो जाये और सीमाशुल्क प्रवेश बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति बैंक को प्रस्तुत की जाये। जो आयात साख-पत्र के अंतर्गत नहीं किये गये हों उनके मामले में नकदी मार्जिन की राशि इन्हीं शर्तों पर प्रदान की जाये, बशर्तें ऐसे आयात कम-से-कम 6 महीने तक की अवधि के लिए आपूर्तिकर्ता के ऋण के अंतर्गत शामिल हों।

(ग) किन मामलों में निर्यात-आयातक अपने भावी निर्यातकों और/या आपूर्तिकर्ता के ऋण पर निर्यात मूल्य वसूल करने की अवधि को शामिल करने के लिए अधिम राशि प्राप्त करने की स्थिति में उन मामलों में रिजर्व बैंक नकदी मार्जिन की अपेक्षाओं से छूट प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

(घ) निर्यात बिल निर्यात की तारीख से छह महीने में अधिक अवधि के लिए बकाया है या नहीं इसका निर्णय करने के लिए बैंक कारणों से उन बकाया बिलों को नहीं गिना जायेगा जो पिछले तीन वर्षों के दौरान की गयी औसत निर्यात-वसूली के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हैं ऐसे बकाया बिल 50 लाख रुपये की वर्तमान सीमा के स्थान पर एक करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के स्थान पर एक करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन होंगे।

13.67 नयी व्यापार नीति के परिप्रेक्ष्य में 9 अगस्त, 1991 से निर्यात-सम्बद्ध कार्यक्रमों के लिए कुछ और रियायतें दी गयीं :

(क) विनिर्मिता-निर्मातकों और निर्यात तथा व्यापार प्रतिष्ठानों द्वारा अमड़ा और खाल, परिष्कृत अमड़ा और रसायनों के कुछ प्रकारों के आयात न्यूनतम-नकदी माजिन से छूट प्राप्त है, बशर्ते निर्यात बकाया निर्धारित अपेक्षित स्तर से अधिक न हो ।

(ख) पूंजीगत वस्तुओं से इतर वस्तुओं के आयात के लिए विनिर्माता-निर्यातों की कुछ श्रेणियों को उनके पिछले वर्ष के दौरान सामान्य करों की सीमा को किये गये वास्तविक निर्यातों के 10 प्रतिशत तक छूट उपलब्ध है । ये छूट एक वर्ष में 2.5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है । यह छूट सीमा अब बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गयी है तथा यह वर्ष में 5 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है ।

निर्यात ऋण-बैंकों का कार्य-निष्पादन

13.68 49 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों जिनका सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (भाग 1 में उल्लिखित) के बैंक ऋण में 95 प्रतिशत अंश है, के आंकड़ों से पता चलता है कि उनमें बकाया निर्यात ऋण की राशि मार्च 1990 के अंत के 8,245 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1991 के अंत में 9,153 करोड़ रुपये हो गयी जिससे 11.0 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित होती है ।

निर्यात वित्त संबंधी म्यादी समिति

13.69 निर्यात वित्त पर स्थायी समिति जो निर्यात वित्त से संबंधित एक उच्च अधिकार प्राप्त नीति निर्धारक निकाय है, निर्यातक समुदाय के सामने आनेवाली विभिन्न समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श करने के बाद निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं :

(i) नियत तारीख के बाद बसूले किये गये विलों पर पोत लदानोत्तर ऋणों के लिए उपलब्ध रियायती ब्याज दरों की सुविधा को बंद कर दिया जाए; तथा

(ii) निर्यात ऋण के प्रयोजन के लिए अधिकतम अवधि की विदेशी मुद्रा निर्यातक विनियमावली के अंतर्गत निर्यात प्राप्तियों की बसूली के लिए निर्धारित पोत लदान की तारीख से 6 महीने की अवधि के अंतर पर बढ़ा दिया जाए ।

निर्यात ऋण (ब्याज सहायता) योजना, 1968

13.70 भारत सरकार की विपणन विकास सहायता में से रिजर्व बैंक को उपलब्ध करायी गयी निधियों को रिजर्व बैंक ने नकदी आधार पर वाणिज्य बैंकों तथा पात्र सहकारी बैंकों को पोत लदानपूर्व ऋणों के मामले में 5 प्रतिशत वार्षिक तथा पोत लदानोत्तर ऋणों के संबंध में 3.85 प्रतिशत वार्षिक ब्याज उपदान संवितरित किया । 1 जुलाई, 1990 से 30 जून, 1991 तक की अवधि के दौरान कुल संवितरणों की राशि 290 करोड़ रुपये थी । निर्यात के संबंध में सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता बंद कर दिये जाने के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा दिये जाने वाले निर्यात ऋण संबंधी ब्याज दर में किये गये संशोधन की वजह से बैंकों को सूचित किया गया है कि 6 अगस्त, 1991 से इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपदान के लिए पात्र नहीं होंगे ।

शुल्क वापसी ऋण-योजना, 1976

13.71 1 नवंबर, 1990 से 31 अक्टूबर, 1991 तक की अवधि के लिए 27 बैंकों कुल 99.70 करोड़ रुपये की ऋण सीमा मंजूर की गयी ताकि वे शुल्क वापसी ऋण-योजना, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य ब्याज-रहित पुनर्वित्त की सुविधा का लाभ उठा सकें ।

आवास ऋण

13.72 आवास वित्त के आवंटन के संबंध में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे अपने-अपने अंश की गणना पिछले वर्ष के दौरान अपनी वृद्धिशील जमा राशियों के 1.5 प्रतिशत के हिसाब से करते रहें । वर्ष 1989-90 के दौरान आवास वित्त के लिए संवितरित वास्तविक बैंक ऋण 390 करोड़ रुपये था जो लक्ष्य की 322 करोड़ रुपये की राशि से अधिक है । आवास वित्त के लिए निर्धारित की गयी कुल राशि 1990-91 के लिए 387 करोड़ रुपये तथा 1991-92 के लिए 365 करोड़ रुपये थी । अभी तक बैंकों को राज्य स्तरीय संस्थाओं की आवास ऋणों के संबंध में आवास और शहरी विकास निगम के पक्ष में गारंटियां जारी करने की अनुमति दी गयी थी, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करें । राज्यों द्वारा प्रायोजित निकायों को आवास और शहरी विकास निगम तथा कुछ अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों के संबंध में जिन पर लगायी जाने वाली ब्याज दरें बाह्य कुछ भी क्यों न हों, राज्य सरकारों को उक्त निकायों की ओर से गारंटियां जारी करने का अधिकार दिए जाने के परिणामस्वरूप अक्टूबर 1990 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे राज्यों द्वारा प्रायोजित निकायों को दिये गये ऋणों के संबंध में आवास और शहरी विकास निगम के पक्ष में गारंटियां जारी न करें ।

13.73 गैर-सरकारी भवन-निर्माताओं को 18 महीने की अधिकतम अवधि के लिए किसी विशिष्ट परियोजना से संबद्ध सांग-ऋण के रूप में बैंक-ऋण लेने की अनुमति दी गयी थी, अब 5 जून 1991 से वे 3 से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए सहायता ऋणों के रूप में बैंक ऋण ले सकते हैं जो राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत प्लेट/मकानों के निर्माण के साथ-साथ भूखंडों के विकास की प्रत्येक विशिष्ट परियोजना से संबद्ध होंगे, बशर्ते वे कतिपय महत्वपूर्ण शर्तों का अनुपालन करें जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि भवन-निर्माता विकास और निर्माण के चरणों को कोई जमा राशि, भुगतान प्राप्त न करें तथा पूरा बन जाने पर मकान को पूर्वनिर्धारित मूल्यों पर आबोदेनी को मुरान विक्री के आधार पर बेच दिया जाए ।

राष्ट्रीय आवास बैंक

13.74 राष्ट्रीय आवास बैंक की शीघ्र पूर्ण पहली मिनंबर 1989 में 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये की गयी थी, अक्टूबर 1990 में और बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दी गयी । राष्ट्रीय आवास बैंक ने केन्द्रीय सरकार द्वारा गारंटीकृत 80 करोड़ रुपये की राशि के बांधों को अपनी सीतरी शृंखला जारी की जिन पर 11.5 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज देय है, अभी तक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लिये गये इस प्रकार के ऋणों की कुल राशि 160 करोड़ रुपये है । रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को पिछले वर्ष मंजूर 25 करोड़ रुपये के दीर्घावधि ऋण की राशि को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया और इसमें अभी तक राष्ट्रीय बैंक को दी गयी कुल सहायता 125 करोड़ रुपये हो गयी ।

13.75 20 जुलाई, 1990 को राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी पूंजीगत बांड योजना शुरू की जिसके अंतर्गत बांड न तो अंतरणीय है और न ही परक्राम्य है और इन पर ब्याज-दर 9 प्रतिशत वार्षिक है, छमाही आधार पर या शारंभ में ही बढ़ते के आधार पर देय होंगी, एवं आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54(ई) के अंतर्गत दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों जैसे भूमि, भवन, शीघर तथा प्रतिभूतियां, आभूषण आदि के विक्रय/अंतरण से प्राप्त पूंजीगत अधिलाभ पर 100 प्रतिशत कर की छूट दी जाती है । इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक ने जून 1991 के अंत तक 2,480 आवेदकों से 82,21 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं ।

13.76 अमरीकी सहायता सरकारी आवास गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक ने पहली शृंखला के रूप में 18 अप्रैल, 1991 को अमरीकी पूर्वी बाजार से 25 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि जुटायी ।

इस ऋण की परिपक्वता-मर्यादा 30 वर्ष की है और इस पर 8.63 प्रतिशत वार्षिक की निश्चित दर पर व्याज लगाया जाएगा। ऋण का विदेशी मुद्रा षटक केन्द्रीय सरकार को अंतरित कर दिया गया और इसके बदले में केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक को रुपये राशि उपलब्ध करायी। जुटायी गयी निधियों का उपयोग दमियानी आय (2,000 रुपये प्रति माह) से न्यून आय वाले परिवारों हेतु दीर्घावधि आवास वित्त उपलब्ध कराने के लिए पात्र आवास वित्त कंपनियों की सहायता के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारत सरकार के माध्यम से विदेशी आर्थिक सहयोग निधि, जापान से भी 2.97 बिलियन येन का ऋण प्राप्त किया, इसका उपयोग भी दमियानी आय से न्यून आय वाले परिवारों को आवास ऋण देने के लिए किया जाएगा।

13.77 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों के उधार पर व्याज-दरों के स्वरूप में 22 मितंबर, 1990 से परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपनी पुनर्वित्त दरों में भी निम्नानुसार परिवर्तन किये:

ऋण की राशि (रुपय में)	व्याज दर (प्रतिशत वार्षिक)	
	राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा लगायी जाने वाली व्याज- दर	प्राथमिक ऋण- दाता द्वारा ऋण- कर्ता से ली जाने वाली व्याज-दर
7,500 तक	8.0	10.0
7,501 - 15,000	9.5	11.5
15,001 - 25,000	10.0	12.0
25,001 - 50,000	12.5	14.0
50,001 - 2,05,000	14.0	15.0

नये आवास प्लॉटों, जिनका निम्न-क्षेत्र 40 वर्गमीटर से अधिक न हो, निर्माण अधिग्रहण के लिए ऋणों के 100 प्रतिशत पुनर्वित्त की अधिकतम सीमा को भी बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। 40 वर्ग मीटर से अधिक निम्न-क्षेत्र वाले प्लॉटों, जिनका लागत 1.50 लाख रुपये से अधिक न हो (भूमि की लागत सहित) के लिए 1 लाख रुपये तक के ऋणों के संदर्भ में 100 प्रतिशत तक का पुनर्वित्त मिलना रहेगा। भारत सरकार या सुधारों के लिए 30,000 रुपये तक के ऋण, 100 प्रतिशत पुनर्वित्त के लिए पात्र बने रहेंगे। 22 मितंबर, 1990 को या उसके बाद अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित सभी पात्र आवास ऋणों पर उपलब्ध संशोधन लागू होने। आवास वित्त कंपनियों और राज्य स्तरीय निष्पक्ष सहकारी आवास वित्त समितियों के संबंध में पुनर्वित्त योजनाओं के संशोधन प्रावधान 1 जनवरी, 1991 से लागू किये गये थे। बाद में, 1 मई, 1991 से आवास वित्त कंपनियों के मामले में 50,000 रुपये--2,00,000 रुपये की ऋण स्लैब को विभाजित कर 50,001 रुपये--1,00,000 रुपये तथा 1,00,001 रुपये--2,00,000 रुपये के दो ऋण स्लैब बना दिये गये जिन पर अधिम हिताधिकारी को लगायी जाने वाली व्याज दर क्रमशः 14.5 प्रतिशत और 15.0 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित की गयी तथा राष्ट्रीय आवास बैंक के पुनर्वित्त पर व्याज दर क्रमशः 13.5 प्रतिशत और 14.0 प्रतिशत वार्षिक थी।

13.78 जून 1991 के अंत तक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सभी श्रेणियों के पात्र प्राथमिक ऋणदाताओं को उपलब्ध करायी गयी पुनर्वित्त सहायता (तबर्ध वित्तीय सहायता सहित) की राशि 567.5 करोड़ रुपये थी जबकि जून 1990 के अंत में यह राशि 131.7 करोड़ रुपये थी। कुल मंजूर पुनर्वित्त में आवास वित्त कंपनियों का अंश 83.7 प्रतिशत था और इसके बाद सहकारी क्षेत्र का संस्थाओं का अंश 11.2 प्रतिशत और अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का अंश 5.1 प्रतिशत था। करोड़ 2.0 लाख आवासीय प्लॉटों के संबंध में

पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करायी गयी; इन प्लॉटों के लब्धन संबंधी प्लॉटों तथा भूमि विकास और भवन बनाने संबंधी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

13.79 1 जुलाई, 1989 से चल रही आवास ऋण खाता योजना में अब चुनिंदा आवास वित्त कंपनियों को भी शामिल किया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च 1991 के अंत तक इस योजना के अधीन 4 लाख से अधिक खाते खोले गये एकत्रित जमा राशि लगभग 68 करोड़ रुपये थी।

13.80 सरकारी एजेंसियों, सहकारी आवास समितियों और व्यावसायिक विकासकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निष्पादित भूमि विकास और आवास संबंधी परियोजनाओं और सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नियोजकों को किराया आवास-परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त योजनाओं के अधीन व्याज दरों में संशोधन किया गया ताकि उन्हें संशोधित व्याज दर संरचना के अनुरूप बनाया जा सके। मोदीय ऋणों पर व्याज दर की गणना अलग-अलग षटकों के संबंध में लागू दर से भारत औद्योगिक के अनुसार की जाएगी और सभी परियोजना ऋण पर लागू की जाएगी, राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त पर व्याज की दर उपर्युक्त दर से एक प्रतिशत कम होगी। मार्गदर्शी सिद्धांतों को भी उदार बनाया गया तबनुसार, निर्धारित प्लॉट और आवास इकाई के प्रकार के संबंध में मामूली सी छूट दी जा सकती है बशर्ते उनका मूल्य क्रमशः 50,000 रुपये और 1.5 लाख रुपये से अधिक न हो। आलोच्य वर्ष के दौरान इन पुनर्वित्त योजनाओं को सभी पात्र आवास कंपनियों पर भी लागू किया गया जून 1991 के अंत तक राष्ट्रीय आवास बैंक ने 17,803 प्लॉटों का विकास और 38,449 मकानों के निर्माण के लिए कुल 298.4 करोड़ रुपये की 43 परियोजनाओं का अनुमोदन किया इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आवास बैंक ने 22,200 प्लॉटों के विकास और 31,650 मकानों के निर्माण के लिए कुल 618.7 करोड़ रुपये की लागत वाली 77 परियोजनाओं को मौखिक रूप से मंजूर कर दिया है।

13.81 राष्ट्रीय आवास बैंक, गुणवत्ता के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की ईक्यूइटी में भी भाग लेता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने निर्दिष्ट रूप में यह निर्णय लिया है कि वह केवल उन रुपये मौजूदा आवास वित्त कंपनियों की ईक्यूइटी में भाग लेता जो, मध्य, उत्तर, और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में अपनी आवासीय खानों के लिए प्रविष्ट हैं। जहां गायब वित्त प्रणाली के विकास को अभी काफी मुश्किल है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अब तक, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रशिक्षित की जानकारी। कुल 5.00 करोड़ रुपये की ईक्यूइटी वाली 4 आवास वित्त कंपनियों में भाग लेने का निर्णय लिया है। 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक के अग्र्य आवास निर्माण निधि (बैंक ऑफ इंडिया) तथा वैश्य बैंक हाउसिंग फाइनेंस लि. (वैश्य बैंक लि.) की ईक्यूइटी में 2.8 करोड़ रुपये का अग्रिम किया है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने अब तक 16 आवास वित्त कंपनियों को वित्त सहायता के लिए पात्र माना है। इनमें से 2 सरकारी क्षेत्र में, 2 संयुक्त क्षेत्र में और शेष 12 निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में जिन कंपनियों को मान्यता दी गयी उनमें से 7 कंपनियों संस्थाओं बैंकों द्वारा प्रायोजित और 5 प्राइवेट कंपनियों द्वारा प्रायोजित हैं।

13.82 राष्ट्रीय आवास बैंक ने जून 1991 तक 4 परियोजनाओं के लिए कुल 116 लाख रुपये की ईक्यूइटी सहायता मंजूर की है। कृषि और उद्योगों के अवशिष्ट मान का प्रयोग करने हुए स्थानीय रूप से तैयार की गई मानक भवन निर्माण सामग्री और श्रमिकों को सहायता देने के लिए निर्धारित मानदंडों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सामग्रियों का निर्माण करने वाली इकाइयों को सहायता प्रदान की गई है - (क) रेत चुने की ईंट, (ख) फ्लाईएश से बने भवन निर्माण सामग्री के उत्पाद और (ग) पालिस्टर कास्ट मोल्ड्ड उत्पाद।

**रुण औद्योगिक उपक्रम**

13.83 वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया है कि वे उन योजनाओं में अपना सक्रिय सहयोग दें जो रुण इकाइयों के उनके अपने श्रमिकों द्वारा गठित सरकारी समिति द्वारा अधिग्रहण और पुनर्गठन से संबंधित हैं। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे रुण इकाई में ईक्विटी शेयर खरीदने के लिए श्रमिकों की सहकारी समितियों को सुलभ ऋण उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा तैयार की गई ईक्विटी फंड योजना से लाभ उठाने के अतिरिक्त उन मामलों पर गुण दोष के अनुसार विचार करें, जहां पुनर्गठन पैकेज के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों से भिन्न रियायतें शामिल हों। यह निर्णय लिया गया है कि पुनर्गठन कार्यक्रम के अधीन रुण/कमजोर इकाइयों के लिए मौजूदा/अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट जोखिम लागू नहीं होगी। बैंकों को किसी रुण इकाई के मौजूदा ऋणों को रियायती दरों पर खरीदने के लिए तैयार किसी अन्य बैंकों को बेचने की अनुमति केवल उन मामलों में दी गई है, जहां पुनर्गठन पैकेज को अंतिम रूप दे दिया गया हो और सहायता संघ के अन्य सहभागी सदस्यों की सहमति प्राप्त हो। पुनर्गठन पैकेज के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को तेज करने की दृष्टि से बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व-नुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बगैर संभावित सक्षमतायुक्त लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्न रुण/कमजोर इकाइयों के पुनर्गठन के लिए तैयार किये गये पैकेज कार्यक्रम के भाग के रूप में निर्धारित मानदंडों से भिन्न राहतों/रियायतों की सीमा पर विचार करने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की गई हैं।

13.84 उपलब्ध, नवीनतम आंकड़ों (सितम्बर, 1989) के अनुसार रुण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985, द्वारा यथा परिभाषित बैंको द्वारा पता लगायी गयी लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्न रुण इकाइयों की संख्या सितम्बर 1989 के अन्त में 1,419 थी, जिनके पास 4,258 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था। इनमें से 1,167 इकाइयों के संबंध में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरे किये गये और उनमें से 456 इकाइयों को सक्षम माना गया। सक्षम मानी गई इकाइयों में से 280 के संबंध में बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। इस अवधि के दौरान बैंको द्वारा पता लगायी गई लघु उद्योग क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र की कमजोर इकाइयों की कुल संख्या 762 थी, जिनके पास, 2,183 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था। 560 इकाइयों के संबंध में सक्षमता संबंधी अध्ययन पूरा किया गया और 315 इकाइयों को सक्षम माना गया। सक्षम इकाइयों में से 182 इकाइयों के संबंध में बैंकों द्वारा पोषण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। सितम्बर, 1989 के अन्त में लघु उद्योग क्षेत्र की रुण इकाइयों इनमें ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योग क्षेत्र के यूनिट शामिल हैं, की संख्या 1,86,441 थी जिनमें 2,243 करोड़ रुपये का बैंक वित्त लगा हुआ था। इनमें से केवल 16,042 इकाइयों को जिनके पास 568 करोड़ रुपये का बैंक ऋण बकाया था, को बैंकों द्वारा सहाय्य रूप से सक्षम माना गया और 8,201 इकाइयों के संबंध में पोषण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया।

वित्तीय संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायता

13.85 रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को वर्ष 1990-91 के लिए ~~...~~ ऋण स्वीकृत नहीं किया। तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने वर्ष 1990-91 के दौरान 117.15 करोड़ रुपये की राशि ~~...~~ और इसकी कुल बकाया ~~...~~ की राशि 30 जून 1990 तक 3,705.15 करोड़ रुपये रह गयी। यद्यपि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के 2 मार्च, 1991 को बैंक दर (अर्थात् 10 प्रतिशत वार्षिक) पर 400 करोड़ रुपये की अल्पावधि ऋण सीमा मंजूर की गई, जो कि 30 जून, 1991 तक वैध थी, परन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस ऋण सीमा का उपयोग नहीं किया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो अब अन्य अखिल भारतीय सीमावर्ती ऋण दात्री संस्थाओं की तरह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 और 46 के अधीन

भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण प्राप्त करने का पात्र है, को राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के दौरान उपयोग हेतु 400 करोड़ रुपये का दीर्घावधि ऋण स्वीकृत किया गया, जो 6 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है। भारतीय लघु-उद्योग विकास बैंक ने इस सीमा का पूरा उपयोग किया। इसके अतिरिक्त, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 300-300 (कुल 600 करोड़ रुपये की दो और सीमाएं स्वीकृत की गईं। परन्तु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 300 करोड़ रुपये की प्रथम सीमा में से केवल 75 करोड़ रुपये का उपयोग किया है।

13.86 राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से भारतीय निर्यात आयात बैंक को वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के लिए 120 करोड़ रुपये की दीर्घावधि ऋण सीमा मंजूर की गई जो कि 7 प्रतिशत वार्षिक की व्याज दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकायी जानी है। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने इस सीमा का पूर्णतया उपयोग किया और उक्त निधि से इसके बकाया ऋण की राशि 30 जून, 1991 को 745 करोड़ रुपये हो गई।

13.87 भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि में से 35 करोड़ रुपये की दीर्घावधि ऋण सीमा मंजूर की गई जो कि 6 प्रतिशत वार्षिक की व्याज दर पर 15 वर्षों की अवधि में चुकायी जानी है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक ने इस सीमा का पूर्णतया उपयोग किया जिससे निधि में से लिये गए उधारों की बकाया राशि 30 जून 1991 को 130 करोड़ रुपये हो गयी।

13.88 भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को पिछले वर्ष मंजूर की गई 40 करोड़ रुपये की तुलना में कैलेंडर वर्ष 1991 के लिए 44 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सीमा मंजूर की। तदनन्तर 6 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सीमा मंजूर करके इस सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया। निगम अपनी तदर्थ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सीमा का उपयोग कर रहा है। 30 जून 1991 को इसकी बकाया ऋणों की राशि 41 करोड़ रुपये हो गई।

13.89 राजकोषीय वर्ष 1990-91 के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को 33 करोड़ रुपये की तदर्थ सीमा मंजूर की गई। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने तदर्थ आधार पर इस सीमा का उपयोग किया और 30 मार्च, 1991 को समस्त बकाया राशि की चुकौती कर दी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को वित्त वर्ष 1991-92 के लिए 30 करोड़ रुपये की एक नवीन ऋण सीमा मंजूर की गई है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को दिये गये तदर्थ ऋण, बैंक दर पर हैं।

13.90 भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 राज्य वित्तीय निगमों को (तमिलनाडु औद्योगिक और निवेश निगम सहित) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत तदर्थ बांडों की जमानत पर वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के लिए कुल 98.23 करोड़ रुपये की तदर्थ ऋण सीमा मंजूर की। ये सीमाएं 25 जून 1991 तक वैध थीं और वास्तव में लिये गये ऋणों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की बैंक दर पर व्याज लगाया गया। 30 अप्रैल, 1991 को इन तदर्थ सीमाओं के अन्तर्गत कुल बकाया राशि 30.78 करोड़ रुपये थी (इसमें 30 अप्रैल 1991 को 10 राज्य वित्तीय निगमों और 31 मार्च, 1991 को 5 राज्य वित्तीय निगमों की बकाया राशि शामिल है)।

वायदा प्रभाव

13.91 ऋण कर्ताओं को स्वीकृत कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के उपयोग न किए गए हिस्सों पर न्यूनतम वायदा प्रभाव वसूल करने के बारे में रिपोर्ट के भाग I में उल्लेख किया गया है। तथापि, निम्नलिखित

सीमाओं को इन शर्तों से छूट दी गई है (क) रुग्ण/कमजोर इकाइयों को स्वीकृत कार्यकारी पूंजीगत सीमाएं (ख) निर्यात ऋण के लिए स्वीकृत सीमाओं (पोतलदानपूर्व और पोत लदानोत्तर दोनों के लिए) तथा निर्यात प्रोत्साहनों, जैसे शुल्क वापसी, नकद क्षतिपूर्क समर्थन इत्यादि पर स्वीकृत सीमाएं (ग) खरीदे गए/भुनाए गए बिलों अथवा वसूली के लिए बिलों पर ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण सीमा/उप सीमा के रूप में प्रदत्त देशी बिल सीमाएं (घ) भूमि विकास बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सहकारी बैंकों को स्वीकृत की गई ऋण सीमाएं। 9 मई से 30 सितम्बर 1991 के दौरान बड़ी नकदी ऋण सीमाओं के अधीन आहरणों पर लगाये गए प्रतिबंधों को देखते हुए बैंकों को सूचित किया गया था कि इस अवधि के दौरान वे ऋणकर्ताओं को स्वीकृत कार्यकारी पूंजीगत सीमाओं के उपयोग न किए गए हिस्से पर प्रतिशत वार्षिक की दर वसूली किये जाने वाले न्यूनतम वायदा प्रभार के अंतर्ध में भारतीय रिजर्व बैंक अनुदेशों को स्विकृत कर दें।

सह स्वीकृत गारंटियों जारी करना—

13.92 भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्त कि बैंकों को वित्तीय संस्थाओं (जहां वित्तीय संस्थाएं किसी प्रस्ताव का मूल्यांकन करती हैं और ऋण जोखिम उठाती हैं) के पक्ष में गारंटियों का निष्पादन नहीं करना चाहिए, के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा परिचालित खरीदार ऋण सुविधा योजना के अधीन वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में गारंटियों/सह-स्वीकृतियों का निष्पादन नहीं करना चाहिए।

#### 14. सहकारी बैंकिंग से संबंधित गतिविधियां

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

प्रगति

14.1 वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के दौरान बैंकिंग व्यवसाय प्रारम्भ करने और/या चलाने के लिए 10 नये प्राथमिक सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी किये गये। एक बैंक (कुन्दरा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. कुन्दरा) को बैंकिंग व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस देने से इंकार किया गया था क्योंकि पंजीयक, सहकारी समितियां, केरल द्वारा परिसमापन के अन्तर्गत इस बैंक को लिये जाने की सूचना मिली थी। प्राथमिक सहकारी बैंकों की सूची में से एक प्राथमिक सहकारी बैंक और एक वेतन-भोगियों के बैंक को हटाने के बाद जून 1991 की समाप्ति पर देश में प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या (93 वेतनभोगियों के बैंकों, 38 महिला बैंकों और 49 परिसमापन के अधीन बैंकों को मिलाकर) 1397 थी, इनमें से जून 1991 की समाप्ति पर बैंकिंग व्यवसाय करने हेतु लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल संख्या जून 1990 की समाप्ति पर विद्यमान 1,013 से 1,028 तक बढ़ गयी थी।

14.2 रिजर्व बैंक ने नये प्राथमिक सहकारी बैंक स्थापित करने और समितियों को प्राथमिक सहकारी बैंकों के रूप में परिवर्तित करने सहित अन्य संबंधित विषयों के संबंध में वर्तमान नीति की समीक्षा करने के लिए श्री एस. एस. मराठे, सदस्य, केन्द्रीय निदेशक बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

14.3 दिसम्बर 1990 की समाप्ति पर प्राथमिक सहकारी बैंकों के कार्यालयों की संख्या जून, 1990 की समाप्ति पर विद्यमान 3,358 की तुलना में 3,391 (अनंतिम) रही। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए 1991-92 से 1993-94 तक के तीन वर्षों की अवधि को सम्मिलित करते हुए नई शाखा लाइसेंसीकरण नीति बनाई गई है और केन्द्रीय आर्बिट्रि करने के लिए प्राप्त आवेदन विचाराधीन हैं।

14.4 तीन और बैंक, जो सभी महाराष्ट्र में हैं, अर्थात् वसई कैथलिक को-ऑपरेटिव बैंक लि. वसई, काजूमूस को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे और न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. बम्बई को 1 दिसम्बर 1990 से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। इसके साथ अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों की कुल

संख्या जून 1990 की समाप्ति पर विद्यमान 11 से 14 (महाराष्ट्र 11 और गुजरात 3) तक बढ़ी।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

14.5 जून 1990 की समाप्ति पर 579 रिपोर्टिंग प्राथमिक सहकारी बैंकों में से 398 बैंकों ने निर्धारित लक्ष्य अर्थात् प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार हेतु अपने कुल अग्रिमों का 60 प्रतिशत प्राप्त किया था तथा 416 बैंकों ने निर्धारित उप लक्ष्य, अर्थात् कमजोर वर्गों को उधार हेतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का 25 प्रतिशत प्राप्त किया था। रिपोर्टिंग बैंकों के विषय में ऐसे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम कुल 1,703.33 करोड़ रुपये थे जो कि उनके कुल बकाया अग्रिमों का 63.1 प्रतिशत थे।

जमा राशियों पर ब्याज-दर

14.6 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के पास अब तक देशी बचत और सावधि जमा राशियों पर 1.0 प्रति वर्ष से अधिक दर पर अतिरिक्त ब्याज की अनुमति देने का विवेकाधीन अधिकार रहा है। सावधि जमा राशियों के संबंध में अब उपलब्ध उच्चतर ब्याज दरों को ध्यान में रखते हुए 24 जुलाई 1991 से अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों के संबंध में इस प्रकार की परिपक्वता-अवधि वाली सावधि जमा राशियों के लिए 0.5 प्रतिशत अंक से अधिक की सीमा तक कम कर दिया है। तैर-अनुसूचित प्राथमिक शहरी बैंकों के लिए 3 वर्ष और उससे अधिक की अधिकतम परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियों हेतु उसकी 0.5 प्रतिशत अंक ब्याज का विवेकाधिकार निर्धारित किया गया है; अन्य परिपक्वता-अवधियों के लिए यह 1.0 प्रतिशत अंक रखा गया है। सभी प्राथमिक सहकारी बैंकों को बचत जमा राशियों के लिए भी अनुमत अतिरिक्त ब्याज 1.0 प्रतिशत अंक से अधिक की दर पर रखा गया है।

अग्रिमों पर ब्याज दर

14.7 वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज-दरों का मुक्तिकरण करने के बाद प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए भी ऐसा ही प्रयोग किया गया तथा एक नयी ब्याज दर संरचना उनके आकार और छोटे आकार वाले ऋणों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए 1 जून 1991 से निर्धारित की गयी। इसके पश्चात्, वाणिज्य बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज दरों में आगे और वृद्धि होने के परिणाम-स्वरूप 24 जुलाई 1991 से प्राथमिक सहकारी बैंकों द्वारा अग्रिमों पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों के संबंध में ऐसी ही वृद्धि लागू की गयी। सामान्य श्रेणी (अर्थात् रियायती दरों को छोड़कर अन्य) के संबंध में उक्त वृद्धि 2 लाख रुपये तक के सभी आकारों के अग्रिमों के लिए 15.0 प्रतिशत से 16.5 प्रतिशत तक एवं 2 लाख से अधिक के अग्रिमों के लिए 17.0 प्रतिशत (न्यूनतम) से 18.5 प्रतिशत (न्यूनतम) तक के दायरे में प्रत्येक 0.5 प्रतिशत अंक थी।

अग्रिमों पर अधिकतम सीमा

14.8 प्राथमिक सहकारी बैंकों के ग्राहकों द्वारा हेराफेरी के कार्य-कलापों को निर्मित करने के उद्देश्य से यह अनुदेश दिया गया था कि "वसूली के लिए भेजे गये चेकों" (स्थानीय और बाहरी-बैंकों) के आधार पर अनुमत आहरणों को आरक्षित अग्रिम माना जाएगा और वे रिजर्व बैंक द्वारा इस विषय पर जारी किये गये निर्देशों के अधीन होंगे। निम्नलिखित स्थानों पर स्थित समाशोधन गृहों के प्राधिकारियों को भी सूचित किया गया था कि वे अनुकूल समाशोधन शेषराशियों के उपयोग को निर्मित करने वाले सदस्यों द्वारा उपयुक्त नियमों का पालन होना सुनिश्चित करें जिससे कि वापस प्राप्त चेकों का समाशोधन होने से पहले ऐसी निधिओं का उनके द्वारा उपयोग रोका जा सके। 20 मई 1991 से 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक परंतु 10 करोड़ रुपये से कम तथा 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक की मांग और सावधि देयताओं वाले

प्राथमिक सहकारी बैंकों के संबंध में व्यापार, वाणिज्य, कुटीर और लघु उद्योग तथा अभिव्यक्त उद्देश्यों के लिए एक निदेशक (रिस्तेदारों सहित) अध्याय: किसी भी अन्य एकल पार्टी/संबंधित समूह को आरक्षित अधियों पर अधिकतम सीमाओं में क्रमशः 25,000 रुपये और 53,000 रुपये तक उध्वमुखी संगोष्ठन किया गया था।

#### पट्टेदारों/किराया खराद का वित्तपोषण

14.9 जिन प्राथमिक सहकारी बैंकों का कार्यकारी पञ्चोक्त निधियुक्त 25 करोड़ रुपये और उचित आधिकार हैं, उन्हें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के साथ गृहयोजना-संबंध व्यवस्था रखने वाला पट्टेदारों/किराया खराद कंपनियों का वित्तपोषण प्रारंभ करने का अनुमति दी गई थी।

#### प्रारंभिक नकदा निधि अनुदान में वृद्धि

14.10 ग्यारह अनुसूचित प्राथमिक (गृहरी) बैंकों से अपेक्षित है कि वे 13 जुलाई 1991 से शुरू होने वाले पञ्चवाड़े में भारत में अपनी मांग और मांवादी देशताओं के 6 प्रतिशत से अधिक आरक्षित नकदा निधि अनुदान (सीआरआर) बनाये रखें जब कि अन्य तक उनके द्वारा अनुसूचित यह अनुदान न्यूनतम 3 प्रतिशत रहा। शेष तीन अनुसूचित प्राथमिक (गृहरी) सहकारी बैंक, जो कि हाथ ही में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1944 की दूसरी अनुसूची में शामिल किये गये थे, जनवरी 11, 1992 में शुरू होने वाले पञ्चवाड़े में, 6 प्रतिशत से अधिक आरक्षित नकदा निधि अनुदान बनाये रखेंगे।

#### पुनर्वित्त सुविधाएं

14.11 पिछले वर्ष में 53 प्राथमिक सहकारी बैंकों के निमित्त स्वीकृत 20.71 करोड़ रुपये का तुलना में वित्तीय वर्ष 1990-91 के दौरान कुटीर लघु औद्योगिक इकाइयों का कार्यकारी पञ्चोक्त आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए 37 प्राथमिक सहकारी बैंकों के निमित्त राज्य सहकारी बैंकों को रियायती ब्याज दर (बैंक दर से 2.5 प्रतिशत कम) पर कुल 18.33 करोड़ रुपये की अवकाशीय ऋण सीमाएं मंजूर की गईं। 31 मार्च 1991 की स्थिति के अनुसार इन ऋण सीमाओं के संबंध में पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि में बकाया 18.70 करोड़ रुपये की तुलना में 16.22 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी।

#### ऋण गारंटी योजना

14.12 विशेष बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (ओआईसीजीसी) द्वारा संचालित लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 और लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत गारंटी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए लाइसेंस प्राप्त प्राथमिक सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से संयुक्त लाइसेंस-रहित प्राथमिक सहकारी बैंक पात्र हैं। जो प्राथमिक सहकारी बैंक इन दोनों योजनाओं में सम्मिलित हुए हैं उनकी संख्या दिसंबर 1990 की समाप्ति पर, पिछले वर्ष की तदनुसूची तारीख की क्रमशः विद्यमान 187 और 89 की तुलना में क्रमशः 191 और 90 रही।

14.13 जून 1991 की समाप्ति पर 58 प्राथमिक सहकारी बैंकों को रूपों में अनिवार्य (साधारण/चिरंजी) खाने खोलने का अनुमति दी गई।

14.14 31 मार्च 1991 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय, नीर पर कमजोर बैंकों के रूप में वर्गीकृत प्राथमिक सहकारी बैंकों की संख्या 230 थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यता के मानकों को पूरा न करने हुए उनकी स्वाधिकृत निधियों में धार, कर्त, अधिव्यक्त के उच्च स्तर, बैंककारी वित्तियमन अधिनियम, 1949 (जैसा सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 31 (1) के अधिनियम के अनुसार अपेक्षित न्यूनतम शेयर पूंजी की शर्त पूरी न करने आदि के कारण इन्हें "कमजोर" बैंकों के

रूप में नामित किया गया। वर्ष के दौरान 3 प्राथमिक सरकारी बैंकों, अर्थात् वर्तमान को-ऑपरेटिव बैंक लि., मराठा मार्फेट फांफुस को-ऑपरेटिव बैंक लि., और बैभव को-ऑपरेटिव बैंक लि., को उनका असंतोष-जनक वित्तीय स्थिति और एक गंभीर चल-निधि संकट की ओर ध्रुवसर पत्ताखन-प्रणालियों के कारण बैंककारी वित्तियमन अधिनियम, 1949 (जैसा सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 35-क के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ जमाकर्तारों की भुगतान करने और विनिदिष्ट राशियों से अधिक खर्च करने पर प्रतिबंध लगाते हुए निवेश जारी किये गये थे। ऋणों की वसूली आदि के कारण उसका चल-निधि में पर्याप्त सुधार होने के बाद, निदेशों के अंतर्गत कार्य करने वाले आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लि., पुणे के मामले में जमाकर्तारों की देय राशि में 5,000 रुपये तक जमा राशियों के नवीकरण सहित नयी जमा राशियों की स्वीकृतियों और मृत जमानतों के आधार पर अधिम प्रदान करने में कुछ छूट दी गयी थी। 29 जून 1991 को कार्य समाप्ति पर दो सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद की दो डेवलपमेंट को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई के साथ मिलाया गया था।

#### निरीक्षण

14.15 1 जुलाई 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि के दौरान बैंककारी वित्तियमन अधिनियम, 1949 (जैसा सहकारी समितियों पर लागू है) की धारा 35 के अंतर्गत 494 प्राथमिक सहकारी बैंकों का सांविधिक निरीक्षण किया गया।

#### समितियां और कार्यकारी दल

14.16 गृहरी सहकारी बैंकों के लिए गठित स्थायी सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4) (ग) के साथ पठित धारा 17(2) (ख) के अंतर्गत पुनर्वित्त की संगोष्ठन योजना, (2) वर्तमान गृहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करना, (iii) महिला गृहरी सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली, आदि से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

#### राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक

##### (i) लाइसेंस

14.17 जुलाई 1990 से अप्रैल 1991 तक की अवधि में तीन राज्य सहकारी बैंकों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्रों में स्थित 5 केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए बैंककारी वित्तियमन अधिनियम, 1949 की धारा 3 के अंतर्गत लाइसेंस जारी किये गये थे।

##### (ii) ब्याज दरें

14.18 वाणिज्य बैंकों की जमा राशियों पर ब्याज-दरों के संबंध में लागू किय गये आधिकारिक परिवर्तनों (जो कि पूर्व के खंड में वर्णित किये हैं) के समान ही राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की जमा राशियों की ब्याज दरों में भी तदनुसूची वृद्धि की गई थी। इस प्रकार जमा ब्याज-दरों में उध्वमुखी संगोष्ठन अप्रैल 1990 तथा अप्रैल और जुलाई 1991 के दौरान किये गये थे। 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज-दर के साथ तीन वर्ष और उससे अधिक अवधि वाली जमा राशियों की एक नयी श्रेणी 10 अक्टूबर 1990 से प्रारंभ की गई। 13 अप्रैल 1991 से, 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि की सीमायुक्त जमा राशियों पर ब्याज-दर 12.0 प्रतिशत तक एक प्रतिशत अंक बढ़ायी गयी। सीमायुक्त जमा ब्याज दरें 4 जुलाई 1991 से एकबारगी एक प्रतिशत अंक और बढ़ायी गयीं। उक्त संगोष्ठन राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों पर भी लागू हैं। इसके अलावा, राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने विवेक से, निर्धारित दरों से अधिकतम 1/4 प्रतिशत और 1/2 प्रतिशत के अनिवार्य ब्याज की अनुमति दे सकते हैं।

## 15. अन्य बैंकिंग गतिविधियाँ

## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

15.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम ने बैंकों में छोटे जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए निक्षेप बीमा स्कीम और सहभागी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत प्राथमिकता क्षेत्र प्रथियों की गारंटी देने के लिए पांच ऋण गारंटी स्कीमों (चार स्कीमों छोटे उधारकर्ताओं के लिए और एक स्कीम लघु उधारों के लिए) का परिचालन जारी रखा।

15.2 30 जून 1990 की स्थिति के अनुसार बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,917 थी जो बढ़कर 30 जून 1991 को 1,924 हो गई, जिनमें 16 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के 80 वाणिज्यिक बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,648 सहकारी बैंक शामिल हैं। 1,09,316 करोड़ रुपये की बीमाकृत जमा राशियाँ जून 1990 के अंत में कुल आकलन योग्य जमा राशियों का 69.7 प्रतिशत भाग हैं। कुल जमा खातों में से पूर्णतया रक्षित जमा खातों की संख्या 96.5 प्रतिशत होती है। वर्ष के दौरान इस निगम ने पांच वाणिज्यिक बैंकों और दो सहकारी बैंकों के दावों के निपटान में कुल 31.20 करोड़ रुपये की घन-राशि का भुगतान किया।

15.3 जून 1991 के अंत में लघु ऋण गारंटी स्कीम, 1971 में भाग लेने वाले बैंकों की कुल संख्या 258 थी, जिनमें 64 वाणिज्यिक बैंक और 194 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल थे। राज्य वित्तीय निगमों (एक राज्य औद्योगिक विकास निगम सहित) में से केवल दो ने अल्प ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी स्कीम, 1971 में भाग लिया। जून 1991 के अंत में 150 ऋण संस्थाओं ने सेवा सहकारी सोसाइटी गारंटी स्कीम में भाग लिया, जबकि लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी स्कीम में भाग लेने वाले प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 39 थी। उक्त चार स्कीमों के अंतर्गत मार्च 1990 के अंत में कुल गारंटीकृत प्रथिम 27,692 करोड़ रुपये के थे जो मार्च 1989 के अंत स्तर की तुलना में 8.2 प्रतिशत अधिक है।

15.4 निगम की अल्प ऋण (लघु उद्योग) गारंटी स्कीम 1981 भाग लेने वाली संस्थाओं की संख्या जून 1990 के अंत में 555 थी जो जून 1991 में घटकर 375 हो गई। लघु औद्योगिक क्षेत्र के गारंटीकृत-प्रथिमों में 19.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और ये मार्च 1989 के अंत में 14,094 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 1990 में 16,826 करोड़ रुपये हो गए।

15.5 जुलाई 1990 और जून 1991 के बीच निगम को छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी स्कीम के संदर्भ में 492.49 करोड़ रुपये के 19.90 लाख और लघु उद्योगों के लिए स्कीम के संदर्भ में 246.93 करोड़ रुपये के 0.82 लाख दावों प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान निगम ने छोटे उधारकर्ताओं के संदर्भ में 426.33 करोड़ रुपये के लिए 18.60 लाख दावों और लघु उद्योगों के संदर्भ में 239.36 करोड़ रुपये के लिए 0.80 लाख दावों का निपटान किया।

15.6 गारंटी शुल्क प्राप्ति, जो 1989-90 के दौरान दावों की प्राप्ति से अधिक था, 1990-91 में गारंटी दावों से 80.99 करोड़ रुपये कम हो गया। वर्ष 1990-91 के लिए गारंटी का भुगतान करने के लिए प्राथमिकता क्षेत्र को प्रथियों के कुछ वर्गों को शामिल न करने के निगम के निर्णय के परिणामस्वरूप शुल्क प्राप्ति (सकल) और दावों के बीच इस अंतराल की और बढ़ने की संभावना है।

गैर-बैंकिंग कंपनी विनियमवली निक्षेप सफारना नियंत्रण :

15.7 जून 1991 को समाप्त वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय, विविध गैर-बैंकिंग और शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों को जारी

निदेशों के सेट में संशोधनों को माध्यम से विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। निदेशों में कुछ संशोधन किए गए हैं जिनके अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों अपनी जमा राशियों पर व्याज की अधिकतम दर का भुगतान कर सकती हैं उसे 27 जुलाई 1991 से प्रभावी करने हुए 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। किराया खरोद और पट्टादारी कंपनियों द्वारा बैंकों के पास जमा राशि और या अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में नकदी परिपत्तियों के अनुक्षण की अपेक्षा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर, 1 नवंबर 1991 से 15 प्रतिशत कर दिया गया है। जमा राशि के लिए निर्धारित 24 माह की न्यूनतम अवधि में पहले ही जमा राशि आहरित किए जाने पर इन कंपनियों को ऐसे मामले में कोई भी व्याज देने से मनाकर दिया गया है। फिर भी, ये कंपनियाँ जमा राशियों की समाप्ति की तारीख से 6 माह की अवधि के पश्चात् जमा धनराशि के 75 प्रतिशत तक ऐसी जमा राशियों पर देय दर से 2 प्रतिशत अधिक दर पर ऋण दे सकती हैं।

चिट फंड अधिनियम, 1982

15.8 चिट फंड अधिनियम, 1982 के अंतर्गत शामिल राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या वर्ष 1990-91 के दौरान भी 19 ही रही। ये हैं—असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, मिझोरम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी। शेष राज्यों में आवश्यक, अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

अनिगमित निकायों द्वारा जमा राशियों की स्वीकार किया जाना :

15.9 चार और राज्यों ने 1990-91 के दौरान अधिवृत्तान्ता जारी करके उपयुक्त अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 टी और 58 ई के अनुसार अनिगमित निकायों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। इसके साथ ही, ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल संख्या 27 हो गई है। अन्य राज्यों में भी इस मामले का अनुशीलन किया जा रहा है। गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में स्थित जिन 129 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान के नौ निकाय भी शामिल हैं) निकायों की बैंक द्वारा राज्य पुलिस सहायक अधिकारियों की सहायता से जांच पड़ताल की गई उनमें से 19 के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III सी के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। ये मुकदमें सुनवाई के भ्रम्य अलग स्तरों पर हैं।

गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र के पास जमा राशियों में वृद्धि प्रवृत्तियाँ :

15.10 अस्थायी आंकड़ों में रिपोर्ट देने वाली 9,057 गैर-बैंकिंग कंपनियों की कुल जमा राशियाँ 31 मार्च 1990 की समाप्त वर्ष के अंत में 32,216 करोड़ रुपये की थी, इसकी तुलना में मार्च 1989 के अंत में 10,197 कंपनियों के पास 29,208 करोड़ रुपये की जमा राशियाँ थी। गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास कुल जमा का 64.4 प्रतिशत, वित्तीय कंपनियों के पास 30 प्रतिशत और विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों तथा शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों के पास 5.4 प्रतिशत है। 1989-90 के दौरान सूचना देने वाली गैर-बैंकिंग कंपनियों की विनियमित जमा में 443 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और यह 6,518 करोड़ रुपये हो गई, जबकि छूट प्राप्त जमा राशियाँ, 2,565 करोड़ रुपये बढ़कर 25,698 करोड़ रुपये हो गई। गैर-बैंकिंग क्षेत्र की विनियमित जमा राशियाँ 1988-89 के 6,075 करोड़ रुपये से बढ़कर 1989-90 में 6,518 करोड़ रुपये हो गई जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमा राशियों का 3.7 प्रतिशत है। 1989-90 के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की विनियमित जमा राशियाँ 4,044 करोड़ रुपये हो गई जबकि वित्तीय कंपनियों का राशि बढ़कर 1,585 करोड़ रुपये पहुँच गई। गैर-बैंकिंग कंपनी क्षेत्र में जमा राशियों वृद्धि वाला विवरण सारणी 15.1 में दिया गया है।



सारणी 15.1 : गैर-बैंकिंग नियमित क्षेत्र के पास अमा राशिदा

(करौड़ रुपये)

(मार्च के अन्त में स्थिति)

वर्ग	1988-89				1989-90 (अस्थायी)			
	रिपोर्ट देने वाली कंपनियों की संख्या	दिनियमित जमा राशियाँ	छूट प्राप्त जमा राशियाँ	जोड़	रिपोर्ट देने वाली कंपनियों की संख्या	दिनियमित जमा राशियाँ	छूट प्राप्त जमा राशियाँ	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल जमा राशियाँ	10,197	6,075	23,133	29,028	9,057	6,518	25,698	32,216
इनमें से निम्नलिखित के पास जमा:								
(i) गैर-बैंकीय कंपनियाँ	2,531 (24.8)	3,901 (64.2)	14,219 (61.5)	18,120 (62.0)	2,438 (26.9)	4,044 (62.1)	16,759 (65.2)	20,803 (64.6)
(ii) वित्तीय कंपनियाँ	6,374 (62.5)	1,494 (24.6)	8,058 (34.8)	9,552 (32.7)	5,459 (60.3)	1,585 (24.3)	8,064 (31.4)	9,649 (30.0)
(iii) विविध गैर-बैंकिंग कंपनियों और शेष गैर-बैंकिंग कंपनियों	1,292 (12.7)	680 (11.2)	856 (3.7)	1,536 (5.3)	1,160 (12.8)	889 (13.6)	875 (3.4)	1,764 (5.4)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े यथास्थिति, रिपोर्ट करने वाली कंपनियों की कुल संख्या/दिनियमित छूट प्राप्त गुरुल अमा राशियों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

#### 16. विदेशी मुद्रा नियंत्रण से संबंधित गतिविधियाँ

आयात के लिए वित्त व्यवस्था : विशेष विनियम

16.1 जैसा कि इस रिपोर्ट के भाग I में उल्लेख किया गया था विदेशी मुद्रा प्रारंभित निधि की विपम स्थिति को देखते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा मात्र पत्र को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम नकदी माजिनों और सामान्य रूप से आयात के लिए वित्त व्यवस्था के नियामक का विशेष उल्लेख करते हुए अनुदेशों की श्रृंखला जारी की गई है। इन अनुदेशों में कुछ सीमा से अधिक या कुछ अन्य परिस्थितियों में किए गए आयात के लिए प्रेषण के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग का पुर्यातमोदन लेने की अपेक्षाएँ शामिल हैं। इस सम्बन्ध में, प्रारम्भिक शर्तों का विवरण और बाय में उनमें दी गई छूट विशेषकर निर्यात क्षेत्र पर कुशल केंद्रित करने हुए विस्तृत ध्येयों की रिपोर्ट के पिछले खण्ड के अनुच्छेद 13.10 से 13.25 में समय क्रम के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

#### 2.5 करोड़ रुपये से अधिक तुल्य राशि का प्रेषण

16.2 प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया कि 23 अप्रैल 1991 से विदेशी मुद्रा अनिवार्यता खाते और अनिवार्यता विदेशी खातों में धन की चुकीसी तथा अन्तर बैंक लेनदेनों को छोड़कर 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की तुल्य राशि की विदेशी मुद्रा के विक्रय या भुगतान या भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति को उधार देने के लिए किया जाने वाला हर लेनदेन, लेनदेन पूरा करने से पहले ही अनुमति के लिए विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के पास भेजा जाना चाहिए।

यह अपेक्षा रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही जारी की गयी और उपर्युक्त तारीख को प्रचलित रहने वाली किसी भी अनुमति के परिणामस्वरूप किए जाने वाले विदेशी मुद्रा के यथास्थिति, क्रय या किए जाने वाले भुगतान पर भी लागू होगा।

आस्थगित भुगतान के लिए आवश्यक बायदा खरीद निर्यात और आयात

16.3 प्राधिकृत व्यापारी आस्थगित आयात की शर्तों पर किए जाने वाले निर्यातों के मामलों में आवश्यक आधार पर बायदा दम संविदाएँ और आस्थगित आयात की शर्तों पर किए जारी गए आयात साहसैनों

के अंतर्गत किए जाने वाले आयातों के मामलों तथा विदेशी मुद्रा शर्तों की चुकीसी के लिए आवश्यक आधार पर बायदा विक्रय संविदाएँ कर सकते हैं। प्रारंभिक संविदा छः माह की अवधि के लिए हो सकती है और इसके पश्चात् जैसे जैसे प्रत्येक आस्थगित किस्म को लिया जाता है, बायदा संविदा की बकाया राशि को प्रत्येक बार छः माह की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि ही में, यह निर्णय लिया गया है कि ग्राहकों के विशिष्ट अनुबंध पर, प्राधिकृत व्यापारियों को छोटे-छोटे अंतरालों पर आवश्यक संविदाएँ करने की अनुमति दी जाए ताकि संबंधित ग्राहकों द्वारा देय लागत को कम किया जा सके।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों की अमरीकी डालरों का बायदा विक्रय

16.4 भारतीय रिजर्व बैंक पौड-स्टॉलिंग, अमरीकी डालर, ड्यूय मार्क और जापानी येन की तात्कालिक और बायदा खरीद, और पौड-स्टॉलिंग तथा अमरीकी डालर को केवल तात्कालिक बिक्री करना था। अन्तर-बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिति की समीक्षा करने पर रिजर्व बैंक ने 8 मई 1991 से बैंक के बम्बई कार्यालय में क्रमशः तीसरे और छठे महीने में सुपुर्देगी के विकल्प सहित छठे महीने पर सुपुर्देगी के लिए प्राधिकृत व्यापारियों की अमरीकी डालर को बायदा बिक्री करने का निर्णय लिया है ताकि आयात, ऋण चुकीसी हत्यादि के लिए किए गए प्रेषण जैसे बायदा या विशिष्ट व्यापारिक लेन-देन के लिए प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा अमरीकी डालर और अन्य चल मुद्राओं की बिक्री को पूरा किया जा सके। रिजर्व बैंक के पास बुक को गई अमरीकी डालर की बायदा खरीद की संविदा के अवधि विस्तार/निस्सीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है।

निर्यात आगामी की प्राप्ति की अनुमत पद्धति

16.5 अब तक सामान्यतः निर्यातकों की निर्यातों के लिए विदेशी जेताओं में बैंक ड्राफ्टों, मुगान आदेशों, बैंकों के चैकों, निजी चैकों, विदेशी मुद्रा नोटों या विदेशी मुद्रा में वाली जेकों के रूप में मोधे ही भुगतान प्राप्त करने को अनुमति नहीं दी जाती थी। रिजर्व बैंक ने अब प्राधिकृत व्यापारियों को उन मामलों में निर्यात प्रवेक्षों पर कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है जहाँ उनके निर्यातक ग्राहक ने प्रति पात लदान 7,500 अमरीकी डालर से अधिक के लिए विदेशी जेता द्वारा निर्यातक के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकों के चैक और निजी

चेक के रूप में भुगतान सीधे ही विदेशी ऋता से प्राप्त कर लिया हो, इस पर निम्नलिखित गतें लागू होंगी (i) लिखत प्राधिकृत व्यापारी के पास प्राप्त के सात दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाए और यह निर्यात के लिए भुगतान में सम्बद्ध हो, (ii) निर्यात दस्तावेज प्राधिकृत व्यापारी/शाखा जिसके पास लिखत की बसूलों के लिए प्रस्तुत किया जाता है, के माध्यम से भेजे गए हों, (iii) भुगतान अनुमोदित रीति से प्राप्त किया गया हो और (iv) लिखत की बसूलों के पश्चात् ही निर्यात किया गया है।

16.6 प्रति पौतलदान 7,500 अमरीकी डॉलर में अधिक या इसकी समतुल्य राशि के आवेदन पत्रों या भारत का यात्रा पर आय विदेशी ऋताओं द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों या विदेशी मुद्रा में यात्रा चेकों के रूप में भेजे गए भुगतान प्राप्त करने संबंधी आवेदन पत्रों को रिजर्व बैंक के पास वित्तराश भेजा जाता चाहिए।

16.7 इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक निर्यात के लिए प्रति पौतलदान 7,500 अमरीकी डॉलर में अधिक की उचित सीमा तक के भुगतानों को बैंक ड्राफ्टों, भुगतान आदेशों, बैंकों के चेकों और निजी घको के रूप में विदेशी ऋताओं से सीधे ही प्राप्त करने के लिए सामान्य अनुमति देने के लिए निर्यातकों से प्राप्त आवेदनों पर विचार कर सकता है। इस अनुमति में एक सीमा तक तक विदेशी मुद्रा नोटों और/या विदेशी मुद्रा में यात्रा चेकों के रूप में भुगतान प्राप्त करना शामिल होगा। इस प्रयोजन के लिए, सम्बंधित निर्यातक से अपेक्षित है कि वह प्राधिकृत व्यापारी की एक यात्रा नामित करें, जिसके पास वह किए जाने वाले सभी पौतलदानों के सम्बंध में दस्तावेजों की नोंद रखा और निर्यात के भुगतान के संबंध में प्राप्त बैंक ड्राफ्ट, बैंकों के चेकों, भुगतान आदेशों जैसे लिखतों की बसूलों के लिए प्रस्तुत करेगा। आवेदन पत्र प्राधिकृत व्यापारी का नामित शाखा के माध्यम से रिजर्व बैंक में प्रस्तुत किया जाएगा।

परेषित/परेषित की विदेश रियत एजेंटों को पौतलदान दस्तावेजों का सीधे ही भेजा जाता

16.8 रत्नों/प्रभिरत्नों तथा स्वर्ण और आभूषणों के निर्यातकों को अब यह सामान्य अनुमति दी गई है कि वे 15,000 अमरीकी डॉलर की विदेशी सीमा की तुलना में 25,000 अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य से अधिक राशि तक के गाल-अपेक्षा के संबंध में पौतलदान दस्तावेज परेषितियों को सीधे ही भेज दें।

विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा स्वीकार किया जाता

16.9 विदेशी पर्यटकों को विदेशी मुद्रा के परिवर्तन संबंधी अधिकारिक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से सीमा मुद्रा परिवर्तकों (होटलों और आई एम सी ए, आई डब्ल्यू सी ए इत्यादि जैसे खानदान और आवास सुविधाओं वाली अन्य संस्थाओं के अलावा) को किसी भी एक समय प्रति व्यक्ति 500 अमरीकी डॉलर या इसकी समतुल्य राशि का सीमा तक विदेशी मुद्रा नोटों/सिक्कों और यात्रा चेकों को रूप में परिचालित करने के लिए स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। उक्त अनुमति उन्हें अपने यात्राओं की उपलब्ध कराये गए सामान को और/या प्रदत्त वस्तुओं को यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा नोटों/सिक्कों और/या यात्रा चेकों में किए गए भुगतान को स्वीकार करने के लिए पत्र ही से दी गई अनुमति के अतिरिक्त है। मुद्रा-परिवर्तक के लक्ष्यधारक होटलों और आई एम सी ए, आई डब्ल्यू सी ए इत्यादि जैसे खानदान/आवास सुविधा वाली संस्थाओं के पास उपलब्ध कराए जाते हैं सामान और/या प्रदत्त वस्तुओं की यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने के साथ-साथ किसी भी व्यक्ति, पाठे वह होटल या संस्था में रहता हो या नहीं, से संबंधित रूप से विदेशी मुद्रा नोटों/सिक्कों और यात्रा चेकों की यात्रा से परिचालित करने के लिए पहले ही से बैंक का प्राधिकार प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में नकद-राशि को बनाये रखा

16.10 होटलों से इनर अन्य सीमा-मुद्रा-परिवर्तकों को 100 अमरीकी डॉलर या इसी मुद्राओं के लिए कुल सीमा तक इसकी समतुल्य से अधिक की लिखत नकद-राशि रखने का अनुमति है। यह निर्णय लिया गया है कि नकद-राशि को मात्रा का बढ़ाकर 1,000 अमरीकी डॉलर या इसी मुद्राओं के लिए इसकी समतुल्य राशि कर दी जाए।

निवासियों द्वारा विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण

16.11 रिजर्व बैंक द्वारा प्रदत्त सामान्य अनुमति के अंतर्गत, अब तक किसी भी व्यक्ति को यह अनुमति थी कि वह भारत के बाहर के निवासियों के लिए या किसी वैध देयता के निराकरण में 100 अमरीकी डॉलर या उसके बराबर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है, और उसके लिए यह आवश्यक था कि उक्त राशि की प्राप्ति की तारीख से आठ दिन के भीतर उसे किसी प्राधिकृत व्यापारी को अर्पित किया जाए। 100 अमरीकी डॉलर का इस सीमा को निम्नो कर 300 अमरीकी डॉलर कर दिया गया है।

तबथ परमिटरधारकों को अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता

16.12 वर्तमान विनियमों के अंतर्गत केवल बैंक परमिट या काफेस परमिटधारक फार्म/कम्पनियों को ही उनके विदेश जाने वाले प्रतिनिधियों के प्रयोग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाती थी। अब यह सुविधा तबथ परमिट पर बार-बार विदेश जाने वाले व्यक्तियों जैसे भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी, गौर्वजिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और आई डी बी, आई यू, टी, आई, जैसी अन्य विनीय संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए भी उपलब्ध करा दी गई है।

द्विपक्षीय खाना संधू के देशों की यात्रा करने के लिए विदेशी मुद्रा जारी किया जाता

16.13 द्विपक्षीय खाना संधू के देशों को व्यापार, अध्ययन-यात्रा और सम्मेलन, मेमिटर विचार गोष्ठी में सम्मिलित होने के लिए यात्रा करने वाले व्यक्तियों को अब अपना समस्त विदेशी मुद्रागत कोटा मुक्त विदेशी मुद्रा में लेने की अनुमति है भले ही रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियम के दैनिक मानों और परमिटों को रूप में ही व्यक्त किया जाता रहेगा। डाकटरी इलाज और उच्चतम शिक्षा के लिए जारी किये गये परमिटों के मामले में, सीमा स्तर पर वर्तमान में दी जा रही मुद्रा परिवर्तन सुविधाएं जारी रहेंगी। पंजीकरण, प्रवेश परीक्षा सदस्यता शुल्क इत्यादि जैसे उद्देश्यों के लिए बिना मुद्रा परिवर्तन सुविधाओं को रूप में ही प्रेषण करने की अनुमति पहले की तरह जारी रहेगी।

पड़ोसी देशों की यात्रा योजना के अंतर्गत भारीभास की यात्रा करने वाले यात्रियों को विविध प्रसार आवेदन सुविधा

16.14 पड़ोसी देशों की यात्रा योजना (एन टी एस) के अंतर्गत भारीभास की यात्रा करने वाले अनिवामी भारतीयों को यह अनुमति दी गयी है कि वे जब भूतल परिवहन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए विविध प्रसार आवेदन (एम सी ओ) सुविधा का लाभ उठावें। इस सुविधा का लाभ 15 या उससे अधिक के समूह में यात्रा करने वाले व्यक्ति प्रति व्यक्ति 150 अमरीकी डॉलर की सीमा तक उठाया जा सकता है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण यात्रा (एफ ई सी टी) कर की वापसी

16.15 विदेशी मुद्रा संरक्षण यात्रा कर नियमावली, 1987 के नियम 5 के उपनियम (i) के अनुसरण में, जिस विदेश यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा जारी की गयी हो, उसमें लौटने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर एफ ई सी टी कर की वापसी के लिए दावा किया जाता चाहिए। जिस अवधि के भीतर उक्त कर की वापसी के लिए दावा किया जा सकता है, उस अवधि को, रिजर्व बैंक को विनाश

27 फरवरी 1988 की अधिसूचना सं. एक ई आर ए. 73/58-आर.पी. के अनुसूचन में जिस अधि के शीतल अनुसूचन विदेशी मुद्रा का अनुसूचन किया जाना था, उस अधि के अनुसूचन बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने नियम (5) के उप नियम (i) को संशोधित कर दिया था जिसके जर्गि, एक ई सी टी कर की आपसी का दावा करने के लिए समय सीमा को विदेश शाखा में लौटने की गरीब में 90 दिन तक बढ़ा दिया गया है।

उच्चतर अधिनियमों के लिए विदेशी मुद्रा प्रत्यागोचन

16.16 1 जून 1990 से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नामित शाखाओं में विदेशों में उच्चतर अधिनियम के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के अधिकार प्रत्यागोचन किये गये हैं। इन बैंकों द्वारा नामित की गयी ऐसी शाखाओं की संख्या 328 है।

विशेषीकृत प्रशिक्षण

16.17 प्रतिष्ठित विदेश स्थित संस्थाओं में अत्यधिक विशेषीकृत शिक्षा क्षेत्र में जिस अधि के लिए उच्चतर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अधिकार प्रत्यागोचन किये गये हैं। इन बैंकों द्वारा नामित की गयी ऐसी शाखाओं की संख्या 328 है।

मासिक पेंशन के प्रत्यागोचन के संबंध में रिफ़ी गृहिष्ठा में बढोतरी

16.18 जो भारतीय राष्ट्रिक और भारतीय मूल के व्यक्ति अपने पहले के विदेशी नियोक्ताओं से विदेशी मुद्रा में पेंशन पाते हों और संपूर्ण पेंशन राशि को नियमित रूप से भारत में प्रत्यागोचन करने हों उन्हें यह अनुमति है कि वे अप्रैल 1990 और उसके बाद से आहरित और भारत को प्रत्यागोचन की गयी पेंशन के मंदर्ब में 25 प्रतिशत तक का उपयोग "स्वदेश लौटने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा पात्रता योजना" (रिफ़िज) के अंतर्गत शामिल किये गये विशिष्ट निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए करें। अप्रैल 1990 से पहले आहरित और भारत को प्रत्यागोचन पेंशन राशियों के लिए योजना के अंतर्गत पात्रता का प्रतिशत अब तक की तरह 10 प्रतिशत पर अपरिबर्तित रहा।

स्थानीय आनिध्य

16.19 भारतीय कम्पनियों द्वारा अनिवार्य निदेशकों के पांच दिन से अधिक के स्थानीय आनाम के लिए 3,000 रुपए दैनिक व्यय की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति दिन कर दिया गया है।

अनिवार्यियों द्वारा धरेलू वस्तुओं को देश से बाहर ले जाना

16.20 वर्तमान नियमावली के अंतर्गत जो यात्री नियत माल अमवाय नियमावली (एक्सपोर्ट बेगेज रूल) के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक वस्तुओं को भारत से बाहर ले जाना चाहते हैं, उन्हें उन मामलों को छोड़कर जहां उन्होंने विदेशी मुद्रा में भुगतान कर उन वस्तुओं को खरीदा हो, जो आर फार्म की अपेक्षा से छूट प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक की आवेदन करना पड़ता था। यह निष्पक्ष किया गया है कि भारतीय राष्ट्रियता/मूल के जो व्यक्ति विदेशों में रहते हों और जो अपनी भारत की अस्थायी यात्रा के दौरान अपने निवास के देश में निजी उपयोग के लिए खरीदी गयी 10,000 रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं को (मोने और चांदी से शरी वस्तुओं तथा भारत की व्यापार नियंत्रण विनियमावली के अंतर्गत आने वाली नियमित के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं को छोड़कर) अपने माय देश के बाहर ले जाने की अनुमति दी जाए, भले ही उन वस्तुओं का मूल्य उन्होंने अपने सामान्य अनिवार्यी रूपया खाते में से भुकाया हो। इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन किये जाने चाहिए।

सामान्य अनिवार्यी रूपया (एन आर ओ) खातों में जमा

16.21 भारतीय राष्ट्रिकता/मूल के अनिवार्यियों (अनिवार्यी) और मुख्यतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वाधिकृत विदेश स्थित कंपनी

निकायों द्वारा सामान्य अनिवार्यी रूपया खातों (एन आर ओ खाते) में लेनदेन करने से संबंधित वर्तमान विनियमों को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है :-

प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गयी है कि वे अनिवार्यी भारतीयों/विदेश स्थित कंपनी निकायों द्वारा बताये गये एन आर ओ खातों में बिना किसी सीमा के उन रूपया निधिओं को जमा करने का अनुमति दे जो खाताधारक के लिए वैध तरीके से देय था, जबकि पहले की सीमा एक महीने में 4,000 रुपये था और प्राधिकृत व्यापारी रिजर्व बैंक को पूर्व अनुमति लिए बिना 1,500 रुपये तक का व्यक्तिगत जमा करने की अनुमति दे सकता था। प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया है कि वे 10,000 रुपये से अधिक का व्यक्तिगत जमाओं के मंदर्ब से लेनदेन के वास्तविक संचा को सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों प्रमाण संग्रही और स्वयं की इस बात से आश्चर्यचकित कर ले कि इस जमा राशियों खाताधारक को वैध देय राशियों की होकर है। प्राधिकृत व्यापारियों को यह भी सूचित किया गया है कि खाताधारकों से (वर्तमान तथा नए) इस आदेश का एक वस्तुतः ले ले कि वे भारत में किया भी व्यक्त को रुपये में प्रतिर्णी करने पर या भारत में किसी अन्य तरीके से कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं करायेंगे।

प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली ऋण सीमाएं

(i) अनिवार्यी सामान्य खाता धारकों को

16.22 प्राधिकृत को अपने उन अनिवार्यी घटकों को, जो अनिवार्यी भारतीय हैं, निदेश से इतर प्रयोजनों के लिए अनिवार्यी (सामान्य) खातों में रखी गयी सावधि जमा राशियों को जमानत पर जिस सीमा तक ऋण और ओवरड्राफ्ट प्रदान करने के अधिकार दिये गये हैं, उसे 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

(ii) अनिवार्यी विदेशी खाता धारकों को

16.23 मध्य अनिवार्यी विदेशी खाताधारकों को अनिवार्यी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवार्यी खातों में रखी गयी सावधि जमा राशियों की जमानत पर, निदेश से इतर प्रयोजनों के लिए, प्रदान किये जाने वाले ऋणों/ओवरड्राफ्टों की सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये और बाव में और बढ़ा कर 10 लाख रुपये कर दिया गया। तथापि, ऐसे मामलों में अनिवार्यी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवार्यी जमा राशि के समायोजन द्वारा या विदेश के तथे आशक प्रणियों द्वारा चुकोती की जानी चाहिए।

(iii) निदेश करने के लिए अनिवार्यी (विदेशी) खाता धारकों को

16.24 प्राधिकृत व्यापारियों को अपने अनिवार्यी भारतीय घटकों को अनिवार्यी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवार्यी खातों में उनके द्वारा रखी गयी सावधि जमा राशियों की जमानत पर निमित्त-कार्य/औद्योगिक कार्यकलापों, अस्पतालों, थ्री स्टार या उच्चतर ग्रेड के होटलों, नौवहन, कम्प्यूटर साफ्टवेयर के विकास और तेल अन्वेषक सेवाओं के कार्य में लगी हुई/उन कार्य करने का प्रस्ताव रखने वाली भारतीय फर्मों/कंपनियों की पूंजी में गैर प्रत्यागोचन के आधार पर भारत में मोधे हो निदेश करने के प्रयोजन के लिए कनिष्ठ निर्दिष्ट शर्तों पर 10 लाख रुपये तक के ऋण/ओवरड्राफ्ट प्रदान करने के अधिकार दिये गये हैं। इससे पहले ऐसे आवेदन पत्रों को रिजर्व बैंक के पास विचारार्थ भेजने को आवश्यकता थी।

(iv) अनिवार्यी (विदेशी) खातों में रहने वाली सावधि जमा राशियों की जमानत पर निधामियों को

16.25 प्राधिकृत व्यापारियों से अब तक यह अपेक्षा की जाती थी कि वे भारत स्थित निवास व्यक्तियों फर्मों कंपनियों को अनिवार्यी (विदेशी) खातों में रखी गयी सावधि जमा राशियों की जमानत पर ऋण/ओवरड्राफ्ट प्रदान करने संबंधी आवेदन पत्रों को रिजर्व बैंक के पास भेज

वे। अब प्राधिकृत व्यापारियों में शक्तिया प्रत्यायोजित करते हुए उन्हें यह अनुमति दी गयी है कि वे ऐसे ऋण निम्नलिखित शर्तों पर बिना किसी सीमा के प्रदान करें :-

(क) निवासि व्यक्ति/कर्म कंपनी ऐसे ऋण/ओवरड्राफ्ट ले सके इस उद्देश्य से अपनी साक्षि अमाराशियों शिखर रखने के लिए सहमत होंगे बल्कि अनिवार्य जमाकर्ता के लिए कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष विवेका मुद्रागत प्रतिकर नहीं होता चाहिए।

(ख) ऋणों का अवधि, अनातन के रूप में स्वीकृत की गयी अनिवार्य विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवार्य साक्षि अमाराशियों की सममान्य परिपक्वता अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, अनिवार्य जमाकर्ता को प्राधिकृत व्यापारी को इस आशय का प्रत्यक्ष वचनप्रस्तुत करना होगा कि, कम से कम ऋण/ओवरड्राफ्ट को अवधि के दौरान वह अमाराशि वापस नहीं लेगा।

(ग) प्रदान किया जानेवाला ऋण/ओवरड्राफ्ट रिजर्व बैंक द्वारा ऋण के प्रयोजन के आधार पर नियमित मॉनिटर, ब्याज दर आदि के संदर्भ में समय-समय पर निश्चित किये जाने वाले विनियमों के अनुरूप होना चाहिए।

(घ) उक्त ऋण का निजी प्रयोजनों के लिए या कृषि/व्यावसायिक के कार्यकलापों या स्थावर संपदा के कारोबार से इतर कारोबारों कार्यकलाप जारी रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

अनिवार्य भारतीयों के अनिवार्य विदेशी खातों के बीच निधियों का अंतरण

16.26 यदि अंतरणकर्ता और अंतरिणी दोनों धनिष्ठ संबंधों हों तो उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर एक व्यक्ति के अनिवार्य विदेशी खाते में निधियों के अंतरण के लिए अब तक भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन आवश्यक था। अब निम्नलिखित परिस्थितियों में प्राधिकृत अधिकारियों को इस प्रकार के अंतरण कराने की शक्तिया प्रत्यायोजित की गयी है :-

(i) अंतरण वास्तविक निजी प्रयोजनों के लिए हों, अर्थात् बच्चों की शिक्षा, उपहार, खाताधारी का निजी व्यय इत्यादि।

(ii) यदि अंतरणकर्ता और अंतरिणी खाताधारक बाह्य समूह के देशों में निवास करते हैं अथवा अंतरणकर्ता और अंतरिणी दोनों द्विपक्षीय समूह के देशों के हों।

यदि इस प्रकार के अंतरण में एक बैंक ने दूसरे बैंक में निधियों का अंतरण शामिल है तो अंतरणकर्ता बैंक को यह प्रमाणित करना होगा कि जिस खाते से निधियों का अंतरण किया जाता है उस खाते को स्थिति अनिवार्य विदेशी खाते के रूप में है। उपहार के रूप में निधियों के अंतरण के लिए उपहार कर की अवायगी क अधीन अनुमति दी जाएगी। (यदि लागू हों)।

ईराक/कुवैत से आयात तथा उन्हें निर्यात करने और प्रेषण भेजने पर प्रतिबंध

16.27 ईराक और कुवैत के साथ व्यापार इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संकल्प के परिणामस्वरूप आयात निर्यात मुख्य नियंत्रक के बिनाक 5 अक्टूबर 1990 को एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार भारत से ईराक और कुवैत स्थित बन्दरगाह या स्थान में या ईराक कुवैत स्थित बन्दरगाह या स्थान से भारत के बन्दरगाह या उसके किसी स्थान को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सभी वस्तुओं के आयात-निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तदनुसार 11 अक्टूबर 1990 को सभी प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया कि वे ईराक और कुवैत को कोई प्रेषण न भेजें अथवा ईराकी सरकार के खाते में प्रेषण न भेजें या ईराक या कुवैत में स्थित अपनी किसी भी एजेंसी अथवा उनके राष्ट्रियों को कोई प्रेषण न भेजें और न ही ईराक या कुवैत के किसी निवासी व्यक्ति, फर्म या बैंक के साथ या किसी ईराकी राष्ट्रिक के साथ

रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना किसी प्रकार के लेनदेन करें। मध्य आयात-निर्यात नियंत्रक ने 14 मार्च 1991 में कुवैत के साथ व्यापार करने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। तदनुसार ईराक के साथ किये जाने वाले व्यापार पर लगा प्रतिबंध और सम्बन्ध ईराक और उसके राष्ट्रिकों को भेजे जाने वाले प्रेषणों पर लगी रोक जारी रहेगी।

कुवैत से लौटने वाले भारतीय नागरिकों को रियायतें

16.28 ईराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप कुवैत में उत्पन्न स्थिति के कारण कुवैत में रहने वाले जिन भारतीय राष्ट्रियों को मजबूर होकर भारत लौटना पड़ा उन्हें एक विशेष मामले के रूप में भारत में स्थित बैंकों में रखे गये अनिवार्य स्वदेशी खाते/विदेशी मुद्रा अनिवार्य खाते साथ ही विदेशी मुद्रा में रखे गये खाते तथा विदेशों में रखी गयी परिणामस्थितियों को प्रारम्भ में 31 मार्च तक और बाद में 30 जून 1991 तक जारी रखने की अनुमति दी गयी।

कुवैत से लौटने वाले भारतीयों को करेंसी नोट बदलने की सुविधा

16.29 विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अंतर्गत अब तक प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा नोटों के किये गये सभी क्रय उनकी जोखिम और जिम्मेवारी पर थे और उनके द्वारा खरीदी गयी अधिशेष विदेशी मुद्रा का विनियम मूल्य प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी ही व्यवस्था करनी थी। ईराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किये जाने के परिणाम तथापि, स्वरूप प्राधिकृत व्यापारियों को यह सूचित किया गया था कि वे कुवैत से भारत लौटने वाले भारतीयों को भारत स्थित सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों/बंदरगाहों पर 10 अगस्त 1990 से 5,000 रुपये की भारतीय मुद्रा के बराबर राशि को रु० 25-कुवैती दीनार की दर से परिवर्तन सुविधा प्रदान करें। 5,000 रुपये की जमा राशि बाद में 30 अगस्त 1990 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी थी। प्राधिकृत व्यापारियों से यह अपेक्षा की गयी कि वे खरीदे गये कुवैती दीनारों को सरकारी खाते में अपने पास रखें तथा उनकी मूल्य बमूली को लम्बित रखें। उनके द्वारा रुपये में की गयी अवायगी को प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक ने सामान्य खाते के नाम छालकर कर दी थी।

भारत और पोलैंड के बीच व्यापार और भुगतान लेनदेन

16.30 भारत और पोलैंड के बीच वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक स्वरूप के सभी लेनदेनों का भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में किया गया। भारत सरकार और पोलैंड की सरकार ने एक नया व्यापार और भुगतान करार किया है जिसके अनुसार वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक स्वरूप के सभी लेनदेनों का भुगतान पहली जनवरी 1991 से मुक्त विदेशी मुद्रा में किया जाएगा, अतः निर्यातकों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया कि पहली जनवरी 1991 को या इसके बाद भारत और पोलैंड में साल के निर्यात के लिए की गयी संधिवाओं के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान उन्हें अनुमत मुद्राओं में प्राप्त होना है, जैसे अमेरिकी डालर पौंड स्टर्लिंग इत्यादि जो संधिवाएं 31 दिसम्बर तक की गयी है उन्हें लिए पूर्ववत् अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना जारी रहेगा।

व्यापार-जर्मन जनवादी गणराज्य-व्यापार और भुगतान करार

16.31 जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में, जर्मन जनवादी गणराज्य और भारत सरकार के बीच भारतीय रुपया भुगतान व्यवस्था के भविष्य के बारे में बातचीत का आयोजन किया गया और इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देशों के बीच पहली नवम्बर 1985 को निष्पादित भारत-जर्मन जनवादी गणराज्य व्यापार करार 31 दिसम्बर 1990 तक अपरिवर्तनीय भारतीय रुपये में भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के आधार पर जारी रहेगा। जो पाठिया इन वस्तुओं के बारे में भी निर्बाध रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करना चाहती है, उनके लिए विशिष्ट मामलों में भारत सरकार ने अनुमति प्राप्त करना आवश्यक बना दिया गया। उपर्युक्त रुपया अवायगी प्रणाली के अतिरिक्त जर्मन जनवादी

गणराज्य से भारत की और भारत से जर्मन जनवादी गणराज्य की प्रतिष्ठित वस्तुओं के निर्यात में सम्बंधित द्विपक्षीय व्यापारिक लेन-देनों का भुगतान 28 दिसम्बर 1990 से 31 दिसम्बर 1990 तक की शेष अवधि के दौरान किसी भी निबन्धित रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में करने की अनुमति दी गयी।

16.32 पहली जनवरी 1991 से एकीकृत जर्मनी के साथ मुक्त विदेशी मुद्रा में लेन-देन किये जा रहे हैं। फिर भी, भारत जर्मनी जनवादी गणराज्य व्यापार करार के अनुसार 31 दिसम्बर 1990 तक रूपयों में की गयी संविदाओं में उत्पन्न भुगतान सम्बंधी शर्तियों का निपटारा संविदा की शर्तों के अनुसार करार जारी रहेगा।

#### परियोजना निर्यात

16.33 पहली जुलाई 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि के दौरान, परियोजना निर्यात के कार्यकारी दल ने 5027.59 करोड़ रुपये मूल्य के 104 प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया। इन प्रस्तावों में टन की संविदाओं के 68 प्रस्ताव शामिल हैं, जिनका मूल्य 4,089.07 करोड़ रुपये है।

#### विदेशों में सहयोगी संस्थाएँ/संयुक्त उद्यम

16.34 पहली जुलाई 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि के दौरान, भारतीय कंपनियों को विदेश में अपनी सहयोगी संस्थाएँ स्थापित करने की अनुमति देने वाले 5 प्रस्ताव तथा भारतीय कंपनियों को विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने में समर्थ बनाने वाले 25 प्रस्ताव स्वीकृत हुए।

#### विदेशों में कार्यालय खोलना

16.35 पहली जुलाई 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि के दौरान, भारतीय कंपनियों को विदेश में 32 व्यापार-कार्यालय, 61 गैर-व्यापारिक कार्यालय खोलने और 12 मामलों में प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अनुमति दी गयी।

#### भारत में कार्यालय खोलना

16.36 पहली जुलाई 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि के दौरान विदेशी कंपनियों को भारत में 70 संयुक्त कार्यालय, 16 प्रतिनिधि कार्यालय और 12 परियोजना कार्यालय खोलने की अनुमति दी गयी। जिनमें से निधियों का प्रंतरण करना प्रस्तावित हो। उपहार के रूप में निधियों के प्रंतरण की अनुमति दी जायेगी। यह प्रंतरण उपहार रूप की अवधारणा के अधीन होगा (यदि लागू हो)।

#### विदेशी मुद्रा अतिवसी खाता--आधानी लेन और ड्यूय मार्के खरीदना/बिकना

16.37 विदेशी मुद्रा अतिवसी योजना के अंतर्गत 13 अगस्त 1990 से आधानी लेन और ड्यूय मार्के के क्रय-विक्रय का सुविधा रिजर्व बैंक को कालगुर गाथा में भी उपलब्ध कराया गया। यह सुविधा बैंक के बंगलूर, बंबई/कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली कार्यालयों/शाखाओं में पहले से ही उपलब्ध है।

#### विदेशी मुद्रा अतिवसी खाते की जमा राशियाँ

16.38 अब भारत के प्राधिकृत व्यापारियों को 28 नवम्बर 1990 से कम्पिशन प्रदान करने की अनुमति दी गयी है। यह कम्पिशन विदेशी मुद्रा अतिवसी योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमा राशियों के एक प्रतिजन में अधिक नहीं होगा। दलालों को प्रदायगों को निःसंश्लिष्ट तक सीमित रखा जायेगा। (i) पेंशन योजना के अंतर्गत जुटायी गयी जमा राशियाँ, और (ii) विदेशी मुद्रा अतिवसी योजना के अंतर्गत 2.5 मिलियन अमरीकी डॉलर की शेष प्रत्येक जमा राशि तक इस प्रकार की जमा राशियों की न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक रखना आवश्यक होगा।

#### मध्यपूर्व के लिए विदेशी मुद्रा अतिवसी--विशेष जमा योजना

16.39 मध्यपूर्व के देशों में रहने वाले अतिवसी भारतीय विदेशी निगमित निकायों की विशेष प्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए 20 अगस्त 1990 में एक नयी योजना लागू की गयी जिसका नाम "विदेशी मुद्रा अतिवसी खाता--विशेष जमा योजना" था। इस योजना के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारियों को यह अनुमति दी गयी कि वे मध्यपूर्व के देशों में स्थित अतिवसी भारतीय विदेशी निगमित निकायों के नाम केवल अमेरिकी डॉलर में शेषों बनते ऐसे खाते खोलने के लिए भारी खाताधारी द्वारा अपने निवासी देश में अवस्था वास्तु समूह के किसी अन्य देश से अनुमोदित पद्धति में निधियाँ अंतरित की गयी हों। देशवासीधारी के वर्तमान विदेशी मुद्रा अतिवसी खाते अतिवसी विदेशी खाते में से निधियाँ अंतरित करके अवस्था विदेशी मुद्रा के नोट और या यात्री चेक प्रस्तुत करके निर्धारित शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति भी दी गयी। इन विशेष खातों से किये जा सकने वाले आहरणों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया और इसलिए इन खातों की जमा राशियों पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। इन खातों में रखी गयी निधियों की जमानत पर ऋण/घोबरड्राफ्ट नहीं दिया जा सकता। विदेशी मुद्रा अतिवसी खातों पर जो अर्थ उपबंध लागू होते हैं, वही उपबंध प्रावश्यक परिवर्तनों के साथ इन विशेष खातों पर लागू हैं।

16.40 बाद में, यह निर्णय किया गया कि यदि इन खातों में और राशि जमा नहीं की जाती अवस्था उममें में राशि आहरित नहीं की जाती और जमा राशि बैंक के पास कम से कम 6 महीने की अवधि तक रहनी है तो बैंक ऐसी जमा राशियों पर ब्याज भुगतान कर सकता है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक जमा राशि खाता ब्याज के लिए तभी पात्र होगा जब यह खाता 6 महीने या इससे अधिक अवधि तक रखा गया हो अवस्था उममें किसी प्रकार का लेन-देन न किया गया हो। इससे इन खातों की मीथारी जमा राशि खातों का स्वरूप प्राप्त होगा। ऐसे मामलों में ब्याज दर वही होगी जो अमेरिकी डॉलर में दर्शायी गयी है और उस अवधि के लिए देय होगी जिस अवधि तक वे बैंक में रही हों।

#### विदेशी मुद्रा (साधारण--अप्रत्यावर्तनीय) अतिवसी योजना

16.41 विदेशों में रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयकता मुन के व्यक्तियों तथा अतिवसी भारतीयों के अधिकतम स्थायित्व वाले विदेश स्थित कानूनी निकायों को भारत में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन देने तथा अधिक बिलम्ब प्रदान करने की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने 17 जून 1991 से एक नयी जमा खाता योजना अर्थात् विदेशी मुद्रा (साधारण--अप्रत्यावर्तनीय) जमा खाता योजना शुरू की। इस योजना के अधीन स्वोकार की गयी जमा राशियाँ पाँच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए अमरीकी डॉलर में रखनी होती है। इस पर देय ब्याज दर विदेशी मुद्रा अतिवसी खाते में तब तक की अवधि के लिए डॉलर में रखी जमा राशियों पर उपयुक्त खाते की जमा राशि की तारीख को लागू ब्याज दर से एक प्रतिशत अधिक होगी। जमाकर्ताओं की जमा राशि को जमानत पर ऋण/घोबरड्राफ्ट को उपलब्धता तथा भारतीय प्राय कर एवं मर्यादा कर के अधीन कर से छूट के कतिपय लाभ भी प्राप्त होते हैं। एक बार उपहार दिये जाने के मामले में यह जमा राशि उपहार कर में भी छूट-प्राप्त होगी। निश्चित अवधि से पूर्व जमा राशि के आहरणों की अनुमति है तथा ऐसे मामलों में वह ब्याज दर देय होगी जो जमा राशि की तारीख को उस अवधि के लिए देय ब्याज दर है जितनी अवधि तक जमा राशि बैंक में रखी जानी है। किन्तु इस प्रकार आहरित अवस्था अवधि समाप्ति पर प्राप्त ब्याज सहित राशि के समकक्ष अवस्था जमा राशि-आय के अतिवसी साधारण रूप से खाते में जमा करनी होगी।

#### भारत ईक्विटी फंड यूनिट योजना--1990

16.42 भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपने "भारत ईक्विटी फंड यूनिट योजना 1990" नामक विशेष यूनिट के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों में निवेश करने के लिए विदेशों से 100 मिलियन अमरीकी डॉलर

तथा की निधिवा जूटाने के लिए निहित निधिवा का प्राप्ति को के मांग प्रारम्भ करने की अनुमति दी गयी।

16.43 यथावर्तनीय प्राध्याय पर अनिवार्य भारतीय राष्ट्रीय/मूल के लोगों को भारतीय स्टेट बैंक को दूसरी सीरीज के अनिवार्य भारतीय बाह्य जारी करने की अनुमति दी गयी है। इस योजना की विवेक मांग इस प्रकार है :

- (क) भारत के प्राधिकृत व्यापारियों का उपयुक्त बांडों की जमानत पर अनिवार्य भारतीय बांड धारकों को स्वयं कृण देने की अनुमति दी गयी है।
- (ख) ये बांड बिना किसी प्रतिबंध के और उपहार कर अधिनियम के प्रावधानों की बिना प्राकृत करते हुए केवल एक बार मूल धारक अथवा अनिवार्य—भारतीय अंतरिनी किसी भारतीय राष्ट्रिकता अथवा मूल के व्यक्ति को उपहार स्वरूप दे सकता है, चाहे वह भारतीय निवासी हो अथवा नहीं, या किसी ऐसे भारतीय धर्मार्थ ट्रस्ट को दे सकता है जो प्रायकर अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।
- (ग) अनिवार्य भारतीय और निवासी भारतीय, जिनका प्राप्त में नगदीकी रिश्वतदार होना आवश्यक नहीं है वे भी संयुक्त रूप से बांडों के प्रायक बन सकते हैं।

#### भारतीय विकास निधि (साइ ओ एफ)

16.44 इंडियन बैंक का तीदरुंड में अग्रणीय निधि की स्थापना करने की अनुमति दी गयी है जिसका नाम भारतीय विकास निधि (साइ ओ एफ) है। यह निधि प्रिटेन के पर्येष्यप्राल ऑफिशोर की सहायता से विदेशों में निधि जुटाने के लिए स्थापित की गई ताकि इंडियन बैंक द्वारा इंड बैंक (अग्रणीय) म्युचुअल फंड की सुविधा में भारत में निवेश करने के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि जुटा सकेगा।

अग्रत्यावर्तन प्राध्याय सीन—वर्षीय—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूंजीगत बांडों की शोषविधि पंजीगत लाभ का अनिवार्य भारतीयों द्वारा पुननिवेश

16.45 निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को सीन-वर्षीय-भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूंजीगत बांड अग्रत्यावर्तन प्राध्याय पर अनिवार्य भारतीयों को जारी करने की सामान्य अनुमति दी गयी है :

- (क) भविष्य में किसी भी समय न तो पूंजी निवेश और न ही अग्रित भाग को भारत के बाह्य प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दी जाएगी; और
- (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूंजीगत बांडों के वर्षीय व्याज उपपक्ष और परिपक्वता प्राप्तिवा निवेशकर्ता के उस प्राधिकृत बैंक के अनिवार्य (सामान्य) शान में डाल दी जाएगी जो भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्य करता है।

#### 17. संगठनात्मक मायसे और बैंक के लेखे

##### करंसी चेस्ट

17.1 करंसी चेस्टों की कुल संख्या गत वर्ष के 3,938 से बढ़कर जून 1991 के अंत में 4,006 हो गयी। रिजर्व बैंक के पास करंसी चेस्टों की संख्या, जो 17 थी, में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहयोगी बैंकों के करंसी चेस्ट बढ़ कर 2,790 हो गये। राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास 649 चेस्ट 545 कोषागार तथा उन कोषागार और जम्मु तथा कश्मीर बैंक लिमिटेड के पास 5 थे। इसके अतिरिक्त 505 निशेषागार गणतंत्री क्षेत्रों के बैंकों में बैंकों में रखे थे।

17.2 हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि करंसी चेस्टों को स्थापित करने और रखरखाव की जिम्मेदारी खुनिदा अनुमति निजी क्षेत्र

के बैंकों को इस शर्त पर दी जाये कि वे बैंक के उन मानदण्डों का पालन करें जो इसके लिए निर्धारित किये गये थे।

#### मुद्रा प्रबंध समिति

17.3 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि 30 सितंबर 1990 को मुद्रा प्रबंध समिति से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद एक स्थायी दल और एक छोटी प्रांतरिक समिति प्रमण: बिन मन्त्रालय और रिजर्व बैंक ने गठित की ताकि प्रमण: सरकार और रिजर्व बैंक से संबंधित मामलों में रिपोर्ट के कार्यान्वयन और सिफारिशों को लागू किया जा सके। स्थायी दल की शान्तीन के अलावा, भारत सरकार के माध्यम से विचार-विमर्श किये गये ताकि सिफारिशों के कार्यान्वयन में संबंधित कतिपय नीतिगत मामलों पर किये जा सकें।

#### मुद्रा प्रबंध के व्यापक उपाय

17.4 पिछले दशक में मुद्रा के संचलन में असाधारण वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप नये मुद्रा/विक्रय नोटों की मांग में भी असाधारण वृद्धि हुई। नासिक तथा देवान में विश्वमान दो नोट मुद्रणालय, जिनकी उत्पादन श्रमता ज्यों की त्यों रही, मांग की पूर्ति करने की स्थिति में नहीं है। इस परिस्थिति के होने तथा मांग में और वृद्धि हो जाने के कारण नये नोटों की उपलब्धता में कमी हो गयी। सरकार द्वारा वर्तमान दो नोट मुद्रणालयों के प्राध्वनिकीकरण, रिजर्व बैंक द्वारा दो नये नोट मुद्रणालयों की स्थापना तथा 1 रुपये, 2/5 रुपये एवं 5/- रुपये के मुख्य वर्ग के नोटों, जो संचलन बलि नोटों का एक बहुत बड़ा भाग है, का विभिन्न वर्णों में सिक्के में बदलने की योजना से नये नोटों की उपलब्धता में सुधार होगा। छोटे सिक्कों की प्राप्ति की स्थिति अच्छी है और किसी भी प्रकार की मांग को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त स्टॉक है।

#### मुद्रा मज्जी पूर्वानुमान

17.5 रिजर्व बैंक ने मुद्रा की आवश्यकता से संबंधित पूर्वानुमान का कार्य भारतीय मौल्यकीय संस्थान, कलकत्ता को सौंपा था। इस संस्थान ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसमें दिये गये निष्कर्षों की समीक्षा रिजर्व बैंक कर रहा है।

#### नया नोट प्रेष परियोजना

17.6 मैमूर (कर्नाटक) और मलबोली (पश्चिम बंगाल) स्थित नया नोट प्रेष परियोजना, जो जनवरी 1990 में सरकार से भारतीय रिजर्व बैंक को दे दी गयी। बैंक नोटों के मुद्रण के लिए विभिन्न औद्योगिकियों का तकनीकी-आर्थिक पुनर्मूल्यांक भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा, सफल टेडरकर्ता के चयन संबंधी कार्य समाप्ति के अधिम चरणों में है। जहाँ तक प्रेषणाकृत छोटे मूल्यवर्ग के नोटों का मज्ज है, यह निर्णय लिया गया है कि वेद तकनीक के लिए टेडरकर्ताओं को प्रामाणिक किया जाये ताकि किन्हीं संभव विकल्पों का उल्लेख मूल्यांकन किया जाना संभव हो सके।

#### गर्वेशन

17.7 "विदेशी मुद्रा (अनिवासी) और अनिवार्य (बाह्य) प्रपदा याने—जुलाई 1985 से जून 1988 तक के परिणाम, जो परिणाम्य सर्ववि संबंधी पद्धति, निधियों के मांग तथा बाह्य दरों के अनुसार विदेशी अमात्राजियों को अर्पित करने हैं, भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धित के जून 1988 के अंक में प्रकाशित किये गये थे। 31 मार्च 1988 की समाप्ति संदर्भाधीत वर्ष के माध्य भारत की विदेशी देयताओं और प्राप्तियों के संबंध में पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था। जन गणता परिणामों की शामिल करने हुए भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धित, जुलाई 1989 में एक लेख प्रकाशित हुआ। जन गणता के अंशों की अद्यतन ज्ञानों के लिए यापिक विदेशी निवेश सर्वेशन (ए फकट्राएएम), मार्च 1988 के परिणामों का उपयोग किया गया था और मार्च 1988 की समाप्ति वर्ष के लिए अन्तिम अनुमानों सहित, मार्च 1988 के अंत तक भारत की विदेशी देयताओं और प्राप्तियों के मज्ज में एक लेख भारतीय रिजर्व बैंक वृद्धित

के अप्रैल 1991 के अंक में प्रकाशित किया गया था। वार्षिक विदेशी निवेश सर्वेक्षण, मार्च 1989 की आधार मानकर, मार्च 1989 के अंक की स्थिति अद्यतन बनाई जा रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कैलेडर वर्ष 1992 के दौरान उनके 48वें दौर में ग्रामिण भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण, 1991-92 किया जाएगा, बैंक सर्वेक्षण के लिए डिजाइन, अनुसूचियों, सारणी के फॉर्मेट आदि तकनीकी कार्य से सज्ज्य रूप से जुड़ा हुआ है।

कम्प्यूटीकरण में प्रगति

17.8 शहरी बैंक विभाग (केन्द्रीय कार्यालय), व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, परिसर विभाग, प्रबंधक सेवा विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग केन्द्रीय कार्यालय, आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, मुद्रा प्रबंध विभाग, निर्गम विभाग का दावा अनुभाग, बम्बई कार्यालय और उप गवर्नरों तथा गवर्नर सचिवालय के इस्तेमाल के लिए सी कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित की गई हैं। बाह्य निवेश और परिचालन विभाग तथा रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास के लिए अतिरिक्त प्रणालियों की आपूर्ति की गई थी। बैंकिंग परिवर्तन और विकास विभाग केन्द्रीय कार्यालय विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, सचिव विभाग, प्रबंध सेवा विभाग, और इतिहास कक्ष के लिए शब्द संसाधनों की व्यवस्था की जा चुकी है। भायखला, अहमदाबाद, नागपुर और नई दिल्ली के निर्गम विभाग में स्थापित की गई कम्प्यूटर प्रणालियों की जगह कोटि-उत्तम प्रणालियां स्थापित की गई हैं बंगलूर, हैदराबाद, कानपुर, विवेकानंद, जयपुर, मद्रास तथा पटना के निर्गम विभाग में कम्प्यूटर लगाये हैं।

17.9 सांख्यिकीय विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग में विद्यमान सी हनीवेल मेनफ्रेम कम्प्यूटर प्रणाली को स्टेट-ऑफ-द-आर्ट लाज मेनफ्रेम कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा, जिसमें आंकड़ों की निरंतर संचार व्यवस्था की सुविधा हो, प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया चालू है। बंबई स्थित कर्मचारियों के वेतन पत्रकों की बनाने के लिए उपयोग में लायी जाने वाली वर्तमान बी डी पी-101 माइक्रोप्रोसेसर प्रणाली को दी स्टेट-ऑफ-द-आर्ट मिनी कम्प्यूटर से करने की योजनाएं प्रतिस्थापित करने की योजनाएं अग्रिम चरण में हैं। औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग के केन्द्रीय कार्यालय, वित्तीय संस्था कक्ष तथा विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के सांख्यिकीय कार्यालयों के लिए निजी कम्प्यूटर प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। बाह्य वाणिज्यिक ऋणों को संसाधित करने के लिए वि. कामन्वेल्थ सॉफ्टवेयर सी एस-डी आर एस एस (वर्शन 4.5) को निजी कम्प्यूटर पर संस्थापित किया गया है और मार्च 1991 तक के सभी ऋणों के व्योरे का पहले से ही कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से अधिक क्षमतावाला वर्शन शीघ्र ही स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए, नवीनतम पी. सी. हार्डवेयर प्राप्त किया जा रहा है।

कार्यालय ऑटोमेशन

17.10 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, कामिक नीति विभाग और नई दिल्ली, मद्रास, तथा कलकत्ता कार्यालयों में फैक्स मशीनें लगायी जा चुकी हैं। यह निर्णय लिया गया है कि बम्बई स्थित केन्द्रीय कार्यालय के विभागों के इस्तेमाल के लिए कुछ और परिसरों में तथा शेष भवन कार्यालयों में फैक्स मशीनें लगायी जाएं।

17.11 मित्रांतर रूप में यह भी निर्णय लिया जा चुका है कि खात बहो प्रविष्टि मशीनों के स्थान पर बंबई, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलूर और हैदराबाद में उपलब्ध स्थानीय क्षेत्र नेट-वर्क व्यवस्थाओं के साथ विकास अन्तराखाता बहो प्रविष्टि मशीनें लगायी जाएं।

लक्ष्मीकांत झा स्मारक व्याख्यान

17.12 भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री लक्ष्मीकांत झा की रिजर्व बैंक और राष्ट्र के प्रति उनकी सराहनीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी यादगार बनाये रखने के लिए भी भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री लक्ष्मीकांत झा स्मारक व्याख्यान के नाम से वार्षिक व्याख्यान माला

प्रारंभ किया है। "इकानिम्सस लिबरलिज्म, सेंट्रल बैंकिंग एण्ड डि डेवलपिंग वर्ल्ड" नामक व्याख्यान बंबई में 16 अक्टूबर 1990 को बैंक आफ इंग्लैंड के गवर्नर श्री रॉबिन ली फिन्मैटन ने दिया।

सीएजा-सेंट्रल बैंकिंग पाठ्यक्रम

17.13 भारतीय रिजर्व बैंक 30 वर्षों के बाद दूसरी बार 18 वें दक्षिण पूर्व एशिया, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया (सीएजा) सेंट्रल बैंकिंग पाठ्यक्रम का मेजबान (होस्ट) था। पाठ्यक्रम का आयोजन 29 अक्टूबर से 14 दिसंबर 1990 तक इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, मोरगांव (बंबई) में किया गया। इस पाठ्यक्रम में सहभागियों की कुल संख्या 25 थी जिनमें से 3 सदस्य डारेक्टिंग स्टाफ के थे। मोरगांव (बंबई) दो (बांग्ला देश और न्यूजीलैंड) को छोड़कर पाठ्यक्रम में सभी सीएजा-सदस्य देशों ने प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त, कनाडा, तंजानिया, मूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और वनोतु (सहयोजित सदस्य) के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इंदिरा गांधी विकास संस्थान में "उपरोडिक्शन एण्ड ऑटोनोमी आफ सेंट्रल बैंक" पर हुई गवर्नरों की विचार-गोष्ठी के साथ पाठ्यक्रम पहले की तरह 14 दिसंबर 1990 को सम्पन्न हुआ और इसमें सीएजा, सेंट्रल बैंक के गवर्नर, उप-गवर्नर तथा अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। (जिसकी अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने की)।

रिजर्व बैंक का इतिहास

17.14 पिछले वर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि "भारतीय रिजर्व बैंक का इतिहास" के प्रकाशन के और खंड प्रकाशित करने के लिए एक ग्रंथ से इतिहास कक्ष स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कक्ष की स्थापना की गयी है और 1967 तक की गति-विधियों को शामिल करने हुए एक खंड का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान

17.15 बम्बई में बैंक द्वारा स्थापित किये गए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान ने खाद्य तथा उर्वरक सहायता, परिवहन क्षेत्र में तेल के स्थान पर गैस का इस्तेमाल और सुपर कंडक्टरों में भार एण्ड बी, नीति के लिए टेक्नालोजी मूल्यांकन के क्षेत्र में अध्ययन पूरे कर लिये हैं। वर्ष के दौरान, ऊर्जा, नीति, कृषि और ग्रामीण विकास नीतियों, औद्योगिक क्षेत्र, समष्टि आर्थिक तथा पैट्रिक नीतिगत मामलों, बाह्य क्षेत्र और परिवहन संबंधी मामलों में अध्ययन का कार्य जारी रहेगा। संस्थान द्वारा संगत विषयों पर सम्मेलनों और कार्यशालाएं भी आयोजित की गयीं। बम्बई विश्वविद्यालय से संबद्ध (अच्युपेशन) इस विकास नीति में 4 वषीय पी.एच.डी. कार्यक्रम 1990 में प्रारम्भ किया गया।

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, बम्बई

17.16 वर्ष के दौरान बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय द्वारा कम्प्यूटरीकृत पर्यावरण के अंतर्गत कम्प्यूटर सुरक्षा तथा बैंकों के लेखा परीक्षा संबंधी निरीक्षण लेखा परीक्षा कार्य कक्ष परिचालन, आस्थ पित भूगतान और परियोजना नियंत्रित, वित्तीय नवीन पद्धतियों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में उधर राशिधियों, सर्वजनात्मक और संगठनात्मक विशेषता और प्रवर्धकीय प्रम वशीलता एवं मूल्य प्रणाली कार्यक्रम प्रारम्भ किये गए।

17.17 वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने हिन्दी के 10 कार्यक्रमों अंतर्गत 104 कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें 2,085 प्रशिक्षण विधियों भाग लिया। इससे महाविद्यालय के 1954 में प्रारम्भ होने से अब तक प्रशिक्षित किये जागे जाने प्रशिक्षणविधियों की कुल संख्या

रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, मद्रास

17.18 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय व्यापक स्तरवाला तथा प्रयोजन मूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता रहा। इन कार्यक्रमों में 'ए' और 'बी' में वे सभी किये गये अधिकारियों के लिए और आर्थिक विश्लेषण और नीति तथा विश्लेषण और कम्प्यूटर सेवा विभाग के अनुसंधान अधिकारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों में शामिल हैं: राष्ट्रीय समाजीयन अधिकारियों के नि: (लिव्गट सोमायटी फार वल्वेवाइट इंटर बैंक फ इन्सिडल कम्प्यूटेशन) पी.सी. अनुप्रयोग, जी-बेस कार्यक्रम और कर्सेसी लैस्ट संबंधी निरीक्षण पर कार्यशाला।

17.19 वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 1,316 सहभागियों के लिए 69 कार्यक्रम चलाये। इनमें 1963 में महाविद्यालय की स्थापना में लेकल अब तक प्रशिक्षण सहभागियों की संख्या 26,863 हो गयी।

अधि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे

17.20 यह महाविद्यालय सहकारी बैंकों, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), रिजर्व बैंक और सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण आवश्यकता को पूरा करता रहा है वर्ष के दौरान महाविद्यालय द्वारा 2 नये कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये यर्षा (i) प्रारम्भिक सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लिए श्रृण मूल्यांकन और (ii) सेवा श्रेण योजना और गरीबी निवारण कार्यक्रम महाविद्यालय, बेकार भूमि का विकास, वन विकास वर्षा पर निर्भर होती (रेन फीड फार्मिंग और प्लास्टीकल्स और कृषि-जलवायु वाले क्षेत्र पर 4 दिन की एक गोण्टी का आयोजन भी किया। इसके अनिर्कृत एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय कृषि श्रृण संघ (ए.पी.आर.ए.सी.ए.) की ओर से जुलाई 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित किया।

17.21 वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने 2,078 अधिकारियों के लिए 94 कार्यक्रम आयोजित किये। इसमें 1969 में महाविद्यालय के प्रारम्भ होने से अब तक प्रशिक्षित किये गये अधिकारियों की संख्या बढ़कर 38,056 हो गयी।

17.22 वर्ष के दौरान बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा श्रेणी के 10,769 तथा खुर्च श्रेणी के 232 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया इससे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 38,100 तथा 2,689 हो गयी।

वाणिज्य बैंकों में प्रशिक्षण

17.23 वाणिज्य बैंकों में बैंक के अधिकारियों का प्रशिक्षण देने की योजना के अंतर्गत 1986 में इस योजना के आरंभ अब तक 76 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है फिलहाल 40 अधिकारियों का तीसरा बैच प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है वर्ष के दौरान वाणिज्य बैंकों के मुख्य विभागों की कार्यप्रणाली का गहराई से अध्ययन करने के लिए छह महीने की अवधि के लिए 4 बरिष्ठ अधिकारियों का चयन किया गया है।

कर्मचारियों की भारत और विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति

17.24 बैंक ने वर्ष के दौरान भारत के प्रबन्ध तंत्र/बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, विचार-मोडिफिकेशन और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए 275 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया है।

अधिकारियों ने स्पिट सेंटर फार डेवलपमेंट स्टडीज, लिवेन्स में व्यापक-समयिक अध्ययन में एम. फिल पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रहे हैं बैंक ने ए.ए.ए., यू.के., फ्रांस, स्विट्जरलैण्ड, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, चीन, बंगला देश, थाईलैण्ड और दक्षिण कोरिया स्थित बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं में प्रशिक्षण अध्ययन के लिए 23 अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति किया।

17.25 स्वर्ण जयन्ती समारोह के अंश में रूप में बनायी गयी बैंक के अधिकारियों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने से संबंधित योजना अंतर्गत वर्ष के दौरान 4 अधिकारियों को विदेश की विभिन्न संस्थाओं में उच्चतर अध्ययन के लिए भेजा गया।

विदेशी बैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं

17.26 वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आये 48 विदेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण अध्ययन के लिए सुविधाएं प्रदान की गयी। इन अधिकारियों में 9 अफगानिस्तान से, 7-7 केन्या और ईरान से 5-5 नेपाल और इराकिया से, 2-2 जॉर्जिया, श्रीलंका, जियाबे नाइजीरिया और भूटान से 1-1 सोमा लिया, युगाण्डा, तंजानिया, जर्मनी से और एक अध्ययनार्थी एशियाई विकास बैंक से थे।

कम्प्यूटर टेक्नालाजी में प्रशिक्षण।

17.27 कंप्यूटरों के क्षेत्र में योग्यता और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बैंक की प्रोत्साहन योजना पर वर्ष के दौरान कार्यवाई जारी रही।

व्यवसायिक योग्यताएं प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहन योजना

17.28 विभिन्न श्रेणी में व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने के लिए स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने की नीति के अनुसरण में, श्रेणी I और श्रेणी II जो कर्मचारी इंडस्ट्रियल आफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल एला-विस्टस आफ इंडिया (आई सी एफ एफ आई), हैराबाब द्वारा चलाए जा रहे सी एफ ए कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं उन्हें प्रोत्साहन (जैसे टैक्स फ्री की प्रतिपूर्ति आदि) देता आ रहा है प्रती लक्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 103 कर्मचारियों को अनुमति प्रदान की जा चुकी है।

पी एच डी के लिए प्रायोजकता योजना

17.29 आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग के अधिकारियों को अपनी व्यावसायिक कक्षाल में विशिष्टता प्राप्त करने तथा कोटि-उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि में, यह निर्णय लिया गया है कि हर वर्ष भारतीय औद्योगिकी संस्थान, बम्बई के लिए चार अधिकारियों (2 अर्थ-वैश्विक कार्यक्रमों में 2-2) और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बम्बई में पी एच डी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 2 अधिकारियों को प्रायोजित किया जाये। इन दोनों ही मामलों में चुनिंदा अधिकारियों को बाहरी उम्मीदवारों के रूप में अपने अध्ययन जारी रखने के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जाएगी।

रिजर्व बैंक पर नई फिल्म नियोजता कर्मचारी संबंध

17.30 रिजर्व बैंक के कार्य और कार्य-प्रणाली में सम्बन्धित 50 मिनट की अवधि वाली अंग्रेजी तथा हिन्दी में एक नई फिल्म बनायी गयी है।

17.31 आलोच्य वर्ष में बैंक में औद्योगिक संबंध का वातावरण आमतौर पर शांत रहा।

17.32 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में कहा गया था, बैंक के अंशदायी भविष्य निधि योजना के एवज में पेंशन योजना 16 जनवरी 1990 को घोषित की गई केन्द्र सरकार, के अनुमोदन के पश्चात् 1 नवम्बर 1990 में यह योजना लागू कर दी गई। ऐसी सभी कर्मचारी जो 1 नवम्बर को या उस तारीख से बैंक सेवा में हैं, उन पर भारतीय रिजर्व बैंक वेजन विनियम, 1990 लागू होंगे, जबकि 1 नवम्बर 1990 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वे पूर्ववर्ती अंशदायी भविष्य निधि योजना में, यदि वे चाहें तो, शामिल हो सकते हैं। यह पेंशन योजना उन भूतपूर्व कार्य



कारियों पर भी लागू होगी जो 1 जनवरी 1986 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हो चुके हैं, तथापि उनको यह पेंशन 1 नवम्बर 1990 में उनके द्वारा पूर्व में ला गई अंशदायी भविष्य निधि राशि को ब्याज सहित लौटा देने पर देय होगी।

17.33 कर्मचारियों के मंदायी बच्चों के लिए बैंक की स्वयं अपनी छात्रवृत्ति योजना, जो 1985 में बनायी गई थी, के अंतर्गत 120 बच्चों को 11वीं तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई और 70 बच्चों को स्नातक अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जन्म शताब्दी

17.34 भारत रत्न, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जन्म शताब्दी के उपलक्ष में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक ने 50 लाख रुपये तक की एक निधि स्थापित करने की घोषणा की है। निधि में प्राप्त होनेवाली ब्याज की राशि का बैंक के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की शैक्षणिक और व्यवसायिक योग्यताओं तथा परिचालनगत कौशल में सुधार लाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही उनके बच्चों के लिए वतायी गयी छात्रवृत्ति योजनाओं पर भी इसे खर्च किया जाएगा। बैंक के केन्द्रीय बोर्ड के निर्देशक की अध्यक्षता में गठित अतिरिक्त समिति उपयुक्त योजनाएं बनावेगी। जन्म शताब्दी मनावने के अंश के रूप में बैंक ने बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई में प्रवेशास्त्र विभाग में राजनैतिक प्रवेशास्त्र व्यवस्था में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रोफेसरशिप नाम में एक प्रोफेसर पद (चियर) स्थापित किया है।

वित्तीय संस्था कक्ष

17.35 बैंक द्वारा अगस्त 1990 में वित्तीय संस्था कक्ष स्थापित किया गया जो वित्तीय संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों में मुख्य यूनिट के रूप में कार्य करेगा। प्रारम्भ में 11 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (प्रधान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण और विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को इस कक्ष के अंतर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है। इस कक्ष को स्थापित करने के मुख्य लक्ष्य हैं-- (1) बैंकों और संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन संस्थाओं के परिचालनों पर स्थूल रूप से नजर रखना, (1) वित्तीय संस्थाओं की परिसम्पत्तियों की वित्तीय संस्थाओं की परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता की वित्तीय मूल्यांकन प्रणाली प्रारम्भ करना, (3) जिन समष्टि क्षेत्रों में परिवर्तन/सुधार की संभावना है उनका पता लगाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक के वरिष्ठ तंत्र और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ तंत्र के बीच आबिधिक रूप से विचार-विमर्श को व्यवस्था करना। कक्ष ने पहले ही एक निमाही सूचना प्रणाली प्रारम्भ कर दी है जो अप्रैल-जून 1991 की निमाही से लागू है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों आरक्षित श्रेणियों को रोजगार

17.36 फ़ेब्रुअरी वर्ष 1990 के दौरान की गई कुल सीधी भर्तियों में विभिन्न वर्गों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार रहा --

श्रेणी/वर्ग

भर्ती किए गए कुल उम्मीदवार अनुसूचित जाति उनमें से अनुसूचित जनजाति प्रतिशत अनुसूचित जाति

1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	116	21	5	18.1	4.3
श्रेणी III	436	77	66	17.7	15.1
श्रेणी V	433	192	41	44.3	9.5
उन में से					
(क) सफाई कर्मचारियों की छोड़कर	377	159	29	42.2	7.7
(ख) सफाई कर्मचारी	56	33	12	58.9	21.4

17.37 इससे 1 जनवरी 1991 को बैंक में भर्ती किए जाने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर श्रेणी IV में क्रमशः 2,302 और 689, श्रेणी III में 2,355 और 1,056 तथा श्रेणी I में 464 और 111 हो गई है।

भूतपूर्व सैनिक

17.38 फ़ेब्रुअरी वर्ष 1990 के दौरान श्रेणी III श्रेणी IV में भरी गयी 436 और 433 रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की 14.5 और 24.5 प्रतिशत की निर्धारित छंटों पर क्रमशः 63 और 106 रिक्तियां आरक्षित रखी जानी थी। इसके मुकाबले, श्रेणी III में 22 और श्रेणी IV में 38 रिक्तियां भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी गयी। इससे 31 दिसंबर 1990 तक बैंक में इनकी कुल संख्या बढ़कर श्रेणी III में 761 और श्रेणी IV में 1,027 हो गई। केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुसार श्रेणी III में 14.5 प्रतिशत के और श्रेणी IV में 24.5 प्रतिशत के आरक्षण को और विभक्त किया गया है ताकि इनमें क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों की रखा जा सके

और ग्रेड 4.5 प्रतिशत का प्रत्येक श्रेणी में (श्रेणी III श्रेणी IV) मुख्यतः विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों और/या युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित रखा जाए।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

17.39 फ़ेब्रुअरी वर्ष 1990 के दौरान श्रेणी III और श्रेणी IV के 8 विकलांग व्यक्तियों को भर्ती किया गया, इससे बैंक में विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या बढ़कर 385 हो गई। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सितम्बर 1980 में पता लगाये गए पदों के अतिरिक्त, श्रेणी IV में सफाई कर्मचारी और फरॉश के पदों पर ऐसे व्यक्तियों को रखा जाएगा जिन्हें कम दिखाई देता है (जो गुने और/या बहरे नहीं हैं)

हिल्स की प्रगति

17.40 वर्ष के दौरान बैंक ने हिल्स के प्रयास में वृद्धि करके प्राण प्रयासों को जारी रखा। द्विभाषिक प्रकाशनों के अतिरिक्त बैंक को नियमित रिपोर्टों और प्रकाशनों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट, भूत और विल संबंधी रिपोर्ट, भारतीय

रिजर्व बैंक इलेटिन, रिजर्व बैंक न्यूजलेटर और सूचना समीक्षा, भारतीय रिजर्व बैंक प्रोजेक्टविटी न्यूज, मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियाँ, इत्यादि, कतिपय महत्वपूर्ण संयुक्त/प्रकाशन जैसे, विदेशी मुद्रा नियंत्रण नियम पुस्तक (हिन्दी पाठ), परिमर विभाग नियम पुस्तक, औद्योगिक और नियति और विभाग परिपत्र जुलाई 1986—जून 1989 के निविदा करार फार्म, बैंकों में कंप्यूटरीकरण समिति की रिपोर्ट और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित किया गया है।

17.41 वर्ष के दौरान, हिन्दी कार्यशालाओं में 832 कर्मचारियों/अधिकारियों को, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 186 अधिकारियों को और प्रशिक्षणमूलक हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 12 वरिष्ठ अधिकारियों को हिन्दी में प्रशिक्षित किया गया। बैंक ने गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 9वीं हिन्दी कार्यशाला का आयोजन भी किया जिसमें 19 अधिकारियों ने भाग लिया।

17.42 मार्च 1990 में राजभाषा प्रभाग के अधिकारियों और कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हिन्दी विभागों के प्रमुखों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की गयी जिसका कार्य अंग्रेजी में इस्तेमाल किये जाने वाले शब्दों के हिन्दी पर्याय की बैंकिंग शब्दावली का संशोधन और अद्यतन करना था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस्तेमाल किए जाने वाले हिन्दी शब्दों में एकरूपता लायी जा सके। इसके अलावा, हिन्दी में बैंकिंग के शब्दों का एक व्याख्यापरक कोश—“परिभाषा कोश” तैयार करने का काम भी प्रगति पर है।

17.43 विभिन्न कार्यालयों में अंतर्विभागीय शील्ड प्रतियोगिता तथा अंतर-कार्यालय प्रतियोगिता और केन्द्रीय कार्यालय के विभागों में प्रतियोगिता की गयी और शील्ड प्रदान किये गये। वर्ष के दौरान, विभिन्न केन्द्रों में 14 सितम्बर हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया जिसमें कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।

17.44 बैंक द्वारा प्रकाशित “बैंकिंग चिंतन-अनुसंधान” नामक हिन्दी तिमाही प्रकाशन बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में काफी लोकप्रिय हुआ। इसी प्रकार, बैंक की गृह पत्रिका “बिदाउट रिजर्व”, हिन्दी को पर्याप्त महत्व देते हुए प्रकाशित की जाती रही।

#### कार्यालय भवन और आवासीय स्थान

17.45 वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के दौरान कार्यालय भवनों और आवासीय के निर्माण/अभियन्ता करने और अद्यतन परिसरों में परिकल्पना तथा परिवर्तन करने में 16.89 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। वर्ष के दौरान, भोपाल, में कार्यालय भवन और न्यू बम्बई में कार्यालय भवन की एक एनेक्सी का निर्माण कार्य पूरा किया गया। जम्मू तथा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय हैदराबाद में कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने वाला ही है जबकि वर्ष के दौरान बम्बई में 92 अधिकारी क्वार्टर, लखनऊ में श्रेणी III तथा IV के 224 स्टाफ क्वार्टर बनाये गये।

17.46 अहमदाबाद, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, जयपुर लखनऊ और मद्रास में 553 अधिकारी क्वार्टरों तथा 228 स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, न्यू बम्बई में अतिरिक्त कार्यालय भवन के निर्माण और न्यू बम्बई, पटना, नागपुर तथा तिरुवनंतपुरम में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन है।

#### हॉलीडे होम

17.47 वाजिलिंग में हॉलीडे होम बनाने के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रयास जारी है।

#### आवास ऋण

17.48 1 जुलाई, 1990 से 30 जून 1991 तक की अवधि के दौरान आवास ऋण योजना के तहत में निम्नलिखित मुख्य गतिविधियाँ संचालित परिवर्तन, आदि किए गए :

- (i) श्रेणी III के कर्मचारियों के लिए आवास ऋण की न्यूनतम सीमा को 1 मार्च, 1991 से विद्यमान 1,00,000/- रु.

की सीमा से बढ़ाकर 1,25,000/- रु. कर दिया गया। श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए आवास ऋण की न्यूनतम सीमा को 3 जुलाई 1990 से 75,000/- रुपये में बढ़ाकर 88,000/- रुपये किया गया, और वाच में यह सीमा 1 अप्रैल, 1991 से बढ़ाकर 1,13,000/- रुपये कर दी गई।

- (ii) आवास प्राप्त करने के उद्देश्य में अविपक्ष निधि में अग्रिम राशि प्राप्त करने के लिए बैंक की नियमित न्यूनतम विद्यमान 5 वर्ष की सेवा जिसमें कर्मचारी की अस्थायी सेवा भी शामिल है, 15 नवम्बर, 1990 से कम कर 3 वर्ष कर दिया गया।

- (iii) श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों के लिए मकान/प्लैट खरीदने/निर्माण करने हेतु आवास ऋण/अविपक्ष निधि अग्रिम आहरण दोनों को मिलाकर, सितंबर, 1990 से कुल अधिकतम सीमा रु. 2,25,000/- से बढ़ाकर रु. 3,00,000/- कर दी गई है। इसके साथ ऋण स्वीकृत करने वाला अधिकारी अपने विवेक से कुल अधिकतम सीमा का 25 प्रतिशत तक का राशि स्वीकृत कर सकता है।

- (iv) पूर्व में “गैराज” की निर्माण लागत और स्टाप्स ड्यूटी/रजिस्ट्रेशन प्रभारों को बैंक की आवास ऋण योजना के अंतर्गत अनुमत नहीं समझा जाता था। सितंबर, 1990 से इन मदों को योजना के अंतर्गत अनुमत माना गया है बशर्ते “गैराज” की निर्माण को मूल प्लान परियोजना में शामिल किया गया हो और स्टाप्स ड्यूटी/रजिस्ट्रेशन प्रभारों को प्लैट मकान अभियन्ता करने की कुल (मूल) लागत में शामिल किया गया हो।

17.49 वर्ष 1990-91 (जुलाई-जून) के दौरान कर्मचारियों (ममितियों/अलग-अलग व्यक्तियों) की नीचे दिये गये व्योरे के अनुसार 19.49 करोड़ रुपये का आवास ऋण स्वीकृत किया गया :

श्रेणी	समितियों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या	ऋणों की राशि
(अ) सहकारी आवास समितियाँ	29	502	1,80,99,576
(i) नये ऋण	5	85	61,79,569
(ii) अतिरिक्त ऋण	24	217	1,19,20,007
(आ) केन्द्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण		482	5,29,40,589
(i) नये ऋण	—	360	4,89,30,685
(ii) अतिरिक्त ऋण	—	122	40,09,904
(इ) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत व्यक्तिगत ऋण		1,710*	12,38,89,659*
(i) नये ऋण		718*	7,86,56,212*
(ii) अतिरिक्त ऋण		992*	4,52,33,447*
अ + आ + इ का योग	29	2,494*	19,49,29,824*

\*भुवनेश्वर तथा पटना कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों की इस वर्ष के आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है, इसके लिए अलग स्पष्टीकरण मांगा गया है।

भोपाल तथा कानपुर कार्यालय से संबंधित आंकड़े केवल 30 सितम्बर 1990 की समाप्त अवधि के हैं।

कलकत्ता (निर्गम) कार्यालय से संबंधित आंकड़े केवल 31 दिसम्बर 1990 की समाप्त अवधि के हैं।

पामबना, चंडीगढ़ तथा जम्मू कार्यालयों से संबंधित आंकड़े केवल 31 मार्च, 1991 की समाप्त अवधि के हैं।

## केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड

17.50 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री गणेशधर मल्होत्रा ने 22 दिसंबर, 1990 पृथ्विन को अपना पद त्याग दिया और भारत सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री एस बेंकटर्मणन को उनके स्थान पर उगी दिन, अर्थात् 22 दिसंबर 1990 से गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया। बोर्ड श्री मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए उनका समर्पण करता है।

17.51 डॉ. बिमल जालान, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार, परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप 3 जनवरी 1991 से केंद्रीय बोर्ड में भारत सरकार के नामिनी नहीं रहे और उनके स्थान पर वित्त मंत्री, श्री एम.पी. शुक्ल को उम्मी सारोख में नामित किया गया। डॉ. बिमल जालान द्वारा अपने सेवा काल के दौरान बोर्ड के निदेशक के रूप में की गई सराहनीय सेवाओं के लिए उनका समर्पण करता है।

17.52 बोर्ड को यह जानकारी हासिल हुई कि बैंक के दक्षिण क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य श्री एम.एस. भट्ट का 4 दिसंबर, 1990 को देहान्त हो गया। बोर्ड, उनके संतान परिवार के सदस्यों के प्रति आर्थिक सहानुभूति व्यक्त करता है।

17.53 श्री म.म.ट. कर्नाडिस को 1 फरवरी, 1991 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

## ध्यान

## (i) आय

17.54 30 जून, 1991 को समाप्त लेखा वर्ष के दौरान विभिन्न प्रावधानों के लिए समायोजन करने के पश्चात् बैंक की आय पिछले वर्ष के 4,426.73 करोड़ से 43 प्रतिशत बढ़कर 1,624.97 करोड़ रुपये हो गई।

आय के स्तोन नीचे दिए गए हैं :

(करोड़ रुपये)

## (क) प्रतिभूतियों पर व्याज

बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर व्याज (विदेशी प्रतिभूतियों, जमागणियों आदि पर व्याज सहित)

3,415.56

(ख) रुपये और विदेशी स्रजाना बिलों पर बट्टा

962.01

(ग) प्रेषणों, खरीदे गये तार अंतरणों आदि पर कमीशन (विदेशी लेन-देनो सहित)

219.79

(घ) जीतः ऋण के प्रबंधन पर कमीशन और अन्य विविध प्रकार की आय

27.61

4,624.97

17.55 रुपया प्रतिभूतियों की औसत धारित राशियों में वृद्धि एवं उच्चतर व्याज-दरों वाली प्रतिभूतियों में भी वृद्धि के कारण 1990-91 के दौरान व्याज में 85.10 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। मुख्यतः विदेशी स्रजाना बिलों की निम्नतर धारित राशियों के कारण अर्जित बट्टे में 99.08 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज हुई।

## (ii) व्यय

17.56 कुल व्यय, जो 1989-90 में 3,256.61 करोड़ रुपये तक 23.36 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। उक्त वृद्धि प्रमुख रूप से स्थापना

प्रतिभूति मुद्रण और अभिकरण प्रभारों में घटी हुई लागत के कारण थी जिसकी प्रथम धनपूर्ति व्याज अदायगियों में कमी द्वारा हुई।

17.57 2,547.70 करोड़ रुपये की व्याज अदायगियों में एक प्रमुख मद 1990-91 के दौरान बैंक के पास रखी गई पाठ्य अभिरिक्त तकदी लोप राशियों पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 2,431.02 करोड़ रुपये की व्याज अदायगियां थी, यह मद कुल व्यय का 74.1 प्रतिशत रही।

17.58 स्थापना की लागत में 243.69 करोड़ रुपये तक 15.30 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई और वह कुल व्यय का 7.4 प्रतिशत रही। जिसका मुख्य कारण सभी अंगियों के स्टाफ की देय महंगाई भत्ते में प्रावधिक वृद्धि एवं वेतन के समय-मानों में वार्षिक वेतन वृद्धियां थी।

17.59 प्रतिभूति मुद्रण और प्रामाणिक लागतें 162.28 करोड़ रुपये की थी जो 18.57 करोड़ रुपये अधिक थी और वे कुल व्यय का 5.0 प्रतिशत बनी जो नोट फार्मा के मुद्रण एवं नोटों की संख्या विप्लव उच्चतर मुद्रणियों में नोटों की संख्या की आपूर्ति की दरों में वृद्धि के कारण थी।

17.60 एजेंसी बैंकों द्वारा किये गये सरकारी लेन-देनों में उच्चतर प्रावत (टर्नओवर) के कारण एजेंसी प्रभागों में 265.62 करोड़ रुपये तक 4.37 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई और वह कुल व्यय का 8.1 प्रतिशत बनी।

17.61 पिछले वर्ष में उपर्युक्त 1,170.12 करोड़ रुपये की तुलना में निम्न प्रयोज्य आय 1990-91 के दौरान 1,345.00 करोड़ रुपये 174.88 करोड़ रुपये अधिक दर्ज की गयी। मासिक निशियों में देय के अंशदान नीचे दर्शाये गये हैं।

(करोड़ रुपये)

	1990-91	1989-90
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	523.00	525.00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	400.00	375.00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थिरकरण) निधि	20.00	10.00
राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	50.00	50.00
	995.00	960.00

17.62 सरकार को पिछले वर्ष में अंतरित 210.12 करोड़ रुपये की तुलना में 1990-91 के दौरान 350.00 करोड़ रुपये का अधिशेष अंतरित किया गया था।

## मुलन-पल बैंक जमागणियां

17.63 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों, अन्य अनुसूचित सहकारी बैंकों एवं अन्य बैंकों की कुल जमागणियों में 1,869.70 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई जिससे वे 26,725.09 करोड़ रुपये के पिछले वर्ष के स्तर से 31,594.66 करोड़ रुपये तक बढ़ गई थी। उक्त जमागणियों में 30,789.62 करोड़ रुपये की विप्लव राशि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से प्राग्भिन तकदी निधि अनुपात में रखरखाव हेतु प्राप्त राशि थी।

## अन्य जमागणियां

17.64 अन्य जमागणियों में पिछले वर्ष के 2,142.17 करोड़ रुपये के स्तर से 5,868.62 करोड़ रुपये तक की वृद्धि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) खाता में 1 में जोष राशि में बढ़ावरी के कारण थी।

मुख्यतः भारत सरकार की कृपा प्रतिष्ठितियों में निवेश में वृद्धि के कारण है।

17.65 रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 33 (4) में संशोधन होने के परिणामस्वरूप सोना जिसका अब तक मूल्यांकन 0.118189 शुद्ध ग्राम/रुपया पर किया गया था, अब "अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में घनधिक" दर पर मूल्यांकित किया जा रहा है। सोने का वह पुनर्मूल्यांकन 17 अक्टूबर 1990 को 1,991.64 रुपये प्रति ग्राम 10 की दर से किया गया था और सोने के मूल्य में हुई वृद्धि प्रारक्षित निधि में जमा की गई थी जैसा कि 1956 और 1969 में पिछले अवसरों पर किया गया था, जिससे प्रारक्षित निधि 6,350 करोड़ रुपये से 6,500 करोड़ रुपये तक बढ़ गई थी।

कृष्ण और अग्रिम

17.68 अनुसूचित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को दिए गए ऋण में 4,085.74 करोड़ रुपये की तीव्र वृद्धि हुई और यह जून 1990 के अंत में 5,420.69 करोड़ रुपये से बढ़कर जून 1991 के अंत में 9,506.43 करोड़ रुपये हो गयी। यह वृद्धि मुख्य रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए विवेक-सम्मत बिल (1,546.00 करोड़ रुपये) और नियत पुनर्वित्त (4,468.00 करोड़ रुपये) के अन्तर्गत प्रत्याधिक बकाया और नाबर्ही ऋण की सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत उच्चतर देयताओं के कारण हुई।

17.66 विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में निर्गम विभाग में "विदेशी प्रतिभूतियाँ" और विदेशों में जमा राशियाँ तथा बैंकिंग विभाग में "निवेश" शामिल है। इन प्रारक्षित निधियों, जो कि 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार 5,356.17 करोड़ रुपये थीं, में 30 जून 1991 की स्थिति के अनुसार 2,382.69 करोड़ रुपये तक तेजी से 2,973.48 रुपये की गिरावट हुई।

नेम्बा परीक्षक

17.69 बैंक के लेखों की लेखा परीक्षा मैसर्स खन्ना एण्ड अम्नाधनम, नई दिल्ली मैसर्स अमित रे एण्ड कंपनी, डलाहाबाद, मैसर्स मुखर्जी बिस्वास एण्ड पाठक, कसकता मैसर्स सोराब एम. इंजीनियर, एण्ड कंपनी, बम्बई, मैसर्स ए. के कपूर एण्ड कंपनी और मैसर्स कश्यप एण्ड कंपनी महाराष्ट्र द्वारा की गई है। एक ओर जहाँ भारत सरकार ने पहले वाले पांच लेखा परीक्षक 1990-91 के लिए नियुक्त किए, वहीं दूसरी ओर मैसर्स बिश्ननाथन के स्थान पर चार वर्ष के लिए नए लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। बैंक के सभी कार्यालयों, जो छठ अक्षरों में बंटे गए हैं, का लेखा परीक्षा, सांख्यिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई थी।

मागशीय रिज्वं बेंफ

30 जून 1991 की स्थिति का सन्दर्भ-पत्र

(हजार. रुपये में)

देयताएं	1990-91 रु.	1989-90 रु.	निर्गम विभाग आस्तियां	1990-91 रु.	1989-90 रु.
			सोने का मिक्का और बुलियन :		
बैंकिंग विभाग में रखे हुए नोट	11,87,86	18,21,19	(क) भारत में रखा हुआ	7410,79,89	280,66,99
संचालन में नोट	57858,45,88	50082,26,71	(ख) भारत में बाहर रखा हुआ	—	—
बाकी किये गये कुल नोट	57870,33,74	50100,47,90	विदेशी प्रतिभूतियां	200,00,00	1564,05,75
			जोड़	7610,79,89	1844,72,74
			रुपये का मिक्का	91,46,03	38,96,21
			भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	50168,07,82	48216,78,95
			देशी वित्तिय विल और दुबारे	—	—
			वाणिज्यिक पत्र	—	—
कुल देयताएं	57870,33,74	50100,47,90	कुल आस्तियां	57870,33,74	50100,47,90
			बैंकिंग विभाग		
देयताएं	रु.	रु.	आस्तियां	रु.	रु.
प्रश्न पूर्ती	5,00,00	5,00,00	नोट	11,87,86	18,21,19
			रुपया मिक्के	10,89	10,50
प्रारक्षित निधि	6500,00,00	150,00,00	छोटे निक्के	6,96	6,09
			खरीदे तथा भुनाये गये धातु	—	—
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वैयक्तिक) प्रवर्तन) निधि	5675,00,00	5150,00,00	(क) आंतरिक	—	—
			(ख) बाहरी	—	—

वतनाएं	रु.	रु.	आस्तियां	रु.	रु.
राष्ट्रीय आवास ऋण (बीर्धकालीन प्रवर्तन) निधि	175,00,00	125,00,00	(ग) सरकारी खजाना बिल	399,20,21	1796,88,08
जमाराशिया			विदेशों में रखे गये बकाया शेष निवेश <sup>3</sup>	2087,54,77	2378,33,76
			निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा भ्रमिम	46337,16,59	32350,68,89
(क) सरकार			(i) केन्द्र सरकार	—	—
(i) केन्द्र सरकार	105,62,06	140,86,96	(ii) राज्य सरकारें	16,99,00	10,64,00
			निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा भ्रमिम		
(ii) राज्य सरकारें	15,75,60	16,66,85	(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	6104,28,23	2467,31,04
			(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	18,83,64	27,42,25
(ख) बैंक			(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	9,83	—
(i) अनुसूचित वाणिज्य बैंक	30789,61,72	26026,15,69	(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	—
			(v) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3322,36,70	2858,34,67
			(vi) अन्य	60,84,16	67,61,00
(ii) अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	548,01,79	464,62,78	राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (बीर्धकालीन प्रवर्तन)		
(iii) अन्य अनुसूचित सहकारी बैंक	88,13,88	122,37,20	निधि में ऋण, भ्रमिम तथा निवेश :		
(iv) गैर-अनुसूचित राज्य सरकारी बैंक	10,89,76	15,00,46	(क) निम्नलिखित को दिये गये ऋण तथा भ्रमिम		
(v) अन्य बैंक	57,98,58	96,93,35	(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	3705,15,46	3822,30,46
(ग) अन्य	5868,61,65	2142,17,20	(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	745,00,00	625,00,00
देय बिल	185,22,75	112,86,03	(iii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	130,00,00	95,00,00
अन्य देयताएं <sup>4</sup>	15853,01,52	14170,38,53	(iv) अन्य	400,00,00	—
			(ख) निम्नलिखित द्वारा जारी किये गये बांडों/डिबेंचरों में निवेश		
			(i) भारतीय विकास बैंक	—	—
			(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—
			(iii) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	—	—
			(iv) अन्य	—	—
			राष्ट्रीय आवास ऋण (बीर्धकालीन प्रवर्तन) निधि से ऋण, भ्रमिम तथा निवेश :		
			(क) राष्ट्रीय आवास बैंक को ऋण एवं भ्रमिम	125,00,00	75,00,00
			(ख) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों/डिबेंचरों में निवेश	—	—
			अन्य आस्तियां	2513,35,01	2145,13,12
कुल देयताएं	65977,89,31	48738,05,05	कुल आस्तियां	65977,89,31	48738,05,05

1. सोने के सिक्के और बुलियन के पुनर्मूल्यन के कारण हुई 6350 करोड़ रुपये की वृद्धि शामिल है।
2. इसमें आकस्मिक लेखों को शामिल किया गया है।
3. विदेशों में विदेशी मुद्रा में रखे हुए 95.14 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 1413.77 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

(हज़ारों में)

30 जून, 1991 को समाप्त वर्ष के लिये साध-हानि लेखा

धाय	1990-91 रु.	1989-90 रु.
भ्याज, चट्टा, चिनिमय शुल्क कमीशन आदि	4624,97,34	4426,72,53
जाड़	4624,97,34	4426,72,53

आय	1990-91 रु.	1989-90 रु.
व्यय	2547,69,66	2571,33,44
व्याज	243,68,89	228,38,92
स्थापना व्यय	5,34	5,68
निवेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और व्यय	4,73,59	5,69,19
खजाना प्रेषण	265,62,33	261,25,11
एजेन्सी प्रभार	162,27,50	143,71,16
प्रतिभूति छपाई (बैंक, नोट, फार्म आदि)	2,54,43	2,68,50
मुद्रण और लेखन-सामग्री	468,05	2,77,54
डाक और तार खर्च	12,78,63	13,10,37
किराया, कर, बीमा, बिजली आदि	9,16	9,65
लेखा परीक्षकों के शुल्क और व्यय	11,44	22,46
बिधि प्रभार	20,28,00	19,82,26
बैंक संपत्ति का मूल्यांकन और उसकी मरम्मत	15,40,32	7,46,49
बिबिध व्यय	3279,97,34	3256,60,77
जोड़	1345,00,00	1170,11,76

उपलब्ध शेष राशि		
घटाइये : निम्नलिखित में अंशदान		
राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण		
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	525,00,00	525,00,00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण		
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	400,00,00	357,00,00
राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण		
(स्थिरीकरण) निधि :	20,00,00	10,00,00
राष्ट्रीय आवास ऋण		
(दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	50,00,00	50,00,00
	995,00,00	960,00,00

केन्द्रीय सरकार को देय अधिशेष 350,00,00 210,11,76

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार नियमित या आवश्यक प्रावधान करने के बाद।
2. ये निधियां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा रखी जाती हैं।

(बी. जी. आठवले) मुख्य लेखाकार	(रा. जानकीरामन) उप गवर्नर	(पी. भार. नायक) उप गवर्नर	(सी. रंगराजन) उप गवर्नर	(ए. बी. पी.) उप गवर्नर	(ए. वेकिटरमणन) गवर्नर
----------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------

#### लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें

भारत के राष्ट्रपति की सेवा में

हम भारतीय रिजर्व बैंक के अधीनस्थित लेखा परीक्षक इसके द्वारा 30 जून, 1991 की स्थिति के तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि लेखों पर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करते हैं।

हमने भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून, 1991 की स्थिति के तुलन-पत्र की ओर उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि लेखों की जांच की है और यह रिपोर्ट करते हैं कि हमने बैंक से जो स्पष्टीकरण और जानकारी मांगी, ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण हमें दिये गये और वे संतोषजनक हैं। हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक के बही-खातों में दर्शाए गए अनुसार यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण दिये गये हैं तथा इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसरण में सही तरीके से बनाया गया है ताकि इससे बैंक के कार्यों की सच्ची और सही स्थिति का पता लग सके।

मैसर्स सी.ए.एस. इंजीनियर एण्ड कं. लेखा-परीक्षक	मैसर्स खन्ना एण्ड अन्नाधनम लेखा-परीक्षक	मैसर्स अमिन रे एण्ड कं. लेखा परीक्षक	मैसर्स मुखर्जी विश्वास एण्ड पार्टनर्स लेखा-परीक्षक	मैसर्स एस. के. कपूर एण्ड कं. लेखा-परीक्षक	मैसर्स ब्रह्ममथ्या एण्ड कं. लेखा-परीक्षक
--	---	---	--	--	--

[सं. एफ.-19/23/91-बी.ओ.-1]

एम.एस. सीतारामन, गवर्नर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 25th September, 1991

S.O. 937.—In accordance with Section 53(2) of the Reserve Bank of India Act, 1934, the Central Board of Directors has submitted to the Government of India the following Annual Report on the working of the Reserve Bank of India during the year ended June 30, 1991 :—

## THE ANNUAL REPORT

## ON THE WORKING OF THE RESERVE BANK OF INDIA

for the Year July 1, 1990 to June 30, 1991

## PART I—THE ECONOMIC SITUATION

## 1. AN OVERVIEW

1.1 Notwithstanding the continuing fiscal and external payments imbalances, the growth momentum in the economy during 1990-91 was sustained at a reasonably satisfactory level, thanks to the third successive good harvest. The growth of real gross domestic product (GDP) in 1990-91 is estimated at 5.0 per cent as compared with a growth of 5.2 per cent in the previous year. While agriculture and manufacturing sectors performed better, there was a slower growth of the infrastructural sectors and the services sector also registered a somewhat slower growth.

1.2 The overall agricultural production is estimated to have increased by a little over 4.0 per cent in 1990-91 as against 17 per cent in 1989-90 and 21.0 per cent in 1988-89. Food-grains output in 1990-91 is estimated at over 176 million tonnes as against 170.6 million tonnes in 1989-90. In the sphere of industry, due to accelerated performance in the manufacturing sector the overall index of industrial production recorded a growth of 8.4 per cent during 1990-91 as compared with that of 8.6 per cent in 1989-90.

1.3 The rate of domestic saving registered a decline albeit fractionally. Despite this, the gross domestic investment rate was over 24 per cent in 1990-91 because of increased foreign inflows (i.e., the counterpart of the current account deficit). During 1990-91, the primary issues segment of the capital market experienced considerable sluggishness due to macro-economic stresses and uncertainties. The secondary market, on the other hand, experienced contrary trends and continued to register an overall increase in share prices—a process which was noticeably reinforced after the series of structural reform measures announced in July 1991.

1.4 The performance of the export sector was not satisfactory in 1990-91. Merchandise trade data suggest that export growth in real terms, which was about 10 to 12 per cent per annum during the preceding four years, showed a very sharp deceleration in 1990-91. In rupee terms, exports rose by 17.5 per cent during 1990-91 as against a growth of 36.8 per cent in the previous year. In US dollar terms, the growth rate declined to 9.0 per cent from 18.7 per cent in the previous year. Imports in rupees grew by 21.9 per cent as against 25.4 per cent in the previous year, while in dollar terms they grew at a faster rate of 13.1 per cent against 11.2 per cent. The resulting deterioration in the merchandise trade was almost entirely due to POL imports—a sizeable increase in volume growth and, more importantly, a large spurt in POL prices. Apart from the higher trade deficit, there occurred a significant fall in invisible receipts which resulted in an increase in the ratio of current account deficit to GDP from 2.3 per cent in 1989-90 to an estimated 2.5 per cent in 1990-91.

1.5 The Central Government's budgetary deficit, which was budgeted at Rs. 7,206 crore for 1990-91, rose to Rs. 15,442 crore towards the middle of November 1990 and finally stood at Rs. 11,430 crore, i.e., nearly 60 per cent more than the budget estimate. Likewise, the monetised deficit of the Central Government was also significant larger than envisaged.

1.6 Despite the expansion in the monetised deficit, there was a slower pace of expansion of broad money ( $M_3$ ) in 1990-91 and this essentially attributable to a massive loss of foreign exchange reserves. Apart from the foreign exchange reserve loss, some sluggishness in the real economy consequent upon transport and other infrastructural constraints, persistent increase in the cost of living which adversely affected the household saving propensity and the emergence of other attractive instruments of saving, particularly mutual funds, have all contributed to a slow-down in the growth of bank deposits.

1.7 The macro-economic imbalances tended to aggravate the inflationary pressures. The increase in the Wholesale Price Index, on a point-to-point basis, accelerated from 9.1 per cent in 1989-90 to 12.1 per cent in 1990-91. Apart from the inflation being generalised the high rates of increases in prices of commodities of common consumption are reflected in a rise of 13.6 per cent in the Consumer Price Index for industrial workers in 1990-91 as against 6.6 per cent in the previous year.

1.8 The foreign exchange reserves came under acute pressure in the second half of 1990-91 and in the early weeks of the financial year 1991-92. Hence, the short-term management of the balance of payments became the over-riding immediate concern of economic policy. With the rapid decline in the foreign exchange reserves, the financing of the current account deficit became difficult as short term and long-term finance which were available earlier became increasingly difficult to obtain. It was in this context that exceptional financing was sought and obtained from both multi-lateral and bilateral agencies. Gold transactions also provided bridge finance. The stresses and strains on the economic front appeared amidst the absence initially of a regular Central Government Budget. In such a milieu, the burden of short-term economic management fell to a great extent on monetary and credit policy. Vigorous use of unconventional monetary policy instruments thus became an imperative.

1.9 The month of July 1991, however, saw far-reaching policy initiatives to achieve macro-economic stabilisation and structural adjustment. First, the Reserve Bank effected a two downward adjustment in the exchange rate of the rupee by about 18-19 per cent against major currencies with a view to promoting competitiveness of our exports, reducing inessential imports, minimising incentives for capital flight, stabilising the capital account and generally restoring viability of the country's balance of payments position. To ensure that the gains of the exchange rate adjustment were not dissipated in inflation the monetary policy was simultaneously tightened with increase in the Bank Rate, deposit and lending rates and refinancing rates. Secondly, along with the exchange rate adjustment, significant structural reforms were effected in India's trade policy so as to liberalise the system from administrative controls and licences, to boost exports and for generally encouraging competitiveness and enterprise in the economy. An important element in the trade policy reforms is the linking of all imports, other than specified essential imports, to exports. A further set of liberalisation measures including the decanalisation of 20 important and 16 export items and the facility to open foreign currency accounts by exporters was introduced in August 1991. Thirdly, radical changes have been introduced in the policy framework relating to industrial licensing, the role of public sector, the MRTP Act, foreign direct investment and foreign technology agreements. The new Policy package has sought to abolish the requirement of industrial licensing for all industries except for 18 specific industrial categories and continue reservation for the small-scale sector, to remove the asset limit in respect of MRTP companies and dominant undertakings, to allow for private investment also in as many as 10 areas hitherto reserved for the public sector, to provide approval for foreign equity participating up to 51 per cent in 34 select areas and also to provide for automatic approval to foreign technology agreements. A series of measures have already been put in place for promoting and strengthening the small tiny and village enterprises. Fourthly, the Centre's Budget for 1991-92 has sought to initiate the process for fiscal adjustments and thus contribute to macro-economic stabilisation during 1991-92, with a promise to follow it up with continued fiscal consolidation thereafter over a medium-term perspective of about three years. Towards that end the Budget proposes

concrete measures to reduce the gross fiscal deficit from about 8.4 per cent of GDP in 1990-91 to the desired of 6.5 per cent in 1991-92, as also to contain revenue deficit and monetised deficit to a significant extent. The Budget also sets out a number of non-fiscal reform measures which impinge on the financial system such as, increases in interest rates on small savings, giving the term-lending financial institutions the freedom to charge interest in accordance with their perception of the credit worthiness of their borrowers subject to a floor rate of 15 per cent, removal of all restrictions on interest rates offered on debentures, measures for strengthening the capital market, transferring capital issue control to the SEBI, and permitting mutual funds activity in the private sector. Finally, insofar as the financial sector itself is concerned, the Government have indicated their intention to introduce sector reforms with the objective of preserving the sectors basic role as an essential adjunct to

economic growth and competitive efficiency, while improving the health of its institutions.

## 2. NATIONAL INCOME, SAVING AND INVESTMENT

### Growth-Profile

2.1 The growth of real gross domestic product (GDP) is tentatively estimated at about 5 per cent during 1990-91. This follows the growth of 5.2 per cent in 1989-90, a higher-than-targeted average annual growth of 5.6 per cent achieved in the Seventh Plan and a trend growth rate of 5.3 per cent during the 'eighties. While agricultural growth is estimated to have registered a slight improvement, the slower growth of infrastructural sectors and services have contributed to the somewhat lower growth in GDP in 1990-91.

Table 2.1 : Growth Rate in Real GDP

Sector	Percentage Share (in real GDP)			Growth Rate (per cent)				
	1970-71	1980-81	1989-90*	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Agriculture and allied activities	44.5	38.2	32.1	+30.3	-1.7	+0.4	+15.4	+2.5
(a) Agriculture	39.7	34.7	29.7	+0.3	-1.7	+0.7	+16.3	+2.3
2. Industry	18.6	20.8	24.6	+4.5	+7.8	+7.0	+8.7	+7.7
(a) Manufacturing	16.1	17.6	20.5	+4.0	+7.0	+7.3	+8.4	+7.4
3. Services@	36.9	41.0	43.3	+7.2	+6.4	+6.2	+7.8	+5.8
Total GDP	100.0	100.0	100.0	+4.1	+3.9	+4.5	+10.4	+5.2
@Inclusive of construction.	*Quick Estimates							

### Trends in Saving and Investment

2.2 Provisional estimates for 1990-91 point to a fractional fall in the ratio of gross domestic saving to GDP at current market prices to 21.6 per cent from 21.7 per cent in 1989-90 (Table 2.2); even so, it is estimated to be higher than the rate of 21.1 per cent attained in 1988-89 and the Seventh Plan average of 20.2 per cent.

2.3 Estimates suggest that there was a further increase in the net inflow of foreign resources in 1990-91 to 2.8 per cent of GDP from 2.5 per cent in 1989-90. Despite some fall in the rate of gross domestic saving, the ratio of aggregate

domestic investment to GDP at current market prices is estimated to show a marginal increase in 1990-91 to 24.4 per cent from 24.2 per cent in 1989-90.

2.4 The slight fall in the gross domestic saving ratio in 1990-91 reflects the decline in the rate of household saving in financial assets, as also that in the rate of public sector saving. The saving rate of private corporate sector, however, registered some further improvement. The sectoral composition of net domestic saving continues to be characterised by a large dissaving by the public sector and meagre saving of the private corporate sector.

Table 2.2 : Estimates of Domestic Saving and Investment Ratios

Sector/Fiscal Year	(In per cent)					
	Gross Saving and Investment as percentage of GDP at Current Market Prices			Net Saving and Investment as percentage of NDP at Current Market Prices		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. Household Sector Saving of which : Saving in	17.1	17.8	17.6	14.6	15.5	15.5
Financial Assets*	7.3	8.9	8.6	8.3	9.9	9.7
2. Public Sector	2.0	1.7	1.6	-2.7	-3.3	-3.6
3. Domestic Private Corporate Sector	2.0	2.1	2.4	0.5	0.5	0.5



1	2	3	4	5	6	7
4. Total : Domestic Saving (1+2+3)	21.1	21.7	21.6	12.4	12.7	12.4
5. Net Inflow of Foreign Resources	2.8	2.5	2.8	3.1	2.7	3.2
6. Aggregate Investment (4+5)	23.9	24.2	24.4	15.5	15.4	15.6
GDP/NDP at Current Market Prices	3,94,992	4,42,769	5,18,500	3,55,902	3,97,239	4,64,245
(Rupees crore)						

\* These are adjusted for financial liabilities. As savings in financial assets do not involve capital consumption for fixed assets, net ratios work out higher than gross ratios : like-wise, in net inflow of foreign resources.

Notes : 1. The ratios for 1988-89 and 1989-90 differ from those given in the previous year's Annual Report of the Bank and those published in the COS's Quick Estimates for 1989-90 because of the revision in the estimates of national income and those of saving and investment consequent on the availability of fresh data. These estimates would undergo further revision when the CSO publishes its Quick Estimates for 1990-91.

2. Figures may not add up to the totals because of rounding off differences.

#### Saving in Financial Assets and its Composition

2.5 Contrary to the significant increase in household saving in financial assets (gross) observed in 1989-90, the ratio of such saving to GDP showed a decline from 11.3 per cent in 1989-90 to 10.8 per cent in 1990-91. The household sector's saving in financial assets (net) as a proportion of NDP is also expected to decline to 9.7 per cent during 1990-91 from that of 9.9 per cent of NDP in 1989-90.

2.6 The incremental holding of currency, which was 1.7 per cent of GDP during 1989-90, is expected to decline during 1990-91. Similarly, savings in the form of bank deposits, which were equivalent to 4.3 per cent of GDP in 1989-90, are also likely to be lower in 1990-91. The share of monetary assets held in the form of currency and bank deposits is, therefore, expected to decline during 1990-91 from that in 1989-90. The contractual savings (life insurance premia, provident and pension funds) as a proportion of GDP declined from 3.1 per cent in 1989-90 to 2.9 per cent in 1990-91. Savings in the form of claims on Government virtually remained the same at around 1.4 per cent of GDP both in 1989-90 and 1990-91. However, the household savings in shares and debentures including units of UTI and other mutual funds, constituting 0.7 per cent of GDP in 1989-90, are expected to move up nominally during 1990-91. The share of such assets in gross financial assets is also expected to rise from 5.6 per cent in 1989-90 to 9.5 per cent in 1990-91.

2.7 A feature of household saving in financial assets has been a shift, within such savings, from bank deposits to shares and debentures and units of UTI and mutual funds, reflecting both the growing diversification of the financial system and the emergence of a more sophisticated investing class sensitive to returns.

#### 3. AGRICULTURAL PRODUCTION

3.1 During 1990-91, agricultural production recorded a sustained progress for the third year in succession, thus imparting considerable strength to the economy. With the 1990 South-West monsoon being considered as exceptionally good, the rainfall during the period ranked the third best in the past decade; it was well distributed over time and space. The North-East monsoon was also favourable.

3.2 The overall index of agricultural production is estimated to have increased by a little over 4.0 per cent as against 1.7 per cent in 1989-90 and 21.0 per cent in 1988-89. Apart from significant increase in foodgrains output, the production of commercial crops like jute and mesta and sugarcane is estimated to have expanded sizeably.

##### Foodgrains Production

3.3 Total foodgrains production during 1990-91, estimated at over 176 million tonnes, surpassed the peak level of output of 170.6 million tonnes in 1989-90 by about 3.3 per cent and also compared favourably with the target of 176.5 million tonnes fixed for the year. While Kharif foodgrains output, placed at 100.4 million tonnes, was slightly lower as compared with the level in 1989-90 (100.9 million tonnes), Rabi production was slated to be significantly higher at 75.9 million tonnes as against 69.7 million tonnes in 1989-90. Good soil moisture and comfortable reservoir levels contributed to this marked improvement, thus regaining the lost ground in the previous year's Rabi production. Amongst individual crops, wheat output has made a remarkable recovery as a result of both increased acreage and improved productivity (Table 3.1).

Table 3.1 : Production of Foodgrains

(Million Tonnes)														
All foodgrains						Kharif				Rabi				
Total	Rice	Wheat	Coarse-grains	Pulses		Total	Rice	Coarse-grains	Pulses	Total	Rice	Wheat	Coarse-grains	Pulses
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1988-89	169.9	70.5	54.1	31.5	13.8	95.6	63.4	26.6	5.6	74.3	7.1	54.1	4.9	8.2
1989-90	170.6	74.1	49.6	34.3	12.6	100.9	66.3	29.2	5.4	69.7	7.8	49.6	5.1	7.2
1990-91														
(Likely achievement)	176.0-176.5	74.6	54.0-54.5	33.4	14.0	100.4	66.8	28.1	5.5	75.6-76.1	7.8	54.0-54.5	5.3	8.5

Source : Ministry of Agriculture.

3.4 From the view point of food security and nutritional requirements, the further improvement in 1990-91 in the overall output of pulses, is noteworthy though substantial imports are still necessary to meet domestic needs. The implementation of the National Pulses Development Programme and Special Foodgrains Production Programme which covered pulses like gram and arhar have helped to substantially step-up their outturn in 1990-91 to 14.0 million tonnes from the previous year's level of 12.6 million tonnes, though

it was short of the target of 15 million tonnes fixed for the year.

#### Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains

3.5 In line with better harvest followed by substantial hike in procurement/minimum support prices, procurement of foodgrains (rice and wheat) by the public sector agencies was higher at 23.8 million tonnes during the 1990-91 fiscal year as against 20.2 million tonnes in the previous year (Table 3.2).

Table 3.2 : Procurement, Off-take and Stocks of Foodgrains

(Million tonnes)										
Fiscal year period	Procurement			Off-take			Stocks*			
	Rice	Wheat	Total	Rice	Wheat	Total@	Rice	Wheat	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1988-89	7.6	6.5	14.1	9.1	8.7	18.0	4.7	2.7	7.4	
1989-90	11.2	9.0	20.2	8.4	7.3	15.8	7.9	3.6	11.7	
1990-91 §	12.7	11.1	23.8	8.3	8.3	16.7	11.2	5.8	17.3	
First quarter (April-June)										
1990	1.4	10.9	12.3	2.0	1.4	3.4	6.9	13.2	20.3	
1991	1.3	7.7	9.0	2.4	2.1	4.5	9.9	11.0	21.1	

\* : Stocks are as at end-March for fiscal year period and as at end-June for first quarter period.

@ : Includes coarse grains.

§ : Provisional.

3.6 Although there has been a bumper wheat crop in 1990-91, wheat procurement during the current 1991-92 marketing season (April-March) has been lower than in the previous year. Up to the end of June 1991 wheat procurement aggregated 7.7 million tonnes against 10.9 million tonnes in the corresponding period of 1990-91 and 11.1 million tonnes in the whole of the Rabi 1990-91 marketing season. The lower wheat procurement is attributable to farmers' anticipation of a mid-season increase in procurement price, transportation bottlenecks and overall uncertainty in the major procurement regions, and aggressive buying by the trade.

3.7 The off-take of foodgrains increased from 15.8 million tonnes in 1989-90 to 16.7 million tonnes in 1990-91 largely due to higher open market sales of wheat by FCI. The large procurement in face of relatively smaller increase in off-take resulted in a higher level of food stock at 17.3 million tonnes at the end of March 1991, which was significantly above the level of 11.7 million tonnes a year ago.

3.8 Amongst commercial crops, output of sugarcane and jute and mesta showed improved from 222.6 million tonnes in 1989-90 to 234.7 million tonnes in 1990-91 and from 82.9 lakh bales to 91.0 lakh bales, respectively. Consequently, the stocks of sugar at the end of June 1991 were substantially higher at 60.96 lakh tonnes as compared to 47.37 lakh tonnes a year ago. The performance of these crops was favoured by improved weather conditions. The prolonged and unseasonal rains, as also pest attacks, damaged the cotton crop which fell from 114.1 lakh bales—a bumper crop in the previous year—to an estimated 100.0 lakh bales in 1990-91. As a sequel to this, the stocks of cotton at the end of the 1990-91 cotton season (September–August), as estimated by the Cot-

ton Advisory Board (CAB) on June 21, 1991, would be lower at 17.29 lakh bales as compared to 30.79 lakh bales at the end of the previous cotton season (1989-90). In oilseeds the Kharif 1990 output of groundnuts received some set-back due to poor rains in the main growing areas of Gujarat and Tamil Nadu. This was, however, more than offset by a bumper Rabi output of rapeseed/mustard and soyabean. Total production of oilseeds during 1990-91 is placed at a new high of 19.1 million tonnes—a marked rise over the output of 16.8 million tonnes achieved in the previous year.

#### 4. TRENDS IN INDUSTRIAL PRODUCTION

4.1 The overall industrial performance during 1990-91 was quite encouraging, mainly on account of better performance by the manufacturing sector which had remained sluggish in the same period of the previous year. The mining and quarrying segments recorded relatively poor growth which was due to low cost output and a decline in the output of petroleum crude. Electricity generation, which maintained an accelerated pace of growth throughout 1989-90, suffered a slight set-back in 1990-91 due to low generation in thermal plants. Over the fiscal year period 1990-91, the general index of industrial production (base : 1980-81=100) registered an increase of 8.4 per cent as compared with 8.6 per cent in 1989-90 (Table 4.1). After registering an impressive growth in the initial months albeit over a low base and as a carry-over of the increased tempo in the later half of the previous year, industrial production experienced a deceleration in its growth rate in the second half of 1990-91. The quarterly growth rate in the general index slowed down from 12.7 per cent in the first quarter to 10.6 per cent in the second quarter and to about 4.9 per cent in the third quarter; it slightly picked up to 6.3 per cent in the fourth quarter of 1990-91.

Table 4.1 : Trends in Index of Industrial Production

(Base : 1980-81=100)

Sector and Weight	Mining and Quarrying		Manufacturing —		Electricity		General Index	
	11.46		77.11		11.43		100.00	
	Index	Growth rate (per cent)	Index	Growth rate (per cent)	Index	Growth rate (per cent)	Index	Growth rate (per cent)
Year								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1986-87	177.9	+6.2	149.7	+9.3	168.1	+10.3	155.1	+9.1
1987-88	184.6	+3.8	161.5	+7.9	181.0	+7.7	166.4	+7.3
1988-89	199.1	+7.9	175.6	+8.7	198.2	+9.5	180.9	+8.7
1989-90	211.6	+6.3	190.7	+8.6	219.7	+10.8	196.4	+8.6
1990-91	219.1	+3.5	208.2	+9.2	238.6	+8.6	212.9	+8.4

#### Major Groups

4.2 While manufacturing output experienced an acceleration in growth rate from 8.6 per cent in 1989-90 to 9.2 per cent in 1990-91 the tempo of growth was perceptibly slack in mining and quarrying (3.5 per cent against 6.3 per cent in the previous year) and also, to some extent, in electricity (8.6 per cent against 10.8 per cent in the previous year).

#### Manufacturing Sector

4.3 The acceleration in the general index of industrial production in 1990-91 was thus entirely brought about by the

manufacturing sector in which the bulk of the contribution was made by seven sub-groups, viz., manufacture of electrical machinery, paper and paper board, machinery and machine tools, food products, cotton textiles, wood and wood products, and basic metals and alloy products. Their growth rates during 1990-91 ranged from 9.0 per cent to 22.7 per cent as against a range of (—) 0.8 per cent to 31.8 per cent in the previous year. The data further show that the manufacturing sector's growth was not only impressive but also broadbased. Of the 17 major groups, as many as 14 groups, with a weightage of 71.4 percentage points, registered positive growth; in the previous year, 15 groups recorded

positive growth rates but with a lower weightage of 65.3 percentage points. Only three groups, viz., textile products, rubber, plastic, petroleum and coal products and other manufacturing industries, with weightage of 5.7 percentage points, recorded absolute declines in their output during 1990-91.

#### Use-based Classification

4.4 Data available in respect of 155 selected industries, accounting for a total weight of 85.5 per cent in the index number of industrial production, show that 92 industries with a weight of 68.7 per cent experienced positive rates of growth during 1990-91; of these, 33 industries with a weight of about 15.9 per cent showed increases of more than 10.0 per cent during the period. In the previous year, 47 industries with a weight of 21.4 per cent, showed increases of more than 10.0 per cent.

4.5 In the use-based classification of the data in respect of the above 155 industries, capital goods industries and consumer durable goods industries continued to display a high growth profile during 1990-91 (Table 4.2). Within the capital goods sector, sugar and paper mill machineries showed sizeable increases of 32.7 per cent and 144.2 per cent, respectively, based on the improved performance of their user industries. Similarly, lifts and cranes showed better growth of 14.7 per cent in agricultural tractors on top of a to, amongst others, improved construction activity. The growth of 14.7 per cent in agricultural tractors on top of a similar increase of 14 per cent in the previous year was associated with the uptrend in agricultural production for

the third year in succession. Apart from the general expansion of the electricity industry, the recent phenomenon of installing captive power generators by manufacturing units and even in building complexes has given considerable impetus to the growth of various power equipments, such as electric generators, electric motors, and winding wires (growth rates ranging from 15 per cent to 34 per cent during 1990-91). Likewise, computer systems and peripherals have sustained a consistently high growth rate of over 35 per cent during the past two years due to growing computerisation in different areas of economic activity. Improved road transport activity has restored a high level of production in commercial vehicles after experiencing recession for two years. Amongst consumer durables, substantial improvement in output has taken place in electric fans (12.4 per cent), two and three-wheelers (6.4 per cent), wrist watches (19.4 per cent) and telephone instruments (26.9 per cent). As compared with consumer durables, the growth of consumer non-durable goods sector was low (5.2 per cent) but steady as in the previous year (5.8 per cent). The growth rate in intermediate goods industries was moderate at 5.6 per cent but nevertheless higher than in the previous year (4.3 per cent). The industries which contributed to the higher growth in this category were cotton yarn, jute manufactures and some items of man-made fibres. The performance of basic industries was, however, poorer when compared with the moderate growth of the previous year (4.3 per cent against 5.2 per cent). This, in turn, is explained by the depressed production activity in the mining and quarrying sector due to poor performance of coal and petroleum crude output, as also in electricity generation.

Table 4.2 : Growth Rate of Industrial Production : Use-based classification

Industry Group	All Industries			Selected 155 Industries*			
	Weight	Annual Average		Number of Industries	Weight	Percentage change during	
		Percentage	Growth				
		1981-82 to 1984-85	1985-86 to 1989-90			1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Basic Goods	39.42	+8.8	+7.4	40	36.36	+5.2	+4.3
II. Capital Goods	16.42	+6.3	+14.8	32	11.32	+29.1	+21.9
III. Intermediate Goods	20.51	+6.1	+6.5	36	16.10	+4.3	+5.6
IV. Consumer Goods	23.65	+5.3	+7.3	47	21.76	+5.2	+6.1
(a) Consumer Durable	2.55	+14.4	+11.8	12	2.20	+2.0	+10.9
(b) Consumer Non-Durables	21.10	+4.0	+6.5	35	19.56	+5.8	+5.2
General Index	100.00	+7.0	+8.5	155	85.54	+9.2@	+8.5@

\* Provisional production data relating to 155 industries with a total weight of 85.5 per cent in the general index of industrial production (1980-81 = 100)

@Variation of Index of 155 industries over the corresponding period of previous year.

#### Input-based Classification

4.6 Input-based classification of the same 155 selected industries during 1990-91 shows that within the agro-based industries, a sharp increase was recorded by sugar (22.7 per cent against a decline of 0.4 per cent) following the bumper sugarcane crop, as also due to incentives offered for late and early crushing of cane. Cotton textiles recorded an impressive growth of 16.7 per cent as compared with the rise of 4.2 per cent in 1989-90 due to improved supply of raw cotton for the second year in succession. Within the group, cloth produced in the decentralised sector recorded a substantial increase of 33.5 per cent in 1990-91, while mill sector output declined by 2.2 per cent over and above the declines of 5.7 per cent in

1989-90 and 7.2 per cent in 1988-89. With the improved availability of raw jute, as also better export demand, there was a turnaround in jute textiles output which improved by 10.3 per cent in contrast to a decline of 6.5 per cent in 1989-90 (April-March). Output of vanaspathi, which had declined by 5.7 per cent in 1989-90, fell further by 12.2 per cent in 1990-91. Tea production decelerated to 1.5 per cent in 1990-91 against a growth rate of 3.5 per cent in the previous year due to adverse weather conditions in the growing areas. Amongst chemical-based industries, both nitrogenous fertilisers and phosphatic fertilisers showed improvement; output of phosphatic fertiliser rose by 16.5 per cent in 1990-91 in contrast to a decline of 20.3 per cent

in the previous year following better availability of imported phosphoric acid. Most of the synthetic fibre and yarn group such as PVC resins, polystyrene, viscose filament yarn and nylon filament yarn, registered absolute declines in output due to the Gulf crisis which affected the supply of petrochemical raw materials and their prices, as also the export market. The exceptions in this group are nylon tyre cord, polyester fibre and polyester filament yarn whose growth ranged from 1.7 per cent to 30.1 per cent following domestic availabilities of caprolactum—a basic input for these industries.

4.7 In the metal-based industries group, automobiles output showed divergent trends. Apart from commercial vehicles (showing an output rise of 15.1 per cent during 1990-91), motor cycles (11.0 per cent), scooters and mopeds (4.9 per cent) and auto-rickshaws (4.9 per cent), registered significant production increases. Railway wagons also registered an output increase of 6.4 per cent. On the other hand, output of passenger cars and jeeps fell by 1.1 per cent and 16.0 per cent, respectively, in 1990-91, as compared with increases of 12.8 per cent and 21.4 per cent in the previous year, due to demand recession following periodical increases in selling prices and higher fuel costs.

#### Infrastructure Industries

4.8 As stated above, the performance of infrastructure industries was conspicuously poor as in the previous year. The average composite index for the production of six infrastructure industries (together accounting for a weight of 28.77 per cent in the general index of industrial production) recorded a lower growth of 4.8 per cent in 1990-91 against 6.2 per cent in 1989-90 and 8.2 per cent in 1988-89. Although actual output of four, viz., electricity, coal, saleable steel and cement, out of the six infrastructure industries, improved during the year 1990-91, the achievement in all the industries fell short of the targets set for them. Crude oil production was lower by 3.1 per cent over the previous year (33.1 million tonnes against 34.1 million tonnes) due inter alia to various problems at different locations in Gujarat, Assam and Southern region, non-availability of critical inputs like completion and testing equipment; petroleum refinery products also fell by 0.3 per cent (48.2 million tonnes against 48.3 million tonnes). In powers generation, the lower growth of 7.8 per cent against 10.9 per cent in 1989-90 was due to the poor performance of thermal units which were adversely affected by the backing down of thermal stations in the wake of increased hydro-generation (15.3 per cent). Production of coal, saleable steel and cement registered higher growth during 1990-91 than in the previous year (Table 4.3).

Table 4.3 : Trends in Production of Infrastructure Industries

Industry	Weight	Unit	April-March			Seventh Plan	
			1988-89	1989-90	1990-91	Plan Target	Index* (1980-81 = 100)
1	2	3	4	5	6	7	8
(1) Electricity	11.43	Billion Units	221.13 (+9.5)	245.14 (+10.9)	264.15 (+7.8)	280.00	251.0
(2) Coal(Excluding Lignite)	6.61	Million Tonnes	194.71 (+8.3)	200.89 (+3.2)	211.73 (+5.4)	226.00	198.2
(3) Saleable Steel	5.21	-do-	9.21 (+7.2)	9.03 (-2.0)	9.31 (+3.1)	12.64	201.2
(4) Cement	1.60	-do-	44.28 (+12.0)	45.78 (+3.4)	48.70 (+6.4)	49.00	262.6
(5) Petroleum Crude	2.41	-do-	32.04 (+5.5)	34.08 (+6.4)	33.03 (-3.1)	34.53	330.1
(6) Petroleum Refinery Products	1.52	-do-	45.38 (-2.2)	48.30 (+6.4)	48.15 (-0.3)	45.47	188.5
Composite Index of Infrastructure Production (Base: 1980-81 = 100)	28.77		193.2 (+8.2)	205.2 (+6.2)	215.0 (+4.8)		233.8

Note : Figures in brackets are the percentage variation over the corresponding figures of the previous year.

@These are original targets set to be achieved in the terminal year of the Seventh Five Year Plan.

\* Index compiled by RBI.

#### Industrial Policy Initiatives

4.9 The Government of India's Statement on Industrial Policy announced in Parliament on July 24, 1991 sets out a series of far-reaching policy initiatives taken in regard to industrial licensing, foreign direct investment, foreign technology agreements, public sector policy and the MRTP Act.

The central theme of this policy, which seeks to complement structural reforms already initiated in the areas of trade policy, exchange rate management, and fiscal policy and other macro and sectoral reforms, is liberalisation so as to "let the entrepreneurs make investment decisions on the basis of their own commercial judgement". First, the

requirement of industrial licensing will be abolished in respect of all industries irrespective of the size of investment, except for a short list of 18 specified industries which are related to security and strategic concerns, social reasons, hazardous chemicals and environmental issues, and items of elitist consumption. Industries reserved for the small-scale sector will continue to be so reserved. The mandatory convertibility clause will no longer be applied for term loans from financial institutions for new projects. Second the MRTP Act will be amended to remove the threshold limit of assets of MRTP companies so as to eliminate the requirement of prior approval by them for new undertakings and for expansion, merger, amalgamation and takeover of existing undertakings. The thrust of policy in this regard will be more on controlling and regulating the monopolistic, restrictive and unfair trade practices. Third, in regard to the public sector, its focus in future will be on strategic, high-tech and essential infrastructure industries, thus allowing private investment in 10 other areas hitherto reserved for the public sector. The task of formulating revival/rehabilitation schemes in respect of the chronically sick public sector enterprises will be referred to the BIFR or other similar high-level institutions created for the purpose. A social security mechanism will be created for the protection of the interest of workers which are likely to be affected by such rehabilitation packages. Fourth, with appropriate amendment to the Foreign Exchange Regulation Act, 1973, automatic approval will be given for foreign direct investment in 34 high-priority industrial categories if foreign equity covers the foreign exchange requirement for imported capital goods. Foreign equity proposals need not necessarily be accompanied by foreign technology agreements. With a special programme to attract substantial investment that would provide access to high technology and world markets, a Special Empowered Board would be constituted to negotiate with a number of large international firms and approve foreign direct investment in select areas. Finally, automatic permission will be given for foreign technology agreements in the aforesaid 34 high priority industrial categories up to a lumpsum payment of Rs. 1 crore, 5 per cent royalty for domestic sales and 8 per cent for exports, subject to total payment of 8 per cent of sales over a 10-year period.

4.10 In its new small-scale industry (SSI) policy statement released on August 6, 1991, the Government of India has sought to impart greater vitality and growth-impetus to the sector. The new policy confers greater focus on the promotion and nurturing of 'tiny' enterprises within the small-scale sector. Major ingredients of the policy are: enhancement in the investment limits for 'tiny' enterprises from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh; the restriction of special benefits like easier institutional credit, priority in Government purchases and relaxation from certain provisions of labour laws to the 'tiny' enterprises, while the other small-scale units would enjoy some one-time benefits like land allocation, electricity connection and skill/technology upgradation; widening of the scope of the National Enquiry Fund and the Single Window Loan Scheme including the channelling of composite loans through commercial banks; the shift of emphasis from subsidised/cheap credit to adequate flow of credit and the quality of its delivery which is to be ensured by a special monitoring agency; allowing equity participation, not exceeding 24 per cent, in the SSI units by other industrial undertakings to promote ancillarisation and sub-contracting; introduction of a Limited Partnership Act to enhance the supply of risk capital to the small-scale sector; and enactment of suitable legislation to ensure prompt payment of dues of small industries.

## 5. DEVELOPMENTS IN MONETARY POLICY

### Board Policy Thrust

5.1 As reported in the previous year's Annual Report, in the context of the overhang of liquidity and the resurgence of inflation in 1989-90, the paramount need at the time of formulating the monetary and credit policy for 1990-91 was to bring about a sharp break in inflationary expectation. This was sought to be achieved inter alia by a sharp reduction in the pace of overall monetary expansion—an objective of monetary management which was also buttressed by the fiscal objective of a marked cut-back in overall budgetary deficit. The unexpected turn of events, both domestic and external,

however, contributed to a further deterioration in the macro-economic imbalance. Despite a reasonably good performance of the real sectors, particularly the agricultural sector for the third year in succession, inflationary expectations remained unabated and even worsened during 1990-91. The avowed objective of curtailing the budget deficit, in particular the monetised deficit, was not attained. The rapidly deteriorating external payments situation, particularly after the Gulf crisis of August 1990, was reflected in a massive loss of foreign exchange reserves. In the absence of a regular Central Budget for 1991-92 and a medium-term stabilisation programme for restoring macro-economic balance, the burden of short-term economic management fell largely on the Reserve Bank's monetary and credit policy, particularly since February 1991.

5.2 Measures aimed at containing overall demand and in particular, the demand for imports have become the dominant elements of monetary and credit policy in the recent period. In response to the rapidly unfolding events, the credit and monetary policy measures became progressively stiffer which finally culminated in the imposition of cash margins of as high as 200 per cent on imports of goods under OGL and 150 per cent under specific licences (a sequential narration of these measures is set out in Part II of this Report). As part of aggregate demand management, deposit and lending rates were raised, an incremental cash reserve ratio was introduced, an interest rate surcharge was imposed on export financing and a restriction put on draws by borrowers with large limits. In this restrictive policy regime, while provisions were made to exempt export credit from the rigour of the regulations, interest rates on post-shipment export credit were raised beyond certain maturities to encourage faster realisation of export proceeds. The priority assigned to bank finance for export was reflected in a relaxation of the Reserve Bank's export refinance facility, as also the exquision of export credit from the stipulation relating to the incremental non-food credit-deposit ratio to be maintained in 1991-92. Furthermore, in consonance with the adjustment made in the exchange rate of the Rupee and significant reforms in trade policy with a view to achieving a speedier resolution of the acute external payment imbalance, the monetary measures were further reinforced in early July 1991 with an upward revision in the Bank Rate, across-the-board increase in the scheduled commercial banks' term deposit rates, an increase in the minimum lending rate of schedule commercial banks for credit limits of over 2 lakh, and a step-up in interest rates on various refinance facilities from the Reserve Bank. With the Government's decision to abolish export subsidies consequent upon the adjustment in the exchange rate of the Rupee, the interest rates on export credit were raised with effect from August 6, 1991.

5.3 While the major reoccupation has necessarily been on short-term management, which has necessitated a considerable tightening of monetary policy, the longer term objectives of reforming the credit delivery system, introducing flexibility in the application of the credit control measures, and bringing about structural changes in the money market also received due attention.

5.4 Important credit policy measures taken during the period under review are set out below:

### Rationalisation of the Structure of Lending Rates

5.5 Effective September 22, 1990, a major reform was undertaken of the structure of lending rates of scheduled commercial banks. The lending rate structure prescribed for banks had, over time, evolved into a complex one. The structure was characterised by a multiplicity of rates with concessionality in the interest rate dependent on numerous criteria such as, size of loan, priority nature of a sector, location of activity, programme-specific lending, incomes of borrowers and so on. Administering such a rate structure had become difficult and a rationalisation was overdue. An element of cross-subsidisation within the rate structure was, however, necessary since social concerns warranted continuation of an element of concessionality for small borrowers and the weaker sections of society. It was against this backdrop that a restructuring of the lending rate stipulations for banks was introduced. In the revised rate structure, all sector-specific and programme-specific lending rate prescriptions have been discontinued except for the Differential Rate of Interest (DRI)

Scheme and for export credit. By linking the concessionality in interest rates to the size of the loan, the new structure has sought to ensure that the basic societal concerns were taken care of while significantly reducing the multiplicity and complexity of the rate structure. The revised structure also has done away with the distinction between working capital and term loans except in the case of term loans for amounts of over Rs. 25,000 for agriculture, small-scale industries and road transport operators owning up to two vehicles. Where banks were given the discretion to determine the rate of interest for advances of over Rs. 2 lakh, they were advised to use this discretion judiciously. In the case of public sector procurement/distribution agencies the new lending rate structure did imply an increase over the existing rate. Banks had, however, been advised that it would be reasonable to charge 16.0 per cent per annum on borrowings by such agencies.

5.6 The revised structure of lending rates (other than for DRI advances and export credit) for scheduled commercial banks, effective September 22, 1990, is indicated below :

Interest rate structure for advances of scheduled commercial banks (other than DRI advances and Export Credit) effective September 22, 1990

Size of Limit	Rate of Interest (percent per annum)
(a) Up to and inclusive of Rs.7,500/-	10.0
(b) Over Rs. 7,500/- and up to Rs. 15,000/-	11.5
(c) Over Rs. 15,000/- and upto Rs. 25,000/-	12.00
(d) Over Rs. 25,000/- and upto Rs. 50,000/-	14.0
(e) Over Rs. 50,000/- and up to Rs. 2 lakh	15.0
(f) Over Rs. 2 lakh	16.0
	(minimum)

5.7 The above structure of lending rates was made applicable to both working capital and term loans. In the case of term loans to agriculture, small-scale industry and transport operators owning up to two vehicles, the following fixed rates were prescribed :

Size of limit	Rate of interest (per cent per annum)
(i) Over Rs. 25,000/- and upto Rs. 50,000/-	13.00
(ii) Over Rs. 50,000/-	14.00

5.8 With effect from September 22, 1990, the effective interest rate on discounting of bills for borrowers in the category of 16.0 per cent (minimum) was set at one percentage point below the actual lending rate charged to borrowers in this category.

5.9 In regard to the impact of the new structure of lending rates, in the case of short-term agricultural advances up to Rs. 25,000 there has been no change as compared with the earlier concessive rates, while for advances over Rs. 25,000 and up to Rs. 2 lakh, there occurred some reduction in the rates depending on the amount of the advance. In the case of short-term advances to small-scale industry, the new rates, though related only to the size of the loan, were not materially different from the previous rates for most borrowers. As regards term loans, the new structure of rates, unlike the previous one, is linked solely to the size of the loan; however, for agriculture, small-scale industry and transport operators up to two vehicles, lower rates by one to two percentage points were prescribed in the case of certain ranges of term loans with a view to keeping the new rates as close as possible to the then existing rates.

5.10 As the rationalisation of the lending rate structure was not intended to encourage the demand for certain loans by offering relatively low interest rates, effective October 10,

1990, scheduled commercial banks were permitted to freely determine the rates of interest applicable to the following categories of loans : (i) loans for purchase of consumer durables ; (ii) loans to individuals against shares and debentures bonds ; and (iii) other non-priority sector personal loans.

Policy Measures for the Second Half of the Financial Year 1990-1991.

5.11 The credit policy package for the second half of 1990-91, announced on October 9, 1990 was drawn up against the backdrop of the Gulf crisis, the strain on the balance of payments and the accelerating inflationary pressures. Despite three successive years of good agricultural output, the uptrend in prices had continued. It was felt that with the sharp increase in petroleum prices abroad, inflationary pressures in the Indian economy would be further aggravated. Notwithstanding the subdued monetary expansion in the first half of the financial year 1990-91, it was felt that the strong restrive money growth could result in an acceleration in monetary expansion in the second half of the year. In the context of the Gulf situation and the consequent pressure on balance of payments, banks were advised to make every effort to meet the credit requirements of the export sector. The importance of utilising the lines of foreign currency credit available with the term-lending institutions for the import of capital goods was stressed and banks were advised to direct such credit demands to the financial institutions for being financed under these lines of credit (for details, see Part II of this Report).

5.12 The major policy changes effected during the period are set out below :

(a) Deposit Rates

5.13 Effective October 10, 1990, a new category of deposits of three years and above attracting a rate of interest of 11.0 per cent per annum was introduced raising the maximum rate on term deposits by one percentage point. This measure was intended essentially to offer a better rate on savings in the form of longer term bank deposits and also to assist banks in their deposit mobilisation efforts.

(b) Shut-out Period for Discretionary Refinance Facility

5.14 There were again, as in the previous year, large increases in aggregate deposits and non-food credit of scheduled commercial banks in the last eight days of March 1990 which distorted monetary and banking aggregates. While factors beyond the control of banks such as the Government's receipts and disbursements were partly responsible, it was clear that such factors did not fully explain the phenomenal year-end bulge. As a deterrent, it was decided not to permit banks to draw discretionary refinance without prior sanction from the Reserve Bank during the three fortnights covering the period March 9, 1991 to April 19, 1991.

(c) Access to the Call Money Market

5.15 With a view to further widening and bringing about greater integration of various segments of the money market, all the participants in the bills rediscounting market, who were not operating in the call/notice money market, were granted entry into the call/notice money market as lenders effective October 20, 1990. Institutional participants in the call money market were, however, not allowed to lend in the call/notice money market, if they had short-term borrowings from the Reserve Bank.

(d) Commitment Charges on Unutilised Portion of Credit Limits

5.16 In the context of the problems faced by banks because of large unutilised credit limits and the several constraints this creates in implementing macro-credit policy, it was decided to levy a commitment fee on the unutilised portion of working capital limits. Accordingly, with effect from January 1, 1991, in the case of all borrowers with working capital limits of Rs. one crore and over, scheduled commercial banks were required to levy a minimum commitment charge of one per cent per annum on the unutilised portion of the quarterly operating limits subject to a tolerance level of 15 per cent. This measure was intended to bring about discipline in the availment of bank finance by borrowers and facilitate better funds management by banks.

## (e) Financing of Inland Credit Sales

5.17 With a view to encouraging the bill culture, in March 1987, it was indicated that effective April 1, 1988, the credit limits sanctioned by a bank to the then Credit Authorisation Scheme (CAS) borrowers against book-debts should not be more than 75 per cent of the aggregate limits sanctioned to such borrowers for financing inland credit sales. As sufficient time had elapsed since the prescription of this stipulation, it was decided that in the case of fund-based working capital limits of Rs. 5 crore and over, effective January 1, 1991, interest at 2 percentage points above the rate on the relevant cash credit should be levied on that portion of the book-debt finance which would be in excess of the prescribed norm of 75 per cent of limits sanctioned to borrowers for financing inland credit sales.

## (f) Revised Scheme of Graduated Interest Rates on Cash Balances Maintained with the Reserve Bank

5.18 Effective December 29, 1990, the scheme of graduated interest rates on cash balances maintained by scheduled commercial banks with the Reserve Bank was revised following satisfactory experience in regard to compliance by banks. Unlike under the existing scheme where progressively lower interest rates were stipulated on 'eligible' cash balances as the shortfall in the cash reserve ratio (CRR) increased, under the revised scheme banks earn interest at the normal rate [i.e., 10.5 per cent per annum on 'eligible' cash balances maintained on net demand and time liabilities (DTL) as on March 23, 1990 and 8.0 per cent per annum on 'eligible' cash balances maintained on incremental net DTL thereafter] but the amount of interest so arrived at would be reduced by an amount calculated at a rate of 25 per cent per annum on the amount of the shortfall. On this basis, the effective interest rate on 'eligible' cash balances would decline smoothly and to cost of a shortfall in CRR would not fluctuate as was the case earlier when the cost varied at different ranges of shortfall (Tables 5.1 and 5.2 below).

## (g) Certificates of Deposit (CDs)

5.19 In order to broaden the primary market and to facilitate the development of a secondary market in CDs, the bank-wise limits for issue were raised from 2 per cent to 3 per cent of average aggregate deposits in 1989-90. As a result, the aggregate limits for the banking system for issue of CDs increased from Rs. 3,018 crore to Rs. 4,522 crore. The minimum denomination of a CD was lowered from Rs. 10 lakh to Rs. 5 lakh and the minimum size of an issue also lowered from Rs. 50 lakh to Rs. 25 lakh.

## (h) Export Credit Refinance

5.20 The growth of export credit had not been commensurate with the overall growth in net bank credit and in view of the developments in the Gulf region and the consequent pressure on the balance of payments, banks were advised to make substantive efforts to support exports. Considering the paramount need to promote exports and also to provide greater incentive to banks to finance exports, banks' access to export credit refinance was increased and with effect from January 1, 1991, scheduled commercial banks were provided export credit refinance at a rate of 9 per cent per annum equivalent to 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of export credit for the financial year 1989-90. This measure increased banks' access to export refinance by about Rs. 1,000 crore in the financial year 1990-91.

## (i) Selective Credit Controls

5.21 Taking into account the good Kharif foodgrains production for the 1990-91 season and the comfortable public sector stocks, the minimum margins on bank advances against paddy/rice and 'other foodgrains' were reduced across-the-board by 15 percentage points, effective October 10, 1990. On a review of the subsequent price-output developments relating to paddy/rice and 'other foodgrains', however, effective January 8, 1991 the minimum margins were raised across-the-board by 15 percentage points.

Table 5.1 : Schedule of Graduated Interest Rates on Cash Balances

Previous (Effective April 21, 1990)	
Shortfall during a fortnight as percentage of the absolute amount of cash reserves required to be maintained (up to and inclusive of)	Rate of interest payable on the amount above the statutory minimum of 3 per cent actually maintained on net demand and time liabilities as on March 23, 1990
1	2
0.0	10.50
2.0	10.00
4.0	9.25
6.0	8.50
8.0	7.00
10.0	6.00
Over 10.0	0.00

Revised (Effective December 29, 1990)	
Item	Rate of Interest (per cent per annum)
I. Interest payable on Eligible Cash Balances Relating to:	
(a) Net DTL as on March 23, 1990	10.5
(b) Incremental net DTL thereafter	8.0
II. Interest Deduction on the amount of CRR shortfall	25.0
III. Net Interest Payable (I-II)	

Table 5.2 : Illustration on Effective interest rate on 'Eligible' Balances and the related costs of CRR shortfalls

Previous Scheme (effective April 7, 1990)		Revised Scheme (effective December 29, 1990)		
Shortfall (as percentage of CRR Balances Required to be Maintained)	Effective Interest Rate on Eligible Balance (per cent)	Cost of Short-fall (per cent)	Effective Interest Rate on Eligible Balance (per cent)	Cost of Shortfall (per cent)
1	2	3	4	5
0.0	10.17	0.0	10.17	0.0
0.5	9.74	69.1	10.01	25.0
1.0	9.74	34.3	9.85	25.0
1.5	9.73	22.7	9.69	25.0
2.0	9.73	16.9	9.52	25.0
2.5	9.08	33.5	9.36	25.0



1	2	3	4	5
3.0	9.08	27.7	9.19	25.0
3.5	9.08	23.6	9.02	25.0
4.0	9.08	20.5	8.85	25.0
4.5	8.43	28.9	8.66	25.0
5.0	8.43	25.8	8.49	25.0
5.5	8.43	23.3	8.30	25.0
6.0	8.43	21.2	8.12	25.0
7.0	7.14	31.3	7.75	25.0
8.0	7.14	26.9	7.36	25.0
9.0	6.29	30.3	9.96	25.0
10.0	6.30	26.8	6.56	25.0
10.5	0.00	80.0	6.35	25.0
11.0	0.00	76.5	6.14	25.0
11.5	0.00	73.3	5.92	25.0
12.0	0.00	70.3	5.70	25.0
15.0	0.00	56.8	4.33	25.0
20.0	0.00	43.2	1.73	25.0
22.9	0.00	38.0	0.00	25.0
23.0	0.00	37.9	0.00	37.9

## Notes:

1. The above rate and effective costs have been worked on assuming an increase of 15 per cent in NDTL over the outstanding as on March 22, 1990.
2. The cost of shortfall is the interest loss on eligible balances actually maintained plus the penalty rate applicable in the case of shortfalls exceeding 22.9 per cent.

## Policy Measures for the First Half of the Financial Year 1991-92

5.22 At the time of formulating the credit policy for 1991-92, it was considered prudent to plan on the basis of a real GDP growth of not more than 4 per cent for the year. Given the large overhang of primary liquidity and the need to restrain the rise in demand, a moderation of the pace of monetary and credit expansion was considered imperative. The interim Budget of the Central Government had indicated the intention to contain the gross fiscal deficit at 6.5 per cent of GDP in the financial year 1991-92. Contingent on this fiscal objective and consistent with the postulated real growth of 4 per cent in GDP and inflation rate of not more than 7 per cent, the objective of monetary policy was set at containing monetary expansion ( $M_3$ ) in 1991-92 to 14 per cent.

5.23 Banks were advised to plan their credit budgets on the basis of a working estimate of deposit growth of Rs. 29,500 crore (15.4 per cent) in 1991-92 (April-March). Food credit was estimated to rise by Rs. 1,900 crore during April-June 1991 and decline by Rs. 300 crore in the next quarter. The non-food credit increase was estimated at around Rs. 3,500 crore in the first half of the financial year. As the credit policy for 1991-92 was formulated against the backdrop of the difficult foreign exchange situation, it was clarified to banks that though the imposition of additional cash margins on imports would cause some problems for their constituents, the measure had to be strictly implemented to ensure that the over-riding objective of safeguarding the foreign exchange position was attained. It was also emphasised that exports should be accorded a high priority. While the major pre-occupation of the policy was necessarily on short-term management, certain measures relating to the structural development of the money market, were also introduced.

The following changes were made in the credit policy measures :

## (a) Incremental Net Non-Food Credit (Excluding Export Credit) Deposit Ratio

5.24 With the sharp acceleration in the inflation rate in 1990-91 and the deterioration of the external payments position, there was need for a very cautious approach to expansion in bank credit. Accordingly, for 1991-92 (April-March), scheduled commercial banks were required to ensure that their incremental net non-food credit (excluding export credit)—deposit ratio did not exceed 45 per cent. In view of the paramount need to facilitate the export effort, export credit was kept outside the framework of the stipulated credit-deposit ratio. The base date for this ratio was fixed at March 22, 1991 and the ratio would be monitored cumulatively on a fortnightly basis. Banks which exceed the stipulated ratio are charged additional interest with effect from the fortnight beginning April 20, 1991, at a rate of 3 percentage points on the refinance drawn from the Reserve Bank under all facilities (export, stand-by, discretionary and 182 Days Treasury Bill) on the amount of the excess credit over the stipulated level or the refinance drawn, whichever was lower. Banks which persistently exceed the stipulated ratio would face a total withdrawal of all refinance facilities.

## (b) Export Credit Refinance

5.25 Scheduled commercial banks were hitherto provided export credit refinance equivalent to 100 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of export credit in 1988-89. These refinance limits amounted to Rs. 4,129 crore as on March 22, 1991, equivalent to 44.6 per cent of outstanding export credit. It had been the normal practice to bring forward each year the base for determining export refinance. This is unavoidable under a system where banks are provided 100 per cent export refinance for incremental export credit. Considering the overwhelming importance of providing continued support to the export sector and at the same time avoiding an unduly large increase in created money, the impact of the base change was moderated by the introduction of a two-tier export refinance formula. Accordingly, effective July 27, 1991, banks are provided export refinance to the extent of 50 per cent of the increase in export credit over the monthly average level of 1988-89 up to the monthly average level of 1989-90 plus 100 per cent of the increase over the monthly average level of export credit in 1989-90. The new formula would enable banks to cater to the incremental credit requirements of the export sector without resources constraint. Although banks' refinance levels would initially be reduced, they would be recouped well before the inception of the busy season.

## (c) Lending Rates

5.26 In the context of the existing high inflation rate and the imperative need to restrain monetary expansion, effective April 13, 1991, the lending rate on limits of over Rs. 2 lakh was raised by one percentage point from 16.0 per cent (minimum) to 17.0 per cent (minimum). Banks were advised to raise the rates for all borrowers under this category by at least one percentage point over the prevailing rates. The effective interest rate on discounting of bills of exchange for this category of borrowers was made 16.0 per cent (minimum) instead of the existing 15.0 per cent (minimum) and the actual rate charged was to be one percentage point below the corresponding lending rate charged to borrowers in this category.

5.27 Again, in the context of the need to reduce aggregate demand in the economy and also taking into account the increase in deposit rates (referred to below), effective July 4, 1991, the lending rate on limits of over Rs. 2 lakh was raised by 1.5 percentage points from 17.0 per cent (minimum) to 18.5 per cent (minimum). The effective interest rate on discounting bills of exchange for this category of borrowers would be one percentage point below the corresponding lending rate charged to borrowers in this category. In the case of term loans to agriculture, small scale industry and transport operators owning up to two vehicles, such loans would continue to be governed by the rates prescribed as of September 22, 1990.

## (d) Deposit Rates

5.28 Considering the need for a better alignment between the maximum deposit rate and the yield on alternative savings instruments and to reflected the prevailing inflation rate, scheduled commercial banks' term deposit rate for three years and over was raised by one percentage point, effective

April 13, 1991, from 11.0 per cent to 12.0 per cent. All other deposit rates remained unchanged. The cost for banks arising from the higher interest rate on deposits was approximately equal to their increased interest earnings as a result of the higher lending rates referred to above.

5.29 Furthermore, with a view to ensuring that banks finance their lending operations out of their own resources and to enable banks to compete with alternative savings instruments, the term deposit rates of scheduled commercial banks were raised across-the-board by one percentage point effective July 4, 1991. The change in the structure of deposit rates (excluding FCNR/NRE Accounts) are set out below :

Interest rates on deposits of Scheduled Commercial Banks  
(Excluding FCNR/NRE Deposits)

Category of Account	(per cent per annum)		
	Rates Effective October 10, 1990	Rates Effective April 13, 1991	Rates Effective July 4, 1991
(1)	(2)	(3)	(4)
Current	Nil	Nil	Nil
Savings	5.0	5.0	5.0
Term Deposits			
(a) 46 days to less than one year	8.0	8.0	9.0
(b) One year to less than two years	9.0	9.0	10.0
(c) Two years to less than three years	10.0	10.0	11.0
(d) Three years and over	11.0	12.0	13.0

Note : The changes in deposit rates are applicable only to fresh deposits and renewal of maturing deposits.

(e) Interest Rates on Deposits under Non-Resident (External) Rupee Accounts

5.30 The interest rates on Non-Resident (External) Rupee (NRE) deposits with maturities of 3 years and above but less than 5 years and of 5 years and above were raised by one percentage point effective April 13, 1991. Accordingly, the maximum deposit rate for NRE deposits was raised to 14 per cent from 13 per cent hitherto.

(f) Selective Credit Controls

5.31 In the area of selective credit controls the following measures were effected :

(i) Reference period for Credit Ceilings

For commodities where there was a stipulation of the level of credit ceilings based on the three-year period 1986-87 though 1988-89 (November-October), the base period was brought forward to the three-year period ending 1989-90 (November-October), effective April 13, 1991.

(ii) Level of Credit Ceilings

The level of credit ceilings applicable on oilseeds/vegetable oil was reduced from 100 per cent to 85 per cent of the peak level of credit maintained by each party in the three-year period ending 1989-90 (November-October), effective April 13, 1991.

(iii) Sugar

5.32 Considering the increase in cane price arrears payable to sugarcane growers and the need to provide relief to them, with effect from May 9 1991, the minimum margin

applicable on bank advances against unreleased stocks of sugar was lowered in the case of processing units/mills to 17.5 per cent from the existing stipulation of 20 per cent. This concession was available only for a period of three months, i.e., up to August 8, 1991, after which the minimum margin reverted to 20 per cent. The structure of minimum margins/levels of credit ceilings on advances against commodities covered by selective credit controls is set out in Table 5.3.

(g) Certificates of Deposit

5.33 The outstanding amount of CDs issued by 46 major scheduled commercial banks as on February 22, 1991 amounted to Rs. 3,035 crore and formed 69.0 per cent of the revised limits of Rs. 4,383 crore of these banks for issue of CDs. To enable banks to effectively compete with other instruments for bulk funds and to give banks the flexibility to raise funds from the market when they have a need for mobilising such funds, it was felt necessary to give sufficiently large CD limits so that the smaller banks have adequate limits to mobilise bulk funds. Accordingly, effective April 20, 1991, the limits for issue of CDs by scheduled commercial banks (excluding regional rural banks) were enhanced from 3 per cent to 5 per cent of the fortnightly average of outstanding aggregate deposits in 1989-90. Consequently, the aggregate limits for the banking system for the issue of CDs were raised from Rs. 4,522 crore to Rs. 7,537 crore.

(h) Commercial Paper

5.34 Sufficient experience had been gained regarding the operation of the instrument of Commercial Paper (CP) and it was felt that the guidelines could be relaxed to enable wider participation and also to ensure a greater degree of flexibility in its operation. Accordingly, effective May 30, 1991, the following changes were made in the scheme :

Table 5.3 : Minimum margins and level of credit ceilings  
(effective May 9, 1991)

(Percentage)				
Commodities	Minimum Margins			Level of Credit
	Mills/ Processing units	Others	Warehouse receipts	ceiling (Base year: Three years ending 1989-90 (Nov.-Oct.))
1	2	3	4	5
1. Paddy rice	45	60	45	85
2. Pulses	45	60	45	85
3. Other foodgrains	45	60	45	85
4. Oilseeds (viz. groundnut, rapeseed/mustard, cottonseeds, linseed, castor seed and all imported oilseeds)	60	75	60	85
5. Vegetable oils (viz. groundnut oil, rapeseed/ mustard oil, cottonseed oil, linseed oil, castor oil, vanaspathi and all imported vegetable oils)	60@	75	60	85

1	2	3	4	5
6. Sugar				
(a) buffer stock	nil	—	—	—
(b) Unreleased stock	17.5	—	—	—
(c) Released stock	75	75	60	—
7. Gur and Khandsari	45	75	60	—

@Applicable to registered oil mills and vanaspati manufacturers.

—Not Applicable.

\* Upto August 8, 1991; thereafter the minimum margin to reverted to 20 per cent.

(i) The working capital (fund-based) limit of the issuing company was reduced to not less than Rs. 10 crore instead of Rs. 15 crore hitherto.

(ii) The ceiling on the aggregate amount to be raised by a company by issue of CP was raised from 20 per cent to 30 per cent of its working capital (fund-based) limit.

(iii) The denomination of CP could be in multiples of Rs. 5 lakh (Rs. 10 lakh hitherto) subject to the minimum size of an issue to a single investor being Rs. 25 lakh (face value) instead of Rs. 50 lakh (face value) hitherto.

(iv) The requirement for banks to obtain prior approval from the Reserve Bank was dispensed with. The parties will, however, be required to meet the procedural requirements through their banks and the banks would in turn be required to submit fortnightly returns to the Reserve Bank on a post-sanction basis.

(i) Widening of Participants in the Call/Notice Money and Bills Rediscounting Markets

5.35 In the light of the felt need to widen the call/notice money and bills rediscounting markets, access, as lenders, to these markets would be provided to such entities as were able to show evidence to the Reserve Bank of bulk lendable resources. Such entities would be required to observe a minimum size of operation of Rs. 20 crore per transaction and such transactions would be permitted only through the DFHI. The lending entities would be required to give an undertaking that they had no outstanding borrowings from the banking system. Entities wishing to participate in the call/notice and bills rediscounting markets would be required to approach the Reserve Bank for permission to enter these markets.

(j) Money Market Mutual Funds (MMMFs)

5.36 With a view to providing an additional short-term avenue to investors and to bring money market instruments within the reach of individuals and small bodies, it was considered desirable to allow scheduled commercial banks and their subsidiaries to set up Money Market Mutual Funds (MMMFs). The MMMFs are a special genre of mutual funds which invest only in high quality money market instruments of a short-term nature. The recent introduction of several new money market instruments like the Certificates of Deposit, the Commercial Paper and the 182 Days Treasury Bills, was essentially meant to tap bulk funds and as such a relatively high minimum transaction amount had been stipulated. By bringing a wide range of short-term money market instruments within the reach of individual investors, the MMMFs would undertake a size intermediation. It was in this context that MMMFs is as follows:

Broad framework of the scheme for MMMFs is as follows:

(i) Only banks and their subsidiaries would be permitted to set up MMMFs.

(ii) Individuals and other bodies would be permitted to invest their resources in MMMFs in the form of negotiable/transferrable instruments and MMMF deposit accounts. Suitable ceilings may be fixed on mobilisation of such funds by banks and their subsidiaries (this could, in the first instance be equivalent to one per cent of aggregate deposits).

(iii) The minimum size of investment would be Rs. one lakh and repurchases could be subject to a minimum lock-in-period of 3 months.

(iv) MMMFs could be allowed to invest only in special short-term money market instruments (CDs, CPs, 182 Days Treasury Bills, rediscounting of commercial bills and call and short-notice money) as lenders. A minimum of 20 per cent of the MMMFs funds could be required to be held in 182 Days Treasury Bills and a maximum of 20 per cent in call and short-notice money.

(v) The funds mobilised by MMMFs would not be subject to reserve requirements as these funds are in turn invested in money market instruments.

(vi) The question of stamp duty would need to be examined.

5.37 To fully develop this broad framework and to study the implication of such a scheme a Task Force consisting of representatives of banks and the Reserve Bank of India is to be set up by the Reserve Bank to work out the detailed operative guidelines and documents of MMMFs.

(k) Export Credit Interest Rates

5.38 With a view to providing an incentive to exporters who repatriate the proceeds early, and at the same time making credit costly to those who delay the repatriation of export proceeds, the interest rates on post-shipment credit were revised in three stages with effect from April 1, April 23, and August 6, 1991. As an incentive to repatriate export proceeds faster, a special concessive rate of 7.0 per cent was prescribed for periods up to 45 days, while the rate for periods beyond 45 days and up to 90 days has been left unchanged. For export proceeds repatriated after 90 days but before 6 months of the date of shipment, the interest applicable would be 18 per cent for the entire period from the date of advance. For proceeds repatriated after 180 days, a rate of interest of 25 per cent would be applied for the entire period from the date of advance (Table 5.4).

5.39 With the adjustment in the exchange rate of the Rupee, the Government decided to abolish subsidies on exports. Consequently, effective August 6, 1991, the interest rate structure on export credit was revised. While the interest rate on pre-shipment credit up to 180 days was raised to 12.50 per cent per annum, a rate of 14.50 per cent per annum was stipulated for pre-shipment credit beyond 180 days and up to 270 days (in which case the prior approval of the Reserve Bank has to be obtained).

(l) Incremental Cash Reserve Ratio

5.40 In view of the acute foreign exchange situation and the consequent need to contain overall demand by moderating expansion, in addition to the cash reserve ratio of 15 per cent; scheduled commercial banks were required to maintain, with effect from May 4, 1991 an incremental cash reserve ratio of 10 per cent of the increase in net demand and time liabilities over the level as on May 3, 1991. The effect of the stipulation would be different for individual banks depending on the rates of growth in their net demand and time liabilities. Interest at 8 per cent per annum would be paid on these additional cash balances.

(m) Interest Rate Surcharge on Import Finance

5.41 With a view to discouraging the use of bank credit to finance imports, an interest rate surcharge on import finance was introduced. Accordingly, banks were advised that the use of bank credit to finance imports should be earmarked under a separate sub-limit of the cash credit limit and outstanding under the import credit sub-limit for parties with total credit limit of Rs. 2 lakh and over were subject, effective May 9, 1991, to an interest rate surcharge of 25

Table 5.4 : Scheduled Commercial Banks : Interest Rates on Export Credit

Export Credit	(Per cent per annum)			
	Rates up to March 31, 1991	Rates effective April 1, 1991	Rates effective April, 23, 1991	Rates effective August 6, 1991
1. Pre-shipment credit				
(a) (i) Up to 180 days	7.50	7.50	7.50	12.50
(ii) Beyond 180 days and up to 270 days (with the prior approval of the Reserve Bank of India)	9.50	9.50	9.50	14.50
(b) Against cash incentives, etc. covered by ECGC guarantee up to 90 days	7.50	7.50	7.50	12.50
2. Post-shipment credit				
(i) Demand bills for transit period (as specified by FEDAI)	8.65	8.65	7.00	12.50
(ii) Usance Bills (For period comprising usance period of export bills, transit period, as specified by FEDAI, and grace period, wherever applicable)				
(a) Up to 45 days			7.00	12.50
(b) Beyond 45 days up to 90 days	8.65	8.65	8.65	
	(up to 180 days)	(up to 90 days)		
(c) Beyond 90 days up to six months from date of shipment		16.00 (from the date of advance)	18.00 (from the date of advance)	18.00 (from the date of advance)
(d) Beyond six months from date of shipment		16.00 (plus a surcharge of 2.00 from the date of advance)	25.00 (from the date of advance)	25.00 (from the date of advance)
(iii) Cash incentives, duty draw back, etc. receivable from Government covered by ECGC Guarantee (up to 90 days)	8.65	8.65	8.65	12.50
(iv) Undrawn balance (up to 90 days)	8.65	8.65	8.65	12.50
(v) Against retention money (for supplies portion only) payable within one year from the date of shipment (up to 90 days)	8.65	8.65	8.65	12.50
3. Deferred Credit				
Deferred credit for the period beyond 180 days	8.65	8.65	8.65	12.50
4. Duty Drawback Credit Scheme, 1976	Free of interest	Free of interest	Free of interest	Free of interest
Against duty drawback as provisionally certified by the Customs Authorities (up to 90 days)				
5. Export credit not otherwise specified	14.00 to 15.50	16.00 (minimum)	18.00 (minimum)	18.50 (minimum)

per cent. For purposes of this surcharge, drawals of bank finance for providing the cash margin on imports will be treated as import finance as also debits to make payments for imports. While the outstandings under the import sub-limit would stand reduced when the cash margin on imports is released, repayments to the import sub-limit would be permitted from the same proceeds subject to the proviso that there would be a minimum period of one month during which a payment for imports from the import sub-limit cannot be liquidated by sale proceeds. The surcharge would be levied on imports subject to 'Nil' cash margins on imports as well as imports subject to prescribed cash margins. Imports of capital goods would also be subject to the surcharge. Bank finance provided to meet the cost of imported inputs covered by export packing credit has been exempted from the surcharge.

#### (a) Restriction of Drawals under Large Cash Credit limits

5.42 Due to the difficulties experienced by banks in effectively implementing measures of credit restraints under the existing cash credit system, there was a sizeable gap between the limit sanctional and their actual utilisation. In view of the imperative need to restrain credit expansion in the immediate few months, particularly in the context of the need to conserve foreign exchange reserves, banks were advised that, in the case of all accounts of borrowers with aggregate credit limits of Rs. 1 crore and over from banks, the effective drawing power under the limits for cash credit and inland bills for the period May 9, 1991 up to September 30, 1991 would be limited to 100 per cent of the peak level of actual utilisation during the corresponding period of May

9-September 30 in the past three years. Banks were required to ensure that this method of arriving at the effective drawing limit did, in no case, result in raising the cash credit limits as they stood on May 8, 1991. Limits authorised by the Reserve Banks as also export credit (export finance limits sanctioned for pre-shipment and post-shipment purpose) and sick/weak units where rehabilitation packages have been sanctioned would be outside the framework of this stipulation. Some flexibility has been allowed in the application of the peak utilisation in case of newly-established units which are due to start production and in case of existing units undergoing the process of expansion, diversification or modernisation. In the case of the sugar industry, the banks would sanction need-based credit limits not exceeding 110 per cent of the peak level of actual utilisation.

5.43 Banks were further advised that for the period May 9 to September 30, 1991, sugar mills having higher level of sugar stock during 1990-91 crushing season compared to 1989-90 crushing season may be sanctioned additional credit limits subject to usual margin and other conditions. Banks were, however, to ensure that the amount of additional credit limit so sanctioned and disbursed to sugar mills would be utilised only for paying dues to the cane growers.

(o) Increase in Bank Rate :

5.44 In the context of the need to further tighten monetary measures in consonance with other measures taken to achieve an adjustment of the external payments imbalance, one of the monetary measures taken was to raise the Bank Rate by one percentage point, i.e. from 10.0 per cent to 11.0 per cent, with effect from the close of business of July 3, 1991. All rates of interest on advances from the Reserve Bank specifically linked to the Bank Rate were correspondingly raised by one percentage point unless otherwise specified.

(p) Interest Rates on Reserve Bank Accommodation :

5.45 In consonance with the increase in the Bank Rate and the need to align refinance rates with the increase in lending rates of scheduled commercial banks, interest rates on the following refinance facilities were raised, effective July 4, 1991.

Interest rates on RBI Refinance

(per cent per annum)

Refinance facility	Effective upto July 3, 1991	Effective July 4, 1991
Export Refinance	9.0	9.5
Stand-by Refinance	12.5	13.5
Discretionary Refinance	14.0	17.0
	(Minimum)	(Minimum)
Food Refinance	11.5	14.0

## 6. TRENDS IN MONEY AND CREDIT

6.1 During the period under review, the growth of monetary aggregates was noticeably subdued. The rate of expansion in both broad and narrow money during the fiscal year 1990-91 was significantly lower than in the previous year. The deceleration also persisted during the first quarter of 1991-92. There was some moderation in the growth of bank credit to the commercial sector during the fiscal year 1990-91 a trend which continued during the first quarter of 1991-92. A major factor contributing to the perceptibly slower monetary expansion during the past year or so has been the massive loss of net foreign exchange assets of the banking sector as a result of the sizeable current account deficit in the balance of payments. There was a slower growth in bank deposits during 1990-91; the slowdown in non-food credit expansion was due to a number of factors: continuance of the stipulation regarding 60 per cent incremental non-food credit-deposit ratio; improved cash flow position of the private corporate sector; direct mobilisation of funds through the capital market by corporate entities; the operation of the debt relief scheme leading to lower demand for credit in rural areas; and the actual writing-off of agricultural and other loans by banks under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990.

Money Supply :

6.2 Monetary expansion in terms of broad money (M) at Rs. 35,904 crore (15.5 per cent) during 1990-91 was considerably lower as compared with the increase of Rs. 37,866 crore (19.6 per cent) during 1989-90 (Table 6.1). The monetary expansion during 1990-91 turned out to be close to the targeted decrease in the rate of growth by 4 percentage points below the previous year's expansion, set out in the credit policy announcement in April 1990. Considering that the target was predicated on the postulate that net Reserve Bank credit to Central Government would be Rs. 7,206 crore, whereas the actual (as per March 31, 1991 data) was at Rs. 14,746 crore, or over twice the projected figure, the attainment of the monetary target was fortuitous as it largely reflected the drawdown of the net foreign exchange assets. On the basis of the average of reporting Fridays, the growth of M3 during 1990-91 was 16.6 per cent as compared with 18.8 per cent in the previous year.

6.3 Money supply with the public (M1) recorded a much lower increase of Rs. 13,160 crore (16.2 per cent) during 1990-91 against Rs. 14,814 crore (22.2 per cent) during 1989-90. In terms of average of reporting Fridays too, the rate of expansion of M1 at 17.6 per cent was lower than the rate of 20.1 per cent in the previous year.

Table 6.1: Variations in Money Stock (M<sub>3</sub>)

Items	(Rupees crore)							
	Variations during**							
	1989-90		1990-91*		1990-91 (April-June)		1991-92* (April-June)	
	Absolute Percentage		Absolute Percentage		Absolute Percentage		Absolute Percentage	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. M <sub>3</sub> (a+b+c)	37,866	19.6	35,904	15.5	10,162	4.4	10,166	3.8
(a) Currency with the public	8,231	21.4	6,727	14.4	2,494	5.3	3,482	6.5

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(b) Aggregate Deposits with Banks (i+ii)	29,269	18.9	27,823	15.1	7,681	4.2	7506	3.5	
(i) Demand Deposits	6,217	22.4	5,079	15.0	1,772	5.2	1793	4.6	
(ii) Time Deposits	23,052	18.2	22,744	15.2	5,909	3.9	5713	3.3	
(c) 'Other Deposits with RBI	366	79.2	1,354	163.5	—13	—1.6	—822	—37.7	
II. M 1(a+b(i)+c)	14,814	22.2	13,160	16.2	4,253	5.2	4453	4.7	
III. Sources of Money Stock (M3) (1+2+3+4+5)									
1. Net Bank Credit to Government (A+B)	19,630	20.3	21,483	18.4	9,737	8.4	12677	9.2	
A. RBI's net credit to Government (i+ii)*	13,031(a)	21.7	13,594(b)	18.6	6,661(c)	9.1	9,286	10.7	
(i) Net claims on Central Government (a—b)	12,672	21.2	13,955	19.2	7,172	9.9	9,429	10.9	
(a) Claims on Central Government	12,626	21.1	13,997	19.3	7,259	10.0	9,438	10.9	
(b) Deposits of Central Government	—46	—46.0	42	77.8	87	161.1	9	9.4	
(ii) Net claims on State Government (a—b)	359	245.9	—361	—71.5	—511	—101.2	—143	—99.3	
(a) Claims on State Governments	362	232.1	—359	—69.3	—507	—97.9	—142	—89.3	
(b) Deposits of State Governments	3	30.0	2	15.4	4	30.8	1	6.7	
B. Other banks' credit to Government	6,599	17.9	7,889	18.2	3,076	7.1	3,391	6.6	
2. Bank Credit to Commercial Sector (A+B)	23,183	18.2	21,912	14.6	2,974	2.0	1,667	1.0	
A. RBI's credit to commercial sector@@	257	5.2	305	5.9	—246	—4.7	—20	—0.4	
B. Other banks' credit to commercial sector	22,926	18.8	21,607	14.9	3,220	2.2	1,687	1.0	
3. Net Foreign Exchange Assets of Banking Sector (A+B)	69	1.1	1,429††	21.7	—352	—5.4	—660††	—8.2	
			(-4,944)@	(-75.0)@			(-1,417)	(-17.7)@	
A. RBI's net foreign exchange assets	85	1.4	1,429	23.9	—352	—5.9	—660	—8.9	
B. Other banks' net foreign exchange assets	—16	—2.7	—	—	—	—	—	—	
4. Government's Currency Liabilities to the Public	80	5.4	52	3.3	22	1.4	—	—	
5. Banking Sector's Net Non-monetary Liabilities other than Time Deposits (A+B)	5,096	13.2	8,972	20.5	2,219	5.1	3,518	6.7	
A. Net non-monetary liabilities of RBI	1,930	11.8	7,988††	43.8	203	1.1	1,115††	4.3	
B. Net non-monetary liabilities of other banks (residual)	3,166	14.2	984	3.9	2,016	7.9	2,403	9.1	

\*\* Based on the last reporting Friday of March.

\* Provisional.

† Includes an amount of Rs. 722 crore (a)/Rs. 325 crore (b)/240 crore (c) representing the replacement of non-negotiable non-interest bearing securities issued to IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund.

Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market price, effective October 17, 1990. Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank's net non-monetary liabilities.

Excluding revaluation of gold.

Excludes, since the establishment of NABARD, its refinance to banks.

6.4 All the Major components of M<sub>3</sub>, namely currency and demand and time deposits, experienced reduced pace of expansion during 1990-91.

6.5 Net bank credit to Government, though registering a lower increase in relative terms (18.4 per cent as against 20.3 per cent in 1989-90), was higher in absolute terms at Rs. 21,483 crore as against Rs. 19,630 crore in the previous year. The contribution came mainly from net Reserve Bank credit to Central Government, which rose by Rs. 13,955 crore (19.2 per cent) as against Rs. 12,672 crore (21.2 per cent) during the last year. The average of fortnightly figures of financial year variations in net Reserve Bank credit to Central Government (excluding March 31) at Rs. 10,167 crore was close to that of Rs. 10,513 crore during 1989-90. Bank credit to the commercial sector showed a lower increase of Rs. 21,912 crore (14.6 per cent) during 1990-91 as compared with Rs. 23,183 crore (18.2 per cent) in the preceding year. Net foreign exchange assets of the banking sector increased by 1,429 crore, mainly due to revaluation of gold closes to international market price, effective October 17, 1990. Since such revaluation has a corresponding effect on the Reserve Bank's net non-monetary liabilities (a contractionary factor for money supply), it has no impact on monetary aggregates. Excluding the appreciation in the value of gold, net foreign exchange assets would have shown a decline of Rs. 4,944 crore in 1990-91.

6.6 During the first quarter of the current financial year 1991-92 (i.e., up to June 28, 1991), the pace of expansion of both M<sub>3</sub> and M<sub>1</sub> was slower than that in the corresponding

period of 1990-91. While net bank credit to Government was higher, bank credit to the commercial sector was lower as compared with the corresponding period of 1990-91. Net foreign exchange assets of the banking sector continued to experience a significant loss.

6.7 Reserve money experienced a rise of Rs. 9,020 crore (12.3 per cent) during 1990-91 as against Rs. 10,830 crore (17.4 per cent) in the previous year. On a fortnightly average basis, the expansion in reserve money at 16.0 per cent was lower than that of 18.2 per cent during 1989-90. Component-wise, there was a deceleration in currency with the public and also in bankers' deposits with the Reserve Bank, whereas expansion in 'other' deposits with the Reserve Bank and cash with banks was larger during 1990-91 (Table 6.2).

6.8 Among the sources of reserve money growth, the rise in net Reserve Bank credit to Government was Rs. 13,594 crore (18.6 per cent) as compared with Rs. 13,031 crore (21.7 per cent) during 1989-90. The Reserve Bank's claims on commercial and co-operative banks showed an increase in contrast to a decline in the previous year.

6.9 During the current financial year so far (i.e., up to June 28, 1991), the pace of expansion in reserve money at 12.4 per cent was higher than that during the comparable period of the previous financial year (8.2 per cent). Again, the accelerated rise in net Reserve Bank credit to Government turned out to be the main factor responsible for the increase in reserve money.

Table 6.2 : Reserve Money Variations—Components and Sources

Items	Variations during\$			
	1989-90	1990-91†	1990-91 (April-June)	1991-92* (April-June)
	2	3	4	5
<b>RESERVE MONEY (1+2+3+4)</b>	<b>10,830</b>	<b>9,020</b>	<b>5,993</b>	<b>10,193</b>
1. Currency with the public	(17.4)	(12.3)	(8.2)	(12.4)
2. 'Other' deposits with RBI	8,231	6,727	2,494	3,482
	(21.4)	(14.4)	(5.3)	(6.5)
3. Cash with banks	366	1354	—13	—822
	(79.2)	(163.5)	(—1.6)	(37.7)—
4. Bankers' deposits with RBI	167	257	565	398
	(9.3)	(13.1)	(28.9)	(18.0)
	2,066	682	2947	7,135
	(9.5)	(2.9)	(12.4)	(29.2)
<b>SOURCES OF RESERVE MONEY (1+2+3+4+5—6)</b>				
1. Net RBI credit to Government*	13,031(a)	13,594(b)	6,661(c)	9286
	(21.7)	(18.6)	(9.1)	(10.7)
2. RBI claims on commercial and co-operative banks@	—693	1,627	110	2,703
	(—11.0)	(28.9)	(2.0)	(37.2)
3. RBI credit to commercial sector	257	305	246	—20
	(5.2)	(5.9)	(—4.7)	(—0.4)
4. Net foreign exchange assets of RBI	85	1,429**[-4,944]@	—352	—660**[-1,417]@
	(1.4)	(23.9) (-75.0)@	(-5.9)	(-8.9) (-17.7)@
5. Government's currency liabilities to the public	80	52	22	—
	(5.4)	(3.3)	(1.4)	(—)
6. Net non-monetary liabilities of RBI	1,930	7,987**	202	1,116**
	(11.8)	(43.8)	(1.1)	(4.3)

\* Provisional

\$ Based on last reporting Friday of March.

@ Including NABARD.

† Includes an amount of (a) Rs. 722 crore/(b) Rs. 325 crore/(c) Rs. 240 crore representing the replacement of non-negotiable non interest bearing securities issued to IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund.

\*\* Inclusive of appreciation in the value of gold following its revaluation close to international market price, effective October 17, 1990. Such appreciation has a corresponding effect on Reserve Bank's net non-monetary liabilities.

@ Excluding revaluation of gold.

Note: Figures in brackets indicate percentage variations.

6.10 During 1990-91 there was a relatively higher increase in the Reserve Bank's assistance to commercial and co-operative banks due to larger utilisation of export credit refinance facility and the wider access provided to them under the

RBI's discretionary refinance facility with a view to moderating the volatility in the call money market rate. At the same time, the Reserve Bank's assistance to commercial sector provided directly through the financial institutions continued to show an increase (Table 6.3).

Table 6.3 Reserve Bank's Claims on Banks and Commercial Sector

(Rupees crore)

Outstanding as at the end of	Reserve Bank's Claims on			
	Commercial and Co-operative banks	NABARD	DFHI	Commercial Sector (Financial Institutions)
1984-85	1,584	1,219	—	2,765
1988-89	3,937	2,387	51	4,899
1989-90	2,180	2,821	77	5,130
1990-91	3,999	3,259	77	5,435
June 29, 1990	2,882	2,858	77	4,884
June 28, 1991	6,639	3,322	77	5,415

## Income-Velocity of Money

6.11 Income velocity of money i.e., the ratio of gross domestic product (GDP) at current market prices to the average of broad money ( $M_3$ ), which has been showing a long-term downward trend almost continuously since the early 1970's, showed a marginal rise from 2.08 in 1989-90 to 2.09 in 1990-91 (Table 6.4). The persistent decline in the income velocity of money in India reflects the empirically established fact that the real income elasticity of demand for  $M_3$  during this period has been significantly greater than unity.

## Some Monetary Relationships

6.12 Key monetary ratios related to currency on an average basis such as, currency to aggregate deposits (C/AD) and currency to  $M_3$  (C/ $M_3$ ), moved upwards during 1990-91 mainly reflecting higher monetised deficit throughout the year. Reflecting the downward adjustment in monetary variables, on a point-to-point basis, the incremental money multiplier ( $\Delta M_3 / \Delta RM$ ) unadjusted for changes in the reserve requirements registered a rise. On an average basis, however, this ratio has shown a marginal decline (Table 6.5).

## Banking Variables

6.13 The operations of scheduled commercial banks showed a lower growth profile in all important dimensions throughout the financial year 1990-91 (March 23, 1990 to March 22, 1991). The growth in aggregate deposits decelerated both in absolute as well as percentage terms to Rs. 25,583 crore (15.3 per cent) from the previous year's increase of Rs. 26,809 crore (19.1 per cent). The aggregate deposit growth was lower than the working estimate of Rs. 27,500 crore indicated for the year in the credit policy announcement of April 1990. The lower growth was perceptible in both demand and time deposits.

6.14 The year 1990-91 witnessed a markedly slow pace of expansion in bank credit. While food credit rose sharply, non-food credit experienced a considerably reduced expansion both in absolute and percentage terms from Rs. 15,497 crore (18.5 per cent) in 1989-90 to Rs. 12,348 crore (12.4 per cent) in 1990-91. To an extent, this has to be assessed in conjunction with the amount of Rs. 3,770 crore written off during 1990-91 by the public sector banks and regional rural banks

Table 6.4 Trends in Income velocity of currency, Aggregate Deposits,  $M_1$  and  $M_3$ 

Year	Averages* (Rupees crore)				Income Velocity Ratios			
	Currency	Aggregate Deposits(AD)	$M_1$	$M_3$	GDP/Currency	GDP/AD	GDP/ $M_1$	GDP/ $M_3$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1985-86	24,058	86,714	40,824	1,10,016	10.911	3.027	6.430	2.386
1986-87	27,011	1,03,261	46,835	1,30,527	10.863	2.841	6.265	2.248
1987-88	31,410	1,21,415	53,866	1,53,133	10.587	2.739	6.174	2.172
1988-89	35,842	1,43,136	61,688	1,79,361	11.020	2.760	6.403	2.202
1989-90	42,539	1,70,035	74,113	2,13,148	10.409	2.604	5.974	2.077
1990-91@	49,926	1,97,336	87,149	2,48,446	10.385	2.627	5.950	2.087

\* Averages of reporting Fridays of the year.

@ Provisional.



Table 6.5 : Monetary Ratios—Incremental

Item	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Point-to-point basis						
(Incremental Ratios)						
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.174	0.180	0.293	0.193	0.281	0.242
(b) Currency/M <sub>3</sub> (C/M <sub>3</sub> )	0.152	0.152	0.227	0.161	0.217	0.187
(c) Aggregate Deposits/M <sub>3</sub> (AD/M <sub>3</sub> )	0.870	0.844	0.775	0.834	0.773	0.775
(d) Broad Money Multiplier (M <sub>3</sub> /RM)	2.588	3.233	2.625	3.368	3.496	3.980
(e) Narrow Money Multiplier (M <sub>1</sub> /RM)	0.619	1.090	0.781	0.970	1.368	1.459
(f) Bank Reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.294	0.181	0.201	0.168	0.076	0.034
Average basis						
(Incremental Ratios)						
(a) Currency/Aggregate Deposits (C/AD)	0.181	0.178	0.242	0.204	0.249	0.271
(b) Currency/M <sub>3</sub> (C/M <sub>3</sub> )	0.154	0.151	0.195	0.169	0.189	0.209
(c) Aggregate Deposits/M <sub>3</sub> (AD/M <sub>3</sub> )	0.852	0.848	0.803	0.828	0.796	0.773
(d) Broad Money Multiplier (M <sub>3</sub> /RM)	3.952	3.156	2.477	3.128	3.191	3.180
(e) Narrow Money Multiplier (M <sub>1</sub> /RM)	1.206	0.972	0.771	0.933	1.173	1.174
(f) Bank Reserves/Aggregate Deposits (R/AD)	0.123	0.194	0.257	0.178	0.135	0.117

Note : On a point-to-point basis, the ratios are based on last reporting Friday of March while on an average basis the ratios have been worked out on the basis of average of reporting Fridays of the year. All ratios in this table are incremental ratios.

under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990. As an extent, it has also to be seen against the background of a lower order of growth of the economy in general, as well as a better performance of the corporate sector in the previous year resulting in larger internal generation of resources.

6.15 The increase in banks' investments in Government and other approved securities at Rs. 10,696 crores in 1990-91 was higher than that of Rs. 9,797 crore in 1989-90. Banks' balances with the Reserve Bank recorded a lower rise of Rs. 398 crore as compared with that of Rs. 2,087 crore in the previous year (these large differences are reflective of the large variations between the reporting Friday figures from one fortnight to another and do not reflect the stance of policy on cash reserve requirements). Banks' borrowings from the Reserve Bank recorded a rise of Rs. 1,069 crore in the contrast to a decline of Rs. 1,128 crore in the preceding year (Table 6.6).

#### Year-End Bulge In Banking Variables

6.16 Scheduled commercial banks have been reporting unusually large increases in aggregate deposits and credit in the last week of March of each year; this trend was accentuated during the financial year 1990-91. Thus, between March 22, 1991 and March 31, 1991 a 9-day period aggregate deposits increased by Rs. 12,232 crore (6.4 per cent) and bank credit by Rs. 7,134 crore (6.1 per cent). During the corresponding period of 1989-90, the increase in aggregate deposits was Rs. 8,434 crore (5.1 per cent) and that in bank credit was Rs. 5,182 crore (5.1 per cent). In the last week of March 1991, the increase was more in respect of demand deposits at

Rs. 7,329 crore (22.1 per cent) which was markedly higher as compared to an increase of Rs. 5,538 crore (19.2 per cent) in the corresponding period of 1989-90. The increase in aggregate deposits formed 47.8 per cent of the increase in deposits on reporting Friday basis during the whole year of 1990-91, and that of demand deposits was as high as 169 per cent during this period (Table 6.7). The most striking aspect is the escalation in deposit growth during the two day period March 30, 1991 and March 31, 1991. The two-day rise was Rs. 3,575 crore (1.8 per cent) in aggregate deposits and Rs. 1,570 crore (1.3 per cent) in respect of bank credit. This compares with an increase of Rs. 1,878 crore (1.1 per cent) in aggregate deposits and Rs. 1,185 crore (1.1 per cent) in bank credit in a single day, i.e., between March 30, 1990 and March 31, 1990. As happened in previous two years, the unusual rise in deposits in the last week of March could not be sustained as is evident from the steep unwinding of deposits in the immediate following week ended April 5, 1991 and also in the subsequent fortnight ended April 19, 1991 when aggregate deposits declined by Rs. 6,705 crore and Rs. 2,090 crores, respectively, thus wiping out 72 per cent of the increase in deposits in the last week of March 1991. The increases in the banking aggregates towards the end of March could be partly attributable to the year-end settlement of accounts by public sector organisations and Government Departments, application of interest and the bank managers' anxiety to project their individual branch performance based on the growth of deposits. The year-end bulge in the banking aggregates in 1990-91 re-emphasises the fact, mentioned in the previous year's Report, that March 31 data are not meaningful for purposes of assessment of the basic underlying banking developments and therefore, banking analysis in this Report is based on data as on the last reporting Friday and not March 31.

Table : Important Banking Indicators—Scheduled Commercial Banks

Items	Outstanding as on					Variations during the financial year		Variations	
	March 24	March 23	March 22	June 29	June 28	1989-90	1990-91	1990-91	1991-92
	1989	1990	1991	1990	1991*			(April to June)	(April to June)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Total Demand and Time Liabilities (excluding borrowings from RBI/IDBI/NABARD)	156,637	185,845	212,086	192,349	218,446	26,241	29,708	6,564	6,360
2. Aggregate Deposits (a+b)	140,150	166,959	192,542	173,088	198,753	26,809 (19.1)	25,583 (15.3)	6,129 (3.7)	6,211 (3.2)
a) Demand Deposits	23,342	28,856	33,193	29,946	34,354	5,514 (23.6)	4,337 (15.0)	1,090 (3.8)	1,161 (3.5)
b) Time Deposits	116,808	138,103	159,349	143,142	164,399	21,295 (18.2)	21,246 (15.4)	5,039 (3.6)	5,050 (3.2)
3. Borrowings from RBI	3,527	2,399	3,468	2,458	6,104	—1128 (—32.0)	1069 (44.6)	59 (2.5)	2,636 (76.0)
4. Bank Credit (a+b)	84,719	101,453	116,301	104,011	117,552	16,734 (19.8)	14,848 (14.6)	2,558 (2.5)	1,251 (1.1)
a) Food Credit	769	2,006	4,506	3,917	5,317	1237	2,500	1911	811
b) Non-food Credit	83,950	99,447	111,795	100,094	112,235	15,497 (18.5)	12,348 (12.4)	647 (0.7)	440 (0.4)
5. Investments (a+b)	54,662	64,369	75,065	67,568	78,248	9,707 (17.8)	10,696 (16.6)	3,199 (5.0)	3,183 (4.2)
(a) Government Securities	35,814	42,292	49,998	47,321	53,401	6,477 (18.1)	7,706 (18.2)	3,029 (7.2)	3,403 (6.8)
(b) Other Approved Securities	18,847	22,077	25,067	22,247	24,847	3,230 (17.1)	2,990 (13.5)	170 (0.8)	—220 (—0.9)
6. Cash in hand	1,444	1,648	1,804	2,100	2,069	204	156	452	265
7. Balances with RBI	21,376	23,463	23,861	26,026	30,790	2,087 (9.8)	398 (1.7)	2,563 (10.9)	6,929 (29.0)
8. Credit-Deposit Ratio (%)	60.4	60.8	60.4	60.1	59.1				
9. Non-food Credit-Deposit Ratio (%)	59.9	59.6	58.1	57.8	56.5				

\* Provisional

Notes: 1. Figures in brackets are percentage variations.

2. Constituent items may not add up to the totals due to rounding off.

3. No sign is indicated for positive variations.

## Trends in the First Quarter of 1991-92

6.17 During the first quarter of 1991-92, deposit growth was marginally higher at Rs. 6,211 crore (3.2 per cent) as com-

pared with Rs. 6,129 crore (3.7 per cent) in the corresponding period of 1990-91. The expansion in bank credit at Rs. 1,251 crore (1.1 per cent) was substantially lower than that of Rs. 2,558 crore (2.5 per cent) in the previous year.

Table 6.7 : Variations in Selected Items of Scheduled Commercial Banks;

Last Week of March 1991

(Rupees crore)

Items	Outstanding as on						Variations					
	March 23, 1990	March 22, 1991	March 29, 1991	March 31, 1991*	April 5, 1991*	April 19, 1991*	March 22, 1991 over March 23, 1990	March 29, 1991 over March 22, 1991	March 31, 1991 over March 29, 1991	March 31, 1991 over March 22, 1991	April 5, 1991 over March 31, 1991	April 19, 1991 over April 5, 1991
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Aggregate</b>												
Deposits (a+b)	166959	192542	201199	204774	198069	195979	25583 (15.3)	8657 (4.5)	3575 (1.8)	12232 (6.4)	-6705 (-3.3)	-2090 (-1.1)
								[33.8]	[14.0]	[47.8]		
(a) Demand												
Deposits	28856	33193	38300	40522	35254	33845	4337 (15.0)	5107 (15.4)	2222 (5.8)	7329 (22.1)	-5268 (-13.0)	-1409 (-4.0)
								[117.8]	[51.2]	[169.0]		
(b) Time Deposits	138103	159349	162899	164252	162815	162134	21246 (15.4)	3550 (2.2)	1353 (0.8)	4903 (3.1)	1437 (-0.9)	-1681 (0.4)
								[16.7]	[6.4]	[23.1]		
<b>2. Bank Credit (a+b)</b>	101453	116301	121865	123435	118376	118395	14848 (14.6)	5564 (4.8)	1570 (1.3)	7134 (6.1)	-5059 (-4.1)	19 (0.0)
								[37.5]	[10.6]	[48.0]		
(a) Food Credit	2006	4506	4569	4569	4441	4391	2500 (124.6)	63 (1.4)	0 (0.0)	63 (1.4)	-128 (-2.8)	-50 (-1.1)
								[2.5]	[0.0]	[2.5]		
(b) Non-Food												
Credit	99447	111795	117296	118866	113935	114004	12348 (12.4)	5501 (4.9)	1570 (1.3)	7071 (6.3)	-4931 (-4.1)	69 (0.1)
								[44.5]	[12.7]	[57.3]		

\* Provisional.

Notes : 1. Figures in parentheses indicate percentage variations.

2. Figures in square brackets indicate absolute variation as percentage of financial year variation.

3. No sign is indicated for positive variations.

## Sectoral Deployment of Credit

6.18 During the fiscal year 1990-91, there occurred a significant change in the composition of incremental gross bank credit. Credit extended to food procurement agencies increased rather sharply. Reference has already been made about the slowdown in the non-food credit expansion. The slowdown was more pronounced in the case of priority sector advances which was however largely technical in nature and reflected the writing-off of rural debt. The increase in bank credit to priority sectors at Rs. 2,497 crore (19.9 per cent of the incremental gross bank credit) was far below that of Rs. 6,164

crore (39.2 per cent) attained in the previous year. The outstanding priority sector credit as a percentage of net bank credit at the end of March 1991 stood at 39.2 per cent and was close to the target, though below the previous year's level of 42.4 per cent. Because of the writing-off of rural loans, the outstanding level of credit to this sector was reduced and as such credit for agriculture as per the data shows an increase of only Rs. 230 crore (1.8 per cent) as against Rs. 2,576 crore (16.4 per cent) during 1989-90. Gross bank credit to medium and large scale industries, expanded by Rs. 6,163 crore as compared with Rs. 6,077 crore in the previous year. However, its percentage share in

incremental non-food credit was sizeable at 49.1 per cent as compared with only 38.7 per cent in 1989-90. Bank credit extended to 'other sectors' (which is a residual category and includes credit to financial institutions, hire purchase agencies, leasing companies, housing finance, etc.) registered a noticeably larger increase of Rs. 3,480 crore (27.7 per cent) as compared with Rs. 2,760 crore (17.6 per cent) in the previous year (Table 6.8).

6.19 An analysis of industry-wise (small, medium and large) distribution of bank credit reveals that while advances to engineering, iron and steel, other textiles, paper and paper products, rubber and rubber products, cement, construction and gems and jewellery showed substantial deceleration during 1990-91 (April-March), credit to chemicals, dyes, paints, etc. coal, other metal and metal products and vegetable oils (including vanaspati) registered higher increases than in the previous year. Declines in credit were sizeable in the case of electricity (Rs. 100 crore) and SAFAUNS (Rs. 62 crore) (Table 6.9). Industries which accounted for a major part of the expansion in credit during the period 1990-91 (April-March) were: all engineering (Rs. 1,430 crore), chemicals, dyes and paints etc. (Rs. 931 crore), other textiles (Rs. 459 crore), iron and steel (Rs. 442 crore), cotton textiles (Rs. 404 crore), other metal and metal products (Rs. 378 crore) and construction (Rs. 223 crore).

## RBI Refinance.

### (i) Export Credit Refinance

6.20 As on June 29, 1990, the export credit refinance limits of scheduled commercial banks amounted to Rs. 4,118.2 crore (46.3 per cent of the outstanding export credit). When the base for purpose of determining export credit refinance limits was shifted effective August 25, 1990, to the monthly average level of outstanding export credit for the financial year 1988-89 instead of that for calendar year 1987. The ratio of export refinance limits to outstanding export credit declined from 44.1 per cent as on August 24, 1990 to 32.6 per cent as on September 7, 1990. Effective January 1, 1991, the proportion of export credit refinance was raised from 75 per cent to 100 per cent of the increase in export credit over their monthly average level of export credit outstanding for 1988-89. As a result of this change, the banks' export credit refinance limits increased from Rs. 2,718 crore as on December per cent as on September 7, 1990. Effective January 1, 1991, accordingly, the ratio of export credit refinance limits to export credit rose from 32.6 per cent on December 28, 1990 to 43.4 per cent on January 11, 1991. As on June 28, 1991, the export credit refinance limits of banks were Rs. 5,222 crore (52.6 per cent of outstanding export credit). During the period June 29, 1990 to June 28, 1991, the maximum fortnightly average utilisation under export credit refinance facility was Rs. 5,168 crore during the fortnight ended June 14, 1991, whereas the daily peak level of utilisation was at Rs. 5,203 crore or 98.2 per cent of the total limit which was attained in the same fortnight.

Table 6.8 : Sectoral Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors@

Sector	Outstanding as on			Variations during	
				(Rupees crore)	
	March 24, 1989	March 23, 1990	March 22, 1991	(Financial Year) 1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
(I) Gross Bank Credit (1+2)	85,728	1,02,671	1,17,723	+16,943	+15,052
1. Public Food Procurement Credit	769	2,006	4,506	+1,237	+2,500
2. Non-food Gross Bank Credit	84,959	1,00,665	1,13,217	+15,706 (+100.0)	+12,552 (+100.00)
(A) Priority Sectors	34,219	40,383	42,880	+6,164	+2,497
	[43.2]	[42.4]	[39.2]	(+39.2)	(+19.9)
(i) Agriculture	13,950	16,526	16,756	+2,576	+230
	[17.6]	[17.4]	[15.3]	(+16.4)	(+1.8)
(ii) Small Scale Industries	13,135	15,543	17,151	+2,408	+1,608
				(+15.3)	(+12.8)
(iii) Other Priority Sectors	7,134	8,314	8,973	+1,180	+659
				(+7.5)	(+5.3)
(B) Industry (Medium and Large)	32,185	38,262	44,425	+6,077	+6,163
				(+38.7)	(+49.1)
(C) Wholesale Trade (Other than food procurement)	4,767	5,472	5,884	+705	+412
				(+4.5)	(+3.3)
(i) Cotton Corpn. of India	37	140	91	+103	—49
				(+0.7)	(—0.3)
(ii) Food Corpn. of India for fertiliser distribution	202	230	212	+28	—18
				(+0.2)	(—0.1)
(iii) Jute Corpn. of India	98	54	62	—44	+8
				(—0.3)	(—)
(iv) Other Trade	4,430	5,048	5,519	+618	+471
				(+3.9)	(+3.7)
(D) Other Sectors	13,788	16,548	20,028	+2,760	+3,480
				(+7.6)	(+27.7)
(II) Export Credit (included under item (I) 2)	6,141	8,245	9,153	+2,104	+1,908
(III) Net Bank Credit (including inter-bank participations)	79,234	95,132	1,09,283	+15,898	+14,151

### (iii) Provisional

Notes: 1. Data relate to 50 scheduled commercial banks (49 from March 1990 and 48 from August 1990 due to merger) which account for about 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial banks. Further, these gross bank credit includes bills rediscounted with RBI, IDBI, EXIM bank, other approved financial institutions and inter-bank participations.

2. Figures in brackets are proportions to incremental non-food gross bank credit.

3. Figures in square brackets are proportions to net bank credit (including inter-bank participations) given in item III.

## (ii) Standby Refinance

6.21 During the period June 29, 1990 to June 28, 1991, three banks were provided standby refinance limits ranging between Rs. 2 crore and Rs. 20 crore.

## (iii) Discretionary Refinance

6.22 With a view to moderating the volatility in the call money market rate, the Reserve Bank provided wider access to its discretionary refinance facility. The discretionary re-

finance limits sanctioned to banks decreased from Rs. 1,631 crore as on November 30, 1990, to Rs. 898 crore by the end of December 1990. The tight liquidity was reflected in high call money rates and to moderate these rates the limits sanctioned were increased to Rs. 2,181 crore on March 8, 1991 and to Rs. 4,987 crore on April 19, 1991. Subsequently, with the easing of call money rates there was a significant reduction in these limits which reached Rs. 2,432 crore on June 28, 1991 (Table 6.10). The outstandings under this facility reached a peak level of Rs. 4,677 crore (93.8 per cent of the sanctioned limits), as on April 18, 1991 (Table 6.11).

Table 6.9 : Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit @

(Rupees Crore)

Industry	Outstanding as on			Variations during	
	March 24, 1989	March 23, 1990	March 22, 1991	(Financial Year) 1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6
Industry (Total of Small, Medium and Large Scale)	45,320	53,805	61,576	+8,485	+7,771
1. Coal	210	178	241	-32	+63
2. Iron and Steel	2,245	2,835	3,277	+590	+442
3. Other Metals and Metal Products	1624	1,838	2,216	+214	+378
4. All Engineering Of which: Electronics	10623 (677)	12,509 (1,290)	13,939 (1,852)	+1,886 (+613)	+1,430 (+562)
5. Electricity	1,042	1,258	1,158	+216	+100
6. Cotton Textiles	3,216	3,659	4,063	+443	+404
7. Jute Textiles	276	340	348	+64	+8
8. Other Textiles	2,742	3,297	3,756	+555	+459
9. Sugar	669	647	624	-22	-23
10. Tea	524	571	575	+47	+4
11. Food Processing	469	1,056	1,214	+587	+158
12. Vegetable Oils (including Vanaspathi)	599	700	864	+101	+164
13. Tobacco and Tobacco Products	297	379	392	+82	+13
14. Paper and Paper Products	1,142	1,346	1,478	+204	+132
15. Rubber and Rubber Products	750	912	982	+162	+70
16. Chemicals, Dyes, Paints, etc. Of which	5,922	6,785	7,716	+863	+931
(i) Fertilizer	(1,019)	(1,075)	(1,298)	(+56)	+223
(ii) Petro-chemicals	(339)	(681)	(681)	(+342)	(—)
(iii) Drugs and Pharmaceuticals	(452)	(1,013)	(989)	(+561)	(—24)
17. Cement	689	843	899	+154	+56
18. Leather and Leather Products	691	931	996	+240	+65
19. Gems and Jewellery	483	1,214	1,242	+731	+28
20. Construction	759	1,091	1,314	+332	+223
21. Petroleum	30	137	54	+107	-83
22. SAFAUNS*	191	149	87	+42	-62
23. Other Industries	10,127	11,130	14,141	+1,003	+3,011

@ Provisional.

\* Ships acquired from abroad under new scheme.

The scheduled commercial banks were advised that this order of discretionary refinance limits could be provided for only a short period as otherwise the macro objectives of monetary policy would be undermined and that, therefore, these very large discretionary refinance limits would be phased out. Accordingly, the discretionary refinance limits were gradually reduced to Rs. 2,432.02 crore for the fortnight ended June 28, 1991.

#### Overall Position of Refinance

6.23 Total refinance limits provided to scheduled commercial banks under various facilities (excluding special refinance against shipping loans, duty drawback, etc) stood at Rs. 4,992 crore as on June 29, 1990. As on April 19, 1991, total limits sanctioned to banks rose sharply to Rs. 9,911 crores which was the peak level of limits sanctioned during July 1, 1990 to June 28, 1991. The utilisation as on that date aggregated Rs. 9,113 crore (92.0 per cent). Export credit refinance limits accounted for a major proportion (63.6 per cent) of total refinance limits (Table 6.10).

#### Credit Budgets

6.24 During the period under review, the credit budgets of 56 scheduled commercial banks for 1990-91 were examined. Discussions were held with the Chief Executive of 21 public sector banks and 3 foreign banks during June-August 1990. During the discussions, the banks were advised to plan their credit operations on the basis of their market share in the projected growth in aggregate deposits of the banking system for 1990-91. Secondly, banks were advised to strictly adhere to the stipulation limiting the incremental net non-food credit-deposit ratio within 60 per cent throughout the year 1990-91 with March 23, 1990 as the base. Thirdly, they

were advised to ensure that their credit operations were commensurate with their own stable resources and to avoid over-extension of credit and heavy reliance on volatile money market funds. Fourthly, it was indicated to the banks that to the extent that their liabilities were of a volatile or transient nature, they would do well to have a matching portfolio of short-maturing and near-liquid assets such as 182 Days Treasury Bills. Fifthly, banks were advised to ensure that, while issuing Certificates of Deposit (CDs), the rates of interest offered should be in alignment with the maturity period of the instrument issued. Lastly, banks were urged to desist from window dressing their deposits/non-food credit towards the close of March since such increases in deposits and non-food credit were non reflective of real developments in the system.

#### Trends in the Incremental Net Non-Food Credit Deposit Ratio

6.25 The measure of stipulating a 60 per cent incremental net non-food credit-deposit ratio, which was originally introduced in November 1989 for the fiscal year 1989-90, was continued for the fiscal year 1990-91 but the base for calculating the ratio was brought forward to March 23, 1990. The incremental net non-food credit-deposit ratio of scheduled commercial banks worked out to 48.3 per cent in 1990-91 (April-March). If, however, adjustment is made in the nonfood credit data in respect of write-off of agricultural/other loans under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme 1990, the incremental net non-food credit-deposit ratio in 1990-91 would be about 58.4 per cent as compared with 57.8 per cent in 1989-90. For the full year March 23, 1990 to March 22, 1991 out of the 74 reporting scheduled commercial banks, 13 banks exceeded the 60 per cent stipulation and the total amount of excess credit was Rs. 732 crore.

Table 6.10 : RBI Accommodation to Scheduled Commercial Banks

(excluding special refinance against shipping loans, duty drawback, etc.)

As on the last reporting Friday of	Export Credit Refinance		Stand-by Refinance		Discretionary Refinance		182 Days Treasury Bill Refinance		Total Refinance	
	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing	Limit	Out-standing
1990										
March	3,564.00	2,133.41	—	—	476.17	85.16	209.72	2.50	4,249.90	2,221.07
April	3,782.58	2,652.58	5.00	—	508.75	89.68	223.26	—	4,519.59	2,742.26
May	4,057.73	3,716.41	22.00	20.00	510.94	186.72	268.01	2.50	4,858.68	3,925.63
June	4,118.15	2,338.45	11.00	9.00	433.13	—	429.75	—	4,992.03	2,347.45
September	2,697.71	1,211.67	11.00	9.00	479.54	—	668.14	22.50	3,856.39	1,243.17
December	2,717.52	1,641.67	18.00	—	898.26	29.74	560.49	2.50	4,194.27	1,674.01
1991										
March	4129.08	2812.25	—	—	3225.97	533.97	210.93	—	7565.98	3346.22
April	4575.76	4448.34	—	—	4987.00	4655.00	348.03	10.00	9910.79	9113.34
May	5111.06	3167.57	—	—	3065.76	120.00	291.38	37.50	8468.20	3325.07
June	5222.10	4467.98	—	—	2432.02	1546.33	555.10	—	8209.22	6014.31

**Table 6.11 : Consolidated discretionary Refinance  
Scheduled Commercial Banks**

(Rupees crore)		
For the fortnight ended	Limits	Peak Outstanding during the fortnight
October 5, 1990	609.23	330.02
19, 1990	1,599.73	1,410.98
November 2, 1990	1,587.80	1,331.81
16, 1990	1,561.73	1,282.62
30, 1990	1,630.76	1,330.46
December 14, 1990	946.55	94.82
28, 1990	898.26	415.34
January 11, 1991	1,824.32	1,352.82
25, 1991	2,402.99	1,961.60
February 8, 1991	2,349.07	1,469.85
22, 1991	2,164.03	1,908.51
March 8, 1991	2,180.56	1,882.25
22, 1991	3,175.97	3,106.97
April 5, 1991	4,747.00	4,325.00
19, 1991	4,987.00	4,677.00
May 3, 1991	3,917.20	3,841.38
17, 1991	3,368.75	3,299.56
31, 1991	3,065.76	2,966.11
June 14, 1991	2,750.45	2,620.51
28, 1991	2,432.02	2,312.03
July 12, 1991	2,338.99	2,109.03
26, 1991	2,128.37	1,839.07
August 9, 1991	2,095.60	1,530.99

**Table 6.12 : Cumulative Turnover of the DFHI in Money-  
Market Instruments During the Fiscal Year Period**  
(Rupees crore)

Instrument	1989-90	1990-91
1	2	3
1. Call and Notice Funds	88,577	2,02,792
2. 182 Days Treasury Bills	21,953	32,329
3. Commercial Bills	10,682	12,675
4. Certificates of Deposit	3	8
5. Commercial Paper	26	107
6. Term Deposits	244	3,532

6.28 The average daily call money lendings of the DFHI increased to Rs. 546 crore in 1990-91 as compared with Rs. 240 crore during 1989-90. The DFHI was also able to substantially increase its term money placements in 1990-91. The DFHI also increased its turnover considerably in 182 Days Treasury Bills and commercial bills which provided liquidity to the banking system. During the year, DFHI opened branches at New Delhi, Calcutta, Madras, Ahmedabad and Bangalore with a view to decentralising its activities and provide money market facilities at the major centres in the country. This is expected to facilitate integration of the money market.

#### RBI's Refinance to (DFHI) :

6.29 During the year under review, the Reserve Bank sanctioned to DFHI peak refinance limit of Rs. 1,000 crore against the collateral of 182 Days Treasury Bills and Rs. 700 crore against commercial bills (Table 6.13). The rate of interest for refinance against 182 Days Treasury Bills ranged between 10.0 per cent and 14.5 per cent per annum and for commercial bills between 13.0 per cent and 18.0 per cent per annum during 1990-91 (up to June 30, 1991). The Reserve Bank's rate of interest charged on refinance made available to DFHI are adjusted by the Reserve Bank, depending on the conditions in the money market. Accordingly, the Reserve Bank's rates of interest on refinance were altered, during the year under review, on 53 occasions for 182 Days Treasury Bills and on 30 occasions for commercial bills (Table 6.14).

#### Bills Rediscounting Market :

6.30 The outstanding amount of commercial bills rediscounted by scheduled commercial banks with financial institutions came down from Rs. 5,230 crore at the end of November 1990 to Rs. 3,479 crore at the end of March 1991 as against Rs. 3,934 crore at the end of March 1990. In order to augment the flow of funds in the bills rediscounting market, the Reserve Bank provided enhanced refinance limits to DFHI against the collateral of commercial bills/ derivative usance promissory notes having an unexpired usance not exceeding 90 days and the peak limits under the facility amounted to Rs. 700 crore in 1990-91.

#### Trends in the Short-Term Money Market :

6.26 The trends in the money market during the year under review are set out below :

#### Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI) :

6.27 The DFHI's cumulative turnover in call money market and other short-term money market instrument the financial year 1990-91 was significantly higher than that in the previous year as set out in Table 6.12.

**Table 6.13 : Reserve Bank Refinance to DFHI**

As on the last day of the month	Refinance against the collaterals of 182 Days Treasury Bills			Refinance against short-term Commercial Bills				
	Limit	Outst- anding	Peak level utilisation during the month	Limit correspon- ding to the peak utilisation as in Col. 4	Limit	Outst- anding	Peak level utilisation during the month	Limit correspon- ding to the peak utilisation as in Col. 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1990								
March	500.00	460.35	596.70 (29-3-90)	600	500.00	492.64	492.64 (31-3-90)	500
June	100.00	—	140.58 (18-6-90)	200	100.00	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
September	700.00	684.55	700.00 (17-9-90)	700	100.00	100.00	100.00 (22-9-90)	100
December	500.00	437.35	500.00 (3-12-90)	500	100.00	85.89	89.08 (20-12-90)	100
1991								
March	200.00	126.81	230.26 (19-3-91)	300	700.00	700.00	700.00 (23-3-91)	700
June	100.00	—	212.17 (20-6-91)	300	700.00	—	700.00 (1-6-91)	700

(a) 182 Days Treasury Bills :—

6.31 The 182 Days Treasury Bills introduced in November 1986 on an auction basis has by now come to be established fairly well as a monetary instrument. The outstanding amount of 182 Days Treasury Bills increased from Rs. 774.30 crore as on March 23, 1990 to Rs. 1,077.59 crore as on March 22, 1991, and further to Rs. 2,146.77 crore as on June 28, 1991. The peak level of outstanding 182 Days Treasury Bills was Rs. 2,363 crore on October 3, 1990. The cut-off yield on these bills increased from 9.97 per cent in July 1990 to 10.08 per cent per annum in January 1991 and subsequently declined to 10.00 per cent in early August 1991 (Table 6.15).

(b) Certificates of Deposit (CDs) :

6.32 The amount of CDs outstanding in respect of the instrument issued by 50 schedule commercial banks as on June 28, 1991 was Rs. 4,556 crore which worked out to 62.2 per cent of the limits of these banks (Table 6.16). Banks have been issuing CDs with the maturities ranging from 3 months to 1 year. Although CDs for a maturity of 3 months were issued in the interest rate range of 9.0 per cent to 16.6 per cent, the typical interest rates for this maturity period were in the range of 11.0 per cent to 12.5 per cent per annum. For one year maturities, while the interest

1	2	3
November	3, 90	13.00
	5, 90	12.50
	8, 90	13.00
	9, 90	12.50
	14, 90	13.00
	17, 90	14.00
	19, 90	14.50
	23, 90	12.50
December	1, 90	11.00
	8, 90	10.50
	29, 90	11.00
January	12, 91	10.50
February	15, 91	10.00
March	5, 91	10.25
	16, 91	10.50
	23, 91	10.00
	27, 91	10.25
April	6, 91	10.00
	15, 91	10.25
	16, 91	10.50
	18, 91	11.00
	19, 91	10.75
	20, 91	10.00
May	6, 91	10.25
	8, 91	10.50
	13, 91	10.75
	20, 91	11.00
	21, 91	11.50
	25, 91	11.00
June	1, 91	10.25
	6, 91	10.00
	13, 91	10.25
	14, 91	10.00
	18, 91	10.25
	19, 91	10.50
	22, 91	10.00
July	8, 91	10.25
	9, 91	10.00
	13, 91	10.50
	15, 91	10.75
	17, 91	10.50
	18, 91	10.25
	22, 91	10.00

Table 6.14 : Interest Rates for Reserve Bank Refinance to DFHI

Refinance against holdings of  
182 Days Treasury Bills

Effective Date		Rate of Interest (per cent per annum-)
July	2, 90	10.50
	9, 90	10.00
	16, 90	10.50
	21, 90	10.00
August	25, 90	10.50
	30, 90	11.00
September	12, 90	11.50
	14, 90	12.00
	15, 90	13.00
	18, 90	12.50
	26, 90	13.00
October	6, 90	13.50
	10, 90	14.00
	13, 90	14.50
	20, 90	14.00
	22, 90	13.50
	26, 90	14.00



Refinance against Commercial Bills			(1)	(2)	(3)
Effective Date		Rate of Interest (per cent per annum)			
October	1, 90	15.00	March	26, 91	14.00
	11, 90	16.00		28, 91	14.50
	13, 90	17.00		4, 91	15.00
	15, 90	17.50		6, 91	15.50
	16, 90	18.00		11, 91	15.75
	23, 90	17.50	April	23, 91	16.75
	25, 90	17.00		3, 91	15.75
	27, 90	17.50		6, 91	14.00
	30, 90	17.00		9, 91	14.50
	31, 90	13.00		10, 91	15.00
				11, 91	15.50
November	5, 90	15.00	July	13, 91	16.50
	10, 90	14.00		16, 91	16.50
	13, 90	15.00		17, 91	16.25
	15, 90	16.00		18, 91	16.00
	20, 90	14.00		29, 91	15.75
December	8, 90	13.00	August	5, 91	15.00
February	15, 91	13.50		7, 91	14.00

Table 6.15 : 182 Days Government of India Treasury Bills

Date of Auction		Bids Tendered		Bids Accepted		Cut-off price for Rs. 100 of face value	Cut-off yield (per cent per annum)	Total amount of Treasury Bills outstand- ing (Rupees crore)
		Number	Aggregate nominal amount (Rupees crore)	Number	Aggregate nominal amount (Rupees crore)			
1		2	3	4	5	6	7	8
1990								
July	11	21	149.00	10	90.50	95.25	9.97	1489.94
	25	20	194.00	11	101.00	95.25	9.97	1475.44
August	8	27	536.00	19	416.00	95.25	9.97	1811.34
	21	18	147.50	9	111.50	95.25	9.97	1856.89
September	5	22	216.60	12	167.00	95.25	9.97	1994.84
	19	19	450.50	12	416.50	95.25	9.97	2347.84
October	1	23	72.00	8	53.00	95.25	9.97	2363.34
	15	13	73.50	6	49.50	95.25	9.97	2329.94
	30	12	41.49	6	26.49	95.25	9.97	2295.59
November	14	8	127.25	4	113.75	95.25	9.97	2204.24
	27	7	135.00	4	126.50	95.25	9.97	2030.24
December	12	8	52.10	5	41.60	95.25	9.97	1909.34
	26	11	80.45	10	75.45	95.24	10.00	1788.79
1991								
January	9	9	57.00	9	57.00	95.22	10.04	1755.29
	23	11	62.70	11	62.70	95.20	10.08	1716.99
February	6	16	220.05	12	275.05	95.20	10.08	1576.04
	20	13	108.00	10	88.00	95.20	10.08	1552.54
March	6	6	38.30	6	38.30	95.20	10.08	1423.84
	20	13	79.75	9	70.25	95.20	10.08	1077.59
April	3	19	243.00	15	197.00	95.20	10.08	1221.59
	16	25	596.00	21	579.00	95.20	10.08	1751.09
	30	6	100.40	5	97.90	95.20	10.08	1822.50
May	14	13	244.27	10	229.27	95.20	10.08	1938.02
	30	8	167.30	5	156.80	95.20	10.08	1968.32
June	12	9	98.00	7	87.50	95.20	10.08	2014.22
	26	24	715.00	4	208.00	95.22	10.04	2146.77
July	10	23	326.00	9	198.00	95.23	10.02	2287.77
	24	22	444.50	14	275.50	95.23	10.02	2500.57
August	7	25	1001.25	10	576.25	95.24	10.00	2801.77

rates ranged between 10.75 per cent and 16.6 per cent, the typical rates were in the range of 12.0 per cent to 13.0 per cent per annum.

(c) Commercial Paper (CP) :

6.33 Since the introduction of the scheme in January 1990, 23 companies have issued CP worth Rs. 419.4 crore (50 issues) till June 30, 1991. The outstanding amount of CP issued by 9 companies (as on June 30, 1991), amounted to Rs. 64.70 crore. Although the maturity period of CP issued by companies varied from 3 months to 6 months, the majority of CP were issued with a maturity of six months. The effective interest rates were in the range of 11.7 per cent to 18.50 per cent per annum.

Table 6.16 : Issue of Certificates of Deposit (CDs) by Scheduled Commercial Banks

Fortnight ended	Number of banks which issued CDs (as at the end of the fortnight)	Total outstanding (Rupees crore)	Effective interest rate (range) of CDs issued during the fortnight for all maturities (per cent per annum)
1	2	3	4
July	13	37	2,000
	27	39	2,162
August	10	41	2,341
	24	42	2,377
September	7	42	2,406
	21	43	2,480
October	5	43	2,476
	19	43	2,489
November	2	43	2,494
	16	44	2,529
	30	44	.00-13.70
December	14	43	2,439
	28	43	2,462
1991			
January	11	42	2,690
	25	45	2,703
February	8	46	2,952
	22	46	3,035
March	8	47	3,181
	22	48	3,265
April	5	48	3,551
	19	48	3,874
May	3	49	3,979
	17	49	4,398
	31	49	4,695
June	14	50	4,506
	28	50	4,556

Call Money Market :

6.34 The call money rates remained stable till the middle of October 1990 but immediately thereafter they galloped to high levels which is reflected in the call money rate of the DFHI to as high a level as 61 per cent on October 19, 1990. In order to moderate the volatility in the call money rates, the Reserve Bank took certain measures including increased access to the discretionary refinance facility, softening of the loss of interest in cases of CRR defaults, and enhancement of limits for issue of Certificates of Deposit by banks. The call money rates subsided from the fortnight ended November 2, 1990 and the maximum call rate came down to 16.25 per cent during the fortnight ended Decem-

ber 28, 1990. The call money rates remained at a level of 15-16 per cent till the fortnight ended February 22, 1991. During the fortnight ended March 22, 1991, the DFHI's peak call rate again rose to 28 per cent. During the fortnight ended April 19, 1991, the call rate flared up and the DFHI's call rate rose to a peak of 46 per cent in the fortnight ended April 19, 1991. The sharp rise in call money rates in the recent period is attributable to the sharp rise in banks' net demand and time liabilities in the fortnight ended April 5, 1991, following the large bulge in banks' deposits in the last week of March 1991, which increased banks' requirement of funds for maintaining higher level of cash reserve ratio in the fortnight ended April 19, 1991, and for statutory liquidity ratio for the fortnight ended May 3, 1991. Some financial institutions either reduced or stopped lending in the call money market in the fortnight ended April 5, 1991, as a result of which the total average daily lendings by the financial institutions came down to Rs. 4,146 crore in the fortnight ended April 5, 1991 from Rs. 5,024 crore in the fortnight ended March 22, 1991.

6.35 The measures taken to widen the call and notice money market by increasing the number of participants increased the flow of funds in the call and short notice money market. The total average daily lendings by financial institutions increased considerably from Rs. 3,296 crore in the fortnight ended July 13, 1990 to Rs. 4,902 crore in the fortnight ended July 26, 1991; of this, UTI, LIC, IDBI and NABARD together accounted for about three-fourths of the total. Data relating to trough, peak and average of middle rates of lending rates of DFHI in the call money market are set out in Table 6.17.

Role of the Money Market :

6.36 A freely operating money market is a sensitive barometer of current conditions in the financial markets and ideally this market should provide for market clearing of short-term surpluses and deficits. During the past four years, there have been a number of significant developments in the Indian money market. Until 1987, the money market had a paucity of instruments and both interest rates and participants were tightly regulated and as a result the market was virtually moribund. After the series of reforms introduced in recent years there has been a significant activation of the money market. A number of new instruments have been introduced, the money market interest rates have been totally freed, participation has been made broad-based and a secondary market developed with the setting up of the Discount and Finance House of India Ltd. (DFHI). Freeing one segment of the financial market while other segments remain tightly controlled does create an element of distortion in that the entire burden of equilibrating the system falls on the segment which is deregulated.

6.37 It is sometimes erroneously argued that the deregulation of the money market has had an adverse impact on banks which are borrowers as their cost of funds has increased. Even when money market rates were subject to ceilings, the actual rates escalated during periods of tight money and various devices were used to beach the ceilings. As such it is simplistic to argue that interest rates in the money market under a deregulated regime are higher than under a regulated regime.

Table 6.17 : Call Money Lending Rates of DFHI

1989-90				
For the fortnight ended	Lending Rate (per cent per annum)			
	Trough	Peak	Average* of middle rate	
1	2	3	4	5
1989				
July	14	5.50	11.00	9.85
	28	6.50	10.50	8.85
August	11	8.25	12.00	9.85
	25	7.25	10.75	9.30

1	2	3	4	5
September	8	7.25	10.50	9.15
	22	8.75	10.75	9.60
October	6	6.50	13.50	11.30
	20	10.50	20.00	14.80
November	3	8.75	21.00	15.15
	17	14.50	27.00	18.70
December	1	7.00	25.00	13.20
	15	7.50	13.50	10.45
	29	9.25	15.50	12.35
1990				
January	12	10.50	15.00	12.35
	26	8.75	14.00	10.85
February	9	6.50	12.75	11.10
	23	10.25	25.00	15.80
March	9	7.00	28.00	16.65
	23	10.00	34.00	21.50
April	6	10.00	58.25	40.05
	20	13.00	22.00	15.90
May	4	8.75	23.75	17.50
	18	13.00	36.00	23.00
June	1	9.50	38.00	21.65
	15	13.00	14.00	13.50
	29	11.00	11.50	11.50
July	13	8.50	13.75	11.45
	27	7.50	12.25	10.10
August	10	8.00	11.00	9.50

\* This is a simple average of daily middle rates

1990-91				
For the fortnight ended		Lending Rate (per cent per annum)		
		Trough	Peak	Average* of middle rate
1990				
July	13	8.50	13.75	11.45
	27	7.50	12.25	10.10
August	10	8.00	11.00	9.50
	24	6.00	11.00	9.40
September	7	6.50	15.75	12.25
	21	10.00	26.00	16.50
October	5	10.00	34.00	22.50
	19	16.00	60.50	37.20
November	2	9.00	31.00	21.00
	16	8.00	28.00	19.35
	30	7.50	28.00	16.60
December	14	4.00	14.00	10.50
	28	7.50	15.00	13.20
1991				
January	11	7.00	15.25	13.40
	25	5.00	15.00	11.80
February	8	6.00	14.25	12.65
	22	8.75	15.75	12.80
March	8	13.75	17.75	16.10
	22	7.00	27.75	21.30
April	5	5.00	25.00	16.05
	19	14.25	46.00	23.75
May	3	24.25	45.00	32.25
	17	20.00	60.50	42.90
	31	4.50	45.00	29.10
June	14	13.50	28.00	23.40
	28	6.00	38.00	25.13
July	12	10.25	38.50	23.40
	26	5.00	27.00	14.05
August	9	5.00	17.50	12.60

6.38 Another issue which needs to be addressed is the question of chronic borrowers and chronic lenders. Such chronic one-way position of participants in the money market both by borrowers and lenders points to less than optimal funds management. A bank just cannot plead that it has a large and structural dependence on the money market and that measures should be taken to ensure that funds are provided to it at low rates of interest. The discipline of a deregulated money market is that bank with a large dependence on the money market is forced to undertake a correction of its imbalance. As such, a deregulated money market ensures prudent funds management by banks.

6.39 Another question that arises in this context is the role of the Reserve Bank vis-a-vis the movements in money market interest rates. While the Reserve Bank can certainly cool down a tight money market by stepping up its refinance either directly or through the DFHI, it needs to be appreciated that Reserve Bank refinance is also a tool of monetary policy and it is necessary to ensure that such refinance is not so excessive as to militate against the basic tenets of the monetary policy. In the recent period, the Reserve Bank provided discretionary refinance to the tune of Rs. 5,000 crore in early April 1991 and the DFHI's average call rate during the fortnight ended April 5, 1991 was around 16 per cent as compared with 40 per cent in the comparable period of the previous year. It would not, however, be prudent to maintain discretionary refinance at that level for long periods as it would go against other objectives of monetary policy.

6.40 In the months of April and May 1991, there were escalations of call money rates to very high levels and the average for the fortnight ended May 17, 1991 was as high as 43 per cent for the comparable fortnight in the previous year. Such high call rates are clearly not viable from the view point of borrowers and as such their demand for funds has come down. Thus, in the recent period, there have been clear signals of call money rates scaling down. For the fortnight ended May 31, 1991 the average rate was 29 per cent as against 22 per cent in the corresponding period of the previous year. The call money market turned further easy in the months of June and July 1991 and the average call rate was 23 percent during the fortnight ended July 12, 1991 and still lower at 14 per cent during the next fortnight ended July 26, 1991. High call rates do distort the pattern of investment in favour of short-term lending rather than for more productive purposes. If reasonable rates are to prevail, banks have to see that they do not over-extend themselves in terms of provision of credit in the hope that the call market would meet the gap.

## 7. REVIEW OF THE PRICE SITUATION

7.1 The general price level came under severe pressure during the financial year 1990-91. The tempo of increase in prices, built up in 1989-90, escalated progressively especially following the Gulf crisis, and crossed the double-digit mark reaching 12.1 per cent by the end of the financial year. This order of price increase, coming as it did in the wake of an increase of 9.1 per cent in 1989-90 and despite satisfactory agricultural production for three years in succession, caused serious concern. The sharpest increases were generally in the prices of essential commodities.

7.2 The high annual price rise during 1990-91 has been characterised by a sharp contra-seasonal price increase. Though the pressure on the price level came largely from 'primary articles', both food and non-food, the 'fuel power, light and lubricants' group also imparted considerable upward pressure to the general price level. In addition, the large price increases in food items, as also in agro-based industrial raw materials, in turn caused further price increases of 'manufactured products'. This generalised inflationary situation has been precipitated by the operation of several factors—both domestic and external, most importantly, liquidity pressures arising from persistent fiscal in the past few years. The unsettled situation prevailing in

the country during the latter half of the financial year added to the inflationary pressures. The important factors were supply-demanded imbalances in essential commodities like pulses, oilseeds and edible oils; constraints in augmenting supplies of commodities in short supply through imports due to the severe foreign exchange shortage; large increases in administered prices of industrial products like mineral oils and electricity and also in procurement support prices of major crops such as, wheat, rice, barley, gram, etc.; increases in railway freights, excise duties and other levies; cascading effects of the fuel price hike and curtailment of energy quota to some sectors leading to

supply bottlenecks in the wake of the Gulf crisis; rising import costs; market imperfections as in the case of cement.

#### Annual Trends in WPI and CPI

7.3 The rate of rise in the Wholesale Price Index (WPI) (base: 1981-82=100), on a point-to-point basis accelerated further to 12.1 per cent in 1990-91 from 9.1 per cent in 1989-90 and 5.7 per cent in 1988-89. On an average basis also, the increase in WPI was higher at 10.3 per cent as against 7.5 per cent each, witnessed in the previous two years..

Table 7.1 : Annual Rates of Price Increases as reflected in WPI and CPI (Percentage increase)

Year	Wholesale Price Indices				Consumer Price Indices for			
	(Base : 1981-82=100)		Industrial Workers*		Urban Non-Manual Employees%		Agricultural Labourers\$	
	Point-to-point basis	Average basis	Point-to-point basis	Average basis	Point-to-point basis	Average basis	Point-to-point basis	Average basis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1985-86	4.8	4.5	8.9	6.4	8.1	6.7	7.5	4.8
1986-87	5.1	5.7	7.5	8.8	7.0	7.9	3.1	4.8
1987-88	10.7	8.2	9.8	9.1	10.3	8.9	14.8	10.0
1988-89	5.7	7.5	8.6	9.1	7.0	8.2	10.8	12.7
1989-90	9.1	7.5	6.6	6.6	8.0	6.9	1.0	5.4
1990-91	12.1	10.3	13.6	11.2	13.4	11.0	16.6	7.6

\* From October 1988 base is 1982=100; earlier to that it is 1960=100.

@ Base : 1984-85=100. —\$Base : 1960-61=100.

7.4 All the three Consumer Price Indices (CPI), for industrial workers urban non-manual employees, and agricultural labourers, showed conspicuously accelerated rates of increases during 1990-91. Thus, on a point-to-point basis, the CPI for industrial workers (base : 1982=100) rose by 13.6 per cent against 6.6 per cent in the previous year, that for urban non-manual employees (base: 1984=100) rose by 13.4 per cent against 8.0 per cent and that for agricultural labourers (base: 1960-61=100) showed the largest increase of 16.6 per cent against 1.0 per cent. Such accelerated increases were also noticed in the indices on average basis. These higher increases in the consumer price indices in 1990-91 as compared to their increases in 1989-90 as also to the increase in WPI in 1990-91, are mainly due to a sharp increase in prices of food items which carry higher weightage in the consumer price indices than in the WPI (Graph A).

#### Group-wise Trends

7.5 Group-wise, on a point-to-point basis, the increases in the WPI of 'primary articles' (17.1 per cent in 1990-91 against 6.4 per cent in 1989-90) and 'fuel, power, light and lubricants' (14.4 per cent against 6.3 per cent in 1989-90) contrasted with the lower increase in manufactured products (8.9 per cent against 11.1 per cent). Price increases on an average basis also revealed a similar trend in all major groups.

#### Seasonal Behaviour

7.6. An analysis of seasonal behaviour of wholesale prices, on a point-to-point basis, shows that in the first phase covering

the period between end-March and end-August 1990, the price rise was high but marginally smaller than in the corresponding phase of the previous year. In the second phase covering the period between end-August and end-December which is normally characterised by a seasonal decline in the WPI, there was a sizeable increase of 3.9 per cent in contrast to a fall of 0.4 per cent in the corresponding period of 1989. During the last phase covering the period end-December to end-March, there was a slight deceleration as compared to the increase in the last phase of 1989-90. The 'primary articles' group witnessed a double-digit price rise (10.1 per cent) in the first phase, a contra-seasonal increase of 3.3 per cent in the second phase, and an increase of 3.1 per cent in the last phase. The other two major groups, 'fuel, power, light and lubricants' and 'manufactured products', witnessed exceptional increases in the second phase.

#### Commodity-wise Variations

7.7 Commodity-wise data on price trends are presented in Table 7.2. On a point-to-point basis, the index for rice price rose by 13.4 per cent as against only 1.6 per cent in 1989-90, while wheat price rose sharply by 48.9 per cent in contrast to a decline of 16.6 per cent in the previous year; this was attributable to the substantial increases in procurement prices and consequent rise in issue prices which set the trend for open market prices. Price of pulses rose by 10.8 per cent over and above an increase of 11.2 per cent in 1989-90 due to stagnation in production and secular increase in demand. Fruits and vegetables, eggs, fish and meat

Table 7.2 : Variations in Index Numbers of Wholesale Prices  
(Base : 1981-82=100)

Major Groups/Groups/ Sub-Groups/Commodities	Weight	Percentage increase during					
		Financial Year				First Quarter	
		Point-to-point basis		Average basis		Point-to-point basis	
		1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5	6	7	8
ALL COMMODITIES	100.000	9.1	12.1	7.5	10.3	4.1	2.4
I. PRIMARY ARTICLES	32.295	6.4	17.1	2.1	13.1	8.7	4.6
1. Food articles	17.386	2.1	18.9	1.2	12.0	11.5	6.2
(a) Cereals	6.824	6.2	25.3	2.2	7.9	7.8	2.2
(i) Rice	3.685	1.6	13.4	4.7	5.7	5.6	4.7
(ii) Wheat	2.248	-16.6	48.9	-3.7	16.2	14.0	-15.4
(b) Pulses	1.093	11.2	10.8	2.9	10.7	6.7	4.1
(c) Fruits and vegetables	4.089	3.6	22.7	-8.1	19.8	25.8	18.2
(d) Milk	1.961	4.5	8.9	8.9	4.2	3.6	6.0
(e) Eggs, fish & meat	1.783	6.3	10.5	4.5	9.1	1.5	11.0
(f) Condiments & spices	0.947	5.4	32.3	-13.8	25.9	16.6	13.2
(g) Other food articles	0.689	26.1	-2.0	46.2	13.3	13.0	-6.5
(i) Tea	0.564	29.7	-12.6	55.4	6.1	11.8	-2.3
(ii) Coffee	0.125	7.9	61.3	5.3	60.6	20.3	-19.9
2. Non-food articles	10.081	13.4	19.3	3.4	17.2	6.5	2.6
(a) Fibres	1.791	-4.0	24.5	11.1	5.2	5.9	15.2
(i) Raw cotton	1.335	-17.6	44.3	4.3	-0.7	9.9	21.1
(b) Oilseeds	3.861	27.4	26.6	-0.3	28.9	10.5	2.4
3. Minerals	4.828	10.8	-0.5	3.7	6.7	-0.5	1.0
(i) Petroleum crude & natural gas	4.274	12.5	-0.4	2.9	8.5	-0.4	—
II. FUEL POWER, LIGHT AND LUBRICANTS	10.663	6.3	14.4	3.7	12.3	0.7	0.5
(a) Coking coal	0.353	—	—	9.9	—	—	—
(b) Mineral oils	6.666	9.1	20.6	0.5	19.3	0.4	—
(c) Electricity	2.741	4.7	11.4	6.3	7.1	1.8	1.5
III. MANUFACTURED PRODUCTS	57.042	11.1	8.9	11.3	8.4	2.3	1.5
(a) Sugar, khandsari & gur	4.059	13.1	0.1	19.7	0.3	6.3	10.7
(i) Sugar	2.013	10.5	0.4	11.6	—	-0.9	4.0
(ii) khandsari	0.300	36.4	-2.8	32.2	-1.9	-2.8	16.0
(iii) Gur	1.746	12.7	0.1	27.0	0.8	15.5	16.9
(b) Edible oils	2.445	17.2	32.7	4.0	26.0	9.4	1.8
(c) Cotton textiles	6.093	16.6	6.5	13.9	8.0	-0.5	2.2
(d) Chemicals & chemical products	7.355	4.8	7.3	3.1	5.6	0.8	1.2
(e) Cement	0.860	14.9	14.1	10.9	17.2	-0.7	7.5
(f) Iron & steel	2.441	11.8	6.0	15.5	6.7	0.8	—

and condiments and spices witnessed price increases in the range of 10.5 per cent to 32.3 per cent, partly due to transport cost increases. Amongst other food articles, coffee prices rose by 61.3 per cent, while among fibres, raw cotton prices rose by 44.3 per cent. Due to the failure of Kharif groundnut crop in major producing areas owing to adverse weather conditions, oilseeds prices rose by 26.6 per cent on top of an increase of 27.4 per cent in 1989-90. Shortfall in production coupled with paucity of imports, pushed up the edible oil prices rather sharply by 32.7 per cent in addition to an increase of 17.2 per cent in 1989-90. Prices of mineral oils registered a significant increase of 20.6 per cent as compared

to 9.1 per cent in 1989-90, following the 25 per cent hike in their prices in October 1990. Cement prices rose by 14.1 per cent in 1990-91 on top of an increase of 14.9 per cent in 1989-90. Wholesale prices data on an average basis reveal a similar picture for almost all commodities.

#### Weighted Contribution

7.8 An analysis of weighted contribution of different groups/commodities to the increase, in the general index of wholesale prices reveals that, on a point-to-point basis, the primary articles, with a weight of 32.3 per cent in the

general index, contributed the most to the total price rise at 44.6 per cent in 1990-91 as compared with about half the contribution of 23.0 per cent in 1989-90. The 'fuel group' with a weight of 10.7 per cent in the general index, contributed 12.2 per cent as compared with that of 7.3 per cent in the previous year whereas, the contribution of 'manufactured products' to the increase in WPI stood at 43.0 per cent as compared to 70.3 per cent in 1989-90. About 25 per cent weighted contribution came from three items, viz., oilseeds, edible oils and mineral oils with another 12.7 per cent emanating from cereals alone. A generally similar trend is seen on average basis.

#### Administered Prices.

7.9 The composite index of the administered prices of industrial products namely, coal, iron and steel, non-ferrous metals (excluding aluminium), petroleum crude and natural gas, mineral oils, electricity and fertilizers, with a weight of 19.7 per cent in the general index of wholesale prices, recorded a rise of 9.9% in 1990-91 which was higher than that of 7.5 per cent in the previous year. The weighted contribution of the administered manufactured products to the increase in WPI, was, on a point-to-point basis, marginally lower at 14.3 per cent in 1990-91 as compared with 14.7 per cent in 1989-90. Changes in the indices of the major items subsequent to upward revisions in their administered prices were: petroleum products (20.6 per cent), electricity (11.4 per cent), iron and steel (6.0 per cent) and non-ferrous metals (3.4 per cent).

#### First Quarter (April-June 1991-92) Trends

7.10 During the first quarter (April-June) of the current financial year 1991-92, the pressure on general price level eased to some extent and the general index of wholesale prices registered a much smaller rise of 2.4 per cent as compared with the increase of 4.1 per cent in the similar quarter of 1990-91. The slowdown in price rise was mainly due to lower increase in the 'primary articles' index which rose by 4.6 per cent as compared with the significant rise of 8.7 per cent registered in the comparable period of 1990-91. The absence of supply bottle-necks alongwith comfortable stock position of rice and wheat are some of the factors contributing to the lower rise in prices of primary articles. The index of 'fuel, power light and lubricants' rose by 0.5 per cent as against a rise of 0.7 per cent in the previous corresponding period. The 'manufactured products' group registered a relatively smaller increase during April-June 1991-92 of 1.5 per cent as compared with an increase of 2.3 per cent in the first quarter of 1990-91.

7.11 During the first quarter (April-June) of 1991-92, the CPI for Industrial Workers, on a point-to-point basis, registered a rise of 4.0 per cent which was lower than the rise of 4.5 per cent recorded in the corresponding period of 1990-91. On the other hand, the increase of 12.4 per cent, on an average basis, was significantly higher than that of 7.7 per cent in the corresponding period of the previous year.

\*Since proposed to be reduced to an increase of 30 per cent with exemption for small and marginal farmers.

#### Agricultural Price Policy

7.12 Procurement/support prices were raised for all the important crops in 1990-91 despite substantial upward revisions in their prices in the previous year; the increase in wheat was 17.5 per cent and paddy/rice (average variety) 10.8 per cent. The percentage increases in prices of wheat, barley, gram and mustard were higher for the 1990-91 marketing season than those in the previous year. The increases for paddy, pulses, oilseeds (other than mustard) albeit proportionately lower than in 1989-90, were nevertheless substantial. For the 1991-92 marketing season, procurement prices of wheat, barley, gram, safflower, toria, mustard, sugarcane and raw jute have been announced. Of these, the proportionate increase in raw jute price was over 17 per cent while that of wheat was 4.7 per cent. The regular Union Budget for 1991-92 seeks to compensate farmers through suitable increases in procurement prices, the resultant increase in cost of agricultural output as a result of freeing low analysis fertilisers from price and movement controls and an increase in the prices of all other fertilisers by 40 per cent\* on an average and a ceiling on the subsidy per tonne on single super phosphate.

#### Industrial Price Policy

7.13 Mineral oils prices have had to be increased by 25 per cent to neutralise the effect of sharp increases in the prices of imported crude oil and petroleum products following the Gulf crisis; these increases were preceded by price increases earlier in the year. Again, the Union Budget for 1991-92 has proposed in July 1991 an increase of 20 per cent in prices of petrol, motor spirit and aviation turbine fuel. Diesel was exempted from the upward revision and kerosene prices were reduced by 10 per cent. Prices of iron and steel were revised to cover the escalation in input prices and other levies. Prices of non-ferrous metals (other than aluminium), namely, copper, zinc, lead and nickel, which are mostly imported, were revised from time to time to reflect changes in international prices and exchange rates. Prices of electricity were also raised. The Central Budget for 1991-92 has proposed the enhancement of sugar prices under PDS as also the increase in excise duty on free sale sugar. The Railway Budget 1991-92 has proposed a general increase of 10 per cent in railway freight charges; however, some essential commodities like edible oils, foodgrains, sugar, gur and fruits and vegetables were exempted from the increase.

#### Bullion Prices

7.14 As depicted in Table 7.3, the price of gold in the Bombay market rose by 8.3 per cent during 1990-91, that is, much higher than the increase of 1.9 per cent in 1989-90. The rise in the price of gold was also much higher than the increase in the price of silver. Even so, the premium prevalent in the domestic price of silver over its international price not only remained phenomenally high (at 162 per cent in 1990-91 against 59.5 per cent in gold) but also widened much more sharply in recent years as compared with the trend in the premium available in the domestic price of gold.

Table 7.3 : Gold and Silver Prices in Bombay and International Markets

Year	Gold		Silver		Spread between	Spread between
	Bombay Market (Rs. per 10 grammes for standard gold)		Bombay Market (Rs. per Kg. for 0.999 fineness)		Bombay and London prices	Bombay and New York prices
					(Average in percentage)	
	Year-end	Average	Year-end	Average	Gold*	Silver*
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1,700 (27.8)	1,522 (31.3)	2,720 (2.4)	2,617 (13.9)	+2.5	34.9
1981-82	1,645 (-3.2)	1,719 (12.9)	2,680 (-1.5)	2,636 (0.7)	+42.1	+0.3
1982-83	1,800 (9.4)	1,723 (0.2)	3,105 (15.9)	2,798 (6.2)	+37.8	+1.1

1	2	3	4	5	6	7
1983-84	1,975 (9.7)	1,859 (7.8)	3,570 (15.0)	3,506 (25.3)	+38.5	+0.3
1984-85	2,130 (7.8)	1,984 (6.8)	3,955 (10.8)	3,594 (2.5)	+53.3	+27.9
1985-86	2,140 (0.5)	2,126 (7.1)	4,015 (1.5)	3,918 (9.0)	+64.8	+63.5
1986-87	2,570 (20.1)	2,324 (9.3)	4,794 (19.4)	4,247 (8.4)	+47.3	+91.3
1987-88	3,130 (21.8)	3,082 (32.7)	6,066 (6.5)	5,539 (30.4)	+61.2	+83.6
1988-89	3,140 (0.3)	3,175 (3.0)	6,755 (11.4)	6,367 (14.9)	+62.0	+114.3
1989-90	3,200 (1.9)	3,229 (1.7)	6,463 (-4.3)	6,842 (7.5)	+56.5	+140.4
1990-91	3,466 (8.3)	3,452 (6.9)	6,646 (2.8)	6,761 (-1.2)	+59.5	+162.1

\* The spread has been worked out after converting the quotations in dollars per troy ounce in London market into rupees per 10 grams at the cross rates based on daily average of spot buying and selling rates of U.S. dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and selling rates of sterling.

\*\* The spread has been worked out after converting the quotations in cents per troy ounce in New York market into rupees per Kg. at the cross rates based on the daily average of spot buying and selling rates of US dollars in London and average of Reserve Bank's spot buying and selling rates of sterling.

7.15 The relative price movements of gold and silver are depicted in Table 7.4 and Graph B. As may be seen therefrom, distinctly contrary trends are observed in these relative prices as between domestic and international markets during the 1980s. In the international market, one gramme of gold could, on an average, buy 37 grammes of silver in 1980-81 but 'it could' fetch as much as 83 grammes of the white metal in 1990-91 thus indicating a sharp price movement in favour of gold. Contrariwise, in the domestic market, one gramme of gold could be exchanged for 59 grammes of silver in 1980-81 or 66 grammes of silver in 1981-82 but only for 51 grammes in 1990-91, which reflects the relative price movement favouring silver. The acute pressure on silver prices in the domestic market is possibly attributable to reduced distress sales from rural areas and a more rapid increase in industrial uses of the metal.

Table 7.4 : Gold and Silver Ratio in terms of Grammes.

Grammes of silver (of 0.999 fineness) available per 1 gramme of standard gold.

Year	In Bombay Market*		In International Market†	
	On average Price basis (grammes)	On Year-end Price basis grammes	On average Price basis (grammes)	On Year-end Price basis (grammes)
1	2	3	4	5
1980-81	59	63	37	43
1981-82	66	61	46	45
1982-83	62	58	44	39
1983-84	53	55	38	40
1984-85	55	53	46	49
1985-86	55	54	54	65
1986-87	55	54	71	67
1987-88	56	51	64	68
1988-89	50	46	66	66
1989-90	47	49	72	75
1990-91	51	53	83	92

\* Based on quotations of Bombay Bullion Association.

† Based on quotations received from Press Trust of India for London and New York Market.

7.16 With the two-step adjustment in the exchange rate of the Rupee, the gold and silver prices in the Bombay market have firmed up rather sharply during the month of July 1991.

## 8. GOVERNMENT FINANCES

### Centre's Budget Deficit

8.1 The Central Government finances faced many pressures during 1990-91. The persistent macro-economic difficulties accentuated by the outbreak of the Gulf crisis brought about severe pressure on the already strained fiscal situation. Revenue receipts lagged behind, while aggregate disbursements outstripped the original estimates. This occurred despite additional tax measures during the mid-year, expenditure cuts and other economy measures. The conventional budget deficit of the Central Government, as per the revised estimates, stood at Rs. 10,772 crore during 1990-91, about 50 per cent higher than the budgeted level of Rs. 7,206 crore. As per the Reserve Bank records, the actual deficit for 1990-91, after the closure of accounts, was placed at Rs. 11,430 crore (or 2.2 per cent of GDP) as against Rs. 10,624 crore (2.4 per cent of GDP) in 1989-90. As per revised estimates of 1990-91, net RBI credit to the Central Government, which captures the monetary impact of the Centre's budgetary operations, was estimated at Rs. 13,000 crore, that is, slightly lower than the actuals of Rs. 13,813 crore in 1989-90. The final outcome for 1990-91 turned out to be much larger at Rs. 14,746 crore as on March 31, 1991 after closure of Government accounts.

8.2 A study of the seasonal movement of the budgetary deficit and net RBI credit to the Central Government during 1990-91 reflects the tendency of these deficit measures ruling way above the estimated level for the major part of the year and dropping drastically in the last week of the year on closure of Government accounts. The budgetary deficit and net RBI credit to the Central Government during 1990-91 exceeded their estimated levels as early as in May 1990. The estimated budgetary deficit of Rs. 9,977 crore in the interim budget for 1990-91 was also exceeded in the first week of June 1991. The overshooting of the estimated deficit in the early months of the fiscal year has become a regular feature now for some years (Table 8.1).

8.3 According to the regular Budget of the Central Government for 1991-92 submitted to the Parliament on July 24, 1991, the deficit according to the conventional definition, after taking into account additional resource mobilisation, is estimated at Rs. 7,719 crore, that is, lower by 28.3 per cent

over the revised figure of Rs. 10,772 crore in 1990-91. This implies that about 6.6 per cent of the total budgetary outlay would remain uncovered in 1991-92 as compared with 9.8 per cent in 1990-91.

## Fiscal Deficit

8.4 In the last year's Annual Report, specific attention was drawn to different measures of the deficit to capture the full impact of the Central Government's budgetary operations.

Table 8.1 : Fortnightly Levels of the Centre's Budget Deficit and Net RBI

Credit to Central Government @

(Rupees crore)

Period		Centre's Budget Deficit				Net RBI Credit to the Centre			
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
		1	2	3	4	5	6	7	8
Budget Estimates		7,484	7,337	7,206	7,719	7,484	7,337	7,206	7,719
(Fortnight Actuals)	Dates								
1	6-4-90	2,401	1,170	2,679	2,271	2,036	2,011	2,712	2,427
2	20-4-90	3,782	3,497	3,204	3,716	3,508	3,722	4,050	3,269
3	4-5-90	4,976	6,045	5,754	5,508	4,378	5,461	4,994	3,962
4	18-5-90	5,539	6,176	6,638	8,409	5,001	6,392	7,058	6,764
5	1-6-90	6,134	8,565	8,228	8,925	4,180	7,675	6,907	7,534
6	15-6-90	7,525	9,508	7,698	11,029	6,976	7,784	7,463	9,607
7	29-6-90	8,667	9,824	9,107	11,503	8,582	7,858	7,703	9,168
8	13-7-90	9,468	11,378	9,996		9,035	9,500	9,883	
9	27-7-90	8,515	11,382	10,128		7,344	9,140	8,185	
10	10-8-90	9,300	13,416	10,976		8,331	10,277	9,018	
11	24-8-90	8,332	12,596	8,729		7,029	9,938	6,543	
12	7-9-90	9,897	13,265	10,290		7,355	10,664	82,09	
13	21-9-90	8,831	11,535	10,289		6,723	9,111	7,269	
14	5-10-90	9,438	12,953	11,971		7,253	11,186	9,245	
15	19-10-90	9,249	10,375	10,755		7,474	9,869	10,241	
16	2-11-90	9,079	10,934	11,830		6,424	8,901	10,438	
17	16-11-90	9,422	13,044	13,636		8,081	12,403	12,476	
18	30-11-90	10,308	13,789	13,001		7,875	12,748	12,978	
19	14-12-90	10,154	13,317	15,330		9,065	13,634	15,159	
20	28-12-90	8,546	11,789	13,097		8,060	12,611	13,029	
21	11-1-91	9,172	14,206	15,093		9,679	15,277	15,055	
22	25-1-91	9,134	14,158	15,123		9,334	15,255	14,621	
23	8-2-91	10,187	13,675	15,442		9,965	15,395	15,447	
24	22-2-91	9,437	13,790	14,627		9,742	15,804	15,107	
25	8-3-91	8,597	14,266	15,072		9,228	16,383	16,064	
26	22-3-91	7,184	10,290	11,969		8,175	14,344	14,486	
March 31		5,810	10,624	11,430		6,503	13,813	14,746	
Quarterly Averages									
First Quarter		5,060	6,398	6,187		4,347	5,843	5,841	
Second Quarter		9,001	12,262	10,068		7,771	9,772	8,185	
Third Quarter		9,457	12,314	12,803		7,747	11,622	11,938	
Fourth Quarter		8,503	13,001	14,108		8,947	15,182	15,075	
Financial Year Average		8,114	10,947	10,818		7,309	10,635	10,337	

@ Based on RBI records.

The relevant dates of fortnights for 1990-91 have been specified; the data for other years pertain to corresponding fortnights.

Note : 1. For 1989-90 Net RBI credit to Centre included from August 23, 1989, amounts ranging from Rs. 78 crore to Rs. 721.43 crore representing replacement of non-negotiable non-interest bearing securities issued to the IMF by RBI claims on Central Government for facilitating repurchases from the Fund. Till March 22, 1990 budget deficit also included these amounts as a special security for Rs. 721.43 crore was created on March 23, 1990. A similar security for Rs. 325 crore was created in March 1991.

2. As per budgetary data, Centre's deficit was Rs. 5,642 crore in 1983-89 and Rs. 10,592 crore in 1989-90.



The conventional deficit and the net RBI credit to the Central Government only reveal a part of the structural imbalances in the Government's fiscal operations, whereas the broader concept of deficit, viz., the gross fiscal deficit, provides measure of overall resource gap in terms of excess of aggregate disbursements over revenue receipts including grants which fully reflects the impact of fiscal operations on the indebtedness of the Central Government. The trends in the alternative measure of the Central Government's deficit since 1980-81 together with their respective ratios to GDP at current market prices are set out in Table 8.2.

8.5 Apart from the growing size of the conventional deficit and monetised deficit, the gross fiscal deficit registered a large increase during the past decade. It increased from Rs. 8,299 crore in 1980-81 to Rs. 21,857 crore in 1985-86, and to Rs. 43,331 crore in 1990-91. As a percentage to GDP, the gross fiscal deficit registered an increase from 6.1 per cent in 1980-81 to 8.3 per cent in 1985-86 and is estimated to have reached 8.4 per cent in 1990-91. In 1990-91, the conventional deficit captured only one-fourth of the overall resource gap as represented by the gross fiscal deficit (see also Graphs C and D).

8.6 The financing pattern of the gross fiscal deficit over the last decade, as shown in Table 8.3, reveals that while the reliance on external finance declined from 15.4 per cent in 1980-81 to 9.2 per cent in 1990-91, the domestic borrowings financed an increasing portion of the gap; its share increased from 84.6 per cent to 90.8 per cent over this period. Within the domestic sources, the share of market borrowings and conventional deficit declined from 32.3 per cent and 29.9 per cent, respectively, in 1980-81 to 18.5 per cent and 24.8

percent respectively in 1990-91, whereas other liabilities comprising small savings, provident funds, special deposits and net accretion from public account, etc., mainly financed the increasing magnitude of the resource gap. These sources financed 47.5 per cent of the gap in 1990-91, i.e. more than their share of 22.4 per cent in 1980-81.

8.7 The escalating levels of overall resource gap resulted in a rapid growth of domestic indebtedness of the Central Government during the 'eighties. The total outstanding internal liabilities of the Central Government increased to Rs. 2,79,528 crore as at the end of March 1991 accounting for 53.9 per cent of GDP from Rs. 48,251 crore or 35.6 percent of GDP as at the end of March 1981 (Table 8.4).

8.8 The growing liabilities accumulated in recent years at a rapidly rising cost which are associated with a widening revenue account gap large absorption of resources by non-plan expenditures sum up the fiscal malaise facing the Indian economy.

8.9 According to the revised estimates, the total expenditure for 1990-91 amounted to Rs. 1,09,385 crore reflecting a significant increase over the budgeted level by Rs. 7,251 crore. Apart from a large increase in expenditure on account of subsidies, interest payments, rural debt relief, technical credits and higher non-Plan assistance to States and Union Territories, one of the unanticipated expenditures was that incurred for repatriation of Indian citizens from Kuwait to the extent of Rs. 300 crore. Gross tax revenue was expected to fall short of the budget estimates by Rs. 862 crore and the shortfall was

TABLE 8.2 : Monetised, Budget, Gross and Net Fiscal Deficit

(Rupees crore)						
Year	Gross Fiscal Deficit@	Net Fiscal Deficit@	Monetised Deficit	Conventional Deficit	Revenue Deficit	GDP at Market Prices
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	8,299	5,110	3,551	2,477	2,037	1,36,013
1981-82	8,666	4,591	3,207	1,400	392	1,59,760
1982-83	10,627*	5,973*	3,368	1,656*	1,308	1,78,132
1983-84	13,030*	8,171*	3,949	1,417*	2,540	2,07,589
1984-85	17,416	10,972	6,055	3,745	4,225	2,31,387
1985-86	21,857*	13,543*	6,190	5,315*	5,889	2,61,920
1986-87	26,342	17,036	7,091	8,261	7,777	2,91,974
1987-88	27,044	18,431	6,559	5,816	9,137	3,32,616
1988-89	30,923	20,770	6,503	5,642	10,515	3,94,992
1989-90	35,630	23,720	13,813	10,592	11,912	4,42,769
1990-91(a)	43,331	30,207	14,746†	10,772	17,585	5,18,500†
1991-92 (Interim Budget Estimates)	38,475	27,991	9,977	9,977	17,766	
1991-92 (Regular Budget Estimates)	37,727	24,191	7,719	7,719	13,854	5,80,400£
As a Percentage to GDP at Market Prices.						
1980-81	6.10	3.76	2.61	1.82	1.50	
1981-82	5.42	2.87	2.01	0.88	0.25	
1982-83	5.97	3.35	1.89	0.93	0.73	
1983-84	6.28	3.94	1.90	0.68	1.22	
1984-85	7.53	4.74	2.62	1.62	1.83	
1985-86	8.34	5.17	2.36	2.03	2.25	
1986-87	9.02	5.83	2.43	2.83	2.66	
1987-88	8.13	5.54	1.97	1.75	2.75	
1988-89	7.83	5.26	1.65	1.43	2.66	
1989-90	8.05	5.36	3.12	2.39	2.69	
1990-91	8.36	5.83	2.84	2.08	3.39	
1991-92 (Regular Budget Estimates)	6.50	4.17	1.33	1.33	2.39	

@ These data differ from those published earlier on account of certain adjustments of contra entries on the capital account.

\* Excluding medium-term loans of Rs. 1,743 crore in 1982-83, Rs. 400 crore in 1983-84 and Rs. 1,628 crore in 1985-86 given to States to clear their overdrafts with the RBI.

+ Actuals as per RBI records.

\$ Estimated. See Chapter 2 of the Report.

£ Rough estimate

(a) Figures relate to Revised Estimates.

Note : 1. The data are based on the latest Budget Documents and may differ from those published earlier.

2. For definition of deficit concepts, see Annual Report, 1989-90 pp. 84-85.

Source : Central Government Budget Documents and RBI records and National Accounts Statistics, 1991.

Table 8.3: Financing of Fiscal Deficit.

Year	External Finance	Internal Finance			(Rupees crore)	
		Market Borrowings†	Other Liabilities@	Conventional Deficits §	Total (3+4+5)	Total Finance/Gross Fiscal Deficit (2+6) (2+5)
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	1281 (15.4)	2679 (32.3)	1862 (22.4)	2477 (29.9)	7018 (84.6)	8299 (100.0)
1981-82	964 (11.1)	2913 (33.6)	3389 (39.1)	1400 (16.2)	7702 (819)	8666 (100.00)
1982-83	1258 (11.8)	377 (35.5)	3942 (37.1)	1656* (15.6)	9369 (88.2)	10627 (100.0)
1983-84	1338 (10.3)	4038 (31.0)	6237 (47.8)	1417* (10.9)	11692 (89.7)	13030 (100.0)
1984-85	1452 (8.3)	4095 (23.5)	8124 (46.7)	3745 (21.5)	15964 (91.7)	17416 (100.0)
1985-86	1449 (6.6)	4884 (22.4)	10209 (46.7)	5315* (24.3)	20408 (93.4)	21857 (100.0)
1986-78	2024 (7.7)	5532 (21.0)	10525 (39.9)	8261 (31.4)	24318 (92.3)	26342 (100.0)
1987-88	2893 (10.7)	5862 (21.7)	12473 (46.1)	5816 (21.5)	24151 (89.3)	27044 (100.0)
1988-89	2460 (8.0)	8418 (27.2)	14403 (46.6)	5642 (18.2)	28463 (92.0)	30923 (100.0)
1989-90	2595 (7.3)	7404 (20.8)	15039 (42.2)	10592 (29.7)	33035 (92.7)	35630 (100.0)
1990-91 (RE)	3984 (9.2)	8000 (18.5)	20575 (47.5)	10772 (24.8)	39347 (90.8)	43331 (100.0)
1991-92 (Interim Budget Estimates)	4000 (10.4)	7500 (19.5)	16998 (44.2)	9977 (25.9)	34475 (89.6)	38475 (100.0)
1991-92 (Regular Budget Estimates)	3510 (9.3)	7500 (19.9)	18998 (50.3)	7719 (20.5)	34217 (90.7)	37727 (100.0)

Note Figures in brackets represent percentages to total finance/gross fiscal deficit.

† These may, for some years, differ from the data presented in Table 8.11 based on RBI records due to accounting leads and lags.

\* Excluding medium term loans of Rs. 1,743 crores in 1982-83, Rs. 400 crores in 1983-84 and Rs. 1,628 crores in 1985-86 given to States to clear their overdraft with RBI.

@ 'Other Liabilities' comprise small savings, provident funds, special deposits, reserve funds, etc.

§ Defined as variations in 91-day Treasury bills issued net of changes in cash balances with RBI.

Source : Budget documents of Government of India.

Table 8.4 : Total Outstanding Liabilities of Government of India

(Rupees crore)							
Year	Internal Debt	Small Savings	Provident Fund & other Accounts	Reserve Fund & Deposits	Total Internal Liabilities	External Liabilities	Total Liabilities
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	30864 (22.7)	7976 (5.9)	5977 (4.4)	3634 (2.6)	48451 (35.6)	11298 (8.3)	59749 (43.9)
1981-82	35653 (22.3)	9375 (5.9)	7203 (4.5)	3627 (2.3)	55858 (35.0)	12328 (7.7)	68186 (42.7)
1982-83	46939 (26.4)	11098 (6.2)	8789 (4.9)	4364 (2.5)	71190 (40.0)	13682 (7.7)	84872 (47.7)
1983-84	50263 (24.2)	13506 (6.5)	10368 (5.0)	6004 (2.9)	80141 (39.6)	15120 (7.3)	95261 (45.9)
1984-85	58537 (25.3)	17157 (7.4)	12547 (5.4)	8563 (3.7)	96804 (41.8)	16637 (7.2)	113441 (49.0)
1985-86	7139 (27.1)	21449 (8.2)	15410 (5.9)	11433 (4.4)	119331 (45.6)	18153 (6.9)	137484 (52.5)
1986-87	86312 (29.6)	24725 (8.5)	20204 (6.9)	15006 (5.1)	146247 (50.1)	20299 (6.9)	166546 (75.0)
1987-88	98646 (29.6)	28358 (8.5)	26170 (7.9)	19164 (5.8)	172338 (51.8)	23223 (7.0)	195561 (58.8)
1988-89	114498 (29.0)	33833 (8.6)	34702 (8.8)	20992 (5.3)	204025 (51.7)	25746 (6.5)	229771 (58.2)
1989-90	133193 (30.1)	41791 (9.4)	45273 (10.2)	19592 (4.4)	238949 (54.2)	28343 (6.4)	268192 (60.6)
1990-91 (RE)	151352 (29.2)	49071 (9.5)	57208 (11.0)	21897 (4.2)	279528 (53.9)	31831 (6.1)	311359 (60.0)
1991-92 (BE)	171589 (29.5)	56281 (9.7)	68046 (11.7)	24162 (4.2)	320078 (55.1)	35123 (6.1)	355201 (61.2)

Note: Figure in brackets represent percentages to Gross Domestic Product at current market prices.

Source: Budget documents of Government of India.

mostly in customs and excise duties. In the middle of the fiscal year 1990-91, the Government introduced a package of measures for short-term adjustment of the economy which intended to mobilise additional resources and at the same time to exercise strict control over expenditure. There were a few rounds of additional tax imposition between October and December 1990 which were expected to mobilise Rs1,600 crore as additional tax revenue. On the expenditure side, there were expenditure cuts effected twice during the year-on July 2 and November 30, 1990. Despite additional taxes, the revised estimates for the year showed a substantial shortfall in gross tax revenue, particularly in customs and excise collections. Likewise, notwithstanding the expenditure cuts, the revised of aggregate expenditure turned out to be higher by 7.1 percent than the budget estimates. In the then Finance Minister statement presented to parliament in December 1990, the Government assured that it would continue the process of fiscal correction and consolidation during the financial year 1991-92. It was hoped that the gross fiscal deficit of the Central Government would be reduced significantly to about 6.1 percent of GDP in 1991-92. As perceived in that Statement, such a reduction would be the beginning of our transition to a sustainable fiscal regime, over of three years, in which the fiscal deficit returns to a range of 3 to 4 percent of GDP as it was in the mid-1970s.

#### Fiscal Adjustments and Structural Reforms

8.10 The 1980's witnessed serious macro-economic imbalances in the economy culminating in to an unprecedented fiscal and balance of payment crisis in 1990-91. Against this background, the Central Government has sought to initiate the process of fiscal adjustment and macro-economic stabilisation

to be followed by continued fiscal consolidation thereafter over a medium-term perspective of three years beginning with the current fiscal year 1991-92. Such an adjustment programme is proposed to be carried out without supping the growth process in the economy and with an endeavour to minimise the burden of adjustment on the poor.

#### The Interim Budget 1991-92

8.11 The process of correction of fiscal imbalance was first initiated by the interim Budget by envisaging a lower level of gross fiscal deficit of Rs. 38,471 crore in 1991-92 as compared with Rs. 43,331 crore in 1990-91. Such a reduction in the gross fiscal deficit in the interim Budget was expected to be achieved by introducing certain selective rationalisation measures in the sphere of revenue and non-Plan expenditure : (i) cut in expenditure on major subsidies by Rs. 934 crore; (ii) reduction in loans to States and Union Territories on account of their share in small savings as a result of the transfer of the National Savings Scheme to the proposed Bharat Bachat Bank; (iii) as a major initiative, the proposed disinvestment up to 22 per cent of the Centre's equity holdings in selective public sector enterprises in favour of Mutual Funds and other financial or investment institutions to net in resource of Rs. 2,500 crore in 1991-92. A further review of all expenditure provisions during the course of the year alongwith the above measures were expected to bring down gross fiscal deficit to 6.5 per cent of GDP in 1991-92 from 8.4 per cent in 1990-91.

8.12 The interregnum period of the first four months of the current year saw, in the absence of appropriate policy

measures which could result in the desired expenditure reduction, further worsening of the fiscal situation.

#### The Regular Budget for 1991-92

8.13 The regular Budget of the Central Government initiated a major attempt of fiscal adjustment by rationalising the tax and expenditure structure. In the fiscal sector, the Budget has envisaged a substantial reduction in the levels of gross fiscal deficit, revenue deficit as well as the conventional deficit. At the revised rates of taxes and duties, gross fiscal deficit has been estimated at Rs 36,727 crore for 1991-92 implying a reduction of Rs. 5,604 crore from the level of Rs. 43,331 crore in 1990-91. At this level, the gross fiscal deficit as a percentage of GDP would come down from 8.4 per cent in 1990-91 to 6.5 per cent in 1991-92.

8.14 The conventional deficit has been placed at Rs.9,724 crore without reckoning with the measures for additional resource mobilisation (ARM). After taking into account the additional yield of Rs.2,005 crore accruing to the Centre from the ARM proposals, the deficit is estimated at Rs.7,719

crore in 1991-92 as compared with Rs.10,772 crore in 1990-91. More significantly the level of revenue deficit, which has been showing unabated increases over the last decade is estimated at Rs.13,854 crore in 1991-92, that is, lower by Rs 3,731 crore than that of Rs.17,585 crore in 1990-91 (T.8.5)

8.15 The envisaged reduction in the gross fiscal deficit, as well as revenue deficit has been effected by rationalising the non-plan expenditure and resorting to additional taxation. While the provision for major subsidies has been pruned by Rs.1,726 crore in the current year, no provision has been made for additional instalments of dearness allowance that may become payable during the current year. Such additional expenditures are expected to be absorbed within the approved budget estimates of the Ministries without, however, affecting their Plan allocations. As a result, total provision for non-plan expenditure, excluding interest payment, for 1991-92 represents a reduction of 4.9 percent compared with that in the revised estimates for 1990-91. The Budget retains the proposal for disinvestment in public sector enterprises to the extent of Rs.2,500 crore indicated in the interim Budget, but the equity

**Table 8.5: Budgetary Deficit, Market Loans and RBI support to the Central Government**  
(Fiscal Years 1989-90 to 1991-92)

Items	(Rupees crore)			
	1989-90 (Accounts)	1990-91 (Budget Estimates)	1990-91 (Revised Estimates)	1991-92 (Budget Estimates)
1	2	3	4	5
<b>1. Revenue Account</b>				
(i) Receipts (a)	54614	60763	60049	70870
(ii) Expenditure (a)	66526	73795	77634	84724
(iii) Surplus (+)/Deficit(-)	-11912	-13032	-17585	-13854
<b>2. Capital Account</b>				
(i) Receipts	30018	34165	38564	38174
(ii) Disbursements	28698	28339	31751	32039
(iii) Surplus (+)/Deficit(-)	+1320	+5826	-6813	-6135
<b>3. Total Receipts (1(i) + 2(i))</b>	<b>84632</b>	<b>94928</b>	<b>98613</b>	<b>109044</b>
<b>4. Total Expenditure (1(ii) + 2(ii))</b>	<b>95224</b>	<b>102134</b>	<b>109385</b>	<b>116763</b>
<b>5. Overall Surplus (+)/Deficit(-)</b>	<b>-10592</b>	<b>-7206</b>	<b>-10772</b>	<b>-7719</b>
<b>6. (5) as percent of (4)</b>	<b>11.1</b>	<b>7.1</b>	<b>9.8</b>	<b>6.6</b>
<b>7. Net Market Loans*</b>	<b>7404</b> (8044)	<b>8000</b> (8988)	<b>8000</b> (8988)	<b>7500</b> (8918)
<b>8. (7) as percent of (3)</b>	<b>8.7</b>	<b>8.4</b>	<b>8.1</b>	<b>6.9</b>
<b>9. Increase(-)/Decrease(-) in RBI holdings of Government Rupee Securities other than Treasury Bills(b)</b>	<b>-3000</b>		<b>+33481</b>	
<b>10. Increase(-)/Decrease(-) in net RBI Credit to Central Government(c)</b>	<b>+13813</b>	<b>+7206</b>	<b>+13000</b>	<b>+7719</b>

\* Gross market loans are shown in brackets.

(a) Include commercial departments. Revenue receipts include effects of Budget proposals.

(b) On book value basis, according to RBI records.

(c) As per memorandum item given in the Union Budget.

(d) As per book value.

would be incurred not only to horticulture and workers but also to investing public at large (as set out in the new industrial policy statement). In addition to this, the Budget contains resource mobilisation measures to fetch an additional revenue of Rs. 2,617 crore in 1990-91.

8.16 In order to provide stimulus for foreign exchange inflow and investment, the Budget has outlined two important measures. The first measure allows remittances in foreign exchange to be made to any person in India and exempts them from gift tax. Such remittances will enjoy general immunity from tax laws including the absence of scrutiny of sources of such funds. Under the second measure State Bank of India proposes to float India Development Bonds for purchase by NRIs and their overseas corporate bodies. Apart from being exempted from Wealth Tax, these Bonds guarantee exchange rate protection and free repatriation of the face value and interest. In addition to this NRI investment on non-repatriable basis is opened for areas like housing, infrastructure and real estate including general exemption under Foreign Exchange Regulation Act requiring permission for them to acquire residential property.

8.17 Under another measure, any person would be allowed to open deposits with the National Housing Bank (NHB) on or before November 30, 1991 with complete immunity from enquiry and investigations as to the sources of funds 40 per cent of such deposit would be deducted as a special levy to be kept as a corpus for the NHB which will be utilised for slum clearance and low cost housing for the poor.

8.18 The budget proposes to carry out several reforms in the interest rate structure in the country. Apart from the rates applicable to the capital market, the interest rate payable on small savings schemes is purposed to be raised on the lines of the recent hike in interest rates on bank deposits.

8.19 The Budget has laid utmost emphasis on the development of agricultural and rural sectors. The share of these sectors would continue to be at 50 per cent of the Plan resources. The strategy of development would be reoriented with employment programmes and creation of social welfare programmes conducive to the development of human resources and weaker sections of society. The Budget outlines five new areas of action, viz., establishment of a Corporation for the welfare of the backward classes, setting up of a National Renewal Fund for absorbing the burden on labour of technical change and modernisation, programme for the development of families affected by communal riots, promoting national integration through youth participation, and promotion of South-South co-operation.

#### Central's Plan Outlay

8.20 Total Central Plan outlay placed at Rs. 42,969 crore for 1991-92 shows an increase of 12.9 per cent over the revised outlay for 1990-91 and by 9.3 per cent over the budgeted outlay for the same year. The budgetary support to the Plan outlay, which was brought down from Rs. 18,159 crore in 1989-90 to Rs. 17,594 crore in 1990-91, would increase to Rs. 19,015 crore in 1991-92, though its share in total financing would slip down to 44.3 per cent from 46.2 per cent in 1990-91. The budget support for the State and Union Territory plans, which has been showing a high order of increase during recent years, is estimated to go up by 19.0 per cent to Rs. 14,710 crore in 1991-92 on top of an increase of 20.7 per cent in 1990-91.

#### Plan and Non-Plan Expenditure\*

8.21 Total Plan expenditure estimated at Rs. 33,725 crore in 1991-92 would increase by 12.6 per cent over the corresponding level of Rs. 29,956 crore in 1990-91. Of this, the revenue Plan expenditure would account for 50.6 per cent of the total implying that a major share of the Plan expenditure would be incurred under current heads like consumption expenditure, maintenance of assets, etc., rather than in the creation of new assets. In a significant attempt to cut down expenditure, total non-Plan expenditure has been budgeted to show an increase of 3.8 per cent from Rs. 76,761 crore in 1990-91 to Rs. 79,697 crore in 1991-92; in real terms this represents a substantial cut over the previous year. Under non-Plan expenditure, interest payments would continue to

be the single largest expenditure item, and are estimated to go by 25.6 per cent to Rs. 27,450 crore in 1991-92. Net interest burden, adjusted for interest receipts at Rs. 16,441 crore in 1991-92, would absorb 31.3 per cent of the Centre's net tax receipts as compared with 27.7 per cent in 1990-91. Total defence expenditure anticipated at Rs. 16,350 crore in 1992-92 would be only 3.8 per cent or Rs. 600 crore higher than that in the previous year. Total provision for subsidies has been curtailed from Rs. 12,121 crore in 1990-91 to Rs. 10,395 crore in 1991-92 including Rs. 1,500 crore for debt relief to farmers in each of the years. Expenditure on major subsidies which was brought down in the interim Budget to Rs. 8,616 crore in 1991-92 from Rs. 9,550 crore in 1990-91 is further printed to an estimated Rs. 7,824 crore. This implies a saving of Rs. 792 crore over the provision made in the interim Budget but represents a large cut of Rs. 1,726 crore over the level in 1990-91. Consequent upon the adjustments in the exchange rate and the expansion of the Replenishment Licensing System, the export subsidy has been reduced to Rs. 1,224 crore in 1991-92 from Rs. 2,700 crore in 1990-91 representing a cut of the order of Rs. 1,476 crore in the current year. In the case of fertilisers, there would be an increase of 40 per cent on an average, in the price of all fertilisers other than low analysis ones which have been freed from price and movement controls. Subsequently, it was announced in Parliament that the increase in fertilizer prices would be scaled down from 40 per cent to 30 per cent resulting in a reduction in the budgeted saving from Rs. 1,800 crore to Rs. 1,350 crore. Besides, the small and marginal farmers would be exempted from this price increase, thus imposing an additional estimated burden of Rs. 450 crore during 1991-92. While the Government has proposed to abolish the subsidy for sugar (amounting to Rs. 350 crore), it has stepped up the provision for food subsidy to Rs. 2,600 crore for the current year as compared with Rs. 1,800 crore provided in the interim budget and Rs. 2,450 crore allocated for 1990-91. The budget has also proposed reduction in the non-Plan expenditure on other non-essential items, such as, non-Plan grants to State and Union Territories and Foreign Governments, non-Plan loans to public enterprises and other non-Plan capital outlay. As a result, without taking into account the provision for interest payments, defence and major subsidies, total non-Plan expenditure would come down to Rs. 28,073 crore in 1991-92 reflecting a reduction of Rs. 1,538 crore from Rs. 29,611 crore in 1990-91. Moreover, as said earlier, the Budget has not made any separate provision for the payment of additional dearness allowance that may become payable during the course of the current year. As a result of these adjustment programmes in the sphere of expenditure, total non-Plan expenditure, excluding interest payments, will come down to Rs. 52,247 crore in 1991-92 from Rs. 54,911 crore, implying a decrease of 4.9 per cent over the last year. Nevertheless, interest payments, defence and subsidies taken together would still account for 68.0 per cent of the total non-Plan expenditure in 1991-92 as against 64.8 per cent in 1990-91.

#### Budget Proposals

8.22 A major thrust of the fiscal adjustment has been placed on the additional resource mobilisation to the extent of Rs. 2,617 crore in 1991-92. Such a resource mobilisation attempt is to come about by reversing the declining trend in the contribution of direct taxes to total tax revenue, curbing conspicuous consumption, subjecting affluent sections of society to increasing tax burden and by providing liberal tax treatment to commodities of essential consumption. Some of the important features of the budget proposals in the sphere of direct taxes are a hike in the corporate tax rate by 5 percentage points, lowering the general rate of depreciation for plant and machinery to 25 per cent from 33.3 per cent, the revival of interest-tax on gross interest income of banks and financial institutions with the rate fixed at 3 per cent and the extension of expenditure tax base. Changes in indirect tax structure proposed include; increase in the rate of special excise duty by 5 per cent, upward revision in duty rates for certain luxury items, reduction in ad valorem rate of basic plus auxiliary customs duties to a maximum of 150 per cent, etc. The details of the revenue impact of the ARM measures are given in the table below :

(Rupees crore)

Tax Head	Budget Proposals	States Share	Net to Centre
1. Corporate Tax	1,304	..	1,304
2. Income Tax	125	97	28
3. Interest Tax	535	..	535
4. Expenditure Tax	150	..	150
5. Wealth Tax	25	..	25
6. Customs	510	..	510
7. Union Excise Duties	988	515	473
Total	2,617	612	2,005

8.23 Apart from this, in the area of administered prices, the prices of motor spirit, domestic LPG and aviation turbine fuel is proposed to be increased alongwith some petroleum products, while there will be a reduction in the prices of kerosene for non-industrial use from that prevailing since October 1990.

#### State Budgets 1991-92

8.24 The combined budgetary position of 25 States, of which 10 States presented Vote-on-Account Budgets, in February/March 1991, suggests that, at 1990-91 rate of taxation, the consolidated State Budgets are estimated to result in an overall (conventional) deficit of Rs. 2,164 crore in 1991-92 as compared with Rs. 578 crore (RE) in 1990-91 and Rs. 127 crore in 1989-90. The Additional Resource Mobilisation (ARM) measures envisaged by 7 States would net Rs. 93 crore as against the additional resource mobilized by 17 States at Rs. 772 crore in 1990-91. The States' share in the Centre's new tax proposals as per the regular Union Budget for 1991-92 is placed at Rs. 612 crore. The overall deficit adjusted to the ARM and States' share in the Centre's additional tax proposals would be Rs. 1,459 crore. A few States have committed to go in for ARM measures at the time of their regular budgets, while others are hopeful of bridging the deficit by way of greater control over non-Plan, non-developmental expenditure, such as, impounding of dearness allowance to Government employees, additional mobilisation of small savings, checking tax evasion, rationalisation and efficient management of the existing tax structure and additional Central assistance.

#### Broader Concept of Budget Deficit and States

8.25 As in the case of the Central Government, the overall resource gap in the budgetary operations of the States had increased manifold during the last decade. While the

absolute levels of the gross fiscal deficit of the States, doubled during the first half of the 'eighties from Rs. 3,712 crore in 1980-81 to Rs. 7,5200 crore in 1985-86, its growth in the latter half was faster at 158 per cent and stood at Rs. 19,404 crore in 1990-91. It is budgeted to increase to Rs. 20,567 crore or by 6.0 per cent in 1991-92 over the previous year (Table 8.6 and Graph E). Correspondingly, gross fiscal deficit of the States as a percentage of GDP increased from 2.7 per cent in 1980-81 to 2.9 per cent in 1985-86 and further to 3.7 per cent in 1990-91.

8.26 The growth in the size of the overall resource gap of the States and its adverse implications on their finances must be reckoned with the State Governments operation in the revenue account which suffered a distinct deterioration during the second half of the 'eighties. The combined overall revenue account of States, which was, by and large, showing surplus till 1986-87, turned into a deficit in the following year and since then, the magnitude of revenue deficit has been growing at a rapid pace which is required to be financed from capital resources. In 1991-92, the revenue deficit budgeted at Rs. 4,573 crore accounts for 22.2 per cent of the gross fiscal deficit of States in that year.

8.27 The financing pattern of the States' resource gap revealed that on an average, half of the gap was financed through loans from the Central Government, while the remaining half was met through market borrowings, State provident funds and others (Table 8.7).

#### Consolidated Budgetary Position : Centre and States

8.28 The combined overall deficit in 1991-92 after taking into account the yield from additional resource mobilisation measures is placed at Rs. 9,178 crore showing a reduction of 19.1 per cent over the deficit of Rs. 11,350 crore in the revised estimates of 1990-91 (Table 8.8). However, this deficit may undergo some revision after 10 States have presented their regular Budgets.

8.29 Aggregate receipts of the Centre and States, at the revised rates of taxes and duties, estimated at Rs. 1,77,084 crore in 1991-92 would be higher by 11.9 per cent as against 15.8 per cent rise recorded in the previous year. Both revenue and capital receipts are expected to show increases over their respective levels in 1990-91. The anticipated decline of 1 percentage point in the Centre's net capital receipts has caused the overall capital receipts to increase by 2.6 per cent as compared with an impressive increase of 26.5 per cent in 1990-91. The overall decline in net capital receipts of the Centre is because of some of the structural adjustments proposed in the Budget for 1991-92 such as, the lower provision of net market borrowings, and external assistance and a decline in other capital receipts.

Table 8.6: Monetised, Budget, Revenue, Gross and Net Fiscal Deficit of States

(Rupees crore-)

Year	Gross Fiscal Deficit	Net Fiscal Deficit	Monetised Deficit*	Conventional Deficit	Revenue Deficit	Gross Fiscal Deficit as percentage of GDP at current market price
1	2	3	4	5	6	7
1980-81	3712	1714	487	897	+1486	2.7
1981-82	4062	2209	789	1020	+1379	2.5
1982-83	4986	2830	+860	820	+888	2.8
1983-84	6359	4067	38	561	+211	3.1
1984-85	8199	5834	1486	1438	924	3.5
1985-86	7520	4799	+1862	+1688	+654	2.9
1986-87	9269	6107	516	667	+169	3.2
1987-88	11219	7742	+157	66	1088	3.4
1988-89	11672	8884	425	+380	1807	3.0
1989-90	15359	11547	255	127	3580	3.5
1990-91(RE)	19404	14661	419	578	5308	3.7
1991-92(BE)	20567	15093	N.A	1549	4573	—

\*+ indicates Surplus

\*Data pertains to 23 States having accounts with Reserve Bank of India.

Table 8.7 : Financing of States' Gross Fiscal Deficit

Year	Loans from the Centre (net)	Market Borrowings (net)	Others	Gross Fiscal Deficit (2+3+4)	(Rupees crores)		
					States' Outstanding Liabilities \$ (end-yea )		
					Total	of which:	
						Loans & Advances from Central Government	Market Loans
1	2	3	4	5	6	7	8
1980-81	1564	184	1964	3712	23977	17071	2973
	42.1	5.0	52.9	100.0			
1981-82	2000	339	1723	4062	27729	19080	3328
	49.2	8.4	42.4	100.00			
1982-83	2735	393	1858	4986	29457	20425@	3735
	54.9	7.9	37.2	100.0			
1983-84	3031	563	2765	6539	38493	27539@	4408
	47.7	8.8	43.5	100.0			
1984-85	3580	693	3926	8199	44394	31226	5111
	43.7	8.4	47.9	100.0			
1985-86	5757	1010	753	7520	51113	36984@	6110
	76.6	13.4	10.0	100.0			
1986-87	4786	1147	3336	9269	57912	41770	7257
	51.6	12.4	36.0	100.0			
1987-88	5832	1523	3864	11219	67162	47602	8779
	52.0	13.6	34.4	100.0			
1988-89	6688	1973	3011	11672	78184	54292	10712
	57.3	16.9	25.8	100.0			
1989-90	7917	1869	5573	15359	91597*	62557*	12902*
	51.5	12.2	36.3	100.0			
1990-91*	10318	2341	6745	19404	106481a	72091a	15830@
	53.2	12.1	34.7	100.0			
1991-92@	11297	2205	7065	20567	N.A.	N.A.	N.A
	54.9	10.7	34.4	100.0			

\$ These include internal debt, loans and advances from the Central Government and provident funds etc.

\* Revised Estimates. a Budget Estimates N.A. = No Available.

@ Includes medium term loans of Rs. 1743 crores in 1982-83, Rs. 400 crores in 1983-84 and Rs. 1628 crore in 1985-86 given by the Centre to States to clear their overdrafts.

Notes (1) Figures in decimal are percentages to the total.

Table 8.8: Combined Receipts and Disbursements of Central and State Governments Fiscal Years 1989-90 to 1991-92

Items	(Rupees crore)					
	1989-90 (Accounts)	1990-91 (Budget Estimates)	1990-91 (Revised Estimates)	1991-92* (Budget Estimates)	Percentage Variations	
					Col. 4 over Col. 2	Col. 5 over Col. 4
1	2	3	4	5	6	7
I. Total Receipts	136714	154571	158309	177094	15.8	11.9
A. Revenue Receipts	97950	109111	109260	126781	11.5	16.0
of which:						
Tax Receipts (a+b)	77441	89285	89107	103323	15.1	16.0
(a) Direct Taxes	13025	14793	15507	17829	19.1	15.0
(b) Indirect Taxes	64416	74492	73600	85494	14.3	16.2
B. Capital Receipts	38764	45460	49049	50313	26.5	2.6
II. Total Disbursements (A+B+C)	147433	163514	169659	186272	15.1	9.8

A. Developmental Expenditure (a+b+c)	88418	96153	100713	104960	13.9	4.2
(a) Revenue	63155	69947	72536	75976	14.9	4.7
(b) Capital Outlay	15127	16585	16712	17608	10.5	4.5
(c) Loans and Advances	10136	9621	11465	11376	13.1	-0.8
B. Non-Developmental Expenditure (a+b+c)	55089	62889	64455	74435	17.0	15.5
(a) Revenue	49735	57218	58815	68304	18.3	16.1
(b) Capital	4648	5349	5263	5750	13.2	9.3
(c) Loans and Advances	706	322	377	381	-46.6	1.1
C. Others	3926	4472	4491	6877	14.4	53.1
III. Overall Surplus (+)/Deficit(-)	-10719	-8943	-11350	-9178		

\*Includes effect of budget proposals.

- Note :** 1. Data relates to 25 States, of which 10 are from Vote-on-Account Budgets and the remaining 15 are from Final Budgets Further, data in respect of Nagaland, Bihar and Jammu and Kashmir for the year 1989-90 are Revised Estimates.
2. Other disbursements comprise discharge of internal and external debt, compensation and assignments to local bodies and Panchayati Raj Institutions, appropriation to contingency funds and net remittances and are adjusted for difference in figures of repayments of loans by States to the Central Government given in their respective budgets.

#### Disbursements; Developmental and Non-Developmental

8.30 Aggregate disbursements of the Centre and States placed at Rs. 1,86,272 crore in 1991-92, would grow by 9.8 per cent as compared with the rise of 15.1 per cent in 1990-91. While non-developmental expenditures are budgeted to increase by 15.5 per cent in 1991-92 on top of an increase of 17.0 per cent in 1990-91, the growth in developmental expenditures would come down significantly from 13.9 per cent to 4.2 per cent. Consequently, the share of non-developmental expenditures of the Centre and States in their aggregate disbursements would move up to 40.0 per cent in 1991-92 from 38.0 per cent in 1990-91, and that of developmental expenditure would slip down to 56.3 per cent from 59.4 per cent in the corresponding period. These shares were 66 per cent and 30.6 per cent, respectively for developmental and non-developmental expenditure in 1980-81, thus representing a sharp deterioration in the Government's expenditure pattern over the last decade (Table 8.9). The growth of direct and indirect taxes of the Centre and States is presented in Table 8.10.

#### Market Borrowings

8.31 Table 8.11 sets out the progress in market borrowings of the Central and State Governments, as also by the local authorities and institutions sponsored by them. Of the Centre's gross market borrowings of Rs. 8,989 crore, cash subscriptions accounted for Rs. 8,531 crore and conversion of maturing loans for Rs. 458 crore. In respect of the State Governments, there were no maturing loans in 1990-91.

8.32 In its Budget for 1991-92, the Centre has estimated gross market borrowings of Rs. 8,918 crore, which after making a provision of Rs. 1,418 crore for repayment of maturing loans, would net an amount of Rs. 7,500 crore, that is, lower by Rs. 501 crore (6.3 per cent) over that in 1990-91.

#### Coupon Rates on Central Government Loans

8.33 During 1990-91, the structure of coupon rates on Central Government loans was changed, with a telescoping of the rates within the maximum coupon rate of 11.50 per cent. The revised rates are as under :

Maturity (years)	1989-90 (p r cent)	1990-91 (per cent)
5	10.00*	10.50
10	10.50	10.75
15	11.00	11.25
20	11.50	11.50

\*The 5 year's maturity was not issued in 1989-90.

**Table 8.9: Developmental and Non-Development Expenditure of Centre and States**

(Rupees crore)

Year	Centre's			States'			Centre and States (Combined)				
	Develop- mental Expendi- ture	Non- Develop- mental Expendi- diture	Total @	Develop- mental Expendi- diture	Non- Develop- ment Expen- diture	Others*	Total	Develop- mental Expendi- diture	Non- Develop- mental Expendi- diture	Others**	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1980-81	13923 (57.6)	10245 (42.4)	24177 (100.0)	15961 (70.1)	4289 (18.8)	2520 (11.1)	22770 (100.0)	25845 (66.0)	11977 (30.6)	1338 (3.4)	39160 (100.0)
1981-82	16084 (60.9)	10331 (39.1)	26415 (100.0)	17960 (70.2)	4996 (19.6)	2615 (10.2)	25571 (100.0)	28796 (64.7)	13609 (30.6)	2074 (4.7)	44479 (100.0)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1982-83	19557 (60.7)	12673 (39.3)	32230 (100.0)	20649 (71.0)	5883 (20.2)	2565 (8.8)	29097 (100.0)	33643 (64.6)	16473 (31.7)	1941 (3.7)	52057 (100.0)
1983-84	22207 (58.8)	15564 (41.2)	37771 (100.0)	23972 (71.2)	6882 (20.4)	2814 (8.4)	33668 (100.0)	38352 (63.9)	19936 (33.3)	1701 (2.8)	59989 (100.0)
1984-85	27375 (59.6)	18525 (40.4)	45900 (100.0)	27958 (70.3)	8340 (21.0)	3448 (8.7)	39746 (100.0)	46265 (64.6)	23390 (32.6)	1999 (2.8)	71654 (100.0)
1985-86	22979 (58.9)	20927 (41.1)	50906 (100.0)	31733 (70.7)	9617 (21.4)	3519 (7.9)	44869 (100.0)	55032 (65.1)	27332 (32.4)	2106 (2.5)	84470 (100.0)
1986-87	35498 (57.7)	26060 (42.3)	61558 (100.0)	36827 (70.6)	11220 (21.5)	4149 (7.9)	52196 (100.0)	64441 (63.4)	33682 (33.2)	3479 (3.4)	101602 (100.0)
1987-88	36573 (54.7)	30261 (45.3)	66834 (100.0)	42141 (70.2)	13754 (22.9)	4104 (6.9)	59999 (100.0)	69087 (62.2)	39460 (35.5)	2614 (2.3)	11116 (100.0)
1988-89	41536 (53.9)	35579 (46.1)	77055 (100.0)	47064 (69.8)	15803 (24.4)	4599 (6.8)	67466 (100.0)	78983 (61.6)	45940 (35.8)	3322 (2.6)	128245 (100.0)
1989-90\$	53639 (56.3)	41585 (43.7)	95224 (100.0)	52555 (68.5)	19761 (25.8)	4393 (5.7)	76709 (100.0)	88418 (60.0)	55089 (37.4)	3926 (2.6)	147433 (100.0)
1990-91 (RE)\$	60257 (55.1)	49128 (44.9)	109385 (100.0)	64487 (69.5)	23336 (25.1)	5042 (5.4)	92865 (100.0)	100713 (59.4)	64455 (38.0)	4491 (2.6)	169659 (100.0)
1991-92 (BE)\$	62015 (53.1)	54748 (46.9)	116763 (100.0)	69896 (67.4)	28616 (27.6)	5197 (5.0)	103709 (100.00)	104960 (56.3)	74435 (40.0)	6877 (3.7)	186272 (100.0)

@ Exclude discharge of internal and external debt.

\$ Data relates to 25 States, of which 10 are from Vote-on-Account and the remaining 15 are from Final Budgets. Further, data in respect of Nagaland, Bihar and Jammu and Kashmir for the year 1989-90 are Revised Estimates Developmental and No n-Developmental expenditures in the case of Centre for 1989-90 are tentative.

\* Comprise discharge of internal debt, repayment of loans to the Centre, appropriation for contingency fund and remittances (net) compensation and assignments to Local Bodies and Panchayat Raj institutions.

\$\$ Comprised discharge of internal and external debt, compensation and assignment to Local Bodies and Panchayat Raj institutions appropriation for contingency funds, net remittances of State Governments and are adjusted for differences in the figures of loan by the State Government to the Government given in their respective budgets.

Note: (1) Figures in brackets represent percentages to respective total expenditure.

(2) Figures for the Centre and States do not add up to the combined position due to inter-Governmental adjustments.

(3) The figures for Centre's expenditure prior to 1989-90 do not take into account capital expenditure on Railways and loans to States against small savings collections.

Table 8.10 : Direct and Indirect Tax Revenues of the Centre and States

(Rupees crore)

Year	Centre (Gros)			States +			Combined		
	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total	Direct	Indirect	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1980-81	2907	10242	13149	686	5929	6615	3593	16171	19764
(a)	22.1	77.9	100.0	10.4	89.6	100.0	18.2	81.8	100.0
(b)	2.1	7.5	9.6	0.5	4.4	4.9	2.6	11.9	14.5
1984-85	4626	18802	23428	1230	1108	12338	5856	29910	35766
(a)	19.7	80.3	100.0	10.0	90.0	100.0	16.4	83.6	100.0
(b)	2.0	8.1	10.1	0.5	4.8	5.3	2.5	12.9	15.4
1985-86	5563	23109	28672	1401	12919	14320	6964	36028	42992
(a)	19.4	80.6	100.0	9.8	90.2	100.0	16.2	83.8	100.0
(b)	2.1	8.8	10.9	0.5	4.9	5.4	2.7	13.7	16.4
1986-87	6234	26559	32793	1685	14934	16619	7919	41493	49412
(a)	19.0	81.0	100.0	10.1	89.9	100.0	16.0	84.0	100.0
(b)	2.1	9.1	11.2	0.6	5.1	5.7	2.7	14.2	16.9

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1987-88	6751	30861	37612	1960	17438	19398	8711	48299	57010
(a)	17.9	82.1	100.0	10.1	89.9	100.0	15.3	84.7	100.0
(b)	2.0	9.3	11.3	0.6	5.2	5.8	2.6	14.6	17.1
1988-89	8824	35596	44420	2413	19988	22401	11237	55584	66821
(a)	19.9	80.1	100.0	10.8	89.2	100.0	16.8	83.2	100.0
(b)	2.2	9.0	11.2	0.6	5.1	5.7	2.8	14.1	16.9
1989-90*	10003	41578	51581	3022	22838	25860	13025	64416	77441
(a)	19.4	80.6	100.0	11.7	88.3	100.0	16.8	83.2	100.0
(b)	2.2	9.4	11.6	0.7	5.2	5.8	2.9	14.6	17.5
1990-91 (RE)*	12180	46673	58853	3327	26927	30254	15507	73600	89107
(a)	20.7	79.3	100.0	11.0	89.0	100.0	17.4	82.6	100.0
(b)	2.3	9.0	11.3	0.6	5.2	5.8	3.0	14.2	17.2
1991-92 (BE)*	13892	54863	68755	3937	30631	34568	17829	85494	103323
(a)	20.2	79.8	100.0	11.4	88.6	100.0	17.3	82.7	100.0
(b)	2.4	9.4	11.8	0.7	5.3	6.0	3.1	14.7	17.8

+ Excluding State's share in central taxes as reported in Central budget documents

\* Regarding State Government, data relating to 10 States are from Vote-on-Account Budget, while those relating remaining 15 states are from Final Budget. Further, data in respect of Nagaland, Bihar and Jammu and Kashmir for the year 1989-90 are revised estimates.

Note: (a) Represents percentages to total tax revenue, and  
(b) Indicates tax to GDP ratio in percentages.

Table 8.11: Market borrowing of Central and State Government, Local Authorities and Institutions sponsored by Central and State Governments—1989-90 and 1990-91 (Fiscal Year)\*

(Rs. crores)

Government/Authority	Gross Market		Repayments		Net Market Borrowings	
	Borrowings		Total Maturities)			
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
1. Central Government	8,044	8,989	639	988	7,405	8,001
2. State Governments	2,555	2,569	306	0	2,249	2,569
3. Institutions Sponsored by Central Government	2,622	2,443	457	14	2,165	2,429
4. Institutions Sponsored by State Governments (including Local Authorities)	1,519	1,195	416	96	1,103	1,099
5. Aggregate Market Borrowings	14,740	15,196	1,818	1,098	12,922	14,098

\*Actuals as per R.B.I. records.

#### Reserve Bank Support to Central Loans

8.34 The Reserve Bank's initial subscription to the Central Government loans during 1990-91 amounted to Rs. 4,432 crore or 49.3 per cent of the total loans floated, which was substantially lower than its initial subscription of Rs. 4,861 crore (60.4 per cent of the total) in the previous year. During 1990-91, the Reserve Bank sold through its open market operations a portion of its securities initially acquired by it. The Reserve Bank's holding of Central Government dated securities increased by Rs. 3,261 crore as against an increase of Rs. 3,106 crore in 1989-90. The holdings of Central Government dated securities by institutions under the buy-back arrangements with the Reserve Bank declined by Rs. 406 crore in 1990-91 in contrast to an increase of Rs. 197 crore during 1989-90. During the year, the Central Government issued to the Reserve Bank special securities worth

Rs. 30,220 crore of which Rs. 30,000 crore were towards the funding of ad hoc Treasury bills. The funding of ad hoc Treasury bills was last undertaken in 1987-88 for Rs. 17,500 crore.

#### Internal Debt and Other Liabilities

8.35 Taking into account resources mobilised through other instruments such as small savings and provident funds, the net addition to the outstanding internal debt and other liabilities of the Centre and the States amounted to Rs. 45,029 crore, thus rising from Rs. 40,972 crore in 1989-90.

#### Bonds of Public Sector Undertakings

8.36 A number of Central public sector undertakings also raised resources through the issue of bonds/debentures in

the domestic market and external commercial borrowings/suppliers credit abroad for financing their Annual Plan in 1990-91. As per the Union Budget for 1991-92, these public sector undertakings would mobilise Rs. 5,859 crore through the issue of bonds in the domestic market and Rs. 2,001 crore through external commercial borrowings as compared with Rs. 4,933 crore and Rs. 2,553 crore raised, respectively, in 1990-91.

#### Ways and Means Advances from Reserve Bank of India and Over-drafts of States

8.37 Ways and Means Advances (WMAs) provided by the Reserve Bank to 23 States to tide over temporary gaps in their cash flows remained unchanged at Rs. 744.8 crore. Likewise, the special WMAs given to these States against the pledge of Central Government securities also remained unaltered at Rs. 266 crore.

8.38 During 1990-91, all State Governments complied with the Overdraft Regulation Scheme, 1985, under which any overdrafts have to be cleared within the stipulated period of seven working days.

#### 9. FINANCIAL INSTITUTIONS AND CAPITAL MARKET

9.1 The rapid changes witnessed in the Indian financial system in recent years emphasise the vastly diversified roles of financial institutions in the process of financial intermediation. Banks have strengthened their association with the capital market. The structural changes in the economy are reflected in many inter-related features such as, changes in the financing pattern of big-size companies with preference for long-term loan and equity capital, the emergence of a sophisticated and risk-bearing saving class with preference for alternative avenues of saving with greater risk and higher yield, and a quantum jump, as also a qualitative change, in the operations of primary as well as secondary capital market. The Reserve Bank apart from monitoring and regulating the process of transformation, has been playing a crucial role by putting in place a liberal and conducive policy regime and by rendering cautious and well-modulated financial support to financial institutions and commercial/co-operative banks.

##### Financial Institutions

9.2 Mention was made in the last year's Report about the significant changes in recent years in the process of financial intermediation in the country, the role of financial institutions in this process, the inter-institutional linkages, and provision of substantial concessive support from the Reserve Bank to financial institutions.

9.3 The combined balance sheet of all banks and financial institutions shows that the share of financial institutions in total assets increased from 32.2 per cent at the end of March 1989 to 33.2 per cent at the end of March 1990 (Table 9.1). As at the end of March 1990, while the financial assets of banks stood at Rs. 2,05,515 crore, those of financial institutions stood at Rs. 1,02,184 crore (Tables 9.1 and 9.2). At the same point of time, outstanding loans and advances of financial institutions were equivalent to about 47 per cent of outstanding credit of commercial banks. Investments of financial institutions in Government securities, in bonds and debentures of public sector undertakings and in private corporate sector equities and debentures were equivalent to about 49 per cent of such investments of commercial banks. While the increase during 1989-90 in outstanding loans and

advances of all financial institutions (including NABARD) was Rs. 6,173 crore, that in the case of commercial banks was about Rs. 16,737 crore. As pointed out in last year's Report, while these figures are not strictly comparable because of some financial flows between financial institutions and banks, they do give some idea about the dimension of the operations of the banks and the financial institutions.

9.4 It would be pertinent to note here that the country's financial structure is itself undergoing a further process of widening and diversification. A number of financial institutions designed to cater to specific needs of certain sectors such as, the railways, power, transport, housing, etc. have also been set up in recent years. Some of these have been mobilising resources through issue of bonds or debentures. Besides, a number of non-bank financial companies are now mobilising a part of the household sector's savings and are providing a variety of financial services. The subsidiaries floated by banks have entered into activities such as mutual funds, leasing, venture capital, housing finance, and factoring. The mutual funds of five bank subsidiaries have raised significant amounts during 1990-91 from the public through various schemes, including equity-linked savings schemes with substantial tax concessions.

9.5 A major source of resources for the financial institutions has been the Reserve Bank of India's financial assistance through its long-term operations (LTO) funds, as well as through short-term limits (Table 9.3). The total outstanding under all LTO funds stood at Rs. 9,465 crore as at end of June 1991. Besides this, the Reserve Bank's claims on commercial and co-operative banks have increased from Rs. 2,810 crore as at the end of March 1990 to Rs. 3,999 crore at the end of March 1991. The Small-Scale Industries Development Bank of India (SIDBI) like other all-India term-lending institutions, is now eligible to borrow short and long-term funds from the Reserve Bank under Sections 17 and 46 of the Reserve Bank of India Act, 1934, which have since been amended suitably to make it possible for the latter to render such assistance. During 1990-91, (July-June) SIDBI was sanctioned a long-term loan of Rs. 400 crore out of the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund for utilisation during the year repayable after 15 years at a concessive rate of 6 per cent per annum. SIDBI fully availed of the limit and its outstanding borrowings from NIC (LTO) Fund till date amounts to Rs. 400 crore. In addition, two separate limits of Rs. 300 crore each of short durations aggregating Rs. 600 crore were sanctioned to SIDBI during the year. However, SIDBI utilised only Rs. 75 crore of the first limit of Rs. 300 crore until the end of June 1991.

##### Assistance by Financial Institutions during 1990-91

9.6 During the financial year 1990-91, the assistance sanctioned (provisional) by All Financial Institutions (AFIs\*) at Rs. 19,917.1 crore showed an increase of Rs. 4,269.8 crore or 27.3 per cent over the previous year (Rs. 15,647.3 crore). Disbursements by these institutions during 1990-91 aggregating Rs. 12,369.1 crore recorded an increase of Rs. 2,335.2 crore or 23.3 per cent over the previous year's disbursements of Rs. 10,033.9 crore (Table 9.4).

9.7 The total amount of assistance sanctioned (provisional) by the all-India financial institutions during the financial year 1990-91 at Rs. 19,414.5 crore was higher by 27.9 per cent than those of Rs. 15,179.7 crore sanctioned in the preceding year. Likewise, disbursements by these institutions for the same period at Rs. 11,863.6 crore also recorded an increase of 27.9 per cent as compared with Rs. 9,274.8 crore disbursed in 1989-90.

\*All Financial Institutions (AFIs) include All-India Financial Institutions (IDBI, IFCI, ICICI, SIDBI, TFCI, SCICI, IRBI, UTI, LIC and GIC and its subsidiaries) and 18 SFCs and 26 SIDCs.

**Table 9 1 : Financial Assets of Financial Institutions and Banks**  
as at the end of last Friday of March

(Rupees crore)						
Institution Category	1981	1986	1987	1988	1989	1990
I	2	3	4	5	6	7
1. Banks (1+2+3)*	46,987	1,03,372	1,27,876	1,47,186	1,76,461	2,05,515
1. All Scheduled Commercial Banks**	44,622	1,03,627	1,22,513	1,40,747	1,68,480	1,96,377
2. Non-Scheduled Commercial Banks***	9	23	30	36	53	62
Total Commercial Banks (1+2)	44,631	1,03,650	1,22,543	1,40,783	1,68,533	1,96,439
3. State Co-operative Banks**	2,356	4,722	5,333	6,403	7,928	9,076
II. Financial Institutions	16,650	45,907	54,470	66,828	83,651	1,02,184
4. Term-lending Institutions% (All-India)	6,143	21,555	25,674	31,239	37,874	44,941@
5. State Level Institutions	1,733	4,341	5,290	6,241	7,204	7,899
6. Investment Institutions¶	8,534	19,143	22,475	28,037	36,980	47,694
7. Other Institutions@@	240	868	1,031	1,311	1,593	1,650
III. Aggregate (I+II)	63,637	1,54,279	1,82,346	2,14,014	2,60,112	3,07,699
IV. Percentage Share:						
(a) I to III	73.8	70.2	70.1	68.8	67.8	66.8
(b) II to III	26.2	29.8	29.9	31.2	32.2	33.2

\*Include the following items : (i) Cash in hand and balances with the Reserve Bank, (ii) Asset with the Banking System, (iii) Investments, (iv) Bank Credit (Total loans, cash-credits and overdrafts and bills purchased and discounted) and dues from banks.

\*\*As per returns under Sec. 42 of the RBI Act, 1934.

\*\*\*As per returns under Sec. 27 of the Banking Regulation Act, 1949.

%Term-lending Institutions include NABARD, ICICI, IDBI, IFCI, IRBI and Exim Bank.

¶Investment Institutions include UTI, LIC and GIC & Subsidiaries.

@Includes NHB.

@@Other Institutions include DICGC & ECGC.

Table 9.2 : Financial Institutions : Total Outstanding Financial Assets

Institution	(Rupees crore)					
	1980-81	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. All-India Term</b>						
Lending Institutions						
1. IDBI	3098.6	9633.9	11529.6	13922.3	17053.9	20317.9
2. NABARD@	1635.1	6568.6	7445.4	8776.4	10363.8	11771.7
3. ICICI	727.9	2210.6	2799.4	3652.8	4500.1	5603.9
4. IFCI	589.1	1988.3	2426.7	3105.7	3707.3	4477.6
5. Exim Bank	—	811.1	1042.2	1276.0	1478.4	1715.9
6. IRBI	92.4	342.3	430.2	505.6	589.8	694.0
7. NHB	—	—	—	—	181.1	360.3
Total of A (1 to 7)	6143.1	21554.8	25673.5	31238.8	37874.4	44941.31
<b>B. State Level Institutions</b>						
8. SFCs	1073.6	2696.7	3264.9	3910.9	4657.0	5494.2
9. SIDCs	659.5	1443.9	2024.6	2329.6	2547.2	2404.9
Total of B (8 to 9)	1733.1	4340.6	5289.5	6240.5	7204.2	7899.1
<b>C. Investment Institutions</b>						
10. LIC	5814.9	12935.9	14225.2	17086.9	20118.0	23988.4
11. GIC & Subsidiaries	1198.9	2860.7	3323.0	3735.5	4418.8	5284.6
12. UTI	520.6	3346.3	4927.3	7214.6	12443.1	18421.2
Total of C (10 to 12)	8534.4	19142.9	22475.5	28037.0	36979.9	47694.2
<b>D. Other Institutions</b>						
13. DICGC	200.3	781.6	919.6	1168.9	1377.5	1423.1
14. FCGC	39.5	86.9	112.0	142.3	215.3	226.9
Total of D (13 to 14)	239.8	868.5	1031.1	1311.2	1592.8	1650.0
Grand Total (A+B+C+D)	16650.4	45906.8	54469.6	66827.5	83651.3	102184.6

@ Figures relating to 1980-81 are pertaining to ARDC as NABARD was formed only during 1982.

Table 9.3: RBI Assistance—LTO Funds, Profit Allocation and Medium/Short-term Credit to Financial Institute

(Rupees Crore)

	1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91	
	Sanc- tioned for the year	Out- standing/ cumula- tive at end June	Sanc- tioned for the year	Out- standing/ cumula- tive at end June	Sanc- tioned for the year	Out- standing/ cumula- tive at end June	Sanc- tioned for the year	Out- standing/ cumula- tive at end June	Sanc- tioned for the year	Out- standing/ cumula- tive at end June
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>A. Long-term</b>										
Assistance from:										
<b>I. NIC (LTO)</b>										
Fund										
1. I.D.B.I.	330.0	2,875.3	360.0	3,198.6	375.0	3,528.3	375.0	3,822.0	—	3,705.2
2. Exim Bank	85.0	345.0	90.0	435.0	95.0	530.0	95.0	625.0	120.0	745.0
3. I.R.B.I.	15.0	25.0	20.0	45.0	25.0	70.0	25.0	95.0	35.0	130.0
4. S.I.D.B.I.	—	—	—	—	—	—	—	—	400.0	400.0
<b>II. NHC (LTO)</b>										
Fund/NHB										
	—	—	—	—	50.0	50.0	25.0	75.0	50.0	125.0
<b>B. RBI Profit allo-</b>										
cation for the pur-										
pose of:										
<b>I. NRC (LTO)</b>										
Fund/NABARD										
	350.0	2,355.0	300.0	2,655.0	330.0	2,985.0	330.0	3,315.0	375.0	3,690.0
<b>II. NRC</b>										
(Stabilisation)										
Fund/NABARD										
	10.0	630.0	10.0	640.0	10.0	650.0	10.0	660.0	10.0	670.0
Total (A+B)		6,230.3		6,973.6		7,813.3		8,592.0		8,465.2
<b>C. Medium/Short-</b>										
term Credit										
Assistance by RBI										
1. I.D.B.I.	300.0	82.5	300.0	24.5	300.0	42.4	400.0	67.6	400.0	41.0
2. I.F.C.I.	15.0		15.0		30.0		40.0		50.0 @	
3. I.C.I.C.I.	20.0		25.0		25.0		30.0		33.0*	
4. S.F.Cs	55.2		65.4		82.9		88.0		98.2	
5. S.I.D.B.I.	—		—		—		—		300.0	10.6 @ (a)
									300.0	—
<b>D. General Line of</b>										
Credit-NABARD										
	1,400.0	949.7	1,950.9	1,416.8	2,700.0	2,777.7	3,350.0	2,858.4	3,350.0	3,322.4
Total (C+D)		1,032.2		1,441.3		2,320.1		2,926.0		3,374.0
<b>Grand total of out-</b>										
standings/cumulative										
assistance (A+B+C+D)										
		7,262.5		8,414.9		10,133.4		11,518.0		12,839.2

@ Sanctioned for Calendar year 1991 (subsequently the limit was raised to Rs. 60 crore).

\* sanctioned for 1990-91 (April—March).

@ (a) Provisional.

% Of the two limits only Rs. 75 crore from the first limit was availed of.

Table 9.4: Assistance by All-Financial Institutions (April—March)

(Rupees crore)

Institutions	1989-90		1990-91*	
	Sanctions	Disbursements	Sanctions	Disbursements
	2	3	4	5
A. All India Development Banks (1 to 6) @	12,936.5	7,418.3	16,101.6	9,603.2
(a) (ii)	(11,170.2)	(6,437.7)	(14,035.3)	(8,329.8)
1. IDBI	5,330.9	3,130.0	6,450.0	4,016.0
(ii) (a)	(4,664.2)	(2,823.8)	(5,569.9)	(3,483.8)
2. IFCI	2,294.9	1,121.8	2,965.1	1,574.9
3. ICICI	2,850.6	1,357.1	3,861.1	1,967.6
4. SIDBI	2,086.1	1,570.9	2,408.8	1,838.5
(a) (a)	(986.5)	(896.5)	(1,222.6)	(1,077.3)
5. TFCI	52.8	12.8	85.0	39.2
6. SCICI	321.2	225.7	331.6	167.0
B. Investment Institutions (7+8+9+)	2,096.6	1,715.4	3,078.2	2,106.5
7. UTI	1,307.2	1,080.6	2,077.2	1,532.7
8. LIC	578.2	455.2	688.1	427.4
9. GIC	211.2	179.6	312.9	146.4
C. Other Institutions	146.6	141.1	234.7	153.9
10. IRBI	146.6	141.1	234.7	153.9
D. Total Assistance by All India Financial Institutions. @	15,179.7	9,274.8	19,414.5	11,863.6
E. State Level Financial Institutions (11+12)	2,233.9	1,739.7	2,568.9	1,778.9
11. SFCs	1,543.6	1,190.2	1,870.1	1,260.1
12. SIDCs	690.3	549.5	698.8	518.8
F. Total Assistance by All Financial Institutions (A+B+C+D)@@	15,647.3	10,032.9	19,917.1	12,369.1

\* Provisional

@ Data are net of inter-institutional (all-India) flows.

@@ Data are net of inter-institutional (all-India and state level) flows.

Note: 1. Data have been adjusted for inter-institutional flows. This involves adjustment in regard to IDBI's and SIDBI's refinance to SFCs and SIDCs, seed capital assistance and resource support to other financial institutions by IDBI and LIC. SFCs and SIDC data for 1990-91 are estimated.

2. SIDBI commenced its operations from April 2, 1990 and the date for 1989-90 for SIDBI pertains to Small Industries Development Fund and National Equity Fund Schemes taken over by SIDBI from IDBI. Sanctions and Disbursements of SIDBI for 1990-91 exclude short-term bills of Rs. 415 crore.

3. TFCI commenced its operations from February 1, 1989.

Source: Respective Financial Institutions.

### Corporate Investment

9.8 The Reserve Bank's third study on annual forecast of investment of private corporate business sector, based on expected phasing of capital expenditures on all projects for which assistance has been sanctioned by IDBI, ICICI and IFCI, has estimated that capital expenditures aggregating Rs. 15,813 crore would have been incurred during 1990 denoting a rise of 44.0 per cent over the expected capital expenditure during 1989. Including the amounts expected to be disbursed under the institutions' Bills Rediscounting Scheme and the Technical Development Fund Scheme, the expected total capital expenditure during 1990 worked out to Rs. 16,372 crore, showing a rise of 16.9 per cent over the similar expenditure in 1989. When deflated by an appropriate deflator, the total investment (in real term) at 1980-81 prices shows a higher rise of 34.9 per cent in 1989 and 33.4 per cent in 1990. Industry-wise, 'metals and metal products' would account for the highest share of 26.2

per cent (107 projects) as against its share of 26.9 per cent (109 projects) during 1989. The chemicals and petrochemicals group ranked second with a share of 22.1 per cent (170 projects) in 1990 as against its share of 18.7 per cent (115 projects) in 1989. Textiles (other than jute) followed next with a share of 8.0 per cent in 1990 as compared with 15.0 per cent in 1989.

### Small Industries Development Bank of India (SIDBI)

9.9 Mention was made in the earlier Report about the setting up of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI) as a wholly owned subsidiary of IDBI under the Small Industries Development Bank of India Act 1989 which commenced its operations on April 2, 1990. With a view to ensuring larger flow of financial and non-financial assistance to small-scale sector, the immediate thrust of SIDBI was on: (i) initiating steps for technological upgradation and modernisation of existing units; (ii) expanding the

channels for marketing the products of SSI sector in domestic and overseas market; and (iii) promotion of employment-oriented industries especially in semi-urban areas to create more employment opportunities and thereby checking migration of population to urban and cosmopolitan areas. During the financial year 1990-91, the sanctions and disbursements by SIDBI amounted to Rs. 2,823.8 crore and Rs. 2,253.5 crore, respectively. The bulk of the assistance by SIDBI was in the form of refinance which accounted for 72.7 per cent of the total sanctions and 69.3 per cent of the total disbursements during the year.

9.10 In order to mitigate the difficulties faced by SSI units on account of delayed payments, SIDBI has decided to join the nodal banks identified by the Reserve Bank in promoting separate factoring companies. SIDBI has equity participation in SBI Factors and Commercial Services Private Limited set up by the State Bank of India. Recently SIDBI has also made a similar equity participation in Canbank, Factors Limited set up by Canara Bank. In addition SIDBI has introduced the scheme for financing establishment of marketing channels for the sale of SSI products for minimising delays in realisation of sales proceeds of their products.

#### Capital Market

9.11 Reflecting the ready response to a series of macro-economic imbalances accentuated by the Gulf crisis and depletion of the foreign exchange reserves, as also the uncertainties in the economy, the primary segment of the capital market witnessed a significant slowdown during 1990-91, mainly due to a fairly large decline in convertible debenture issues, as compared with the previous year. The overall public response to the new issues, however, continued to be encouraging.

9.12 Approvals (consents/acknowledgements including premium but excluding those for bonus shares) to both Government and non-Government companies during 1990-91 reached a peak level of Rs. 12,191 crore, which was higher by 4.2 per cent over the previous year's approval for Rs. 11,702 crore (Table 9.5). While approvals given to non-Government companies at Rs. 6,124 crore during 1990-

91 were lower by 19.1 per cent than those in the previous year (Rs. 7,567 crore), those to Government companies at Rs. 6,067 crore in 1990-91 were higher by as much as 46.7 per cent than in 1989-90 (Rs. 4,135 crore).

#### New Issue Market

9.13 As alluded to earlier, the new issue market witnessed a significant slowdown during 1990-91. Capital issues (including premium but excluding bonus issues) by non-Government public limited companies during 1990-91 at Rs. 4,201.8 crore (through 365 issues) registered a decline of 35.1 per cent as compared with the issues in 1989-90 of Rs. 6,473.1 crore through 408 issues (Table 9.6). Security-wise debenture issues were substantially lower at Rs. 2,941.0 crore registering a decline of Rs. 2,305.4 crore or 43.9 per cent over 1989-90. This decline was on account of convertible debentures which showed a decline of 51.9 per cent; non-convertible debenture issues registered an increase of 34.7 per cent. Equity shares at Rs. 1,247.5 crore witnessed a marginal increase of 2.4 per cent over 1989-90.

#### Public Sector Bonds

9.14 The issues of bonds by Public Sector Undertakings (PSUs) during 1990-91 at Rs. 5,463 crore (as per provisional data) recorded an increase of 46.5 per cent over the amount of bonds issued during the previous year (Rs. 3,729 crore). Of these, only Rs. 100 crore were offered to the public during both the years and the rest were privately placed.

#### Performance Analysis of New Issues

9.15 According to available data from the Bombay Stock Exchange (BSE), the overall public response to new issues (including public sector bonds) during 1990-91 continued to be reasonably encouraging. The number of issues which were subscribed more than 10 times accounted for 15.1 per cent of the present issue though it was lower as compared with 30 per cent in 1989-90. The BSE data indicate that the total amount offered for public subscription amounted to 45 per cent of the present issue as compared with 26 per cent in 1989-90.

**Table 9.5: Consents/Acknowledgements Granted by the Controller of Capital Issues to Government and Non-Government Companies for raising capital**

Sl. No.	Type of Issue	(Rupees crore)			
		1989-90		1990-91	
		(April	March)	(April	March)
		Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5	6
1. Shares(i+ii)		437	1,749	503	2,613
		(4)	(61)	(4)	(60)
	(i) Initial	189	906	233	1,282
		(-)	(-)	(2)	(30)
	(ii) Further*	248	843	270	1,331
		(4)	(61)	(2)	(30)
2. Debentures and Bonds(i+ii)		205	9,953	250	9,578
		(16)	(4,074)	(17)	(6,007)
	(i) Convertible	80	2,798	137	2,588
		(-)	(-)	(-)	(-)
	(ii) Non-convertible	125	7,154	113	6,990
		(16)	(4,074)	(17)	(6,007)
3. Sub-Total(1+2)		642	11,702	753	12,191
		(20)	(4,135)	(21)	(6,067)



1	2	3	4	5	6
4. Bonus Shares		319 (1)	374 (22)	352 (10)	441 (140)
5. Grand Total (3 + 4)		961 (21)	12,076 (4,157)	1,105 (31)	12,632 (6,207) -

\* Including Premium of Rs. 213 crore for 77 issues in 1989-90 and Rs. 274 crore for 62 issues in 1990-91.

Note: Figures in the brackets relate to approvals to Government Companies which are included in the respective totals.

Source: Controller of Capital Issues (CCI), Ministry of Finance, Government of India.

**Table 9.6 : Capital Issues by Non-Government Public Limited Companies**

Sl. No.	Type of Issue	(Rupees crore)			
		1989-90 <sup>1</sup> (April-March)		1990-91 <sup>2</sup> (April-March)	
		Number	Amount	Number	Amount
1	2	3	4	5	6
1. Equity Shares* (a + b)		268 (57)	1,218 (272.0)	248 (41)	1,247.5 (126.4)
	(a) Prospectus	143 (17)	734.1 (30.0)	105 (15)	963.5 (73.3)
	(b) Rights	125 (40)	484.7 (242.0)	143 (26)	284.0 (53.1)
2. Preference shares (a + b)		4	7.9	4	13.3
	(a) Prospectus	3	5.4	2	13.0
	(b) Rights	1	2.5	2	0.3
3. Debentures (a + b)		136	5,246.4	113	2,941.0
	(a) Prospectus	44	2,400.7	44	997.8
	(b) Rights Of which	92	2,845.7	69	1,943.2
	I. Convertible (a + b)	109	4,762.2	92	2,288.7
	(a) Prospectus	37	2,240.4	36	831.6
	(b) Rights	72	2,521.8	56	1,457.1
	II. Non-convertible (a + b)	27	484.2	21	652.3
	(a) Prospectus	7	160.3	8	166.2
	(b) Rights	20	323.9	13	486.1
4. Total (1 + 2 + 3)		408	6,473.1	365	4,201.8
	(a) Prospectus	190	3,140.2	151	1,974.3
	(b) Rights	218	3,332.9	214	2,227.5

@Provisional.

\* Exclude bonus issues.

Notes: (1) Figures in brackets indicate date in respect of premium on capital issues which are included in respective totals.

(2) Data exclude issues privately placed with financial institutions, etc.

(3) Data include amount of over-subscription retained in case where specific information was available. However, the amount of under-subscription was not taken into account as the information was not available.

Source: Prospectus/circulars/advertisements/letter of offer issued by companies; replies given by companies to the Reserve Bank questionnaires, information received/collected Stock Exchange Division of Ministry of Finance, Stock Exchanges, Press reports, hand-out, etc.

### Policy Developments During 1990-91

9.16 With a view to bringing transparency and openness, the Government of India released in July 1990 guidelines for valuation of shares and fixation of premia. This has been done to help the companies which are seeking consents from the Controller of Capital Issues (CCI) and also for the benefit of the investing public.

9.17 The Government of India notified "Factoring" as an eligible activity for banks to engage in under Section 6(1)(O) of the Banking Regulation Act, 1949, on July 2, 1990. The Reserve Bank has also issued guidelines which would cover the conduct of factoring business in India. The operations of the factoring subsidiaries will be covered by Section 19(2) of the Banking Regulation Act 1949. Following this, State Bank of India and Canara Bank have launched factoring subsidiaries, with equity participation inter alia from SIDBI as mentioned above.

9.18 The IDBI and other term-lending financial institutions have introduced a two-tier interest rate structure for loans for industrial projects in the large, medium and small-scale sector with effect from August 1, 1990. The first tier relates to the initial two years or the construction period of industrial projects (whichever is shorter) and the second tier applies to the period thereafter when industrial projects are expected to commence production. For the first tier, the normal interest rate would remain unchanged at 14 per cent per annum, whereas for the second tier, the normal interest rate would be 15 per cent per annum. To impart greater flexibility it has been decided in July 1991 to give term-lending financial institutions the freedom to charge interest rates above the floor rate of 15 per cent.

9.19 Some important changes have been announced in relation to the capital market. It has been decided to free the interest rates on convertible and non-convertible debentures. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is to be conferred statutory powers for administering the relevant provisions of the Securities Contracts and Regulations Act, 1957 and the Companies Act by transferring these powers from the Controller of Capital Issues (CCI). This will invest necessary authority with SEBI to effectively regulate, promote and monitor the working of the stock exchanges in the country. In order to further promote the development of mutual funds, these have been made open to the private sector and the joint sector.

### Activities of SEBI

9.20 SEBI has initiated various measures relating to merchant banking, mutual funds and investors' protection during 1990-91. These are as under :

#### Merchant Banking

9.21 In order to facilitate supervision of merchant banking activities, SEBI issued guidelines to the merchant bankers in November 1990 covering various areas such as net worth and the actual operations authorised to be taken up by merchant bankers, their code of conduct and allocation of responsibilities for lead managers. SEBI revised norms relating to number of lead managers, advisers and consultants to an issue in February 1991. Accordingly, for total amount of each issue aggregating less than Rs. 50 crore, the number of lead managers will not exceed two; for total amount of each issue aggregating Rs. 50 crore and above but less than Rs. 100 crore, the number may go up to three; and for total amount of each issue aggregating Rs. 100 crore and above, the number may go up to a maximum of four. SEBI has started grading public issue prospectuses based on the information disclosed to the public. With effect from May 1, 1991, SEBI has introduced a penalty system for the merchant bankers who default in the code of conduct laid down for them and in the compliance of various guidelines issued to them relating to their activities such as issue management, underwriting, portfolio management services and advisory services.

#### Mutual Funds :

9.22 SEBI issued guidelines in January 1991 for mutual funds with regard to advertisements and disclosure and

reporting requirements. Alongwith the statements promising benefits and portraying past performances, the potential investors are also to be informed about the associated material risk of investment in mutual funds. Furthermore, all mutual funds have been asked by SEBI to formulate disclosure norms and to inform the investors about the status of their investment in equity, debenture and Government securities, etc. Besides, it has been made mandatory for mutual funds to disclose to the shareholders and unit holders the details regarding private placement. The mutual funds are also required to disclose to the public bi-annual unaudited results and audited annual accounts in the format prescribed by SEBI.

#### Investors' Protection :

9.23 SEBI has evolved a system of redressal for investors' grievances and has been consistently taking up investors' complaints against companies, brokers and other intermediaries. Since August 1990, SEBI has been giving fortnightly press statement on the nature and types of complaints and also revealing list of major defaulting companies.

#### Credit Rating Agencies in India :

9.24 During 1990-91 (April-March), Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) rated 77 debt instruments viz., debentures, fixed deposit and commercial paper programmes etc.) in respect of 46 companies covering a debt volume of Rs. 1,689.9 crore as compared with 72 debt instruments in respect of 49 companies for a debt volume of Rs. 2,089.4 crore rated in the previous year. The cumulative number and value of debt instruments rated by CRISIL since its inception in January 1988, till end-March 1991, were 176 debt instruments issued by 124 companies covering a total debt volume of Rs. 4,357 crore, of which 44 related to commercial paper for a total amount of Rs. 423 crore.

9.25 IFCI has set up a credit agency known as the Investment Information and Credit Rating Agency of India (IICRA) on January 16, 1991. IICRA is a public limited company with an authorised share capital of Rs. 10 crore. Initial paid-up share capital will be Rs. 3.50 crore which will be subscribed by IFCI, UTI, LIC, GIC, SBI and 17 other banks. IICRA has started operations from March 15, 1991.

#### Equity Prices :

9.26 The buoyancy witnessed in the share prices during 1989-90 continued further in 1990-91 till about the middle of October 1990. Reflecting the rise, the RBI (Weekly) Index Numbers of Ordinary Share Prices (base: 1980-81=100) reached an all-time peak level of 654.2 for the week ended October 13, 1990. Even though there was a significant decline thereafter, the average index for 1990-91 at 500.3 showed an increase of 39.2 per cent over the previous year (Table 9.7).

9.27 On a point-to-point basis, the RBI index recorded a net gain of 63.6 per cent from 400 at end-March 1990 to the peak level of 654.2, for the week ended October 13, 1990. The index declined thereafter by 19.3 per cent to 527.9 by the end of March 1991, recording a net rise of 32 per cent over the year.

9.28 The industry-wise analysis indicates that all the industry groups recorded net gains between the end-March 1990 and the peak reached in October 1990 except shipping which showed a net fall of 17.8 per cent. The industry groups which recorded over 100 per cent net gains during April-October 1990 were: electricity generation and supply (256.6 per cent), cement (239.3 per cent), and cotton textiles (185 per cent). Thereafter, except for the cement industry (which recorded a net gain of 4.3 per cent), all other industry groups experienced declines in share prices. The industry groups which recorded substantial declines were: man-made fibres (41.9 per cent), cotton textiles (35.0 per cent), electricity generation and supply (34.9 per cent) and aluminium (30.0 per cent).

Table 9.7 : Reserve Bank of India All India Index Number of Ordinary Share Prices (Weekly) (Base 1980-81 = 100)

Year/Month	Average	High	Low	Last week-end of the month/year		
1	2	3	4	5		
1989-90	359.4	411.4	317.7	400.00		
(April—March)	(45.2)@					
1990-91	500.3	654.2	395.6	527.9		
(April—March)	(39.2)@					
April '90	399.9	405.7	395.6	401.6		
May	409.4	413.5	402.7	413.5		
June	414.9	420.0	408.9	419.3		
July	450.9	481.4	430.4	481.4		
August	506.4	527.5	488.6	527.5		
September	599.1	643.0	555.9	643.0		
October	617.2	654.2	587.4	587.4		
November	588.1	608.7	567.3	567.3		
December	518.3	552.1	490.7	490.7		
January	468.6	471.5	463.6	463.6		
February	483.3	510.8	462.7	510.8		
March	531.3	536.2	527.9	527.9		
1991—92						
April	455.9	568.0	536.9	568.0		
May	563.8	570.2	558.9	570.2		
June*	563.4	573.5	554.7	565.5		
July*	602.2	634.1	565.1	634.1		
Memorandum Items	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	Average for the five-year (1986-87 to 1990-91)
(A) Co-efficient of variation (in percentage) :-	3.65	4.82	16.36	6.10	14.80	9.15
(B) Dispersion (The Range)*	3.83 :-	40.0	121.1	93.7	258.6	110.3

@ Indicates percentage variation over the previous year.

\* Provisional.

+ Based on weekly indices.

9.29 Over the full financial year, cement industry witnessed the maximum gain (254.0 per cent) followed by electricity generation and supply (132.1 per cent) and cotton textiles (85.2 per cent). However, shipping and manmade fibres registered declines of 23.1 per cent and 20.1 per cent, respectively.

9.30 The volatility of equity prices during 1990-91 was higher as compared with the previous year. This is reflected in a high co-efficient of variation at 14.8 per cent for the years as compared with that of 6.1 per cent for 1989-90. The dispersion (or the range of fluctuation between the high and low) in the index of Ordinary Share Prices was also higher at 258.6 points during 1990-91 as compared with 93.7 points during 1989-91.

9.31 After the pause experienced in the share prices in the post-October 1990 phase, there was a sign of some cautious recovery with an underlying optimism during the first

quarter of 1991-92 (April-June) when the index of equity prices rose by 7.7 per cent. The optimistic sentiment witnessed during the first quarter of the current financial year turned buoyant during the month of July 1991 and the index recorded an increase of 12.1 per cent over June 1991 following the series of structural adjustment measures undertaken during the period.

## 10 DEVELOPMENTS IN THE EXTERNAL SECTOR.

### Balance of Payments :

10.1 The external sector came under pressure of a crisis proportion during the fiscal year 1990-91 and the first quarter of 1991-92 and this was reflected in a massive depletion of foreign exchange reserves and an extremely critical payments situation. While the symptoms of the emerging crisis were evident even in the Seventh Plan period, global developments aggravated the problem thereafter since 1990-91. There was also a conscious attempt on the part of international banks

to reduce exposures in order to meet capital adequacy norms. The access to short-term credit, particularly Bankers' Acceptance Facility, was becoming restricted. International rating agencies lowered the credit ratings of India/Indian entities which made it difficult to raise funds in the commercial markets. Under these circumstances, the country had to approach multilateral agencies and donor countries for balance of payments support. In addition to the drawdown of India's Reserve Tranche position of SDR 487 million in the Fund, the country also purchased SDR 1.27 billion under the IMF's financing facilities. A number of measures were also taken by the Government and the Reserve Bank of India to control imports and expedite the repatriation of export proceeds.

10.2 With a view to ensuring that external payment obligations are met and that the foreign exchange reserves remain at a reasonable level, certain exceptional steps were taken during the recent period including transactions relating to gold which are detailed in subsequent paragraphs.

10.3 A development of great significance has been the structural reforms relating to India's trade policy effected in association with the exchange rate adjustments. Two sharp downward adjustments in the external value of the Rupee were effected on July 1 and July 3, 1991 with a view to placing it at an appropriate level consistent with the need to maintain the competitiveness of our exports. Secondly, major reforms in trade policy were announced by the Government on July 4, 1991 to liberalise the system from administrative controls and licences, to boost exports, and to generally encourage competitiveness and enterprise in the economy. While protecting essential imports like POL, fertiliser and edible oils the new trade policy regime seeks to link other imports to exports. This is sought to be achieved by enlarging and liberalising the Replenishment Licensing System (REP) under which exporters will enjoy a uniform REP rate of 30 per cent of the FOB value as against the varying rates at present. The REP licence to be called Eximscrip will be freely tradeable. With the substantial liberalisation of trade policy regime and also the downward adjustments in the exchange rate, the Cash Compensatory Scheme (CCS) has been suspended effective from July 3, 1991. The new trade policy regime was further reinforced on August 13, 1991 by providing inter alia higher rates of Eximscrips and decanalisation of certain import and export items.

10.4 There were major international developments during 1990-91 which resulted in a payments bind for the country. First, the global slowdown in world trade following the recessionary conditions in industrialised countries and the economic disruption in Eastern Europe including the USSR had already begun to affect India's exports during the initial months of 1990-91, and had, in the face of rising imports, contributed to a widening of the merchandise deficit. Secondly, on top of this, the Gulf crisis, which set-in in August 1990, resulted in a wide-ranging disruption in the external payments situation; sharp increases in the petroleum oil and lubricant (POL) import bill, due to a steep rise in prices and also volume growth in the wake of relative stagnation

in domestic output of crude petroleum, partial loss of the export markets in West Asia and some foreign exchange expenditure on repatriation of Indians from affected countries in the Middle East. Thirdly, there occurred, during the period, due to certain social and political instability in certain parts of the country, a precipitous fall in invisible receipts in the form of private remittances, travel and tourism earnings, etc. Fourthly, as a result of the temporary loss of confidence arising from the above mentioned factors, net accruals under non-deposits, which financed nearly one-fourth of the current account deficit in recent years, suffered an unprecedented setback, during 1990-91 and more significantly in the first quarter of 1991-92. Fifthly, the erosion in the country's credit rating, combined with the general shortage of liquidity in the international financial markets, tended to dry up commercial borrowings both as long-term and short-term sources of finance. Despite the larger aid utilisation and also borrowings from the IMF during 1990-91, the stresses and strains on the external payments situation became acute towards the end of the year in the absence of a medium-term stabilisation programme.

10.5 As a result of the factors cited above, the estimated current account deficit during 1990-91 would be much higher as compared with that in 1989-90. For 1989-90 it was placed at Rs 10,391 crore (US \$ 6,241 million or SDR 4,863 million). POL imports increased to Rs. 10,706 crore (US \$ 5,948 million) in 1990-91 from the level of Rs. 6,273 crore (US \$ 3,768 million) in 1989-90, reflecting higher prices and also volume growth. The imports of crude and petroleum products amounted to 20.8 million tonnes and 8.2 million tonnes, respectively, as against 19.6 million tonnes and 7.1 million tonnes, respectively, in 1989-90. The average prices for crude and petroleum products were \$ 21.13 per barrel and \$ 279.2 per metric ton respectively, in 1990-91 as against \$ 17.37 per barrel and \$ 176.8 per metric ton, respectively, in 1989-90. The current account deficit during 1990-91 is thus expected to be around Rs. 12,100 crore (US \$ 7,301 million or SDR 5,271 million). As a percentage of GDP (at current market prices), the current account deficit is estimated to have gone up to 2.5 per cent in 1990-91 from 2.3 per cent in 1989-90.

10.6 The balance of payments position remained under pressure throughout the Seventh Plan period due mainly to large trade deficits and a fall in the surpluses on invisible account, as also large repurchases from the IMF under the Extended Fund Facility (EFF), which amounted to SDR 2,752 million during the period. During 1990-91, such repurchases under EFF amounted to SDR 469 million. During the Seventh Plan period, the current account deficit averaged around Rs. 7,771 crore (SDR 4,461 million and US \$ 5,538 million) per annum as against an annual average of Rs. 2,277 crore (SDR 2,100 million and US \$ 2,328 million) during the Sixth Plan period. The current account deficit as a proportion of GDP during the Seventh Plan period would average around 2.2 per cent as against the Planning Commission's target of 1.6 per cent for the Plan period and an average of 1.3 per cent observed during the Sixth Plan period (Tables 10.1 and 10.2). Table 10.2 presents a summary of India's balance of payments for the period 1986-87 to 1989-90.

Table 10.1 : Current Account Transactions as Proportion of GDP at Current Market Prices

Item	(In percentage)						
	1980-85 annual average	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90 (Provisional Estimate) <sup>a</sup>	1985-90 annual average
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Export	5.0	4.4	4.5	4.9	5.2	6.4	5.1
2. Imports	8.4	8.1	7.7	7.7	8.7	9.3	8.3
3. Trade Deficit	3.4	3.7	3.2	2.8	3.4	2.9	3.2
4. Invisible Receipts @ (Including official grant assistance)	3.6	3.0	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9
5. Invisible Payments	1.5	1.6	1.6	1.9	2.0	2.3	1.9
6. Invisibles (net) (4—5)	2.1	1.4	1.2	0.9	0.8	0.6	1.0
7. Current Account Deficit (3—6)	1.3	2.3	2.0	1.9	2.6	2.3	2.1

<sup>a</sup> Official grants are shown under the inflow of foreign resources presented in Table 2.2 of this Report.

Table 10.2 : India's Overall Balance of Payments

Item	(Rupees crore)			
	1989-90 (Estimate)	1988-89	1987-88	1986-87 (PR)
1	2	3	4	5
<b>A. Current Account</b>				
1. Exports, f.o.b.	28,234.7	20,646.7	16,396.4	13,315.0
2. Imports, c.i.f.	41,173.6	34,202.3	25,692.5	22,668.9
3. Trade Balance	-12,938.9	-13,555.6	-9,296.1	-9,353.9
4. Non-Monetary Gold Movement	6.4	—	—	—
5. Official Transfers, net	841.9	724.2	532.4	525.3
6. Other Invisibles, net	1,699.5	2,421.4	2,471.1	2,999.6
7. Current Account, net	-10,391.1	-10,410.0	-6,292.6	-5,830.0
<b>B. Capital Account</b>				
1. External Assistance, net	3,054.20	3,209.7	2,928.2	1,807.8
Disbursements	4,970.0	4,859.6	4,453.9	3,056.2
Amortisation	-1,915.8	-1,649.9	-1,525.7*	-1,248.4
2. Commercial Borrowings, net*	2,866.0	2,742.9	1,282.6	2,513.2
Disbursements	4,237.9	4,265.0	1,945.7	3,115.6
Amortisation	-1,371.9	-1,522.1	-663.1	-602.4
3. NRIDeposits, net	2,174.7	2,465.4	1,840.1	1,650.0
4. Other Capital, net	2,246.5	1,886.6	1,442.2	-71.64
5. Capital Account, net	10,341.4	10,304.6	7,493.1	5,899.4
<b>C. IMF, net</b>	-1,459.6	-1,547.3	-1,209.0	-674.3
<b>D. SDR Allocation</b>	—	—	—	—
<b>E. Total Capital Account, and SDR Allocation</b>	8,881.8	8,757.3	6,284.1	5,227.1
<b>F. Total Current Account, Capital Account and SDR Allocation</b>	-1,509.3	-1,652.7	-8.5	-602.9
<b>G. Errors and Omissions</b>	277.8	203.4	-947.7	-129.3
<b>H. Reserves and Monetary Gold (Increase—/Decrease+)</b>	1,231.5	1,449.3	956.2	732.2
<b>Memorandum Item</b>				
<b>Current Account Deficit</b>				
(i) In SDR Million	4,863	5,404	3,675	3,77
(ii) In US \$ Million	6,241	7,188	4,854	4,562

PR=Partially Revised.

\* Excludes refinancing credits and prepayment.

10.7 Final balance of payments data for 1989-90 and 1990-91 are not yet available. However, in order to provide some early indicators in respect of the main heads of accounts, provisional estimates have been published by the Reserve Bank since 1988-89 to give an idea on the broad order of magnitudes. Such provisional estimates for 1989-90 have been presented in Table 10.2. For the first time, 'Quick Estimates' have been prepared for balance of payments statistics for 1990-91 based on data available with the Reserve Bank and other sources information. The results of the Quick Estimates are presented in Table 10.3. They show that the trade deficit during 1990-91 stood at Rs. 15,142 crore (\$ 8,439 million), higher by Rs. 2,203 crore (667 million) over the previous year. Estimates of other net invisible receipts during 1990-91 showed a decline to Rs. 1,200 crore (\$ 669 million) from Rs. 1,700 crore (1,021 million) a year earlier. As a result, the current account deficit showed a sharp increase of Rs. 2,697 crore (\$ 1,053 million). In the capital account, larger net drawals under external assistance and receipts under 'Other Capital', over the year, were offset by a steep decline under net commercial borrowings and non-resident deposits. There was, however, a net drawal of Rs. 2,178 crore (\$ 1,214 million) from the IMF as against a net repayment of Rs. 1,460 crore (\$ 877 million) during 1989-90. The drawdown on reserves was almost double that during the preceding year.

639 GI/92-23

## Foreign Exchange Reserves

10.8 The fiscal year 1990-91 and the first quarter (April-June) of 1991-92 witnessed a steep fall in the country's foreign exchange reserves attributable to a combination of adverse short-term factors such as a surge in the POL import bills, continuing erosion in net invisible earnings, reduced access to international financial markets and lower inflows into non-resident deposit accounts. At the beginning of April 1990, India's foreign exchange reserves, at Rs. 6,251 crore (SDR 3,045 million) stood equivalent to a little under the value of two months' imports, having declined by Rs. 789 crore (SDR 670 million) during the fiscal year 1989-90. During the year, there were some special transactions. The amount of SDR 487 million (equivalent to Rs. 1,170 crore) in the reserve tranche in IMF was drawn in instalments on July 20, August 14 and September 4, 1990. By the end of September 1990, the reserves declined to Rs. 5,656 crore (SDR 2,523 million). With effect from October 17, 1990, gold holdings are being revalued nearer to the international market price in contrast to the erstwhile statutory price of Rs. 84.39 per 10 fine grammes. During the quarter October-December 1990, exclusive of the revaluation of gold, reserves recorded a precipitous fall of Rs. 2,658 crore (SDR 1,080 million). The import cover of reserves shrank to three weeks of imports by the end of December 1990. As part of concerted efforts towards liquidity management, India, negotiated

with the International Monetary Fund (IMF) for a drawal of SDR 716.90 million under its Compensatory and Contingency Financing Facility (CCFF) and SDR 551.93 million under the First Credit Tranche of its stand-by arrangement. The drawals were made on January 23, 1991. Excluding

Table 10.3 : India's Balance of Payments--1990-91  
(Quick Estimates)

Item	(Rupees crore)
<b>A. Current Account</b>	
1. Exports f.o.b.	33,178
2. Imports c.i.f.	48,320
3. Trade Balance	-15,142
4. Official Transfers, net	854
5. Other Invisibles, net	1,200
6. Current Account, net	-13,088
<b>B. Capital Account</b>	
1. External Assistance, net	3,241
Disbursements	5,528
Amortisation	2,287
2. Commercial Borrowings, net	1,244
Disbursements	3,507
Amortisation	2,263
3. Non-Resident Deposits, net	209
4. Other Capital, net	3,923
5. Capital Account net,	8,617
<b>C. IMF, net</b>	2,178
<b>D. SDR Allocation</b>	—
<b>E. Capital Account, IMF and SDR Allocation</b>	10,795
<b>F. Total Current Account, Capital Account, IMF and SDR Allocation</b>	-2,293
<b>G. Errors and Omissions</b>	—
<b>H. Reserves and Monetary Gold</b>	2,293
(Increase—/Decrease +)	

the revaluation of gold, reserves rose by Rs. 1,871 crore (SDR 668 million) during the last quarter of the financial year and amounted to Rs. 4,869 crore (SDR 2,111 million) at the end of March 1991, giving a decline in reserves during the year of Rs. 1,382 crore (SDR 934 million). Inclusive of gold referred to earlier, foreign exchange amounted to Rs. 11,416 crore at the end of Rs. 9,926 crore at the end of June 1991. In SDR terms, the reserves stood at SDR 4,329.3564 million, respectively. Exclusive of credit and drawal of Reserve Tranche, gold revaluation, the actual loss of was of the order of SDR 2,221. In 1989-90, What is more, between June 1991, there occurred, net of other erosion of Rs. 2,073 crore exchange reserves; net of transfer loss during the quarter SDR 754 million. A second SDR 56.18 million (Rs. 570.41 crore) under the Compensatory and Contingency Financing Facility (CCFF).

to SDR 525 million comprising SDR 469 million under the Trust Fund Facility and tapering off, and of March 1991, Rs. 1,789 crore, Rs. 148 crore, and Rs. 148 crore, respectively.

#### Foreign Currency Assets

10.10 Among the three components of foreign exchange reserves, foreign currency assets of the Reserve Bank declined by Rs. 1,399 crore during 1990-91 (April-March) as against a decline of Rs. 818 crore during 1989-90 and there was a further fall of Rs. 2,006 crore between end-March 1991 and end-June 1991.

#### SDRs

10.11 Holdings of SDRs fell by SDR 6.0 million during 1990-91 (April-March) as compared with a rise of SDR 2.4 million during 1989-90. The decline during 1990-91 was the combined result of a net acquisition of SDRs worth SDR 94.3 million, receipts on account of remuneration of SDR 10.1 million, IMF drawals worth SDR 557.4 million, repurchases of SDR 524.9 million, and payment of charges/interest amounting to SDR 142.9 million (net of interest subsidy) to the IMF. During the period April-June 1991, there was a decline of SDR 28.2 million primarily due to repurchase transactions (SDR 79 million) and payment of charges to the IMF (SDR 51 million).

#### Gold

10.12 Gold holdings of the Reserve Bank at Rs. 6,828 crore at the end of March 1991 and at Rs. 7,411 crore at the end of June 1991 compared with Rs. 281 crore till October 16, 1990, a year ago reflect the revaluation of gold close to international market price, effective October 17, 1990.

#### Merchandise Trade :

10.13 During 1990-91 (April—March), the balance on account of merchandise trade showed a deterioration due to a sharp fall in the rate of growth of exports in the face of a sizeable import growth caused by the spurt in POL prices. According to the provisional data on foreign trade released by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the fiscal year 1990-91, the trade deficit widened by Rs. 2,913 crore (37.7 per cent) to Rs. 10,644 crore from Rs. 7,731 crore during the preceding year (Table 10.5). However, on a payments basis (balance of payments data—Quick Estimates referred to earlier), trade deficit during 1990-91 stood higher at Rs. 15,142 crore. The break-up of the total deficit into oil and non-oil components reveals that during 1990-91, the 'oil deficit' rose by 77.7 per cent to Rs. 9,768 crore from Rs. 5,96 crore in 1989-90, while during the same period, the 'non-oil deficit' declined by 60.8 per cent to Rs. 876 crore from Rs. 2,235 crore. As a proportion of the total trade deficit, oil deficit constituted 91.8 per cent in 1990-91, rising from 71.1 per cent in 1989-90 and 49.6 per cent in 1988-89.

10.14 The striking growth in export performance observed during the four years since 1986-87 was not sustained during 1990-91. According to the DGCI&S data, exports during 1990-91 rose by 17.5 per cent to Rs. 32,527 crore as against a growth of 36.5 per cent during the previous year; in terms of US dollars, the export growth rates declined from 18.7 per cent to 9.0 per cent and while in SDR terms, it declined from 23.0 per cent to 1.0 per cent. The high rates of growth in imports witnessed during the last two years of the Seventh Plan period continued during 1990-91. Imports at Rs. 43,171 crore grew by 21.9 per cent during 1990-91 although somewhat lower than the increase of 27.9 per cent recorded during the previous year. In terms of US dollars, the rate of growth at 13.1 per cent was higher in comparison with a 11.2 per cent growth during the previous year. In terms of SDRs, however, imports grew at a substantially lower pace of 4.8 per cent as against 15.3 per cent in the previous year.

10.15 As emphasized earlier, it is the import of POL which has contributed to the high overall import growth. The value of POL imports in rupee terms grew by 48.2 per cent in 1989-90 and by 72.9 per cent in 1990-91 following a substantial increase in the dollar price of POL. The growth of non-POL imports fell from 22.3 per cent in 1989-90 to 11.1 per cent in 1990-91, or in US dollar terms from 8.1 per cent to 3.1 per cent and in SDR terms from an increase of 12.0 per cent to a decline of 4.5 per cent. The arresting of non-oil import growth followed a series of measures

S. DR IMF  
isted for  
ig 1990-91  
gainst an ac  
million during  
1991 and end-Ju  
ation effect, a fur  
million) in foreign e  
with the IMF, the res  
out to Rs. 1,857 crore or  
from the IMF of SDR 1.4  
made in July 1991 under  
Financing Facility (CCF).

to the IMF amounts  
e) during 1990-91 co  
re) under the Extende  
ion (Rs. 135 crore)  
der EFF have been  
99 and as at the ei  
t of SDR 3,900.1  
SDR 679 million  
56 million (1  
as comp.

Table 10.4 : India's Foreign Exchange Reserves

End of Month	Foreign Exchange		Reserves (Rupees core)		Total Foreign Exchange Reserves (In SDR Million)	Movement in Foreign Exchange Reserves (In SDR Million)	Reserve Position in the Fund (In SDR Million)	Transactions with the I M F (In SDR Million)				Movement in Foreign Exchange Reserves (net of IMF credit and drawal of Reserve Tranche) (in SDR Million)	
	SDRs	Gold@	Foreign Currency Assets	Total (2÷3—4)				Gross Drawings	Cumulative Repurchases	Outstanding Net drawings (9—10)	Net Drawals Repayments(—) of IMF Credit		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
March 1989	161	274	6,605	7,040	3,715	—771	487	3,900	2,071	1,829	—804		33
June 1989	213	274	6,075	6,562	3,408	—307	487	3900	2,219	1,681	—148		—159
March 1990	183	281	5,787	6251	3,045	—670	487	3,900	27,52	1,148	—681		11
June 1990	206	281	5,356	5,843	2,784	—261	487	3,900	2,863	1,037	—111		—150
September 1990	863	281	4,512	5,656	2,523	—522	—	3,900	3008	892	—256		—753
December 1990	565	6585	2,152	9302 (2,998)	3,659	614 (—1,443)	— (1,602)	3,900	3,100	800	—348		—475 (-1741)
March 1991	200	6,828	4,388	11,416 (4,866)	4,329 (2,111)	1,284 (—934)	—	5,169	3,221	1,948	800		—3 (-2,221 ,)
June 1991	133	7,441	2,382	9,926 (2,796)	3,564 (1,278)	—765 (—8,33)	—	5,169	3,300	1,869	—79		—686 (—754)

At rupee-SDR exchange rate at the end of the respective month.

@In column 3, Gold has been valued at Rs.8 4.39 per 10 grammes till October 16, 1990 and close to international market price thereafter. In column 6, gold has been valued at SDR 35 per troy ounce till October 16, 1990 and thereafter the rupee value in column 3 converted at rupee-SDR exchange rate at the end of the month.

Note : (1) Gross drawings, repurchases and outstanding net drawings from the IMF are in respect of Extended Fund Facility, Stand-by Credit Arrangement and Compensatory and Contingency Financing Facility i.e. exclusive of Trust Fund Loans.

(2) Figures in brackets represent reserves adjusted for gold revaluation.

(3) All variations are over the previous March.

Table 10.5 : India's Foreign Trade

Year (April-March)	(Rupees crore)			(Million US A)			(Million SDR)		
	1990-91	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89	1990-91	1989-90	1988-89
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Exports	32,527 (17.5)	27,681 (36.5)	20,281 (29.0)	18,128 (9.0)	16,626 (18.7)	14,005 (15.5)	13,090 (1.0)	12,954 (23.0)	10,529 (14.7)
Crude oil	—	—	—	—	—	—	—	—	—
POL	938 (34.8)	696 (37.8)	505 (—20.2)	523 (25.1)	418 (19.8)	349 (—28.6)	377 (15.6)	326 (4.4)	262 (—29.1)
Non-oil	31,589 (17.1)	26,985 (36.5)	19,776 (31.1)	17,604 (8.6)	16,208 (18.7)	13,656 (17.4)	12,713 (0.7)	12,628 (23.0)	10,267 (16.5)
II. Imports	43,171 (21.9)	35,412 (27.9)	27,693 (23.9)	24,060 (13.1)	21,269 (11.2)	19,123 (11.0)	17,373 (4.8)	16,572 (15.3)	14,377 (10.2)
Oil and POL	10,706 (72.9)	6,192 (48.2)	4,178 (3.5)	5,967 (60.4)	3,719 (28.9)	2,885 (—7.3)	4,308 (48.7)	2,898 (33.6)	2,169 (—8.0)
Non-oil	32,465 (11.1)	29,220 (24.3)	23,515 (28.5)	18,093 (3.1)	17,550 (8.1)	2,238 (15.0)	13,065 (—4.5)	13,674 (12.0)	12,208 (14.2)
III. Trade Balance	—10,644	—7,731	—7,412	—5,932	—4,643	—5,118	—4,283	—3,618	—3,848
Oil Balance	—9,768	—5,496	—3,673	—5,444	—3,301	—2,536	—3,931	—2,572	—1,907
Non-oil Balance	—876	—2,235	—3,739	—488	—1,342	—2,582	—352	—1,046	—1,941

Note : (1) Figures in brackets indicate percentage variation over the previous year.

(2) Col. 1, 2, & 3 are provisional figures based on March 1991, 1990 and 1989 press notes, respectively.

Source : D.G.C.I&S

taken by the Government and the Reserve Bank to conserve acutely scarce foreign exchange reserves.

10.16 Available indicators suggest that the growth of 10 to 12 per cent in exports in physical terms observed for about four years from 1986-87 to 1989-90 has not been sustained in 1990-91 and that in fact, the real export growth, if at all, has been reduced to a miniscule number.

#### Exports :

10.17 Commodity-wise data in value terms for the fiscal year 1990-91 indicate that while the export growth of primary commodities remained buoyant at 29.5 per cent on top of an increase of 30.5 per cent in the previous year, that of manufactured goods decelerated to 15.2 per cent against a 34.3 per cent increase in the previous year (Table 10.6). Consequently, primary product exports improved their share in total exports to 23.7 per cent from 21.5 per cent in 1989-90, while the share of manufactured goods slipped from 73.4 per cent to 71.9 per cent. Under the category of manufactured goods, significant increases were recorded in exports of cotton yarn, fabrics and madeups (39.5 per cent), readymade garments (25.4 per cent), and engineering goods (20.4 per cent). However, exports of gems and jewellery, which enjoyed a steady rise of 38.0 per cent per annum, on an average, during the previous four years and generally formed about one-fourth of total manufactured goods exports, recorded an absolute fall of 1.6 per cent in 1990-91, due mainly to recessionary trends in industrial countries. Under primary products, the perfor-

mance of agricultural and allied products was notable, for it rose by 31.5 per cent during 1990-91.

10.18 Destination-wise, the OECD group of countries continued to absorb more than 50 per cent of India's exports, with EEC as the most important sub-region. While the share of East European countries and OPEC countries declined albeit marginally, that of developing countries improved, during 1990-91. The share of OPEC countries declined primarily due to the stoppage of trade with Iraq and Kuwait.

#### Imports :

10.19 The spurt in imports witnessed during the last two years of the Seventh Plan period continued for the third consecutive year in 1990-91 mainly because of a substantial increase in POL imports. Apart from an increase of about 12 per cent in the quantity of POL imports, the estimated average rise of about 40 per cent in the cost of those imports following the Gulf crisis pushed up the import bill.

10.20 Commodity-wise data for the year 1990-91 indicate that of the total increase in imports of Rs. 7,755 crore, bulk imports, which comprise POL imports, other bulk consumption goods and other bulk items which are in the nature of basic inputs for industry, rose by Rs. 4,904 crore (34.4 per cent) accounting for 63.2 per cent. Non-bulk imports increase by Rs. 2,855 crore or 13.5 per cent the main item being capital goods which rose by Rs. 1,585 crore



Table 10 7-India's Imports of Principal Commodities

Commodity Group	(Rupees crore)					
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90(P)	1990-91(P)
1	2	3	4	5	6	7
Primary Products of which	3,803 (34.9)	4,145 (33.3)	4,086 (26.1)	4,560 (22.5)	5,951 (21.5)	7,708 (23.7)
1. Agricultural & Allied Products	3,108 (27.7)	3,422 (27.5)	3,312 (21.1)	3,544 (17.5)	4,571 (16.5)	6,013 (18.5)
2. Ores & minerals	785 (7.2)	723 (5.8)	774 (4.9)	1,016 (5.0)	1,380 (5.0)	1,695 (5.2)
Manufactured Goods	6,447 (59.2)	7,808 (62.7)	10,900 (69.5)	14,128 (74.8)	20,310 (73.4)	23,387 (71.9)
1. Textile Fabrics & Manufactures	1,795	2,179	3,212	3,618	5,236	6,755
Of which						
Cotton yarn, fabrics, made-ups	574	637	1,131	1,134	1,480	2,065
Readymade Garments	1,067	1,331	1,823	2,118	3,224	4,042
2. Leather & Leather manufactures	770	992	1,252	1,522	1,951	2,554
3. Handicrafts	1,881	2,548	3,245	5,188	6,285	6,247
Of which						
Gems and Jewellery	1,503	2,074	2,612	4,391	5,296	5,210
4. Chemicals & Allied Products	498	583	839	1,259	1,997	2,330
5. Engineering Goods	954	1,148	1,492	2,321	3,321	3,997
Minerals and Lubricants*	645 (5.9)	411 (3.3)	649 (4.1)	505 (2.5)	697 (2.5)	938 (2.9)
Total (including others)	10,895	12,452	15,674	20,232	27,681	32,527

P—Provisional.

\*—Relates to Petroleum Crude and petroleum products only.  
Figures in brackets represents percentages to total exports  
Source : D.G.C.I. & S.

or 17.9 per cent (Table 10.7). Imports of export-related items\* fell by Rs. 18 crore (or 0.3 per cent) entirely due to a decline in imports of pearls, precious and semiprecious stones from Rs. 4,242 crore in 1989-90 to Rs. 3,732 crore in 1990-91.

10.21 The OECD continued to be the most important source of India's imports; its share in total imports, however, declined from 60.0 per cent in 1989-90 to 57.2 per cent during 1990-91. Around 20 per cent of imports came from the USA and Japan. While the share of East European Countries as suppliers declined, that of OPEC and developing countries showed a rise.

#### India's Trade with Rupee Payment Countries :

10.22 The trade with the countries under Rupee Payment Agreement (RPA) is carried out in consonance with the trade agreement which provides for a framework for He size of turnover and commodity composition of trade with each country. At present, only three countries viz., the USSR, Czechoslovakia and Romania, settle their payments under the RPA. However, the trade is dominated by the USSR which accounts for 95 per cent of the total trade turnover between India and the three countries under RPA.

10.23 During 1990-91, there was a steep deceleration in the growth rate of both, exports and imports in relation to the rupee payment countries. Exports during the period at Rs. 5,506 crore rose by 13.9 per cent and imports at Rs. 2,870 crore by 22.7 per cent as against the growth of about 70.8 per cent and 60.6 per cent, respectively, re-

corded during 1989-90. As a result of lower growth rate in imports, the trade surplus with these countries rose by Rs. 143 crore to Rs. 2,636 crore during 1990-91 from that of Rs. 2,493 crore during the previous year. India was in a surplus position with the rupee payment countries during the 'eighties. The surplus rose from Rs. 218 crore in 1980-81 to Rs. 2,493 crore during 1989-90.

10.24 India's trade with the USSR is presently conducted under the Trade Plan for 1991. The commodities enumerated in the Agreement indicate that India's imports from the USSR would predominantly consist of crude oil and products, fertilisers, industrial raw materials, machinery and transport equipments. India's exports, on the other hand, would be of agricultural items, ores and minerals, ready-made garments and textiles, intermediate chemicals, medicinal and pharmaceutical products and light engineering goods. India has been enjoying a surplus trade balance with the USSR almost during the entire 1980's. The trade surplus in favour of India rose from Rs. 212 crore in 1980-81 to Rs. 2,425 crore in 1989-90, and further to Rs. 2,714 crore during 1990-91.

#### Policy Developments :

10.25 In view of the tight foreign exchange reserves position, a number of measures were undertaken by the Government and at the Reserve Bank to conserve scarce foreign exchange. The Government of India shifted certain categories of capital goods from OGI to the licensing category in order to have greater control on their imports. Industrial units were advised to import raw materials and components against replenishment licences/additional licences. The imports of raw materials, components and consumables under

\*Export-related imports cover pearls, precious and semiprecious stones, cashewnuts, textile yarn and chemicals, both organic and inorganic.

Table 10.7-India's Imports of Principal Commodities

		(Rupees crore)				
Commodities	Group	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90(P) 1990-91(P)
1	Bulk Imports	10763 54.8	8024 39.9	90843 40.8	11316 40.1	14239 40.2 19143 44.3
Of Which :						
(a)	Petroleum, Petroleum products and related material	4989 25.4	2811 14.0	4043 18.2	4358 15.4	6274 17.7 10820 25.1
(b)	Bulk consumption goods	1466 7.5	1179 5.9	1503 6.7	1889 6.7	914 2.6 955 2.2
(i)	Cereals and cereal preparation	110 110	87 87	66 66	774 774	378 378 151 151
(ii)	Edible Oils	749 749	634 634	969 969	730 730	211 211 322 322
(iii)	Pulses	189 189	234 234	275 275	385 385	228 228 473 473
(iv)	Sugar	418 418	224 224	193 193	Neg Neg	97 97 9 9
(c)	Other bulk items	4308 21.9	4034 20.0	3538 15.9	5069 18.0	7051 19.9 7368 17.1
(i)	Fertilizers	1436 163	921 145	508 139	934 190	1776 253 1697 339
	Crude Sulphur & unroasted iron pyrites	220 220	200 200	181 181	251 251	295 295 267 267
	Manufactured	1053 542	576 517	188 639	493 776	1228 1253 1091 1109
(ii)	Non-ferrous metals					
(iii)	Paper, paperboard and manufactures thereof (including newsprint)	226 226	217 217	270 270	303 303	358 358 463 463
(iv)	Crude rubber	101 101	107 107	120 120	173 173	172 172 226 226
(v)	Pulp and waste paper	245 245	244 244	239 239	260 260	304 304 454 454
(vi)	Metalliferous ores and metal scrap	363 363	472 472	442 442	690 690	883 883 1209 1209
(vii)	Iron & Steel	1395 1395	1556 1556	1320 1320	1933 1933	2305 2305 2210 2210
2	Non-bulk imports	8895 45.2	12072 60.1	13160 59.2	16919 59.9	21173 59.8 24028 55.7
Of which :						
(a)	Capital Goods	4286 21.8	6488 32.3	6566 29.5	6956 24.5	8831 24.9 10416 24.1
(b)	Mainly export related items	2366 12.0	2856 14.2	3351 15.1	5400 19.1	6803 19.2 6785 15.7
(i)	Pearls, precious and semi-precious stones	1100 5.6	1489 7.4	2018 9.1	3176 112	4242 12.0 3732 8.6
(ii)	Chemical, organic and inorganic	1089 5.5	1145 5.7	1082 4.9	1894 6.7	2135 6.0 2472 5.7
(iii)	Textile yarn, fabrics, etc	153 153	151 151	187 187	269 269	349 349 4492 4492
(iv)	Cashew, nuts, raw	24 24	71 71	64 64	61 61	77 77 137 137
(c)	Others	2243 11.4	2728 13.6	3243 14.6	4563 61.2	5539 15.7 682 15.8
Of which :						
(i)	Artificial resins & plastic materials	322 322	434 434	567 567	809 809	996 996 1096 1096
(ii)	Professional, scientific & optical goods, etc	379 379	512 512	500 500	679 679	886 886 1082 1082
(iii)	Coal, coke & briquettes, etc	224 224	203 203	227 227	431 431	562 562 780 780
(iv)	Medical & pharmaceutical products	177 177	214 214	168 168	236 236	272 272 325 325
(v)	Cotton, wool, silk & other textile related items	200 200	164 164	232 232	379 379	259 259 280 280
(vi)	Chemical material & products	144 144	152 152	191 191	187 187	222 222 279 279
(vii)	Non-metallic mineral manufactures	102 102	129 129	105 105	164 164	168 168 211 211
Total (1+2)		19658	20096	22244	28235	35416* 43171

P : Provisional Neg : Negligible

\* : Total for the year 1989-90 is partially revised

Note : Figures in decimals represents percentage to total imports

Source : D.G.C.I &amp; S.

the OGL by actual users engaged in the manufacture of automobiles, electronic items and consumer durables were subject to a cut of 15 per cent of the value of actual OGL imports during the preceding licensing year—a measure which was subsequently extended to all actual users against their supplementary licences for the import of above items. Restrictions were also imposed on canalised imports requiring clearance by the Finance Ministry on a case-by-case basis. To expedite the repatriation of export proceeds, the Government decided to issue import replenishment licences only after their realisation.

10.26 One of the measures taken by the Reserve Bank was the levy of a cash margin which essentially implies the use of a monetary instrument in a non-discretionary manner to moderate the level of imports. As explained earlier in detail, the measures have been modified from time to time keeping in view, the difficulties experienced by exporters and other important sectors of the economy. Imports by 100 per cent Export-Oriented Units (EOUs) and Units located in Free Trade Zones (FTZs) and Export Processing Zones (EPZs) are exempt from the margins provided the exports are to general currency area (GCA) and there is no export bill outstanding beyond a period of six months from the date of export. In cases where exports are made both to the general currency area and the rupee payment area, imports against which margin requirement will be exempt will be determined by the proportion of exports to the general currency area in the total exports made during the previous year. Imports against various types of advance and import licences for own consumption are also exempt from the margin requirement subject to certain pre-conditions one of which is the realisation of export proceeds within the stipulated period. The concerned importers are, however, required to obtain approval of (i) the head office of bank/ Reserve Bank if the transaction is of the value of Rs. 25 lakh/Rs. 50 lakh and above, respectively, and (ii) the Reserve Bank if the cumulative value exceeds Rs. 2 crore. The latter stipulation of the Reserve Bank's prior approval for imports has been modified from the cumulative Rs. 2 crore import to Rs. 2 crore plus 20 per cent of the previous year's export realisation, subject to a ceiling of Rs. 5 crore. Also, maintenance imports including raw materials, will be allowed to be imported without cash margins up to 10 per cent of their actual export realisations from the general currency area during the previous accounting year. While the Reserve Bank would give priority in granting clearance for export-related import bills, all of these concessions are available for those exporters who have no export bills outstanding beyond six months from the date of export.

10.27 In response to the rapidly declining foreign exchange reserves and as part of short-term economic management, the Government took several measures. The Government leased 20 tonnes, out of confiscated gold, to State Bank of India (SBI) which in turn entered into a sale with a repurchase option in the international market. The net foreign exchange augmentation as a result of this transaction was of the order of \$ 200 million equivalent to about Rs. 400 crore. The lease of gold will not affect either the domestic pool of gold or the gold held by the Reserve Bank as a part of its foreign exchange assets. The gold has been given to the SBI purely on a lease basis for a period of 6 months. According to the lease agreement, the SBI is under a contractual obligation to return the gold to the Government at the expiry of the lease period. Secondly, the Reserve Bank, both as part of its reserve management policy and as a means of raising resources temporarily, took a decision to keep its gold abroad up to the limit permitted by the Reserve Bank of India Act, 1934. Thus the Reserve Bank in four instalments, sent gold to the vaults of the Bank of England to the extent of a total quantity of 46.9 tonnes which is close to the permissible limit. The Reserve Bank of India Act, 1934 authorises the Bank to keep 15 per cent of its gold holdings outside India. The Act also authorises the Reserve Bank to borrow from any monetary authority for a period of one month and provide the necessary security for that purpose. A total amount of Rs. 1,037.73 crore (equivalent to \$ 405 million) was raised from Bank of England and Bank of Japan in July 1991 against the gold deposited with the former.

## New Trade Policy Regime

10.28 Following the two sharp downward adjustments in the external value of the rupee on July 1 and July 3, 1991, the Government announced major reforms in the trade policy. According to the new policy regime, while essential imports like POL, fertiliser and edible oil would be protected, all other imports should be linked to exports. A major ingredient of the policy as announced on July 4, 1991 is the introduction of an enlarged and liberalised Replenishment Licence System (REP) with a uniform REP rate of 30 per cent of the FOB value instead of the existing varying rates between 5 per cent and 20 per cent of FOB value. The REP licence will now be called Eximscrip and will be freely tradeable. In the light of the substantial liberalisation of the trade regime and also the sharp adjustments in the exchange rate of the rupee, the Cash Compensatory Scheme (CCS) has been suspended with effect from July 3, 1991.

10.29 The trade policy announcement envisages that the Government objective would be to remove in three years time all import licensing for capital goods and raw materials except for a small negative list and to decanalise all items except those that are essential; it is also hoped that the Rupee will become fully convertible on the trade account in three to five years.

10.30 On August 13, 1991, the Government announced further reforms in trade policy. They included, among others, a new package of incentives for 100 per cent export-oriented units (EOUs) and export-processing zones (EPZs), higher rates of Eximscrip for value-added items, decanalisation of certain import and export items and strengthening of the Advance Licence System. All COU/EPZ units will be eligible for Eximscrips at 30 per cent of net foreign exchange earnings, whereas high value-added agriculture products, electronic and others will enjoy Eximscrips at 40 per cent. Sixteen items of exports were decanalised immediately. In the case of imports, while six items were decanalised and placed on OGL, 14 items were decanalised. The Government took steps for strengthening the system of Advance Licences as an instrument of export promotion. The procedure for considering Advance Licence was simplified with a view to ensuring its quick issue.

## Difference between Trade and BOP Data

10.31 The difference in import figures as between the Reserve Bank's balance of payments data (quick estimates) and the DGCI&S figures on merchandise trade (Tables 10.2 and 10.5) for 1990-91 would be Rs. 5,149 crore (\$ 2,870 million) compared with Rs. 5,762 crore (\$ 3,461 million—provisional estimates) in 1989-90. During 1988-89, the import figures according to the balance of payments data were similarly higher by Rs. 6,509 crore (\$ 4,495 million). These differences are mainly attributable to the differences in coverage, timing and valuation. These causes were explained in detail in the Annual Report for the years 1988-89 and 1989-90. There are some minor differences in regard to export data.

## Invisibles

10.32 The available information indicates that net receipts from invisibles during 1990-91 might have declined substantially over the previous year, both in Rupee and Dollar terms. A major factor contributing to the decline in net invisible receipts during 1990-91 was the reduced inflow under private transfers, partly due to a decline in receipts from the Gulf region. Besides, earnings from travel and tourism are expected to have recorded a substantial decline in dollar terms. The number of foreign tourist arrivals in the country during 1990-91 (April—March) declined by 8.8 per cent as against a rise of 7.5 per cent during the preceding year. Furthermore, payments under investment payments and service charges on borrowings both under external assistance and on commercial terms. Other components of invisibles taken together, however, are not expected to have shown any marked variation over the previous year.

## External Assistance

10.33 The gross inflow of external assistance rose during 1990-91. Gross utilisation of loans and grants at Rs. 6,660

crore was higher by Rs. 857 crore than that of Rs. 5,803 crore during 1989-90, mainly due to larger utilisation of loan assistance. The amortisation payments continued to show a rising trend and amounted to Rs. 2,395 crore during 1990-91 as against Rs. 1,987 crore in the preceding year. Net inflow of external aid rose by Rs. 449 crore to Rs. 4,265 crore during 1990-91 (Table 10.8). In US dollars terms too, the net inflow of aid at \$ 2,377 million was higher than that of the previous year.

10.34 Efforts to cope with the deepening payments crisis have involved, inter alia, approaching multilateral institutions such as the IBRD, the IMF and the ADB as well as a number of donor countries, for balance of payments support in the form of fast disbursing aid. Early in April 1991, the ADB sanctioned a loan of US \$ 150 million to the Indian Oil Corporation to enable the energy sector to tide over the adverse impact of the Gulf war. On May 29, 1991, Japan provided a loan of US \$ 150 million by way of co-financing assistance of an equal amount extended by the ADB. An additional loan of US \$ 150 million was extended by Japan to cover refinance by the Small Industries Development Bank of India to sub-borrowers for the development of small-scale industries. A mixed credit line of Rs. 140 crore (Swiss Francs 100 million) was signed in June 1991, consisting of 40 per cent as grant from the Swiss Government and 60 per cent as export credit.

#### Modes of Financing of Current Account Deficit over the Plan Period

10.35 The mode of financing during the Seventh Plan period shows that 29 per cent of the financing need was met by way of external assistance from multilateral and bilateral donors, 24 per cent by way of commercial borrowings, 23 per cent through non-resident deposits under Foreign Currency Non-Resident Accounts Scheme (FCNRA) and Non-Resident External Rupee Accounts Scheme [NR(E)RA], about 13 per cent from other capital transactions and the

remaining by the drawdown of reserves (Table 10.9). Other capital transactions referred to above comprise largely Bankers' Acceptance Facility, NRI Bonds, Off-shore Mutual Funds, Foreign Currency Deposits of Banks and Others, and the Reserve Tranche Withdrawal from the IMF (the last two items in 1990-91).

#### Accretions under NR(E) RA and FCNRA Schemes

10.36 Under Non-Resident (External) Rupee Accounts [NR(E)RA] Scheme, provisional data for 1990-91 indicate a withdrawal of Rs. 146 crore (excluding estimated interest element) as compared with Rs. 4 crore in the preceding year. The net inflow under the Foreign Currency (Non-Resident) Accounts (FCNRA) Scheme during 1990-91 was substantially lower at Rs. 255 crore as compared with Rs. 2,179 crore in 1989-90 (Table 10.10).

10.37 Table 10.11 shows that at the end of March 1991, non-resident deposits stood at Rs. 20,446 crore [Rs. 7,041 crore under NR(E)RA and Rs. 13,405 crore under FCNRA].

#### Interest Rates : Non-Resident Deposits

10.38 In view of the trends in interest rate movements in the international markets, the interest rates on deposits under FCNRA Scheme were revised relatively less frequently during the period under consideration than in 1989-90. Table 10.12 sets out the rates of interest on FCNRA deposits for different currencies during the period under review.

#### External Debt

10.39 With the recurrent and widening current account deficits observed in the last few years, India's external liabilities comprising multilateral and bilateral assistance, commercial borrowings and non-resident deposits, have gradually risen over the period. India's medium and long-term debt (other

Table 10.8 : External Assistance

(Rupees crore)						
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 @
1	2	3	4	5	6	7
1. Loans	2,493	3,176	4,574	4,739	5,138	60,89
2. Grants	443	429	478	566	665	571
3. Gross Utilisation	2,936	3,605	5,052	5,305	5,803	6,660
4. Repayments	776	1,176	1,581	1,646	1,987	2,395
5. [Net (3-4)]	2,160	2,429	3,471	3,659	3,816	4,265
Memorandum item						
Net inflow in						
U.S. \$ million	1,766	1,901	2,678	2,527	2,292	2,377

Note : 1. Loans are inclusive of non-government loans but exclusive of suppliers' credit and commercial borrowings and hence these figures may not agree with those in Table 10.2.

2. Grants are exclusive of PL 480-II grants.

@ Provisional.

Table 10.9 : Financing Need and Sources of Financing

	Rupees crore						Millions	Million
	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90P	Total	of US \$	of SDRs Rs
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Current Account Deficit including Errors & Omissions	5,347	5,959	7,240	10,207	10,113	38,866	27,740.0	22,255.7
2. Repayment to IMF	253	672	1,209	1,547	1,460	5,141	3,610.3	2,823.4
3. Financing Need (1+2)	5,600	6,631	8,449	11,754	11,573	44,007	31,350.3	25,079.1
Financed by								
4. External Assistance	1,676 (29.9)	1,808 (27.3)	2,928 (34.7)	3,210 (27.3)	3,054 (26.4)	12,676 (28.8)	9,093.9 (29.0)	7,273.2 (29.0)2
5. Commercial Borrowings	1,166 (20.8)	2,513 (37.9)	1,283 (15.2)	2,743 (23.3)	2,866 (24.8)	10,571 (24.0)	7,524.7 (24.0)	6,043.8 (24.1)
6. Non-Resident Deposits	1,767 (31.6)	1,650 (24.9)	1,840 (21.8)	2,465 (21.0)	2,175 (18.8)	9,897 (22.5)	7,163.1 (22.8)	5,807.8 (23.1)
7. Other Capital	285 (5.1)	—71 (—1.19)	1,442 (17.1)	1,887 (6.1)	2,247 (19.4)	5,790 (13.2)	3,942.2 (12.6)	3,048.0 (12.2)
8. Use of Reserves	706 (12.6)	732 (11.0)	956 (11.3)	1,449 (12.3)	1,231 (10.6)	5,074 (11.5)	3,627.2 (11.6)	2,906.9 (11.6)

Note : Figures in brackets indicate proportions to financing need (item 3). Conversion to US \$ and SDRs has been made respective annual average rates for the years 1985—90.

Table 10.10 : Inflows under NR(E)RA and FCNRA Scheme

Fiscal Year	(Rupees crore)		
	Non-Resident (External) Rupee Account	Foreign Currency (Non-Resident) Account	Total
1	2	3	4
1985-86	616	1,151	1,767
1986-87	477	1,173	1,650
1987-88	477	1,363	1,840
1988-89	235	2,230	2,465
1989-90	—4	2,179	2,175
1990-91	—146*	255	109

\* Excluding the estimated accrued interest.

\* Provisional.

Table 10.11 : Deposit Liabilities Under NR(E)RA and FCNRA Schemes

(Rupees crore)							
As at end-March	NR(E)RA*	FCNRA				Total (3 to 6)	Grand Total (2 + 7)
		US Dollar	Pound Sterling	DM	Yen		
1	2	3	4	5	6	7	8
1986	3,461	1,759 (1,419)	430 (236)	—	—	2,189	5,650
1987	4,336	3,047 (2,360)	464 (224)	—	—	3,511	7,847
1988	5,107	4,406 (3,410)	541 (222)	—	—	4,947	10,054
1989	5,899	6,648 (2,24)	535 (203)	700 (848)	372 (31,571)	8,255	14,154
1990	6,507	9,304 (5,409)	337 (119)	1,928 (1,013)	655 (60,327)	11,324	17,831
1991	7,041P	11,270 (5,754)	305 (89)	1,005 (874)	825 (59,403)	13,405	20,446

\* Inclusive of accrued interest.

P Do not include accrued interest.

P Provisional.

Note : Figures in brackets are outstanding deposits in the relevant currencies in million.

Table 10.12: Interest Rates on FCNRA Deposits

(Per cent per annum)

Effective Dates	US\$				Pound Sterling				DM				Yen			
	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only	6 months to 1 year	1 year to 2 years	2 years to 3 years	3 years only
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
May 30, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	7.75	8.00	8.00	8.00
July 19, 1990	9.00	9.50	10.00	10.25	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.25	8.25	8.25	8.25
August 13, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	8.50	8.50	8.50	8.50
September 3, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.00	9.50	9.75	9.75	9.00	9.25	9.25	9.25
September 25, 1990	9.00	9.25	9.75	10.00	11.50	11.75	12.00	12.00	9.25	9.75	10.00	10.00	9.25	9.50	9.75	9.75
December 4, 1990	8.75	9.00	9.50	9.75	11.50	11.75	12.00	12.00	9.50	9.75	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00
January 14, 1991	8.25	8.50	9.00	9.25	11.50	11.75	12.00	12.00	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50
February 8, 1991	7.50	8.00	8.50	9.00	13.25	13.25	13.25	13.25	10.00	10.25	10.50	10.50	8.50	8.50	8.50	8.50

than non-resident deposits), i.e., having an original or extended maturity of more than one year, amounted to Rs. 81,168 crore (about US \$ 47 billion) at the end of March 1990 and is estimated to have increased to Rs. 1,00,197 crore (US \$ 51 billion) at the end of March 1991 (Table 10.13). Including NRI deposits, India's external liabilities (other than short-term debt) would amount to Rs. 1,20,643 crore (US \$ 61.42 billion) as at the end of March 1991. Besides long-term and medium-term debt, there is also short-term debt associated with imports. This short-term debt is in the nature of trade credits, suppliers' credits (with less than one year's maturity), credits under Bankers' Acceptance Facility (BAF) etc. The bulk of short-term liabilities relate to Bankers' Acceptance and other facilities which were contracted for public sector undertakings. The outstandings under such Bankers' Acceptance and other facilities, which are being financed, among others, through the rollover of inter-bank borrowings, amounted to Rs. 6,975 crore (\$ 3,551 million) at the end of March 1991.

10.40 In relation to GDP at current market prices, external debt (long and medium-term) is estimated to have risen to 19.3 per cent at the end of March 1991 as against 18.3 per cent at the end of March 1990. The debt (long and medium-term) to export ratio was around 202 per cent at the end of March 1990 as compared with 226 per cent at the end of March 1989. It is of importance to note that the debt service ratio (i.e., ratio of debt-service payments, exclusive of interest on non-resident deposits, to export of goods and invisibles excluding official trans-

fer receipts) is estimated to have declined to 21.0 per cent in 1989-90 from 23.6 per cent in 1988-89. The annual average debt-service ratio during the Seventh Plan period was around 20.3 per cent, substantially above the average of 17.6 per cent projected in the Plan document. The debt-service ratio during 1990-91 is expected to be around 21.3 per cent, marginally higher than in the preceding year.

#### Developments in Exchange Rates of Major Currencies

10.41 During the period under review, foreign exchange markets were subject to certain influences, viz., macro-economic developments in major industrialised countries and policy responses to them, the Gulf crisis and political developments in Eastern Europe and the USSR. Faced with the slowing down of economic growth combined with increasing inflationary pressures, the major industrialised countries generally agreed to take necessary adjustment measures in their structural reforms to promote economic efficiency. Nevertheless, there was considerable volatility in the exchange markets. Besides economic and political events, the interest rate factor also contributed to the exchange rate movements. During the Middle East crisis, the US dollar came under pressure which led the currency eventually to its historically low levels, particularly against the DM. The period was marked by a decline in economic performance, leading national economies of the USA, Canada and the U.K. towards recession. The erratic performance of the pound sterling evident till September 1990, however, took a reversal after the British currency

Table 10.13 : India's External Debt

As at end-March								
	1980**	1985	1986	1987	1988	1989	1990(P)	1991(P)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. External Assistance	12,178	24,004	26,638	32,312	36,578	46,838	54,095	65,694
2. IMF		4,888	5,271	5,548	4,732	3,696	2,573	5,133
3. External Commercial Borrowings*	1,252	6,908	8,075	11,243	13,543	19,147	24,500	29,370
4. Total (1+2+3)	13,430	35,800	39,984	49,103	54,853	69,681	81,168	1,00,197
Total in Million of U.S. Dollar	16,392	28,801	32,391	37,699	42,993	44,485	47,109	51,009
MEMORANDUM ITEMS								
1. The Debt Stock (Long and Medium Term) Export Ratio @ (In per cent)		181	209	233	218	226	202	216
2. The Debt-Service Ratio (for respective fiscal year) (In per cent)		12.0	16.1	19.3	21.3	23.6	21.0	21.3

\*\* Based on Survey of India's International Investment position published in RBI Bulletin, April 1985.

\* Include Non-Government loans under External Assistance Programme and suppliers' credits from East-European countries repayable in rupees.

(4) Exports include exports of merchandise goods plus invisible receipts excluding official transfers

P Provisional

joined the European Exchange Rate Mechanism (ERM) in October 1990. With favourable interest rate differentials, the Japanese Yen staged a recovery in the exchange markets. In respect of the DM, inspite of its initial consolidation, the currency came under pressure emanating from the cost of German re-unification. The US dollar staged a sharp recovery after the Gulf war and appreciated against the DM. Inspite of wide scale volatility, in the exchange markets, particularly after the Gulf crisis, G-7 countries expressed confidence in the world economic performance and their Ministers and Governors of Central Banks reaffirmed commitment to co-operate closely for orderly exchange markets.

10.42 During 1990-91 (July-June), in terms of monthly averages, the US dollar continued to exhibit a mixed trend, as in the preceding year. It became weak during July–November 1990, lost direction thereafter until the successful conclusion of Gulf crisis but gained strength subsequently till June 1991 against major currencies. Except against the Yen, the US dollar registered marginal gains vis-a-vis all other currencies. Between end-June 1990 to end-June 1991, the Pound Sterling, on an average, gained in relation to the DM but lost against the SDR, the US dollar and Yen. The DM lost against all major currencies during the period. Contrary to the trend in the previous year, the Yen firmed up against all major currencies and the SDR (Table 10.14).

#### Exchange Rate of the Rupee

10.43 The value of the Rupee continues to be determined in relation to a weighted basket of cur-

rencies of India's major trading partners, with the Pound Sterling as the intervention currency. The exchange rate is a price like any other price in the economy and it can be used to achieve certain objectives. The primary goal of the exchange rate adjustment has been one of promoting competitiveness of our exports in the world market. In this context it is necessary to review the commodity price trends here and abroad to ensure that prices of our exports were not out of alignment with those in the international market. It was observed that since October 1990, there had actually been some appreciation of about 2 per cent in our effective real exchange rate as a result both of a much slower rate of depreciation of the nominal exchange rate and the widening inflation differentials as the country's domestic inflation accelerated after October 1990. In the five-month period between February 1991 and June 1991, the nominal effective exchange rate of the Rupee fell only by 2.5 per cent. There was thus a need for an adjustment in the exchange rate as our international competitiveness was being eroded. One should also take note, in this context, of the behaviour of the exchange rates of countries which are competitors to India in the world market. Besides, there is need to take into account expectations and the ensuing market behaviour arising from such expectations. It was in this context that on July 1 and July 3, 1991, the value of the Rupee in relation to major currencies was adjusted downwards: cumulatively, the adjustment worked out to 17.38 per cent against the intervention currency, namely, the Pound Sterling. With this adjustment, the Rupee has been placed at an

Table 10.14 : Rupee Exchange Rates  
(Rupees per unit of SDR/Foreign Currency)

Period	SDR	U.S. Dollar	Pound Sterling	Deutsche Mark	Japanese Yen
1	2	3	4	5	6
<b>A. Annual Average Rates</b>					
(April-March)					
1986-87	15.4472	12.7782	19.0722	6.2970	0.0820
1987-88	17.1208 (+9.8)	12.9658 (+1.4)	22.0872 (+13.7)	7.4004 (+14.9)	0.0941 (+4.8)
1988-89	19.2619 (+11.1)	14.4819 (+10.5)	25.5959 (+13.7)	8.0494 (+8.1)	0.1130 (+16.7)
1989-90	21.3684 (+9.9)	16.6492 (+13.0)	26.9179 (+4.9)	9.0922 (+11.5)	0.1166 (+3.1)
1990-91	24.8491 (+14.0)	17.9428 (+7.2)	33.1930 (+18.9)	11.4351 (+20.5)	0.1279 (+8.8)
<b>B. Monthly Average Rates</b>					
March 1989	20.1989	15.5137	26.5858	8.3083	0.119
March 1990	22.2961	17.1274	27.8218	10.0454	0.1110
March 1991	26.6358	19.2009	35.0742	11.9658	0.1408
%Appreciation (+) Depreciation(—)					
of March 1991 over March 1990	(+16.29)	(+10.80)	(+20.68)	(+16.05)	(+20.14)
June 1990	22.9224	17.4206	29.7858	10.3484	0.1133
June 1991	27.7722	21.0053	34.6572	11.7874	0.1504
Appreciation(+); Depreciation(—) of June 1991 over June 1990	(+17.46)	(+17.07)	(+14.06)	(+12.21)	(+24.67)
<b>C. Exchange Rates as on</b>					
March 31, 1989	20.2082	15.6630	26.40	8.2764	0.118
March 30, 1990	22.4090	17.3248	28.30	10.2118	0.1104
March 29, 1991	26.3457 <sup>(a)</sup>	19.6429	34.10	11.4784	0.1391
June 29, 1990	23.1820	17.5439	30.50	10.5180	0.1145
June 28, 1991	27.8550	21.0410	34.36	11.7390	0.1523
July 1, 1991	30.3402	23.1215	37.48	12.7613	0.1678
July 3, 1991	33.8930	25.9532	41.59	14.1569	0.1871

(a) As on 28-3-91

Note : Figures in brackets indicate % appreciation (+) / depreciation (—) of the Rupee.



appropriate level consistent with the need to maintain the competitiveness of our exports.

10.44 During 1990-91 (April-March) the Rupee-Sterling rate was adjusted 282 times vis-a-vis 252 such adjustments recorded during the corresponding period of 1989-90. During April-June 1991, these adjustments stood at 91 as against 55 in the preceding corresponding period.

10.45 Between end-March 1990 and end-March 1991, the Rupee depreciated against all major currencies, the depreciation being maximum against the Japanese Yen (20.6 per cent), followed by the Pound Sterling (17.0 per cent), the US dollar (11.8 per cent) and DM (11.0 per cent).

10.46 During April-June 1991, the Rupee depreciated by 6.6 per cent against the US dollar, by 8.7 per cent against the Japanese Yen, 2.2 per cent against the Deutsche Mark and 0.8 per cent against the Pound Sterling. As against the SDR, the Rupee depreciated by 14.9 per cent on a point-to-point basis between end-March 1990 and end-March 1991 and by 16.3 per cent on a monthly average basis during 1990-91 (Table 10.14). During April-June 1991, the Rupee depreciated further by 5.4 per cent on a point-to-point basis.

#### Rupee-Rouble Exchange Rate

10.47 The Rupee-Rouble exchange rate, applicable for settlement of credit and commercial transactions, was changed seven times during the year 1990-91 (April-March), i.e., on May 5, August 3, September 3 and 24, 1990, January 25, February 11 and March 22, 1991. As a result, the Rupee depreciated by 14.9 per cent from Rs. 19.92 per Rouble at end-March 1990 to Rs. 23.40 per Rouble at end-March 1991. With further revisions of the rate on April 20, 1991, and June 1, 1991, the Rupee depreciated by 3.0 per cent each time from Rs. 23.40 per Rouble at end-March 1991 to Rs. 24.13 on April 20, 1991 and further to Rs. 24.87 on June 1, 1991. Subsequent to the sharp adjustment in the Rupee's exchange rate vis-a-vis the major currencies in July 1991, the Rupee-Rouble rate was also adjusted to Rs. 26.73 per Rouble on July 4, 1991, and to Rs. 29.94 per Rouble on July 6, 1991. The rate was revised further to Rs. 30.839 per Rouble with effect from August 17, 1991, implying a 24.1 per cent depreciation of the Indian currency vis-a-vis the Rouble since end-March 1991.

#### International Economic Developments

10.48 India's external payments crisis to an extent reflected the difficult international economic scenario. The third oil shock emanating from the Gulf crisis, which brought about a sharp rise in the price of oil, was the most important development affecting the international economic environment in 1990-91. It was superimposed on an already difficult situation with a slow-down in economic growth in both industrial and development countries. The energy-related adjustments already carried out by the developed countries in response to the earlier two oil shocks helped them to tide over the crisis relatively more easily than the developing countries, which have

experienced high import bills on account of oil, disruption of exports and remittances and the human problem of resettlement and rehabilitation of the workers returning from the Gulf region. The growth of the world economy decelerated from 3.3 per cent in 1989 to 2.1 per cent in 1990. The growth of industrial countries declined to 2.6 per cent in 1990 from 3.3 per cent in 1989 and that of developing countries from 3.1 per cent to 0.8 per cent.

10.49 The volume of world trade is estimated to have grown by 4.6 per cent in 1990 in contrast to an increase of 7.2 per cent in 1989 mainly due to a decline in output growth and, in particular, the weak growth of fixed investment, a component of demand which is relatively trade-intensive. The growth in export volume of industrial countries declined from 6.8 per cent in 1989 to 5.9 per cent in 1990 and in import volume from 7.6 per cent to 6.0 per cent. There occurred a much sharper deceleration in the volume growth of both exports and imports of developing countries from 7.1 per cent in 1989 to 3.9 per cent in 1990 in exports and imports of developing countries; from 7.1 per cent in 1989 to 3.9 per cent in 1990 in exports and from 8.3 per cent to 2.9 per cent in imports.

10.50 Real GDP in Eastern Europe and the USSR fell sharply by around 4 per cent in 1990 and is expected to fall again in 1991 to the same extent. The decline was the result of a combination of domestic and external factors, including the dislocation resulting from the dismantling of the existing economic systems, impact of events in the Middle East-short-term effects of tight financial policies aimed at dealing with high inflation, falling exports to member countries of the Council for Mutual Economic Assistance (CMEA) and disruption in oil supplies from and within the USSR. In spite of an unfavourable environment and the short-run costs of adjustment and reform, all East European countries have introduced sweeping price liberalisation measures and taken significant steps towards currency convertibility and trade reforms. As policies are still evolving, the effects of the reforms on other countries like India, which have significant bilateral trade relations with some of them, are not clear as yet.

10.51 In the recent period, international financial institutions including the World Bank and the IMF have shown keen interest in assisting the East European countries to help in their market-oriented reforms. The European Bank for Reconstruction and Development, which was inaugurated in London on April 15, 1991, has earmarked 30 per cent of its capital for equity investment in East and Central Europe. It is hoped that multilateral institutions would ensure additionality in providing assistance to Eastern Europe so that the needs of other developing countries are met without any diversion of funds.

10.52 Under the Ninth General Review of Quotas, a resolution proposing increases in members' quotas was adopted by the Board of Governors of the IMF on June 28, 1990. The total Fund quotas will increase by 50 per cent of SDR 90.1 billion to SDR 135.2 billion. The increase will come into effect after the acceptance of the Third Amendment to the

Articles of Agreement. The Third Amendment provides for suspension of voting and related rights of members that do not fulfil their obligations under the Articles.

10.53 India's quota would increase from SDR 2,207.7 million to SDR 3,055.5 million, that is, by 38.4 per cent which is somewhat higher than the rise in the Eighth Quota Review (28.5 per cent). Nevertheless, India's share in the total quota would decline from 2.45 per cent to 2.26 per cent under the Ninth Review. In terms of voting power, the decline is from 2.38 per cent to 2.22 per cent.

10.54 The Uruguay Round of multilateral trade negotiations was suspended in December 1990 without agreements on the substantive issues. Its suspension was mainly because of irreconcilable differences between the group led by the USA, on the one hand, and the European Community, on the other, on liberalisation of trade in agriculture. India wants to ensure that obligations are not imposed on the developing countries in respect of domestic agricultural policies. There is a consensus among all developing countries regarding the need to provide special dispensation for them on trade in service. Our aspect of interest to India in the negotiation is that of the possibility of export of manpower. The developed countries have been taking the stand that only managerial personnel and not artisans and unskilled persons could be covered. There is an urgent need for a successful completion of the Uruguay Round for creating a favourable international trading environment. Failure would not only prevent the achievement of larger gains from liberalisation but would also intensify protectionist pressure, aggravate existing disputes among trading partners and encourage bilateral solutions to trade problems or solutions through regional trading blocks, a particularly worrisome departure from GATT disciplines and multilateralism.

## 11. ASSESSMENT AND PROSPECTS

11.1 The Bank's Annual Reports for the past several years have been focusing on the emergence of unsustainable macro-economic imbalances as reflected in large budgetary deficits and large current account deficits in the balance of payments. The Gulf crisis came on top of this already difficult macro-economic scene. This inevitably resulted in a massive loss of foreign exchange reserves which set off a period of short-term economic crisis management in the latter part of 1990-91 and the early months of 1991-92 to ensure maintenance of India's unblemished record of meeting all international debt and payment obligations. The specific policy responses to this unprecedented economic crisis have been detailed in earlier parts of this Report. More recently, as part of a cohesive package of measures of macro-economic stabilisation and structural reforms, Government initiated steps to suitably overhaul the economic policy regime relating to the exchange rate, external trade, fiscal policy, industrial policy, the role of public enterprises, and foreign investment policy. The broad contours of the reform package already put in place during July and August 1991 have also been noted in the respective sections of this Report. This Section presents an assessment

of their implications. It also outlines certain follow-up measures and precautions needed to ensure that India's stabilisation programme and structural reforms which have been initiated with such speed and determination truly achieve the desired results.

### External Sector Issues

11.2 An aspect of the Indian economy which has been a source of major concern in the recent period relates to the balance of payments situation which has dictated the formulation of the economic agenda of the nation. The Seventh Plan period saw a widening of India's current account deficit. The ratio of current account deficit to GDP averaged 2.2 per cent during the period 1985-90, far above the figure of 1.6 per cent projected for this period in the Seventh Plan document. Despite a robust growth in exports, the current account deficit increased because of the increase in imports and a steady decline in net invisible receipts. The mode of financing the current account deficit also changed over time as a result of the decline in concessional assistance available to India and its becoming a smaller and smaller proportion of the total external aid. Past Annual Reports of the Reserve Bank have dealt in detail with the various causes for the difficulties faced in regard to our balance of payments position. The already difficult balance of payments situation was exacerbated in 1990-91 by a sharp rise in oil prices and by other effects of the Gulf war. During 1990-91, the cost of imports of POL products rose by US \$ 2.2 billion. Out of the merchandise deficit of \$ 5.9 billion in 1990-91, \$ 5.4 billion (or over 90 per cent) was due to oil and petroleum products. The volume growth of exports, which averaged around 10 per cent per annum during 1986-87 to 1989-90, also came down substantially reflecting partly the unstable economic conditions in Eastern Europe and the problems in the Middle East. Access to commercial borrowing too became difficult because of perceptions of lenders abroad about the Indian polity and economy, coming on top of a general stringency faced by the larger international banks. As a result of all these, during 1990-91, the level of foreign currency assets declined from US \$3.4 billion in March 1990 to US \$ 2.2 billion by the end of March 1991 despite the drawal of US \$ 1.8 billion from the IMF. The decline of reserves was both the cause and result of a reduced inflow of FCNR deposits during the year as also of an unwillingness on the part of normal banking channels to provide renewal of short-term credit to Indian banks abroad. In the current financial year there was a further sharp decline in the foreign currency assets, stood at a critical level of US \$ 1.2 billion at the end of April 1991, and any further loss in the reserves had to be immediately stemmed. While the current account deficit in 1991-92 may be expected to go down in absolute terms to the levels reached in 1989-90 or 1988-89, the immediate concern has been that for even this lower order of financing it is difficult to arrange resources from normal inflows. With the drying up of some of the sources of financing, more particularly commercial borrowings both short-term and medium-term, immediate measures had to be put in place to ensure a severe compression of

imports so that the commitment to scrupulously honour India's all external financial obligations was fully met. Furthermore, exceptional financing had to be sought from bilateral donors, the IMF, the World Bank and the Asian Development Bank. Gold transactions also provided bridge finance.

11.3 In this effort to contain import growth, monetary and credit policy had to bear more than its usual share of responsibility. Although monetary policy is usually framed against the background of recent trends in money supply, prices and output, in the current financial year monetary policy responses have been framed almost exclusively against the background of a difficult balance of payments situation. There was some moderation in monetary expansion in 1990-91 but it was essentially a consequence of the substantial drawdown of the foreign exchange reserves during the year. There was, however, a sharp increase in prices, part of which was accounted for by the increase in oil prices. As previous Reports of the Bank have pointed out, it would be incorrect to relate the increase in prices in any particular year only to the change in money supply in that year. Because of the various lags that operate in the system, these are relationships that hold good only over a period of time. Consistent with the expected slowdown in the growth of GDP in 1991-92 and the need to moderate the inflation rate, the stance of monetary policy would, in any case, have been one of restraint: the difficult balance of payments situation made it even more compelling. The credit policy for the first half of the year announced on April 12, 1991 raised the rate of interest on bank deposits of maturity of three years and above by one percentage point to a historically high level of 12 per cent and simultaneously the minimum lending rate for large borrowers was also raised by one percentage point to 17 per cent. The incremental non-food credit-deposit ratio excluding exports was fixed at 45 per cent. Subsequently, an incremental cash reserve ratio of 10 per cent was imposed in addition to the average ratio of 15 per cent. A limit was also set on the amount of drawing that large borrowers can make during the first half of the year. Along with these measures, certain other steps directly aimed at import containment and accelerated export realisation were also taken. Cash margins were prescribed with respect to the imports of certain categories. These margins now range between 50 and 200 per cent: however, imports related to exports have been given a concessional treatment and there is an exemption from cash margins in general against such imports. The cost of import finance was increased with the imposition of a 25 per cent interest rate surcharge while the rates of interest of post-shipment export credit beyond 90 days were also increased sharply to accelerate export realisation. Even while imposing tight monetary controls, care has been taken to see that the export efforts are not adversely affected. It is for this reason that in the case of imposition of cash margins, imports meant for exports have generally been excluded from the restriction. Even with respect to overall credit measures an exception has been provided in the case of exports. The restriction on the incremental non-food credit—deposit ratio is now to be calculated after excluding export credit.

11.4 The totality of these measures broadly fall into two categories. One set of measures is directly aimed at import containment. At a time when the balance of payments situation is difficult the need for such measures is perhaps widely recognised. While imports required for exports have been given a special treatment, these measures quite clearly are intended to discourage imports. Measures such as imposition of cash margins and higher interest rates on import finance are seen as non-discriminatory ways of containing imports. The second set of measures stemming from a restrictive monetary policy is also prompted by the need to contain the current account deficit in the balance of payments. Perhaps, sometimes the need for such a policy is not fully perceived. In macro-economic terms the current account deficit which implies an excess of import of goods and services over exports of goods and services means that a country is spending more than it is producing. Therefore, for a given level of income unless the absorption is reduced i.e., expenditures are brought down, it is not possible to bring down the balance of payments deficit. Reducing the absorption essentially means reducing the overall monetary demand in the system. The reduction in the overall monetary demand does not, however, immediately translate itself into an improvement in the balance of payments situation. It has to work through several links in the system and would depend upon such parameters as marginal propensity to import out of income. To some extent measures aimed at restraining the aggregate expenditure may also affect production. While efforts should be made to minimise such adverse effects, the overall compulsion to contain expenditures cannot be avoided until the balance of payments moves to a more sustainable level.

11.5 For reasons discussed in earlier sections of the Report, the growth of exports sharply decelerated in 1990-91 while the pressures on imports increased. In the coming two years, the rate of export growth can be expected to once again reach the levels achieved during the previous 3-4 years while the growth of imports would have to be moderated. The exchange rate adjustments, the reforms in trade policy and industrial policy, and the containment of the fiscal deficit would have a salutary effect on the balance of payments. To the extent all these measures have their full effect, the medium-term objective could be to bring about a reduction in the current account deficit as a proportion of GDP from an estimated 2.5 per cent in 1990-91 to around 1.8 per cent in 1992-93 and further to 1.5 per cent by 1994-95. With this medium-term adjustment in place, the current account deficit would be sustainable as it would then be financed by normal capital flows including multi-lateral and bilateral assistance, a reasonable level of external commercial borrowing and non-debt creating resources such as equity. Obviously, over the long run, only export growth at a rate fast enough to leave a surplus over imports can help repay these loans and sustain a higher rate of growth of the economy.

#### Stabilisation Measures

11.6 In early July 1991, the authorities introduced a cohesive package of stabilisation measures. As

part of the policy to rectify the external payments imbalance the exchange rate of the rupee was adjusted downward in two stages on July 1 and July 3, 1991. The cumulative downward adjustment in terms of US dollars was a little less than 18 per cent. The correction of the current account deficit to levels that can be sustained by normal capital flows has become imperative. Downward adjustment of the exchange rate of the rupee is one of the instruments among others which are necessary pre-conditions for bringing about this correction. A situation of continuing depletion of foreign exchange reserves generates destabilising market expectations. In the immediate short run the exchange rate adjustment should help to reverse the market expectations and thereby stem the outflow of capital in the first instance and later encourage inflow. Over the short and medium-term the downward adjustment should also lead to an improvement of the country's international competitiveness and thereby help to correct the imbalance in the trade and current account deficit. The adjustment in the exchange value of the rupee raises the relative prices of traded goods (by increasing the domestic price of foreign currency) to non-traded (or home) goods, thereby encouraging production of tradable while discouraging the consumption.

11.7 The real exchange rate of a currency which is the nominal exchange rate adjusted for the relative change in prices in the respective countries is a proxy for a country's degree of competitiveness in world markets. As indicated elsewhere, the real effective exchange rate of the rupee in the more recent period had begun to appreciate. In fact, with respect to 26 of our trade competitors, the real effective exchange rate of the rupee appreciated for a long time—by over 20 per cent between 1979—1986. It is only from 1987 that the rupee has been depreciating in real terms compared to these countries and by 1989 India was just back to roughly the same real exchange rate as prevailed in 1979. As against this, many of India's trade competitors made substantial exchange rate adjustments over the past few years. China and Indonesia, for instance, have depreciated their currency against the US \$ more than India has, despite lower inflation. Over the period end-December 1980 to end-December 1989, China depreciated by 68 per cent and Indonesia by 65 per cent while India depreciated by only 53 per cent against the US dollar, whereas the increase in consumer prices in China and Indonesia were lower at 100 per cent and 111 per cent, respectively, against India's 114 per cent over the same period. To restore the competitiveness of our exports and in general to bring about a reduction in the trade and current account deficits, a downward adjustment of the rupee had become essential. In determining the extent of adjustment four relevant factors had to be borne in mind:

- (1) differentials in the price levels between India and the major industrialised countries,
- (2) extent of real depreciation of the currencies of the countries competing with India,
- (3) the degree of correction required in our balance of payments, and

#### (4) market expectations.

Taking all these factors into account, the depreciation of the rupee value by 18-19 per cent seems appropriate.

11.8 In the immediate shortrun, exchange rate adjustment should facilitate the realisation of outstanding export receipts and accelerate in general the inflow of remittances by quelling the destabilising market expectations. With some time-lag it should improve the balance of trade by stimulating the growth in exports, and by curbing increase in imports. Along with the exchange rate adjustment a complementary set of policies needs, to be put in place which will facilitate expansion of output particularly for exports. This is precisely what has been done.

11.9 For the depreciation of the currency to become truly effective, it is necessary to ensure that the domestic prices do not rise to wipe out the price advantage provided by the depreciation. Following the exchange rate adjustment, there was a further tightening of monetary policy measures, namely, a simultaneous one percentage point increase in the Bank Rate, term deposit rates and the lending rate for large borrowers and appropriate increases in the Reserve Bank refinancing rates. The recent restrictive monetary policy measures would enable a reinforcement of earlier monetary policy measures to control inflation by enabling banks to raise more resources, reduce the pressure of demand for credit and reduce reliance on created money. These measures would also bring about greater financial discipline, improve productivity and control inventory build-up; as such, they would buttress the exchange rate policy measures taken to achieve a speedy adjustment of the external payments imbalance. While the package of stabilisation measures will take some time to have an effect on the foreign exchange reserves, given the need to manage the current liquidity requirements and to build additional foreign exchange reserves, external financing of the order of \$ 3 billion needs to be arranged in the current financial year. It is for this reason that a programme is being negotiated with the IMF and the World Bank so that the economy has the wherewithal to undertake reforms without undue disruption in the immediate ensuing period.

#### Longer Term Policy Reforms

11.10 A major rationalisation of the trade policy regime has been introduced under which export subsidies have been abolished and replaced by a comprehensive scheme of import replenishment and entitlements at a uniform rate of 30 per cent linked to export earnings. The trade regime was further liberalised with higher rate of 40 per cent Eximscrip entitlements for high value-added and other products and decanalisation of export-import items. These are significant steps in moving away from a regime of quantitative restrictions. The new industrial policy sets out a series of significant policy initiatives in relation to industrial licensing, foreign direct investment, foreign technology agreements, public sector policy and MRTP Act. The basic thrust of the policy is to free industries from controls which inhibit decision making on business principles and let the entre-

preneurs make investment decisions on the basis of their own commercial judgements.

11.11 Against the background of the procedural and policy changes introduced since the middle of the 1980s coinciding with the beginning of the Seventh Five Year Plan, the new initiatives both in trade and industrial policy areas constitute a quantum jump in freeing the system from regulations and controls and allowing entrepreneurial energies a free play in their productive endeavours. Thus, both in content and significance, the new initiatives are truly far-reaching. In encouraging foreign investment, the aim is to secure for the country the attendant advantage of technology transfer, marketing expertise, sophisticated managerial techniques and strong export possibilities. The modifications in relation to foreign investment have to be viewed in the context of the changing global scenario marked by mobility of capital. As the fetters relating to expansion are being removed there will undoubtedly be problems of transition. However, Indian industry must learn to live in a competitive environment, both domestic and global.

#### Fiscal Correction and Monetary Policy

11.12 The link between fiscal policy and monetary policy is very close in the Indian situation. The major factor leading to the expansion of reserve money and, therefore, money supply has been the net Reserve Bank credit to Government. So long as the Budget deficit remained large, the ability of the Reserve Bank to contain monetary growth was limited. It could at best set limits on the secondary expansion through such instruments as changes in the cash reserve requirement. It is for this reason that the Committee to Review the Working of the Monetary System recommended a system of monetary targeting which could bind both the Government and the Reserve Bank to annual targets in monetary expansion consistent with the increase in real output and the acceptable order of increase in prices.

11.13 Large budget deficits and, more particularly, large revenue deficits have almost become endemic in the Indian fiscal system. Reliance on borrowing has led to rapid accumulation of debt and concomitantly to increase interest burden. As net interest payments as proportion of revenue receipts rise, less out of current revenue is available for other expenditure including capital expenditure. The need to bring down the fiscal deficit has become all the more imperative in the context of the deteriorating balance of payments situation. The Union Budget for 1991-92 presented on July 24, 1991 has made a serious effort to initiate a process of fiscal adjustment and macro-economic stabilisation. The reduction of the gross fiscal deficit from Rs. 43,331 crore (8.4 per cent of GDP) in 1990-91 to Rs. 37,727 crore (6.5 per cent of GDP) in 1991-92 would be a major contribution to the rectification of the macro-economic imbalance. Equally, and in fact more importantly, the reduction in the conventional deficit from Rs. 10,772 crore (2.1 per cent of GDP) in 1990-91 to Rs. 7,719 crore (1.3 per cent of GDP) should help to moderate money supply growth. It is imperative to ensure that the deficit remains within the budget levels through an appropriate monitoring of revenues and expenditures. In the

recent period a recurring feature has been that actual deficits have turned out to be much higher than the budgeted deficits. To the extent there is any shortfall in revenue it will have to be compensated by a combination of appropriate measures of expenditure reductions and resource mobilisation.

#### Financial Sector Issues

11.14 In recent years, there has been substantial growth and diversification in the Indian financial system. The financial market, from the short-end to the long, is developing into a continuum. A process of gradual liberalisation has been initiated in the banking industry to impart greater flexibility to its operations. There has been a relaxation of interest rate regulations and an easing of operational constraints in the credit delivery system. The banking system is, however, subject to a number of constraints, both in respect of liabilities and assets. Sector specific lending at concessive rates of interest, and large pre-emptions under the reserve requirements have put severe pressure on the profitability of the banking system. A few of the policy constraints on bank profitability have been relieved, to some extent, by the major rationalisation of lending rates and revision of service charges.

11.15 Profitability of the banking system; however, continues to be under strain because of the large and growing number of sick industrial units. Timelines of recovery is important, court proceedings for enforcement of bank claims take many years to settle. Establishment of special tribunals to deal expeditiously with the large claims of banks and other financial institutions would greatly alleviate this problem. This needs to be expedited. There have also been severe problems of recycling of funds advanced to the priority sectors. In the recent period, the problem has been accentuated by the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme which offers waiver of overdues under both production and investment credit, subject to specified criteria; this has resulted in a major setback to the general environment of recovery of dues. While there are time-tested procedures for affording relief to borrowers affected by natural calamities, across-the-board loan and/or interest waivers have seriously impaired credit discipline. This discriminates against those who repay their obligations and also damages the health of the credit institutions. The recent experience has been one of a virtual cessation of recovery and also a consequent tendency towards cessation of lending. Such a situation cannot but inflict irretrievable damage to the financial system especially insofar as it caters to agriculture and rural credit. It is, therefore, necessary to take steps to restore normalcy in the rural credit system.

11.16 With a view to improving the overall efficiency of banking operations, multi-pronged action programmes have been evolved and put in place. First, having achieved a fairly wide and adequate network of bank branches in various parts of the country, the banking industry has entered a period of consolidation and future branch expansion will be allowed where the need and business potential, as also financial viability of proposed offices, will be clearly established.

Secondly, there has been emphasis on strengthening the capital base of banks. Thirdly, with a view to greater transparency of accounts and operations, the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949, is being amended. While the revised formats of Balance Sheet and Profit and Loss Account of banks are yet to become effective, banks have been advised to disclose the accounting policies regarding key areas of operations in their financial statements for the accounting year ended March 31, 1991 and onwards. Fourthly, banks have been advised to adopt prudent accounting practices by avoiding inflation of income through the inclusion of interest, which is not likely to be realised. Finally, in view of the need to fix prudential norms for risk management, the Reserve Bank has prescribed limits on exposure to an individual business concern at 25% and to business concerns of a group at 50 per cent of a bank's capital funds. The exposure includes funded and non-funded limits though the weights attached are different. The issues thrown up by the imposition of these ratios, when banks' equity is rather low in relation to their clients' borrowing requests, are being gone into in the context of the wider question of the increase of banks' capital.

11.17 The emergence of new institutions like mutual funds with wholesale financing schemes and lean staff complement are posing severe competition to banks. While it is necessary that the diversification of the financial structure progresses and some disintermediation would be inevitable, the question essentially is whether banking operations would continue to face a situation of uneven playing fields, or should conditions be created for level-playing fields. The banking system is still a major constituent in the financial system and by far the predominant part of financial savings is mobilised by the banking industry and in fact, no institutional system can match the large network of branches with a wide range of services which the commercial banks in India provide. The issue is not that other newer institutions should not be allowed to grow but what steps would need to be taken to improve efficiency and viability of the banking system. The relative position of banks and other financial intermediaries needs to be reviewed and the guidelines set out by different authorities rationalised. It is in this context that the role of different regulating authorities would have to be carefully examined. While arm's length operations is a salutary principle, in practice the operations of banks and their subsidiaries are intertwined and, therefore, the need for consolidated supervision is well recognised the world over. Likewise, the oversight of financial companies (leasing and hire-purchase companies, loans and investment companies, etc.) which are growing rapidly has to be strengthened; in particular, a strengthening of the legislative framework for depositor protection is necessary. The supervising authority should be empowered to take corrective measures well before these financial companies default on their deposit liabilities. In this context, it is necessary to provide for statutory powers to ensure strengthening of capital and reserves of financial companies.

11.18 Against the background of the fiscal adjustment that is being undertaken, it would be necessary to critically review the operation of the statutory liqui-

dity ratio of banks. As fiscal deficits decline, it should be possible to take a fresh look at the present levels of pre-emptions.

11.19 Priority sector lending has now broadly attained the correction which was sought to be achieved in the imbalance between the sectoral output and sectoral credit availability. With the attainment of these targets there is a need to examine how priority sector lending can be made more effective and more sharply focused taking into account the societal concerns for assisting the weaker sections.

11.20 Another major issue which needs to be addressed is interest rate policy. In the recent period interest rates have been actively used as an instrument of aggregate demand management. The lending rates of banks and money market rates have been admittedly high in the recent period but such high interest rates have been necessary as the endeavour has been to bring about a quick monetary correction. As monetary expansion and inflation come down to more moderate levels, it would be reasonable to expect reduction in nominal rates of interest particularly those which have risen very sharply in the recent period.

11.21 While a significant element of deregulation has been undertaken in terms of the freeing of lending rates of banks and institutions to large borrowers, money market rates and debenture rates, there are a number of other areas where interest rates are regulated such as those on government securities, bank deposits, priority sector lending and company deposits. Interest rates should inter se reflect maturity risk and liquidity of different instruments and the level of interest rates should reflect the scarcity of capital. A flexible interest rate policy which is responsive to the overall liquidity position would, eventually, lead to low nominal interest rates as inflation rates come down. It would, therefore, be useful to undertake a total review of the interest rate structure to achieving more efficient use of resources in the economy. These and other issues such as those relating to organisation and structure of the financial system are to be reviewed by the High Level Committee set up by the Government of India. The findings of the Committee would facilitate decisions on financial sector reform.

#### Growth Prospects and Stance of Monetary Policy

11.22 The reform measures already undertaken and those under way will have far reaching consequences on the growth process and the growth profile. In the short-run, the process of readjustment would necessarily imply a slowdown in overall growth, particularly in those sectors of the economy heavily dependent on public sector subventions and those based on large public sector demand. All indications point to a reduction in growth rate of major sectors of the economy in 1991-92. The progress of the 1991 South West monsoon so far has been satisfactory except in meteorological division in Uttar Pradesh, Haryana Rajasthan and Saurashtra. On the whole, agricultural production may increase by about one percentage point in 1991-92 which could be considered as a relatively satisfactory performance as it would come on top of three years of sustained agricultural growth. As for the industrial sector, there would necessarily



be some slowdown in the growth rate during 1991-92. General import compression, credit restraint both with stepped-up cost and reduced availability and reduction in public expenditure and investment programme could all result in some slowdown in industrial growth. While such industries like food processing and other agro-based segments, which have a large weightage in the index of industrial production, may not be affected by import compression, some of the manufacturing industries like fertilisers, electronics and computers, mini-steel plants and plastic goods, which have a relatively high import content, would face subdued growth during 1991-92. Also, a large number of industries which are dependent on demand from public sector would also show some decline. Overall, it is expected that the industrial sector as a whole may achieve a growth rate of about 6 per cent during 1991-92 against 8.4 per cent during 1990-91. Against the backdrop of the difficulties faced by the economy, a GDP growth rate of 3 per cent in 1991-92 (as compared with 5.0 per cent in 1990-91), if achieved, should be considered as a very satisfactory performance.

11.23 Against the background of a decline in the growth rate and the compulsions arising from the balance of payments situation, the stance of monetary policy cannot be but one of continuing and perhaps increased tightness. If the various policy initiatives introduced in the recent period are to bear fruit, there has to be a moderation in price increases. While depreciation of the rupee by itself can exert some upward pressure in prices through increased cost of imported inputs, other measures such as reduced budget deficit and slower rate of growth in money supply should help in keeping aggregate monetary demand under check. The task of monetary policy in 1991-92 is quite clearly one of containment of inflation. While within the available credit some preference for specific sectors such as exports may have to be worked out, the present tight monetary policy can be reversed only when there is a significant improvement in the balance of payments situation and strong inflationary pressures have begun to slow down.

## PART II—BANKING AND OTHER DEVELOPMENTS

### 12. HIGHLIGHTS

12.1 Part II of this Report deals with the operational aspects of banking developments and the Reserve Bank's own operations including organisational matters and accounts.

12.2 The highlights of these developments are :

- (i) Specific attention of the commercial banks has been drawn to augment their profitability and strengthen their financial base. Towards this end, they have been advised inter alia to observe prudent accounting standards and guidelines for classification of advances under appropriate Health Codes.
- (ii) To make the financial statements more transparent, necessary amendments to the Banking Regulation Act, 1949 have been propo-

sed and in the meantime, the scheduled commercial banks (excluding RRBs) have been advised to disclose the accounting policies regarding key areas of operations at one place along with notes on accounts in their financial statements for the year ended March 31, 1991 and onwards.

- (iii) Banks have opened 275 branches during the period July 1990 to March 1991, bringing the total number of branches to 60,101.
- (iv) Two banks have been given final approval to set up separate subsidiaries for undertaking factoring business.
- (v) A committee has been set up under the chairmanship of Shri M. N. Goiporia, Chairman, SBI, to study the current state of customer service in banks.
- (vi) The Union Finance Minister, in his Budget Bank for extending reliefs/concessions beyond the prescribed parameters for the rehabilitation of potentially viable sick units in the small-scale (SSI) sector has been withdrawn.
- (vii) Under the Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990, debt relief to the extent of Rs. 7,917 crore have been provided by the public sector banks, regional rural banks and co-operative banks.
- (viii) The Union Finance Minister, in his Budget speech in July 1991, announced the appointment of a high-level committee under the chairmanship of Shri M. Narasimham, a former Governor of the Reserve Bank, to consider all aspects of structure, organisation, functions and procedures of the financial system.
- (ix) The Reserve Bank has decided to appoint a Committee headed by Shri S. S. Marathe, a member of the Bank's Central Board, to review the present policy in regard to setting up of new primary co-operative banks (PCBs) and other related issues including conversion of Societies into PCBs.
- (x) With a view to bringing about better co-ordination within the financial system, the Reserve Bank has set up a nodal unit called the Financial Institutions Cell.
- (xi) During the period under review, permission has been granted to introduce new schemes of deposits, India Funds, and NRI bonds with a view to raising funds abroad and providing further incentives and wider options to non-resident Indians.
- (xii) A decision has been taken in principle to bring out a new set of coins and notes following the programme to coinise fully Re. 1, Rs. 2 and Rs. 5 notes in a phased manner by 1995.

- (xiii) The Reserve Bank's income, after making adjustments for various provisions, increased by 4.5 per cent to Rs. 4,625 crore during 1990-91 and the net disposable income to Rs. 1,345 crore from Rs. 1,170 crore in 1989-90. After making higher contribution to statutory funds, the surplus transferred to the Union Government was raised from Rs. 210 crore in 1989-90 to Rs. 350 crore 1990-91.

### 13. DEVELOPMENTS RELATING TO COMMERCIAL BANKS

#### Action Plans for Bank : 1990-91

13.1 The Action Plans drawn up by the commercial banks from April 1990 to March 1992 are being implemented by them. Considering the utmost need for augmenting their profitability and strengthening their financial base, banks have been advised to observe prudent accounting standards and guidelines for classification of advances under the prescribed Health Codes as also to stop the application of interest on advances classified under Health Code No. 5 besides those under Code Nos. 6 to 8 @. Banks have been advised to improve their volume of business, to concentrate on effecting quicker recoveries of their dues, ensure efficient management of funds by exploring new avenues of income, control expenditure effectively and reduce the incidence of bad debts. Banks have also been advised to work out detailed strategies for improving their profitability keeping in view the need for generating higher profits so that the existing provisions could be augmented adequately to cover the estimated loan losses and other contingencies. Towards that end, banks were told to reduce the quantum of stick and non-performing advances in a time-bound manner and take effective steps to ensure that the quantum of sticky advances was contained at a much lower level. Smaller banks have been advised to consider reverting to a 3-tier organisational structure from the present 4-tier, in the interest of saving costs as well as for improving the speed and effectiveness of the decision-making process. More importantly, banks have been advised to devote continuing attention to improving the branch-level performance, upgrading unsatisfactory branches as well as developing model branches.

#### Branch Expansion

13.2 With the branch licensing policy 1985-90 coming to an end on March 31, 1990, the policy guidelines for future branch expansion have been finalised. The validity period of the licences issued under the 1985-90 policy in rural/semi-urban areas, which could not be utilised before March 31, 1990, was extended by a year to March 31, 1991 and further to March 31, 1992 to enable banks to fully utilise their pending licences.

@ These Code specifications are :

Code 5 : Advances recalled

Code 6 : Suit filed account

Code 7 : Decreed debts

Code 8 : Bad and doubtful debts.

13.3 As per the new guidelines for branch expansion, (a) fresh branches in rural areas will be considered in cases where the Service Area allocated to a particular branch is unmanageable and where there is a large spatial gap or if the increased volume of business of a rural branch warrants opening of an additional branch; (b) in semi-urban centres, branch expansion will be considered on the basis of well-established need, depending upon growth in trade and industry, increase in other economic activities and viability of the proposed branch; (c) the criteria in respect of industrial/project areas have been clearly spelt out wherein the opening of bank branches will be considered with reference to the immediate need and outlay on projects, etc; and (d) in urban and metropolitan/port-town centres, the identification of unbanked/underbanked/localities in such areas has been entrusted to small working groups, consisting of inter alia the representatives of major commercial banks and under the convenorship of the Reserve Bank's concerned Regional Office. The Reserve Bank is in the process of allotting the identified localities in these centres to various banks on the basis of certain norms.

13.4 Under the new policy, the procedure for allowing Extension Counters has been simplified. Accordingly, instead of the requirement of prior approval by the Reserve Bank, each bank has been allowed to open Extension Counters in a particular year (April-March) up to 2 per cent of its total number of urban and metropolitan branches as at the end of the previous year provided the stipulated norms were satisfied. Keeping in view the priority accorded to the development of housing as also to achieve greater professionalisation, it was recognised that there was a need for the establishment of specialised branches for exclusively catering to the requirements of housing finance. Such specialised branches may initially be restricted to urban and semi-urban areas and the scheme will be eventually extended to rural areas. With a view to improving the operations of odd and unremunerative branches of banks consistent with social objectives, banks have been given the freedom to swap such branches with other banks.

13.5 During the period July 1990 to March 1991, 275 bank branches were opened. Out of 60,101 branches of commercial banks (including RRBs) operating as on March 31, 1991, 35,113 were in rural centres constituting 58.4 per cent of the total. The average population per branch office improved further during 1990-91; the ratio declined to 11,000 at the end of March 1991 from 11,600 as at the end of March 1990.

#### Indian Banks Abroad

13.6 The number of overseas branches of nine Indian banks operating abroad stood at 115 and the number of representative offices at 11. Besides, the Indian banks had six wholly-owned subsidiaries (including three deposit-taking companies) and seven joint-venture banks abroad.

#### Foreign Banks in India

13.7 Licences were issued to four foreign banks to open branches in India. Sanwa Bank Ltd. and Barc-



lays Bank p.l.c. have opened their maiden branches in New Delhi and Bombay, respectively, by upgradation of their representative offices. With the opening of these two branches, the number of foreign banks having branches in India increased to 24 and their total branches to 140 as at the end of March 1991. During the year 1990-91 (up to March 1991), three foreign banks, namely, NMB Post Bank Group, Fuji Bank Ltd., and Institute Bancareo San Paolo Dito-rient, opened one representative office each in India. With this, as also the closure of two representative offices on account of their conversion into branches, the number of representative offices regional rural Banks.

13.8 The number of Regional Rural Banks (RRBs) at 196 covering 369 districts remained unchanged during the year and their total number of offices was 14,497. Total outstanding deposits and advances of all RRBs amounted to Rs. 4,419.35 crore and Rs. 3,501.84 crore, respectively as at the end of December 1990. The working of the RRBs was, however, not satisfactory and as many as 162 RRBs had accumulated losses of Rs. 282 crore as at the end of March 1990.

#### Service Area Approach

13.9 The Service Area Approach (SAA) has been in operation since April 1, 1989. The outlay earmarked in the credit plans under SAA has been enhanced from Rs. 15,590 crore in 1989-90 to Rs. 17,190 crore in 1990-91; it has been stepped up in all the three sectors; agriculture, industry and services. The all-India sector-wise credit disbursement targets and actual achievements are as indicated below :

Sector	1989-90		1990-91
	Target	Achievement	Target
1	2	3	4
Agriculture	10,371	9,270	11,615
Industry	2,643	2,392	2,805
Services	2,576	2,441	2,770
Total	15,590	14,103	17,190

13.10 A review of the functioning of the Block-Level Bankers' Committees constituted under SAA has revealed certain inadequacies in their functioning. Thus, enough importance has not been attached to issues such as recovery of loans, provision of infrastructural facilities and on linkages for making credit more productive, etc. The Reserve Bank has initiated necessary steps for taking remedial action.

13.11 The Reserve Bank has issued revised guidelines on credit planning and monitoring under SAA which have come into force for the Credit Plan period beginning from April 1, 1991. A decision has been taken in consultation with some of the major commercial banks, RRBs and co-operative banks, to computerise the data flow at the district level.

#### Banks' Assistance to Priority Sectors

13.12 The public sector banks increased their lending under total priority sector advances from Rs. 39,418 crore as at the end of March 1990 to Rs. 42,276 crore as at the end of March 1991, but the share of priority sector lending in total bank credit, though it fulfilled the stipulated target, declined from 43.2 per cent at the end of March 1990 to 40.0 per cent at the end of March 1991. This fall was noticeable in all the categories but it was more pronounced in respect of agriculture. This is a sequel to the implementation of the rural debt relief scheme.

13.13 Private sector commercial banks, which are also required to achieve various targets and sub-targets for priority sector advances, provided, Rs. 1,504 crore under priority sector as at the end of September 1990, accounting for 34.9 per cent of their net bank credit. Priority sector advances as a percentage to net bank credit in the case of foreign banks operating in India increased from 8.4 per cent at the end of March 1989 to 9.8 per cent at the end of March 1990, and 9.7 per cent as on the last Friday of September 1990. Foreign banks are required to achieve a target of 12 per cent by the end of March 1990 and 15 per cent by end-March 1992\*.

#### Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990

13.14 The Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990, which envisaged debt relief up to Rs. 10,000 to eligible borrowers of public sector commercial banks and RRBs was implemented effective May 15, 1990. The salient features of the scheme were outlined in previous year's Report. As decided by the Government of India, banks have been advised to complete the implementation of the scheme by March 31, 1991. However, in the states of Assam and Jammu and Kashmir, it has been extended up to end-June 1991. The State Governments also formulated a similar scheme for implementation in the co-operative sector. Provisional figures reported by public sector banks and NABARD indicated that debt relief to the extent of about Rs. 7,917 crore have been provided by banks, of which public sector commercial banks provided Rs. 2,962 crore, RRBs Rs. 808 crore and co-operative banks Rs. 4,147 crore.

#### Recovery of Dues

13.15 The recovery of direct agricultural advances by public sector banks, which was improving till 1988-89, showed a fairly steep decline to 46.8 per cent of demand in 1989-90 (July-June) from the previous year's level of 57.3 per cent. Likewise, in respect of the private sector banks too, there was a fall from 55.1 per cent of demand during the half year ended March 1990 to 45.8 per cent for the half-year ended September 1990. In the case RRBs the percentage of recoveries to demand declined from 48.6 per cent in 1988-89 to 33.9 per cent in 1989-90.

\* Details of the operation of individual schemes of banks' assistance for employment-generation and assetcreation, are set out in the Bank's Report on Trend and Progress of Banking in India, 1990-91.

### Accounting Policies—Need for Disclosure in the Financial Statements of Banks

13.16 Pursuant to the recommendations made by the Committee to consider Full Disclosure in Published Accounts of the Banks (Chairman Shri A. Ghosh), Government of India, as per powers conferred on them by the Banking Regulation Act, 1949, issued a notification giving notice of their intention to make amendments to the Third Schedule to the said Act, incorporating the changes/amendments in the formats of Balance sheet and Profit and Loss Accounts of banks. While the revised formats will become operative only after the amendments to the Third Schedule are made effective, the scheduled commercial banks (excluding RRBs) have been advised to disclose accounting policies regarding key areas of operations at one place along with notes on accounts in their financial statements for the accounting year ended March, 31, 1991 onwards on a regular basis.

### Capital Base of Banks

13.17 The capital base of nationalised banks has been augmented with the Government of India contributing Rs. 700 crore during 1990-91, bringing the aggregate contribution since 1985 to Rs. 2,600 crore. The authorised capital of State Bank of India (SBI) has been raised from Rs. 200 crore to Rs. 1,00 crore and its paid-up capital has also been increased from Rs. 150 crore to Rs. 200 crore.

### Inspection of Banks

13.18 During the period under review, the Reserve Bank conducted Annual Financial Reviews in respect of 28 public sector banks and 13 Local Head Offices of S.B.I. The financial inspections of 3 public sector banks, 11 private sector banks, 12 foreign banks and the State Bank of Sikkim, were undertaken during the year under review.

### Credit Relaxation in Punjab and J & K

13.19 Mention was made in the previous year's Report about certain concessions extended to bank borrowers in the States of Punjab and Jammu and Kashmir. These concessions have been further extended by one more year up to March 31, 1992.

### Financial Diversification by Banks

13.20 The commercial banks have made significant strides in their diversification activities through their subsidiaries into new areas like merchant banking, mutual funds, housing finance, hire purchase/equipment leasing and factoring services. As at the end of March 1991, 8 public sector banks and one private sector bank had been allowed to set up their equipment leasing-cum-merchant banking subsidiaries. The number of bank mutual funds remained at five as at the end of the period. In view of the increasing emphasis given to housing finance, nine banks have set up housing finance companies/subsidiaries or participated in equities of housing finance companies set up by other institutions.

13.21 During the period under review, five banks were permitted to engage in hire-purchase business through their respective merchant banking subsidiaries. Two banks were granted approval to set up separate subsidiaries for undertaking factoring business.

### Moratorium and Amalgamation

13.22 During the year under review, Purbanchal Bank Ltd., Guwahati, which was under moratorium for some period during 1989-90, was amalgamated with Central Bank of India as notified by the Government of India. The Highland Bank Ltd., Tripura State Bank of India Ltd., and Simla Banking Industrial Co. Ltd. were dissolved during the period July 1, 1990 to June 30, 1991; with this the number of banks under liquidation now stands at 121.

### Customer Service

13.23 As mentioned in last year's Report, the Reserve Bank had entrusted the conduct of surveys of customer service in banks in the four States of Gujarat, West Bengal, Tamil Nadu and Uttar Pradesh, to four professional agencies. Except the one in respect of Uttar Pradesh, the reports have been received and their findings are being analysed. As a sequel to the Union Finance Minister's Budget Speech in March 1990, the Reserve Bank set up a Committee of 14 members, representing the Reserve Bank, banks, depositors employees, the manufacturing industry and the export sector, under the chairmanship of Shri M. N. Goiporia Chairman, SBI, to study the current state of customer service in banks and to suggest measures to improve the performance of banks in this area.

### Mechanisation/Computerisation in the Banking Industry

13.24 Twenty offices of the Bank and three Government of India departments have been connected to the Store and Forward Transmission (SFT) network. Similarly, dedicated speech network connecting 19 offices has been developed and so far 17 offices have been connected and the remaining two offices of Jammu and Bhopal will be connected shortly. Also, the Banking Division (Government of India) has been connected to the Reserve Bank speech network.

13.25 The Reserve Bank is coordinating and directing efforts towards establishing BANKNET, a dedicated data communication network for the Reserve Bank and public sector banks. About 200 offices of the Reserve Bank and banks are being connected through BANKNET at seven centres viz., Bombay, Delhi, Madras, Calcutta, Bangalore, Hyderabad and Nagpur. During the year, all inter-city lines were commissioned. The Bank has started furnishing information of net local clearing position through BANKNET at some centres. BANKNET will also be used for transmitting messages relating to funds transfer, issue of draft advices for large amounts, communication of foreign exchange rates, etc.

13.26 The Reserve Bank is coordinating SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) network in India. Forty-two banks in

India including the Reserve Bank, have become members/sub-members of SWIFT. The work on installation of hardware, software, training of staff, provision of data circuits and PSTN (Public switched Telecommunication Network) lines is in progress and banks are expected to cut over to SWIFT on December 2, 1991.

13.27 At the end of June 1991, public sector banks had installed 5,190 Advanced Ledger Posting Machines (ALPMs) at about 1,700 branches, of which 4,977 ALPMs were operationalised with 4,413 on 'live' run. Banks had installed 282 mini-computers Regional/Zonal offices. Six banks had installed and operationalised mainframe computers at their respective Head Offices and several other banks are at an advanced stage in the process of installation. About 45,000 members of staff of banks were imparted training so far in computerisation/mechanisation.

13.28 Total computerisation of branch operations at one branch of each bank is under implementation and has reached an advanced stage at some banks.

#### Computerisation of Cheque Clearance

13.29 It is proposed to introduce shortly mechanised cheque processing system in the Clearing House managed by the Bank at Nagpur.

13.30 The inter-city clearing facility of cheques has been extended one-way to four more smaller centres, viz., Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad and Nagpur. The facility of clearing outstation MICR cheques to some more centres would be extended in a phased manner. The concept of 'Regional Grid' in inter-city clearing has been introduced by connecting Coimbatore to Madras.

13.31 The performance of special clearing of cheques of Rs. one lakh and above with the same-day credit to customers' accounts, introduced in all the four metropolitan cities, has been satisfactory. Settling of inter-bank transactions by the Reserve Bank cheques has been replaced by an inter-bank clearing settlement for the net amounts at six centres, viz., Bombay, Delhi, Madras, Calcutta, Ahmedabad and Hyderabad.

13.32 The report of the Expert Group constituted to review the existing Uniform Regulations and Rules for Clearing Houses in order to place the same on a statutory basis is likely to be finalised shortly.

13.33 During the year, five new Clearing Houses have been opened, raising their number to 848.

#### Credit Monitoring Arrangement (CMA)

13.34 The Credit Monitoring Arrangement (CMA) has been in operation in lieu of the Credit Authorisation Scheme since October 10, 1986, wherein banks have been authorised to sanction credit proposals of large borrowers with a requirement that the proposals

be submitted to the Reserve Bank for post-sanction scrutiny. The number of such proposals increased to 2,135 as at the end of December 1990 from 1,825 as at the end of June 1990. Total working capital limits in force relating to these proposals at the end of December 1990 were Rs. 33,698 crore, of which, the share of public sector undertakings was Rs. 16,366 crore, or 48.6 per cent. The facility-wise distribution of total limits at the end of December 1990 was 90.4 per cent for working capital purposes (including packing credit, inland and foreign bills), 9.0 per cent for term finance, and 0.6 per cent for sale of machinery on deferred payment basis.

13.35 Hitherto, under the CMA, all sanction and/or renewal of credit limits to borrowers enjoying fund-based working capital limits of Rs. 5 crore and above and/or term loan in excess of Rs. 2 crore were required to be reported by the banks (sole bank or leader of the consortium) to the Reserve Bank. On a review, it was decided to introduce, from January 1991, a system of percentage scrutiny of such proposals instead of 100 per cent scrutiny earlier. In view of the progress made by the banks in implementing the recommendations of the Tandon/Chore Committee reports to bring about financial discipline in availing of bank credit. While banks have been advised that the practice of reporting 100 per cent of sanction and/or renewal of credit limits to the Reserve Bank would continue, in view of the reduction in the level of post-sanction scrutiny undertaken by the Bank, they are expected to review their existing system to appraise proposals and to monitor bank credit and improve upon it, wherever necessary.

#### Monitoring of Accounts of Large Groups of Companies

13.36 Instances of the promoters of some large industrial groups going ahead with establishment of new units and/or expansion of existing units even while there were defaults and/or serious irregularities in the accounts of some of their existing units were noticed by the Reserve Bank. As a result, while substantial funds of banks/financial institutions were looked up in non-performing assets, some other banks/financial institutions were required to sanction additional funds for new ventures/expansion. It was, therefore, decided to monitor the accounts of large groups of borrowers on an on-going basis.

#### Revision of Inventory/Receivable Norms and other Related Issues

13.37 In the wake of the country's difficult balance of payments position, banks were advised in October 1990 to restrict the level of holding of imported raw materials to the prescribed levels or up to a period of 3.0 months, whichever was less. These norms represented the maximum levels of holding and should not be construed as entitlements in case borrowers had managed with lower levels in the past.

13.38 The policy measures restricting the drawals under large credit limits have been outlined in subsequent paragraphs of this Section. Certain relaxations were made having regard to peculiar problems faced by certain industries. Thus, although the Reserve Bank is not in favour of financing subsidy receivables

by banks, nevertheless, considering the special problems faced by the fertiliser industry, banks have been permitted to finance such receivables under the normal Retention Price Scheme (RPS) for periods up to 60 days.

13.39 In view of the accumulation of finished goods and extended receivables, with the polyester staple fibre (PSI) manufacturing units which were faced with a low demand and low capacity utilisation, the units were allowed to hold finished goods and receivables up to 3.0 months, as against the regular norm of two months, on a selective basis depending on the merits of each case, for a period up to December 31, 1990. The facility of assessing the working capital requirements under the First Method of Lending had been extended up to end-February 1991 to all textile units taken over by the NTC and State Textile Corporations, wherever they had availed of financial assistance for modernisation, etc., from IDBI/other financial institutions, so that the dependence of these units on Government funds for strengthening the capital base, etc., could be reduced. In respect of composite textile mills which continue to face the problem of stock accumulation of finished goods and extended receivables, banks were advised that they might permit the holding of stocks up to 3.5 months as against the regular combined norms of 3.0 months in respect of finished goods and receivables on a selective basis and on merits of individual cases, for a period up to September 30, 1991. The credit needs of all diamond exporters, which were allowed to be assessed under the First Method of Lending for three years upto the end of 1990, are now being assessed under the Second Method of Lending since January, 1991. After a review of the norms for the diamond industry in June 1991, it was decided to reduce the levels of holdings to 2.5 months for raw materials (including stocks-in-process), 1.0 month for finished good and 3.0 months for receivables as against the earlier levels of 3.5 months, 1.5 months and 3.0 months, respectively. The above norm of 3.5 months for raw materials, and finished goods is inclusive of the transit period of 15 days for receipt of rough diamonds in the case of DTC sight-holders. In the case of non-sight holders, the norm applicable is a maximum of 3 months.

#### Lendings to Leasing and Hire-Purchase Concerns

13.40 Banks' lending to leasing and hire-purchase concerns hitherto were not to exceed three times their Net Owned Funds (NOF) within the prescribed overall ceiling of ten times of their NOF for their total external borrowings. Later, it was clarified to banks in July 1990 that the funds raised from financial investment institutions need not be included in the ceiling of three times of NOF, which is applicable to banks, lending only. However, the hire-purchase/lease assets created out of finance from financial investment should be excluded from the build-up of assets while calculating maximum permissible bank finance (MPBF) so that the bank finance was not provided for financing such assets. It was further clarified that the Deferred Payment Guarantees given by the banks on behalf of leasing/hire-purchase companies need not be included in the ceiling prescribed for the banks' lending. Likewise, assets created against such guarantees need not also be taken into account while calculating MPBF.

#### Financing of Imports : Special Regulations

13.41 As referred to in Part I of the Report, the rapid deterioration in the country's external payments situation called for special attention to issues concerning short-term management with the primary objective of conserving free foreign currency reserves. Towards this end, a series of measures relating to bank finance for imports were introduced which sought to restrain imports to essential levels and reduce the importers' dependence on free foreign exchange for import of capital goods. In response to the rapidly changing situation, the Bank's policy measures, which began in September 1990, have had necessarily to be frequently widened, strengthened and modified in scope and coverage. These measures are summarised below.

#### Import of Capital Goods

13.42 Banks were advised on September 11, 1990 that importers of capital goods under OGL or under a specific import licence should be asked to approach the term-lending institutions for their foreign currency loan requirements. Should the banks for any compelling reasons provide credit for such purposes, they should charge 0.5 percentage point higher than the rate applicable to foreign currency loans covered by the Exchange Risk Administration Scheme (ERAS). In this regard, the earlier ban on issuing guarantees to term lending institutions by banks for the loans extended by the former was removed.

13.43 Effective November 1, 1990, the banks were asked to direct all importers of capital goods, to the financial institutions. Banks were permitted to grant Rupee term loans only if such imports could not be covered under the lines of credit available with the financial institutions.

13.44 On December 24, 1990, banks were permitted to issue guarantees favouring financial institutions on behalf of small borrowers as also others located at places which have no offices of financial institutions, subject to the commercial viability of the proposals and certain other conditions.

13.45 Banks were advised that as import of capital goods from bilateral trade countries were not covered by foreign lines of credit, banks could continue to finance such imports. Banks were also advised that where importers of capital goods claimed to be in a position to meet the Rupee costs of the import from their own resources without having to obtain any term loan from banks or financial institutions, banks could provide the necessary letter of credit facility after satisfying themselves that they would not be required to grant any fund-based facility for the purpose.

13.46 On a review, banks were advised on February 6, 1991, that they could grant Rupee term loans in respect of import of capital goods in the following cases : (a) imports under Technical Development Fund Scheme administered by the IDBI on behalf of the Government of India ; and (b) import of technical know-how by existing units for modernisation and upgradation and where it was proposed not to approach financial institutions for the purpose.

13.47 In supersession of earlier instructions on import of capital goods, banks were advised on March 19, 1991, that no sale of free foreign exchange should be permitted for import of capital goods under any circumstances until further orders and that import of such goods could only be financed out of foreign currency lines of credit available with the financial institutions. For this purpose, where necessary, banks were permitted to issue guarantees beyond March 31, 1991 in favour of financial institutions in order to facilitate sanction of such loans by those institutions.

13.48 Opening of letters of credit for import of capital goods out of free foreign exchange was permissible on or before March 19, 1991, in certain specified cases. On April 25, 1991, the Reserve Bank clarified that it would be in order for banks to honour letters of credit for such imports which were opened on or before March 19, 1991, after ensuring that those were opened in conformity with the then existing guidelines.

13.49 In respect of import of capital goods not covered by letters of credit and where shipments were effected on or before March 19, 1991, banks were advised to try to cover such imports under the foreign currency lines of credit available with financial institutions. In case these imports could not be covered under the foreign currency lines of credit, sale of free foreign exchange might be effected, after having ensured that the rupee cost of imports would be met by the importer from his own resources.

13.50 Bank were advised on May 31, 1991, that import of capital goods not covered by foreign lines of credit but under suppliers' credit for one year will be examined by the Reserve Bank on receipt of certain details about the project for which the import is to be made, the sources of finance for the project, the stage of implementation, terms of suppliers' credit, export performance of the company, and in the case of a new project, the expected earning/saving of foreign exchange.

13.51 Opening of letters of credit for import of capital goods from the USSR, Czechoslovakia and Romania (during the validity period of the agreements with each of them) was permitted effective June 13, 1991.

13.52 Banks and financial institutions were permitted on July 24, 1991, to open letters of credit for import of capital goods for projects where the cost of imports would be reimbursed by international institutions like the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), the International Development Association (IDA) and the Asian Development Bank (ADB).

#### Import of Goods other than Capital Goods

13.53 Banks were advised on October 25, 1990 to maintain a minimum cash margin of 50 per cent on all imports of raw materials, components, etc., except imports relating to certain export activities as well as to the core sector of the economy. The level of imported inventory was also restricted to 3.0

months' consumption or the prescribed levels, whichever was less.

13.54 Banks were advised on November 19, 1990 that import of life saving drugs and equipments were exempt from the application of minimum cash margin requirements.

13.55 With the objective of promoting exports, banks were advised on December 24, 1990, to exempt units having to their credit exports of not less than 25 per cent of their turnover during the previous accounting year or Rs. 10 crore per annum, whichever was less, from the minimum cash margin requirement on letters of credit. Imports from bilateral trade countries were also exempted from the requirement of cash margins.

13.56 Banks were advised on January 24, 1991, to further exempt imports against Advance Licences and Advance Intermediate Licences from the requirement of 50 per cent cash margins provided such imports were strictly for self-consumption.

13.57 Exemptions from the requirement of minimum cash margins were effected in respect of import of bulk drugs, formulations and intermediates, imports made by companies holding Inland Private Bonded Warehouse Licences granted under the Customs Act, 1962, import of technical know-how and imports under suppliers' credit for a minimum period of one year on February 6, 1991.

13.58 Effective March 19, 1991, the minimum cash margins were stipulated at between 50 per cent and 133.33 per cent depending on the type of licence under which the imports, other than capital goods, were to be made and such minimum cash margins were also made applicable to imports not under letters of credit. Simultaneously, the exemption from the prescribed minimum cash margins was curtailed to the following imports only : imports by Government departments; petroleum, oil and lubricants; fertilisers; foodgrains; edible oils; newsprint; and life-saving drugs. Banks were also advised to ensure that no additionality of limits/drawing power was provided to their constituents to meet the requirement of cash margins.

13.59 The 50 per cent margin requirement on imports for own consumption made by registered 100 per cent Export-Oriented Units (EOUs), units located in Export Processing Zones (EPZs) and Free Trade Zones (FTZs) was waived effective April 1, 1991, subject to their exports being made to General Currency Area (GCA) and export proceeds being realised within a period of six months from the date of export.

13.60 Imports for own consumption against Advance and Imprest Licences were exempt, effective April, 1, 1991, from the prescribed minimum cash margins provided the exporter had no export bills outstanding beyond a period of six months from the date of export. Imports under REP and Additional Licences were subject to 50 per cent cash margin, effective April 1, 1991, provided the export proceeds

against which such licences had been issued had been fully realised.

13.61 The minimum cash margins on imports under OGL were further raised to 200 per cent and on imports under Specified Licences to 150 per cent effective April 22, 1991. Import of life-saving equipments for value up to Rs. 2 lakh was exempted from the prescribed minimum cash margins. Imports of gem and jewellery under Imprest Licences, for value added re-export, were exempt from the prescribed minimum cash margins provided the importer had no export bills outstanding beyond 90 days from the date of export and he undertook to realise future exports also within 90 days. Imports of gem and jewellery against REP licences to qualify for relaxed cash margin were further subject to an undertaking that future exports would be realised within 90 days and a minimum period of suppliers' credit of 90 days was available.

13.62 As explained earlier, with a view to providing an incentive to exporters who repatriate export proceeds early and, at the same time, making the credit dearer to those who delay repatriation of such proceeds, the lending rates for post-shipment export credit were further revised.

13.63 Government of India had decided on April 23, 1991, that all the import Replenishment Licences should be issued only after realisation of export proceeds. In view of these changes, the banks were advised to waive the requirement of prescribed minimum cash margins in respect of imports against such post-payment Replenishment Licences.

13.64 Import of goods other than capital goods under suppliers' credit for one year and above were exempt from the requirement of prescribed minimum cash margin of 50 per cent (imposed on March 19, 1991), with effect from May 31, 1991.

13.65 Effective June 6, 1991, in the interest of export promotion, manufacturer exporters of finished leather/leather products, chemical and pharmaceuticals, engineering goods, garments and marine products, were permitted to import, other than capital goods, without any cash margin to the extent of 10 per cent of their actual export realisation from the General Currency Area subject to the ceiling of Rs. 2.5 crore in a year. Imports of hides and skins from USSR by manufacturers-exporters was fully exempt from the requirement of prescribed cash margins. The above relaxation, however, would be available where no export bill remains outstanding beyond a period of six months from the date of export.

13.66 In the light of the Report of a Review Panel, the Reserve Bank has modified on August 1, 1991, the extant guidelines on the prescribed cash margins as under :

- (a) Import of raw materials and intermediate for the manufacture of specified bulk drugs and formulations would be exempt from the requirement of cash margin. Further, the limit for exemption from the prescribed

cash margin for the import of life saving equipments has been raised to Rs. 10 lakh from the existing limit of Rs. 2 lakh.

- (b) In the case of imports under letters of credit, banks have been permitted to release the amount of cash margin once goods are cleared by the Customs and the Exchange Control copy of the Customs Bill of Entry is produced to the bank. In the case of imports not covered by letters of credit, the cash margin amount may be released on similar conditions only if such imports are covered by suppliers' credit for a minimum period of six months.
- (c) The Reserve Bank would consider waiver of cash margin requirements in cases where the exporter-importer would be in a position to obtain advance payments against his future exports and/or suppliers' credit to cover the period of export realisation.
- (d) Export bills outstanding for valid reasons not exceeding 5 per cent of the average export realisation during the previous three years, subject to a ceiling of Rs. 1 crore as against the existing ceiling of Rs. 50 lakh, would not be reckoned for the purpose of deciding whether export bills were outstanding beyond six months from the date of export.

13.67 Certain further relaxations were made on August 9, 1991 for export-related activities in the wake of the new trade policy :

- (a) Imports of certain types of hides and skins, leather and chemicals by manufacturer-exporters as well as by export and trading houses are exempt from the prescribed minimum cash margins, provided export outstandings do not exceed the stipulated tolerance level.
- (b) The exemption available to certain categories of manufacturer-exporters for import of goods other than capital goods up to 10 per cent of their actual exports to GCA during the previous year subject to a ceiling of Rs. 2.5 crore in a year has been enhanced to 20 per cent with a ceiling of Rs. 5 crore in a year.

#### Export Credit : Performance by Banks

13.68 Data relating to 49 scheduled commercial banks which account for about 95 per cent of bank credit of all scheduled commercial banks (referred to in Part I) show that their outstanding export credit increased from Rs. 8,245 crore at the end of March 1990 to Rs. 9,153 crore as at the end of March 1991, thus registering a rise of 11.0 per cent.

#### Standing Committee on Export Finance (SCEF).

13.69 The Standing Committee on Export Finance (SCEF), which is a high-powered policy-making

body on export finance, after discussing various problems faced by the exporting community, took the following two important decisions :

- (i) the availability of concessive rate of interest for post-shipment credit for bills realised beyond the due date be withdrawn, and
- (ii) the cut-off period for the purpose of export credit be synchronised with the Exchange Control Regulations of 6 months from the date of shipment for realisation of export proceeds.

#### Export Credit (Interest Subsidy) Scheme, 1968

13.70 From the funds made available to it out of the Marketing Development Assistance (MDA) of the Government of India, the Reserve Bank has disbursed interest subsidy to commercial banks and eligible co-operative banks at 5 per cent per annum in the case of pre-shipment and 3.85 per cent in respect of post-shipment credit on cash basis. During the period July 1, 1990 to June 30, 1991, the total disbursement amounted to Rs. 290 crore. Consequent upon the revision of the rate of interest on export credit provided by banks as a sequel to the abolition of subsidies on exports by Government, effective August 6, 1991, banks have been advised that they would not be eligible for interest subsidy under the scheme.

#### Duty-Drawback Credit Scheme 1976

13.71 For the period November 1, 1990 to October 31, 1991, 27 banks have been sanctioned limits aggregating Rs. 99.70 crore to enable them to avail themselves of interest-free refinance admissible under the Duty-Drawback Credit Scheme, 1976.

#### Housing Finance

13.72 As regards the allocation for housing finance, scheduled commercial banks were advised to continue to compute their respective share at 1.5 per cent of their incremental deposits during the previous year. During 1989-90, as against a targeted amount of Rs. 322 crore, the actual bank credit disbursed for housing finance was higher at Rs. 390 crore. The overall quantum earmarked was Rs. 387 crore for 1990-91, and for 1991-92, Rs. 365 crore. Till recently, banks were permitted to issue guarantees in favour of Housing and Urban Development Corporations in respect of housing loan to State level institutions provided certain terms and conditions were satisfied. Consequent upon State Governments being empowered to extend guarantee on behalf of State-sponsored bodies in respect of loans given by HUDCO and certain other financial institutions irrespective of the rate of interest charged on the loan, banks have been advised in October 1990 not to issue guarantees favouring HUDCO in respect of loans given to State-sponsored bodies.

13.73 Private builders who were allowed bank finance by way of a demand loan linked to a specific project for a maximum period of 18 months, can, effective June 5, 1991, avail of bank credit by way of term loans for a period ranging from three to five years, linked to each specific project for the development of plots together with construction of flats/houses under the refinance scheme of National Housing Bank, subject to the compliance with a few important conditions including, among others, that builders should

not receive any deposits, payments during the development and construction stages and that on completion, the dwelling units will be sold on outright sale basis at predetermined prices to allottees.

#### National Housing Bank (NHB)

13.74 The share capital of the National Housing Bank (NHB) which was last raised in September 1989 from Rs. 100 to Rs. 150 crore was further raised to Rs. 200 crore in October 1990. NHB issued its third series of bonds guaranteed by the Central Government and carrying an interest of 11.5 per cent per annum amounting to Rs. 80 crore; the total of such loans raised by the NHB so far amount to Rs. 160 crore. The Reserve Bank raised its long-term loan to Rs. 50 crore from Rs. 25 crore sanctioned in the previous year to NHB bringing total assistance extended so far to Rs. 125 crore.

13.75 On July 20, 1990 NHB launched its Capital Bonds Scheme under which the bonds, which are neither transferable nor negotiable, carry 9 per cent interest per annum, payable half-yearly or on discounted basis in the beginning itself, and provide 100 per cent tax exemption on capital gains arising out of sale/transfer of long-term capital assets like land, building, shares and securities, jewellery, etc., under Section 54 (e) of the Income-Tax Act, 1961. Under this Scheme, NHB has collected a sum of Rs. 82.21 crore from 2,480 applicants till the end of June 1991.

13.76 Under the USAID Government Housing Guarantee Programme, NHB had raised as a first tranche, on April 18, 1991, a sum of US \$25 million from the US capital market. The loan has a maturity period of 30 years and bears a fixed rate of interest of 8.63 per cent annum. The foreign currency component of the loan was passed on to the Central Government which in turn made available rupee funds to the NHB. The funds raised are being utilised to support eligible housing finance companies in making long-term shelter finance available for households below the median income (Rs. 2,000 per month). NHB has also secured a loan through the Government of India from the Overseas Economic Co-operation Fund (OECF) of Japan for Yen 2.97 billion which will also be utilised for extending housing loans to households below the median income.

13.77 Consequent to the restructuring of the lending rates of scheduled commercial and State Co-operative banks with effect from September 22, 1990, NHB modified its refinance rates as under :

Loan Amount (in Rupees)	Rate of interest (per cent per annum)	
	To be charged by NHB	To be charged by primary lender to borrower
Upto 7500	8.0	10.0
7501—15000	9.5	11.5
15001—25000	10.0	12.0
25001—50000	12.5	14.0
50001—200000	14.0	15.0



The ceiling for 100 per cent refinance has also been increased to Rs. 2 lakh for loans towards construction/acquisition of new housing units with built up area not exceeding 40 sq. mts. Refinance to the extent of 100 per cent will continue to be available in respect of loans upto Rs. 1 lakh for units with more than 40 sq.mts. built up area but costing not more than Rs. 1.50 lakh (including cost of land). Loans up to Rs. 30,000 for major repairs or upgradation will continue to qualify for 100 per cent refinance. The above modifications were made applicable to all eligible housing loans disbursed by scheduled commercial and co-operative banks on or after September 22, 1990. In respect of housing finance companies and State-level apex co-operative housing finance societies, the modified provisions of the refinance schemes were brought into force from January 1, 1991. Subsequently, with effect from May 1, 1991, in respect of housing finance companies (HFCs), the loan slab of Rs. 50,001—Rs. 2,00,000 was split into two slabs of Rs. 50,001—Rs. 1,00,000 and Rs. 100,000—Rs. 2,00,000 and the rates of interest to be charged to the ultimate beneficiary were fixed at 14.5 and 15.0 per cent per annum, respectively while refinance from NHB attached interest at 13.5 and 14.0 per cent per annum, respectively.

13.78 Till the end of June 1991, refinance assistance (including ad hoc financial assistance) provided by NHB to all categories of eligible primary lenders amounted to Rs. 567.5 crore which compares with that of Rs. 131.7 crore as at the end of June, 1990. The HFCs accounted for 83.7 per cent of the total refinance sanctioned followed by co-operative sector institutions 11.2 per cent and scheduled commercial banks 5.1 per cent. The refinance assistance was extended in respect of about 2.0 lakh dwelling units, including units for upgradation and projects for land development and shelter construction.

13.79 The Home Loan Account Scheme which has been in operation since July 1, 1989 has now been extended to select housing finance companies. On the basis of information received, more than 4 lakh accounts have been opened under the scheme by the end of March 1991. The amount of deposits collected was about Rs. 68 crore.

13.80 Interest rates under refinance schemes for land development and shelter projects executed in accordance with NHB's guidelines by public agencies, co-operative housing societies, professional developers as also for rental housing projects of public and private sector employers were also revised so as to conform to the revised interest rate structure. The interest on term-loans will be worked out as a weighted average of the rate applicable in respect of individual components and charged for the project loan as a whole, interest on refinance from NHB being one per cent lower than the said rate. The guidelines were also liberalised. Accordingly, the prescribed plot and dwelling unit size can be marginally relaxed so long as the cost does not exceed Rs. 50,000 and Rs. 1.5 lakh, respectively. During the year, these refinance schemes were extended to all eligible housing finance companies also NHB has, till the end of June 1991, approved 43 projects aggregating Rs. 298.4 crore for development of 17,803 plots and construction of 38,449 dwelling units. Besides, NHB has also given clear-

ance 'in principle' for 77 projects involving a total outlay of Rs. 618.7 crore for development of 22,200 plots and construction of 31,650 houses.

13.81 The NHB also participates, on merits, in the equity of housing finance companies. As a matter of policy, NHB has decided to participate in the equity of only those new/existing housing finance companies which commit to open branches in the Central, Northern and North-Eastern Regions, where housing finance system is yet to develop in a significant way. NHB has, till now, decided to participate in the equity of 4 HFCs amounting to Rs. 5.5 crore to be promoted by Bank of Baroda, Vysya Bank Ltd., Andhra Bank and Central Bank of India. As on June 30, 1991, NHB has participated in the equity of Akshaya Awas Nirman Vitta Ltd. (Bank of Baroda) and Vysya Bank Housing Finance Ltd. (Vysya Bank Ltd.) to the extent of Rs. 2.8 crore. NHB has, so far, recognised 16 HFCs as eligible for financial assistance. Of these, 2 are in the public sector, 2 in the joint sector and the remaining 12 are in the private sector. Among the companies recognised in the private sector, 7 are sponsored by institutions/banks and 5 are sponsored by private individuals.

13.82 Till June 1991, NHB has sanctioned equity assistance for 4 projects aggregating to Rs. 116 lakh. In keeping with the criteria for extending support to locally produced standardised building materials and components, using agricultural and industrial waste, support has been extended to the following units manufacturing: (a) Sand lime brick, (b) Flyash-based building material products, and (c) Polyester cast moulded products.

#### Sick Industrial Undertakings

13.83 The commercial banks have been advised that they should on their part actively support schemes pertaining to takeover and revival of sick units by the workers' co-operatives of such units. Apart from taking advantages of the Equity Fund Scheme formulated by IDBI for providing soft loans to workers' co-operatives to contribute their share of equity in sick units, in case rehabilitation packages involve concessions beyond the RBI parameters, banks have been advised to consider such reliefs on the merits of individual cases. It has been decided that for existing/additional facilities for sick/weak units being nursed under rehabilitation programme, the stipulated exposure limits would not be applicable. Banks have been permitted to sell their existing debt of a sick unit at a discount to another bank which is prepared to purchase it only in cases where rehabilitation packages have been finalised and with the consent of other participating members in the consortium. Banks have been delegated the discretion to consider the extent of reliefs/concessions as part of the packages evolved for the rehabilitation of potentially viable non-SSI sick/weak industrial units beyond the prescribed parameters without the requirement of obtaining prior approval of the Reserve Bank, with a view to speeding up the process of implementation of revival packages.

13.84 According to the latest available data (September 1989), the total number of non-SSI units identified by banks as sick as defined under the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (SICA), was 1, 419 with outstanding bank credit of



Rs. 4,258 crore as at the end of September 1989. Out of these, viability studies were completed in respect of 1,167 units and 456 of them were considered viable. Again, of the units considered viable, 280 units were put under a nursing programme by banks. The total number of non-SSI units identified by banks as weak in this period was 762 with outstanding bank credit of Rs. 2,183 crore. The viability studies were completed in respect of 560 units and 315 units were considered as viable. Of the viable units, 183 units were put under a nursing programme by banks. The number of sick SSI units, which includes rural artisans, village and cottage industries as also SSI units, were 1,86,441 at the end of September 1989, involving bank finance of Rs. 2,243 crore. Of these, only 16,042 units with outstanding bank credit of Rs. 568 crore were considered potentially viable and 8,201 units were put under nursing programmes.

#### RBI Assistance to Financial Institutions

13.85 The Bank did not sanction any fresh long-term loan to the Industrial Development Bank of India (IDBI) out of the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund for the year, 1990-91. The IDBI, however, repaid Rs. 117.15 crore during 1990-91 and its outstanding borrowings as on June 30, 1991 amounted to Rs. 3,705.15 crore. Although a short-term credit limit of Rs. 400 crore carrying interest at the Bank Rate (i.e. 10 per cent per annum) was sanctioned to IDBI on March 2, 1991 which was valid up to June 30, 1991, the IDBI did not avail of this limit. Like other all-India term-lending institutions, SIDBI, which is now eligible to borrow short and long-term funds from RBI under Sections 17 and 46 of the Reserve Bank of India Act, 1934, was sanctioned a long-term loan of Rs. 400 crore out of the National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund for utilisation during 1990-91 (July-June) repayable after 15 years at a concessive interest rate of 6 per cent per annum, which was fully availed of. In addition, two separate limits of Rs. 300 crore each of short durations (aggregating Rs. 600 crore) were sanctioned to SIDBI. However, SIDBI has utilised only Rs. 75 crore of the first limit of Rs. 300 crore.

13.86 For 1990-91 (July-June), the EXIM Bank was sanctioned a long-term credit limit of Rs. 120 crore out of the NIC(LTO) Fund, repayable after 15 years at an interest rate of 7 per cent per annum. EXIM Bank fully availed of the limit and its outstanding borrowings from the Fund as on June 30, 1991 amounted to Rs. 745 crore.

13.87 The Industrial Reconstruction Bank of India (IRBI) was sanctioned a long-term credit limit of Rs. 35 crore out of the NIC (LTO) Fund, repayable after 15 years at an interest rate of 6 per cent per annum. With fully availed of the limit, IRBI's outstanding borrowings from the Fund as on June 30, 1991, amounted to Rs. 130 crore.

13.88 The Reserve Bank sanctioned an ad hoc borrowing limit of Rs. 44 crore to the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) for the calendar year 1991 as against Rs. 40 crore during the previous

year. This limit was subsequently raised to Rs. 50 crore by sanctioning an additional limit of Rs. 6 crore. The Corporation has been utilising the limit to meet its ad hoc needs. Its outstanding borrowings as on June 30, 1991 amounted to Rs. 41 crore.

13.89 An ad hoc borrowing limit of Rs. 33 crore was sanctioned to the Industrial Credit and Investment Corporation of India (ICICI) for the fiscal year 1990-91. ICICI availed of the limit on an ad hoc basis and repaid the entire outstanding amount on March 30, 1991. A fresh limit of Rs. 30 crore has been sanctioned to ICICI for the financial year 1991-92. The ad hoc borrowings of IFCI and ICICI are at the Bank Rate.

13.90 The Reserve Bank sanctioned an aggregate ad hoc borrowing limit of Rs. 98.23 crore for 1990-91 (July-June) to 15 State Financial Corporations (including Tamil Nadu Industrial and Investment Corporation) against the security of ad hoc bonds guaranteed by the respective State Governments. These limits were valid up to June 25, 1991 and the interest charged was at the Bank Rate of 10 per cent per annum on actual borrowings. The aggregate amount outstanding against these ad hoc limits amounted to Rs. 30.78 crore as on April 30, 1991 (this comprises outstanding of 10 SFCs as on April 30, 1991 and 5 SFCs as on March 31, 1991).

#### Commitment Charge

13.91 Mention has been made in Part I of the Report about the levying of a minimum commitment fee on the unutilised portion of the working capital limits sanctioned to borrowers. The following limits are, however, exempted from this stipulation : (a) Working capital limits sanctioned to sick/weak units; (b) Limits sanctioned for export credit (both pre-shipment and post-shipment) as well as against export incentives, viz., duty drawback, cash compensatory support, etc; (c) Inland bills limits, extended by way of bills purchased/discounted or overdraft/cash credit limit/sub-limit against bill for collection; (d) Credit limits sanctioned to commercial banks, financial institutions and co-operative banks including land development banks. In view of the restrictions imposed on drawals under large cash credit limits during May 9 to September 30, 1991, banks were advised that the Reserve Bank instructions relating to levy of minimum commitment charge of one per cent per annum in the unutilised portion of the working capital limits sanctioned to borrowers would be held in abeyance during this period.

#### Co-acceptance/Issuance of Guarantees

13.92 In accordance with the Reserve Bank's extant guidelines that banks should not execute guarantees in favour of financial institutions (where the latter appraise a proposal and assume the credit risk), it has been clarified that banks should not execute guarantees/co-acceptances favouring financial institutions under the Buyers' Line of Credit Scheme operated by the latter.

## 14. DEVELOPMENTS RELATING TO CO-OPERATIVE BANKING

### Primary (Urban) Co-operative Banks (PCBs)

#### (i) Progress

14.1 During the year 1990-91 (July-June), 10 new PCBs were issued licences to commence and/or carry on banking business. One bank (Kundara Co-operative Urban Bank Ltd., Kundara) was refused a licence to carry on banking business as a prelude to this bank being taken under liquidation by the Registrar of Co-operative Societies, Kerala. With the deletion of one PCB and one salary earners' bank from the list of primary co-operative banks, the number of PCBs at the end of June 1991 was 1,397 (including 93 salary earners' banks, 38 Mahila banks and 49 banks under liquidation) in the country. Of these, the total number of PCBs licensed to carry on banking business as at the end of June 1991 had increased to 1,028 from 1,013 as at end-June 1990.

14.2 The Reserve Bank has decided to appoint a committee headed by Shri S. S. Marathe, Member, Central Board of Directors, to review the present policy in regard to setting up of new PCBs and other related issues including conversion of societies into PCBs.

14.3 At the end of December 1990, the number of offices of PCBs stood at 3,391 (provisional) as against 3,358—as at the end of June 1990. The new branch licensing policy covering the three-year period 1991-92 to 1993-94 for the primary urban co-operative banks has been formulated and the applications received for allotment of centres are under consideration.

14.4 Three more banks, all in Maharashtra, viz., Bassein Catholic Co-operative Bank Ltd., Vasai, Cosmos Co-operative Bank Ltd., Pune, and New India Co-operative Bank Ltd., Bombay were included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 with effect from December, 1990. With this, the total number of scheduled PCBs had risen to 14 (Maharashtra 11 and Gujarat 3) from 11 as at end-June 1990.

#### Priority Sector Advances

14.5 As at the end-June 1990, out of 579 reporting primary co-operative banks, 398 banks had achieved the target prescribed, i.e., 60 per cent of their total advances for lending to priority sector and 416 banks achieved the sub-target prescribed, i.e., 25 per cent of the priority sector advances, for lending to weaker sections. Such priority sector advances in the case of reporting banks aggregated Rs. 1,703.33 crore, forming 63.1 per cent of their total outstanding advances.

#### Interest Rates on Deposits

14.6 The Primary Urban Co-operative Banks (PCBs) hitherto enjoyed the discretion to allow additional interest at a rate not exceeding 1.0 per cent per annum on domestic saving and term deposits. In view of the higher interest rates now available on term deposits, effective July 24, 1991,

the additional interest so allowed to be offered has been reduced to not more than 0.5 percentage point in respect of scheduled PCBs for their term deposits of all maturities. For non-scheduled PCBs the same 0.5 percentage point interest discretion has been prescribed for the maximum maturity deposits of 3 years and above; for other maturities, it has been retained at 1.0 percentage point. Also, for savings deposits of all PCBs, the additional interest permitted has been retained at not more than 1.0 percentage point.

#### Interest Rates on Advances

14.7 Following the rationalisation of interest rates on advances made by commercial banks, a similar exercise was done for PCBs and a new interest rates structure keeping in view their size and preponderance of small-size loans was prescribed with effect from June 1, 1991. Subsequently, as a sequel to further step-up in interest rates on advances made by commercial banks, similar increases were effected in respect of interest rates on advances charged by PCBs effective July 24, 1991. In respect of the general category (i.e., other than the concessive rates), the increase was 0.5 percentage point each to a range of 15.0 per cent to 16.5 per cent for all sizes of advances upto Rs. 2 lakh and from 17.0 per cent (minimum) to 18.5 per cent (minimum) for advances over Rs. 2 lakh.

#### Maximum Limit on Advances

14.8 With a view to curbing kite-flying operations, by the clientele of the primary cooperative banks, it was instructed that drawals allowed against 'cheques sent for collection' (both local and outstation) would be treated as unsecured advances and would be subject to the directives issued on the subject by the Reserve Bank. Clearing House authorities at various places were also advised to ensure compliance of appropriate rules by members governing utilisation of favourable clearing balances so as to deny them the use of such funds before the returned cheques had been adjusted. With effect from May 20, 1991, the maximum limits on unsecured advances to a director (including relatives) or any other single party/connected group for trade, commerce, cottage and small-scale industry and identifiable purposes, were revised upward to Rs. 25,000 and Rs. 50,000 in respect of PCBs with demand and time liabilities (DTL) of Rs. 1 crore and above but less than Rs. 10 crore, and Rs. 10 crore and above, respectively.

#### Financing of Leasing/Hire Purchase

14.9 PCBs with working capital funds of Rs. 25 crore and above had been allowed to take up financing of leasing/hire purchase companies in consortium with scheduled commercial banks.

#### Increase in CRR

14.10 Effective from the fortnight beginning July 13, 1991, eleven scheduled primary (urban) co-operative banks are required to maintain a cash reserve ratio of not less than 6 per cent of DTL in India as against the 3 per cent minimum hitherto maintained by them. The remaining three scheduled primary (urban) co-operative banks, which were inclu-

held in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 recently, shall maintain a CRR of not less than 6 per cent from the fortnight beginning January 11, 1992.

#### Refinance Facilities

14.11 During the financial year 1990-91, short-term credit limits aggregating Rs. 18.70 crore were sanctioned at a concessive rate of interest (2.5 per cent below the Bank Rate) to the State Co-operative Banks on behalf of 37 PCBs for financing working capital requirements of cottage/small-scale industrial units as against Rs. 20.71 crore sanctioned on behalf of 53 PCBs in the previous year. The outstanding against these limits amounted to Rs. 16.27 crore as on March 31, 1991 as against Rs. 18.07 crore in the corresponding period of the previous year.

#### Credit Guarantee Scheme

14.12 Licensed PCBs and unlicensed PCBs specifically recommended by the Reserve Bank are eligible for availing themselves of guarantee cover under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 and Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 administered by the DICGC. As at the end December 1990, the number of PCBs which had joined these two schemes stood at 191 and 90, respectively, as against 187 and 89, respectively, on the corresponding date of the previous year.

#### Non-Resident Accounts

14.13 At the end of June 1991, 58 PCBs were permitted to open and maintain Non-resident (ordinary/external) accounts in Rupees.

#### Weak and Non-viable Banks

14.14 As on March 31, 1991, the number of PCBs classified as financially weak stood at 230. They were designated as weak because of the heavy erosion in their owned funds, high level of overdues non-compliance with minimum share capital required in terms of the provisions of Section 11(1) of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co-operative Societies), not satisfying the viability norms prescribed by Reserve Bank, etc. During the year, directions under Section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co-operative Societies), placing restrictions, among others, on making payments to depositors and incurring of expenditure beyond specified amounts, were issued to 3 PCBs, viz., Vardhaman Co-operative Bank Ltd., Maratha Market Peoples' Co-operative Bank Ltd., and Vaibhav Co-operative Bank Ltd., due to their unsatisfactory financial position and methods of operations leading to serve liquidity crisis. Certain relaxations were made in the amount payable to depositors. Up to Rs. 5000, acceptances of fresh deposits including renewal thereof and grant of advances against tangible securities, in the case of the Adinath Co-operative Bank Ltd., Pune, working under directions following substantial improvement in its liquidity due to recovery of debts, etc. The City Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad was amalgamated with the Development Co-operative Bank Ltd. Bombay, as at the close of business on June 29, 1991.

#### Inspections

14.15 During the period July 1, 1990 to June 30, 1991, statutory inspections of 494 PCBs were conducted under Section 35 of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to Co-operative Societies).

#### Committees and Working Groups

14.16 The Standing Advisory Committee (SAC) for Urban Co-operative Banks met and dismissed, among other matters pertaining to (i) revised scheme of refinance under Section 17(2)(bb) read with Section 17(4)(c) of the Reserve Bank of India Act, 1934; (ii) issue of licences to existing urban co-operative banks; (iii) working of Mahila urban co-operative banks, etc.

#### SCBs & CCBs

##### (i) Licences

14.17 In the period July 1990 to June 1991, licences were issued to three State co-operative banks to open branches at 5 centres in their respective areas of operation under Section 23 of the Banking Regulation Act, 1949.

##### (ii) Interest Rates

14.18 In alignment with the periodical changes effected in respect of interest rates on deposits of commercial banks (set out in earlier Section) the deposits rates of State and Central co-operative banks were also correspondingly raised. Upward revisions in deposit rates during October 1990 and April and July 1991 were thus made. A new category of deposits of three years and above was introduced with effect from October 10, 1990 carrying a rate of interest of 11 per cent per annum. The interest rate on term deposits for 3 years and above was raised by one percentage point to 12.0 per cent effective April 13, 1991. The term deposit rates were further raised across-the-board by one percentage point effective July 4, 1991. The revisions are applicable also to State and Central co-operative banks. Besides, the State and Central co-operative banks may, at their discretion, allow additional interest of 1/4 per cent and 1/2 per cent, respectively over and above the prescribed rates.

### 15. OTHER BANKING DEVELOPMENTS

#### Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation

15.1 During the year under review, the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) continued to operate the Deposit Insurance Scheme to provide insurance cover to small depositors in banks and five Credit Guarantee Schemes (four for small borrowers and one for Small-Scale Industries) guaranteeing the priority sector advances granted by participating banks and financial institutions.

15.2 The number of insured banks increased from 1917 as on June 30, 1990 to 1924 as on June 30, 1991 comprising 80 commercial banks, 196 Regional Rural Banks and 1,648 co-operative banks in 16 States and 3 Union Territories. The insured deposits at

Rs. 1,09,316 crore formed 69.7 per cent of total assessable deposits at the end of June 1990. Of the total number of deposit accounts, the fully protected deposit accounts formed 96.5 per cent. During the year, the Corporation paid an aggregate amount of Rs. 31.20 crore towards settlement of claims in respect of 5 commercial banks and 2 co-operative banks.

15.3 The number of banks participating in the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 as at the end of June 1991 was 258 which included 64 commercial banks and 194 Regional Rural Banks. Only two amongst the State Financial Corporations (including State Industrial Development Corporation) participated in the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971. At the end of June 1991, 150 credit institutions participated in the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, while the number of primary urban co-operative banks participating in the Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme was 39. Total guaranteed advances under the above four schemes at Rs. Rs. 27,692 crore at the end of March 1990 were higher by 8.2 per cent as compared with the level at the end of March 1989.

15.4 The number of institutions participating in the Corporation's Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, declined to 375 at the end of June 1991 from 555 as at the end of June 1990. The guaranteed advances to the small-scale industrial sector increased by 19.4 per cent to Rs. 16,826 crore at the end of March 1990 from Rs. 14,094 crore at the end of March 1989.

15.5 Between July 1990 and June 1991, the number of claims received by the Corporation was 19.90 lakh worth Rs. 492.49 crore in respect of guarantee schemes relating to small borrowers and 0.82 lakh claims worth Rs. 246.93 crore in respect of its scheme for SSIs. The Corporation during this period disposed of 18.60 lakh claims for Rs. 426.13 crore in respect of small borrowers and 0.80 lakh claims for 239.36 crore in respect of the SSIs.

15.6 The guarantee fee receipt, which exceeded the claims during 1989-90 fell short of guarantee claims in 1990-91 by Rs. 80.99 crore. This gap between the fee receipts (gross) and the claims is likely to widen as a sequel to the Corporation's decision to exclude certain categories of advances to priority sector for payment of guarantee fee for the year 1990-91.

#### Non-Banking Companies Regulations Governing Acceptance of Deposits

15-7 During the year ended June 1991, there were no changes in the regulation by way of amendments to the sets of Directions issued by the Reserve Bank to the non-banking financial, miscellaneous non-banking and residuary non-banking companies. Certain amendments have been made to the Directions according to which the maximum rate of interest which the non-banking financial and miscellaneous non-banking companies can pay on their deposits has been increased, effective July 27, 1991, from 14 per cent to 15 per cent per annum. The requirement of maintaining liquid assets in the form of deposits with

banks and/or approved securities by hire-purchase and leasing companies has been raised to 15 per cent from 10 per cent effective from November 1, 1991. These companies have also been prohibited from paying any interest in case the deposits are withdrawn before the stipulated minimum period of deposit of over 24 months; the companies can, however, grant loans after a period of 6 months from the date of placement of the deposits up to 75 per cent of the deposit amount at an interest rate of 2 percentage points above the rate payable on such deposits.

#### Chit Funds Act, 1982

15.8 The number of States/Union Territories covered under the Chit Funds Act, 1982, remained unchanged at 19 during 1990-91. They are, Assam, Bihar, Goa, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Meghalaya, Orissa, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Pondicherry. In the remaining, states necessary follow up action has been taken.

#### Acceptance of Deposits by Unincorporated Bodies

15.9 With four more States having issued notifications during 1990-91 authorising suitable officers to take action against unincorporated bodies in terms of Sections 45T and 58E of the Reserve Bank of India Act, 1934 the total number of such States/Union Territories rose to 27. The matter is being pursued with the remaining States. Of the 129 bodies located in Gujarat, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Delhi, which have been investigated by the Bank till now (including nine during the period under review) with the assistance of State Police/Government officials, prosecution proceedings have been launched against 19 such bodies for violation of the provisions of Chapter III C of the Reserve Bank of India Act, 1934. The cases are at various stages of trial.

#### Trends in Growth of Deposits with Non-Banking Corporate Sector

15.10 The provisional data places the aggregate deposits of 9,057 reporting non-banking companies for the year ended March 31, 1990 at Rs. 32,216 crore as compared with Rs. 29,208 crore held by 10,197 companies at end of March 1989. Non-financial companies accounted for 64.6 per cent of aggregate deposits, financial companies for 30 per cent and miscellaneous non-banking companies and residuary non-banking companies accounted for 5.4 per cent of the total. During 1989-90, regulated deposits of the reporting non-banking companies recorded an increase of Rs. 443 crore and stood at Rs. 6,518 crore, while the exempted deposits rose by Rs. 2,565 crore to Rs. 25,698 crore. The regulated deposits of the non-banking sector, which increased from Rs. 6,075 crore in 1988-89 to Rs. 6,518 crore in 1989-90, formed 3.7 per cent of the aggregate deposits of all scheduled commercial banks. During 1989-90, regulated deposits of non-financial companies amounted to Rs. 4,044 crore while that of financial companies amounted to Rs. 1,585 crore. A statement showing deposits with Non-Banking Corporate Sector is given in Table 15.1.

Table 15.1 : Deposits with the Non-Banking Corporate Sector  
(as at the end of March)

Category	(Rupees crore)							
	1988-89				1989-90 (Provisional)			
	No. of reporting companies	Regulated deposits	Exempted deposits	Total	No. of reporting companies	Regulated deposits	Exempted deposits	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aggregate Deposits	10,197	6,075	23,133	29,208	9,057	6,518	25,698	32,216
Of which held by								
(i) Non-financial companies	2,531 (24.8)	3,901 (64.2)	14,219 (61.5)	18,120 (62.0)	2,438 (26.9)	4,044 (62.1)	16,759 (65.2)	20,803 (64.6)
(ii) Financial companies	6,374 (62.5)	1,494 (24.6)	8,058 (34.8)	9,552 (32.7)	5,459 (60.3)	1,585 (24.3)	8,064 (31.4)	9,649 (30.0)
(iii) Misc. Non-Banking companies and Residuary Non-Banking companies	1,292 (12.7)	680 (11.2)	856 (3.7)	1,536 (5.3)	1,160 (12.8)	889 (13.6)	875 (3.4)	1,764 (5.4)

Note : Figures in brackets are percentage to total number of reporting companies/regulated/exempted aggregate deposits as the case may be.

## 16. DEVELOPMENTS RELATING TO EXCHANGE CONTROL

### Financing of Imports : Special Regulations

16.1 As referred to in Part I of the Report, in view of the difficult foreign exchange reserves position, a series of instructions have been issued by the Reserve Bank stipulating minimum cash margins against letters of credit and generally regulating financing of imports. The instructions included the requirements of obtaining prior approval, from the Reserve Bank's Exchange Control Department, in respect of remittances to be made against imports beyond certain limits or under certain other circumstances. The details of the initial stipulations in this regard and their subsequent relaxations, particularly with focus on the export sector, have been presented in a chronological order in paragraphs 13.10 to 13.25 in a previous Section of this Report.

### Remittance of the equivalent of above Rs. 2.5 crore

16.2 Authorised dealers were advised that effective from April 23, 1991 every transaction of sale of foreign exchange or payment to or for the credit of any person resident outside India, of the equivalent of above Rs. 2.5 crore; other than for repayment of balance in FCNR and NRE accounts and inter-bank transactions, should be referred to the Reserve Bank for clearance before effecting the transaction. This also applied to the sale of foreign exchange or making payment as the case may be, pursuant to any permission already issued by the Reserve Bank and subsisting on the above date.

### Roll-over forward cover for deferred payment exports and imports

16.3 Authorised dealers can enter into forward purchase contracts, on a roll-over basis, in cases of exports on deferred payment terms and forward sale contracts on a roll-over basis in case of imports under import licences issued on deferred payment

terms as well as for repayment of foreign currency loans. The initial contract made could be for a period of six months and thereafter as each deferred instalment is taken up, the outstanding balance of the forward contract could be extended each time for a further period of six months. It has since been decided to allow authorised dealers, on specific requests from the customers to undertake roll-overs at shorter intervals with a view to reducing the costs payable by the customers concerned.

### Forward sale of U.S. Dollars by Reserve Bank of India to authorised dealers

16.4 Reserve Bank was buying spot, as well as forward Pound sterling, U.S. dollar, Deutsche mark and Japanese yen and selling Pound sterling and U.S. dollar only on spot basis. On a review of the situation in the inter-bank foreign exchange market, the Reserve Bank decided to sell forward U.S. dollar to authorised dealers with effect from May 8, 1991 at the Bank's Bombay Office, for delivery in three months and six months basis with option of delivery in the third and sixth months, respectively, for covering their sale of U.S. dollar or other currencies for specific merchant transactions or commitments such as remittances to be made on account of imports, loan repayments, etc. No extension/cancellation of the forward purchase U.S. dollar contract booked with the Reserve Bank is allowed.

### Permitted methods of receipts of export proceeds

16.5 Hitherto exporters were not normally permitted to receive payments for exports directly from the overseas buyers in the form of bank drafts, pay orders, bankers' cheques, personal cheques, foreign currency notes or foreign currency travellers' cheques. The Reserve Bank has now permitted authorised dealers to handle export documents in cases where their exporter customer has received payment, in the form of bank draft, pay order, banker's cheque and personal cheque drawn by overseas buyer in favour of the exporter, not exceeding US \$7,500 per shipment,

directly from the overseas buyer, subject to the conditions that (i) the instrument is tendered to the authorised dealer within seven days from its receipt and is meant for payment for exports, (ii) the export documents are routed through the authorised dealer/branch to whom the instrument is presented for realisation, (iii) the payment is received in an approved manner, and (iv) the export is made only after realisation of the instrument.

16.6 Applications involving amounts in excess of US \$7,500 or its equivalent per shipment or applications for receiving payments in the form of foreign currency notes or foreign currency travellers' cheques tendered by overseas buyers while on a visit to India, require a reference to the Reserve Bank for its consideration.

16.7 In addition, the Reserve Bank could also consider applications from exporters, for grant of general permission, to receive directly from overseas buyers, payment for exports in the form of bank drafts, pay orders, bankers' cheques and personal cheques up to a reasonable limit beyond US \$ 7,500 per shipment. The permission would also cover receipt of payments in the form of foreign currency notes and/or foreign currency travellers' cheques up to a limited extent. For this purpose, the concerned exporter is required to designate a branch of an authorised dealer to whom documents in respect of all shipments effected by him would be delivered and instruments such as bank drafts, bankers' cheques, pay orders, received towards payment for exports would be tendered for realisation. The application to the Reserve Bank should be submitted through the designated branch of the authorised dealer.

Despatch of shipping documents direct to consignees/overseas agents of consignees

16.8 Exporters of precious/semi-precious stones and nongold jewellery have now been granted general permission to despatch shipping documents directly to the consignees in respect of consignments not exceeding US \$ 25,000 or its equivalent in value as against the earlier limit of US \$ 15,000.

Acceptance of foreign exchange from foreign tourists

16.9 With a view to affording greater facilities to foreign tourists for conversion of foreign currency, restricted money changers (other than hotels and other boarding and lodging establishments like YMCA, YWCA, etc.) have been permitted to accept foreign currency notes/coins and travellers' cheques up to a limit of US \$ 500 or its equivalent per person at any one time for conversion into rupees. The above permission is in addition to the one already granted to them for accepting payments in foreign currency notes/coins and/or travellers' cheques for meeting the cost of goods and/or services supplied/rendered to their customers. Hotels and boarding/lodging establishments like YMCA, YWCA, etc., holding money changing licences are already holding the Banks authorisation to accept, besides payments in foreign currency notes/coins and travellers' cheques freely

from any person whether residing in the hotel or established or not for conversion into rupees.

Maintenance of cash-float in foreign currency

16.10 Restricted money-changers other than hotels are allowed to keep a fixed cash-float of an amount not exceeding US \$ 100 or its equivalent in the aggregate for all the currencies. It has been decided to raise the quantum of the cash-float to US \$ 1,000 or its equivalent in the aggregate for all the currencies.

Acquisition of foreign exchange by residents

16.11 Under the general permission granted by the Reserve Bank, thereto a person was permitted to acquire foreign exchange not exceeding US \$ 100 or its equivalent from any person resident outside India, who is on a visit to India for services rendered or in settlement of any lawful obligation and was required to surrender it to an authorised dealer within seven days of receipt. This limit of US \$ 100 has since been tripled to US \$ 300.

Issue of International Credit Cards (ICC) to ad hoc permit holders

16.12 Under the current regulations, only, firms/companies holding either a Blanket Permit or a CAFEX permit are allowed to subscribe to International Credit Cards (ICC) for use of their representatives during their visits abroad. The facility is now available to those who travel abroad frequently on ad hoc permits such as, senior most officers of Government of India, top executives of public sector undertakings, public sector banks and financial institutions like the IDBI, the UTI, and others.

Release of exchange for visits to Bilateral Group of countries

16.13 Persons visiting the Bilateral Group of countries for business, study tour, and attendance at a conference, seminar/symposium, are now being allowed to draw their entire exchange quota in free foreign exchange even though per diem scales of exchange and the permits issued by the Reserve Bank would continue to be expressed in rupees. In the case of permits issued for medical treatment and higher studies, the conversion facilities on a limited scale allowed at present would be continued. Remittances for purposes such as registration, admission, examination, membership fees etc. would continue to be allowed in rupees without any conversion facilities.

MCO facility for travellers visiting Mauritius under NTS.

16.14 Indian residents visiting Mauritius under the Neighbourhood Travel Scheme (NTS) have been permitted to avail of the facility of Miscellaneous Charges Order (MCO) to cover expenses of surface transportation. This facility can be availed of by person travelling in a group of 15 or more, up to a limit of US \$ 150 per person.

### Refund of foreign exchange conservation travel (FECT) tax

16.15 In terms of sub-rule (1) of Rule 5 of FECT Tax Rules, 1987, refund of FECT tax should be claimed within a period of one month from the date of return of foreign travel, for which exchange was released. In order to bring the period within which refund could be claimed in conformity with the period within which the unutilised foreign exchange had to be surrendered in terms of the Reserve Bank Notification No. FERA. 73/88-RB dated February 27, 1988, the Government of India had amended sub-rule (1) of Rule 5 whereby the time limit for claiming refund of FECT tax had been increased to 90 days from the date of return of foreign travel.

### Exchange for higher studies Delegation

16.16 With effect from June 1, 1990 powers to release exchange for higher studies abroad were delegated to designated branches of public sector banks. The total number of branches designated by these banks is 328

### Specialised Training

16.17 The period up to which requests for release of exchange, for undergoing advanced training, in highly specialised medical fields at reputed overseas institutions, from medical practitioners/specialist has been enhanced from six months to a maximum of twelve months.

### Enhancement of RIFEE facility against repatriation of monthly pension

16.18 Indian nationals and persons of Indian origin receiving pension in foreign exchange from their erstwhile foreign employers and also regularly repatriating the entire pension amount to India are allowed to utilise up to 25 per cent in respect of pension amounts drawn from the month of April 1990 and onwards and repatriated to India for various specified purposes covered under the "Returning Indians Foreign Exchange Entitlement Scheme" (RIFEES). The percentage of entitlement for pension amounts drawn prior to April 1990 and repatriated to India remained unchanged at 10 per cent as hitherto under the Scheme.

### Local hospitality

16.19 The existing limit of Rs. 3,000 per diem up to which local living expenses of non-resident directors for a period not exceeding 5 days at a time can be met by Indian companies has been raised to Rs. 5,000 per diem.

### Taking out of house-hold articles by non-residents

16.20 Under the existing regulations, travellers wishing to take out of India articles in excess of the limits prescribed under the Export Baggage Rules were required to apply to the Reserve Bank for grant of GR waiver except when they were purchased against payment in foreign exchange. It has been decided to permit persons of Indian nationality/origin who are resident abroad and who wish to take out with them

household articles up to the value of Rs. 10,000 (except articles made of gold or silver and items banned for export under the Trade Control Regulations in India) purchased by them during their temporary visit to India for personal use in the country of their residence, even if the cost of goods has been paid by them out of funds held in their Ordinary Non-resident Rupee (NRO) accounts. Applications for the purpose were required to be made to the Reserve Bank.

### Credits to Ordinary Non-Resident Rupee (NRO) Accounts

16.21 The existing regulations governing operations on Ordinary Non-Resident Rupee Account (NRO accounts) by non-residents of Indian nationality/origin (NRIs) and Overseas Corporate Bodies (OCBs) predominantly owned by such persons had been revised as under:

Authorised Dealers (ADs) are permitted to freely allow credits of rupee funds without any limit to NRO accounts maintained by NRIs/OCBs which were legitimately due to the account holder as against the previous limit of Rs. 4,000 in a month with an individual credit not exceeding Rs. 1,500 up to which the authorised dealers could allow such credits without prior approval of the Reserve Bank. Authorised dealers have been advised to call for documentary evidence in respect of individual credits exceeding Rs. 10,000 to ascertain the bonafide nature of the transaction and satisfy themselves that the credits represent legitimate dues of the account holder. Authorised dealers have also been advised to get an undertaking from the account holders (existing and new) stating that they shall not make available to any person in India any foreign currency against reimbursement in rupees or in any other manner in India.

### Loans Limits by ADs

#### (i) To NRO Account Holders

16.22 The limit up to which authorised dealers have been empowered to grant loans and overdrafts to their non-resident constituents who are NRIs, for purposes other than investment, against the security of fixed deposits held in NR(O) accounts has been increased from Rs. 2 lakhs to Rs. 5 lakhs.

#### (ii) To NRE account holders

16.23 The limit for grant of loans/overdrafts to NRE account holders themselves against the security of their fixed deposits held in NRE/FCNR accounts has been raised from Rs. 2 lakh to Rs. 5 lakh and later up to Rs. 10 lakh for purposes other than investment. Repayment in such cases would, however, have to be made either by adjustment of the NRE/FCNR deposit or by fresh inward remittance from abroad.

#### (iii) To NRE Account holders for investments

16.24 Authorised dealers have now been empowered to grant, subject to certain specified conditions, rupee loans/overdrafts up to Rs. 10 lakh to their NRI constituents against security of fixed deposits held by them in NRE/FCNR accounts for the purpose of making direct investment in India on non-repatriation basis in



the capital of Indian firms|companies engaged|proposed to engage in manufacturing|industrial activities, hospitals, hotels of three star or higher grades, shipping, development of computer software and oil exploration services. Earlier such applications were required to be referred to the Reserve Bank

(iv) To residents against security of NRE fixed deposits

16.25 Authorised dealers were hitherto required to refer to the Reserve Bank, applications for grant of loans|overdrafts to resident individual|firms|companies in India against collateral of fixed deposits, held in Non-resident (External) Accounts. Powers have now been delegated to authorised dealers permitting them to grant such loans|overdrafts without any limit, subject to the following conditions :—

- (a) There should be no direct or indirect foreign exchange consideration for the non-resident depositor agreeing to pledge his fixed deposits to enable the resident individual|firm|company to obtain such loans|overdrafts.
- (b) The period of loans should not exceed the unexpired period of maturity of NRE|FCNR fixed deposits accepted as security. In addition, the non-resident depositor should furnish an irrevocable undertaking to authorised dealer not to withdraw the deposit at least during the period of the loan|overdraft.
- (c) The loan|overdraft to be granted should conform to the regulations relating to normal margin, rate of interest depending on the purpose of loan, etc. as stipulated by the Reserve Bank from time to time.
- (d) The loan could be utilised for personal purposes or for carrying on business activities other than agricultural|plantation activities or real estate business.

#### Transfer of Funds between NRE Accounts of NRIs

16.26 Hitherto, Reserve Bank's approval was required for transfer of funds from the NRE account of one person to the account of another person on application if the transferor and transferee are close relatives. The powers have now been delegated to authorised dealers to authorise such transfers if the :—

- (i) transfer is for genuine personal purposes e.g. education of children, gift, personal expenses etc.
- (ii) Transferor and transferee account holders are resident in the External Group of countries or the transferor and transferee are resident in the same Bilateral Group country.

If such transfer involves transfer of funds from one bank to another bank, the transferor bank has to certify the NRE states of the account from which the transfer of funds is proposed to be made. Transfer of funds as a gift would be allowed subject to payment of gift tax, if applicable.

Ban on Imports from|Exports to Iraq|Kuwait and Remittances to Iraq and Kuwait

16.27 Consequent upon the U. N. Resolution banning trade, etc. with Iraq and Kuwait, the Chief Controller of Imports & Exports (CCIE) issued an order on October 5, 1990, prohibiting imports and exports of all goods, whether directly or indirectly into or from any port or place in India from or to any place in Iraq and Kuwait. Accordingly, on October 11, 1990, all authorised dealers were advised not to make any remittances to Iraq or Kuwait or any remittances on account of the Government of Iraq or any of its agencies in Iraq or Kuwait or accounts of its nationals nor to enter into any transactions with any person, firm or bank resident in Iraq or Kuwait or with Iraqi nationals, without the permission of the Reserve Bank. CCIE had lifted the ban on trade with Kuwait with effect from March 14, 1991. Accordingly, the ban on trade with Iraq and restrictions on remittances, insofar as they relate to Iraq and its nationals, remain.

#### Concessions to Indian Citizens returning from Kuwait

16.28 Indian nationals in Kuwait, who were forced to return to India due to the situation prevalent in that country consequent on invasion by Iraq, have been allowed as a special case to continue to maintain their NRE|FCR accounts with banks in India as well as their foreign currency accounts and assets abroad initially up to March 31, and later up to June 30, 1991.

Facility for exchange of currency notes to Indians returning from Kuwait

16.29 Under the Exchange Control Regulations, all purchases of foreign currency notes made by authorised dealers hitherto, were at their own risk and responsibility making their own arrangements to realise the proceeds of surplus foreign currency notes purchased by them. However, consequent on the invasion of Kuwait by Iraq, authorised dealers were advised to provide, with effect from August 10, 1990 conversion facilities up to the equivalent of Indian Rs. 5,000 (this was increased up to Rs. 10,000 with effect from August 30, 1990) at the rate of Rs. 25 = 1 Kuwaiti Dinar, to returning Indians from Kuwait at all international Air|Sea ports in India. Kuwaiti Dinars purchased by authorised dealers were required to be held by them on Government Account pending realisation and the rupee payments made by them were reimbursed by the Reserve Bank of India by debit to Government account.

#### Trade and Payment Transactions between India and Poland

16.30 All transactions of both commercial and non-commercial nature between India and Poland were settled in non-convertible Indian rupees. The Government of India and Poland had concluded a new trade and payments agreement in terms of which all transactions of commercial and non-commercial nature would be settled in free foreign exchange with effect from January 1, 1991. Exporters had, therefore, been advised that they should ensure that payments in respect of contracts for export of goods from India to Poland entered into on or after January 1, 1991, were received by them in one of the permitted currencies such as US dollar, Pound sterling, etc. For contracts



entered into up to December 31, 1990, payments would continue to be received in non-convertible Indian rupees, as hitherto.

#### Indo-GDR Trade and Payments Agreement

16.31 In the context of the unification of Germany, negotiations were held between the German Democratic Republic (GDR) and the Government of India on the future of rupee payments arrangements and it had been agreed that the Indo-GDR Trade Agreement executed between the two countries on November 1, 1985 would continue up to December 31, 1990 on the existing basis of payments in non-convertible Indian rupees in respect of the specified goods. Parties desiring to settle payments in a freely convertible currency even in respect of these goods had to obtain permission from the Government of India in specific cases. In addition to the above mentioned rupee payments track bilateral trade transactions involving exports of non-specified goods from GDR to India and vice-versa were also allowed to be settled, with effect from September 28, 1990, in any freely convertible currency during the balance period till December 31, 1990.

16.32 With effect from January 1, 1991, transactions with Unified Germany are conducted in free foreign exchange. However, the contractual obligations under the contracts concluded up to December 31, 1990 in rupees in terms of Indo-GDR trade arrangement, would continue to be settled according to the terms of the contract.

#### Project Exports

16.33 During the period July 1, 1990 to June 30, 1991, the Working Group on Project Exports (WG) accorded approval for 104 proposals valued at Rs. 5,027.59 crore. These comprise of 68 proposals of turnkey contracts valued at Rs. 4,089.07 crore, 25 proposals of civil construction contracts valued at Rs. 770.39 crore and 11 proposals of consultancy service contracts valued at Rs. 168.13 crore. During the same period, the Working Group cleared 33 proposals of total value of Rs. 810.18 crore at post-award stage.

#### Subsidiaries/Joint Ventures Abroad Opening of offices abroad

16.34 During the period July 1, 1990 to June 30, 1991, 5 proposals allowing Indian companies to establish their subsidiaries abroad and 25 proposals enabling Indian companies to enter into joint ventures abroad were cleared.

16.35 During the period July 1, 1990 to June 30, 1991, Indian companies were granted approvals for opening 32 Trading Offices, 64 Non-trading Offices and posting representatives abroad in 42 cases.

#### Opening of offices in India

16.36 During the period July 1, 1990 to June 30, 1991, approval for opening 70 Liaison Offices, 16 Representative Offices and 12 Project Offices in India were granted to foreign companies

#### Purchase/Sale of Yen and DM-FCNR

16.37 Effective from August 13, 1990, the facility of purchases/sales of Japanese Yen and Deutsche Mark, under the FCNR Scheme, was also made available at the Reserve Bank's branch at Kanpur in addition to its offices/branches at Bangalore, Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi.

#### FCNRA Deposits

16.38 Authorised dealers in India have now been permitted to pay commission not exceeding one per cent of the deposits mobilised under the FCNRA Scheme with effect from November 26, 1990. The payment of brokerage would be restricted to (i) the deposits mobilised under Pension Scheme and also to (ii) other deposits of US \$ 25 million each under the FCNRA Scheme. Such deposits would be required to be kept for a minimum period of two years.

#### FCNRA-Special Deposit Scheme for the Middle East

16.39 With a view to meeting the special requirements of NRIs/OCBs residents in the countries of the Middle East, a new Scheme called 'FCNR-Special Deposit Scheme' was introduced on August 20, 1990. Under the scheme, authorised dealers are permitted to open accounts in US dollars only in the name of NRIs/OCBs resident in the countries of the Middle East, provided the funds for the purpose are transferred to India in an approved manner from the country of residence of the prospective account holder or from any other country in the External Group. The accounts are also permitted to be opened either by transfer of funds from the existing FCNR/NRE accounts of account holders or by tendering foreign currency notes and/or travellers cheques subject to the conditions laid down for the purpose. No restrictions have been placed on the number of withdrawals that could be made from these special accounts and accordingly, no interest is payable on the balances in these accounts. Loans/overdrafts cannot be granted against the security of the funds held in these accounts. The other provisions, as applicable to FCNR accounts are applicable, mutatis mutandis, to these special accounts.

16.40 Subsequently, it was decided that banks may pay interest on such deposits in cases where there is/are no further deposits/or withdrawal/s in the same account and the deposits remain with the bank for a minimum period of six months. In other words, each deposit account would qualify for interest if it is maintained for six months or for any longer period without any operation whatsoever, thereby partaking of the nature of term deposits. In such cases, the rates of interest shall be same as is applicable to deposits denominated in US dollars for period for which the deposits have remained with the banks.

#### Foreign Currency (Ordinary-Non-repatriable) Deposit Scheme

16.41 With a view to providing further incentives and giving wider options to persons of Indian nationality/origin residing abroad (NRIs) and overseas

corporate bodies predominantly owned by NRIs (OCBs), for making investments in India, Reserve Bank introduced with effect from June 17, 1991, a new Deposit Scheme viz., Foreign Currency (Ordinary)—Non-repatriable Deposit Scheme. The deposits accepted under the Scheme are to be kept denominated in US dollars for a fixed period of five years. The rate of interest is one per cent above the applicable rate for FCNR dollar deposit for three years ruling on the date of deposit. Certain benefits like availability of loans/overdrafts against the security of the deposit and tax exemption under the Indian Income Tax and Wealth Tax are also available to the depositors. The deposit will also be free from Gift Tax for one time lifting. Premature withdrawals of the deposit are permissible and the interest rate payable in such cases is the rate ruling on the date of deposit, for the period for which the deposit remained with the bank. However, the rupee equivalent of the amount so withdrawn or the maturity proceeds of the deposit including interest thereon shall have to be credited to the NRO account of the deposit holder.

#### India Equity Fund Unit Scheme-1990

16.42 Unit Trust of India (UTI) was granted permission for entering into an agreement with the India Equity Fund Inc. for raising funds abroad upto US \$ 100 million for investing in units of UTI under its special unit entitled "India Equity Fund Unit Scheme 1990"

#### NRI Bonds II series by State Bank of India

16.43 State Bank of India was granted permission for issue of Second Series of NRI Bonds to non-residents of Indian nationality/origin on non-repatriation basis. The special features of the scheme are as under :

- (a) Authorised dealers in India have been permitted to grant rupee loans for certain purposes to NRI Bondholders against the collateral of the above Bonds held by them;
- (b) These Bonds can be gifted without restriction and without attracting the provisions of Gift Tax Act once only either by the original holder or NRI transferee to any individual of Indian nationality or origin, whether he is resident in India or not or to any charitable Trust in India which is recognised under the Income Tax Act, 1961.
- (c) Joint holdings between NRI and a resident Indian who need not be a close relative are allowed.

#### Indian Opportunities Fund (IOF)

16.44 Indian Bank has been granted permission for establishment of an off-shore Fund named Indian Opportunities Fund (IOF) in Netherlands in collaboration with Perpetual Chescor, U.K. for raising funds abroad to the extent of US \$ 200 million for investing in India in the units of Indbank (Offshore) Mutual Fund established by Indian Bank.

Reinvestment of Long-term Capital Gains in 3 years IDBI Capital Bonds by NRIs on non-repatriation basis

16.45 Industrial Development Bank of India (IDBI) has been granted general permission for issue of 3 year IDBI Capital Bonds to NRIs on non-repatriation basis subject to the following conditions:

- (a) Neither the capital invested nor the income earned thereon shall be allowed to be repatriated outside India at any time in future; and
- (b) All interest accruals and maturity proceeds of IDBI Capital Bonds shall be credited to the investor's non-resident (Ordinary) Account maintained with a bank authorised to deal in foreign exchange in India.

#### 17. ORGANISATIONAL MATTERS AND ACCOUNTS OF THE BANK

##### Currency Chests

17.1 The total number of currency chests rose to 4,006 at the end of June 1991 from 3,938 a year ago. The currency chests with the Reserve Bank remained unaltered at 17 and those with State Bank of India and its associate banks increased to 2,790. The chests with nationalised banks were 649, treasuries and sub-treasuries 545 and 5 were with Jammu and Kashmir Bank Ltd. In addition, 505 repositories were maintained with public sector banks.

17.2 It has been recently decided to entrust the responsibility of establishing and maintaining currency chests to selected scheduled private sector banks however, subject to their adhering to the Bank's norms specified therefor.

##### Committee on Currency Management

17.3 A mention was made in the last year's Reports that following the submission of the Report on the Committee on Currency Management on September 30, 1990, a Standing Group and a small In-House Committee were formed by the Ministry of Finance and the Reserve Bank, respectively, with a view to implementing the recommendations of the Report insofar as they concern matters relating to the Government and the Reserve Bank, respectively. Apart from the deliberations of the Standing Group, discussions have been held with the Government of India to sort out certain policy issues concerned with the implementation of the recommendations.

##### Broader Measures of Currency Management

17.4 There has been a phenomenal growth in the circulation of currency during the last decade which has resulted in a steep rise in the demand for fresh currency bank notes. The existing two note printing presses at Nashik and Dewas, whose production capacities have remained somewhat static, have not been able to meet fully the indent placed on them. This situation, coupled with a high turnover, has resulted in inadequate availability of fresh notes. With the plans for modernisation of

the existing two note printing presses by the Government, the setting up of two new note printing presses by the Reserve Bank and the proposal to coincide, in a phased manner, Re. 1 Rs. 2 and Rs. 5 denomination notes which constitute the bulk of the notes in circulation, the availability of fresh notes should improve. The supply position of small coins is comfortable and there is adequate stock to meet any demand.

### Currency Forecasting

17.5 The Reserve Bank had entrusted the work of forecasting the currency requirement to the Indian Statistical Institute, Calcutta. The Institute has since submitted its Report and the projections made by it are being scrutinised by the Reserve Bank.

### New Note Press Project

17.6 The new note press projects at Mysore (Karnataka) and Salboni (West Bengal), which was transferred from the Government to the Reserve Bank of India in January 1990, are in progress and phase I of the project has been completed. Techno-economic reassessment of different technologies for printing bank notes has also been completed. Further, action regarding identification of the successful tenderer is in advanced stages of completion. Insofar as the notes of lower denominations are concerned, it was decided to invite re-tenders for web technology so that it could be possible to have a proper evaluation of the alternatives possible.

### Surveys

17.7 The results of the 'Survey of Foreign Currency (Non-Resident) and Non-Resident (External) Rupees Accounts for July 1985 to June 1988' which classifies external deposits, according to maturity pattern, sources of funds and interest rates were published in June 1991 issue of the Reserve Bank of India Bulletin. A mention was made in the last year's Report regarding the Census of India's Foreign Liabilities and Assets with the reference year ended March 31, 1987. An article embodying the Census results appeared in the Reserve Bank of India Bulletin, July 1989. The results of the Annual Foreign Investment Survey (AFIS), March 1988, were used to update the Census details and the detailed article on India's Foreign Liabilities and Assets as at the end of March 1987, along with the provisional estimates for the year ended March 1988, were published in April 1991 issue of the Reserve Bank of India Bulletin. The position is being updated for end March 1989 based on the AFIS, March 1989. The All India Debt and Investment Survey, 1991-92, will be conducted by the National Sample Survey Organisation in their 48th Round during the calendar year 1992. The Bank is actively associated with the technical work of design, schedules, tabulation formats, etc., for the Survey.

### Progress of Computerisation

17.8 Computer Systems have been installed in Urban Banks' Department (Central Office), Department of Expenditure and Budgetary Control, Department

of Government and Bank Accounts, Premises Department, Management Services Department, Training Division, Department of Economic Analysis and Policy, Department of Currency Management, Claims Section of Issue Department in Bombay Office and also for the use of Deputy Governors and the Governor's Secretariat. Additional systems were supplied to Department of External Investments and Operations and Reserve Bank Staff College, Madras. Word processors have been provided to Department of Banking Operations and Development (Central Office), Exchange Control Department, Secretary's Department, Management Services Department and History Cell. The Computer Systems installed in the Issue Department at Byculla, Ahmedabad, Nagpur and New Delhi have been replaced by upgraded systems. Issue Department Computer Systems have also been installed at Bangalore, Hyderabad, Kanpur, Trivandrum, Jaipur, Madras and Patna.

17.9 The process of replacement of present Cii-Honeywell Bull Mainframe Computer System in the Department of Statistical Analysis and Computer Services (DESACS) by a state of art large Mainframe Computer System with on-line data communication facility is underway. Plans to replace the present BDP-100 Microprocessor System used for processing payrolls of Bombay-based employees by a pair of state-of-art minicomputers are at an advanced stage. The process of acquisition of personal computers for Central Office of IECD, Financial Institutions Cell and 7 more regional offices of ECD is in progress. The Commonwealth software CS-D RMS (Version 4.3) to process the external commercial loans has been installed on a PC and the details of all loans up to March 1990 have already been captured. A more powerful version to speed up the processing is proposed to be installed shortly. For this purpose, a sophisticated PC hardware is being acquired.

### Office Automation

17.10 FAX machines have been installed in Department of External Investment & Operations, Exchange Control Department, Personnel Policy Department and Offices at New Delhi, Madras and Calcutta. It has been decided to install FAX machines at some more premises for the use of Central Office Departments in Bombay and at all the remaining Offices.

17.11 It has also been decided in principle to replace Ledger Posting Machines by installing Advanced Ledger Posting Machines with Local Area Network arrangements at Bombay, New Delhi, Madras, Bangalore and Hyderabad.

### L.K. Jha Memorial Lecture

17.12 In recognition of the meritorious service rendered by the late Shri Lakshmi Kant Jha, former Governor of the Reserve Bank of India, to the Bank and to the nation and also to perpetuate his memory, the Reserve Bank of India has instituted an annual lecture series styled as L.K. Jha Memorial Lecture. The inaugural lecture on the theme entitled 'Economic Liberalism, Central Banking and the Developing

World' was delivered by Mr. Robin Leigh-Pemberton, Governor, Bank of England, on October 16, 1990 in Bombay.

#### SEANZA-Central Banking Course

17.13 The Reserve Bank of India was the host for the Eighteenth South-East Asia, New Zealand and Australia (SEANZA), Central Banking Course for the second time, after a span of 30 years. The Course was held at the Indira Gandhi Institute of Development Research, Goregaon (Bombay), from October 29 to December 14, 1990. There were in all 25 participants, of whom 3 were members of the Directing Staff. With the exception of two (Bangladesh and Philippines), all the SEANZA member countries were represented at the Course. Besides, there were participants from Canada, Tanzania, the United Kingdom, the United States of America and Vanuatu (an associate member). The Course, as in the past, culminated with a Governors' Symposium on December 14, 1990 on 'Jurisdiction and Autonomy of Central Banks' which was presided over by the Governor of the Reserve Bank of India and attended by Governors. Deputy Governors and other representatives of the SEANZA Central Banks.

#### History of Reserve Bank

17.14 A mention was made in last year's Annual Report about the setting up of a separate History Cell to bring out further volumes of the publication 'The History of the Reserve Bank of India'. The Cell has since been set up and the drafting of the volume covering the developments up to 1967 is in progress.

#### Indira Gandhi Institute of Development Research

17.15 The Indira Gandhi Institute of Development Research, established by the Bank in Bombay, has completed studies in the area of food and fertiliser subsidy, oil substitution in transport sector by natural gas & technology assessment for R&D policy in superconductors. During the year, work continued on the studies in energy policy, agricultural and rural development policies, industrial sector, macro-economic and monetary policy issues, external sector and environmental aspects. The Institute also conducted Conferences and Workshops on relevant topics. A four-year Ph.D Programme in Development Policy, in affiliation with the Bombay University, was commenced in August 1990.

#### Bankers Training College (BTC) Bombay

17.16 The new programmes introduced by BTC during the year were in the areas of computer security and audit/inspection of banks under computerised environment, auditing dealing room operations, deferred payment and project exports financial innovations, borrowings in international financial markets, creativity and organisational excellence, and managerial effectiveness and value system.

17.17 During the year, the College conducted 104 programmes, including 10 programmes in Hindi with 2,085 participants, bringing the total number of

participants trained at the College since its inception in 1954 to 41,378.

#### Reserve Bank Staff College (RBSC) Madras

17.18 During the year, the RBSC continued to conduct broad spectrum, as also functional, training programmes. These included the Intensive Induction Programmes for newly recruited officers in Grades 'A', and 'B', and for Research Officers in the Department of Economic Analysis and Policy and the Department of Statistical Analysis and Computer Services. The new programmes introduced include SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), for officers in National Clearing Cell, PC application, 'd-base' programme, and workshop on Currency Chest Inspections.

17.19 During the year, the College conducted 69 programmes with 1,316 participants, bring the total number of participants trained since its inception in 1963 to 26,863.

#### College of Agricultural Banking (CAB), Pune

17.20 The College continued to cater to the training needs of personal of co-operative banks, commercial banks, Regional Rural Banks, NABARD, Reserve Bank, and Government officials. During the year the College introduced two new programmes viz., (i) Credit Appraisal for Officers of Primary Co-operative Banks and (ii) Service Area Planning and Poverty Alleviation Programme. The College also conducted a 4-day Seminar on Development of Wasteland, Forestry, Rainfed Farming, Plasticulture and Agro-Climatic Zones. Besides, an international programme was conducted on behalf of the Asian and Pacific Regional Agricultural Credit Association (APRACA) in July 1990.

17.21 During the year the College conducted 94 programmes imparting training to 2,076 officers, raising the number of officers trained by the College since its inception in 1969 to 38,056.

#### Zonal Training Centres

17.22 The Zonal Training Centres (ZTC) at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi imparted training during the year to 1,769 Class III and 232 Class IV staff, raising the total number of staff trained by the ZTC to 38,100 and 2,689 respectively.

#### Training in Commercial Banks

17.23 Under the scheme of training of the Bank's Officers in commercial banks, so far 76 officers have completed the training since its introduction in 1986. Presently the third batch of 40 officers is undergoing training. During the year, four senior officers have been selected for in-depth exposure in key departments of commercial banks for a period of six months.

#### Deputation of Staff for Training in India and Abroad

17.24 During the year, the Bank deputed 275 officers to participate in training programmes, seminars and conferences organised by management

banking institutions in India. Two officers are currently undergoing M. Phil course in Applied Economics at the Centre for Development Studies, Trivandrum. The Bank had deputed 23 officers for training study to banking and financial institutions in the USA, the UK, France, Switzerland, Germany, Japan, Singapore, China, Bangladesh, Thailand and South Korea.

17.25 Under the Scheme for award of scholarships to the officers of the Bank formulated as part of its Golden Jubilee Celebrations, four officers were selected during the year, who have proceeded for higher studies at various institutions abroad.

#### Training Facilities to Officers of Foreign Banks

17.26 During the year, 48 foreign officials from different countries, i.e., 9 from Afghanistan, 7 each from Kenya and Iran, 5 each from Nepal and Ethiopia, 2 each from Gambia, Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria and Bhutan, one each from Somalia, Uganda, Tanzania, Germany and an economist from the Asian Development Bank, were given facilities for training study.

#### Training in Computer Technology

17.27 The Bank's scheme of incentives for acquiring qualifications and training in the field of computers continued during the year.

#### Scheme of Incentives for Acquiring Professional Qualifications

17.28 The Bank has been offering incentives (like reimbursement of tuition fees etc.) to employees in Classes I and II who complete the CFA programme conducted by the Institute of Chartered Financial Analysts of India (ICFAI), Hyderabad, in pursuance of the policy of encouraging staff members to acquire professional knowledge in different spheres. So far 103 employees have been granted permission to join the programme.

#### Scheme of Sponsorship for Ph.D.

17.29 With a view to encouraging officers from Department of Economic Analysis and Policy to acquire specialisation and upgradation of professional skills, it has been decided to sponsor up to four officers (two each in two semester programmes) every year at the Indian Institute of Technology, Bombay and two officers at the Indira Gandhi Institute of Development Research, Bombay, for pursuing their Ph.D. programmes. In both cases, the officers selected will be given necessary facilities to pursue their studies as external candidates.

#### New Film on RBI

17.30 A new film of 50 minutes duration, on functions and working of the Reserve Bank, has been produced in English and Hindi.

#### Employer-employee Relations

17.31 Industrial Relations climate in the Bank continued to be generally peaceful during the year under review.

689 GJ/92—78

17.32 As reported in the previous year's Annual Report, the Pension Scheme, in substitution of the Bank's Contributory Provident Fund Scheme, was announced on January 16, 1990. After receipt of the Central Government's approval, the Scheme came into force from November 1, 1990. All employees joining the Bank's service on and from November 1, 1990 will thus be governed by the Reserve Bank of India Pension Regulations, 1990, while the employees in service as on November 1, 1990 were given the option to continue with the earlier Contributory Provident Fund Scheme, if they so desired. The Pension Scheme covers the ex-employees who were in the Bank's service and retired on or after January 1, 1986; pension is, however, payable to them from November 1, 1990 only, on their surrendering the Contributory Provident Fund benefits already drawn by them together with interest.

17.33 Under the Bank's Golden Jubilee Scholarship Scheme instituted in 1985, for meritorious performance by wards of employees, 120 wards were awarded scholarship leading to XII Standard and 70 wards were awarded scholarship for graduate studies.

#### Birth Centenary of Dr. B. R. Ambedkar

17.34 In order to commemorate the birth centenary of Bharat Ratna Dr. B. R. Ambedkar, the Bank announced the establishment of a Fund with a corpus of Rs. 50 lakh for the benefit of its SC/ST employees. The interest from the Fund will be utilised for improving the educational/professional qualifications and operational skills of the Bank's SC/ST employees, including scholarship schemes for their children. Appropriate schemes will be formulated by an internal Committee headed by a Director of the Bank's Central Board. As part of the birth centenary celebrations, the Bank has also established a Professorial Chair designated as Dr. Babasaheb Ambedkar Professorship in Political Economy at the Department of Economics, University of Bombay, Bombay.

#### Financial Institutions Cell

17.35 The Financial Institutions Cell was set up in August 1990 by the Bank to function as a nodal unit for matters pertaining to financial institutions. Initially, eleven All-India Financial Institutions (viz., IDBI, IFCI, IRBI, ICICI, NABARD, Exim Bank, NHB, SIDBI, UTI, LIC and GIC) are proposed to be covered by the Cell. The principal objectives in setting up the Cell are (i) to broadly oversee the operations of these institutions so as to bring about a better functioning of the financial system and to achieve greater co-ordination between banks and financial institutions; (ii) to introduce a system of annual assessment of the quality of assets of the financial institutions; (iii) to organise periodical interaction between top management of the Reserve Bank and those of the financial institutions so as to identify broader areas where changes/improvements are called for. The Cell has already introduced a quarterly information system, which is operative from the quarter April-June 1991.

### Employment to Reserved Categories: Scheduled Castes/Scheduled Tribes

17.36 Of the total direct recruitment in the Bank during the calendar year 1990, the representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes in different categories was as under:

Category/Class	Total number of candidates recruited	Of them		Percentage	
		SC	ST	SC	ST
Class I	116	21	5	18.1	4.3
Class III	436	77	66	17.7	15.1
Class IV	433	192	41	44.3	9.5
of which					
(a) Excluding Sweepers	377	159	29	42.2	7.7
(b) Sweepers	56	33	12	58.9	21.4

17.37 With this the total number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the Bank as on January 1, 1991 rose to 2,302 and 689 in Class IV, 2,355 and 1,056 in Class III, and 464 and 111 in Class I respectively.

### Ex-Servicemen

17.38 During the calendar year 1990, out of 436 and 433 vacancies filled in Classes III and IV, 63 and 106 were required to be reserved for ex-servicemen at the prescribed rates of reservation of 14.5 and 24.5, respectively. As against this, 22 vacancies in Class III and 38 in Class IV were filled up by appointing ex-servicemen, raising their total strength in the Bank to 761 in Class III and 1,027 in Class IV as on December 31, 1990. As per the Central Government's directives, the reservation of 14.5 per cent in Class III and 24.5 per cent in Class IV is further bifurcated to provide 10 per cent and 20 per cent reservations, respectively, for ex-servicemen and the remaining 4.5 per cent in each class (Classes III and IV) to disabled ex-servicemen and/or dependents of ex-servicemen, killed in action, respectively.

### Physically Handicapped Persons

17.39 During the calendar year 1990, 8 handicapped persons were recruited in Classes III and IV raising the total number of handicapped employees in the Bank to 385. In addition to the jobs identified in September 1980 for physically-handicapped persons, the posts of Sweeper and Farash in Class IV have been identified for partially-blind persons (who are not deaf and/or dumb).

### Promotion of Hindi

17.40 During the year, the Bank continued its efforts to accelerate the use of Hindi. Besides the publication—in bilingual form of the Bank's regular reports and publications such as, Annual Report, Report on Trend and Progress of Banking in India, Report on Currency and Finance, Reserve Bank of India Bulletin, RBI Newsletter, Credit Information Review, RBI Productivity News, Basic Statistical Returns, etc., certain important manuals/publications such as, Exchange Control Manual (a Hindi version), Premises Department Manual, circulars relating to

Industrial and Export Credit Department for the period 1986-89 (July-June), Tender Agreement Forms, Report of the Committee on Computerisation in Banks and the Reserve Bank of India Act, 1934, have also been published both in Hindi and English.

17.41 During the year, training in Hindi was imparted to 832 employees/officers in Hindi Workshops, 186 officers under intensive training programme and 12 senior officers under functional Hindi training programme. The Bank also organised the Ninth Hindi Workshop for senior officers through Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad, in which 19 officers participated.

17.42 A Committee consisting of officers of Rajbhasha Division and Chiefs of Hindi Departments of some of the public sector banks was set up in March 1990 to revise and update 'Banking Shabdavali' in Hindi for terms used in English with a view to ensuring uniformity in usage of Hindi terms in public sector banks. Besides, preparation of 'Banking Paribasha Kosh', an interpretative dictionary of banking terms in Hindi, is also in progress.

17.43 Inter-departmental shield competitions at various offices as well as inter-office competition and competition between Central Office departments were held and shields awarded. During the year, Hindi functions were held at various centres to commemorate September 14 as Hindi Diwas which evoked good response from employees.

17.44 A Hindi quarterly journal titled 'Banking Chintan Anuchintan' published by the Bank has acquired wide popularity among banks and financial institutions. Similarly, the Bank's house magazine 'without Reserve' continued to be published with appropriate coverage in Hindi.

### Office Buildings and Residential Accommodation

17.45 During the year 1990-91 (July-June), a sum of Rs. 16.69 crore was spent on construction/acquisition of office buildings and residential quarters, as also additions and alterations to the existing premises. The construction of office building at Bhopal and an annexe to office building at New Bombay was completed during the year. Constructions of office buildings at Jammu and the Bankers Training College at Hyderabad are in advanced stages. 92 officers' quarters at Bombay and 224 staff quarters for Class III and IV at Lucknow were completed during the year.

17.46 Constructions of 553 officers' quarters and 228 staff quarters are in progress at Ahmedabad, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Jaipur, Lucknow and Madras. In addition, proposals to construct additional office building at New Bombay and residential quarters at New Bombay, Patna, Nagpur and Thiruvananthapuram are under way.

### Holiday Home

17.47 Efforts are on to acquire property to establish a Holiday Home at Darjeeling.

## Housing Loan

17.48 Major developments, policy changes, etc., in regard to Housing Loan Scheme during the period from July 1, 1990 to June 30, 1991 are as under :

- (i) Effective from March 1, 1991, the minimum limit of housing loan to Class III employees has been raised to Rs. 1,25,000 from the present Rs. 1,00,000. The minimum limit of housing loan to Class IV employees has also been raised from Rs. 75,000 to Rs. 88,000 effective from July 1, 1990 and then further to Rs. 1,13,000 effective from April 1, 1991.
- (ii) Effective from November 15, 1990, the minimum service for availing P. F. advance for housing purposes has been reduced from the present 5 years to 3 years of continuous service including temporary service of the employee in the Bank.
- (iii) Effective from September 1990, the aggregate ceiling of housing loan and P. F. advance/withdrawal together for acquisition/construction of houses/flats to employees in Classes III and IV has been raised from Rs. 2,25,000 to Rs. 3,00,000 with a further discretion to the extent of 25 per cent of the aggregate ceiling to the sanctioning authority.
- (iv) Construction cost of a garage as also stamp duty/registration charges were hitherto not considered admissible under the Bank's housing loan Scheme. Effective from September 1990 these items are considered admissible under the scheme provided the construction of a garage forms part of the original plan/project and stamp duty/registration charges are included in the total (original) cost of acquisition of flat/house.

17.49 During the year 1990-91 (July-June), housing loan sanctioned to employees (Societies/Individuals) amounted to Rs. 19.49 crore as detailed below.

Category	No. of societies	No. of employees	Amount of loan
1	2	3	4
(A) Co-operative Housing Societies	29	302	1,80,99,576
(i) Fresh loans	5	85	61,79,569
(ii) Additional loans	24	217	1,19,20,007
(B) Individual loans sanctioned by Central Office		482	5,29,40,589
(i) Fresh loans	---	360	4,89,30,685
(ii) Additional loans	---	122	40,09,904
(C) Individual loans sanctioned by Regional Offices		1,710(*)	12,38,89,659(*)
(i) Fresh loans		718(*)	7,86,56,212(*)
(ii) Additional Loans		99(*)	4,52,33,447(*)
Total of A+B+C	29	2,494(*)	19,49,29,824(*)

(\*) Data from Bhubaneswar and Patna Offices are not included for the year.

Data in respect of Bhopal and Kanpur offices for the period ended September 30, 1990 only.

Data in respect of Calcutta (Issue) for the period ended December 31, 1990 only.

Data in respect of Byculla, Chandigarh and Jammu offices for the period ended March 31, 1991 only.

## Central Board/Local Boards

17.50 Shri R. N. Malhotra relinquished charge of the office of the Governor of the Bank in the forenoon of December 22, 1990 and Shri S. Venkitaramanan, former Finance Secretary, Government of India, was appointed to succeed him as Governor of the Bank with effect from the same day, i.e., December 22, 1990. The Board wishes to place on record its high appreciation of the services rendered by Shri R. N. Malhotra as the Governor of the Bank and the Chairman of its Central Board.

17.51 Dr. Bimal Jalan ceased to be the Government nominee on the Central Board with effect from January 3, 1991 consequent on his appointment as Chairman, Economic Advisory Council to the Prime Minister and Shri S. P. Shukla, Finance Secretary, was nominated in his place from that date. The Board wishes to place on record its appreciation of the services rendered by Dr. Bimal Jalan during his tenure as a Director on the Central Board.

17.52 The Board learnt with profound sorrow of the sad demise of Shri N. S. Bhatt, a member of the Southern Area Local Board of the Bank on December 4, 1990. The Board wishes to place on record its deep sympathy to the members of his family in their bereavement.

17.53 Shri M.L.T. Fernandes was appointed as Executive Director with effect from February 1, 1991.

## Accounts : (i) Income

17.54 During the accounting year ended June 30, 1991, the Bank's income, after making adjustments for various provisions increased by 4.5 per cent to Rs. 4,624.97 crore from Rs. 4,426.73 crore of the previous years. The sources of income are given

	(Rupees crore*)
(a) Interest on Securities, Loans and Advances to banks, financial institutions, State Governments etc. (including interest on foreign securities, deposits, etc.)	3,415.56
(b) Discount on rupee and foreign treasury bills	962.01
(c) Exchange on remittances, T T purchased, etc. (including foreign transactions)	219.79
(d) Commission on management of public debt and other miscellaneous income	27.61
	4,624.97

17.55 There was an increase of Rs. 85.10 crore in interest earnings during 1990-91 due to a rise in the average holdings of rupee securities as also an increase in securities bearing higher interest rates. Discount earned registered a decline of Rs. 99.08 crore mainly on account of lower holdings of foreign treasury bills.

## (ii) Expenditure

17.57 Of the interest payments at Rs. 2,547.70 crore, a major item was the interest payments at Rs. 2,431.02 crore during 1990-91 to Scheduled commercial banks on the eligible additional cash balances maintained with the Bank, this item constituted 74.1 per cent to total expenditure.

17.57 Of the interest payments at Rs. 2,547.70 crore a major item was the interest payments at Rs. 2,431.02 crore during 1990-91 to Scheduled commercial banks on the eligible additional cash balances maintained with the Bank; this item constituted 74.1 per cent to total expenditure.

17.58 Establishment costs went up by Rs. 15.30 crore to Rs. 243.69 crore and formed 7.4 per cent of the total expenditure mainly on account of periodic increase in dearness allowance to staff in all categories and annual increments in the time scales of pay.

17.59 Security printing and incidental costs, which constituted 5.0 per cent of the total expenditure, were higher by Rs. 18.57 crore at Rs. 162.28 crore and due to increases in the rates for printing of note forms and in the supply of note pieces particularly in the higher denominations.

17.60 A higher turnover in Government transactions handled by agency banks resulted in agency charges registering a rise of Rs. 4.4 crore to Rs. 265.62 crore and formed 8.1 per cent of the total expenditure.

17.61 Out of the net disposable income in 1990-91 at Rs. 1345.00 crore compared to Rs. 1170.12 crore for the previous year, contributions to the statutory funds are as shown below:

	(Rupees crore s)	
	1990-91	1989-90
National Industrial Credit (Long-Term Operations) Fund	525.00	525.00
National Rural Credit (Long-Term Operations)	1400.00	375.00
National Rural Credit Stabilisation) Fund	20.00	10.00
National Housing Credit (Long-Term Operations) Fund	50.00	50.00
	995.00	960.00

17.62 A surplus of Rs. 350.00 crore was transferred during 1990-91 to the Union Government as against Rs. 210.12 crore transferred in the previous year.

## Balance Sheet

### Bank Deposits

17.63 The aggregate deposits of scheduled commercial banks, scheduled state co-operative banks other scheduled co-operative banks and other banks rose by Rs. 4,869.57 crore from the previous year's level of Rs. 26,725.09 crore to Rs. 31,594.66 crore. The bulk of the deposits of Rs. 30,789.62 crore was from scheduled commercial banks towards maintenance of the cash reserve ratio.

### Other Deposits

17.64 The rise of Rs. 3,726.45 crore in other deposits, from the last year's level of Rs. 2,142.17 crore, to Rs. 5,868.62 crore was mainly on account of increase in the balance in IMF Account No. 1.

### Gold Coin and Bullion

17.65 Consequent on an amendment to Section 33(4) of the Reserve Bank of India Act, 1934, gold which was hitherto valued at 0.118489 fine grms. rupee is being valued at a rate 'not exceeding the international price'. Gold was revalued on October 17, 1990 at Rs. 1,991.64 per 10 grms. and the appreciation in the value of gold credited to the Reserve Fund as was done on previous occasions in 1956 and 1969, raising the Reserve Fund by Rs. 6,350 crore to Rs. 6,500 crore.

### Foreign Exchange Assets

17.66 Foreign exchange reserves include 'Foreign Securities' in Issue Department and 'Balances Held Abroad' and a part of the 'Investments' in Banking Department. These reserves stood at Rs. 5,356.17 crore as on June 30, 1990, declined sharply by Rs. 2,973.48 crore to Rs. 2,382.69 crore as on June 30, 1991.

### Government of India Rupee Securities and Investments

17.67 The investments in Government of India Rupee Securities and shares, which were Rs. 79,153.71 crore as on June 30, 1990, registered an increase of Rs. 17,256.40 crore to Rs. 96,410.11 crore as on June 30, 1991 mainly on account of increase in investments in Government of India Rupee Securities.

### Loans and Advances

17.68 The credit extended to scheduled banks and financial institutions registered a sharp increase of Rs. 4,085.74 crore from Rs. 5,420.69 crore as at end of June 1990 to Rs. 9,506.43 crore as at the end June 1991 mainly owing to higher outstandings under discretionary finance (Rs. 1,546.00 crore) and export refinance (Rs. 4,468.00 crore) against scheduled commercial banks and higher dues from NABARD mainly on account of loans extended to State Governments toward meeting the States' share of agricultural loans written off under Agricultural and Rural Debt Relief Scheme, 1990.



## Auditors

17.69 The accounts of the Bank have been audited by M/s. Khanna & Annadhanam, New Delhi, M/s. Amit Ray & Co., Allahabad, M/s. Mookherjee, Biswas and Pathak, Calcutta, M/s. Sorab S. Engineer & Co. Bombay, M/s. S. K. Kapoor & Co., Kanpur and

M/s. Brahmayya & Co., Madras. While the first five auditors were re-appointed by the Government of India for 1990-91, M/s. Brahmayya & Co., was the newly appointed auditor for the current year in place of M/s. S. Viswanathan. All the offices of the Bank, divided into six zones, were audited by the Statutory Auditors.

RESERVE BANK OF INDIA  
BALANCE SHEET AS AT 30TH JUNE 1991

(Rs. Thousands)					
Liabilities	1990-91 Rs.	1989-90 Rs.	Assets	1990-91 Rs.	1989-90 Rs.
Notes held in the Banking Department	11,87,86	18,21,19	Gold Coin and Bullion :		
Notes in circulation	57858,45,88	500082,26,71	(a) Held in India	7410,79,89	280,66,99
Total Notes issued	57870,33,74	50100,47,90	(b) Held outside India		
			Foreign Securities	200,00,00	1564,05,75
			Total	7610,79,89	1844,72,74
			Rupee Coin	91,46,03	38,96,21
			Government of India Rupee Securities	50168,07,82	48216,78,95
			Internal Bills of Exchange and other Commercial Paper		
Total Liabilities	57870,33,74	50100,47,90	Total Assets	57870,33,74	50100,47,90

## BANKING DEPARTMENT

LIABILITIES	Rs.	Rs.	ASSETS	Rs.	Rs.
Capital paid up	5,00,00	5,00,00	Notes	11,87,86	18,21,19
Reserve Fund	6500,00,00	150,00,00	Rupee Coin	10,89	10,50
National Industrial Credit (LTO) Fund	5675,00,00	5150,00,00	Small Coin	6,96	6,09
National Housing Credit (LTO) Fund	175,00,00	125,00,00	Bills Purchased and Discounted :		
(a) Deposits			(a) Internal		
(i) Central Government	105,62,06	140,86,96	(b) External		
(ii) State Governments	15,75,60	16,66,84	(c) Government Treasury Bills	399,20,21	1796,88,03
(b) Banks			Balances Held Abroad	2087,54,77	2378,33,76
(i) Schedule : Commercial Banks	30789,61,72	26026,15,69	Investments	46337,16,59	32350,68,89
(ii) Scheduled State Co-operative Banks	548,01,79	464,62,78	Loans and Advances to :		
(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	188,13,88	122,37,20	(i) Central Government		
(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks	10,89,76	15,00,46	(ii) State Governments	16,99,00	10,64,00
(v) Other Banks	57,98,58	96,93,35	Loans and Advances to :		
			(i) Scheduled Commercial Banks	6104,28,23	2467,31,94
			(ii) Scheduled State Co-operative Banks	18,83,64	27,42,25
			(iii) Other Scheduled Co-operative Banks	9,83	
			(iv) Non-Scheduled State Co-operative Banks		
			(v) NABARD	3322,36,70	2858,34,67
			(vi) Others	60,84,16	67,61,00
			Loans, Advances and Investments from National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund :		
			(a) Loans and Advances to :		
			(i) Industrial Development Bank of India	3705,15,46	3822,30,46
			(ii) Export Import Bank of India	745,00,00	625,00,00
			(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	130,00,00	95,00,00
			(iv) Others	100,00,00	
			(b) Investments in bonds/debentures issued by :		

1	2	3	4	5	6
(c) Others	5868,61,65	2142,17,20	(i) Industrial Development Bank of India	—	—
			(ii) Export Import Bank of India	—	—
Bills Payable	185,22,75	112,86,03	(iii) Industrial Reconstruction Bank of India	—	—
Other Liabilities	15853,01,52	14170,38,53	(iv) Others	—	—
			Loans, Advances and Investments from National Housing Credit (Long Term Operations) Fund :		
			(a) Loans and Advances to National Housing Bank	125,00,00	75,00,00
			(b) Investments in bonds/debentures issued by National Housing Bank	—	—
			Other Assets	2513,35,01	2145,13,12
Total Liabilities	6597789,31	48738,05,05	Total Assets	65977,89,31	48738,05,05

1. Includes increase of Rs. 6,350 crores due to revaluation of gold coin and bullion.
2. Includes contingency accounts.
3. Includes Rs. 95.14 crores (previous year Rs. 1,413.77 crores) held abroad in foreign currencies.

(Rs. Thousands)

## PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 30TH JUNE, 1991

INCOME	1990-91 Rs.	1989-90 Rs.
Interest, Discount, Exchange, Commission, etc.	4642,97,34	4426,72,53
Total	4624,97,34	4426,72,53
EXPENDITURE		
Interest	2547,69,66	2571,33,44
Establishment	243,68,89	228,38,92
Director's and Local Board Members' Fees & Expenses	5,34	5,68
Remittance of Treasure	4,73,59	5,69,19
Agency Charges	265,62,23	261,25,11
Security Printing (Cheque, Note forms, etc.)	162,27,50	143,71,16
Printing and Stationery	2,54,43	2,68,50
Postage and Telecommunication charges	4,68,05	2,77,54
Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	12,78,63	13,10,37
Auditor's Fees and Expenses	9,16	9,65
Law Charges	11,44	22,46
Depreciation and Repairs to Bank Property	20,28,00	19,82,26
Miscellaneous Expenses	15,40,32	7,46,49
Total	3279,97,34	3256,60,77
	1345,00,00	1170,11,76
Available Balance		
LESS : Contributions to National Industrial Credit		
(Long Term Operations) Fund	525,00,00	525,00,00
National Rural Credit		
(Long Term Operations) Fund <sup>a</sup>	400,00,00	375,00,00
National Rural Credit		

(Stabilisation) Fund	20,00,00	10,00,00
National Housing Credit		
(Long Term Operations) Fund	50,00,00	50,00,00
	995,00,00	960,00,00
Surplus Payable to Central Government	350,00	210,11,76.00

1. After making the usual or necessary provisions in terms of Section 47 of the Reserve Bank of India Act, 1934.
2. These funds are maintained by National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).

(V.G. Athavale)	(R. Janakiraman)	(P.R. Nayak)	(C. Rangarajan)	(A. Ghosh)	(S. Venkataraman)
Chief Accountant	Deputy Governor	Deputy Governor	Deputy Governor	Deputy Governor	Governor

## TO THE PRESIDENT OF INDIA

We, the undersigned Auditors of the Reserve Bank of India, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet of the Bank as at 30th June 1991 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date.

We have examined the above Balance Sheet of the Reserve Bank of India as at 30th June, 1991 and the Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date and report that where we have called for explanations and information from the Bank such information and explanations have been given and have been satisfactory. In our opinion and according to the best of our information and explanations given to us and as shown by the books of accounts of the Bank, the Balance Sheet is a full and fair, Balance Sheet containing all necessary particulars and is properly drawn up in accordance with the Reserve Bank of India Act, 1934 and Regulations framed thereunder so as to exhibit a true and correct view of the state of the Bank's affairs.

M/s. Sorab S. Engineer & Co. Auditors	M/s. Khanna & Annadhanam Auditors	M/s. Amit Ray & Co. Auditors	M/s. Mookherjee Biswas & Pathak Auditors	M/s. S.K. Kapoor & Co. Auditors	M/s. Brahmayya & Co. Auditors
---	---	---------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

Dated 16th August, 1991

[F. No. 19/23/91-Bo. I]  
M.S. SEETHARAMAN, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1992

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1992

का.आ. 938 राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध (स्कीम, 1970 के खण्ड 9 के साथ पठित खण्ड 3 के उपखण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद् द्वारा श्री अनिल कुमार जना, मुख्य अधिकारी, इण्डियन बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता को 12 मार्च, 1992 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे इण्डियन बैंक के एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इन्में से जो भी पहले हो, इण्डियन बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एक. 9/8/91-बो-ओ. 1]

एम. एस. सीथारामन, अधीन सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 12th March, 1992

S.O. 938.—In pursuance of sub-clause (c) of clause 3 read with clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Anil Kumar Jana, Chief Officer, Indian Bank, Regional Office, Calcutta, as a Director on the Board of India Bank with effect from the 12th March, 1992 for a period of three years or until he ceases to be an officer of Indian Bank, whichever is earlier.

[F. No. 9/8/91-B.O. 1]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

का.आ. 939 --राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम 1970 के खण्ड 9 के साथ पठित खण्ड 3 के उप खण्ड (ग) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात्, एतद् द्वारा, श्री सुनील कुमार मुखोपाध्याय, मुख्य अधिकारी, विपणन विभाग, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, प्रधान कार्यालय, कलकत्ता को 12 मार्च, 1992 से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वे यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया के एक अधिकारी के रूप में अपनी सेवा छोड़ नहीं देते हैं, इन्में से जो भी पहले हो, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. एक. 9/14/91-बो-ओ. 1]

एम. एस. सीथारामन, अधीन सचिव

New Delhi, the 12th March, 1992

S.O. 939.—In pursuance of sub-clause (c) of clause 3 read with clause 9 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby appoints Shri Sunil Kumar Mukhopadhyay, Chief Officer, Marketing Department, United Bank of India, Head Office, Calcutta, as a Director on the Board of United Bank of India with effect from the 12th March, 1992 for a period of three years or until he ceases to be an officer of United Bank of India, whichever is earlier.

[F. No. 9/14/91-B.O. 1]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

(अध्यक्ष विभाग)

New Delhi, the 11th March, 1992

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1992

का.आ. 940.—प्रविधिविधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित लोक संस्थान को शामिल करती है :—

“इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बम्बई” ।

[सं. 4(1)-संस्था, V/92(I)]

जी. जोसेफ, निदेशक

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 11th March, 1992

S.O. 940.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby adds to the Schedule to the said Act the name of the following public institution, namely :—

“Indira Gandhi Institute of Development Research, Bombay.”

[No. 4(1)-E.V./92 (I)]

G. JOSEPH, Director

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1992

का.आ. 911.—प्रविधिविधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के अन्वय (धारा 6 के अन्तर्गत) इन्दिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, बम्बई के कर्मचारियों के लाभ के लिए संस्थापित प्रविधिविधि का अन्वय होगा ।

[सं. 4(1)-संस्था-VI/92(II)]

जी. जोसेफ, निदेशक

S.O. 941.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act (except section 6-A) shall apply to the Provident Fund established for the benefit of the employees of the Indira Gandhi Institute of Development Research, Bombay.

[No. 4(1)-E.V./92(II)]

G. JOSEPH, Director

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1992

का.आ. 942.—राजनीतिक कौंसल (श्रावण एवम् शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत का मुख्य कौंसल, मेडान में सहायक श्री जे.एम. सार्कार को 3 फरवरी, 1992 में कौंसल एजेंट का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[सं. टी-4330/1/92]

यह को. नि.स. गव. सचिव (पब्लिक)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th February, 1992

S.O. 942.—In pursuance of the clause (a) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri J. M. Sarkar, Assistant in the Consulate General of India, Medan to perform the duties of Consular Agent with effect from 3-2-1992.

[No. T-4330/1/92]

Y. P. SINGH, Under Secy. (PVS)

राष्ट्र एवं नागरिक पति मंत्रालय

(नागरिक पति विभाग)

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1992

का.आ. 943.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन/जिन लाइसेंस (सो) का/के विवरण नीचे दिया गया है/दिए गए हैं, वही/वे उसने/उनके सामने दी गई तिथि से रद्द कर दिया गया है/दिए गए हैं ।

अनुसूची

क्र.सं.	लाइसेंस संख्या तथा विभाग	लाइसेंसधारी का नाम व पता	रद्द लाइसेंस के अनुरूप वस्तु/प्रमाण तथा सम्बद्ध भारतीय मानक	रद्द किए जाने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम एल-1476862	मे. वेंमसिल ग्लास वर्क्स प्रा. लि. दंगमौर	आईएस : 915-1975 एक चिह्न घाटा घायतनी प्लास्क	1991 09 01

[सं.प्रा.वि./55 : 1476862]

एन. श्रीनिवासन, अपर सहायक निदेशक

## MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 30th January, 1992.

S.O. 943.—In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence(s) particulars of which is given below has been Cancelled with effect from the date indicated :

## SCHEDULE

Licence No. (CM/L - -)	Name and Address of the licensee	Article/Processes with relevant Indian Standard covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
(1)	(2)	(3)	(4)
CM/L-1476862	M/s. Vensil Glass Works Pvt. Ltd., Bangalore.	IS : 915-1975—One Mark Volumetric Flosk.	1991-09-01

[No. CMD/55 : 1476862]

N. SRINIVASAN, Addl. Director General

पेट्रोलियम और केमिकल्स मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1992

का.भा. 944.—जब कि केन्द्रीय सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक गैस लाने के लिए पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पेरवली से तुनुक तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाया जाना है।

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके हाथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है।

अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम 1982 (1982 का 50) के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की अंशा की घोषणा करती है।

अतः कि उक्त भूमि में अपनी कृषि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के बिरोध में अपनी आपत्ति सभ्य प्राधिकारी संश्लेष में प्राधिकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, के.जि. प्रोजेक्ट भूसेकरणा, कार्यालय, राजमुक्ति, भागप्रवेश में दर्ज करा सकता है।

और यदि आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विश्वव्यापक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है।

## शेड्यूल

आर.भो.दु. कलो पाइप लाइन पेरवली से तुनुक

स्टेट : आंध्र प्रदेश	मंडल : वेरवलि :	जिला : पूरबगोदावरी					
गांव	आर.एस. नं.	हेक्टास	एर्स	सेन्टिएर्स	एकर्स	सेन्टस	
1	2	3	4	5	6	7	
वेरवलि (पाटे)	131/3ए	0	05	0	0	12	
	131/3बी	0	04	5	0	11	
	131/1 ए 2 ए	0	08	5	0	21	
	132/1 बी 5 बी	0	05	5	0	13	
	132/1 बी 2 बी	0	05	5	0	13	

1	2	3	4	5	6	7
पेरवलि (रिपोर्ट)	132/1/ए 1 बी	0	16	0	0	40
	132/2 बी	0	14	5	0	36
	137/5 बी 2 बी 2	0	10	5	0	26
	2 बी 1	—	—	—	—	—
	137/1 बी 2	0	06	5	0	46
	76/5 बी 2	0	04	0	0	10
	76/4 बी 1	0	06	0	0	15
	76/3 बी 77/1 बी 3	0	07	5	0	18
	76/3 बी 2	0	10	0	0	25
	76/2 बी 1	0	09	0	0	23
	76/1 बी 1	0	09	5	0	24
	77/1 बी 4 2 ए	0	10	5	0	26
	77/1 बी 1	0	04	0	0	10
	85/2 ए 1	0	07	0	0	17
	85/2 ए	0	04	5	0	11
	86/2 सी	0	08	0	0	20
	86/2 ए	0	10	0	0	25
	86/1 बी 1	—	—	—	—	—
	87/4 ए 5 ए	0	21	5	0	53
	87/5 सी	0	10	0	0	25
	87/6 ए	0	01	0	0	02
कुल मिन्नाकर		1	99	5	4	92

[सं. बी.-12016/197/91-ओएनजीसी 4]

एम. यादव, डी.एस. अधिकारी

# MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS New Delhi, the 13th February, 1992

S.O. 944,—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Peravali to Tanuku in A.P. State Pipe line should be laid by the Oil and Natural Gas Commission.

And whereas it appear that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hreto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals

pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 1962 the Central Government hereby declare its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this Notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, K.G. Project, Rajahmundry. (533103).

And every person making such an objection shall also state specifically where he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

R.O.U. Gas pipe line from Peravali to Ranuku (Panavalipart) Indrapradesh State.

Mandal : Peravali

District : West Godavari

Village	R. S. No.	Hectares	Acres	Centiares	Acres	Cents
Peravali Part	131/3A	0	05	0	0	12
	131/3B	0	04	5	0	11
	131/1A 2A	0	08	5	0	21
	132/1B 5B	0	05	5	0	13
	132/1B 2B	0	05	5	0	13
	132/1A1B	0	16	0	0	40
	132/2B	0	14	5	0	36
	137/5B	0	10	5	0	26
	2B1					
	2B2					
	137/1B /2	0	06	5	0	16
	76/B5B2	0	04	0	0	10
	76/4B1	0	06	0	0	15
	76/3B					
	77/1B3	0	07	5	0	18
		0	94	0	2	31
	76/3B2	0	10	0	0	25
	76/2B1	0	09	5	0	23
	76/1B1	0	09	5	0	24
	77/1B4					
	2A	0	10	5	0	26
	77/1B1	0	04	0	0	10
	85/2A1	0	07	0	0	17
	85/2A1	0	04	5	0	11
	86/2C	0	08	0	0	20
	86/2A	0	10	0	0	25
	86/1B1					
	87/4A	0	21	5	0	53
	5A					
	87/5C	0	10	0	0	25
	87/6A	0	01	0	0	02
1st Page		0	94	0	2	31
2nd Page		1	05	5	2	61
GRAND TOTAL		1	99	5	4	92

[No. O-12016/197/91-ONGD-4]

M. MARTIN, Desk Officer.

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय,

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1992

अनुसूची

व्यक्तियों का नाम	पता	क्षेत्राधिकार
श्री एस. वार्ह. रत्नदिवे	मै. सुप्रीम पेट्रोकेम निमिटेड 17/18, शाह इन्डस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400058	महाराष्ट्र राज्य

[सं. 45011/6/91-प्र. स. (पी.सी.)]

ध. श्री. मेन्दीरत्ता, प्रवर सचिव,

का. प्रा. 945 :—पेट्रोलियम और मिनरल पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिग्रहण (अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (1) में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त अनुसूची के कालम (3) की तबनुकूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों के अन्तर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

## MINISTRY OF CHEMICALS &amp; FERTILIZERS

(Department of Chemicals &amp; Petrochemicals)

New Delhi, the 28th February, 1992

S. O. 945 :—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorises the authority mentioned in Column (1) of the Schedule below to perform the function of Competent Authority under the said Act within the areas mentioned in the Corresponding entry in the Column (3) of the said Schedule

## SCHEDULE

Name of the persons	Address	Territorial Jurisdiction
1	2	3
Shri S. Y. Ranadive	M/s. Supreme Petrochem Ltd., 17/18, Shah Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri (West), Bombay-400058.	State of Maharashtra.

[No. 45011/6/91—US(PC)]

D. V. MENDIRATTA, Under Secy.

डाक विभाग

तीरुचिरापल्ली, 9 मार्च, 1992

DEPARTMENT OF POSTS

Tiruchirapalli, the 9th March, 1992

का. प्रा. 946 :—चूंकि भारत सरकार की राय में विभागीय जांच के निमित्त जिससे पट्टुकोट्टै डाक मंडल के मुत्तुपेट उप डाक घर के अधीनस्थ टी. मेलक्काडु शाखा—डाक घर के शाखा डाक पाल श्री वि. धर्मलिंगम संबंधित हैं। यह आवश्यक हुआ है कि मेलक्काडु के श्री एन. शन्मगम तथा उनकी पत्नी श्रीमती मलरकोडी को साक्षी देने के लिए आज्ञा पत्र जारी करें/उनसे कोई लेख प्रस्तुति करावें।

इसलिए अब विभागीय पर्यवेक्षण

(साक्षियों के उपस्थिति प्रवर्तन एवं लेख प्रस्तुति)

अधिनियम 1972 (1972 का 18) की उपधारा 4 द्वारा प्रवर्त अधिकार का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 में उल्लिखित अधिकार का प्रयोग मेलक्काडु के श्री एन. शन्मगम और श्रीमती एस. मलरकोडी के प्रति साक्षियों के प्रवर्तन के संबंध में करने के लिए पट्टुकोट्टै स्थित, पट्टुकोट्टै पूर्वी उप मंडल के उप अधीक्षक डाक घर श्री ए. सवारिराज को प्राधिकृत करती है।

[क. सं. आई एन बी/145—13/81/टी. आर]

डी. पार्थसारथी, महा डाकपाल

S.O. 946.—Whereas the Central Government is of opinion that for the purposes of the Departmental Inquiry relating to Shri V. Dharmalingam, Branch Postmaster T. Melakkadu Branch Office account with Muthupet Sub-office under Pattukottai Postal Division, it is necessary to summon as the witnesses/cell for any document from Shri N. Shanmugam and his wife Shrimathi Malarkodi, Melakkadu.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-Section 4 of the Departmental Inquiries (Enforcement of Attendance of witnesses and Production of Document(s)) Act, 1972 (18 of 1972) the Central Government hereby authorises Shri I. Savariraj, (I. Savariraj) Assistant Superintendent of Post Offices Pattukottai East Sub-Division, Pattukottai, as the Inquiry Authority to exercise powers specified in Section 5 of the said Act in relation to enforcement of witnesses of Shri N. Shanmugam and Smt. S. Malakodi-Melakkadu

[No. INV/145-13/81/TR]

D. PARTHASARATHY, Postmaster-General



श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1992

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1992

का. प्रा. 947.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इण्डिया के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-3-92 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल—12012/231/89—डी-2 (ए)]

वे० के० वेणुगोपालन, डेस्क अधिकारी

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 3rd March, 1992

S.O. 947.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure to the industrial dispute between the employers in relation to the Management of Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 3-3-1992.

[No. L-12012/231/89-D.II (A)]

V. K. VENUGOPALAN, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-  
CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 89 of 1990

In the matter of dispute :

Shri Rajesh Kumar Saini C/o Sri R. S. Saini Gauj  
Moradabad Branch, Unnao.

AND

The Regional Manager Bank of India Civil Lines

## AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12012/231/89-D.II (A) dated 21-3-1990 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of Bank of India Kanpur in terminating the services of Shri Rajesh Kumar Saini is justified? If not to what relief is the workman entitled?

2. In this case reference order was received on 26-3-90 wherein on 10-4-90 was fixed for filing of claim statement. Since then no claim statement has been filed. On 21-5-91, Km. Neeta Mathur, auth. representative for the workman moved an application for time to file statement of claim which was allowed and time till 21-6-91 was granted. Again on 21-6-91 another application was moved by the authorised representative for the workman for time without giving sufficient reasons. Thus from the above it can be safely inferred that the workman is not at all interested in the dispute raised.

3. Therefore, from the facts and circumstances stated above, a no claim award is given in the case.

4. Reference is answered accordingly.

ARJAN DEV, Presiding Officer

का. प्रा. 948.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान ही जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (इ) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 2385 दिनांक 6 सितम्बर, 1991 द्वारा जिन खनन उद्योगों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 सितम्बर, 1991 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (इ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योगों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 मार्च, 1992 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस—11017/9/85—डी-1 (ए) (i)]

एस. एस. पराशर, अव्वर सचिव

New Delhi, the 12th March, 1992

S.O. 948.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. No. 2385 dated the 5th September, 1991, the give Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 14th September, 1991 ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 14th March, 1992.

[No. S-11017/9/85 D.I (A-I) (i)]

S. S. PRASHER, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1992

का. प्रा. 949.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान ही जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (इ) के उपखंड (6) के उपबंधों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. प्रा. 2384 दिनांक 5 सितम्बर, 1991 द्वारा जिन खनन उद्योगों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 सितम्बर, 1991 से छह मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छह मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः अब, औद्योगिक विवाद, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (इ) के उपखंड (6) के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योगों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 मार्च, 1992 से छह मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[संख्या एस—11017/9/85—डी-1 (ए) (ii)]

एस. एस. पराशर, अव्वर सचिव

New Delhi, the 12th March, 1992

S.O. 949.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the Notification of the Government of India in the Ministry of Labour S.O. N.O. 2384 dated the 5th September, 1991, the Lead Mining Industry to be a public utility service for a period of six months, from the 14th September, 1991 ;

And, whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a further period of six months from the 14th March, 1992.

[No. S-11017/9/85 D.1 (A) (H)]

S. S. PRASHFR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1992

का.प्र. 950--बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि नियमावली, 1978 के नियम 3 के उप नियम (1) और नियम 4 के उप नियम (1) के साथ पठित बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 3 मार्च, 1984 को भारत के राजपत्र भाग-II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का.प्र. सं. 665 दिनांक 16 फरवरी, 1984 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित करती है और उक्त समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है, अर्थात्:--

1. श्रम उप मंत्री  
भारत सरकार  
नई दिल्ली -- अध्यक्ष
2. अधीन सचिव  
श्रम मंत्रालय  
नई दिल्ली -- उपाध्यक्ष-पदेन
3. महानिदेशक (श्रम कल्याण)  
श्रम मंत्रालय,  
नई दिल्ली -- सदस्य पदेन,  
केन्द्रीय सरकार के नामित
4. कल्याण प्रायुक्त (मुख्यालय),  
श्रम मंत्रालय,  
नई दिल्ली -- सदस्य-पदेन  
केन्द्रीय सरकार के नामित
5. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
555-ए/3,  
तया समुफोर्ड रंज,  
इलाहाबाद-211002 -- सदस्य-पदेन
6. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
75, मीनर रोड,  
बंगलौर-560052 -- सदस्य-पदेन
7. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
44-ए, गान्धी नगर,  
भीलवाड़ा-311001 -- सदस्य-पदेन

8. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
33 प्रभोक नगर,  
भुवनेश्वर-751009 -- सदस्य-पदेन
9. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
102, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड  
कलकत्ता-700026 -- सदस्य-पदेन
10. कल्याण प्रा. क्त.,  
श्रम कल्याण प्रा. क्त.  
ब्लॉक V, (भ तम),  
सामान्य पुल, कार्यालय हरहाईली काम्प लेक्स  
(निकट सरकारी प्रसूति मैटर्निटी अस्पताल)  
सुल्तान बाजार,  
हैदराबाद 700026 -- सदस्य-पदेन
11. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
44, लक्ष्मी रोड,  
जबलपुर-482001 -- सदस्य-पदेन
12. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
पो. प्रा. नुमरी तलैया,  
जिला-हजारीबाग  
करमा (बिहार)-829137 -- सदस्य-पदेन
13. कल्याण प्रायुक्त,  
श्रम कल्याण संगठन,  
5, सेंट्रल बाजार रोड,  
नागपुर-440010 -- सदस्य-पदेन

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

14. श्री भीकान्त साहा,  
पार्टनर,  
मै. प्रभोक बीड़ी फैक्ट्री,  
28/8, गैरीहाट रोड,  
कलकत्ता-700029
15. श्री मृणाल कुमर,  
पार्टनर,  
मै. भारत बीड़ी फैक्ट्री,  
पो. प्रा. -औरंगाबाद-742201  
जिला-मुर्शिदाबाद (प. बं.)
16. श्री जयदेव डे,  
प्रबंध निदेशक,  
मन्जु बीड़ी फैक्ट्री,  
56/1 श्यामपुष्कर स्ट्रीट,  
कलकत्ता
17. श्री प्रानन्ध पाल,  
पार्टनर,  
राधेश्याम, तोपें बाशी पाल,  
मैनुफैक्चरिंग संघ बीड़ी,  
मी. एफ.-125, विधान नगर (साल्ट लेक सीटी)  
कलकत्ता-700064

18. श्री गीरेन्द्र किशोर साहू,  
पार्टनर,  
गणेश चन्द्र साहू  
19, प्रामेनियन स्ट्रीट,  
कलकत्ता-700001
19. श्री रजनीकांत पटेल,  
मै. प्रभुवास किशोरदास टोबेको प्रॉडक्ट्स  
(प्रा.) लि. गोमतीपुर रोड,  
महमदाबाद-380021
20. श्री नीतिम प्रार. वेसाई,  
निर्देशक,  
मै. वेसाई बक्स लि.  
भतुर चैम्बर्स, बूसरी मंजिल,  
2ए, मोलेबिना रोड,  
पुणे-411001
21. श्री प्रफुल्ल पटेल,  
निर्देशक,  
मै. सी. जे. पटेल टोबेको प्रॉडक्ट्स (प्रा.) लि.,  
मुस्तफा बिल्डिंग, तीसरी मंजिल,  
सर किरोजशाह मेहता रोड,  
बम्बई-400001
22. श्री गणपति पर्वे,  
मै. भारत बीडी बक्स प्राइवेट लि.,  
पो. ब. नं. 730  
काचरी रोड, बंगलूर-575003
23. श्री सुधीर साबले,  
मै. साबले बाबरी एण्ड कं. प्राइवेट लि.,  
105 भवानी पीठ,  
पुणे-411002
24. श्री सुब्रह्मण्य सरीन,  
मैनेजिंग पार्टनर,  
मै. सेचुरी इन्वैस्टमेंट्स लि.,  
प्लॉट नं. 183, सेंटर-24,  
फरीदाबाद (हरियाणा)
25. श्री एस. के. भानु,  
मै. भानुप्रकाश इन्टरप्राइज,  
जेड-72, ब्रैस्ट पटेल नगर,  
नई दिल्ली-110008
- कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
26. श्री हुमायूँ रजा,  
सहासचिव,  
जोगपुर महाकु मा बीडी अमिक यूनियन (इष्टक)  
मुख्यालय, औरंगाबाद  
मुशिवाबाद (प. बं.)
27. श्री सुरेश शर्मा,  
प्रध्यक्ष,  
भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश राज्य,  
24/26, साउथ टॉरिया टोपे नगर,  
भोपाल-462003
28. श्रीमती विजया रामचन्द्र कावगी,  
342, गजपेट  
पुणे-411002
29. श्री स्याना इग्नाहुल  
महसचिव,  
बीडी मजदूर सभा,  
1371, मोमिनपुरा,  
संगमनेर, जिला-महमदनगर (महाराष्ट्र)
30. श्री अभिनव सिन्हा,  
महासचिव,  
ए-1-1, बंगाल बीडी बक्स एण्ड एम्प्लॉईज फेडरेशन,  
यूटक (एल. एस.) प्राक्स,  
77/2/1 लेमिन सारणी,  
कलकत्ता-700013
31. श्री जी. कन्नाबीरन,  
7/बी, राजाजी स्ट्रीट,  
पो. प्रा. -गुडियास्टम-632602,  
जिला-तार्थ अकटि (तमिलनाडु)
32. श्री प्रार. के. रत्नाकर,  
महासचिव,  
प्राल. इंडिया बीडी सिगार एण्ड टोबेको बक्स  
फेडरेशन,  
224, चौपाटी करंजा,  
पो. प्रा. महमदनगर (महाराष्ट्र)  
पिन-414001
33. श्री एम. कृष्णामूर्ति,  
बीडी एण्ड सिगार बक्स यूनियन,  
शिवनगर, अण्डर रिज रोड,  
वाराणसी-506003 (आ. प्र.)
34. श्री सी. कानन,  
केरल स्टेट कमेटी प्राफ सीटू,  
मेल्लेयाम्पानूर,  
त्रिवेन्द्रम-695001  
केरल
35. श्री हरिगोपाल दास,  
सचिव,  
पाकुर बीडी प्राइवेटिंग मजदूर इण्ड स्ट्रियल  
का-आपरेटिव सोसायटी लि.,  
पाकुर (साहिबगंज)
36. फादर एस्टोनी,  
मंजिला कालवरी सोशल सेंटर,  
पूथोले,  
त्रिचूर जिला, केरल
37. श्री सत्योष कुमार मूर,  
चेयरमैन,  
बांकुरा बीडी सिन्हा को-आपरेटिव सोसायटी लि.,  
रजिन्द्र सारणी, बांकुरा
38. कल्याण प्रशासक (मुख्यालय),  
भम मंत्रालय,  
नई दिल्ली

—सचिव

[संख्या यू-23011/1/87-इस्यू-II (सी.)]

बी.डी. नगर, प्रवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th March, 1992

S.O. 950.—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976) read with sub-rule (1) of rule 3 and sub-rule (1) of rule 4 of the Beedi Workers Welfare Fund Rules, 1978 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour number S.O. 665 dated the 16th February, 1984 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 3rd March, 1984, the Central Government hereby constitutes the Central Advisory Committee and appoints the following persons to the said Committee, namely :—

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Deputy Minister for Labour,<br>Government of India,  | Chairman.   | 15. Shri Mustak Hossain,<br>Partner,<br>M/s. Bharat Biri Factory,<br>P.O. Aurangabad-742201,<br>District Murshidabad (W.B.).  |
| 2. Additional Secretary,<br>Ministry of Labour,<br>New Delhi.   | Vice-Chairman<br>(Ex-officio)                           | 16. Shri Jaydev Dey,<br>Managing Director,<br>Mantu Biri Factory (P) Ltd.,<br>56/1, Shyampukur Street,<br>Calcutta-700004.  |
| 3. Director General (Labour Welfare),<br>Ministry of Labour,<br>New Delhi.  | Member, ex-<br>officio, nominee of<br>the Central Govt. | 17. Shri Ananda Paul,<br>Partner,<br>Radhashyam Tirthabashi Paul<br>Manufacturing Sankha Biri,<br>CF-125, Bidhan Nagar (Salt Lake City),<br>Calcutta-700064.        |
| 4. Welfare Commissioner (Headquarters),<br>Ministry of Labour,<br>New Delhi.  | -do-  | 18. Shri Gourendra Kishore Shaha,<br>Partner,<br>Ganesh Chandra Shaha,<br>19, Armenian Street,<br>Calcutta-700001.  |
| 5. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>555-A/2, New Mumfordganj,<br>Allahabad-211002.  | Member, ex-<br>officio.                                 | 19. Shri Rajnikant Patel,<br>M/s. Parbhudas Kishordas Tobacco<br>Products (P) Ltd.,<br>Gomtipur Road,<br>Ahmedabad-380021.  |
| 6. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>75, Millers Road,<br>Bangalore-560052.  | -do-  | 20. Shri Nitin R. Desai,<br>Director,<br>M/s. Desai Brothers Ltd.,<br>Atur Chambers, 2nd Floor,<br>2A, Moledina Road,<br>Pune-411001.                               |
| 7. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>44-A Gandhinagar,<br>Bhilwara-311001.   | -do-  | 21. Shri Frafal Patel,<br>Director,<br>M/s. C. J. Patel Tobacco Products (P) Ltd.,<br>Mustafa Building, 3rd Floor,<br>Sir Phirozeshah Mehta Road,<br>Bombay-400001. |
| 8. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>33, Ashok Nagar,<br>Bhubaneswar-751009.   | -do-  | 22. Shri Ganapathi Pai,<br>M/s. Bharat Beedi Works Private Limited,<br>Post Box No. 730,<br>Kadri Road,<br>Mangalore-575003.  |
| 9. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>162, Shyama Prasad Mukherjee Road,<br>Calcutta-700026.  | -do-  | 23. Shri Sudhir Sable,<br>M/s. Sable Waghire and Company Private Limited,<br>105, Bhavani Peth,<br>Pune-411002.   |
| 10. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>Block V (Ground Floor),<br>General Pool Office Accommodation Complex,<br>(Near Government Maternity Hospital),<br>Sultan Bazar,<br>Hyderabad-500195. | -do-  | 24. Shri Sudarshan Sareen,<br>Managing Partner,<br>M/s. Century Engineering Company,<br>Plot No. 183, Sector 24,<br>Faridabad (Haryana).                            |
| 11. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>44, Narmada Road,<br>Jabalpur-482001.  | -do-  | 25. Shri S. K. Anand,<br>M/s. Anandas Enterprises,<br>Z-72, West Patel Nagar,<br>New Delhi-110008.  |
| 12. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>P.O. Jhumritelaiya,<br>District Hazaribagh,<br>Karma (Bihar)-829137.   | -do-  | Members Representing Workers :  |
| 13. Welfare Commissioner,<br>Labour Welfare Organisation,<br>5, Central Bazar Road,<br>Nagpur-440010.   | -do-  | 26. Shri Humayun Reza,<br>General Secretary,<br>Jangipur Mahakuma Biri<br>Shramik Union (INTUC),<br>Head Office,<br>Aurangabad,<br>Murshidabad (W.B.).              |
| Members Representing Employers :  |   | 27. Shri Suresh Sharma,<br>President,<br>Bharatiya Mazdoor Sangh M.P. State,<br>24/26, South Tatya Topa Nagar,<br>Bhopal-462003.                                    |
| 14. Shri Srikanta Saha,<br>Partner,<br>M/s. Ashok Biri Factory,<br>28/8, Gariahat Road,<br>Calcutta-700029.   |   |   |

28. Smt. Vijaya Ramchander Kadgi,  
342, Gajpet,  
Pune-411002.
29. Shri Sayanna Engandul,  
General Secretary,  
Beedi Mazdoor Sabha,  
1371, Mominpura,  
Sangamner,  
District Ahmednagar (Maharashtra).
30. Shri Achintya Singha,  
General Secretary,  
A1-1, Bengal Beedi Workers and  
Employees Federation,  
UTUC(LS) Office,  
77/2/1, Lenin Sarani,  
Calcutta-700013.
31. Dr. G. Kannabiran,  
7/B, Rajaji Street,  
P.O. Gudiyatnam-632602,  
District North Arcot,  
(Tamil Nadu).
32. Shri R. K. Ratnakar,  
General Secretary,  
All India Beedi, Cigar and  
Tobacco Workers' Federation,  
224, Choupati Karanja,  
P.O. Ahmednagar (Maharashtra),  
Pin-414001.
33. Shri M. Krishnamurthy,  
Beedi and Cigar Workers' Union,  
Shivnagar,  
Under Bridge Road,  
Warangal-506003,  
Andhra Pradesh.
34. Shri C. Kannan,  
Kerala State Committee of CITU,  
Melethumpanoor,  
Trivandrum-695001,  
Kerala.
35. Shri Hari Gopal Das,  
Secretary,  
Pakur Beedi Producing Mazdoor  
Industrial Cooperative Society Ltd.,  
Pakur (Sahibganj).
36. Father Antony,  
Manjila Calvary Social Centre,  
Poothole,  
Trichur District,  
Kerala.
37. Shri Santosh Kumar Sur,  
Chairman,  
Bankura Birla Silpa Cooperative  
Society Limited,  
Rabindra Sarani,  
Bankura.
38. Welfare Administrator (Hqrs.),  
Ministry of Labour,  
New Delhi.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1992

का.प्र. 951—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उपधारा (3) द्वारा प्रवृत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1-4-92 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसका उक्त अधिनियम के अध्याय-4 धारा-44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है (और अध्याय-5 और 6) धारा-76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

केन्द्र	राजस्व ग्राम के अन्तर्गत	तालुक	जिला
मेल विश्राम	1. पैरुमुगई	वैलूर	नार्थ आर्कोट अम्बेदकर
	2. पुटुथाक्कु	आर्कोट	नार्थ आर्कोट अम्बेदकर

[संख्या एस-38013/4/92-एस.एस.-1]

जे. पी. शुकला, प्रवर सचिव

New Delhi, the 18th March, 1991.

S. O. 951—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st April, 1992 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI (except sub-section (1) of section (1) of section 76 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force of the said Act shall come into force in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Area comprising revenue village	Taluk	District
Mel Visharam	1. Perumugai	Vellore	North Arcot Ambedkar
	2. Puttuthakkku	Arcot	North Arcot Ambedkar

[No. S—38013/4/92-SSI]

J. P. SHUKLA, Under Secy,

[No. U-23011/1/87-W.II(C)]  
V. D. NAGAR, Under Secy.

